नेपाल की कहानी



महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव

नेपाल की कहानी

(सचित्र)

लेखक
काशी प्रसाद श्रीवास्तव, एम ए
सदस्य, सलाहकार सभा
नेपाल

प्राक्कथन
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन

१९७८

आत्माराम एण्ड संस
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता
काश्मीरी गेट
दिल्ली-६

प्रकाशक
रामलाल पुरी
आत्माराम एण्ड संस
काश्मीरी गेट, दिल्ली–६

मूल्य आठ रुपये

मुद्रक
नैशनल प्रिंटिंग वर्क्स
दिल्ली

ज्ञात-अज्ञात उन शहीदों को

जिन्होंने

नेपाली जनता की भलाई

तथा

देश में प्रजातन्त्र लाने के

निमित्त अपने प्राणों की

आहुति दी

प्राक्कथन

नेपाल हमारा पड़ोसी देश ही नहीं हमारे हिमालय का एक महत्वपूर्ण और विशाल खंड है, पर पिछले सौ सालों में हमारा नेपाल-विषयक ज्ञान पहिले से भी कम हो गया था। हमारे लोग उसे एक रहस्यपूर्ण अज्ञात देश समझने लगे थे। राणाशाही ने इसमें सहायता की थी। शिवरात्रि के समय कुछ सौभाग्यशाली स्त्री-पुरुष बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करते समय नेपाल के एक थोड़े से भाग की झांकी कर पाते और वह उससे भी अधिक वहां की हर चीज को एक जादू की सी समझकर लौटकर उसको अतिशयोक्तिपूर्ण कथामें दुहराते। हम भारतीयों के लिए नेपाल का यद्यपि यही रूप था, पर अंग्रेज इससे भली भांति परिचित थे। राणाशाही उनके रास्ते में उतनी रुकावट नहीं डालती थी, जितनी भारतीय जिज्ञासुओं के लिए। यह प्रसन्नता की बात है, कि अब वह अज्ञान का परदा हट रहा है। नये नेपाल में अब हरेक भारतीय किसी भी मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरित अपने फोटोग्राफ के साथ प्रवेश कर सकता है लेकिन इतने से वह नेपाल का परिचय नहीं प्राप्त कर सकता। परिचय कराने वाले कुछ अंग्रेजों के लिखे ग्रंथ हैं जो तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। वह भी, उनकी दृष्टि से अतीत काल में लिखे गये होने से उतने उपयोगी नहीं हैं। हमें एक सांगोपांग इदमित्थम् ग्रंथ की आवश्यकता थी, जिसे श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तवजी की 'नेपाल की कहानी' पूरी करेगी, इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है। लेखक का उस देश से परिचय किसी बाहरी व्यक्ति जैसा नहीं है बल्कि वह वहां के जीवन में सहगामी तथा नये नेपाल के निर्माण के लिए हुए संघर्ष में सहकारी रहे। उन्होंने अपने वैयक्तिक अनुभव और ज्ञान के साथ इस बात की पूरी कोशिश की कि नेपाल सम्बन्धी कोई भी ज्ञातव्य बात छूटने न पाये। इस पुस्तक को देख कर ही पाठक जान जायेंगे कि अपनी सामग्री को जमा करने में लेखक ने कितना परिश्रम किया है। 'नेपाल की कहानी' इस बात का सबूत है कि हिन्दी वाले कितनी शीघ्रता से गंभीर ग्रंथों के प्रणयन में अग्रसर हो रहे हैं।

नेपाल का धूमिल ज्ञान हमारे लिए इष्टकर नहीं हो सकता। हमारे दोनों देश निसर्ग-जात यमल हैं। हमारी आज की आर्थिक प्रगति एक-दूसरे के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करती है। सिंचाई और बिजली के स्रोत हिमालय की सदानीरा नदियों में से कितनों ही के उद्गम या प्रथम स्पन्दन भूभाग नेपाल में हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या तथा सबसे अधिक सामर्थ्य—सिंचाई और बिजली दोनों में—कोसी, अपनी दो धारों के रूप में तिब्बत से निकल महान् हिमालय को फोड़ नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यही नहीं उस पर काबू पाने के लिए जो बांध बनाया जा सकता है वह नेपाल की सीमा के भीतर ही तैयार किया जा सकता है। हमारे दोनों राष्ट्रों ने अपनी भलाई समझकर इसके बारे में

समझौता भी कर लिया है। आशा करनी चाहिए कि कोसी-योजना अब बहुत दिनों तक सिर्फ कागजी योजना नहीं रहेगी। कोसी की तरह ही गंडक और घाघरा (सरयू) जिनका स्रोत हिमालय छोड़कर आने वाली नदियाँ भी नेपाल के भीतर से आकर नेपाल के भीतर ही मैदान (तराई) में प्रवेश करती हैं। उनके अपार जल और विद्युत के धन को हम मिलकर ही उपभोगी बन सकते हैं। राप्ती जैसी कितनी ही और नदियों के बारे में तो कहना ही क्या है। ये नदियाँ जिनकी भूमि में भारत में प्रवेश करती हैं और इनसे जिनको सबसे अधिक हानि-लाभ उठाना पड़ता है वह हिन्दी बोलने वाले ही लोग हैं। उन्हीं की भाषा में लिखी यह पुस्तक उन्हीं के लिए और भी अधिक ज्ञानवर्धक और मार्ग-दर्शक होगी इसमें सन्देह नहीं। यह भी स्मरण रखने की बात है, कि नेपाल के नागरिकों में सबसे अधिक संख्या हिन्दी बोलने तराई प्रदेश के हैं जो ही नेपाल सरकार के राजस्व को सबसे अधिक देने के लिए मजबूर हैं। तराई की हिन्दी-भाषी जनता नेपाल की एक अत्यंत कठिन समस्या हो सकती है, यदि नेपाल के वर्तमान शासकों ने भी उसके साथ वही बर्ताव रक्खा, जिसे गोरखा-शासक अपने शासन के आरंभ से करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में जैसा पूर्वी पाकिस्तान के साथ बर्ताव करने की प्रवृत्ति देखी जाती है उससे भी कहीं अधिक हीन मनोवृत्ति नेपाली शासकों की तराई के प्रति मालूम होती है। वह नहीं चाहते कि तराई की जनता कभी भी अपनी संख्याबल के अनुसार शासन में अधिकार पावे। यह निश्चय ही है कि स्वाभाविक बुद्धि रखने वाले इतने नागरिकों को उनके उचित अधिकार से वंचित नहीं रक्खा जा सकता। न उनके ऊपर सबसे अधिक कर-भार लादा जा सकता है। नेपाल के हर हितैषी की यही कामना होगी कि अब से तराई-निवासियों को विजित प्रजा नहीं, बल्कि स्वतंत्र नागरिक माना जावे। शासन और प्रशासन केवल पर्वतवासियों की इजारेदारी न मानी जावे, और तराई वासियों को दब्बू-गुलाम समझने की प्रवृत्ति को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जावे। इतिहास ने यदि हमारे इन लाखों भाइयों को नेपाल के भीतर रहने के लिए मजबूर किया, तो उससे सदा लाभ उठाने की कोशिश करना आज बुद्धिमानी नहीं मानी जा सकती। आखिर मोरंग से लेकर काली धारदा के किनारे तक बसे ये हिन्दी-भाषी तराई-निवासी उन्हीं लोगों के रक्त और मांस हैं जो उनके दक्षिण में पूर्णिमा से पीलीभीत तक के जिलों में बसते हैं। तराई वासी नेपाल में होकर किसी विदेशी शक्ति के गुलाम नहीं हैं, नेपाल भारत का सहोदर है उसके भीतर रहने में उन्हें अरुचि नहीं हो सकती यदि वह वहां समान नागरिक माने जावें। यदि ऐसा करने में नेपाल के आज के तथा भविष्य के शासक अपने प्रभुत्व को खतरे में समझें, तो यह उनकी अत्यंत अदूरदर्शिता होगी। यदि नेपाल में निहित स्वार्थों की रक्षा करना आवश्यक न समझ जनकल्याण को शासन का ध्येय माना जाये और तदनुसार काम किया जावे तो भय करने की कोई जरूरत नहीं। पर्वतीय भाग अपने बहुमूल्य खनिजों, तथा औद्योगिक कच्चे माल से वहां देश की जनता को समृद्ध और सुखी बना सकता है, वहां तराई खाद्य और दूसरी औद्योगिक वस्तुओं से मालामाल कर सकती है।

नेपाल के नये शासकों की मनोवृत्ति अभी भी कितनी ही बातों में बदली नहीं है, यह इस पुस्तक में दिये नेपाल और ब्रिटेन के उस समझौते से मालूम होगा, जिसके अनुसार नेपाल अपने पुत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन सैनिक बनाने की जिम्मेवारी लिये हुए है। उसके शासकों की यह कितनी लचर दलील है, कि ऐसा न करने पर बहुत से नेपालियों के बेकार होने की संभावना है। क्या बेकारी दूर करने का उनके पास यही रास्ता रह गया है कि नेपाली नागरिक अपने ऐशियाई भाइयों तथा जिनसे कोई शत्रुता नहीं, उन मलाई देशभक्तों को—मर्दों को ही नहीं निरीह स्त्री-पुरुषों को भी—साम्राज्यवादी वरिष्ठों के दिये टुकड़ों के लिए निष्ठुरतापूर्वक भून डालें। यह कोई वीरता नहीं, दासवृत्ति है जिसके लिए नेपाल के शासकों को शरम आनी चाहिए। भारत ने जब अपनी भूमि से अंग्रेजी रंगरूटी अड्डों को हटाया तो नेपाल ने उन्हें अपने यहाँ स्थान दिया। बहुत दिनों तक जनता की आँखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। कुछ हजार गोरखा तरुणों को अंग्रेजों की न तृप्त होने वाली लोलुपता की भेंट करने से नेपाल की बेकारी नहीं हट सकती। वहाँ तो सारी पहाड़ी प्रजा भूखी मर रही है।

श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी की यह पुस्तक बड़ी सामयिक और उपयोगी है। उन्होंने हमारी जानकारी बहुत बढ़ाई है और नेपाल को समझने का मौका दिया है।

मसूरी
२१ मार्च १९५५

राहुल सांकृत्यायन

लेखक-परिचय

प्रस्तुत पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गयी है, जो नेपाल के एक नागरिक हैं और वहाँ की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक एक राजनीतिक संस्था का सदस्य है तथापि उसने एक इतिहास के लेखक के कर्तव्य का पालन बहुत ही शुद्ध हृदय से किया है।

'नेपाल की कहानी' के लेखक श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म १ फरवरी सन् १९२५ ई० में भगवान् गौतम बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनी उपवन के सन्निकट पैंतिया ग्राम में हुआ। बाल्यकाल ही में आपके माता-पिता की मृत्यु हो गयी थी, जिससे आपका लालन-पालन आपकी ननिहाल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ।

आपकी शिक्षा काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में भारतीय नेता श्री प्रकाशजी, जो आजकल मद्रास के गवर्नर है की संरक्षता में हुई। वहाँ से आपने सन् १९४८ ई० में हिन्दी-साहित्य में एम. ए की शिक्षा प्राप्त की और वहीं आप भाषा-विज्ञान में अनुसंधान भी करने लगे। धर्म तथा दर्शन में भी आपने कई परीक्षाएं पास कीं जिनमें आप बराबर सर्व-प्रथम रहे। इस बीच पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन् के विशेष संपर्क में रहे।

सन् १९४२ ई० के भारतीय आन्दोलन में आपको काशी विश्वविद्यालय में गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश में नजरबन्द भी किया गया था। इसके बाद ही से आप राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे।

नेपाल की विप्लव सशस्त्र क्रांति में आपने सक्रिय भाग लिया। क्रांति भर आप पश्चिमी नेपाल की विद्रोही सरकार के प्रधान मंत्री भी रहे।

श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव एक अच्छे पत्रकार तथा साहित्यिक व्यक्ति भी हैं। कहानियां तथा कविताएं लिखने में आपकी विशेष अभिरुचि है।

इस समय आप नेपाल सलाहकार सभा के सदस्य तथा एक प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।

नेपाल के सम्बन्ध में इतनी सामग्री हिन्दी में अब तक उपलब्ध नहीं थी, जिसकी पूर्ति लेखक ने 'नेपाल की कहानी' लिखकर कर दी है। नेपाल के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन परम आवश्यक है। आज तक भारत और नेपाल के सम्बन्ध में जितने समझौते, संधिया तथा संधियां हुई है वह सब पुस्तक के परिशिष्ट भाग में दिये गये हैं जो भारत तथा नेपाल सरकार के अधिकारियों के लिए भी उपयोगी हैं।

रामलाल पुरी

दो शब्द

नवम्बर सन् १९५० ई० में नेपाल में एक क्रान्ति छिड़ी। यह अपने ढंग की एक निराली ही क्रान्ति थी—जिसमें नेपाल के सम्राट् ने अपने ही शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया और समस्त देश में जनता ने शासन-कर्ताओं का विरोध तथा अपने नरेश का समर्थन किया। उस समय देश की जनता को ऐसा प्रतीत हुआ कि क्रान्ति के फलस्वरूप उस पर किये गये विगत एक सौ चार वर्षों के निरंकुश अत्याचारों का अन्त हो जायगा और उनकी मातृभूमि भी संसार के अन्य स्वतन्त्र देशों की भांति ही एक सम्पन्न राष्ट्र बन जायगी। यही एक प्रेरणा थी जिसके बल पर क्रान्ति की ज्वालाएं भभक उठीं और सारे देश की जनता एकतन्त्री शासन-पद्धति को समाप्त करके प्रजातन्त्र के लिए कटिबद्ध हुई।

क्रान्ति का विस्फोट देशव्यापी हुआ किन्तु जब वह सफलता की पूर्णावस्था में पहुंच चुकी तब उस बीच ही में जनता की इच्छा के विपरीत रोक दिया गया और शासकों से समझौता कर लिया गया। इस प्रकार नरेश, देश तथा आन्दोलन को सहयोग देने वाली भारतीय जनता की इच्छा पूरी होने में बाधा डाल दी गई। यही कारण है जो क्रान्ति के पश्चात् भी देश में व्यापक असन्तोष बना ही रहा और चार वर्ष का अमूल्य समय भी जनतन्त्र की नींव कायम में बेकार ही साबित हुआ। इस बीच कई सरकारें बनीं-बिगड़ीं किन्तु प्रत्येक सरकार जनता की भलाई करने की अपेक्षा अपनी ही स्थिति संभालने में लगी रही। इससे देश में जहां एक ओर आर्थिक परिस्थिति और निराशा की सृष्टि हुई वहां दूसरी ओर अनुदार तत्वों को संगठित होने का भी पूरा मौका मिलता गया जो जनता की एकता का छिन्न-भिन्न करके उसे गुमराह भी करते रहे। वे नेपाल की भोली जनता को अपने अभिन्न पड़ोसी तथा घनिष्ट मित्र—भारत और चीन के विरुद्ध भी भड़काने से बाज नहीं आते—जो अपनी नतिकता के बल पर विश्व की जनता को शान्ति के प्रयास में नियोजित करके राष्ट्रों के बीच की तनातनी को काफी हद तक कम करने में विशेष सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं।

लेखक को नेपाल का एक राष्ट्रीय होने का सौभाग्य प्राप्त है। उसे इस बात का भी गर्व है जो वह अपनी क्षीण शक्ति के अनुसार नेपाल की क्रान्ति में सक्रिय भाग भी ले सका। उसने नेपाल के इतिहास का अध्ययन

करके ही सशस्त्र क्रान्ति में अपना हाथ डाला था—यद्यपि वह गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर शुरू ही से हिंसा छल-नीति का विरोधी और शांति एवं स्पष्ट कूटनीति का कट्टर अनुयायी रहा।

पुस्तक का नाम 'नेपाल की कहानी' है। कहानियां प्रायः कपोल-कल्पित और मनगढ़न्त हुआ करती हैं—किन्तु 'नेपाल की कहानी' वास्तव में नेपाल का इतिहास है जिसमें असत्य को लेशमात्र भी स्थान नहीं दिया गया है। वस्तुतः लेखक ने अपनी ओर से नेपाल की इस वृहद् कहानी में कुछ भी नहीं लिखा है।

एक नेपाली होते हुए भी लेखक ने यह पुस्तक हिन्दी भाषा में लिखी है। यह केवल इसलिए जिससे नेपाल और भारत दोनों देशों की जनता नेपाल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हासिल कर सके—जिसके आधार पर ही नेपाल का भविष्य निर्भर करता है। नेपाल की जनता और भारतीय जनता एक ही आदर्शों पर प्राचीन काल से चली आ रही है। दोनों देशों के परिस्थिति उद्देश्य एवं समस्यायें एक-से तथा समान हैं जिन्हें नेपाल और भारत परस्पर सहयोग तथा शान्ति के सिद्धान्त द्वारा बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।

नेपाली जनता भारतीय जनता की भांति उच्चादर्शों एवं नैतिकता पर आधारित राजनीति को ही निश्चय रूप से सफल कूटनीति मानती है। उसकी दृष्टि में वर्तमान समय की भारत की नीति एवं कार्यों में जो एकरूपता पायी जाती है वही नेपाली जनता के भी हृदय से अभिव्यक्त होती हुई प्रतिभासित होती है।

लेखक की गिरफ्तारी के साथ पुस्तक की पाण्डुलिपि भी मई सन् १९५२ ई० में बिहार पुलिस के हाथ लग गयी थी जो पूरे ढाई साल के बाद काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावास के कठिन प्रयत्न से वापस मिल सकी। इसके लिए लेखक उन सभी व्यक्तियों का विशेष आभारी है जिनकी दौड़-धूप से पुस्तक की पाण्डुलिपि उसे साबित रूप में प्राप्त हो सकी।

'नेपाल की कहानी' को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री रामलाल पुरी तथा डाक्टर होरीलाल सक्सेना को है, जिनकी प्रेरणा और सहयोग से लेखक सतत् प्रोत्साहित होता रहा। मेरे मित्र श्री गोरख नाथ वर्मा भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं जिनकी अभिरुचि से यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित हो सकी। अस्तु!

शान्ति कुटीर
लुम्बिनी उपवन

काशी प्रसाद श्रीवास्तव

विषय-सूची

प्रथम खण्ड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय खण्ड प्राकृतिक तथा राष्ट्रीय रूपरेखा

तृतीय खण्ड राजनीतिक स्थिति

परिशिष्ट

चित्र-सूची

नेपाल की कहानी

१

एक निराला देश

नेपाल एक निराला देश है। आज बीसवीं शताब्दी में जब कि समस्त संसार वायुयानों मोटरों तथा रेलों को अपने जीवन का साधारण अंग अनुभव करता है इस बीहड़ तथा एकान्त देश के लाखों नर-नारियों ने इन वस्तुओं के दर्शन करने तो दूर कभी नाम तक नहीं सुने हैं। आधुनिक सभ्यता ने तो इस देश में वहाँ की राजधानी काठमाण्डू तथा तीन चार अन्य नगरों को छोड़कर कहीं भी अपना घर नहीं बनाया है और अंग्रेजों ने भी कभी इस देश को उन्नत करने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि उन्हें तो नेपाल के वीर गोरखा सैनिकों की ही आवश्यकता थी और उन्हें भय था कि यदि नेपाल शिक्षित अथवा जागरूक हो गया तो यह वीर मनुष्यों की खान सदा के लिए समाप्त हो जायगी और एशिया में उनका ब्रिटिश साम्राज्य अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा।

नेपाल के वास्तव में दो भाग हैं—उत्तर में पहाड़ी प्रदेश तथा दक्षिण में तराई। नेपाल का सैनिक बल पहाड़ी प्रदेश पर आधारित है और उसका आर्थिक बल तराई की उपजाऊ भूमि पर।

सरल तथा सत्यवादी

पहाड़ के निवासी अर्थात् 'पहाड़ी' सरल तथा सत्यवादी होते हैं। उनकी बोली न समझ सकने के कारण लोग उनके हृदय की निष्कपटता की सराहना मुक्त कंठ से नहीं कर पाते परन्तु पूरी बात समझने वाले उनकी सरलता पर नतमस्तक हुए बिना नहीं रहते। यहाँ की शैल-कुमारियाँ मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों की अभिन्न चिरसंगिनी होती हैं। उनकी भावनायें सात्त्विक होती हैं। वे मद-मस्त अवस्था में वन-वीथिका में अहर्निश काम करती हैं। वे कृत्रिमता से अछूती रहती हैं। इनमें बहुत सी ऐसी होती हैं जो सदैव पुरुषों के साथ काम तो करती रहती हैं किन्तु वह यह जानती ही नहीं कि कामुकता क्या होती है। वे सहज भाव से अपने सहचरों के साथ नाचती-कूदती विचरती और गाती हैं। कहा जाता है कि सर्दी के आधिक्य से उनकी वासनायें अधिक काल तक जागृत नहीं होतीं और अधिक वयस्क हो जाने पर ही उनकी कामवासना जागृत होती है किन्तु इसका मुख्य कारण यहाँ का निर्मल प्रशान्त वातावरण है। पुरुषों की अपेक्षा नेपाल की स्त्रियों में कर्म-परायणता कहीं अधिक कूट-कूट कर भरी हुई है। नारियाँ जब रजस्वला-धर्म का पालन

करती है तो वह किसी भी पुरुष से अपना स्पर्श नहीं होने देती। विधवायें तो अपना अधिकांश समय प्रतिदिन पूजा-पाठ में ही बिताया करती हैं। पुरुषों में चन्दन लगाने का बहुत चलन है। नेपाल में ऐसे बहुत ही कम ब्राह्मण दिखाई पड़ेंगे जिनके ललाट चन्दन-अर्चित न हों।

आतिथ्य-सत्कार

नेपाली अपने परिवार की सुरक्षा अथवा सेवा-शुश्रूषा तो करते ही हैं परन्तु उससे अधिक अतिथि की आवभगत करते हैं। इस बीसवीं सदी में भी वे 'अतिथि देवो भव' का चिर वैदिक मंत्र अपनाये रहते हैं। यह सच है कि अधिकांश पहाड़ी खाने-पीने को मुहताज रहते हैं उनका समस्त जीवन पेट की चिन्ता में ही व्यतीत होता है, तब भी वह अपने द्वार पर आये हुए अतिथि अथवा साधु-सन्यासी का प्रेमपूर्वक स्वागत करते हैं। वे उन्हें देवता मानकर अपने परिवार की स्त्रियों के बीच में रखते हैं और उनकी सेवा-शुश्रूषा तन-मन-धन से तत्परता के साथ करते हैं। पहाड़ी समाज में जो व्यक्ति अतिथियों की पूजा हृदय खोलकर नहीं करता वह बहुत नीच और पापी माना जाता है। गुरु तथा ईश्वर में वे भेद नहीं मानते। जो गुरु का मंत्र नहीं लेता उसे पहाड़ी 'निगुरा' कहते हैं। उनका पुरातन विश्वास है कि निगुरा चाहे जितना विद्वान् और चरित्रवान् क्यों न हो तब भी यदि उसने अपने गुरु से कान नहीं फुकवाये तो वह अन्त में नरक ही पायेगा। कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि पंचत्व को प्राप्त हुए निगुरों को श्मशान-घाट पर भी चिता से उतारकर गुरु से मंत्र दिलवा दिया जाता है। उनकी धारणा है कि जो गुरु की सेवा नहीं करते वे अपना अमूल्य पुण्य क्षीण करके एक दिन अवश्य ही महा कंगाल हो जाते हैं। ये लोग गुरु की केवल सेवा ही नहीं करते वरन् उन्हें विदाई के रूप में अधिक से अधिक द्रव्य भी देते हैं। चलते समय उनका चरणामृत तथा जूठन परिवार के बाल-वृद्ध सभी बड़े प्रेम से पान करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं।

धर्म-परायणता

नेपाल वस्तुतः धार्मिकों का देश है। यहाँ के पुराने शासक धर्म का डर दिखाकर भोली भाली जनता को सदियों से धर्मभीरु बनाते रहे हैं। नेपाली शासकों के लिए धर्म सदैव ही [illegible] की वस्तु रही हो परन्तु उनके सामाजिक जीवन पर धर्म का कुछ भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। शासकवर्ग में दासियों और कुटनियों का भी रक्खा जा सकना था। यही कारण है कि उस वंश के शासक दर्जनों पत्नियाँ रखते थे। अधिकृत रोल वाले राणा परिवार में कुछ ही प्रमुख व्यक्ति होते थे परन्तु बहु विवाह के फलस्वरूप अब उनकी संख्या घास-फूस सदृश खूब बढ़ गई है। रखैलियों की सन्तानों को छोटे-छोटे पद दे दिये जाते थे। किन्तु रूप में शासकों के छोटे-छोटे टुकड़े भी अनियम ऐसे राणाओं को मिल जाते थे।

नेपाल में सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली की बहुलता है। जो लोग अपनी पत्नी को लेकर माँ-बाप से अलग स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे समाज में अनादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इतर जातियों में इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है। वे अन्तर्जातीय सगाई भी कर लेते हैं। इन जातियों में बहुपत्नी प्रथा खूब प्रचलित है। दस-पन्द्रह रुपये मासिक कमाने वाला सिपाही अथवा मजदूर भी दो अथवा अधिक पत्नियाँ रख सकता है।

नेपाल के उच्च पदाधिकारी पहले केवल राणावंशीय ही हो सकते थे। भारतवर्ष में जैसे अंग्रेज किसी काले आदमी को कोई ऊँचा पद नहीं देते थे उसी प्रकार नेपाल में अफसर होने की योग्यता केवल राणावंश में ही मानी जाती थी। दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि राणावंश की स्त्रियाँ तक यहाँ 'हाकिम' जनती थीं और नेपाल राज्य में अन्यत्र रहने वाली अन्य माताएँ केवल गुलाम ही गुलाम।

जातियों का अजायबघर

नेपाल सदा से ही जातियों का एक अजायबघर-सा रहा है। इसमें अधिकांश जातियाँ असंस्कृत ही हैं। मुस्ताङ-मनाङ क्षेत्रों में केवल भोट-जातियाँ ही बसती हैं। ये जातियाँ तिब्बत के निवासियों से बहुत मिलती जुलती हैं। काठमाण्डू के पचास मील पश्चिम में गोरखा नगर बसा हुआ है जहाँ प्राचीन काल में शैवमत के प्रचारक गुरु गोरखनाथ तपस्या करते थे। उन्हीं के नाम पर यहाँ के रहने वाले गोरखे कहे जाते हैं। गोरखा जाति धर्म का प्रचलन बारहवीं शताब्दी में हुआ। यह जाति वेदानुयायी सनातनधर्मी हिन्दुओं की शाखा है। इसमें ब्राह्मणों के अतिरिक्त ठकुरी तथा खस जाति के क्षत्रिय अधिक प्रसिद्ध हैं।

ठकुरी क्षत्रियों में शाह, शाही, सेन, मल्ल, खान और चन्द उप-जातियाँ तथा खस क्षत्रियों में पाँडे, पन्त, बस्नेत, बिष्ट और कुँवर उप-जातियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं। तामाङ, गुरुङ तथा मगर जातियाँ भी गोरखा जाति के ही अन्तर्गत आती हैं। खस और ठकुरी शुद्ध हिन्दू धर्मावलम्बी हैं। गोरखा जाति के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं और इस प्रकार अपना रक्त शुद्ध रखने पर गर्व करते हैं परन्तु तामाङ, गुरुङ और मगर जातियाँ केवल नाम-मात्र के लिए ही हिन्दू हैं। वह मुख्यतः बौद्ध हैं और आपस में विवाह भी करती हैं किन्तु इनमें भी अनेक उप-जातियाँ हैं। इनकी सगाई में वर-पक्ष की ओर से कन्या को चाँदी या सोने की चूड़ियाँ दी जाती हैं। और विवाह निश्चित हो जाने पर कन्या को सगाई की 'सही मुदरी' दी जाती है। इस जाति में यदि किसी युवक तथा युवती में प्रेम हो जाये और वह युवक युवती को भगा ले जाये तो वह दोनों उसी युवती के घर आते हैं जब ससुर उनको आमंत्रित करे। युवती का पिता जब दोनों को दही तथा अक्षत का टीका लगा देता है तब ही वह पति-पत्नी मान जाते हैं। गोरखे इस विधि को 'भाग-बिन्दू' कहते हैं। मगर तथा गुरुङ जातियों में हिन्दू-प्रथा के अनुसार ही विवाह-संस्कार सम्पन्न होता है उन्हीं की तरह यह विवाह को 'फेरा' (सप्तपदी) कहते हैं और विवाह के पश्चात् वर तथा

वधू का वस्त्र गाँठ देकर बाँधा जाता है जिसे 'मंगलगाँठ' कहा जाता है।

गुरुंग तथा मगर जातियों में तलाक की भी प्रथा है। तलाक देने के पूर्व 'सिंको दामो' या 'छिंको पसरउ' की प्रथा पूरी करनी पड़ती है। तलाक में पति-पत्नी दोनों की ही स्वीकृति अनिवार्य है और वह तभी पूर्ण समझा जाता है जब दोनों एक बाँस की पिटारी दो सटी हुई मट्टी की कच्ची दीवारों पर रख देते हैं। दोनों को कुछ-कुछ रुपये भी पिटारियों के पास रखने पड़ते हैं और जब उन दोनों में कोई एक दोनों पिटारियों को तोड़कर रुपया ले लेता है तो दूसरा व्यक्ति तुरन्त ही चला जाता है और भविष्य में कहीं भी दूसरा विवाह कर सकता है। इन जातियों में विधवा-विवाह अपराध माना जाता है। राणा शासन में पत्नी यदि अपने किसी प्रेमी से व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाती थी तो पति उसे आजीवन कारावास का दण्ड दिला सकता था और उसके प्रेमी को जनता के सामने अपनी खुकरी अथवा भुजाली से काट सकता था। पत्नी यह कहकर अपने प्रेमी की प्राण-रक्षा करा सकती थी कि यह पहला ही व्यक्ति नहीं था जिसके साथ उसने प्रेम किया था। प्रेमी भी अपने प्राणों की रक्षा करा सकता था यदि वह अपने को जाति-च्युत मान ले अथवा उस स्त्री के पति को आत्म-समर्पण कर दे।

वन-जातियाँ

मगरों में कुछ वन-जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें तीन चार स्त्रियाँ रखी जाती हैं। विदेश से लौटने पर लोगों को तीन रुपया प्रति व्यक्ति कर राणा सरकार को देना पड़ता था जिसे नेपाल में 'पानी पतिया' कहते थे जिसे न देने पर उन्हें जाति एवं अधिकारों से च्युत होना पड़ता था।

मुर्दे मरने पर फेंके नहीं जाते वरन् गाड़े जाते हैं। फौज में रहने वाले तो अपनी इच्छानुसार ही गाड़े जाते हैं या फेंके जाते हैं। मृत्यु के पश्चात् शव को कफन में लपेटकर कब्र में रख दिया जाता है और मिट्टी से ढककर ऊपर से एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है।

नेवारों में ब्राह्मण के बाद ठाकुर पूज्य माने जाते हैं। ठाकुरों में एक जाति 'शाह' की होती है। नेपाल के महाराजाधिराज श्री पाँच सरकार इसी जाति के होते हैं। शाही, मल्ल सेन स्थान इत्यादि ठाकुरों की उप-जातियों में यज्ञोपवीत पहिनना अनिवार्य होता है। नेपाल की अति प्राचीन जाति 'खस' है जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मिश्रित रक्त से उत्पन्न हुई एक वर्णसंकर जाति है जो पहले अपने को हिन्दू नहीं कहती थी।

नेवार और नेपाल शब्दों में क्या सम्बन्ध है यह विवादास्पद है। 'नेवार' शब्द 'नेपा' के अपभ्रंश 'नेवा' से बना हुआ मानकर इसी के आधार पर कुछ लोग नेवारी का अभिप्राय नेपाली से लगाते हैं। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि कर्नाटक के राजा हरिसिंह देव के साथी मुलगाव के 'नयार' में रहने वाले थे जो नेपाल में आकर बस गए तथा कालान्तर में 'नेवार' कहलाने लगे। नेवार जाति की जन्मभूमि काठमाण्डू भात-गाँव पाटन कीर्तिपुर नामकोट तथा थानाकोट है। धार्मिक दृष्टि से नेवार जाति शैव

मतावलम्बी हैं, कुछ बौद्ध भी हैं। यह व्यापार-कुशल कृषि-जीवी शिक्षा तथा कलानुरागी एवं मितभाषी होते हैं। इनकी भाषा 'नेवारी' है जो तिब्बती भाषा से बहुत-कुछ मेल खाती है। नेवार जाति की प्रत्येक कन्या का दो बार विवाह होता है बाल्यावस्था में कन्या नारायण से ब्याह दी जाती है। कतिपय नेवार जाति में विधवा-विवाह प्रचलित है और तलाक भी होता है।

लिम्बू जाति

लिम्बू जाति को 'याकथुम्बा' जाति भी कहते हैं। इसमें दस उपजातियाँ हैं जिनमें पाँच 'काशी गोत्र' और पाँच 'लासा गोत्र' की हैं। काशी गोत्र में पथर, हुकेरिया, फेबर, पॅगोबर और थोबिसा तथा लासा गोत्र में चरसामा, मियाखोला, मार्दखोला, फरप और तम्बरखोला हैं। इस जाति के लोग बौद्ध तथा हिन्दू धर्म दोनों के ही प्रतीकों को सामान्य रूप से पूजते हैं। इस जाति में प्रायः 'प्रेम विवाह' होता है। प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए नाना प्रकार के वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करते हैं। दोहा गा गा कर तथा कविता सुना-सुना कर एक दूसरे को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें नायिका रूप प्रेम ही आदर्श माना जाता है। जहाँ वर तथा वधू में पहले से कोई परिचय नहीं होता वहाँ वर वधू के पिता के पास अपने किसी निकट सम्बन्धी द्वारा एक मारा हुआ सूअर भेजता है और इस प्रथा को लिम्बू लोग 'फुरंग' कहते हैं। विवाह के समय वर एक भैंसा या सूअर मारकर और उसके मस्तक पर एक मोहर अथवा रुपया रखकर देता है। इसके पश्चात् वर और वधू एक दूसरे की हथेली पर हथेली रखकर खड़े हो जाते हैं और दूसरे हाथ में वर एक मुर्गा और वधू एक मुर्गी लिये रहते हैं जिन्हें बिजुआ (पुरोहित) ले लेता है और मंत्रोच्चारण के पश्चात् विवाह-संस्कार सम्पन्न हो जाता है। इसके बाद वर एक पक्षी को काटता है और उसका रक्त एक केले के पत्ते पर रोप लिया जाता है। दूसरे पत्ते पर सिन्दूर या लाल रंग रक्खा जाता है। तब वर इस रंग से अपनी उंगली रंगकर पुरोहित के ललाट पर लगाता है और बाद में वधू का स्पर्श करता है और यह कहकर कि "आज से तुम मेरी पत्नी हो" सिन्दूर उसकी भौं पर लगाकर मृत पक्षी को फेंक देता है। इसके पश्चात् लिम्बू लोग नाना प्रकार के नृत्य तथा मारुनी इत्यादि भी करते हैं। यह लोग शव को जमीन में गाड़कर सूतक भी मनाते हैं।

राई अथवा राय लोग अपने को लिम्बू मानते हैं। यह विष्णु तथा शिव की पूजा करते हैं। विवाह के पूर्व इनमें पूर्ण 'यौन स्वतन्त्रता' रहती है परन्तु जिससे गर्भ रह जाता है उससे अनिवार्यतः विवाह करना पड़ता है। इनमें विवाह की बातचीत वर-पक्ष की ओर से चलाई जाती है। वर किसी शुभ दिन कन्या के घर जाकर 'सियामपुगी' अथवा वधू का मूल्य चुकाता है और उसी रात्रि में विवाह हो जाता है। विवाह के समय वर वधू की माँग सिन्दूर से भरता है। पत्नी के व्यभिचारिणी हो जाने पर 'सियामपुगी' लेकर उसको तलाक भी दिया जा सकता है। इनमें विधवा-विवाह तथा पुनर्विवाह का भी चलन है। इनके

गृहदेवता मरमग पशुपति से तथा शिव देवता दुग्ध और दूर्वादल से प्रसन्न होते माने जाते हैं। यह लोग 'दव' का गाढ़ भी रखते हैं और फूक भी उचते हैं। कभी-कभी तो सब का 'जलप्रवाह' भी कर दिया जाता है।

'किरात' जाति का इतिहास महाभारत काल से प्रसिद्ध है परन्तु नेपाल के किरात नेपाल वालों से अधिक भिन्न दिखते हैं। यह लोग प्राय बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। इनके धर्म पर शैवमत का भी विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है और इसीलिए यह लोग वृक्ष शिला तथा भूत-प्रेत का पूजन करते हैं तथा मद्यमांस आहार करते हैं। नेपाल में किरातों को लोग बारहजोम्बा भी कहते हैं। किरातों में जाति-परिवर्तन बड़ी सुगमतापूर्वक हो जाता है।

अन्य जातियाँ

इनके अतिरिक्त गुरुंग, तकाले, पौड़ियाल, थेनी और मगी इत्यादि जातियाँ भी नेपाल में पाई जाती हैं। शिमुली और चमक प्रदेश में चेपाङ और कुसुण्डा जातियाँ रहती हैं। ये दक्षवार की जातियों की भाँति प्राय इधर-उधर घूमा करती हैं। काठमाण्डू के आसपास च्यामे सार्की सुनार दमाइ मालरी, कमाई मागरी कुमाले पोड़े पुनरा कसाई च्यामे की धूमी कसाले बाग्ली नाऊ तेली गर्ने छिपा सिकर्मी डकर्मी इत्यादि कर्मानुसार जातियाँ बनी हुई हैं।

मगर और गुरुंग जातियों की अपनी-अपनी बोलियाँ हैं। गुरुंग तातार जाति के हैं और इनमें 'चार जाति वाले' कुलीन माने जाते हैं तथा 'सोलह जाति वाले' साधारण माने जाते हैं। 'मगर' सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दोनों ही होते हैं। यह यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इनकी बुढ़ाथोकी घरती पुन राना और थापा उप-जातियाँ हैं। यह दासी जातियाँ साहसी और स्वामिभक्त होती हैं। 'मतवाला-धर्म' के लोग यज्ञोपवीत नहीं पहिनते। यह सम और मगर की स्त्रियों की सन्तान हैं। थारू जाति की बीसियों उप-जातियाँ हैं। भाषा में साथ मरती अवश्य हैं। थारू जाति में सम्बर्ध विवाह होता है। ये लोग चीर की लकड़ी का पानी में उबालकर घी में छौंक देते हैं और जौ के सत्तू के साथ मिलाकर खाते हैं। ये जाल अथवा शराब भी पीते हैं।

सुनवार और सुनमार जातियाँ सुनकोसी नदी के पूर्व तथा पश्चिम में बसी हैं। सुनवार की अग्र बैसा तथा लामा तीन उप-जातियाँ हैं। जेठा दस जातियों में विभक्त हैं जिन्हें 'दसथरे' कहते हैं। जेठा बौद्ध धर्मावलम्बी हैं। बैसा जातियाँ सुनकोसी नदी के पूर्वी तट पर फैली हुई हैं। ये अपने को हिन्दू मानती हैं परन्तु यज्ञोपवीत धारण नहीं करतीं। लामा जातियाँ दक्षिण-पूर्व में रहती हैं। इनके रीति-रिवाज गुरुंग मगर तथा राय जातियों से मिलते जुलते हैं।

मुरमी अपने को शिव की सन्तान मानते हैं। यह अब भी मरे बैलों का मांस भक्षण करते हैं। इनकी दो उपजातियाँ हैं। बारहमूल तथा अठारहमूल। अठारहमूल के लोग गोयल,

गन्धा तथा मंग्री कुलों में विभक्त हैं। वर्तमान बारह कुलों में तितर-बितर हो गई है। स्यार्पा जातियां गौरीशंकर की घाटी के समीप तक बसी है। स्यार्पा जाति सुमन्नू क्षेत्र में तथा लप्चा जाति सिक्किम और दार्जीलिंग प्रदेश के पश्चिम में भी फैली हुई है। स्यार्पा-स्त्रियां बहुत सुन्दर होती हैं किन्तु लप्चा जाति की स्त्रियां वैसी नहीं होती। माने जाति के लोग किरात प्रदेश के उत्तर में अधिक मिलते हैं। ये सब अनार्य बौद्ध मतावलम्बी हैं। यह लोग पहाड़ों में मूढ़ जाति वालों को रुपये देकर खरीद लेते हैं और जब तक वे रुपया चुका नहीं देते तब तक बंधक ही रखते हैं।

देवी-देवताओं में विश्वास

पहाड़ी लोग देवी-देवताओं में अधिक विश्वास करते हैं। और जब कोई रोग अच्छा नहीं होता तब सामेती कराते हैं और देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्धन की लड़की खरीदकर मंदिर में अर्पण कर देते हैं और वह 'देववेसी' (देवदासी) कहलाने लगती है। युवावस्था प्राप्त होने पर उसे विवश होकर वेश्या-वृत्ति धारण करनी पड़ती है, जिससे पर्वतों में नाना प्रकार के भयंकर रोग फैलते रहते हैं।

नेपाल की तराई अथवा मधेश में प्रायः हिन्दू ही पाये जाते हैं। ये सनातन धर्मावलम्बी हैं। नेपाल में इन्हें 'मधेसिया' कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आकर अरसे से नेपाल में बस गये हैं। इनकी बोली भी वही है जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पास वाले बोलते हैं। नेपाल में मधेसियों और भारतीयों की संख्या पचास लाख से भी अधिक है।

तराई में एक थारू जाति भी बसती है। 'थारू' शब्द 'स्थविर' का अपभ्रंश है। इस जाति के लोग कृषि करते हैं। ये कभी बौद्ध भले ही रहे हों परन्तु अब तो ये अपने को हिन्दू ही कहते हैं। इनका प्रत्येक कार्य पंचायतों द्वारा होता है। थारू जादू-टोने और भूत प्रेत में बहुत विश्वास करते हैं।

नेपाल के थारू खेती को छोड़कर कोई दूसरा पेशा पसन्द नहीं करते। यह जाति भारत में भी पायी जाती है। कुछ लोग थारू शब्द 'थर' अथवा 'थार' से बना हुआ अनुमान लगाते हैं। थेर उस भूमि को कहते हैं जो पहाड़ और समतल के बीच में पड़ता है। थर में बसे होने के कारण 'थारू' कहलाने लगे।

थारू जाति में डागवार, कम्मुच्छा, कठरिया, राना, दंगवरिया तथा रउतार आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। डागवार यज्ञोपवीत धारण करते हैं और पुनर्विवाह नहीं करते किन्तु कठरिया यज्ञोपवीत और पुनर्विवाह दोनों नहीं करते। कम्मुच्छा सभ्य जाति मानी जाती है। राना जंगली जाति है जो अपने को महाराणा प्रताप की संतान मानती है।

पछवाली दंगवरिया मारंगिया चितवनिया तथा कोचनपुरिया आदि जातियां क्षेत्र विशेष में बसने के कारण कहलाने लगी हैं।

एक प्राचीन देश

नेपाल एक अत्यन्त प्राचीन देश है। इसका इतिहास भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेपाली वंशावली में सतयुग के उस प्राचीन काल का इतिहास मिलता है जबकि नेपाल की घाटी का जन्म तक नहीं हुआ था और वह एक बड़ी झील थी। इस वंशावली के प्रारम्भ में सतयुग तथा त्रेतायुग का वर्णन है और अनेक आख्यायिकाएं दी गई हैं जिनमें बहुत से तीर्थ स्थानों आदि के नाम गिनाये गये हैं। इस वृहद् ग्रन्थ में सतयुग, त्रेता तथा द्वापर युग के नरेशों आदि का वर्णन लाखों वर्षों तक बताया गया है। संस्कृत तथा बौद्ध साहित्य, ताम्रपत्र, शिलालेख, पत्र तथा लेखक सिलवन लेवी, किर्कपैट्रिक, राइट इत्यादि द्वारा नेपाल के प्राचीन इतिहास की पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है।

'नेपाल' शब्द का प्राचीन इतिहास महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन भाषाओं के वैज्ञानिकों ने भी 'नेपाल' शब्द के सम्बन्ध में खोज की है।

हिमालय पर्वत के ऊपरी भागों के अन्तर्गत हिमालय की तराई के पहाड़ी भूभाग को अपनी भाषा में 'पालदेश' कहते हैं। 'पाल' शब्द तिब्बती भाषा में पश्मीना (ऊन) का पर्याय है। नेपाल में ऊन बहुत मिलती है इसलिए तिब्बत वालों ने नेपाल को 'पालदेश' कहा। सिक्किम तथा नेपाल के पूर्वी भाग के लोग पवित्र गुफाओं तथा देवताओं के तीर्थ स्थानों को 'ने' कहते हैं। 'ने' शब्द का अर्थ मोट प्रदेश के लामाओं की भाषा में पवित्र गुफा और देवता का वासस्थान होता है। नेपाल में असंख्य बौद्ध तथा हिन्दू मूर्तियाँ पाई जाती हैं इसलिए इस प्रदेश का नाम 'नेपाल' पड़ गया। प्राचीन काल की आख्यायिकाओं के आधार पर कहा जाता है कि 'ने' नाम के प्रख्यात मुनि बागमती और विष्णुमती नदियों के संगम पर तपस्या करते थे और 'ने' मुनि का ही आशीर्वाद लेकर तत्कालीन राजाओं ने शासन-व्यवस्था की और प्रजा का पालन किया। महर्षि 'ने' मुनि की आज्ञा द्वारा पालित देश का नाम 'नेपाल' पड़ गया। महर्षि 'ने' की कथा पार्वतीय वंशावलियों में मिलती है। स्कन्धपुराण, देवीपुराण, बृहन्नीलतन्त्र, वाराहितन्त्र की आख्यायिकाओं में भी 'नेपाल' का वर्णन आता है। स्कन्धपुराण के हिमवत् खण्ड में नेपाल का विशद वर्णन है। उपर्युक्त पौराणिक ग्रन्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नेपाल ही में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था।

प्रारम्भिक इतिहास

नेपाल का प्रारम्भिक इतिहास बौद्ध साहित्य तथा स्वयम्भू पुराण में मिलता है। पर कथा रूप ही मालूम है। कैप्टन मारिसन ने भी अपनी अपनी पुस्तक 'गोरखा' में

लिखा है कि बौद्धमार्गी मंजुश्री तथा सनातन धर्मावलम्बी विष्णु ने 'नागह्रद' के जल को पहाड़ काटकर बाहर निकाला और मनुष्यों के रहने के लिए सुन्दर प्रदेश बनाया। इसलिए नेपाल का नाम प्राचीन काल में 'नागह्रद' था। सतयुग में विपश्वि नाम के प्रथम बुद्ध ने नागह्रद में आगमन किया और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन नागह्रद के मध्य में एक कमल का बीज लगाया। उस कमल से आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन एक पुष्पित पूर्ण कमल खिला जिसके मध्य में बौद्ध-मार्गी मत के मानने वालों के लिए स्वयंभूनाथ और शिवमार्गी मत के मानने वालों के लिए पशुपतिनाथ की ज्योतिर्मयी मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात् द्वितीय बुद्ध भगवान् की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन करने के लिए ध्यानोचगिरि में आसन शिखिनाम धारण कर अवतरित हुए।

इसके पश्चात् त्रेतायुग में विश्वभू नाम के तृतीय बुद्ध ने अपनी शिष्यमण्डली सहित फुल्लोचगिरि में आकर एक लक्ष पुष्पों द्वारा ज्योतिर्मय भगवान् की पूजा की और नागह्रद का पवित्र जल बाहर निकालने का प्रयास किया। उसी समय चीन देश के मंजुश्री भी वाशिमतल में ज्योतिस्वरूप भगवान की आराधना करने के निमित्त महाचीनपर्वत से नगरकोट (महामण्डप गिरि) में बसकर तीन रात अनिमेष दृष्टि रखकर ज्योतिस्वरूप भगवान् का स्तवन किया। मंजुश्री ने 'वरदा' और 'मोक्षदा' नाम की शक्तियों की अनुकम्पा प्राप्त करके नागह्रद के रुके हुए जल को बाहर निकालकर उसे मनुष्यों के रहने योग्य बनाया। मंजुश्री ने महामण्डपगिरि की शृंखला की तलहटी फुल्लोच (फूलचोक) और ध्यानोच में 'वरदा' और 'मोक्षदा' को स्थापित किया। उसी शृंखला के मध्य को काटकर नागह्रद का जल बाहर बहने लगा और इसीलिए उस स्थान का नाम कटुवाल दह पड़ गया। आजकल यह स्थान तीर्थ कहलाता है। नागह्रद का जब सब जल बाहर निकल गया तब मंजुश्री ने पदम शाम्यगिरि में श्री गुह्येश्वरी के बीजमन्त्र की स्थापना की। मंजुश्री ने उस गिरि में मंजुपत्तन नाम का ग्राम बसाकर अपने शिष्यों को वहीं बसने के लिए आदेश दिया और वे कालान्तर में अपने शिष्य धर्माकर को उस ग्राम का राज्याधिकार सौंपकर स्वयं चीन चले गए।

इसके पश्चात् मंजुपत्तन में क्रकुच्छन्द नाम के चतुर्थ बुद्ध अवतरित हुए और नेपाल में जल का अभाव देखकर भगवती गङ्गा देवी की प्रार्थना करने लगे। उन्हीं की प्रार्थना से प्रभावित होकर स्वयं गुह्येश्वरी माता शिवपुरी पर्वत के ऊपर से वाग्मती नदी के रूप में प्रकट हुईं। क्रकुच्छन्द ने धर्माकर राजा का शिष्यत्व पाकर उसकी मृत्यु के पश्चात् धर्मपाल नामक शिष्य को मंजुपत्तन का राजा बनाया। इसी धर्मपाल के वंश का राजा सुधन्वा मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम का समकालीन था। राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नाम का नगर बसाया और बाद में उसी को अपनी राजधानी बनाया। यही सुधन्वा जनकनन्दिनी सीता जी के स्वयम्बर में जनकपुर गया था और वहां महाराजा विदेह के भ्राता कुशध्वज द्वारा मारा गया था जिसके फलस्वरूप सांकाश्य नगर राजा कुशध्वज के हाथ में चला गया। राजा कुशध्वज का वंश सहस्रों वर्षों तक सांकाश्य नगर में राज्य करता रहा।

द्वापर युग के मध्य में काश्यप नाम के पंचम बुद्ध ने आकर ज्योतिर्मूर्ति और गुह्येश्वरी के दर्शन करने के पश्चात् गौड देश की राह ली और गौड देश के तत्कालीन राजा प्रचण्डदेव से ज्योतिर्मूर्ति तथा गुह्येश्वरी देवी का माहात्म्य वर्णन किया। इससे प्रभावित होकर राजा प्रचण्ड देव नेपाल आए और उन्होंने महात्मा गुणाकर को अपना दीक्षा गुरु बनाया। यही शान्तिश्री के नाम से प्रसिद्ध हुए।

इसके पश्चात् ही कलियुग का कुप्रभाव चारों ओर फैल गया और कलियुग के मनुष्य प्रत्यक्ष दर्शन को सह सकने में असमर्थ हो गये। इसलिए ज्योतिर्मूर्ति को ढक करके स्थान स्थान पर चैत्यों का निर्माण हुआ। राजा कुशध्वज के निर्वंश हो जाने पर शान्तिश्री ने गौड राज्य के एक पुरुष को नेपाल का राज्य-शासन दिया। इसी गौड राजवंश के अन्तिम राजा सिंहदेव परमयोगी सिद्ध हुए। राजा सिंहदेव के शासन-काल में नेपाल का वाणिज्य तथा व्यापार सिंहल द्वीप तक फैल गया था। इस राजा ने अपने अन्तिम काल में सिद्ध समाधि ले ली थी और इसी की स्मृति में भाक्तपुर ठवहिल नामक स्थान में प्रतिवर्ष मेला हुआ करती है। राजा सिंहदेव का दूसरा नाम राजा सिंहल भी पड़ गया था और उसी के राज्यकाल में नेपाल में एकबार भयंकर भूचाल आया था जिसके फलस्वरूप अनेक देवस्थल तथा भवनों का विध्वंस हो गया और शान्तिश्री तथा गौडेश्वर प्रचण्डदेव जी भी चैत्य के साथ ही ध्वस्त हो गये।

इसके अधिक कालोपरान्त नेपाल में महर्षि 'ने' नाम के मुनि प्रकट हुए। उस समय श्रीमद् पुरुषोत्तम भगवान् कृष्ण के साथ आये हुए ग्वालवंशियों की संख्या अधिक थी। ग्वालवंश में 'ने' नाम की एक कुमारी गऊ थी जो प्रतिदिन निर्धारित समय पर जंगल में घास चरने जाया करती थी और एक एकान्त स्थान पर पहुँचते ही उसके स्तनों से सहसा दूध की धार निकलने लगती थी। एक दिन ग्वाले ने उस गाय का पीछा किया और यह जानने की चेष्टा की कि गाय कुमारी है परन्तु क्या कारण है कि हम लोगों को दूध नहीं देती। चरवाहे ने जब यह देखा कि अमुक स्थान पर पैर रखते ही उसके स्तनों से दूध की धार निकल पड़ी है तो उसने दुग्ध-प्लावित उस स्थान की मिट्टी हटानी प्रारम्भ की। ज्योंही उस ग्वाले ने थोड़ी सी मिट्टी हटाई कि भगवान् ज्योतिर्मूर्ति प्रकट हो गये। यह पार्वतीश्वर पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग था। इस समाचार को सुनते ही 'ने' मुनि ने उन पशुपतिनाथ ज्योतिर्मूर्ति के दर्शन किये और ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते ही गोपाल मुखिया भस्म हो गया और उसका पुत्र भुक्तमान गुप्त नेपाल का शासक बनाया गया।

गोपाल वंश

इस प्रकार नेपाल की राज्यलक्ष्मी ने प्रथम गोपालवंश ही में वरमाला पहनायी। गोपालवंशीय प्रथम राजा ने ८८ वर्ष तक राज्य किया। इन्हीं के राज्यकाल में श्री पशुपति

नाथ के प्रादुर्भाव तथा देवल का निर्माण हुआ। इसका पुत्र जयगुप्त ७२ वर्ष तक तथा क्रमशः परमगुप्त ८० वर्ष भीमगुप्त ९३ वर्ष मणिगुप्त ३६ वर्ष विष्णुगुप्त ४२ वर्ष यक्षगुप्त ७१ वर्षों तक राज्य करते रहे। सबको मिलाकर आठ पुश्तों तक ५२१ वर्ष गोपालवंशीय राजाओं ने राज्य किया। गोपालवंशीय राजाओं का निवास-स्थान कीर्तिपुर के दक्षिण में मातातीर्थ नामक स्थान के पास था। गोपाल वंश के अन्तिम राजा यक्षगुप्त निवंशी थे इसलिए उन्होंने अपने अन्तिम काल में भारतवर्ष आकर वरसिंह नामक एक अहीर वंशी व्यक्ति को राज्याधिकार दे दिया।

अहीर वंश

वरसिंह के पीछे क्रमशः उनके पुत्र जयमतिसिंह और उनका पुत्र भुवनसिंह राजा बने। इसी काल में किरातों के सरदार यलम्बर ने पूर्व की ओर से नेपाल पर आक्रमण किया। इस संग्राम में भुवनसिंह मारे गये और किरातवंशीय राजाओं के हाथ में राज्य की बागडोर चली गई।

किरात वंश

किरात वंश के प्रथम राजा यलम्बर द्वापर युग के अन्त तथा कलियुग के प्रारम्भ में थे। इस वंश का राज्य २९ पुश्तों तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। यलम्बर की मृत्यु के पश्चात् पवि, स्कन्धर, बलम्ब, हृति तथा हुमती के राज्यकाल में पाण्डव लोग वनवास आये और अर्जुन तथा शिवरूपी किरात के साथ युद्ध हुआ और पाशुपतास्त्र भी प्राप्त हुए। इनके सातवें राजा जितेदस्ती महाभारत के कौरव-पाण्डव युद्ध में सम्मिलित हुए थे और इसमें उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखलाया था। इन्होंने अपनी युवावस्था ही में अश्वमेध यज्ञ किया। इनके पश्चात् माल्गे और नव राज यसो और पुष्कर के राज्यकाल में शाक्यसिंह बुद्ध नेपाल में पधारे।

इनके बाद पर्भमा, पर्व, थुंक, स्वनन्द तथा थुंको आदि ने शासन किया। इसी समय में सम्राट् अशोक नेपाल आये और उन्होंने ललितपत्तन में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। सम्राट् अशोक ने एक स्तूप पत्तन में और दूसरा कीर्तिपुर में बनवाया। सम्राट् अशोक के डर से स्थुङ्क के पीछे किरातवंशीय राजाओं ने गोकर्ण के जंगल में एक दुर्भेद्य दरबार में छिपकर शरण ली। सम्राट् अशोक की पुत्री चारुमती ने चाबेल नगर बसाया। इसके पश्चात् नाने, लोक, थोका, वर्मा, गुज, पुष्क, त्यसु, सुग, संस, गणन, तिग्मु तथा पटुक आदि ने राज्य किया। इनके शासनकाल में सोमवंशीय राजपूतों ने पश्चिम की ओर से आक्रमण किया और किरातवंशीय राजाओं को मातातीर्थ छोड़कर शंखमूल तीर्थ के समीप एक दूसरा दरबार बनाकर शरण लेनी पड़ी। किरात वंश के उन्तीसवें राजा गस्ती अन्तिम राजा हुए। यह सोमवंशीय राजा निमिष द्वारा पराजित हुए और इन्हें भागना पड़ा। इस प्रकार ५२९

वर्षों के पश्चात् किरातवंशीय राजाओं के हाथ से नेपाल का राज्याधिकार सोमवंशीय क्षत्रियों के हाथ में चला गया।

सोमवंशीय राजा

राजा निमिष ने राज्याधिकार प्राप्त करके पुष्पनाथ पर्वत में गोदावरी तीर्थ के सन्निकट अपना दरबार बनवाया। राजा निमिष के पश्चात् क्रमश: मताक्षर, काकवर्मा तथा पशुप्रेक्षदेव नेपाल के राजा हुए। राजा पशुप्रेक्षदेव ने कलि के १२२४ वर्ष में श्री पशुपतिनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार किया और चारों वर्णों के हिन्दुओं को बसाया। इसके पश्चात् भास्कर वर्मा राजा हुए। इसकी विशाल सैन्यवाहिनी सेना देश-विदेश विजय करके सेतुबन्ध रामेश्वर तक पहुंची। इन्होंने देवपाटन का नाम स्वर्णपुरी रखा। भास्कर वर्मा सोमवंशीय राजाओं में पांचवें और अन्तिम राजा हुए। यह नि:सन्तान थे इसलिए इन्होंने शाक्यसिंह बुद्ध के साथ आए हुए गौतम गोत्रोत्पन्न सूर्यवंशी लिच्छवी क्षत्री भूमिवर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार सोमवंशीय क्षत्रियों के बाद लिच्छवी वंश के क्षत्रियों के हाथ में राज्याधिकार चला गया।

लिच्छवी वंश

नेपाल में प्राप्त अशोक-लिपि द्वारा यह पता चलता है कि शाक्यवंशीय राजा काफी समय तक राज्य करते रहे। वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण में शाक्यवंशीय राजाओं की नामावलि मिलती है। इस प्रकार यह अनुमान किया जाता है कि शाक्यसिंह भगवान बुद्ध के बाद पांच-सात राजाओं ने राज्य किया। भास्कर वर्मा के पश्चात् वैशाली से आये हुए लिच्छवी वंश का प्रादुर्भाव हुआ। पत्ना के गुप्त सम्राट् द्वारा पराजित होकर प्रसिद्ध लिच्छवी सरदार सुपुष्प नेपाल की तराई में आ बसे। लिच्छवी शासकों में से वर्षदेव मानदेव रानी राज्यवती महिदेव शिवदेव नरेन्द्रदेव भीमदेव अंशुवर्मन आदि शासकों के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रभाकरवर्धन लिच्छवी वंश में सबसे महान् प्रतापी राजा हुए। कौमुदी महोत्सव से स्पष्ट होता है कि गुप्तों को प्राप्त हुआ था। लिच्छवियों ने ही नेपाल में गणतन्त्र की परम्परा तोड़कर विशुद्ध राजतन्त्र स्थापित किया था जिसका प्रभाव आज भी नेपाल के राजनीतिक वायुमण्डल पर परिलक्षित होता है।

गणतन्त्र में शासन एक राष्ट्रपति द्वारा हुआ करता था। उस गणतन्त्र की प्रशंसा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी की है। अंशुवर्मन गणतन्त्र के ही प्रचारक थे जो बाद में 'ठाकुरी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके उत्तराधिकारी जिष्णुगुप्त गणतन्त्र को नष्ट करके पुन: राजतन्त्र स्थापित करना चाहते थे किन्तु तिब्बत तथा चीनवाले उदयदेव को राज्य दिलाना चाहते थे। इसलिए दोनों देशों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप उदयदेव को राज्य मिल गया किन्तु नेपाल पच्चीस वर्ष के लिए परतन्त्र हो गया। इस

राज्यकाल में नेपाल, तिब्बत तथा चीन का सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ। चाइ इतिहासकारों के अनुसार चीन का एक शिष्टमंडल राजा हर्षवर्धन से मिला था। इस प्रकार अर्जुन द्वारा तिब्बत की विजय के पश्चात् स्थापित लिच्छवी शासन समाप्त हो गया। काश्मीरी कवि कल्हण की 'राजतरंगिणी' से यह सिद्ध होता है कि लिच्छवियों ने नेपाल को अच्छी तरह संगठित करके काश्मीर पर भी आक्रमण किया था और वहाँ के राजा जयपीड को पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया था।

वैशाली गणतन्त्र राज्य मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान बसाढ़ में था। वैशालियों के पतन के बाद लिच्छवी राजपुत्र सुपुष्प ने पुष्पपुर में अपना वास-स्थान बनाया। इसके पश्चात् तईस पुश्तों तक राजाओं का नाम शिलालेखों में नहीं मिलता। चौबीसवीं पुश्त में राजपुत्र जयदेव ने मानगृह में लिच्छवी वंश का राज्य स्थापित किया। राजा जयदेव के पीछे बारह राजाओं का नाम भी शिलालेखों में नहीं मिलता। चौदहवें लिच्छवी राजा वृषदेव बहुत ही प्रतापी निकले। राजा वृषदेव ने गुप्त संवत्-प्रवर्तक सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सहायता करने के लिए नेपाली सेना सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस के विरुद्ध भेजी। इसी नाते सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य नेपाल भी गये। राजा वृषदेव ने अपनी पुत्री कुमारदेवी का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। राजा वृषदेव ने नेपाली सिक्के में अपने नाम के साथ लिच्छवी शब्द भी अंकित करवाया। कुमारदेवी के गर्भ से शक विजेता सम्राट् समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। शक युद्ध में नेपाली सेना ने विशेष पराक्रम का परिचय दिया। राजा वृषदेव के समय में वैश्य ठकुरी वंश के पराक्रमी योद्धा अंशुवर्मा हुए।

गुप्त संवत् ९५ सन् ५५४ में अंशुवर्मा के पद में वृद्धि हुई। पन्द्रहवें महाराज शिवदेव द्वारा वैसाशकट सचिव राज्य का शासनाधिकार ताम्रपत्र द्वारा अंशुवर्मा को दिया गया। इसी समय से अंशुवर्मा को महासामन्त की पदवी मिली। अंशुवर्मा बहुत ही प्रतापी निकले। उन्होंने नेपाल राज्य की बहुत उन्नति की। लिच्छवी राज सनातन हिन्दू धर्म तथा बौद्ध मतावलम्बियों दोनों को समान ही दृष्टि से देखते थे। महासामन्त अंशुवर्मा दोनों धर्मों के प्रति बराबर भक्ति रखते थे। राजा भुवदेव और राजा भकदेव के बाद मानदेव अठारहवें राजा हुए। राजा मानदेव बहुत ही पराक्रमी थे। इन्हीं के राज्यकाल में महासामन्त अंशुवर्मा के वंश के ठकुरी राजाओं ने लिच्छवी शरण की आधीनता त्यागकर स्वतन्त्र होना चाहा परन्तु पराक्रमी राजा मानदेव ने ठकुरियों का मान-मर्दन कर दिया। इसी समय में भक्त जयवर्मा ने पशुपतिनाथ के मंदिर में जलशयन नाम की शिव मूर्ति की स्थापना की परन्तु थोड़े ही दिनों के बाद यह मूर्ति नष्ट हो गई। इसलिए राजा मानदेव के पिता राजा शंकरदेव ने वहाँ एक चौदह हाथ का त्रिशूल स्थापित किया। लिच्छवी राजा मानदेव ने नाना चैत्य और एक विहार बनवाया। इसके बाद राजा मानदेव राजा महीदेव तथा राजा वसन्तदेव शासक हुए। वसन्तदेव ने नेपाल में वनमोचिनदवार की

प्रधानता और पूजन का प्रचलन किया । इनका प्रभाव ऐसा बढ़ा कि अवलोकितेश्वर (मत्स्येन्द्रनाथ) नेपाल के अधिष्ठाता देवता मान लिये गये । जयदेव द्वितीय के शिलालेख में तईसवें राजा उदयदेव और चौबीसवें राजा नरेन्द्रदेव के पराक्रम की प्रशंसा की गई है।

कान्यकुब्ज राजा हर्षवर्धन की प्रबल अभिलाषा थी कि वह नेपाल को विजय करके अपने राज्य में मिला लें किन्तु वह ऐसा कर नहीं सके । इसी समय चीनी यात्री ह्वानसांग नेपाल आये । ह्वानसांग ने नेपाल-यात्रा का वर्णन बहुत ही मर्मस्पर्शी शब्दों में किया है। उन्होंने लिखा है कि नेपाल पर्वतमाला से आवृत है और नेपाल के निवासी (बौद्ध) तथा अविश्वासी (सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी) एक ही साथ प्रेमपूर्वक बिना किसी धार्मिक मतभेद के रहते हैं । उन्होंने यह भी लिखा है कि नेपाल हिमाच्छादित एक बहुत ही पवित्र देश है जहां का लिच्छवी राजा सुन्दर, आचरणवान तथा उदार और विद्वान् है । उसके राज्य में महायान और हीनयान दोनों मतावलम्बी पाये जाते हैं । पच्चीसवें राजा शिवदेव द्वितीय ने अपना विवाह मगध-सम्राट् आदित्यसेन की पौत्री वत्सादेवी से किया । छब्बीसवें राजा जयदेव द्वितीय ने अपना विवाह कलिंग और कौशल के राजा हर्षदेव की पुत्री राज्यमति से किया । पर्वती 'वंशावली' से स्पष्ट होता है कि राजा शंकरदेव से चौथे पीढ़ी में उत्पन्न जयदेव मुक्तकाम ने सन् ७१३ ई०में काठमाण्डू नगर बसाया। राजा जयदेव मुक्तकाम संतान-हीन होकर मरे । इसलिए मुक्ताकोट के महासामन्तों ने अपने कुल में श्रेष्ठ श्रीभास्कर वर्मा को राजा बनाया । श्रीभास्कर वर्मा के पश्चात् क्रमशः बालदेव पद्मदेव नागार्जुन देव तथा शंकरदेव चार राजा हुए । शंकरदेव बहुत ही कट्टर धर्मप्रिय थे इसलिए उन्होंने पाटन में एक सुन्दर मठकुण्ड बनवाया । यह काल धार्मिक दृष्टि से नेपाल के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में शंकराचार्य का धर्म-प्रचार व्यापकता के साथ हो रहा था । सनातन हिन्दू धर्म के इस प्रचार को देखकर विशालनगर के बौद्ध मतावलम्बियों ने भाल सौ ब्राह्मणों को आग में भूनकर मार डाला जिसके फलस्वरूप इन ब्राह्मणों की स्त्रियां भी सती होगईं और इसी पाप के कारण बौद्धों का भी क्षय हो गया। इसमें भाग के राहियों का भी शाप का भागी होना पड़ा । इसकी शांति के निमित्त राजा शंकरदेव ने शांतेश्वर महादेव की स्थापना की । इसके बाद राजपुत्र वामदेव ने पाटन और कान्तिपुर के सरदार बाघा की सहायता से नेपाल में अपना राज्य स्थापित किया।

सूर्यवंशी राजा

वामदेव के सूर्यवंश ने कई पुश्त तक नेपाल में राज्य किया । हर्षदेव और सदाशिव ने सन् १८५१ में पशुपतिनाथ के मन्दिर का छत्र बनवाया । इसी समय कीर्तिपुर ग्राम भी बसाया गया । नेपाल में इसी ने पहले-पहल 'मुनिद' नामक मुद्रा का प्रचलन किया जिसमें श्रीनाम ताम्बा इत्यादि धातुओं का सम्मिश्रण था । इस वंश के राजागण देव नरसिंहदेव नन्ददेव रुद्रदेव मित्रदेव अरिदेव इत्यादि सभी मल्लयुद्ध के विशेष प्रेमी थे । एक समय

अरिदेव जब मल्लयुद्ध से लौट रहे थे तभी उनको पुत्र-जन्म की शुभ सूचना दी गई। इसी नाते अरिदेव के पश्चात् जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए सब अपने अपने नामों के अन्त में 'मल्ल' शब्द लिखने लगे। अभय मल्ल और जयदेव मल्ल इनके बाद शासक हुए। जयदेव मल्ल ने अपने भ्राता आनन्द मल्ल को भातगाँव का राज्य दिया। राजा आनन्द मल्ल की आज्ञा लेकर सांखवाल नामक एक शूद्र वणिक ने नेपाली संवत् चलाया। नेपाली संवत् तदनुसार सन् ८८० ई० से प्रारम्भ होता है।

कर्णाट वंश

कर्णाट देश के पराक्रमी राजा नान्यदेव ने नायरा स्थानवासी क्षत्रिय जातियों के सहित एक विशाल सेना लेकर नेपाल पर आक्रमण किया और जय मल्ल तथा आनन्द मल्ल को तिरहुत भगाकर स्वयं भक्तपुर को अपनी राजधानी बनाया। यही नायर लोग नेवार कहलाने लगे।

नान्यदेव के पश्चात् क्रमशः गंगदेव नरसिंहदेव शक्तिदेव रामसिंहदेव तथा हरिसिंह कर्णाटवंशी राजे नेपाल में शासन करते रहे। राजा गंगदेव और नरसिंह देव ने चम्पापुरी नाम का गाँव बसाया। हरिदेव इस वंश के अन्तिम राजा थे। इनके शासनकाल में नेपाल में प्रजा का विद्रोह हुआ और एक विकल विद्रोही नगर ने पाल्पा के तत्कालीन राजा मुकुन्दसेन को नेपाल पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। फलतः सन् १ ९८ ई० खस और मगर सेना को लेकर राजा मुकुन्दसेन ने भीषण रूप से आक्रमण किया। इस युद्ध में राजा मुकुन्दसेन की विजय हुई और उनकी सेना ने नेपाल की अनेक देवमूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया और लूट-पाट भी बहुत की। विजयोपरान्त राजा मुकुन्दसेन ने मत्स्येन्द्रनाथ के सामने की विशाल मूर्ति पाल्पा भेज दी। नेपाल-विजय से राजा मुकुन्दसेन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और इसी वर्ष में उन्होंने मत्स्येन्द्रनाथ की भव्य-विशाल मूर्ति को एक स्वर्ण-हार पहनाया। राजा मुकुन्दसेन ने खस और मगर सैनिकों का विशेष प्रोत्साहन किया और तभी से खस और मगर जातियाँ नेपाल में विस्तृत रूप से फैलती गईं। राजा मुकुन्दसेन की शानदार विजय तो हुई परन्तु ज्योंही उन्होंने राज्याधिकार अपने हाथों में लिया वैसे ही पाल्पा में विकराल महामारी का रोग फैल गया जिससे विकल होकर राजा मुकुन्दसेन को सन्यासी वेश धारण करके नुवाकोट की ओर भाग जाना पड़ा। इतना ही नहीं अपितु इसी महामारी से पाल्पा की समस्त सेना का नाश हो गया। राजा मुकुन्दसेन की मृत्यु नुवाकोट में देवीघाट पर हुई।

वैस्य ठकुरी वंश

इसके पश्चात् आठ वर्ष तक राजगद्दी खाली रही। तत्पश्चात् वैस्य ठकुरी वंश के अनेक राजाओं ने राज्य किया। इस काल में कान्तिपुर में बारह राज पाटन के एक मुहल्ले में एक-एक राजा और भक्तपुर में तीन राजाओं ने राज्य किया। इन्हीं राजाओं की पीढ़ियाँ दो सौ पच्चीस वर्षों तक नेपाल में राज्य करती रहीं।

३

मुसलमानों का आक्रमण

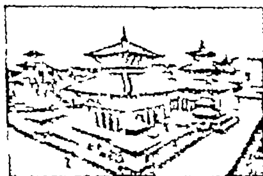
ग्यारहवीं शताब्दी में भारत में यवनों के आक्रमण होने लगे और यवनों की बढ़ती हुई शक्ति देखकर भारतीय आर्य राजा अत्यधिक विकल हो उठे। सन् १३१२ ई॰ में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिसिंह देव ने महम्मद तुगलक के आक्रमण से आक्रान्त होकर अपने मन्त्री कुटुम्ब और धन-सम्पत्ति सहित उत्तरी भारत में मिथिला प्रदेश आकर सिमरौन गढ़ को अपनी राजधानी बनाया परन्तु सन् १३२४ ई॰ में दिल्ली के बादशाह मुहम्मद तुगलक ने सिमरौन गढ़ पर भी धावा बोल दिया। इस आपत्तिकाल में भगवती तुलजाभवानी ने राजा हरिसिंह देव को स्वप्न दिखाया कि तुम तुरन्त नेपाल की ओर भाग जाओ। दैवी स्वप्न में विश्वास करके राजा ने पौष मास में नेपाल की राह ली और इसी मास के अन्त तक वह भादगाँव पहुँच गए। इस समय वहाँ ठकुरियों का शासन लड़खड़ा रहा था। इसलिए प्रजा ने राजा हरिसिंह देव का हृदय से स्वागत किया और उन्हें नेपाल का राजा स्वीकार कर लिया। नेपाल राज्य प्राप्त करके राजा हरिसिंह ने मूलचोक में तुलजाभवानी बीजमन्त्र की प्रतिष्ठा की। सन् १३१७ ई॰ में तुगलक बादशाह ने अपने बहलोई मलिक सुमरू की देख रेख में एक लाख घुड़सवार सैनिकों की एक सुसज्जित सेना चीन के रास्ते से नेपाल पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मुगल सेना को इस आक्रमण में सफलता मिली और मुगलों ने नेपाल की मूर्तियों तथा मंदिरों को विशेष रूप से ध्वस्त किया। काठमाण्डू के एक शिलालेख से सिद्ध होता है कि मुगलों ने काठमाण्डू को बुरी तरह ध्वस्त किया था और भगवान् पशुपतिनाथ की मूर्ति को भी तोड़ा था। यवनों ने चीन के सम्राट् को भी पछाड़ना चाहा था किन्तु चीनियों ने इसका कठोर प्रतिरोध किया। मुगलों के दिल्ली भाग जाने के बाद राजा हरिसिंहदेव ने नेपाल का पुनर्निर्माण किया और वह अट्ठाईस वर्षों तक राज्य करते रहे। इसके बाद मोतीसिंह राजा हुए। सन् १३८४ ई॰ में चीन के सम्राट् हैम उ ने राजा मोतीसिंह के पास अपनी मुद्रा के साथ अपना राजदूत भेजा और राजा मोतीसिंह को नेपाल का राजा माना। इस पर राजा मोतीसिंह ने प्रत्युत्तर में एक स्वर्ण-मूर्ति तथा धार्मिक पुस्तकें चीन भेजीं। राजा शक्तिसिंह ने बनेपा को अपनी राजधानी बनाया और बारह वर्ष तक नेपाल का शासन किया। इस काल में चीनी संवत् ५१५ में नेपाल और चीन में प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान होता रहा। चीन की 'भवना' से सिद्ध होता है कि राजा हरिसिंह के वंश के अन्तिम राजा श्यामसिंह सन् १३८७ ई॰ से १४१८ ई॰ तक नेपाल राज्य की बागडोर संभाले हुए थे। इसी समय काठमाण्डू और पाटन में अपरिग्रमनस्य भी थे। राजा श्यामसिंह के शासन-काल में नेपाल संवत् ५२ माघ सुदी द्वादशी के दिन नेपाल में महाभूकम्प आया था।

मल्ल वंश

राजा अभय मल्ल नान्यदेव द्वारा पराजित होकर तिरहुत की ओर भाग गये थे लेकिन उनके पुत्र जयभद्र मल्ल बहुत ही भाग्यवान् थे। सूर्यवंशी राजा श्यामसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जयभद्र मल्ल से किया और उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस सम्बन्ध से नेपाल में फिर मल्लवंश का राज्य स्थापित हो गया। नेपाली संवत् ५२९ में जयभद्र मल्ल ने नेपाल के ध्वस्त मंदिर इत्यादि का जीर्णोद्धार किया। जयभद्र मल्ल ने पन्द्रह वर्षों तक बहुत ही दूरदर्शितापूर्वक नेपाल में राज्य किया। उनका वंश नेपाली संवत् ५२९ से ८८८ तक नेपाल को सुदृढ़ तथा संयुक्त बनाये रहा। इस वंश के अन्तिम काल में भातगाँव पाटन और कान्तिपुर का राज्याधिकार स्थिर रहा। दूसरे राजा नाग मल्ल ने चौदह वर्षों तक तथा तीसरे राजा जयजगत मल्ल ने पन्द्रह वर्षों तक राज्य किया। चौथे राजा नगेन्द्र मल्ल ने ग्यारह वर्ष और पाँचवें राजा उग्र मल्ल ने पंद्रह वर्ष तक राज्य किया। छठे राजा अशोक मल्ल बहुत ही शान्त प्रकृति तथा धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने विष्णुमती तथा रुद्रमती नदियों के मध्य में श्वेतकाली और रक्तकाली के मन्दिरों की स्थापना की और उस स्थान को पवित्र बनाने के लिए उत्तरकाशी अथवा काशीपुर नाम से प्रसिद्ध किया। अशोक मल्ल ने पाटन के ठकुरी राजाओं को परास्त करके पाटन में भी अपना आधिपत्य जमाया। सातवें राजा जयस्थित मल्ल ने जगतसिंह की अति सुन्दरी कन्या राजल्लदेवी से विवाह करके मल्ल तथा कर्नाटक वंशों को एक प्रेम-सूत्र में बाँध दिया। जयस्थित मल्ल बड़े ही निपुण तथा दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने नेपाल के लिए दण्ड-व्यवस्था निर्धारित की और विधियाँ भी बनवाईं। इन्होंने नेपाली संवत् ५४२ में श्री रामचन्द्र सप्त-मुख गुह्य पारसनाथ कुम्भेश्वर, उन्मत्त भैरव और अमम देवी इत्यादि की मूर्तियाँ स्थापित कीं। यह पचास वर्षों तक धर्मनिष्ठ होकर नेपाल पर निर्विघ्न शासन करते रहे। जयस्थित मल्ल तथा उनके पुत्र ज्योतिर्मल्ल ने हिन्दू धर्म की जड़ें मजबूत करके बौद्ध धर्म की जड़ें हिला दीं। जयस्थित मल्ल के तीन पुत्र थे। इनमें सबसे कनिष्ठ पुत्र ज्योतिर्मल्ल ने सन् १४१३ ई० में पूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली। उन्होंने बौद्धों के पवित्र मंदिर स्वयंभूनाथ का जीर्णोद्धार किया। ज्योतिर्मल्ल की मृत्यु सन् १४२७ ई० में हो गई और उनके पुत्र यक्ष मल्ल अथवा जय मल्ल राजगद्दी के मालिक बने। यक्ष मल्ल राजनैतिक दृष्टि से बड़े ही दूरदर्शी थे यद्यपि उन्होंने राज्य-सत्ता के साथ ही साथ धार्मिक सत्ता भी अपने हाथों में ले ली और दक्षिण भारत से महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को आमंत्रित करके श्री पशुपतिनाथ का पूजन का अधिकार दिया और जगद्गुरु शंकराचार्य के मतों का प्रचार करवाया। यक्ष मल्ल ने धर्मपाल मीननाथ लोकेश्वर का मंदिर निर्माण करवाकर सामन्तभद्र बोधिसत्व पद्मपाणि बोधिसत्व और अन्य बोधिसत्वों के साथ अनेक देवी-देवताओं की पवित्र मूर्तियों की भी स्थापना की। इन्होंने जयदेव गुणकाम द्वारा स्थापित लोकेश्वर की मूर्ति को कान्तिपुर में स्थापित करवाया। यही मूर्ति आज यमलोकेश्वर कहलाती है। इसने सन् १४५१ ई० में भक्तपुर के मध्य में दत्तात्रेय भगवान् का मंदिर

बनवाया और नेपाली संवत् ५९२ अर्थात् सन् १४७२ ई० तक ५३ वर्षों तक राज्य किया। यक्ष मल्ल ने अपने राज्य का विस्तार सिरहुत गोरखा तिब्बत में शिगत्से तथा बुद्ध गया तक कर लिया। सन् १४८० ई० में उन्होंने नेपाल राज्य को अपने तीनों पुत्रों में विभाजित कर दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र राय मल्ल को भक्तपुर मध्यम पुत्र रत्न मल्ल को बनेपा (बाघेमा) तथा कनिष्ठ पुत्र राम मल्ल को काठमाण्डू सौंप दिया और अपनी कन्या धर्मवती को ललित-पत्तन (पाटन) का राज्य दिया। इस विभाजन से यक्ष मल्ल की कीर्ति विनष्ट होगई और नेपाल की कद्रीय शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई जिसके फलस्वरूप गोरखा जाति के लोग बलशाली होते गये। कुछ समय के पश्चात् ललितपत्तन काठमाण्डू में सम्मिलित हो गया। यक्ष मल्ल ने उपत्यका के बाहरी नयकोट के ठाकुरों द्वारा देवी राजेश्वरी पर रंग चढ़ाया जाना सुनकर सन् १४९१ ई० में नयकोट पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में यक्ष मल्ल की विजय मिली और यक्ष मल्ल ने विजयोल्लास में भगवान् पशुपतिनाथ का विशाल मंदिर पुष्पों तथा फलों से भरवा दिया। यक्ष मल्ल के शासन-काल में ही तिब्बत तथा भूटान में कुछ तनातनी हो गई थी। इसी समय से नेपाल में मुसलों का पदार्पण विशेष रूप से होने लगा क्योंकि यक्ष मल्ल ने ही सर्वप्रथम नेपाल में यवनों को प्रवेश करने की आज्ञा दी थी।

यक्ष मल्ल के बाद चौथ राजा हरिहरसिंह के पुत्र सिद्धि नरसिंह मल्ल बहुत ही धर्मात्मा निकले। उन्होंने ललितपुर का विशाल दरबार तथा अड़सठ बौद्ध मठ और विहार बनवाकर अन्त में सन्यास ले लिया। दिल्ली के बादशाह हुमायूँ से मिलने नेपाल के राजा महेन्द्र दिल्ली गये और उन्होंने बादशाह को उपहार में एक सफेद हंस और कुछ बाज दिये। हुमायूँ ने प्रत्युत्तर में राजा महेन्द्र को चाँदी की मुहर (सिक्का) बनाने का अधिकार दिया। यही



एक प्राचीन दरबार

'महर' शब्द नेपाल के सिक्के का नाम अभी तक प्रचलित है। राजा महेन्द्र ने काठमाण्डू में तुलजा भवानी का मन्दिर निर्माण कराया और नगर की समृद्धि की। उन्होंने नाग-रिकों को ऊँची-ऊँची इमारतें बनवाने का भी अधिकार दिया।

महेन्द्र के पुत्र सदाशिव ने ललितपत्तन में महा बौद्ध का मन्दिर बनवाया जो बुद्ध गया के महाबोध तथा जापान के बुद्धदेव के अनुरूप था। सदाशिव बड़े अधि

चारी तथा लम्पट स्वभाव के थे। वह अपने घोड़ों को मार-मार कर इतना दौड़ाते थे कि वे उपत्यकाओं में मर जाया करते थे। उनके समय में किसी भी सुन्दर स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं माना जाता था। अंत में उन्हें मारकर राज्यभवन से बाहर निकाल दिया गया।

सनवसी राजा

पाल्पा के राजा मुकुन्द सेन ने तब नेपाल पर आक्रमण किया। उस समय नेपाली प्रजा ने चावल मूली इत्यादि खाद्य-सामग्री को पृथ्वी के गर्भ में छिपा दिया और जब नेपाल में शान्ति स्थापित हो गई तब उसने छिपाये हुए चावल मूली इत्यादि को बाहर निकाला। अधिक दिनों तक भूमि में गड़े रहने के कारण उनमें एक विचित्र स्वाद आ गया और इसी के फलस्वरूप आजतक भी नेपाल में चावल और मूली कृत्रिमरूप से गाड़कर 'हकुवा' चावल और 'सिन्की' मूली बनाना प्रचलित है।

राजा मुकुन्द सेन के कोई पुत्र नहीं था इसलिए सगोत्री भाई धर्म सेन पाल्पा के राजा बनाये गये। राजा धर्म सेन और नेपाल नरेश हरिसिंह देव में मित्रता थी। राजा धर्म सेन अपनी माता को लेकर गुह्यकाभवानी और श्री पशुपतिनाथ के दर्शन करने नेपाल आये और एक सद्वंशीय क्षत्रिय की सुशील कन्या से पाणिग्रहण भी किया।

राजा धर्म सेन के दो पुत्र थे जिनके नाम राज सेन और अभय सेन थे। अभय सेन बहुत ही विषयी तथा दुष्ट स्वभाव के थे। राजा धर्म सेन की मृत्यु के पश्चात् राजसेन पाल्पा की गद्दी पर बैठे। राजभवन ऋतुराज सेन के नाम से प्रख्यात हुए, किन्तु सहसा अभय सेन की मृत्यु हो जाने से ऋतुराज सेन को बहुत वेदना हुई। कुछ ही दिनों के पश्चात् युवराज प्रेम सेन की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं का प्रभाव ऋतुराज सेन के हृदय पर बहुत गहरा पड़ा और वह अपने कनिष्ठ पुत्र अमरराज को लेकर तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। सन् १३४९ ई० में ऋतुराज सेन हरिद्वार होकर ज्योंही कुरुक्षेत्र पहुँचे त्योंही तैमूरलंग की सुसज्जित सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया और ऋतुराज सेन सहित उनके अधिकांश साथियों को मार डाला। युवराज अमरराज सेन तैमूरलंग की सेना से बचकर पाल्पा आ पहुँचे।

अमरराज सेन ने जब यह देखा कि पाल्पा राज्य के मंत्री इत्यादि बहुत ही अविश्वसनीय हो गए हैं तो उन्होंने मंत्री इत्यादि का मान-मर्दन कर दिया और अपने पिता के राज्य को अपने हाथों में ले लिया। उनके पुत्र चन्द्रमकर सेन बहुत ही मनस्वी तथा मतमानी थे। चन्द्रमकर सेन ने मकवानपुर, मीरकोट, नहाँकोट इत्यादि स्थानों को विजय करना चाहा किन्तु वह सफल नहीं हो सके। उनके पुत्र रुद्र सेन अदूरदर्शी तथा विलासप्रिय थे इसलिए गोरखों ने नहाँकोट, पुरकोट, मीरकोट इत्यादि स्थानों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया।

रुद्र सेन के ज्येष्ठ पुत्र मुकुन्द सेन द्वितीय ने रिसिंग और राजपुर विजय किया और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् पाल्पा के राजा बने। मुकुन्द सेन द्वितीय बड़े ही नीति

परायण तथा व्यवहारकुशल राजा हुए और प्रजा उनके स्वभाव तथा कार्य से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें 'मुनि महाराज' कहने लगी। उनके पाँच पुत्र पृथ्वी सेन, भृमि सेन, लक्ष्मण सेन, चन्द्रचूड़ सेन तथा रामप्रताप सेन हुए। राजा मुकुन्द सेन ने राजा यक्ष मल्ल की भाँति अपने पाँचों पुत्रों में अपना राज्य बाँटकर सन्यास ले लिया। उन्होंने पृथ्वी सेन को पाल्पा, लक्ष्मण सेन को मकवानपुर, चन्द्रचूड़ सेन को राजपुर, भृमि सेन को तनहूँ तथा रामप्रताप सेन को रिसिंग का स्वतन्त्र राजा बना दिया और राज्य को छिन्न-भिन्न हो जाने दिया। उन्होंने अपना अंतिम समय त्रिवेणी में बिताया।

सन् १५८५ ई० में शिवसिंह काठमाण्डू के राजा बनाये गये और वह सन् १६१४ ई० तक राज्य करते रहे। उनकी धर्मपत्नी गंगा रानी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी और उन्होंने अपने पति से अनुमति लेकर स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ तथा चांगुनारायण इत्यादि पवित्र मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया। गंगारानी की मृत्यु की घटना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जब साध्वी रानी ने अपना नश्वर शरीर त्यागा तो भगवान् पशुपतिनाथ के मन्दिर से एक हृदय-विदारक प्रचण्ड ध्वनि हुई जिसको सुननेवाले सब बहरे हो गये।



काष्ठ-मण्डप

शिवसिंह के पश्चात् लक्ष्मी नरसिंह राजा हुए। उन्होंने एक विशाल वृक्ष की लकड़ी से एक सुदृढ़ 'काष्ठ-मण्डप' अथवा 'काठ का महल' बनवाया जिसके आधार पर ही उस नगर का नाम 'काठमाण्डू' पड़ गया।

मल्लवंशियों में भीम मल्ल काफी व्यावसायिक बुद्धि के थे। उन्होंने तिब्बत में जाकर अपना खूब प्रभाव जमाया और कुती घर्रे को नेपाल में मिला लिया। अन्त में भीम मल्ल की दुराशा समझकर राजा लक्ष्मी नरसिंह ने उनकी हत्या कर दी। उनकी धर्मपत्नी ने सती

होते समय यह शाप दे दिया कि उनके दरबार में कभी न तो उचित न्याय ही होगा और न कोई नियम ही चल सकेगा। कहा जाता है कि इसी के फलस्वरूप विक्षुब्ध होकर राजा लक्ष्मी नरसिंह पागल हो गये और अठारह वर्ष तक वह दर-दर की ठोकर खाते रहे।

सन् १६४१ ई० में प्रताप मल्ल सिंहासन पर बैठे। वह बहुत ही योग्य शासक थे। उन्होंने हनुमान ढोका की बाहरी दीवाल पर पन्द्रह भाषाओं में लेख खुदवाये।

सन् १६५० ई० में तिब्बत वालों ने स्वयम्भू स्तूप के तोरण कलश तथा शिखर का पुराना ताम्रपत्र बदलकर सुनहरा ताम्रपत्र मढ़वा दिया। राजा प्रताप मल्ल ने अपने जीवन काल ही में अपना राज्य अपने चारों पुत्रों को एक-एक वर्ष तक शासन करने के लिए दिया। चतुर्थ पुत्र चक्रवर्ती मल्ल एक ही दिन शासन करके मृत्यु को प्राप्त हो गये और उनकी स्मृति में टुंडीखेल के सन्निकट रानीपोखरी नामक सुजल आपूरित सरोवर बनवाया गया।



तानसेन नगर

भास्कर मल्ल शक्तिशाली स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी प्रजा की भी बात न मानकर विजयलक्ष्मी एक मास में मनाने की प्रथा निकालनी चाही किन्तु दैव-कोप से सपाम की उपस्थिति में ताऊन फैलकर महामारी रूप धारण की और अन्त में उन्हें अपनी राजधानी काठमाण्डू की ओर भागना पड़ा किन्तु एक मील की दूरी पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् उनकी रानियाँ आपस में सम्मति से जगज्जय को राजा निर्वाचित करके सती हो गई। जगज्जय ने अपना नाम बदलकर महीपतीन्द्र रख लिया और राज्य का कार्य सन् १७३२ ई० तक करते रहे।

पाल्पा के सेनवंशी

पाल्पा के राजा पृथ्वी सेन की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र फिरोज सेन पाल्पा के राजा बने। इस समय पाल्पा राज्य की शक्ति बहुत ही क्षीण हो चुकी थी किन्तु जगदीश्वर सेन, मय सेन, अहिवर्म सेन, गन्धर्व सेन, उदित सेन, मुकुन्द सेन तथा महादत्त सेन राजाओं ने राज्य को शक्तिशाली बनाया और पाल्पा राज्य की सीमा गोरखपुर तक बढ़ा ली। राजा महादत्त सेन ने नेपाल के महाराजाधिराज रणबहादुर शाह की अपनी सेना द्वारा चौबीसी राज्य विजय करने में बहुत बड़ी मदद की थी किन्तु बाद में रणबहादुर शाह और महादत्त सेन में वैमनस्य हो गया और रणबहादुर शाह ने महादत्त सेन को बन्दी बनाकर पाल्पा राज्य को नेपाल-साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। महादत्त सेन के पुत्र कुमार रत्न सेन को विवश होकर पाल्पा से भागना पड़ा और तराई प्रदेश में निचलौल नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। कुमार रत्न सेन के दो पुत्र लक्ष्मी सेन तथा राम दुर्लभ सेन हुए परन्तु दोनों में से एक के भी कोई सन्तान नहीं रही। इसलिए निचलौल के राज्य का अन्त हो गया।

तन्हौं के सेनवंशी

सेनवंशी राजाओं में मृगिराज सेन और हम्मीर सेन राजा मुकुन्द सेन के ही वंशज थे। हम्मीर सेन तन्हौं के राजा थे। राम प्रताप सेन की मृत्यु के पश्चात् रिसिंग राज्य भी तन्हौं में सम्मिलित कर लिया गया। इस समय बतिया के राजा पूर्वी तराई के क्षेत्रों में बहुत आतंक फैला रहे थे। बेतिया के राजा का झगड़ा सीमा के प्रश्न को लेकर था। इसलिए अकबर बादशाह ने बतिया तथा तन्हौं की सीमायें निर्धारित करा दीं किन्तु तब भी दोनों का मन-मुटाव बढ़ता ही गया। इसी संघर्ष-काल में हम्मीर सेन की मृत्यु हो गई और बतिया नरेश ने तन्हौं के रामनगर के अन्तर्गत ग्यारह तप्पों को अपने राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात् गुप्त सेन तन्हौं के राजा बनाये गये। गुप्त सेन बहुत ही प्रतिक्रियावादी विचार के थे किन्तु युवराज प्रताप सेन की मृत्यु हो जाने से उन्हें बड़ी वेदना हुई।

गुप्त सेन के बाद दामोदर सेन तन्हौं का तथा दया सेन रिसिंग राज्य के अधिकारी हुए। राजपुर नरेश की मृत्यु हो जाने तथा कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण राजपुर भी तन्हौं में मिला लिया गया।

सन् १६७१ ई० में दिग्विजय सेन तन्हौं राज्य के अधिकारी बने। वह बड़े कुशल राजनीतिज्ञ तथा गम्भीर व्यक्ति थे। उन्होंने औरंगजेब बादशाह को प्रसन्न करने के लिए नौ हाथी तथा कस्तूरी आदि इत्यादि दिल्ली भेजे। बादशाह औरंगजेब इस अमूल्य उपहार को प्राप्त कर फूला न समाया और दिग्विजय सेन को प्रमाण-पत्र देकर उन्हें हरिहरपुर का प्रबन्धक राजा मान लिया। कुछ ही दिनों के बाद राजा

दिग्विजय सेन ने बेतिया नरेश से छीनकर रामनगर के दबाए हुए ग्यारहों तप्पों को अपने राज्य में मिला लिया।

सेनवंश में राजा दिग्विजय सेन बहुत ही प्रतापशाली हुए और इन्हीं की अति सुशील पुत्री के गर्भ से नरभूपाल शाह का जन्म हुआ। यही नरभूपाल शाह आगे चलकर गोरखा नरेश कहलाये जिनके पुत्र पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के प्रथम गोर्खाली महाराजाधिराज हुए। सन् १७१४ ई० में अपने पिता राजा दिग्विजय सेन की मृत्यु के बाद कामराज सेन उन्हीं के राज्याधिकारी हुए। राजा कामराज सेन ने दिल्ली के बादशाह फर्रुखशाह को प्रसन्न करने के लिए तराई प्रान्त के पन्द्रह तप्पे छोड़ दिए और कामराज सेन के पुत्र विक्रम सेन उन्हीं के राजा बने। इन्होंने जब यह देखा कि मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती जा रही है और बंगाल का पठान सेनापति बेतिया नरेश के पीछे पड़ गया है तो उन्होंने बेतिया नरेश को शरण दी। विक्रम सेन को यह भली भांति विदित था कि बेतिया-नरेश के वंश वाले उसके वंश के चिर प्रतिद्वन्द्वी तथा घोर शत्रु रहे हैं किन्तु तब भी उन्होंने बेतिया-नरेश का उचित सम्मान करके अपनी सज्जनता का परिचय दिया। सन् १७३४ ई० में विक्रम सेन की मृत्यु हो गई और युवराज कामारिदत्त सेन उन्हीं के राजा हुए। इस प्रकार से नेपाल के मध्यकाल में भक्तपुर, कान्तिपुर तथा ललितपुर में मल्लवंशीय राजाओं की वंशावलि धीरे-धीरे खूब फलती-फूलती रही और एक के बाद दूसरी पीढ़ी क्रमशः उत्तराधिकार प्राप्त करके अपनी-अपनी राजधानी में राज्य करती रही। इनके अतिरिक्त जो अन्य छोटे मोटे राज्य थे वे सब इन्हीं तीनों अथवा गोरखा राज्य में पहले ही मिल चुके थे।

इन तीनों वंशों के इस समय शासक रणजीत मल्ल भातगांव में, जयनरसिंह मल्ल ललितपुर में तथा जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुर में राज्य कर रहे थे। इसी काल में पाल्पो, नुवाकोट, सतौं तथा लम्जुङ में चित्तौड़गढ़ से आये हुए भूपाल राव राणा की संतति शाहवंशीय राजा राज्य कर रहे थे। शाहवंश के प्रवर्तक राजा द्रव्यशाह लम्जुङ नरेश राजा यशो ब्रह्मशाह के कनिष्ठ पुत्र थे जिन्होंने छोटे-छोटे राजाओं की भयंकर आपसी फूट से लाभ उठाकर एक-एक करके सबको अपने 'गोरखा' राज्य में मिलाना प्रारम्भ कर दिया और गोरखों के इष्टदेव महात्मा गोरखनाथ का वरदान प्राप्त करके सफल भी हो गए।

४

अंग्रेजों का हस्तक्षेप

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का विस्तार धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा था और उसके द्वारा ब्रिटिश शक्ति अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। इससे नेपाल के शासकों को भी भय प्रतीत होने लगा और उन्होंने भारत के राजाओं तथा नवाबों से मिलकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी को उखाड़ फेंकने के लिए एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने का प्रयत्न किया किन्तु इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल सकी और अंग्रेजों के पैर भारत में जमते ही गये।

अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक नेवारों के भातगाँव, काठमाण्डू और पाटन के तीनों राज्य आपस में विभक्त हो गये थे और सब आपस में एक दूसरे के विरोधी थे। भातगाँव के राजा ने गोरखों के राजा पृथ्वीनारायण शाह से सहायता माँगी। पृथ्वीनारायण शाह उदयपुर के सिसौदिया राजपूत वंश के उत्तराधिकारी थे। पृथ्वीनारायण ने भातगाँव के राजा की सहायता ही नहीं की वरन् थोड़े ही काल में उन्होंने दोनों राज्यों को एक सूत्र में बाँध दिया। सन् १७६७ ई. में राजा जयप्रकाश मल्ल ने ब्रिटिश सरकार से सहायता माँगी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने कर्नल किनलाक के नायकत्व में एक फौजी टुकड़ी वर्षाऋतु के मध्य में भेजी किन्तु वह टुकड़ी तराई की गर्मी को सहन नहीं कर सकी और उसे वापस लौट जाना पड़ा। इसके पश्चात् गोरखों के प्रधान ने राज्य की सीमा विस्तृत करके पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में मेची नदी तक कर ली और गोरखों के शासक सम्पूर्ण नेपाल के महाराजा कहलाने लगे।

इसके पश्चात् गोरखों ने मकवानपुर का पहाड़ी प्रदेश भी जीत लिया और दक्षिण की जीती हुई भूमि को कर लेकर ब्रिटिश सरकार को देने के लिए स्वीकृति दी गई। अंग्रेज तीस वर्षों तक इस भूमि के लिए प्रतिवर्ष एक हाथी भेंट में दिया करते थे और यह प्रथा सन् १८०१ ई. तक चलती रही। इसके पश्चात् ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस के शासन-काल तक नेपाल से भारत सरकार के सम्बन्ध बहुत ही कम थे। उनके समय में नेपालियों ने बनारस स्थित रेजिडेन्ट मि. डंकन द्वारा पुनः समझौते की बातचीत चलाई।

लार्ड कार्नवालिस ने नेपाल और चीन के बीच सन्धि कराने का प्रयत्न किया और उन्होंने मेजर कर्कपैट्रिक को काठमाण्डू भेजना चाहा किन्तु मेजर कर्कपैट्रिक के नेपाल की सीमा तक पहुँचते ही नेपालियों को बाध्य होकर चीनी जनरल के साथ सन्धि कर लेनी पड़ी। इस सन्धि के अनुसार हर पाँचवें वर्ष नेपाल से चीन के सम्राट के पास भेंट लेकर एक शिष्ट मण्डल भेजे जाने का निश्चय हुआ और जब सन् १ १ ई. में चीन में क्रान्ति के फलस्वरूप मांच्यू वंश समाप्त हो गया और वहाँ कोई सम्राट नहीं रहा तो यह प्रथा बन्द हो गई।

मिस्टर कर्कपैट्रिक को नेपाल के साथ सन् १७९२ ई० में की गई व्यापारिक संधि को पुनः उज्जीवित करने का आदेश हुआ। इसी संदेश को लेकर वह काठमाण्डू गये—परन्तु नेपालियों ने उनके साथ अन्यमनस्कता प्रदर्शित की जिसके फलस्वरूप विवश होकर मि० कर्कपैट्रिक को सन् १७९३ ई० में काठमाण्डू से लौट आना पड़ा।

बहादुरशाह

अठारहवीं शताब्दी तक नेपाल और अंग्रेजों के बीच सम्बन्ध केवल पत्रों तथा मकवानपुर के राजा द्वारा भेजे हुए कभी-कभी उपहारों तक ही सीमित थे। सन् १७७४ ई० में पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु हुई। उनके सिंहप्रताप तथा बहादुर शाह नाम के दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र सिंहप्रताप राज्य के उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने बहुत थोड़े दिन शासन किया क्योंकि उनकी मृत्यु सन् १७७७ ई० में ही हो गई। सिंहप्रताप के पश्चात उनका नन्हा शिशु रणबहादुर शाह राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इस काल में उनके चचा बहादुर शाह संरक्षक हुए। पृथ्वीनारायण शाह की विधवा पत्नी उनके विरुद्ध थी। संरक्षक बहादुर शाह और राजमाता के बीच दस वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। इसी संघर्ष के फलस्वरूप बहादुर शाह को भारत में शरण लेनी पड़ी। सन् १७८९ ई० में राजमाता की मृत्यु के पश्चात् बहादुर शाह पुनः नेपाल वापस आये और वह फिर संरक्षक का काम करने लगे। बहादुरशाह सन् १७९५ ई० तक संरक्षक-पद पर रहे। उन्हें रणबहादुर को अपने पद से हटा कर स्वयं शासन की बागडोर सम्भालनी पड़ी। और बाद में उनकी हत्या महाराज रण बहादुर शाह ने करा दी। रणबहादुर शाह बड़े ही अत्याचारी शासक सिद्ध हुए। पांच वर्षों के बाद इन्हें बाध्य होकर अपने शिशु गीर्वाण को उत्तराधिकारी बनाकर शासन की बागडोर छोड़ देनी पड़ी। नन्हें उत्तराधिकारी का कार्य सम्भालने के लिए राजरानी संरक्षक नियुक्त हुई। रणबहादुर शाह को नेपाल छोड़कर बनारस में शरण लेनी पड़ी जहां कैप्टन नाक्स उनके राजनीतिक गुरु बने। रण बहादुरशाह का ब्रिटिश सरकार ऊपर उनके के प्रशंसा करती रही और ब्रिटिश सरकार उनकी आर्थिक सहायता भी करती रही।

ब्रिटिश सरकार ने रणबहादुर शाह के सहारे नेपाल में फिर मित्रता स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस प्रयास में ब्रिटिश सरकार को सफलता भी मिली। अक्तूबर सन् १८०१ ई० में उसकी नेपाल से एक और संधि हुई जिसके अनुसार सन् १८०२ ई० में कैप्टन डब्लू० डी० नाक्स काठमाण्डू में सर्वप्रथम ब्रिटिश रेजीडेंट नियुक्त हुए। राजरानी ने मि० नाक्स का स्वागत किया। रणबहादुर शाह की बड़ी रानी जो रणबहादुर शाह के साथ बनारस चली गई थी सहसा काठमाण्डू वापस आई और स्वयं राज्य की सर्व-सर्वा बन गई। उन्होंने ब्रिटिश रेजीडेंट कैप्टन नाक्स को मार्च सन् १८०३ ई० में नेपाल से भगा दिया और २४ जनवरी सन् १८०४ ई० को लार्ड वेलजली ने नेपाल से सम्बन्ध तोड़ दिया। इसके पश्चात् रणबहादुर शाह ने नेपाल-दरबार के अपने विरोधियों की हत्या करवाकर शासन की बागडोर पुनः ले ली

परन्तु थोड़े ही काल के पश्चात् सन् १८०७ ई० में रणबहादुर शाह की मृत्यु हो गई। इस समय नेपाल में प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे जो बड़े कुशल कूटनीतिज्ञ माने जाते थे। उन्होंने रणबहादुर शाह की बड़ी रानी की सहायता प्राप्त करके किशोर राजा गीर्वाण युद्ध विक्रम को अपने वश में कर लिया। भीमसेन थापा ने राज्य की सीमा काली नदी से सतलज नदी तक विस्तृत की। इसके अन्तर्गत जितने भी पहाड़ के राजा थे सबने नेपाली शासन को मान लिया। अनेकों सैनिक पद स्थापित किये गये। सन् १८०४ ई० से १८१२ ई० तक नेपालियों और ब्रिटिश के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा सिवाय इसके कि सीमा पर डकैती तथा लूटपाट के समय यह दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहे। सन् १८ ४ ई० में नेपालियों ने बटवल तथा शिवराज के परगने जो अवध के वजीर द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिये जा चुके थे हस्तगत किये। सन् १८०८ ई० में मोरंग के नेपाली गवर्नर ने पूर्णिया सीमा स्थित भीमनगर की जमींदारी को अपने अधिकार में कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया भीषण हुई और जून सन् १८ ९ ई० में ब्रिटिश ने नेपाली सीमा पर आक्रमण करके इन्हें छीन लेने के लिए फौज भेजी। फलतः सन् १८१० ई० में नेपालियों ने ब्रिटिश इण्डिया की सीमा को पार कर बुटवल और बेतिया की सरहद को अपने अधिकार में कर लिया। इसी कारण नेपाल और ब्रिटिश में सीमा पर मुठभेड़ हुई जिसके फलस्वरूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी और नेपाल सरकार की ओर से सीमा-वर्ती झगड़ों को शान्त करने के लिए कमिश्नरों की नियुक्तियाँ हुई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमिश्नरों ने नेपाल सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट दी जिससे चिढ़कर लार्ड हेस्टिंग्स ने मध्य अप्रैल सन् १८१४ ई० में उन जिलों पर अधिकार कर लिया जिनके सम्बन्ध में झगड़ा था।

नेपाल-ब्रिटिश युद्ध

नवम्बर, सन् १८१४ ई० में नेपाल और ब्रिटिश-सरकार के बीच लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेजों की दो टुकड़ी फौज पूर्व में बढ़ी परन्तु नेपालियों ने उनके दाँत खट्टे कर दिये और अंग्रेजों को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों की दो टुकड़ियाँ पश्चिम से काली नदी के पहाड़ी प्रान्तों की ओर बढ़ा परन्तु गोरखों ने बड़ी चतुरता तथा वीरता से डटकर उनका प्रतिरोध किया और अंग्रेजों की सेना को परास्त करके काली और सतलज के बीच का प्रान्त भी जीत लिया।

प्रधान मंत्री भीमसेन थापा ने सन् १८१३ ई० में चीनी सम्राट् से मिलकर भारत से अंग्रेजों को मार भगाने की योजना बनानी चाही परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। सन् १८१४ ई० में अंग्रेजों ने चिढ़कर गोरखपुर की तराई पर अधिकार कर लिया। मेजर जनरल जिलेस्पी ने अपने छः हजार सैनिकों को भेजकर देहरादून के कैलंग किले पर हमला किया। इस युद्ध में पाँच सौ बीस नेपाली सिपाही वीरगति को प्राप्त

हुए और जनरल गिलेस्पी भी किले के फाटक पर मारा गया। २८ दिसम्बर, सन् १८१४ ई० को जनरल मार्टिन्डेल ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर जयथक दुर्ग पर आक्रमण किया किन्तु नेपाली सेना ने अंग्रेजी सेना को पछाड़ दिया। इस पराजय के बाद मार्टिन्डेल ने पुनः आक्रमण करने का साहस छोड़ दिया। इसका रोचक वर्णन प्रो० विल्सन ने अपनी पुस्तक में किया है। लार्ड हेस्टिंग्स को भारत की समस्याओं में उलझा देखकर जनरल भीमसेन थापा ने पुनः चीनी सम्राट् से सम्बन्ध स्थापित किया। नेपाल का सम्बन्ध सिक्खों से अच्छा था और दोनों में युद्धरत से मैत्री आरम्भ की कोशिश भी चल रही थी परन्तु अंग्रेजों ने इस बात को समझकर सिक्खों को नेपाल से दूर रहने के लिए बाध्य किया और नेपाल चीन तथा रूस के बीच सम्बन्ध-विच्छेद हो गया।

मराठों की लड़ाई के समय जनरल भीमसेन थापा ने फिर एक बार बूटवल और तराई तथा गण्डक का भूभाग अंग्रेजों को दो लाख रुपये कर देकर नेपाल में मिला लिया। उन्होंने अपनी कूटनीति से तराई के दो सौ गांवों को अंग्रेजों से लेकर क्रमशः सात वर्षों में अपने राज्य में मिला लिया। इन्हीं सब महान् कार्यों पर रीझकर नेपाली जनता ने भीमसेन थापा को 'महात्मा' की उपाधि दी।

सिगौली की सन्धि

२ दिसम्बर, सन् १८१५ ई० को सर डेविड आक्टरलोनी ने तराई के बदले में नेपाल सरकार को प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि तथा कुछ अन्य सुविधायें देने का प्रलोभन देकर नेपाल सरकार को फुसला लिया और सिगौली के सन्धिपत्र पर नेपाल सरकार से हस्ताक्षर करा लिए। अंग्रेजी सरकार के गवर्नर जनरल ने संधिपत्र को स्वीकृति दी परन्तु नेपाली सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर फरवरी सन् १८१६ ई० में दोनों सरकारों में फिर लड़ाई आरम्भ हो गई। अंग्रेजी सेना सर डेविड आक्टरलोनी के अधिनायकत्व में काठमाण्डू की ओर बढ़ी। नेपाली सैनिकों ने बड़ी वीरता के साथ उनका सामना किया परन्तु अन्त में नेपाल सरकार को पराजित होना पड़ा।

४ मार्च सन् १८१६ ई० को नेपाल सरकार ने सिगौली के प्रस्तावित संधिपत्र पर हस्ताक्षर किये और उसे अंग्रेजी सरकार ने भी स्वीकृति दे दी। इसके अनुसार सतलज नदी के पूर्व की पहाड़ी भूमि तथा मेची नदी और तिस्ता के बीच की तराई का भूभाग सिक्किम को दे दिया गया। ११ दिसम्बर, सन् १८१६ ई० को अंग्रेजी सरकार ने राप्ती और कोसी नदियों के बीच की भूमि के बदले दो लाख रुपए प्रतिवर्ष नेपाली सेनानायकों को पेन्शन के रूप में देने के लिए वादा किया और कोसी नदी के पश्चिम की तराई की भूमि बदले में मिल गई।

सिगौली की संधि के फलस्वरूप मिस्टर गार्डनर नेपाल में रेजीडेन्ट नियुक्त किये गये। उस समय जनरल भीमसेन थापा का नेपाल पर पूर्ण नियन्त्रण था और यह

नियन्त्रण सन् १८३२ ई० तक रहा। सन् १८३४ ई० में भीमसेन थापा राजदूत बनाकर कलकत्ता भेजे गये। सन् १८३६ में उनके स्थान पर माथबर सिंह राजदूत नियुक्त हुए और भीमसेन थापा नेपाल लौट आये।

सन् १८३३-३४ ई० में नेपाल और भारत के बीच एक अपराध सम्बन्धी तथा दूसरी व्यापार सम्बन्धी सन्धि अंग्रेजों ने प्रस्तावित की परन्तु नेपाल सरकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। सन् १८३५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने नेपाल सरकार से अंग्रेजी माल के ऊपर चुंगी कम कर देने के लिए प्रार्थना की परन्तु नेपाल सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। डाकुओं तथा हत्यारों को पकड़ने के लिए दोनों सरकारों के बीच जनवरी सन् १८३७ ई० में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया।

२४ जुलाई, १८३७ ई० में महाराजा के कनिष्ठ पुत्र का स्वर्गवास हो गया और भीमसेन थापा पर शिशु को विष देने का अपराध मढ़ दिया गया। इसी शंका में महाराजा ने भीमसेन तथा उनके भतीजे माथबर सिंह को बन्दी बना लिया किन्तु कुछ दिन बाद वे दोनों मुक्त कर दिये गये। मुक्त होने पर भीमसेन थापा ने सार्वजनिक तथा शासन सम्बन्धी कार्यों से विश्राम ले लिया किन्तु माथबर सिंह ने लाहौर की राह ली और वह लाहौर दरबार में काम करने लगे। महाराजा को इससे संतोष नहीं हुआ और अवकाश प्राप्त वृद्ध भीमसेन थापा को सन् १८३९ ई० में पुनः बन्दी बनाकर नाना प्रकार की अमानुषिक यातनायें दी जाने लगीं। भीमसेन थापा को एक छोटी-सी अंधेरी काल-कोठरी में बन्द करके उनके पास एक पैनी छुरी आत्महत्या करने के लिए छोड़ दी गई। कहा जाता है कि यह कार्यवाही ब्रिटिश दूतावास के संकेत से तत्कालीन शासकों द्वारा कार्यान्वित कराई गई। भीमसेन थापा की धर्मपरायणा सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को नग्न करके काठमाण्डू की सड़कों तथा गलियों में जबर्दस्ती घुमाये जाने का झूठा प्रचार किया गया। इस घटना का समाचार सुनकर नेपाल-गौरव स्वदेश-भक्त भीमसेन थापा का हृदय विदीर्ण हो गया। भीमसेन थापा ने अपने प्रयत्नों से नेपाल को एक समुन्नत गौरवान्वित राष्ट्र बनाया तथा साम्राज्यवादी अंग्रेजों को न केवल भारत से अपितु एशिया के सम्पूर्ण महाद्वीप से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया था जिसके फलस्वरूप ही उनको यह अपमान सहना पड़ा। अन्त को असहाय पाकर अपने पास पड़ी हुई पैनी छुरी से उन्होंने अपनी गर्दन पर वार कर लिया और वह घायल अवस्था में नौ दिन तक काल-कोठरी में तड़पते रहे। मृत्यु के पश्चात् उस श्रेष्ठ सेनानी के शव की असंख्य बोटियाँ काट काट कर गिद्धों तथा कुत्तों से नुचवाने के लिए राजधानी की सड़कों पर फेंक दी गईं।

अंग्रेजों ने नेपाल में जनता पर अत्याचार के लिए नेपाल के शासकों द्वारा अपमानजनक अपराध करवाये किन्तु इसकी प्रतिक्रिया गम्भीर रूप से हुई और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए नेपाल में भीषण कार्य होते ही रहे।

नवम्बर, सन् १८३९ ई० में सिक्किम भूटान तथा नेपाल के प्रश्न को लेकर नेपाल तथा ब्रिटिश सरकारों में तनातनी हुई किन्तु अंग्रेज़ों की कड़ी नीति देखकर नेपाल सरकार को अपनी नीति बदल देनी पड़ी। सन् १८४० ई० में नेपालियों ने रामनगर जमींदारी के अनेक ग्रामों को नेपाल में मिला लिया और सन् १८४२ ई० में नेपाल-सरकार ने इस सम्बन्ध में अंग्रेज़ों की स्वीकृति भी ले ली।

महात्मा भीमसेन थापा के पश्चात् जनरल माथवर सिंह ने राज्य की बागडोर संभाली। उनके शासन-काल में जंग बहादुर एक साधारण सिपाही से सेना में धीरे-धीरे उन्नति करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

आधुनिक काल

आधुनिक काल का इतिहास महाराजा पृथ्वीनारायण शाह के राज्यारोहण के शुभ मुहूर्त से ही प्रारम्भ होता है। शाहवंश के प्रवर्तक महाराजा द्रव्यशाह के पूर्वज पन्द्रहवीं शताब्दी में चित्तौड़ से नेपाल में लम्जुंग आकर राज्य करने लग गये थे। लम्जुंगाधिपति महाराजा यशोब्रह्म और गोरखाधिपति महाराजा द्रव्यशाह के बीच छत्तीस पीढ़ियों का अन्तर था। महाराजा द्रव्यशाह राजा यशोब्रह्म शाह के द्वितीय पुत्र थे। उनकी माता का नाम महारानी बसन्तावती तथा ज्येष्ठ भ्राता का नाम नरहरि शाह था। राजा नरहरि शाह अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर लम्जुंग में राज्य करते थे किन्तु महाराजा द्रव्यशाह अपने पराक्रम से गोरखा राज्य को जीतकर उस पर शासन करने लगे। महाराजा द्रव्यशाह का अभ्युदय देखकर उनके ज्येष्ठ भ्राता राजा नरहरि शाह के मन में ईर्ष्या होने लगी और राजा नरहरि शाह ने महाराजा द्रव्यशाह को पछाड़कर गोरखा राज्य को भी लम्जुंग में मिला लेने का षड्यन्त्र किया। इस षड्यन्त्र का पता जब विधवा महारानी बसन्तावती को लगा तो उन्हें विशेष आकुलता हुई और उन्होंने अपने स्तन का दूध चेपे नदी में गिराकर लम्जुंग तथा गोरखा राज्यों की सीमा निर्धारित कर दी।

महाराजा द्रव्यशाह को जब यह स्पष्ट हो गया कि गोरखा राज्य के आसपास राजाओं में भयंकर फूट है तो उन्होंने एक-एक करके क्रमशः सिद्धानचोक अजीरगढ़ दरौंदी तथा पुरुन्चोक को जीतकर गोरखा राज्य में मिला लिया। इस महान् विजय के कुछ ही दिनों पश्चात् राजमाता बसन्तावती का स्वर्गवास हो गया और ज्येष्ठ भ्राता नरहरि शाह ने ईर्ष्या-वश गोरखा राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी। महाराजा द्रव्यशाह लोक-लाज के भय से अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध करना अनुचित समझकर बार-बार बचते रहे। अन्त में राजा नरहरि शाह ने गोरखा पर आक्रमण कर दिया किन्तु वीर गोरखों ने दरौंदी तथा पुरुन्चोक में लम्जुंग वालों के दांत खट्टे कर दिये। महाराजा द्रव्यशाह ने सन् १५५९ से १५७ ई० अर्थात् ग्यारह वर्ष तक गोरखा पर राज्य किया और सन् १५७ ई० में अपना नश्वर शरीर परित्याग किया। पराक्रमी राजा द्रव्यशाह के पश्चात् पुरन्दरशाह ने पैंतीस वर्षों तक राज्य किया और सन् १६०५ ई० में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र छत्रशाह राज्य-सिंहासन पर बैठे। किन्तु सात मास में राजा छत्रशाह की भी मृत्यु हो गई। राजा छत्रशाह पुत्रहीन थे। इसलिए उनके भ्राता रामशाह सन् १६ ६ ई० में सिंहासन के अधिकारी बनाये गये। राजा रामशाह बहुत ही प्रतापी शासक निकले। उन्होंने सम्पूर्ण में महान् यश लिया। इसी समय से जयाम का राजा प्रशस्ति के साथ 'महाराजाधिराज' की उपाधि

से विभूषित किया जाने लगा। रामशाह ने लम्जुंग के राजा को मीरकोट के युद्ध में पराजित करके उसे सब प्रकार से असमर्थ कर दिया। इसके बाद राजा रामशाह कई वर्षों तक संग्रामों में उलझे रहे और एक-एक करके उन्होंने केरुङ, कुकरघाट, रसुवा भोट, जारी मैदी, बरक निमारचोक तथा धादिङ इत्यादि इलाकों को जीतकर अपने 'गोरखा राज्य' में सम्मिलित करके महाराजाधिराज की उपाधि सार्थक कर दी।

सात विधिया

महाराजाधिराज श्रीरामशाह प्रजा के दुःख-सुख का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए निम्नलिखित विधिया बनाकर लागू कीं—

१ ग्राम-पंचायतों द्वारा संचालित पानी, नहर, बांध तथा कुआं इत्यादि के झगड़े केन्द्रीय न्यायालयों में न भेजे जाकर न्याय के लिए ग्राम-पंचायतों ही में भेजे जायें।

२ राज्य की समस्त भूमि का अधिपति राजा ही होगा और उसकी ही आज्ञा से किसी को भूमि दी जा सकेगी। ब्राह्मण, जौतरिया, राज-परिवार तथा अमरसक इत्यादि किसी को भूमि देने का अधिकारी नहीं माना जायगा तथा खेत की सीमा सम्बन्धी छोटे मोटे झगड़ों का निर्णय पंचों द्वारा ही हुआ करेगा।

३ मुकदमों के सत्यासत्य का निर्णय जानने के लिए वादी तथा प्रतिवादी को शालिग्राम की मूर्ति स्पर्श करके अपना बयान देना होगा और पंच अथवा न्यायालय जिस स्त्री को कुटनी सिद्ध कर देगा उसे गांव से बाहर निकाल दिया जायगा और यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री का पक्ष ग्रहण करके न्याय में बाधा डालेगा तो उसे पांच रुपया दण्ड देना होगा और जो व्यक्ति मुकदमा जीतने के लिए हाकिम को अपने पक्ष में करने की कुचेष्टा करेगा उसे देश से निकाल दिया जायगा।

४ बांस का ढोंगा, काठ की ढोकनी तथा बेंत की डलिया द्वारा नापतोल का प्रचलन उठाकर उनके स्थान पर तांबे का माना (आधा सेर), पाथी (चार सेर), मुरी (दो मन), धार्नी (तीन सेर) इत्यादि का प्रमाणित पैमाना माना जायगा।

५ ऋणकर्ता को दस वर्ष के बाद अधिक से अधिक मूलधन का दुगना (मूलधन तथा ब्याज सहित) महाजन को देना होगा और यदि किसी ने अनाज ऋण में लिया हो तो उसे दस वर्ष के बाद तिगुना देना पड़ेगा।

६ वन, पोखर तथा मार्ग पर आरोपित वृक्षों को जो हानि पहुंचायगा उसे पांच रुपया दण्ड देना पड़ेगा।

७ हत्या करने के अभियोग में जौतरिया तथा सगोत्र आदमियों को देश-निकाला होगा। ब्राह्मण, सन्यासी, जोगी तथा भाटों का सिर मुड़ाकर देश से निर्वासित किया जायगा किन्तु प्रधान मंत्री से लेकर अन्य सरकारी कर्मचारियों की तथा अन्य जातिवालों को मृत्यु-दण्ड दिया जायगा।

इन विधियों के लागू होते ही सरकारी पदाधिकारियों में अनुशासन आ गया और वे पग फूंक-फूंक कर धरने लगे। इसका प्रभाव शासन-विभाग पर बहुत सुन्दर पड़ा और नेपाल सरकार का शासक-वर्ग बहुत ही सचेष्ट तथा न्यायप्रिय हो गया।

इन सातों विधियों के अतिरिक्त महाराजाधिराज रामशाह ने कुछ अन्य छोटे-मोटे नियम भी लागू किये और जनता के परम हितैषी तथा विश्वासपात्र बनकर सन् १६३२ ई० तक शासन किया।

रामशाह की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र डम्बर शाह सिंहासन पर बैठे। महाराजाधिराज डम्बरशाह ने नौ वर्ष तक सुचारु रूप से राज्य किया।

सन् १६४२ ई० में डम्बर शाह के पुत्र कृष्ण शाह राज्याधिकारी हुए और वह दस वर्ष तक शान्तिपूर्वक राज्य करते रहे। इसके पश्चात् सन् १६५२-५३ ई० में चन्द्ररूप शाह नेपाल के महाराजाधिराज हुए। उन्होंने कई वर्षों तक शासन की बागडोर संभाली। चन्द्ररूप शाह के पुत्र पृथ्वीपति शाह सन् १६६९ ई० में सिंहासनासीन हुए और वह चौंतालीस वर्षों अर्थात् सन् १७१६ ई० तक राज्य करते रहे।

संक्रान्ति-काल

महाराजाधिराज पृथ्वीपति शाह के बाद का काल संक्रान्ति-काल कहा जा सकता है क्योंकि *युवराज वीरभद्र शाह गद्दी पर बैठने ही न पाये थे कि वह अपनी गर्भवती स्त्री को* छोड़कर स्वर्ग सिधारे। जिस समय वीरभद्र शाह की मृत्यु हुई उस समय उनकी गर्भवती स्त्री अपने मायके तन्हूँ में थी। पृथ्वीपति शाह के पुत्र कुमार दलशाह एक आँख से काना होने के नाते राज्याधिकारी होने के योग्य नहीं रह गये थे। दूसरे पुत्र उद्योत शाह काल-क्रम से गद्दी के अधिकारी नहीं होते थे। महाराजाधिराज पृथ्वीपति शाह अपने उत्तराधिकारी के लिए चिन्ताग्रस्त ही थे कि उनके कनिष्ठ पुत्र चन्द्ररूप ने यह शुभ समाचार सुनाया कि विधवा युवराज्ञी को अपने मायके तन्हूँ में पुत्र रत्न पैदा हुआ है। इस समाचार को सुनते ही पृथ्वीपति शाह आनन्द-विभोर हो गये और उन्होंने अपने छोटे कुमार चन्द्ररूप शाह को तन्हूँ भेजकर शिशु को तुरन्त गोरखा लाने के लिए आदेश दिया। उधर तन्हूँ के राजा शिशु नरभूपाल शाह की ओट में गोरखा को अपने राज्य में मिला लेना चाहते थे। कुमार चन्द्ररूप शाह को जब यह प्रतीत हो गया कि विधवा युवराज्ञी के मामा शिशु नरभूपाल शाह को पृथ्वीपति के पास गोरखा जाने नहीं देंगे तो उन्होंने तन्हूँ-दरबार की धाय को कुछ प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लिया और चुपके से गन्दे कपड़ों में छिपाकर बच्चे सहित बालक नरभूपाल शाह को गोरखा मंगवा लिया। महाराजाधिराज पृथ्वीपति शाह के पश्चात् यही बालक नरभूपाल शाह सन् १७१६ ई० में गोरखा राज्य का अधिकारी हुआ।

नरभूपाल शाह ने गद्दी पर बैठते ही काठमाण्डू, पाटन तथा भक्तपुर के मल्लवंशीय

राजाओं को आपस में लड़ते हुए देखा तो उन्होंने धीरे-धीरे इन तीनों को अपने राज्य में मिला लेने के लिए युद्ध की तैयारी की। सन् १७१६ ई० में नरभूपाल शाह ने नुवाकोट के मार्ग से मल्लवंशीय राजा जगज्जय मल्ल पर आक्रमण किया किन्तु जगज्जय मल्ल ने यह आक्रमण विफल कर दिया। इसके पश्चात् नरभूपाल शाह का मल्ल राजाओं पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। सन् १७४२ ई० में नरभूपाल शाह की मृत्यु हो गई।

वरदान

महाराजा नरभूपाल शाह की दो महारानियाँ थीं। छोटी महारानी कौशल्या देवी के गर्भ से सातवें महीने में ही एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। महारानी को गर्भ-काल में एक दिन स्वप्न में सूर्यनारायण का साक्षात्कार हुआ इसलिए देवलोक से सूर्यनारायण का पृथ्वी पर अवतरित जानकर पुत्र का नाम पृथ्वीनारायण शाह रखा गया। उनके सूरप्रताप, दलमर्दन, महोद्दाम कीर्ति, दलपत तथा इस नाम के अनेक भाई थे। पृथ्वीनारायण शाह की अवस्था जब छः वर्ष की ही थी तभी एक दिन गोरखा के कुलगुरु गोरखनाथ ने अपनी गुफा में प्रकट होकर अपने मुँह से दही निकालकर बालक पृथ्वीनारायण शाह को प्रसाद में दिया किन्तु बालक ने जूठन समझकर दही को नीचे गिरा दिया। बालक की इस मूढ़ता को देखकर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि यदि तू इस दही को खा लेता तो तुझे वाक्-सिद्धि हो जाती और तेरी सामान्य वाणी को सुनते ही सब राजा अपना राज्य तेरे राज्य में मिला देते अथवा अब तो ऐसा होना तो नहीं किन्तु प्रसाद का दही तेरे पैरों में लग गया है इसलिए तू जिस किसी भी राज्य में पैर रख देगा वह तेरे अधिकार में आ जायगा। इतना आशीर्वाद देकर गुरु गोरखनाथ अन्तर्धान हो गए।

पृथ्वीनारायण शाह का विवाह मकवानपुर राजा के हेमकर्ण सेन की पुत्री स्वर्णमाया देवी के साथ हुआ किन्तु अपने श्वसुर से उनकी न पटी और मकवानपुर तथा गोरखा में बराबर शत्रुता बनी रही।

सन् १७४२ ई० में पृथ्वीनारायण शाह तेरह वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने अपने प्रधान मंत्री तथा सेनापति कालू पाण्डे की सम्मति लेकर गोरखा राज्य की सीमा बढ़ानी आरम्भ की। भादगाँव पाटन तथा काठमाण्डू के नेवार राज्यों को आपस में खूब लड़ते हुए देखकर पृथ्वीनारायण शाह ने भादगाँव के राजा रणजीत मल्ल का संकेत पाकर काठमाण्डू के समीपवर्ती नुवाकोट पर आक्रमण किया किन्तु जयप्रकाश ने गोरखों की सेना को पीछे हटा दिया। इस पराजय से पृथ्वीनारायण शाह की आँखें खुल गईं और वह लमजुङ आदि के पहाड़ी राजाओं को एक सूत्र में बाँधकर अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह करने लगे और उपत्यका के दर्रों के मार्ग का आना बन्द हो गया। सन् १७४४ में पृथ्वीनारायण शाह ने नुवाकोट मार्ग पर पुनः आक्रमण करके जयप्रकाश को वहाँ से भगा दिया और जयप्रकाश की स्त्री अपने नन्हे शिशु को राजसिंहासन पर बैठाकर राज्य-कार्य संभालने लगी।

इसी बीच में जयप्रकाश को गुह्येश्वरी में शरण मिल गई और सन् १७५ ई में उसने एक सिद्ध महात्मा द्वारा एक खड्ग तथा वरदान प्राप्त करके पुनः अपना राज्य प्राप्त किया



पृथ्वीनारायण शाह

किन्तु विजय पृथ्वीनारायण शाह की हुई और खरपाक नरसी दाता वेउरासी सुनकोसी तथा बागमती पर गोरखा-नरेश का अधिकार हो गया। बाइस-चौबिस राज्यों की सहायता

लेकर सम्मुख आकर न गोरखा राज्य पर सहसा आक्रमण किया और सिहानचोक के मैदान में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ किन्तु इस संग्राम में भी गोरखों की विजय हुई। जयप्रकाश मल्ल का मतार्थी था। वह मारकर भी हताशाहित नहीं हुआ और उसने सरदार दलित्वल्लभ को भारतीय सेना की सहायता से गोरखा राज्य पर फिर आक्रमण किया। इस आक्रमण में कालू पाण्डेय को मौत के घाट उतार दिया। किन्तु सन् १७६१ ६२ ई० तक पृथ्वीनारायण शाह न गोरखा सैनिकों की सहायता से शिवपुरी पनौती चौक कविलासपुर, काभ्रकोट तथा चौकोट पर अपना अधिकार जमा लिया। पृथ्वीनारायण शाह ने मकवानपुर के राजा दिग्बन्धन सेन को बन्दी बनाया किन्तु उसका अमात्य कनकसिंह पकड़ मे नहीं आ सका और उन्होंने बंगाल के नवाब की शरण ली। यह समय बंगाल के नवाब मीर कासिम के लिए बहुत ही संकट का था। उसके राज्य को अंग्रेज हड़प लेने की ताक में बैठे थे। इसलिए उसने सन् १७६३ ई० में अपने सेनापति के साथ साठ हजार सैनिक भेजकर मकवानपुर पर धावा बोल देने के लिए आज्ञा दी। गोरखा सेना भी काजी वंशराज पाण्डेय सरदार नहरि सिंह नाहर सिंह तथा रामकृष्ण के अधिनायकत्व में हरिहरपुर तथा पुराने मकवानपुर की ओर से बढ़ी। मुगल सेना को पहाड़ी प्रान्तों में लड़ने का कुछ भी अनुभव नहीं था इसलिए उसके पैर जल्दी ही उखड़ गये और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। इस विजय में गोरखों को हजारों बन्दूक तथा अन्य अस्त्र शस्त्र हाथ लगे। इसी बीच सम्मुख बार्गों ने भी गोरखा राज्य पर आक्रमण किया किन्तु सूरप्रताप शाह तथा कीर्ति महाराज ने आक्रमणकारियों को बड़ी बुरी तरह पराजित किया।

सन् १७६४ ई० में पृथ्वीनारायण शाह ने कीर्तिपुर पर घेरा डाला। दोनों तरफ की सेनाएँ वर्षों तक घेरा डाले पड़ी रहीं। कीर्तिपुर के बहादुर सैनिक दुर्ग के अन्दर से ही जूझते रहे किन्तु अन्त में विवश होकर कीर्तिपुर वालों को आत्म-समर्पण करना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीनारायण शाह के छोटे भाई सूरप्रताप की आँख फूट गई। कहा जाता है कि भाई की आँख फूट जाने से पृथ्वीनारायण शाह बहुत क्रुद्ध हुए और दुर्ग का पतन होते ही उन्होंने अपने सैनिकों को कीर्तिपुर के नन्हे शिशुओं को छोड़कर सब पुरुषों के नाक-कान काट लेने का हुक्म दिया। महाराजाधिराज की आज्ञा पाते ही सैनिक निकल पड़े और कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने कटी हुई नाकों तथा कानों के ढेर लगा दिये। कतिपय इतिहासकार इस घटना को किंवदन्ती मात्र मानते हैं।

एकाधिपत्य

२९ सितम्बर सन् १७६८ को जयप्रकाश के भागते ही सब सैनिकों को इन्द्र-यात्रा-उत्सव के उत्सव में हनुमान ढोका दरबार में घुसा दिया और इस प्रकार काठमाण्डू नगर स्वामी हो गया। यह दरबार पृथ्वीनारायण शाह ने बिना रक्तपात के ही उस पर विजय प्राप्त कर ली और जयप्रकाश तथा ललितपत्तन के राजा तेज नरसिंह ने भातगाँव में शरण ली।

इस प्रकार कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वीनारायण शाह ने काठमाण्डू तथा पाटन पर आधिपत्य जमा लिया और सन् १७७१ ई० में भादगांव के राजा रणजीत मल्ल के राज्य के लोभी सातों बारह पुत्रों को अपनी ओर मिलाकर भादगांव पर चढ़ाई की और सातों पुत्रों ने भादगांव दरबार आदि पृथ्वीनारायण को दे दिये। इस घमासान लड़ाई में जयप्रकाश बुरी तरह घायल हुए किन्तु अपने अन्तिम काल में भी जयप्रकाश ने आत्मसम्मान को नहीं त्यागा। विजेता पृथ्वीनारायण शाह के बार-बार पूछने पर उस संग्राम-शूर ने भगवान् पशुपतिनाथ को रजतपात्र में जल चढ़ाया तथा एक जोड़ी खड़ाऊं, चमर तथा छाते की साभिप्राय प्रार्थना की। अपनी अन्तिम अभिलाषा की पूर्ति कर अन्न के पश्चात् उसने आर्यघाट में अपने दोनों पैर डाले हुए एक पवित्र शिला पर अपनी अन्तिम श्वास तोड़ी। पृथ्वीनारायण अंग्रेजों के कट्टर शत्रु थे। उन्होंने यूरोपियन मिशनरियों को नेपाल से निकलवा दिया और तिब्बत सरकार को भी इसी प्रकार की नीति धारण करने के लिए उत्प्रेरित किया। उन्होंने भादगांव, पाटन तथा काठमाण्डू पर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी गोरखा से हटाकर काठमाण्डू बनाई और बसन्तपुर दरबार तथा रुद्रमति नदी पर एक पुल बनवाया और राजधानी में एक धर्मशाला भी बनवाई। महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा राज्य की सीमा पश्चिम में कृष्णागण्डकी मध्यगण्डकी त्रिशूल भीमसेन महोदोग पम्पू बुवाकोग अरुण नदी तथा पूर्व में सिक्किम राज्य तक बढ़ाकर सन् १७७४ ई० में गण्डकी नदी के तट पर मोहन तीर्थ में एक सिंह से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। अपने पति के साथ परम साध्वी महारानी भी सती हो गईं।

सन् १७७४ ई० में पृथ्वीनारायण शाह के ज्येष्ठ पुत्र सिंहप्रताप शाह सिंहासन पर बैठे और अपने आराध्य माता-पिता की स्मृति में उन्होंने अपनी माता के सती स्थान पर त्रिपुरेश्वर महादेव की स्थापना करके एक धर्मशाला भी बनवाई। महाराजा पृथ्वीनारायण शाह के सदृश ही राजा सिंहप्रताप शाह भी प्रतापी तथा पराक्रमी थे। महाराजा सिंहप्रताप शाह ने मोरङ्ग नगर को परास्त करके अपने राज्य की सीमा सिक्किम तक विस्तृत कर ली। राजा सिंहप्रताप शाह को यह सफलता साधारणतया नहीं मिली। उन्हें मोरङ्ग प्रदेश से सत्रह बार युद्ध करना पड़ा और अन्त में वह अठारहवीं बार पूर्णरूपेण सफल हुए। वह सिक्किम को भी विजय करना चाहते थे किन्तु उनकी यह अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई और सन् १७७५ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद उनके पुत्र रणबहादुर शाह बाल्यकाल में राजसिंहासन के अधिकारी बने। *उनके अल्पवयस्क काल में उनके चाचा बहादुर शाह संरक्षक रहे किन्तु रणबहादुर की* विधवा राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी देवी ने ही राज्यकार्य संभाला। कुछ वर्षों तक यही प्रबन्ध चलता रहा। राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी देवी को बहादुर शाह पर राज्य हड़पने की आशंका हुई इसलिए उन्होंने बहादुर शाह को बन्दी बना दिया। सन् १७८६ ई० में राजमाता की मृत्यु हो गई। इसके बाद रणबहादुर शाह ने दामोदर पाण्डेय को सेनापति बनाया और

बहादुर शाह फिर वापस आ गये। बहादुर शाह ने पाल्पा के नरेश को प्रलोभन देकर बाइसे चौबिसे राज्य पर आक्रमण करके लम्जुंग समेत सबको विजय किया। उसी वर्ष गोरखों ने तन्ही राज्य पर भी धावा बोल दिया और कामारिदत्त सेन को मारकर तन्ही राज्य के साथ किरात प्रदेश तथा सोमेश्वर तक अपना विजय-केतु फहरा दिया। रणबहादुर शाह की प्रबल अभिलाषा सिक्किम पर विजय प्राप्त करके अपने स्वर्गीय पिता की अन्तिम इच्छा पूरी करने की थी। सन् १७८८ ई० में बहादुर शाह ने अठारह हजार सेना लेकर सिक्किम पर हमला किया और थोड़े ही युद्ध के पश्चात् दक्षिण-पश्चिम का भूभाग जीत लिया। इस पराजय से विचलित होकर सिक्किम-नरेश ने तिब्बत तथा चीन से सहायता मांगी किन्तु उसे सफलता नहीं मिली और अन्त में विवश होकर सिक्किम नरेश को गोरखा सरकार से सन्धि करनी पड़ी। सन्धि के पश्चात् गोरखों ने सिक्किम-निवासियों को लूटा और जब तिब्बत सरकार से गोरखा सरकार से उसे बन्द करवाने की प्रार्थना की तो विजयोन्मत्त गोरखा सरकार ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। फलतः तिब्बतवालों ने तिब्बत में बसे हुए नेपालियों को तंग करना प्रारम्भ किया। इस समाचार को सुनते ही गोरखा सरकार ने तिब्बत पर हमला कर देने की घोषणा की और सरदार बमशाह के अधिनायकत्व में गोरखों की सेना बढ़ चली। दोनों राज्यों की सीमा पर सामान्य लड़ाई हुई और अन्त में गोरखों की विजय हुई। इसके पश्चात् तिब्बती सेना ने कुरुङ्ग तथा दिगर्चा में शरण ली किन्तु नेपाली सेना ने वहां भी उन्हें परास्त किया। सरदार बमशाह का तिब्बत प्रदेश भाया नहीं इसलिए उन्होंने नेपाल सरकार को तिब्बत-सरकार से संधि कर लेने की सम्मति दी। इसकी चर्चा सुनते ही तिब्बत सरकार ने सन्धि-प्रस्ताव पर सहर्ष हस्ताक्षर कर दिए।

चीनी आक्रमण

सन् १७९१ ई० में चीन सरकार ने जनरल फु-कंग-उन के अधिनायकत्व में सत्तर हजार चीनी सैनिकों को भेजकर नेपाल पर आक्रमण किया। जनरल दामोदर पाण्डेय ने गोरखों की सेना लेकर प्रतिरोध किया किन्तु चीनी सैनिकों की असंख्य सेना देखकर कूटनीति से काम लेना चाहा और उन्होंने जनरल फु-कंग-उन के पास सन्धि के लिए अपने चार मंत्रियों को भेजा और साथ ही अपनी सेना को पुनः हमला करने के लिए आज्ञा दी। चीनी सैनिक पानी के अभाव से पहले ही अत्यन्त विकल हो उठे थे। बेत्रावती नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीनी जनरल फु-कंग-उन बहुत ही अधीर हो गया और उसके लोग चलकर चीनी सेना का ही समाप्त करने लगा। इस प्रकार चीनी सैनिकों के पैर उखड़ गये। इस युद्ध में हजारों चीनी सैनिक मारे गये। इस युद्ध में लगभग दो हजार गोरखे सैनिक भी वर्षा से मर गये। अन्त में विवश होकर चीनी सरकार से सन्धि कर ली और नेपाल-सरकार हर पांचवें वर्ष उपहारों के साथ एक शिष्टमण्डल चीन के सम्राट् के पास भेजने के लिए प्रस्तुत हो गई।

नेपाल तथा चीन की इस संधि से प्रभावित होकर १ मार्च सन् १७९२ ई० को भारतीय ब्रिटिश गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस ने नेपाल सरकार से व्यावसायिक संधि का प्रस्ताव किया और कप्तान कर्कपैट्रिक नेपाल में राजदूत नियुक्त किये गये। किन्तु कप्तान कर्कपैट्रिक को काठमाण्डू में देखकर नेपाल सरकार का समस्त अधिकारीवर्ग जल भुन गया और मार्च सन् १७९३ ई० में मेजर कर्कपैट्रिक को काठमाण्डू से हटना पड़ा।

सन् १७९५ ई० में रणबहादुर शाह ने अपने को वयस्क घोषित करके राज्यसूत्र अपने हाथों में ले लिया और अपने दुराकांक्षी चाचा बहादुर शाह को बन्दी बना दिया। उन्होंने दामोदर पाण्डेय को अपना प्रधान मंत्री बनाया।

जनशक्ति का प्रयोग

रणबहादुर शाह ने एक मैथिली ब्राह्मण-कन्या पर आसक्त होकर उससे उत्पन्न पुत्र को राज्याधिकारी बनाने की बात स्वीकार कर उससे विवाह किया और उसे महारानी की उपाधि से विभूषित किया। इस कार्य से समस्त प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। कुछ दिनों के पश्चात् मैथिल महारानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ किन्तु राजवंश में रक्त-विशुद्धता की रक्षा के लिए वसन्तपुर के एक चौतरिया के तीन दिन के शिशु को लाकर महारानी की बगल में सुलाकर बच्चा बदल दिया गया। यह शिशु आगे चलकर गीर्वाण युद्ध शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दो वर्ष बाद मैथिल महारानी को चेचक निकली और रानी ने विवश होकर आत्महत्या कर ली। अपनी प्रिय रानी की मृत्यु से रणबहादुर शाह पागल हो गये और उन्होंने अपनी बड़ी महारानी के पुत्र रणोद्योत शाह तथा अनेक सगोत्रियों की हत्या करा दी। पागल राजा रणबहादुर शाह के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर सन् १८०० ई० में प्रजा ने रणबहादुर शाह को राज्य-च्युत करके शिशु गीर्वाण युद्ध शाह को अपना राजा मान लिया।

नेपाल के इतिहास में यह सर्वप्रथम घटना हुई जब संगठित जनशक्ति ने एक महाराजाधिराज को पदच्युत करके उसके स्थान पर दूसरा उत्तराधिकारी चुना।

महाराजा रणबहादुर शाह की धर्मपत्नी त्रिपुर सुन्दरी अपने पति के साथ काशी चली गई। रणबहादुर शाह ने अपना नाम बदलकर निर्गुणानन्द रख लिया। काशी जाकर स्वामी निर्गुणानन्द एक सुन्दरी के प्रेमपाश में फिर फँस गये और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की साँठ-गाँठ से नेपाल जाकर वहाँ के राजा बनने के स्वप्न फिर से देखने लगे। सन् १८०४ ई० में लार्ड वेल्जली का प्रोत्साहन प्राप्त कर रणबहादुर शाह नेपाल वापस आ गये और उन्होंने शिशु गीर्वाण युद्ध का मुख्तार बनकर भीमसेन थापा को प्रधान मंत्री बना लिया और स्वयं राज्य करने लगे। उन्होंने अपने इस नये शासन-काल में गढ़वाल, कुमायूँ, कांगड़ा तथा पाल्पा इत्यादि को अपने राज्य में मिलाकर राज्य की सीमा विस्तृत कर ली। उन्होंने नेपाल में स्वर्ण-मुद्रा भी प्रथम बार चलवाई।

गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह

सन् १८ ७ ई० में गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह गद्दी पर बैठे। और अपनी प्राचीन आर्य परम्परा को गौरवान्वित करने के लिए 'वीर विक्रम' की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ ली। उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री के लिए थी तीन तथा न्यायाधीशों के लिए काजी इत्यादि की उपाधियां अपने-अपने नाम के साथ जोड़ने की प्रथा चलाई। गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह ने अपने विश्वस्त मंत्री भीमसेन थापा की सहायता से विशृंखल तथा असंगठित गोरखा राज्य को सुसंगठित तथा समुन्नत बनाने के लिए सर्वप्रथम एक 'सैनिक शिविर' की स्थापना की। यों तो गोरखा साम्राज्य के महाराजाधिराज गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह ही थे किन्तु राज्य का सारा शासन-कार्य उनके मंत्री भीमसेन थापा द्वारा ही सम्पादित होता था।

मंत्री भीमसेन थापा महाराष्ट्र के नाना फड़नवीस तथा पंजाब के राजा रणजीतसिंह की भांति कुशल विचारों के शासक थे। उन्होंने सैनिकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए पदसूचक हीरे जवाहरात सोने तथा चांदी के कई प्रकार के चाद तौक बनवाए और नेपाल के प्रधान मंत्री के लिए तीन चान्द्रयुक्त पगड़ी निर्धारित कर दी। केन्द्रीय शासन को विकेन्द्रित करके समस्त राज्य को कई प्रदेशों तथा जिलों में विभाजित किया और प्रत्येक खंड का शासन सुचारु रूप से चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया। इस प्रबन्ध से न्याय शीघ्रतापूर्वक होने लगा और राज्य की आय भी बढ़ गई। उन्होंने राज्य में सड़कें बनवाकर वन प्रान्तों तथा पर्वतीय देश को भी साफ करवाया और उन्हें मनुष्यों के रहने योग्य बनवाया। जंगल की लकड़ियों को बचाने के लिए उन्होंने तराई में जगह-जगह छाव निया भी बनवा दीं।



गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह

महाराजाधिराज गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह तथा भीमसेन थापा की प्रबल अभि लाषा अपने राज्य को एक शक्तिशाली तथा सम्पन्न राष्ट्र बनाने की थी किन्तु संग्राम के बादल घिर आए और गड़गड़ाने लगे। मंत्री भीमसेन थापा नेपाल के शासक थे। वह एशिया में

अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चिंतित हुए। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, अवध, बर्मा तथा भूटान आदि ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी राजाओं को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों को मार भगाने के लिए षडयंत्र खड़ा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सन् १८१३ ई॰ में चीन के सम्राट् से भी वार्तालाप करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयत्न किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह का शासन-काल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके शासन-काल में नेपालियों और अंग्रेजों में बार-बार घमासान युद्ध होते रहे। भारतीय नरेशों और मुगल नवाबों को परास्त कर लेने के बाद अंग्रेजों को अपनी भारतीय सीमा की रक्षा करने की विशेष चिन्ता हुई, किन्तु अंग्रेजों को यह भली भांति विदित था कि गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह के मंत्री भीमसेन थापा जीते-जी अंग्रेजों को नेपाल में पैर नहीं रखने देंगे।

अंग्रेजों से मुठभेड़

सन् १८१४ ई॰ में नेपाली सेना ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शासित तराई के बुटवल तथा शिवराज परगना पर आक्रमण करके उन पर अधिकार जमा लिया। बुटवल तथा शिवराज के परगने पहले पाल्पा राज्य के अंग थे, किन्तु सन् १८०२ ई॰ में अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया था। अंग्रेजों ने गोरखा की सेना गोरखपुर की ओर बढ़ती हुई देखकर गोरखा सरकार को पंचायत द्वारा झगड़ा निपटा लेने के लिए आमन्त्रित किया। तदनुसार अंग्रेजों की ओर से मेजर ब्रेडशा तथा नेपाल की ओर से सुब्बा कुलानंद नियुक्त किये गये। दोनों ओर से समझौते की वार्ता प्रारम्भ हुई। अंग्रेजों का दिल जमा-जमा था, इसलिए अंग्रेज पंच मेजर ब्रेडशा ने सुब्बा कुलानंद को कुछ खरी खोटी सुनाई। फलतः समझौता-वार्ता भंग हो गई और पच्चीस दिन की अवधि के पश्चात् सम्भ्रम सन् १८१४ ई॰ में अंग्रेजों की तीन बटालियन सेना ने आकर बुटवल तथा शिवराज के परगनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, किन्तु अंग्रेजी सेना जब वहां से फिर वापस लौट गई तब नेपाली सेना ने • मई सन् १८१४ ई॰ को उन स्थानों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया।

लार्ड हेस्टिंग्ज को जब यह विश्वास हो गया कि नेपाली बिना अंग्रेजी सेना से लोहा लिए शान्त नहीं होंगे, तो उन्होंने अवध के नवाब को पकड़कर उनसे ढाई करोड़ रुपया वसूल किये और १ नवम्बर, सन् १८१४ ई॰ को नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना के तीस हजार सैनिकों ने सैकड़ों तोपें इत्यादि लेकर पांच मार्गों से नेपाल पर आक्रमण किया और छः सौ मील का उजाड़ क्षेत्र युद्ध-स्थल में परिणत हो गया। इस प्रकार अंग्रेज एक ओर तो नेपालियों से संधि करने का ढोंग कर रहे थे और दूसरी ओर उनका जनरल जिलेस्पी आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित अपनी अंग्रेजी सेना लेकर देहरादून पर हमला करने

की तैयारी कर रहा था। नेपाली सैनिक सरल तथा स्वच्छ हृदय के थे। वह अंग्रेजों की कूटनीति से परिचित नहीं थे। नेपाली सेना को जब जनरल जिलेस्पी की खबर मिली तो उसने कप्तान बलभद्र सिंह के सेनापतित्व में 'नालापानी' के पास कलंगा नामक एक गढ़ बनाकर देहरादून की रक्षा करनी चाही। उस समय कलंगा गढ़ में केवल पाँच सौ के लगभग सैनिक थे। अंग्रेजी सेना कर्नल कारपेण्टर, कप्तान फास्ट, कप्तान कैम्पबेल तथा मेजर केलि के संचालन में कलंगा गढ़ को चारों ओर से तीन दिन तक घेरे रही। इस घेरा के अतिरिक्त पाँचवीं बटालियन मेजर लडलो के साथ आपत्ति-काल के लिए सुरक्षित बैठी थी। चौथे दिन अंग्रेजों की अपार सेना ने कलंगा गढ़ पर तोपों द्वारा गोलाबारी करते हुए भीषण रूप से चढ़ाई की। तब भी गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रमुख संचालक जनरल जिलेस्पी जिसने सपाटियम के साथी को पराजित किया था गढ़ के फाटक पर स्वयं मारा गया। जनरल जिलेस्पी के स्थान पर मेजर जनरल मार्टिन्डेल सेनापति हुआ। उसने बाद ही दिल्ली से चार हजार सैनिक तथा पर्याप्त मात्रा में तोपें इत्यादि मँगवाकर नया घेरा बनाया और कलंगा गढ़ का एक मास तक घेरे रहा। अंग्रेजों ने अनुभव किया कि गोरखा सैनिक अपनी तोपों तथा सेना द्वारा किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं किए जा सकते तो उन्होंने कलंगा गढ़ में जाने वाली पानी की नहर बन्द कर दी। प्यास से नेपाली सैनिक विकल हो उठे लेकिन तब भी प्यासे रहकर ये पाँच दिन तक अंग्रेजी सेना से युद्ध करते रहे और गढ़ के सत्तर नेपाली सैनिक अपने कप्तान बलभद्र सिंह के साथ दस हजार अंग्रेजी सैनिकों को चीरते हुए जीवित निकल गए। कलंगा गढ़ के युद्ध में पाँच सौ नेपाली सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तथा अंग्रेजी सेना के इकतीस आफिसर और सात सौ अट्ठारह सैनिक यमलोक सिधारे। इस घटना का वर्णन आर० सी० विलियम ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में किया है। अंग्रेजों ने अपनी विजय के पश्चात् देहरादून के पास रिस्पना नदी के तट पर जनरल जिलेस्पी तथा कलंगा युद्ध में मरे कप्तान बलभद्र सिंह की दो समाधियाँ बनवा दीं और उनके पास शिलालेख भी लगा दिये जिसमें दोनों की प्रशंसा है।

कलंगा गढ़ युद्ध से अंग्रेजों की आँखें खुल गईं और उन लोगों ने नेपाली सेना से युद्ध करने के पहले 'तोड़-फोड़' की नीति से काम लेना निश्चय किया। इस सत्य को प्राक्टर विल्सन मि० प्रिंसेप तथा सर ईटन ने भी स्वीकार किया है।

कर्नल कारपेण्टर ने पहले जौनसार की प्रजा को भड़काकर अपनी नीति की परीक्षा की और जब समस्त प्रजा ने विद्रोह करके गोरखों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया तो उसने एक अंग्रेज कर्नल को भेजकर पच्छुल माहल सगन्द का भाग पक्ष में मिला लिया। इसके पश्चात् जनरल मार्टिन्डेल ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करके मेजर लडलो तथा मेजर रिचर्ड्स को सेनापति बनाकर जयथक दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया।

अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चिंतित हुए। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, अवध, बर्मा तथा मुगल आदि ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी राजाओं का एक मुट्ठ में बांधकर अंग्रेजों को मार भगाने के लिए षड्यंत्र खड़ा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सन् १८१३ ई० में चीन के सम्राट् से भी वार्तालाप करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयत्न किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह का शासन-काल बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके शासन काल में नेपालियों और अंग्रेजों में बार-बार झगड़े होते रहे। भारतीय मरहठों और मुगल नवाबों को परास्त कर लेने के बाद अंग्रेजों को अपनी भारतीय सीमा की रक्षा करने की विशेष चिन्ता हुई, किन्तु अंग्रेजों को यह भली भांति विदित था कि गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह के मंत्री भीमसेन थापा जीते-जी अंग्रेजों का नेपाल में पैर नहीं रखने देंगे।

अंग्रेजों से मुठभेड़

सन् १८१४ ई० में नेपाली सेना ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शासित तराई के बुटवल तथा शिवराज परगना पर आक्रमण करके उन पर अधिकार जमा लिया। बुटवल तथा शिवराज के परगने पहले पाल्पा राज्य के अंग थे, किन्तु सन् १८०२ ई० में अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया था। अंग्रेजों ने गोरखों की सेना गोरखपुर की ओर बढ़ती हुई देखकर गोरखा सरकार को पंचायत द्वारा झगड़ा निपटा लेने के लिए आमन्त्रित किया। तदनुसार अंग्रेजों की ओर से मेजर ब्रेडशा तथा नेपाल की ओर से मुख्या कुलानंद नियुक्त किए गये। दोनों ओर से समझौते की वार्ता आरम्भ हुई। अंग्रेजों का दिल जला-भुना था, इसलिए अंग्रेज पंच मेजर ब्रेडशा ने मुख्या कुलानंद को कुछ खरी खोटी सुनाई। फलतः समझौता-वार्ता भंग हो गई और पच्चीस दिन की अवधि के पश्चात् मध्य अप्रैल सन् १८१४ ई० में अंग्रेजों की तीन बटालियन सेना ने आकर बुटवल तथा शिवराज के परगनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, किन्तु अंग्रेजी सेना जब वहां से फिर वापस लौट गई तब नेपाली सेना ने मई सन् १८१४ ई० को उन स्थानों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया।

लार्ड हेस्टिंग्ज को जब यह विश्वास हो गया कि नेपाली बिना अंग्रेजी सेना से लोहा लिए शान्त नहीं होंगे, तो उन्होंने अवध के नवाब को पकड़कर उनसे ढाई करोड़ रुपये वसूल किये और १ नवम्बर सन् १८१४ ई० को नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना के तीन हजार सैनिक ने सैकड़ों तोप इत्यादि लेकर पांच मार्गों से नेपाल पर आक्रमण किया और छः सौ मील का उपखण्ड अब युद्ध-स्थल में परिणत हो गया। इस प्रकार अंग्रेज एक ओर तो नेपालियों से संधि करने का ढोंग कर रहे थे और दूसरी ओर उनका जनरल जिलेस्पी आकस्मिक रूप से मुसज्जित अपनी अंग्रेजी सेना लेकर देहरादून पर हमला करने

की तैयारी कर रहा था। नेपाली सैनिक सरल तथा स्वच्छ हृदय के थे। वह अंग्रेजों की कूट कूटनीति से परिचित नहीं थे। नेपाली सेना को जब जनरल जिलेस्पी की खबर मिली तो उसने कप्तान बलभद्र सिंह के अधिनायकत्व में 'नालापानी' के पास कलंगा नामक एक गढ़ बनाकर देहरादून की रक्षा करनी चाही। उस समय कलंगा गढ़ में केवल पांच सौ के लग भग सैनिक थे। अंग्रेजी सेना कर्नल कारपेण्टर, कप्तान फास्ट, कप्तान कैम्पबल तथा मेजर केलि के सञ्चालन में कलंगा गढ़ को चारों ओर से तीन दिन तक घेरे रही। इन चारों के अतिरिक्त पांचवीं बटालियन मेजर कुडला के साथ आपत्ति काल के लिए सुरक्षित बैठी थी। चौथे दिन अंग्रेजों की अपार सेना ने कलंगा गढ़ पर तोपों द्वारा गोलाबारी करते हुए भीषण रूप से चढ़ाई की। तब भी गोरखे सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रमुख संचालक जनरल जिलेस्पी जिसने नेपोलियन के साथी को पराजित किया था गढ़ के फाटक पर स्वयं मारा गया। जनरल जिलेस्पी के स्थान पर मेजर जनरल मार्टिण्ड सेनापति हुआ। उसने आते ही दिल्ली से चार हजार सैनिक तथा पर्याप्त मात्रा में तोपें इत्यादि मंगवाकर नया घेरा बनाया और कलंगा गढ़ को एक मास तक घेरे रहा। अंग्रेजों ने अनुभव किया कि गोरखे सैनिक अंग्रेजी तोपों तथा सेना द्वारा किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं किये जा सकते तो उन्होंने कलंगा गढ़ में आने वाली पानी की नहर बन्द कर दी। पानी न पाने से नेपाली सैनिक विकल हो उठे लेकिन तब भी प्यासे रहकर वे पांच दिन तक अंग्रेजी सेना से युद्ध करते रहे और गढ़ के सत्तर मधस्त नेपाली सैनिक अपने कप्तान बलभद्र सिंह के साथ दस हजार अंग्रेजी सैनिकों को चीरते हुए जीतगढ़ निकल गये। कलंगा गढ़ के युद्ध में पांच सौ नेपाली सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तथा अंग्रेजी सेना के इकतीस आफिसर और सात सौ अठारह सैनिक यमलोक सिधारे। इस घटना का वर्णन आर० सी० विलियम्स ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में किया है। अंग्रेजों ने अपनी विजय के पश्चात् देहरादून के पास रिस्पना नदी के तट पर जनरल जिलेस्पी तथा कफगाल युद्ध में मरे कप्तान बलभद्र सिंह की दो समाधियां बनवा दीं और उनके पास शिलालेख भी लगा दिए जिसमें वीरों की प्रशंसा है।

कलंगा गढ़ युद्ध से अंग्रेजों की आंखें खुल गई और उन लोगों ने नेपाली सेना से युद्ध करने के पहले 'तोड़-फोड़' की नीति से काम लेना निश्चय किया। इस सत्य को आफसर विलियम सि० प्रिंसेप तथा सर हंटर ने भी स्वीकार किया है।

कर्नल कारपेण्टर ने पहले जौनसार की प्रजा को तोड़-फोड़कर अपनी नीति की परीक्षा की और जब समस्त प्रजा ने विद्रोह करके गोरखों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया तो उसने एक अंग्रेज कर्नल को भेजकर पदच्युत नाहन नरेश को अपने पक्ष में मिला लिया। इसके पश्चात् जनरल मार्टिण्ड ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करके मेजर लडलो तथा मेजर रिचर्ड्स को सेनापति बनाकर जयथक दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया।

अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चिंतित हुए। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, अवध, बर्मा तथा भूटान आदि ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी राजाओं को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों को मार भगाने के लिए षड्यंत्र खड़ा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सन् १८१३ ई० में चीन के सम्राट् से भी वार्तालाप करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयत्न किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह का शासन-काल बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उनके शासन-काल में नेपालियों और अंग्रेजों में बार-बार घमासान युद्ध होते रहे। भारतीय नरेशों और मुगल नवाबों को परास्त कर लेने के बाद अंग्रेजों को अपनी भारतीय सीमा की रक्षा करने की विशेष चिन्ता हुई, किन्तु अंग्रेजों को यह भली भांति विदित था कि गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह के मंत्री भीमसेन थापा जीते-जी अंग्रेजों को नेपाल में पैर नहीं रखने देंगे।

अंग्रेजों से मुठभेड़

सन् १८१४ ई० में नेपाली सेना ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शासित तराई के बुटवल तथा सिवराज परगनों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार जमा लिया। बुटवल तथा सिवराज के परगने पहले पाल्पा राज्य के अंग थे, किन्तु सन् १८०२ ई० में अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया था। अंग्रेजों ने गोरखों की सेना गोरखपुर की ओर बढ़ती हुई देखकर गोरखा सरकार को पंचायत द्वारा झगड़ा निपटा लेने के लिए आमन्त्रित किया। तदनुसार अंग्रेजों की ओर से मेजर ब्रैडशा तथा नेपाल की ओर से सुब्बा कुलानंद नियुक्त किये गये। दोनों ओर से समझौते की वार्ता प्रारम्भ हुई। अंग्रेजों का दिल जला-भुना था, इसलिए अंग्रेज पंच मेजर ब्रैडशा ने सुब्बा कुलानंद को कुछ खरी खोटी सुनाई। फलतः समझौता-वार्ता भंग हो गई और पच्चीस दिन की अवधि के पश्चात् सन्ध भाग सन् १८१४ ई० में अंग्रेजों की तीन बटालियन सेना ने आकर बुटवल तथा सिवराज के परगनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, किन्तु अंग्रेजी सेना जब वहां से फिर वापस लौट गई तब नेपाली सेना ने ९ मई सन् १८१४ ई० को उस क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार कर लिया।

लार्ड हेस्टिंग्ज को जब यह विश्वास हो गया कि नेपाली बिना अंग्रेजी सेना से लोहा लिए शान्त नहीं होंगे, तो उन्होंने अवध के नवाब से पकड़कर उनसे ढाई करोड़ रुपये वसूल किये और १ नवम्बर सन् १८१४ ई० को नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना के तीन हजार सैनिकों ने मैकरों तार इत्यादि लेकर पांच मार्गों से नेपाल पर आक्रमण किया और छः सौ मील का उजाड़ क्षेत्र युद्ध-स्थल में परिणत हो गया। इस प्रकार अंग्रेज एक ओर तो नेपालियों से संधि करने का ढोंग कर रहे थे और दूसरी ओर उनका जनरल जिलेस्पी आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित अपनी अंग्रेजी सेना लेकर देहरादून पर हमला करने

हुए, और गोरे सैनिकों ने उनके सीने में संगीन घुसाकर उन्हें मार डाला। मकवानपुर की लड़ाई में और मोरङ्ग में शरणागत शत्रुओं की रक्षा करके अपनी आर्य संस्कृति का तथा गोरों ने इस युद्ध में अपनी बर्बरता का परिचय दिया। इसके पश्चात् अंग्रेजों ने एक-एक करके कुमायूं और गढ़वाल के राजाओं तथा सिक्किम नरेश को घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया और इस प्रकार गढ़वाल-कुमायूं तथा मोरंग को बिना रक्तपात के ही अपने अधिकार में कर लिया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की इस सफलता से नेपाल की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति विचलित हो गई और वह अंग्रेजों से संधि करने के लिए प्रस्तुत हो गई किन्तु राष्ट्र की सच्ची सेवा को समासन्न आसे निर्भीक अमरसिंह थापा ने अपनी सरकार को एक लम्बा पत्र लिखकर उसकी सुप्त आत्मा को प्रबुद्ध कर दिया—जिसके फलस्वरूप संधि का प्रस्ताव ठुकराकर सात मास के पश्चात् युद्ध की पुनः तैयारी होने लगी।

सिगौली की संधि

इधर मकवानपुर के पास कर्नल आक्टरलोनी से अंग्रेजी सेना पहुंचने से ही सज रही थी इसलिए बिना किसी प्रकार के प्रतिरोध के शत्रुओं की सेना मकवानपुर आ धमकी। तब भी रणवीर सिंह ने उनको वहीं पछाड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजी सेना के लिए सहायता आ गई जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सेना ने रणवीर सिंह की सेना को परास्त कर दिया और उसने हरिहरपुर गढ़ी में अपना डेरा जमा लिया। इसके बावजूद भी ८ दिसम्बर, सन् १८१५ ई० को अंग्रेजी सरकार ने एक अष्टसूत्री संधि-प्रस्ताव गीर्वाण महाराजा युद्ध वीर विक्रम शाह के पास भेजा जिसे महाराजा गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह ने १[illegible] दिसम्बर, सन् १८१५ ई० को इसे स्वीकार कर लिया और स्मृति-पत्र लिखकर कोसी तथा राप्ती नदी के बीच की भूमि पर नेपाल का नियमित अधिकार स्वीकार हो गया। यह संधि सिगौली की संधि के नाम से प्रख्यात है। इसके फलस्वरूप नेपाल तथा ब्रिटिश सरकार की सीमावर्ती करम की यो बाम बनी और मेची तथा तिस्ता के मध्य की भूमि सिक्किम राज्य को दे दी गई और राप्ती तथा काली नदियों के बीच की भूमि अंग्रेजी सरकार को मिल गई। इसके बदले में अंग्रेजी सरकार ने दो लाख रुपये प्रतिवर्ष नेपाल के सभा-सामन्तों को पेन्शन के रूप में देना स्वीकार किया। इसके साथ ही एडवर्ड गार्डनर काठमाण्डू में ब्रिटिश रेजीडेन्ट नियुक्त किये गये। इसके कुछ ही समय के पश्चात् महाराजा गीर्वाण युद्ध वीर विक्रम शाह की महामारी से मृत्यु हो गई।

राजेन्द्र वीर विक्रम शाह

राजेन्द्र वीर विक्रम शाह तीन वर्ष की ही अवस्था में राज्य सिंहासन पर बैठाये गये और राजमाता महारानी त्रिपुर सुन्दरी देवी संरक्षक के रूप में कार्य सम्पादन करने लगीं। महारानी ने अंग्रेजों की गृद्ध-दृष्टि नेपाल पर देखकर भीमसेन थापा को प्रधान मंत्री बना

उस समय जयथक दुर्ग की रक्षा का भार जनरल अमरसिंह थापा के पुत्र रणधीर सिंह के ऊपर था। जनरल मार्टिण्डेल ने दस हजार सैनिकों को लेकर जयथक दुर्ग पर आक्रमण किया किन्तु गोरखों ने अंग्रेजी सेना का कठिन प्रतिरोध किया और थोड़े समय में ही अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। इस पराजय से चिढ़कर लार्ड हेस्टिंग्स ने भागे हुए अंग्रेजों को पदच्युत करके जनरल वुड के अधिनायकत्व में बुटवल के पास जीतगढ़ के किले पर हमला करने का आदेश दिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों ने तोपों से गोले छोड़-छोड़ कर गोरखों को भगाना चाहा किन्तु गोरखों ने ही अंग्रेजी सेना के पांच आफिसर तथा एक सौ अट्ठाईस सैनिकों को मारकर अपने राज्य से खदेड़ दिया।

इस हार के बाद कर्नल डेविड आक्टरलोनी ने पंजाब के पर्वतीय राजाओं को घूस देकर अपने पक्ष में किया और वह अपने छः हजार सैनिकों को लेकर मालागढ़ रामगढ़ तथा गढ़मण्डू की ओर बढ़ा। अमरसिंह थापा ने अपने तीन हजार रण बांकुरे सैनिकों को लेकर कर्नल आक्टरलोनी से लोहा लिया। इस घमासान युद्ध में अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गये और उसे विवश होकर नेपाल की सीमा से भाग जाना पड़ा। गोरखों ने अंग्रेजी सेना को अस्त-व्यस्त होकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते देखकर पराजित सैनिकों के साथ मित्रता का व्यवहार किया और हर प्रकार से अपने शत्रुओं की रक्षा की। इस व्यवहार की सराहना मि० प्रिंसेप ने अपनी पुस्तक में मुक्त-कण्ठ से की है।

गोरखों की विजय

इधर अंग्रेजी सेना मकवानपुर तथा सिस्नागढ़ी के पहाड़ी मार्ग से परसा पहुंच गई और वहां से कप्तान सिबलि तथा कप्तान ब्लेकनि ने फौज को दो मार्गों में बांटकर गोरखों को घेर लेना चाहा किन्तु मकवानपुर गढ़ के रक्षकों ने अर्द्धरात्रि में अंग्रेजी सेना पर छापा मारकर हजारों सैनिकों को मार डाला और उनके शस्त्र इत्यादि पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में कप्तान सिबलि की किसी प्रकार जान बच गई किन्तु कप्तान ब्लेकनि तथा हेवन मारे गये।

इस पराजय से अंग्रेजी सेना का गढ़मण्डू पर पुनः आक्रमण करने का साहस जाता रहा किन्तु मालागढ़ के राजा रामशरण ने अंग्रेजी सेना को रसद देकर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया और सामान ले जाने के लिए मकवानपुर से लाहन तक सड़क भी बनवा दी। कर्नल आक्टरलोनी तथा अमरसिंह थापा की सेनाओं में छः मास तक लड़ाई होती रही। अन्त में गोरखाली सेना ने अंग्रेजी सेना को पराजित करके उसे भारत की सीमा में भगा दिया। इसपर भी अंग्रेजों ने साहस नहीं छोड़ा और कर्नल कर्लिंग कर्नल टाम्सन मेजर लेटिरो तथा कप्तान वोचर के अधिनायकत्व में छः हजार अंग्रेजी सैनिकों ने रैला तथा देउथल पर अपना अधिकार जमा लिया। सरदार भक्ति थापा की सेना ने अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में सरदार भक्ति थापा शत्रु की गोली से घायल

शाह ने माथवर सिंह की राजनैतिक कुशलता पर रीझकर उसे कलकत्ते में अपना राजदूत बना दिया। भीमसेन थापा के काठमाण्डू पहुँचने के कुछ ही दिनों के पश्चात् २४ जुलाई, सन् १८३७ ई० को बड़ी महारानी के कनिष्ठ पुत्र की सहसा मृत्यु हो गई और रणजंग पाण्डय ने शिशु की हत्या का अपराध भीमसेन थापा पर मढ़ दिया। इसी अपराध में राजेन्द्र वीर विक्रम शाह ने भीमसेन थापा को बन्दी और रणजंग पाण्डेय को प्रधान मंत्री बना दिया। रणजंग पाण्डय ने प्रधान मंत्री होते ही अंग्रेजों से मिलकर अपनी धाक जमा ली और अंग्रेजों के आदेशानुसार बन्दी भीमसेन थापा को नाना प्रकार की अमानुषिक यातनायें देने लगे। रणजंग पाण्डय का दोष अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सका और राजेन्द्र वीर विक्रम शाह ने महारानी तथा फतहजंग चौतरिया की सहमति से राजगुरु पण्डित रंगनाथ उपाध्याय को प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। पण्डित रंगनाथ उपाध्याय भीमसेन थापा की दूरदर्शिता तथा महत्ता को पूर्ण रूप से समझते थे और इसलिए उन्होंने अपना पद ग्रहण करते ही भीमसेन थापा को मुक्त कर दिया। कलकत्ते में दो वर्ष रहकर भीमसेन थापा के भतीजे माथवर सिंह ने लाहौर दरबार से भी अपना घनिष्ठ सम्पर्क कर लिया और सन् १८३८ ई० में वह लाहौर पहुँचकर सेना का अधिनायकत्व करने लगे। अंग्रेजों को जब यह मालूम हो गया कि माथवर सिंह राजदूत पद पर रहकर सिक्खों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित कर रहे हैं तो उन्होंने राजेन्द्र वीर विक्रम शाह से मिलकर एक चाल चलनी चाही। बारह हजार रुपये वार्षिक भत्ता का प्रलोभन देकर उन्होंने माथवर सिंह को पुनः नेपाल आमन्त्रित करवाया किन्तु स्वाभिमानी माथवर सिंह अंग्रेजों की चाल में नहीं आए और उन्होंने इस भी विफल कर दिया।

शासन में सुधार

प्रधान मंत्री पण्डित रंगनाथ उपाध्याय ने भूमि का सुधार किया तथा 'बिर्ता प्रथा' नष्ट की और सैनिकों की जागीरें समाप्त करके उनके स्थान पर उन्हें वेतन देने की प्रथा चलानी चाही किन्तु रणजंग पाण्डय ने इसके विरुद्ध सेना में विद्रोह करा दिया। फलस्वरूप सन् १८३९ ई० में महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी ने पण्डित रंगनाथ उपाध्याय को हटाकर फिर रणजंग पाण्डय को नेपाल का प्रधान मंत्री बना दिया। प्रधान मंत्री होते ही रणजंग ने वृद्ध भीमसेन थापा को पुनः काल-कोठरी में डाल दिया और अंग्रेजों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने नेपाल-निर्माता उस मनस्वी को अपनी आत्महत्या करने पर बाध्य किया और २९ जुलाई सन् १८३९ ई० को महात्मा भीमसेन थापा ने अपने जीवन का अन्त कर लिया।

अंग्रेजों के शत्रु भीमसेन थापा की मृत्यु का समाचार सुनकर अंग्रेजों को विशेष हर्ष हुआ और उन्होंने प्रधान मंत्री रणजंग पाण्डय से मिलकर अपना हाथ-पैर फैलाना प्रारम्भ कर दिया। सन् १८४३ ई० में बड़ी महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी तथा प्रधान मंत्री रणजंग

लिया। प्रधान मंत्री होते ही भीमसेन थापा राज्य के संगठन-कार्य में संलग्न हो गए। दुर्भाग्यवश इसी वर्ष नेपाल में सत्रह बार भूकम्प आया। महारानी त्रिपुर सुन्दरी देवी की ममता युवराज में अत्यधिक थी इसलिए उन्होंने राजेन्द्र वीर विक्रम शाह का विवाह बाल्यावस्था में ही पाल्पापुर के एक कुलीन क्षत्रिय घराने में कर दिया और अक्तूबर, सन् १८२९ ई० को महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी के गर्भ से युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रमशाह का जन्म हुआ।

सन् १८३२ ई० में महारानी त्रिपुर सुन्दरी देवी की मृत्यु हुई। अगले वर्ष भी नेपाल में चार बार भूकम्प आया। चौथे भूकम्प से मन्दिरों तथा अट्टालिकाओं की विशेष क्षति हुई। और चार सौ के लगभग व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा सात सौ के लगभग व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए।


राजेन्द्र वीर विक्रम शाह

प्रधान मंत्री भीमसेन थापा की भांति महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी भी अंग्रेजों की घोर शत्रु थी। वह पंजाब-केसरी महाराजा रणजीतसिंह से मिलकर अंग्रेजों को भारत से निकाल भगाना चाहती थीं। अंग्रेजों ने महारानी तथा भीमसेन थापा दोनों को एकमत देखकर विग्रह-नीति से काम लेना शुरू किया।

राजेन्द्र वीर विक्रम शाह बड़े अदूर दर्शी तथा कायर स्वभाव के थे। उन्होंने भीमसेन थापा का अंग्रेजों से लोहा लेना देखकर भीमसेन थापा को पद-च्युत करने का निश्चय किया और राजेन्द्र वीर विक्रम शाह ने सन् १८३४ ई० में भीमसेन थापा को राजदूत बनाकर कलकत्ते भेज दिया।

इसी वर्ष राजधानी के शस्त्रागार में भयंकर आग लग गई और इसी चपेट में रेजीडेन्सी भी भस्मीभूत हो गई। शस्त्रागार में आग लगाने का रहस्य रेजीडेन्सी को ही विदित करना अभीष्ट जान पड़ता है। भीमसेन थापा के छोटे भाई रणवीरसिंह अपने बड़े भाई की सम्मति प्राप्त करके संन्यासी होना चाहते थे। किन्तु निःस्वार्थ राष्ट्रसेवी भीमसेन थापा ने रणवीरसिंह की प्रार्थना ठुकरा दी। इससे कुपित होकर रणवीरसिंह अपने भाई भीमसेन थापा के घोर शत्रु हो गए और षड्यन्त्रकारियों से मिलकर उन्होंने भीमसेन थापा का ही सर्वनाश कर डालने का निश्चय कर लिया। सन् १८३६ ई० में राजेन्द्र वीर विक्रम

राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह द्वारा राज-परिवार के अतिरिक्त समस्त प्रजा को कारावास, अंग-छेदन, देश-निर्वासन, पदच्युत तथा प्राणदण्ड देने के अधिकार, राजकर्मचारियों को हटाने तथा नियुक्त करने एवं उनके स्थान तथा पदवी में परिवर्तन करने के अधिकार, और चीन, ब्रिटेन तथा विदेशी शक्तियों से संधि-वार्ता करने तथा विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि-विग्रह करने के पूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिये। शासन-सूत्र पर इस प्रकार पूर्ण अधिकार जमाकर रानी राज्य लक्ष्मी देवी ने बड़ी महारानी के दोनों पुत्रों युवराज सुरेन्द्र तथा कुमार उपेन्द्र को मरवाने का षड्यन्त्र किया जिससे कि उसके अपने गर्भ से उत्पन्न रणेन्द्र वीर विक्रम शाह राज्य का उत्तराधिकारी बन सके किन्तु फत्तह जंग चौतरिया के स्वभाव को देखकर दोनों राजकुमारों की हत्या करवाने का उन्हें साहस नहीं हुआ। इसलिए रानी ने माथबर सिंह को लाहौर से बुलाकर उन्हें २५ दिसम्बर, सन् १८४३ ई० में नेपाल का प्रधान मंत्री तथा सेनापति बना दिया। माथबर सिंह महात्मा भीमसेन थापा के भतीजे थे और वह सेना में बहुत ही प्रिय भी थे। जनता ने उनकी शासन-कुशलता पर रीझकर उन्हें 'कम्मा बहादुर' की उपाधि दी थी। माथबर सिंह ने प्रधान मंत्री का पद सम्भालते ही भीमसेन थापा को पदच्युत तथा बन्दी करानेवाले पाण्डेय वर्ग के विरुद्ध मुकदमा पर भारदारी सभा द्वारा विचार करवाया और करवीर पाण्डेय तथा कुलराज पाण्डेय नामक दो भाइयों के साथ अन्य चार पाण्डेय मंत्रियों का प्राण-दण्ड दिलवाया और जितने भी देश द्रोही पाण्डेय थे उन सबों को नेपाल से निर्वासित करवा दिया। माथबर सिंह की इच्छा रणजंग पाण्डेय को प्राण-दण्ड देने की थी किन्तु वह असाध्य रोग से पीड़ित थे और इसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। रानी राज्य लक्ष्मी देवी शुद्ध विचार की थी। उन्होंने माथबर सिंह



रानी राज्य लक्ष्मी देवी

पाण्डय न छोटी रानी राज्य लक्ष्मी देवी की हत्या करने का विफल प्रयत्न किया। बड़ी महारानी तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत हागसन को भी हटा देना चाहती थी। इस समय नेपाल म चार लाख व्यक्ति सेना मे भर्ती होने के योग्य थे और प्रधान मंत्री रणजंग उन सबों का संगठित करके पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र भी एकत्रित कर रहे थे। इसी बीच में नेपाल के ज्योतिषियो ने यह भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश राज्य का अन्तकाल आ गया। फिर क्या था—गोरखों की विशाल सेना ने चम्पारन की ओर अभियान किया और उसने चम्पारन जिले के इक्यानबे गाँवों को जीतकर दो सौ पच्चीस वर्गमील भूमि पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश रेजीडेन्ट ने कुपित होकर नेपाली सेना को वापस बुलाकर हर्जाना देने के लिए नेपाल-सरकार से कहा किन्तु रानी और रणजंग न उसका कोई उत्तर नही दिया और उल्टे नेपाली सेना म यह समाचार उड़ा दिया गया कि अंग्रेजों की आज्ञा से सैनिकों का वेतन घटा दिया गया है जिसके फलस्वरूप नेपाली सैनिक ब्रिटिश रेजीडेन्सी पर आक्रमण कर बैठे। राजेन्द्र वीर विक्रम शाह ने उन्हें जैसे-तैसे काबू में किया और नेपाली



भीमसेन थापा

सैनिकों का समझा-बुझा कर शान्त कर दिया और तब हो ब्रिटिश रेजीडेन्सी की प्राण रक्षा हो सकी। इस घटना से चिढ़कर वाइसराय लार्ड आकलैण्ड ने युद्ध की चुनौती दी जिसके फलस्वरूप महारानी ने अपनी सेना नेपाल वापिस बुला ली। महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी ग्वालियर जयपुर, जोधपुर बड़ौदा अफगानिस्तान और पंजाब-केसरी रणजीत सिंह के पुत्र दलीपसिंह से सम्पर्क स्थापित करके अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने की कल्पना रात दिन किया करती थी और इसीलिए वह राजेन्द्र वीर विक्रम शाह को भी राज्य छोड़ कर बनारस चले जाने के लिए बाध्य करने लगी। महारानी साम्राज्य लक्ष्मी देवी की उत्कट अभिलाषा अंग्रेजों का भगाने तथा अपने अल्पवयस्क पुत्र को अभिभावक बनकर शासन करने की थी किन्तु ६ अक्तूबर, १८४१ ई० को अंग्रेजों ने महारानी का तराई में विष खिलाकर उनके प्राण ले लिये।

षड्यन्त्र

बड़ी महारानी की मृत्यु से छोटी रानी राज्य लक्ष्मी देवी की बाछें खिल गई और

राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह द्वारा राज-परिवार के अतिरिक्त समस्त प्रजा को कारावास अंग-छेदन देश-निर्वासन पदच्युत तथा प्राणदण्ड देने के अधिकार, राजकर्मचारियों को हटाने तथा नियुक्त करने एवं उनके स्थान तथा पदवी में परिवर्तन करने के अधिकार, और चीन तिब्बत तथा विदेशी शक्तियों से सन्धि-वार्ता करने तथा विदेशी राष्ट्रों के साथ सन्धि-विग्रह करने के पूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिये। शासन-सूत्र पर इस प्रकार पूर्ण अधिकार जमाकर रानी राज्य लक्ष्मी देवी ने बड़ी महारानी के दोनों पुत्रों युवराज सुरेन्द्र तथा कुमार उपेन्द्र को मरवाने का षड्यन्त्र किया जिससे कि उनके अपने गर्भ से उत्पन्न रणेन्द्र वीर विक्रम शाह राज्य का उत्तराधिकारी बन सके किन्तु फतह जंग चौतरिया के स्वभाव को देखकर दोनों राजकुमारों की हत्या करवाने का उन्हें साहस नहीं हुआ। इसलिए रानी ने माथबर सिंह को लाहौर से बुलाकर उन्हें २५ दिसम्बर, सन् १८४३ ई० में नेपाल का प्रधान मंत्री तथा सेनापति बना दिया। माथबर सिंह महात्मा भीमसेन थापा के भतीजे थे और वह सेना में बहुत ही प्रिय भी थे। जनता भी उनकी शासन-कुशलता पर



रानी राज्य लक्ष्मी देवी

रीझकर उन्हें 'सम्मा बहादुर' की उपाधि दी थी। माथबर सिंह ने प्रधान मंत्री का पद सम्हालते ही भीमसेन थापा को पदच्युत तथा बन्दी करानेवाले पाण्डे वर्ग के विरुद्ध मुकदमे पर भारदारी सभा द्वारा विचार करवाया और करवीर पाण्डे तथा कुलराज पाण्डे नामक दो भाइयों के साथ अन्य चार पाण्डे सरदारों को प्राण-दण्ड दिलवाया और जितने भी देश द्रोही पाण्डे थे उन सबों को नेपाल से निर्वासित करवा दिया। माथबर सिंह की इच्छा रणजंग पाण्डे को प्राण-दण्ड देने की थी किन्तु वह असाध्य रोग से पीड़ित थे और इसी में उनकी मृत्यु भी हो गई। रानी राज्य लक्ष्मी देवी क्षुद्र विचार की थी। उन्होंने माथबर सिंह

महाराजाधिराज का परिवार निष्कलंक था और नेपाल की प्रजा उन्हें देव-तुल्य मानती थी। महारानी के आचरण तथा राजेन्द्र वीर विक्रम के स्त्रैण स्वभाव ने शाही मर्यादा की नींव डगमगा दी और उसकी क्षमता में भी लोगों को संदेह हो गया।

सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह

१२ मई,१८४७ ई० को सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह अपने पदच्युत पिता के स्थान पर नेपाल के महाराजाधिराज बनाये गये और प्रधान मंत्री जंग बहादुर अपने सभी भाइयों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित करके अंग्रेजों के इशारों पर नेपाल को नचाते रहे। राजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को उनके युवराज-काल में मार डालने के लिए राज्य लक्ष्मी देवी ने कई बार योजनाएं बनाई थीं और जंग बहादुर ने ही युवराज की प्राण-रक्षा की थी। इसलिए महाराजाधिराज हो जाने पर भी सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह इस बात को भुला नहीं सके और जंग बहादुर पर विश्वास करके उन्होंने शासन का समस्त भार उन्हीं पर सौंप दिया। सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह की इस नीति से लाभ उठाकर जंग बहादुर महाराजाधिराज के नाम से 'लाल मोहर' तथा 'पंजापत्र' का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने लगे और उन्हें जनता के सम्पर्क से वंचित कर दिया। जंग बहादुर को यह पट्टी अंग्रेजों ने इंगलैण्ड में पढ़ाई थी। महाराजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह का शासन-काल केवल इसीलिए बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि जंग बहादुर ने किस प्रकार इसी समय 'राणाशाही' की नींव डाली।

महाराजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह के छोटे भाई उपेन्द्र वीर विक्रम शाह जंग बहादुर की कूटनीति को भली भांति समझते थे किन्तु वह विवश थे। जंग बहादुर ने उपेन्द्र वीर विक्रम शाह को वश में करने के लिए डेढ़ लाख रुपय वार्षिक भत्ते का प्रलोभन दिया किन्तु उन्होंने जंग बहादुर की प्रार्थना ठुकरा दी और वह सन्यासी बनकर जंग बहादुर के विनाश का मार्ग ढूंढ़ने लगे।

सन् १८५४ ई० में तिब्बत वाले तिब्बत में रहने वाले नेपालियों को लूटने-पाटने और बन्दी बनाने लगे। इस अत्याचार को सुनकर महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने फरवरी १८५५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी से एक सन्धि की और तिब्बत सरकार से युद्ध छेड़ दिया। नेपाली सेना तीन मार्गों में बंटकर तिब्बत की ओर बढ़ चली और कुछ ही दिनों के पश्चात् नेपाली सेना ने कुती तथा झुंगा पर अधिकार कर लिया। झुंगा की लड़ाई में प्रकृति ने नेपालियों को कोड़े के बल बचवाये किन्तु तब भी नेपालियों ने तिब्बती सेना को पंटागरी से खदेड़कर भगा दिया और झुंगा दुर्ग तथा मुनाबुम्पा पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अन्त में २४ मार्च १८५६ ई० को तिब्बती सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों राज्यों में संधि हो गई। इस संधि में एक दस-सूत्री प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

१　तिब्बती सरकार दस हजार रुपया वार्षिक गोरखा सरकार को दिया करेगी।

२ गोरखा तथा तिब्बत दोनों राज्य चीनी सम्राट् का आदर करते रहे हैं और तिब्बत देश लामाओं का पूज्य तीर्थ-स्थान है इसलिए गोरखा सरकार को किसी भी राजा द्वारा आक्रमण के समय तिब्बत की सरकार की अपनी शक्ति के अनुसार पूरी-पूरी सहायता करनी पड़ेगी।

३ तिब्बत सरकार गोरखा राज्य के किसी भी नागरिक दूकानदार तथा व्यापारी से किसी भी प्रकार की चुंगी नहीं लेगी।

४ तिब्बत सरकार गोरखा सरकार के सभी बन्दी सिक्खों गोरखा सिपाहियों हाकिमों स्त्रियों तथा बन्दूकों को लौटा देगी और गोरखा सरकार तिब्बत सरकार के सिपाहियों केरुंग कुती भुगा तकलाकोट तथा डेउरा गुम्बा के रैतियों हथियारों याक (चौरी गायों) को वापस कर देगी और वह अपनी सेना को सब जगहों से तुरन्त वापस बुला लेगी।

५ गोरखा सरकार की ओर से एक भारदार ल्हासा में रहेगा।

६ गोरखा सरकार ल्हासा में एक व्यावसायिक कारखाना रखेगी जहाँ से हीरे जवाहरातों से लेकर अन्न-वस्त्र तक स्वतन्त्र रूप से बिका करेंगे।

७ ल्हासास्थित गोरखा भारदार दूकानदारों व्यवसायियों इत्यादि के आपसी झगड़ा में हस्तक्षेप करेगी किन्तु जब गोरखा तथा तिब्बत के नागरिकों में झगड़ा होगा तब दोनों राज्यों के अधिकारी मिलकर उसका निर्णय करेंगे। काश्मीरी तथा गोरखा नागरिकों द्वारा जो आमदनी होगी उसे गोरखा सरकार लेगी तथा तिब्बत के नागरिकों द्वारा जो आमदनी होगी उसे तिब्बत सरकार लेगी।

८ दोनों राज्यों के हत्यारे अपनी-अपनी सरकारों को दे दिये जायेंगे।

९ यदि किसी गोरखा नागरिक अथवा व्यापारी का सामान तिब्बत का कोई नागरिक ले लेगा तो तिब्बती अधिकारी उसे माल दिलाने में सहायता देंगे और यदि माल नहीं मिल सकेगा तो तिब्बती अधिकारी उसके लिए कुछ प्रबन्ध कर देंगे और इसी प्रकार की शर्तें गोरखा अधिकारियों को भी पालन करनी पड़ेंगी।

१० इस सन्धि के फलस्वरूप गोरखा तथा तिब्बती सैनिक शासन के वैमनस्य को भुलाकर इन सरकारों से सहयोग करेंगे।

२५ मई सन् १८५७ ई० को बम बहादुर की मृत्यु हो गई और राजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने जंग बहादुर को पुनः प्रधान मंत्री बनाया। इसी वर्ष भारत में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रथम स्वातन्त्र्य-महायुद्ध छिड़ा जिसे अंग्रेजों ने 'सिपाही विद्रोह' कहकर प्रख्यात किया। इसमें जंग बहादुर ने अंग्रेजों की पूरी सहायता की। इस सहायता के बदले में विद्रोह शान्त होते ही पहली नवम्बर, सन् १८६० ई० को अंग्रेजी सरकार ने नेपाल के महाराजाधिराज से एक नई त्रि-सूत्री संधि की जिस पर १५ नवम्बर, १८६० ई०, को वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल लॉर्ड केनिंग के भी हस्ताक्षर हो गये।

महाराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह के शासन-काल में प्रजा की भलाई के लिए कुछ

भी कार्य नहीं हुआ और हजारों मारने भेड़-बकरियों की भांति 'सिपाही विद्रोह' में कटा दिए गए। सन् १८६ ई में सर्वप्रथम बन्दूक आदि बनाने का एक छोटा-सा कारखाना खोला गया और सन् १८६१ ई० में भूमि का लगान अनाज के रूप में न लेकर नकद रुपये में लेने की विधि बनाई गई और इसी समय से जमींदार चौधरी तथा पटवारी आदि नियुक्त किये गये।

इसके बाद सोलह वर्ष तक जंग बहादुर राणाशाही की ही नींव मजबूत करते रहे और वह अपने परिवार को नेपाल का सर्वस्व बनाने के लिए चारों ओर जाल बिछाते रहे। १० फरवरी सन्१८७६ ई को प्रिंस ऑफ वेल्स को शिकार खेलने के बहाने नेपाल लाया गया और जंग बहादुर के समस्त विरोधियों को अंग्रेजी सेना का भय दिखाकर एक-एक करके कुचल दिया गया।

महाराजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को जंग बहादुर के हाथ की कठपुतली देखकर युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह को बहुत ही दुःख होता था। युवराज त्रैलोक्य को यह भी बिल्कुल पसन्द नहीं था कि जंग बहादुर की पुत्री के साथ उनका अपना विवाह हो किन्तु उन्हें अपने पिता महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह की आज्ञा के सामने नतमस्तक होकर विवाह करना पड़ा। युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह राणा परिवार को हाथ-पैर फैलाते देखकर खून का घूंट पीकर रह जाते थे।

२५ फरवरी १८७७ई को बागमती के तट पर महाराज जंग बहादुर की मृत्यु हो गई। किन्तु जंग बहादुर के उत्तराधिकारी छोटे भाई रणोद्दीप सिंह ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का सूचना महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को नहीं दी। रणोद्दीप को पहले से विदित था कि युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह उसे किसी भी हालत में प्रधान मंत्री नहीं बनने देंगे। इसलिए उन्होंने चाल चलकर युवराज को पत्थरघट्टा की ओर भेज दिया। महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को अकेले राज-दरबार में पाकर रणोद्दीप सिंह ने उनसे पंजा प्राप्त करके उस पर लाल मोहर लगवा ली और अपने को नेपाल का प्रधान मंत्री उद्घोषित कर दिया।

भीमसेन थापा तथा माथवर सिंह की सन्तानें जंग बहादुर के भाइयों एवं पुत्रों से बदला लेना चाहती थीं। दूसरी ओर युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह की बड़ी महारानी भी असन्तुष्ट थीं। परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री रणोद्दीप सिंह आदि का समाप्त करने के लिए योजना बना किन्तु बीच ही में वह काम स्थगित हो गया।

युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह राणा-शासकों की स्वेच्छाचारिता के विरोधी थे। उन्होंने बिना इसे समाप्त किए राजमुकुट नहीं धारण करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रधान मंत्री जनरल रणोद्दीप सिंह तथा सेनापति धीरशमशेर आदि के लिए यह एक बहुत बड़ी बात एवं चुनौती थी। कहा जाता है कि प्रधान मंत्री आदि ने भी युवराज को विष देने का निश्चय किया कि इसी बीच में ३ मार्च सन्१८७८ई को युवराज की मृत्यु हो गई। महाराजा-

धिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने सन् १८८० ई० में प्रधान मंत्री का भार भी व्यक्तियों के साथ बाँट दिया जिन्हें अपने अनुशासन में न रख सकने के कारण रणोद्दीप सिंह की बड़ी बदनामी हुई।

१५ मई सन् १८८१ ई० को महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह तथा ११ जुलाई सन् १८८१ ई० को पश्चात् गजेन्द्र वीर विक्रम शाह की मृत्यु हुई। इसके बाद सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह के पौत्र युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह के पुत्र पृथ्वी वीर विक्रम शाह गद्दी के उत्तराधिकारी हुए।

पृथ्वी वीर विक्रम शाह

१ दिसम्बर, सन् १८८१ ई० को पृथ्वी वीर विक्रम शाह सिंहासनासीन हुए। उस समय महाराजाधिराज की अवस्था ६ वर्ष की थी। इसलिए प्रधान मंत्री जनरल रणोद्दीप सिंह तथा प्रधान सेनापति जनरल धीर शमशेर के हाथों में शासन की बागडोर आ गई। इस में भाई और भतीजों का बढ़ता वर्चस्व तथा राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग देख कर राजधानी के युवकों ने प्रधान मंत्री तथा सेनापति को मार डालने का षड्यन्त्र किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए ब्राह्मण युवकों ने प्रतिज्ञा की। ६ जनवरी सन् १८८२ ई० का दिन इसके लिए निश्चय किया गया किन्तु गगनसिंह के पुत्र कप्तान उत्तरध्वज भंडारी ने इस साम्राज्यिक षड्यन्त्र का रहस्योद्घाटन कर दिया। इसमें राजकुमार नरेन्द्र वीर विक्रम एवं जनक विक्रम सिंह शाह आदि भी सम्मिलित थे।



पृथ्वी वीर विक्रम शाह

प्रधान मंत्री तथा सेनापति ने षड्यन्त्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया और नरेन्द्र वीर विक्रम तथा विक्रम सिंह बन्दी के रूप में बनारस भेज दिए गए और इसमें सम्मिलित ब्राह्मण तथा इस कुलीन ब्राह्मणों ने जाति च्युत होकर जीवन-पर्यन्त कारावास का दण्ड पाया। रणोद्दीप सिंह आदि महाराजाधिराज पर भी प्रतिबन्ध लगाकर उनके नाम पर मनमानी करने लगे। महाराजाधिराज को राणा शासकों ने विलासी बनाकर जनसम्पर्क से सर्वथा वंचित कर दिया और उन्हें किसी किस्सी से भी मिलने का अवसर नहीं दिया जाता था।

महाराज बीर शमशेर ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह पृथ्वी बीर विक्रम शाह से कर दिया और महाराजाधिराज को अपनी प्रथम विवाहिता महारानियों के पास जाने से भी वंचित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नरेश को अपनी कन्याओं के पास ही रहने पर बाध्य कर दिया।

महाराज बीर शमशेर के बाद देव शमशेर प्रधान मंत्री हुए। देव शमशेर तीन महीने के बाद ही पदच्युत कर दिये गये और उनके स्थान पर जनरल चन्द्र शमशेर प्रधान मंत्री बनाए गये।

महाराजाधिराज पृथ्वी बीर विक्रम शाह पर राणा शासकों का विश्वास नहीं था तथापि वे उन्हें अप्रसन्न करने का साहस नहीं कर पाते थे।

त्रिभुवन बीर विक्रम शाह

पृथ्वी बीर विक्रमशाह की बड़ी महारानी लक्ष्मीदेवीजी के गर्भ से ३० जून सन् १९६० को त्रिभुवन बीर विक्रम शाह का जन्म हुआ। महारानी लक्ष्मीदेवीजी हिमांचल प्रदेश के ठाकुर मोतीसिंह की सुपुत्री थी। उन्होंने चार पुत्रियों तथा एक पुत्र रत्न को जन्म दिया।

११ दिसम्बर १९११ ई० को त्रिभुवन बीर विक्रम शाह ५ वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठाये गये। इसके तीन वर्ष बाद यूरोपीय महासमर प्रारम्भ हुआ। इस महायुद्ध में महाराज चन्द्र शमशेर ने गोरखों की बहुत बड़ी सेना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए भेजी।

प्रधान मंत्री चन्द्र शमशेर ने बालक त्रिभुवन को अपनी देख रेख में रखा। वह उनको विलासी और अकर्मण्य बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहे, किन्तु किशोर त्रिभुवन खरे ही उतरे। उनकी अभिरुचि विद्याध्ययन की ओर थी और समस साधन प्रस्तुत न होने पर भी वह प्रौढ़ावस्था में पदार्पण करते-करते विश्व की श्रेष्ठ पुस्तकों में अवगत हो गये। नेपाली हिन्दी संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का भी आपने ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वह व्यायाम कुश्ती संगीत तथा फोटोग्राफी में भी विशेष रुचि रखने लगे।

सन् १९१ ई० में उनका विवाह एक भारतीय राजपूत ठाकुर अर्जुनसिंह की दो पुत्रियां कान्ति राजलक्ष्मी देवी तथा ईश्वरी राजलक्ष्मी देवी से एक साथ ही सम्पन्न हुआ। सन् १९२० ई० में महारानी कान्ति राजलक्ष्मी देवी के गर्भ से युवराज महेन्द्र बीर विक्रम शाह का जन्म हुआ।

इसके पश्चात् द्वितीय राजकुमार हिमालय बीर विक्रम शाह का जन्म सन्१९२५ई० में तथा तृतीय राजकुमार बसुन्धरा बीर विक्रम शाह का जन्म सन् १९२७ई० में हुआ।

महाराज चन्द्र शमशेर ने त्रिभुवन बीर विक्रम शाह देव की बड़ी बहन का विवाह जनरल कैसर शमशेर द्वितीय बड़ी बहन का विवाह जनरल सिंह शमशेर तथा तृतीय और

चतुर्थ बहनों का विवाह जनरल कृष्ण शमशेर तथा जनरल शूर शमशेर के साथ सम्पन्न करवाये। इन वैवाहिक सम्बन्धों के पीछे महाराज चन्द्र शमशेर की एक कूटनीति थी जिसके ज़रिये वह शाही परिवार को शासक-वर्ग से बांध देना चाहते थे।

२१ दिसम्बर, सन् १९२३ ई० को नेपाल सरकार ने ब्रिटिश सरकार से एक स्पष्ट मैत्री संधि की और नेपाल को एक स्वतन्त्र देश घोषित करवा लिया।



त्रिभुवन वीर विक्रम शाह

महाराज चन्द्र शमशेर की मृत्यु के पश्चात् महाराजाधिराज ने भीम शमशेर और तत्पश्चात् युद्ध शमशेर को प्रधान मंत्री बनाया। इस समय तरुण नेपाल प्रजा परिषद् के समर्थक थे और वह सफल व्यायाम-शिक्षक धर्मभक्त के द्वारा इस संस्था की प्रगति के सम्बन्ध में अपने विचार भी दिया करते थे। प्रधान मंत्री युद्ध शमशेर तथा भीम शमशेर राजकुमार एवं राजकुमारियों का विवाह अपने ही परिवार में करना चाहते थे फलस्वरूप युवराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह का विवाह जनरल हरि शमशेर की कन्या तथा द्वितीय एवं तृतीय राजकुमारों के विवाह जनरल नर शमशेर की पुत्रियों के साथ सम्पन्न हुए। राजकुमारियों के विवाह नरेश ने भारत में किये।

दिसम्बर सन् १९४५ ई० में महाराज युद्ध शमशेर के राज्य-त्याग के पश्चात् महाराजाधिराज ने भीम शमशेर के पुत्र जनरल पद्म शमशेर को नेपाल का प्रधान मंत्री बनाया। वह शासन में सुधार करना चाहते थे इसलिए महाराज चन्द्र शमशेर के पुत्रों ने उन्हें त्यागपत्र दे देने के लिए बाध्य किया और सेनापति जनरल मोहन शमशेर नेपाल के प्रधान मंत्री बनाये गये।

नेपाली जनता की भांति महाराजाधिराज भी राणा शासकों से अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे और जब उनको ठीक अवसर मिल गया तब उन्होंने अवसर पाते ही राणा शासन के खिलाफ़ महान काम किया। नरेश के इस निर्णय का स्वागत दल-विहीन सभी ने किया और प्रधान मंत्री जनरल मोहन शमशेर को फिर से त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव को नेपाल का वास्तविक शासक मान लेना पड़ा।

सशस्त्र क्रान्ति के पश्चात् भी नरेश ने महाराज मोहन शमशेर को ही प्रधान मंत्री

बनाया। यद्यपि यह सरकार बहुत दिन तक टिक नहीं सकी और मंत्रिमण्डल में कई उलट फेर हुए। इस प्रकार कई मंत्रिमण्डल भंग होने के बावजूद श्री महाराजाधिराज धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश की जनता अब भी उन्हें राष्ट्र का प्रतीक मानती है।

युवराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह एक सुन्दर विचार के होनहार युवक हैं। महाराजाधिराज की उपस्थिति-अनुपस्थिति में वह बराबर शासन-कार्य में अभिरुचि रखते हैं। नये नेपाल को अपने युवराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह से बहुत बड़ी आशायें हैं।

श्री पांच महाराजाधिराज के दाहिने पंजे की पांचों उंगलियों का छाप 'पंजापत्र' कहलाता है। नरेश के पास श्री पच नामक एक हार भी होता है जो बहुत अमूल्य माना जाता है। उनका अपना एक स्वतन्त्र ध्वज है जिसके बीच में एक शेर का चिन्ह रहता है। श्री पांच महाराजाधिराज को इक्कीस तोपों की सलामी दी जाती है। उनकी प्रशस्ति तथा सलामी इस प्रकार है—



युवराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह

प्रशस्ति

स्वस्ति श्री गिरिराजचक्रचूडामणिनरनारायणेत्यादि विविध विरुदावलि विराजमान मानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल तारा ओं राम पट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अति प्रबल गोरखा दक्षिणबाहु महाधिपति सर्वोच्च कमाण्डर-इन-चीफ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराज त्रिभुवन वीर विक्रम जंग बहादुर शाह बहादुर शमशेर जंग देवानां सदा समर विजयीनाम्।

सलामी

श्रीमान् गम्भीर यशस्वी प्रबल प्रतापी भूपति
श्री पांच सर्कार महाराजाधिराज को सदा रहोस उन्नति

राजन् चिरायु ईश से प्रजा कसिम्योस् पुकारौं जय प्रेम से,
हामी नेपाली भाई सारा ले,
गरी सारा हुराकन् शांत होऊन सब विघ्न व्यथा
गाऊन्, सारा दुनियाले सुपूर्व नायको सुकीर्ति कथा
राखौं कमान भारी वीरता से नेपाल नामी सर्व नाव को
भी होस् ठूलो हामी नेपाली को।

नेपाल के महाराजाधिराज

द्रव्य शाह १५५९—१५७०
पुरन्दर शाह १५७०—१६०५
छत्र शाह १६०५—१६०९
राम शाह १६ ९—१६३३
डम्बर शाह १६३३—१६४२
कृष्ण शाह १६४२—१६५८
रुद्र शाह १६५८—१६६९
पृथ्वीपति शाह १६६९—१७१६
वीरभद्र शाह १७१६
नरभूपाल शाह १७१६—१७४२
पृथ्वी नारायण शाह १७४२—१७७४
सिंह प्रताप शाह १७७४—१७७७
रण बहादुर शाह १७७७—१७९९
गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह १७९९—१८१६
राजेन्द्र वीर विक्रम शाह १८१६—१८४७
सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह १८४७—१८८१
त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह १८८१
पृथ्वी वीर विक्रम शाह १८८१—१९११
त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ११ दिसम्बर १ ११

६

राणाओं का शासन-काल

नेपाल का शासन यद्यपि वहां के शाही परिवार के नाम से ही चलता चला आ रहा है वास्तव में गत एक सौ चार वर्षों से वहां के शासन की बागडोर राणा परिवार के हाथों में रही है। इस राणाशाही शासन का अन्त महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव द्वारा भारतीय दूतावास में ६ नवम्बर, सन् १९५ के दिन शरण लेने के फलस्वरूप स्वतन्त्रता-आन्दोलन के उठ खड़े होने के कारण हो सका। राणाशाही का इतिहास रक्तरंजित षड्यन्त्रों आदि से भरा पड़ा है। एशिया के किसी भी अन्य देश का इतिहास इस प्रकार रोमांचकारी नहीं है।

यह राणाशाही शासन सन् १८४६ ई. से प्रारम्भ हुआ जब जंग बहादुर नामक एक व्यक्ति नेपाल के प्रधान मंत्री बने। उन्होंने धीरे-धीरे शासन की समस्त शक्ति अपने हाथों में कर ली और अन्त में वास्तविक शासक बनकर प्रजा की सहायता से महाराज भी बन गए।

जंग बहादुर का जन्म अपनी ननिहाल बोर्लांग में १८ जनवरी सन् १८१७ ई. को हुआ। उनके प्रपितामह रामकृष्ण कुंवर गोरखाली सेना में एक साधारण सैनिक थे और वह उन्नति करके पृथ्वी नारायण शाह के अंगरक्षक हो गये थे। रामकृष्ण कुंवर के पुत्र रणजीत कुंवर के पुत्र बाल नरसिंह कुंवर हुए। बाल नरसिंह की दो पत्नियां थी। मंझली स्त्री के गर्भ से वीर नरसिंह जंग बहादुर, बद्री नरसिंह, रणोद्दीप सिंह, रण शमशेर, जगत शमशेर तथा धीर शमशेर नाम के सात पुत्र उत्पन्न हुए। वीर नरसिंह बाद में जंग बहादुर के नाम से प्रख्यात हुए। वह अधिकतर अपनी ननिहाल में ही रहा करते थे। ननिहाल के लोग उनकी दुष्टता देखकर उन्हें जंग नाम से पुकारते थे। उनकी ननिहाल के लोग बहुत ही दरिद्र थे इसलिए जंग को अपनी ननिहाल में भी भूखों रहकर भेड़-बकरियां चरानी पड़ती थी।

जंग बहादुर का बाल्यकाल

अपने पिता की मृत्यु के बाद जंग बहादुर अपने मामा मामाभाली सगा काजी के घर में रहकर विषम बातें करते थे। जंग बहादुर के समकालीन युवराज सुरेन्द्र विक्रम शाह बहुत ही उद्दण्ड प्रकृति के व्यक्ति थे और पुरस्कार रख-रखकर कुछ न कुछ कौतुक करवाया करते थे। जंग बहादुर बचपन से ही सब प्रकार के उपद्रवों में रत रहते थे, इसलिए वह युवराज के उन सभी कौतुकों में विशेष भाग लेने लगे। जंग बहादुर बड़े साहसी भी थे इसलिए वह पुरस्कार की लालच में अपने प्राण तक पर खेल जाते थे। युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने एक दिन ऊंचे बांध पर चढ़कर एक संकीर्ण पुल को पार करने के लिए

पुरस्कार रखा। जंग बहादुर तुरंत ही उस घोड़े पर सवार होकर पुल को पार कर गये और उन्होंने पुरस्कार पा लिया।

इसी प्रकार युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने एक गहरे कुएँ में कूदने के लिए पुरस्कार घोषित किया। उसमें भी जंग बहादुर ने अपने साहस का परिचय देकर पुरस्कार पा लिया। उन्होंने एक प्रमत्त हाथी को भी अपने वश में करके राजकीय पुरस्कार प्राप्त किया।

जंग बहादुर बहुत मनमौजी प्रकृति के भी थे और उनकी युवावस्था कुसंगति में व्यतीत हुई थी। उनके सब साथी भी वैसे ही थे और वह अपना अधिक समय जुआ खेलने तथा मदिरा-पान करने में बिताया करते थे। जंग बहादुर अपने उन्हीं साथियों के साथ कुव्यसनों में फँसे रहते थे इसीलिए उन्हें सदा ही पैसे के लिए मुहताज रहना पड़ता था। उनके एक जुआरी साथी ने उनसे अपने पैसे माँगे। पैसे नहीं पाने पर उसके साथी ने जंग बहादुर को मारकर बेदम करके एक गन्दी नाली में ढकेल दिया। दैवात उसी मार्ग से काठमाण्डू के एक उदार व्यक्ति जा रहे थे जिनका नाम धननारायण था। धननारायण को जंग बहादुर की यह दुर्दशा देखकर बड़ी दया आई और उन्होंने उन्हें नाली से निकालकर जंग बहादुर ने जो ऋण लिया था उसे चुका दिया। इसके पश्चात् जंग बहादुर धननारायण के यहाँ रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद वह तराई में भाग गये। वहाँ पहुँचकर जंग बहादुर जंगली हाथी बध कर धनोपार्जन करने लगे। तराई में कुछ दिन रहने के बाद वह ऋण के बोझ से ऊब कर काशी भाग गये और वहाँ उन्होंने एक प्रसिद्ध गुण्डे के यहाँ नौकरी कर ली। वहाँ वह कुछ दिन शहर की दरबानी किया करते थे। दैवात् एक दिन उन्हीं के मालिक के दल तथा एक अन्य गुण्डा दल में मारपीट हो गई। उसमें जंग बहादुर भी सम्मिलित हो गये। वह उस समय नशे में थे इसलिए उन्होंने विरोधी दल के एक व्यक्ति की जान ले डाली और जंग बहादुर भयभीत होकर बनारस छोड़कर नेपाल की तराई में भाग गये।

माथबर सिंह

उसी समय जंग बहादुर के मामा माथबर सिंह लाहौर से बुलाकर नेपाल के प्रधान मंत्री बनाये गये। माथबर सिंह ने जंग बहादुर की अवस्था बहुत ही दयनीय देखकर उन्हें नेपाली सेना में एक सूबेदार बना दिया। माथबर सिंह उन दिनों भारतीयों को संगठित कर के अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में थे और इस काम के लिए उन्हें अपने समर्थकों से सम्पर्क स्थापित करना तथा उनसे विचार-विमर्श करना पड़ता था। माथबर सिंह बहुत विश्वासी स्वभाव के थे और वह अपने भान्जे जंग बहादुर को बराबर अपने साथ लिए रहते थे। जंग बहादुर ने माथबर सिंह के सम्पर्क में रहते रहते उनकी प्रत्येक गतिविधि को पूर्ण रूप से समझ लिया था। उन्हीं दिनों राजभंडारी गगनसिंह का सम्बन्ध महारानी राज्य लक्ष्मी देवी से हो गया था और इस प्रकार वह महारानी के विश्वासपात्र

बन गए। जंग बहादुर ने गगनसिंह का महारानी पर प्रभाव देखकर उनसे मित्रता कर ली और वह अपने मामा माथबर सिंह की बातें गगनसिंह को बता देने लगे।

गगनसिंह अंग्रेजों के विश्वासपात्र थे इसलिए वह अंग्रेजों के खिलाफत की सभी बातें ब्रिटिश रेजीडेन्ट से कह सुनाते थे। गगनसिंह बहुत डरपोक प्रकृति के थे और वह राजेन्द्र वीर विक्रम शाह को भी माथबर सिंह की अंग्रेज-विरोधी सम्पूर्ण योजनाओं को सुना-सुना कर प्रकम्पित करते रहते थे। गगनसिंह ने राजेन्द्र वीर विक्रम शाह के कान भर दिये कि माथबर सिंह की कार्यवाहियों से नेपाल पर भयानक आपत्तियां आने की सम्भावना है। साथ ही गगनसिंह ने अंग्रेजों के इशारों पर महारानी राज्य लक्ष्मी देवी से माथबर सिंह की हत्या करवा देने के लिए कहा। माथबर सिंह की हत्या करवाने के लिए ब्रिटिश रेजीडेन्ट ने गगनसिंह तथा जंग बहादुर को प्रलोभन दिया और जंग बहादुर अपने मामा माथबर सिंह को मार डालने के लिए उद्यत होगए। १८ मई सन् १८४५ ई० को महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने बीमारी का बहाना करके माथबर सिंह को अपने महल में बुलवाया और उसी समय जंग बहादुर ने अपने मामा माथबर सिंह को गोली से उड़ा दिया। मंत्रणा का इतने से संतोष नहीं हुआ और ब्रिटिश रेजीडेन्ट को प्रसन्न करने के अभिप्राय से जंग बहादुर ने अपने मामा माथबर सिंह के शव को एक हाथी के पैर में बंधवा कर पशुपति तक घसिटवाया। जंग बहादुर के इस कृत्य से महारानी राज्य लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने जंग बहादुर को 'कर्नल' का पद दिलवाया।

प्रथम मन्त्रिमण्डल

प्रधान मंत्री माथबर सिंह की मृत्यु के पश्चात् महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने अपने समर्थक गगनसिंह को प्रधान मंत्री बनाना चाहा किन्तु महाराजाधिराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाह फतह जंग चौतरिया को प्रधान मंत्री बनाने के पक्ष में थे। अन्त में भारदार सभा ने दोनों को सन्तुष्ट करने के विचार से चार काजी अथवा मंत्री नियुक्त किये। इस प्रकार गगनसिंह तथा जंग बहादुर दोनों को काजी बनवाकर महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने उनसे युवराज सुरेन्द्र तथा राजकुमार उपेन्द्र की हत्या करने के लिए कहा।

जंग बहादुर को जब यह विश्वास होगया कि महारानी दोनों राजकुमारों की हत्या करवाकर ही शान्त होंगी तो उन्होंने महाराजाधिराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाह से सब रहस्यों का उद्घाटन बड़ी ही चतुरतापूर्वक कर दिया और महारानी को इसका पता तक न चल सका। राजेन्द्र वीर विक्रम शाह को जब यह विदित होगया कि महारानी राज्य लक्ष्मी देवी का अनुचित सम्बन्ध गगनसिंह से है तो उन्होंने जंग बहादुर को अपना लिया और वह उन्हीं के द्वारा गगनसिंह को मरवा डालने की योजना बनाने लगे। जंग बहादुर को यह चिन्ता सर्वदा सताया करती थी कि जबतक गगनसिंह जीवित रहेंगे तब तक उनकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध ही रहेगा।

गगनसिंह के यहाँ विजयराज नाम का एक व्यक्ति रहा करते थे जो जंग बहादुर के पुरोहित मित्र थे। जंग बहादुर इन्हीं विजयराज की सहायता से गगनसिंह की गतिविधि का पूरा पता लगाते रहते थे और १४ सितम्बर, सन् १८४६ ई० को जब गगनसिंह पूजा कर रहे थे तब जंग बहादुर के साथी लाखन ने उन्हें गोली मार दी।

गगनसिंह की हत्या का समाचार सुनकर महारानी राज्यलक्ष्मी देवी पागल-सी हो गईं। पहले उन्हें जंग बहादुर पर शंका हुई किन्तु जंग बहादुर ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों तथा अनुनय-विनय से महारानी की शंका निर्मूल सिद्ध कर दी। महारानी राज्यलक्ष्मी देवी की प्रतिहिंसात्मक भावनायें चैन नहीं लेने देती थीं इसलिए अगले दिन १५ सितम्बर, सन् १८४६ ई० को महारानी ने जंग बहादुर के मतानुसार भारदार सभा के सभी सदस्यों को रात्रि में कोत अथवा राजमहल में उपस्थित होने की आज्ञा दी। इसी समय जंग बहादुर ब्रिटिश रेजीडेन्ट कालविन का आदेश लेकर अपने भाइयों के साथ जा पहुँचे और बाहर कोत को तीन पल्टन सैनिकों से घिरवा दिया। महाराजाधिराज राजेन्द्र और विक्रम शाह के समक्ष गगनसिंह की हत्या का प्रसंग छेड़ा गया और महारानी ने दीवार की आड़ से काजी अभिमान को आज्ञा दी कि वृजकिशोर पाण्डेय को पकड़ो। इन्होंने ही गगनसिंह की हत्या की है। अभिमान राणा ने महारानी की आज्ञा पालन की। वृजकिशोर पाण्डेय ने जब देखा कि महारानी क्रोध से पागल हो गई हैं तो तुरन्त राजेन्द्र और विक्रम शाह से निवेदन किया कि मैं निरपराध हूँ। वृजकिशोर की प्रार्थना सुनकर महाराजाधिराज ने आज्ञा दी कि वृजकिशोर पाण्डेय को अभी छोड़ दो। इसका मुकदमा न्यायालय द्वारा निर्णीत होगा। यह आज्ञा देकर फतहजंग चौतरिया के साथ राजेन्द्र और विक्रम शाह कोत के बाहर हो गये किन्तु कोत के बाहर जंग बहादुर की पल्टन देखकर उन्हें शंका हो गई और वह उल्टे पैर वापस आ गये। वह तुरन्त ब्रिटिश रेजीडेन्सी की ओर रवाना हो गये। ब्रिटिश रेजीडेन्ट कालविन को सब बातों का पूरा पता पहले से ही था और उसे किसी प्रकार यह भी ज्ञात था कि यह दोनों उसके पास किस कारण से आये हैं। इसलिए उसने ड्योढ़ी के अन्दर से कहला दिया कि हम सूर्यास्त के बाद रात्रि में किसी भी विदेशी से भेंट नहीं करते, आओ प्रातः काल आना।

इधर कोत में महाराजाधिराज की आज्ञा पाकर काजी अभिमान राणा ने वृजकिशोर पाण्डेय को छोड़ दिया। इस पर महारानी क्रोध से व्यग्र हो उठीं और उन्होंने जंग बहादुर को आज्ञा दे दी कि वृजकिशोर तथा अभिमान राणा दोनों को काट डालो। उसी समय काजी फतहजंग चौतरिया भी कोत में आये और अभिमान राणा जंग बहादुर की पल्टन को देखने के लिए बाहर आये। जब जंग बहादुर ने देखा कि परिस्थिति विषमतम हो उठी है तो वह कोत के बाहर आ गये और राजेन्द्र और विक्रम शाह से सब वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी सलाह दिया कि हम लोगों की रक्षा तभी हो सकती है जब आप महारानी को कैद करा लें। उधर कोत में फतहजंग चौतरिया थे ही। इसलिए महारानी ने उनसे आप भी

शब्दों में पूछा कि गगनसिंह के हत्यारे का पता चला कि नहीं। इस प्रश्न को सुनकर फतहजंग चौतरिया ने कहा कि आप इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिये और मैं शीघ्रातिशीघ्र हत्यारे का पता लगाकर उसे आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। महारानी क्रोध में पागल हो रही थी इसलिए उन्होंने फतहजंग चौतरिया की एक भी न सुनी और वह बार-बार यही कहती रही कि हत्यारे को तुरंत लाकर मेरे सामने खड़ा करो। जंग बहादुर ने देखा कि परिस्थिति भीषणतर होती जा रही है, इसलिए उन्हें यह भय होने लगा कि अब मैं भी इसी में फंस जाऊंगा। उसी समय अभिमान राणा ने महारानी से कोत के बाहर जाने की आज्ञा मांगी किन्तु महारानी ने अभिमान राणा के तुरंत गोली मार देने की आज्ञा दी। अभिमान राणा कोत के फाटक तक भी नहीं पहुंच पाये थे कि जंग बहादुर के छोटे भाई रणदीप कुंवर ने अपनी खुकरी से उन्हें घायल कर दिया। अभिमान राणा ने मूर्छित होते-होते यह कह ही दिया कि गगनसिंह के हत्यारे जंग बहादुर हैं। इस बात को सुनते ही फतहजंग ने भी कहा कि गगनसिंह की हत्या करने वाले जंग बहादुर ही हैं और यह कहकर वह वहां से चल पड़े।

जब जंग बहादुर ने देखा कि वह स्वयं फंसे जा रहे हैं तो उन्होंने महारानी के समक्ष कहा कि इससे आपको धोखा हो सकता है। साथ ही उन्होंने अपने सिपाही रामसिंह अधिकारी को फतहजंग पर गोली चला देने के लिए संकेत कर दिया। जंग बहादुर के संकेत पाते ही रामसिंह की गोलियां फतहजंग तथा उनके समीप ही खड़े दलभंजन पाण्डेय के शरीर में घुस गईं और वे दोनों वहीं ढेर हो गये। उसी समय जंग बहादुर ने अपने भाइयों को संकेत कर दिया कि वह फतहजंग के पुत्र खड्ग विक्रम को भी समाप्त कर दें। इस पर धीर शमशेर ने खड्ग विक्रम का सर धड़ से अलग कर दिया।

इसके बाद जंग बहादुर ने अपने सभी सशस्त्र सैनिकों को कोत में बुला लिया और वहां उपस्थित सभी भारदारों को काट डालने के लिए आज्ञा दे दी। एक घण्टे के भीतर सभी भारदारों का अन्त कर दिया गया। इस प्रकार जंग बहादुर ने थापा पाण्डेय शाह बस्नेत भंडारी बिष्ट तथा अमर वंश के सभी श्रेष्ठ पुरुषों का समाप्त करवा दिया और कोत-हत्याकाण्ड में सैकड़ों निरपराध श्रेष्ठजनों की अमानुषिक हत्या हुई।

नरसंहार को देखकर महारानी का हृदय कुछ शान्त हुआ और उन्होंने जंग बहादुर को आज्ञा दी कि युवराज सुरेन्द्र तथा उपेन्द्र को लाकर इस दृश्य को दिखा दो। महारानी की आज्ञा पाते ही जंग बहादुर दोनों राजकुमारों को लेकर कोत में उपस्थित हो गये और महारानी ने पुनः भी पास बिलखते हुए दोनों राजकुमारों को राज्य छोड़कर भाग जाने की सम्मति दी।

इसके पश्चात् जंग बहादुर ने महारानी राज्य लक्ष्मी देवी के समक्ष दोनों चरण टेक कर यह शपथ ली कि वह जीवनपर्यन्त उनकी ही आज्ञा का पालन करते रहेंगे। कोत-हत्याकाण्ड के पश्चात् जंग बहादुर कोत के बाहर भी रक्तपात करते रहकर बहुत ही

भयभीत हो गये और वह रात्रि में ही कोठ से निकल भागे। प्रातःकाल होते ही जब महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने सुना कि जंग बहादुर डरकर कहीं भाग गय हैं तो उन्होंने जंग बहादुर को खोजने के लिए चारों ओर अपने सिपाहियों को भेजा। जंग बहादुर छिपकर काशी मार्ग तक पहुंच चुके थे किन्तु महारानी के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और महारानी राज्य लक्ष्मी देवी के समक्ष उपस्थित किया। जंग बहादुर को भयभीत देखकर महारानी ने कहा कि अब कापुरुष की भांति क्यों भागते हो चलो मैं तुम्हें नेपाल का प्रधान मंत्री बनाती हूं।

महारानी के कहने पर दूसरे दिन १६ सितम्बर, सन् १८४६ ई० को जंग बहादुर महाराजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह के पास गये और उनसे अपने को प्रधान मंत्री घोषित किये जाने के लिए कहने लगे किन्तु राजेन्द्र वीर विक्रम शाह जंग बहादुर को देखकर और भी चिन्ता उठे और स्वयम् पाल्पा की ओर चले गये। राज्य लक्ष्मी देवी ने जब सुना कि महाराजाधिराज जंग बहादुर से बहुत रुष्ट हैं तो उन्होंने राजेन्द्र वीर विक्रम शाह की कुछ भी परवाह न करके १८ सितम्बर, सन् १८४६ ई० को स्वयं ही पल्टन की कवायद में सम्मिलित होकर जंग बहादुर को नेपाल का प्रधान मंत्री घोषित कर दिया।

प्रधान मंत्री हो जाने के बाद जंग बहादुर में महान् परिवर्तन आया। उन्होंने ब्रिटिश रेजीडेंट से घनिष्ठता और भी बढ़ा ली और वह ब्रिटिश रेजीडेंट कालविन की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने तथा अंग्रेज-विरोधी तत्त्वों को एक-एक करके कुचलने लगे।

जंग बहादुर ने कोत-हत्याकाण्ड में मारे हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति हड़प ली और उनके वंशजों को नेपाल से निर्वासित कर दिया।

महारानी राज्य लक्ष्मी देवी को अपने पति राजेन्द्र वीर विक्रम शाह से भय होने लगा कि वह हमें कोत-हत्याकाण्ड का दण्ड देकर ही रहेंगे इसलिए उन्होंने जंग बहादुर से मिलकर अपने बचने का मार्ग ढूंढ निकालने का निश्चय किया। जब जंग बहादुर ने देखा कि महारानी का स्वभाव विचित्र हो गया है और पता नहीं वह कब क्या कर बैठें तो वह एक-न-एक बहाना करके महारानी की बातों को टालने लगे। महारानी युवराज सुरेन्द्र तथा राजकुमार उपेन्द्र की हत्या करवाकर अपने पुत्र रणेन्द्र को जबर्दस्ती राजा बनाने पर तुली हुई थीं किन्तु जंग बहादुर यह नहीं चाहते थे। वह युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह की सहायता करके उन्हें गद्दी पर बिठाकर अपने पैर जमाना चाहते थे। जंग बहादुर ने जब देखा कि महारानी बड़ी शक्तिशाली होती जा रही हैं तो उन्होंने महाराजाधिराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाह के पास अपने भाई रणोद्दीपसिंह को पाल्पा भेजकर बुलवा लिया। महारानी राज्य लक्ष्मी देवी को जब यह भली भांति विदित हो गया कि जंग बहादुर विश्वासघात करना चाहते हैं तो उन्होंने जंग बहादुर को मरवाकर काजी वीर ध्वज बस्नेत को प्रधान मंत्री बनाने की ठानी।

बताया जाता है कि महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने काजी वीर बस्नेत से कहा कि

गज्दी ने पूछा कि गगनसिंह के हत्यारे का पता चला कि नहीं। इस प्रश्न को सुनकर फतहजंग चौतरिया ने कहा कि आप इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिये और मैं शीघ्रातिशीघ्र हत्यारे का पता लगाकर उसे आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। महारानी क्रोध में पागल हो रही थी इसलिए उन्होंने फतहजंग चौतरिया की एक भी न सुनी और वह बार-बार यही कहती रहीं कि *हत्यारे को तुरंत लाकर मेरे सामने खड़ा करो।* जंग बहादुर ने देखा कि परिस्थिति भीषणतर होती जा रही है, इसलिए उन्हें यह भय होने लगा कि अब मैं भी इसी में फंस जाऊंगा। उसी समय अभिमान राना ने महारानी से कोत के बाहर जाने की आज्ञा मांगी किन्तु महारानी ने अभिमान राना के तुरंत गोली मार देने की आज्ञा दी। अभिमान राना कोत के फाटक तक भी नहीं पहुंच पाये थे कि जंग बहादुर के छोटे भाई रणोद्दीप कुंवर ने अपनी खुकरी से उन्हें घायल कर दिया। अभिमान राना ने मूर्छित होते-होते यह कह ही दिया कि गगनसिंह के हत्यारे जंग बहादुर हैं। इस बात को सुनते ही फतहजंग ने भी कहा कि गगनसिंह की हत्या करने वाले जंग बहादुर ही हैं और यह कहकर वह वहां से चल पड़े।

जब जंग बहादुर ने देखा कि वह स्वयं फंसे जा रहे हैं तो उन्होंने महारानी के समक्ष कहा कि इसमें आपको धोखा हो सकता है। साथ ही उन्होंने अपने सिपाही रामसिंहिर अधिकारी को फतहजंग पर गोली चला देने के लिए संकेत कर दिया। जंग बहादुर का संकेत पाते ही रामसिंहिर की गोलियां फतहजंग तथा उनके समीप ही खड़े दलभंजन पाण्डेय के शरीर में घुस गईं और वे दोनों वहीं ढेर हो गये। उसी समय जंग बहादुर ने अपने भाइयों को संकेत कर दिया कि वह फतहजंग के पुत्र खड्ग विक्रम को भी समाप्त कर दें। इस पर धीर शमशेर ने खड्ग विक्रम का सर धड़ से अलग कर दिया।

इसके बाद जंग बहादुर ने अपने सभी सशस्त्र सैनिकों को कोत में बुला लिया और वहां उपस्थित सभी भारदारों को काट डालने के लिए आज्ञा दे दी। एक घंटे के भीतर सभी भारदारों का अन्त कर दिया गया। इस प्रकार जंग बहादुर ने पाण्डेय, शाह, बस्नेत, भंडारी, बिष्ट तथा थापा वंश के सभी श्रेष्ठ पुरुषों को समाप्त करवा दिया और कोत-हत्याकाण्ड में सैकड़ों निरपराध श्रेष्ठजनों की अमानुषिक हत्या हुई।

नरसंहार को देखकर महारानी का हृदय कुछ शान्त हुआ और उन्होंने जंग बहादुर को आज्ञा दी कि युवराज सुरेन्द्र तथा उपेन्द्र को लाकर इस दृश्य को दिखा दो। महारानी की आज्ञा पाते ही जंग बहादुर दोनों राजकुमारों को लेकर कोत में उपस्थित हो गये और महारानी ने खून की धारा दिखलाते हुए दोनों राजकुमारों को राज्य छोड़कर भाग जाने की सम्मति दी।

इसके पश्चात् जंग बहादुर ने महारानी राज्य लक्ष्मी देवी के समक्ष दोनों घुटने टेक कर यह शपथ ली कि वह जीवनपर्यन्त उनकी ही आज्ञा का पालन करते रहेंगे। कोत-हत्याकाण्ड के पश्चात् जंग बहादुर कोत के बाहर भी रक्तधारा बहते देखकर बहुत ही

भयभीत हो गये और वह रात्रि में ही कोट से निकल भागे। प्रातःकाल होते ही जब महा-रानी राज्य लक्ष्मी देवी ने सुना कि जंग बहादुर डरकर कहीं भाग गये हैं तो उन्होंने जंग बहादुर को खोजने के लिए चारों ओर अपने सिपाहियों को भेजा। जंग बहादुर छिपकर काली भाटी तक पहुँच चुके थे किन्तु महारानी के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और महारानी राज्य लक्ष्मी देवी के समक्ष उपस्थित किया। जंग बहादुर को भयभीत देखकर महारानी ने कहा कि अब कापुरुष की भाँति क्यों भागते हो, चलो मैं तुम्हें नेपाल का प्रधान मंत्री बनाती हूँ।

महारानी के कहने पर दूसरे दिन १५ सितम्बर, सन् १८४६ ई० को जंग बहादुर महाराजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह के पास गये और उनसे अपने को प्रधान मंत्री घोषित किए जाने के लिए कहने लगे किन्तु राजेन्द्र वीर विक्रम शाह जंग बहादुर को देखकर जोर से चिल्ला उठे और स्वयम् पाटन की ओर चले गये। राज्य लक्ष्मी देवी ने जब सुना कि महाराजाधिराज जंग बहादुर से बहुत रुष्ट हैं तो उन्होंने राजेन्द्र वीर विक्रम शाह की कुछ भी परवाह न करके १८ सितम्बर, सन् १८४६ ई० को स्वयं ही पल्टन की कवायद में सम्मिलित होकर जंग बहादुर को नेपाल का प्रधान मंत्री घोषित कर दिया।

प्रधान मंत्री हो जाने के बाद जंग बहादुर में महान् परिवर्तन आया। उन्होंने ब्रिटिश रेजीडेंट से घनिष्ठता और भी बढ़ा ली और वह ब्रिटिश रेजीडेंट कालविन की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने तथा अंग्रेज-विरोधी तत्वों को एक-एक करके कुचलने लगे।

जंग बहादुर ने कोत-हत्याकाण्ड में मारे हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति हड़प ली और उनके वंशजों को नेपाल से निर्वासित कर दिया।

महारानी राज्य लक्ष्मी देवी को अपने पति राजेन्द्र वीर विक्रम शाह से भय होने लगा कि वह हमें कोत-हत्याकाण्ड का दण्ड देकर ही रहेंगे इसलिए उन्होंने जंग बहादुर से मिलकर अपने बचने का मार्ग ढूंढ़ निकालने का निश्चय किया। जब जंग बहादुर ने देखा कि महारानी का स्वभाव विचित्र हो गया है और पता नहीं वह कब क्या कर बैठें तो वह एक-न-एक बहाना करके महारानी की बातों को टालने लगे। महारानी युवराज सुरेन्द्र तथा राजकुमार उपेन्द्र की हत्या करवाकर अपने पुत्र रणेन्द्र को जबर्दस्ती राजा बनाने पर तुली हुई थीं किन्तु जंग बहादुर यह नहीं चाहते थे। वह युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह की सहायता करके उन्हें गद्दी पर बिठाकर अपने पैर जमाना चाहते थे। जंग बहादुर ने जब देखा कि महारानी बड़ी शक्तिशाली होती जा रही हैं तो उन्होंने महाराजाधिराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाह के पास अपने भाई रणोद्दीपसिंह को पत्र भेजकर बुलवा लिया। महारानी राज्य लक्ष्मी देवी को जब यह भली भाँति विदित हो गया कि जंग बहादुर विश्वासघात करना चाहते हैं तो उन्होंने जंग बहादुर को मरवाकर काजी वीर ध्वज बस्नेत को प्रधान मंत्री बनाने की ठानी।

बताया जाता है कि महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने काजी वीर बस्नेत से कहा कि

यह इस तरह का एक षड्यंत्र रचे कि वह जंग बहादुर और उसके भाइयों को साथ लेकर युवराज और उसके भाई राजकुमार के महल में सोने और रात्रि में दोनों राजकुमारों की हत्या करके चला आवे और हत्या का अभियोग जंग बहादुर तथा उनके भाइयों के सिर मढ़ दे।

जंग बहादुर ने गगनसिंह राजभंडारी की हत्या गगनसिंह के अनन्य साथी पंडित विजयराज की ही सहायता से की थी। तभी से जंग बहादुर और विजयराज में बहुत घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो गया था। महारानी राज्य लक्ष्मी देवी के राजमहल में अनेक दासियां रहा करती थीं और उन दासियों से विजयराज का घनिष्ठ सम्बन्ध था। जंग बहादुर के कहने पर विजयराज महारानी के राजमहल की खबरें प्रतिदिन जंग बहादुर को देते रहते थे और एक दिन जब विजयराज को एक दासी द्वारा यह पता चल गया कि महारानी राज्य लक्ष्मी देवी जंग बहादुर को भी मरवा डालना चाहती हैं तो उन्होंने जंग बहादुर को सावधान कर दिया।

सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह

महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने निश्चय किया कि एक दिन जंग बहादुर तथा उनके सभी भाइयों को दरबार में बुलाया जाय और वहीं उन सबों का वध करवा दिया जाय। फलतः २ नवम्बर सन् १८४६ ई० को महारानी राज्य लक्ष्मी देवी ने अपने महल में कुछ सैनिकों को पहले से ही नियुक्त करके जंग बहादुर तथा उनके सभी भाइयों को बुला भेजा। जंग बहादुर को मार डालने की सूचना युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को भी थी इसलिए वह भी जंग बहादुर की सहायता करने के लिए पूरी तैयारी में थे। महारानी ने वीर ध्वज बस्नेत को जंग बहादुर तथा उनके भाइयों को बुलाने के लिए भेजा। महारानी का बुलावा मिलते ही जंग बहादुर अपने भाइयों तथा राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह को लेकर भी सशस्त्र सैनिकों के साथ राज्य-प्रासाद में जा पहुंचे। जंग बहादुर ने जब देखा कि राजमहल में उन्हें तथा उनके भाइयों को मार डालने के लिए सैनिक सन्नद्ध हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को यह आज्ञा दे दी कि सब को तुरंत मार डालो। जंग बहादुर की आज्ञा पाते ही उनके सैनिकों ने महल में छिपे हुए सभी सैनिकों को मारना प्रारम्भ कर दिया और कुछ ही क्षणों में लगभग तेईस व्यक्ति मारकर ढेर कर दिये। यह हत्याकांड 'भंडारखाल-हत्याकांड' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात् महारानी लक्ष्मी देवी को बन्दिनी बना लिया गया। युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने महारानी को अपने भरण-पोषण के लिए बावन लाख रुपया देकर २३ नवम्बर, सन् १८४६ ई० को बनारस भेज दिया। राज्य लक्ष्मी देवी के साथ महाराजाधिराज राजेन्द्र वीर विक्रम तथा राजकुमार रणेन्द्र तथा वीरेन्द्र भी बनारस चले गये। इस प्रकार जंग बहादुर सफल हो गये और युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नेपाल के सर्वेसर्वा बन बैठे।

जंग बहादुर ने 'कोत-हत्याकाण्ड' तथा 'भंडारखाल-हत्याकाण्ड' में सभी योग्य सामन्तों की मृत्यु के बाद अपने भाई बम बहादुर कुंवर को उपप्रधान मंत्री, बद्री नरसिंह कुंवर को सेनापति, कृष्ण बहादुर कुंवर को शासन प्रबन्धकर्ता तथा जगत शमशेर तथा धीर शमशेर को मंत्री बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने भाइयों के सभी पुत्रों तथा भतीजों को कर्नल बनाया और पुराने राजगुरु के वंश को हटाकर अपने मित्र पंडित तथा उनके सम्बन्धियों को राजगुरु और राजपुरोहित के पदों पर विभूषित किया। इस प्रकार जंग बहादुर ने अपने परिवार के सब सदस्यों तथा समर्थकों का एक जाल-सा फैलाकर नेपाल की राजनीति को अपनी व्यक्तिगत वस्तु बना लिया और धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी नाम कमाने लगे।

जंग बहादुर की विदेश-यात्रा

बनारस पहुँचकर महाराजाधिराज राजेन्द्र वीर विक्रम शाह को बहुत पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने अपने दो सिपाहियों को पिस्तौल देकर जंग बहादुर को मारने के लिए काठमाण्डू भेजा। वहाँ पहुँचते ही दोनों सिपाही पकड़ लिये गये और जंग बहादुर ने मार डाला तथा अन्य सामन्तों आदि तीन सौ सत्तर व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेकर राजेन्द्र वीर विक्रम शाह के पास एक धमकी-भरा पत्र भेजा कि देश की समस्त प्रजा तथा भारदारों इत्यादि ने युवराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को अपना महाराजाधिराज बनाने का निश्चय कर लिया है। इस पत्र को देखते ही राजेन्द्र वीर विक्रम शाह बहुत जल-भुन गये और वह अपनी थोड़ी-सी सेना लेकर काठमाण्डू के लिए चल पड़े। नेपाल की तराई में जंग बहादुर ने पहले से ही राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह के सेनानायकत्व में चार हजार सैनिक नियुक्त कर रखे थे और २८ अप्रैल सन् १८४६ ई० को ज्यों ही राजेन्द्र वीर विक्रम शाह की सेना वहाँ पहुँची वैसे ही राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह ने उस पर आक्रमण कर दिया और अनेक सिपाहियों को मारकर बहुतों को भगा दिया। इसके बाद राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह ने अपने पिता राजेन्द्र वीर विक्रम शाह को बंदी बनाकर काठमाण्डू भेज दिया और १२ मई सन् १८४६ ई०, को जंग बहादुर ने भारदारों के द्वारा उन्हें पदच्युत करके भक्तपुर के किले में जीवनपर्यन्त बन्दी बना रखने की सम्मति दे दी। इसके बाद जंग बहादुर ने सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को महाराजाधिराज घोषित कर दिया। जंग बहादुर बहुत ही कम शिक्षित होते हुए भी बड़े दूरदर्शी थे और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। उन्हें अपनी नीति और कूटनीति पर पूरा भरोसा था और स्वदेश छोड़कर बाहर जाने में उन्हें जरा भी आशंका नहीं हुई। वह [illegible] के साथ १५ जनवरी सन् १८५० ई० को अपने भाई जगत शमशेर और धीर शमशेर तथा कतिपय भारदारों के साथ इंगलैंड चले गये। इंगलैंड में जंग बहादुर ने महारानी विक्टोरिया से लेकर साधारण से साधारण व्यक्तियों को प्रभावित किया और थोड़े ही दिनों में उन्होंने

सभी महान् व्यक्तियों से घनिष्ठ संपर्क बढ़ा लिया। इसके बाद महाराज जंग बहादुर वहां से फ्रांस तथा स्विटजरलैंड भी गये। फ्रांस में उन्होंने एक लाख सैनिकों की परेड भी देखी।

भारत लौटकर उन्होंने देश में प्रायश्चितस्वरूप रामेश्वरम् तथा काशी आदि तीर्थ-स्थानों के दर्शन किये। इस प्रकार एक वर्ष विदेश भ्रमण के पश्चात् ६ फरवरी सन् १८५१ को जंग बहादुर नेपाल वापस लौटे और अपने भाई बम बहादुर से अपना कार्यभार लेकर फिर शासन करने लगे। यूरोप से वापस आने के बाद उनकी शासन-पद्धति परिवर्तित हो गई और वह कौम का कानून पसन्द बनाने में कटिबद्ध हो गये।

राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह ने जंग बहादुर के भाई बद्री नरसिंह तथा उनके छोटे पुत्र जय बहादुर कंवर को मिलाकर महाराज जंग बहादुर को पदच्युत तथा पद च्युत करने का प्रयास किया।

इस पर महाराज जंग बहादुर ने राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह पर सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह को हटाकर उनके भाई बद्री नरसिंह कंवर तथा उसके छोटे चचेरे भाई जय बहादुर कंवर इत्यादि की सहायता से स्वयं नेपाल का महाराजाधिराज बनने का दोषारोपण किया। इसी बहाने उन्होंने सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह द्वारा राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम तथा बद्री नरसिंह तथा जय बहादुर कंवर को नेपाल से निर्वासित करके प्रयाग के दुर्ग में बन्दी बनवा दिया। कुछ दिनों के पश्चात् इलाहाबाद के किले में जय बहादुर कंवर की मृत्यु हो गई और राजकुमार उपेन्द्र वीर विक्रम शाह तथा बद्री नरसिंह मुक्त कर दिए गये। जंग बहादुर ने बड़े लाख रुपये भत्ता देने का प्रलोभन देकर उपेन्द्र वीर विक्रम शाह को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहा किन्तु राजकुमार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

प्रधान मंत्री जंग बहादुर की उनकी कमजोरी का भंडाफोड़ करने वाले करवीर क्षत्रिय से बड़ी शत्रुता थी। इसलिए उन्होंने एक षड्यन्त्र द्वारा करवीर का बहुत अनादर कराया और अन्त में उसकी हत्या भी करवा दी। ब्रिटिश रेजीडेंट का अपमान करने के अपराध में जंग बहादुर ने चनम अमृत नामक एक राष्ट्राभिमानी युवक की बांह की टांग से बांधकर पशुपतिनाथ पर मरवा डाला।

उन्होंने अपने बड़े बाबा के नाम के साथ अपने बाबा कंवर की उपाधि छोड़कर 'राणा' की उपाधि लगाना प्रारम्भ किया और तभी से राणा वंश प्रकाश में आया।

महाराज जंग बहादुर बहुत अनुभवी तथा व्यवहारकुशल व्यक्ति थे। उन्होंने अपने भाइयों तथा भतीजों के विवाह कुलीन वंशों में करके अपना विवाह कुंदु राज्य की कन्या तथा पुर प्रसाद शाह चौतरिया की पुत्री राजकुमारी हिरण्यगर्भा देवी से किया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जगत जंग तथा मझले पुत्र जीत जंग का विवाह महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह की पुत्रियों से करके अपने राणा और महाराजाधिराज के शाही परिवार को मिश्रित कर दिया।

प्रधान मंत्री ने थोड़े ही समय में शाही परिवार को अपने वश में कर लिया। उन्होंने महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह से स्वयं जीवनपर्यन्त प्रधान मंत्री बने रहने का ताम्रपत्र लिखवा लिया और अपने भाइयों को संतुष्ट रखने के लिए प्रधान मंत्री पद के लिए पिता से पुत्र को मिलने के बजाय बड़े भाई से छोटे भाई को क्रम से प्राप्त होने का नियम बनाया। इस प्रकार उन्होंने 'राणाशाही' की नींव सुदृढ़ की। इसके बाद जंग बहादुर ने महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह से 'लाल मोहर' भी प्राप्त करली और अपनी इच्छानुसार किसी को भी हटाने तथा नियुक्त करने का संपूर्ण अधिकार स्वयं ले लिया।

चीनी सम्राट् की शक्ति देखकर जंग बहादुर ने १० फरवरी सन् १८५५ ई० को ईस्ट इण्डिया कम्पनी से जी-सुली एक संधि की। छोटे भाई बम बहादुर को संतुष्ट रखने के लिए उन्होंने १ अगस्त सन् १८५६ ई० को प्रधान मंत्री पद से त्यागपत्र देकर बम बहादुर को प्रधान मंत्री बनाया और कास्की तथा लमजुंग की जागीरें प्राप्त करके अपने नाम के साथ 'महाराज' की उपाधि लगाई।

बम बहादुर की मृत्यु के बाद जंग बहादुर ने नियमानुसार बम बहादुर के छोटे भाई को प्रधान मंत्री का पद न देकर स्वयं फिर से नेपाल के प्रधान मंत्री बन गये।

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम

सन् १८५७ ई० में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जब भारत में प्रथम स्वातन्त्र्य-युद्ध नाना साहब पेशवा आदि ने छेड़ा तो जंग बहादुर ने 'सिपाही विद्रोह' को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता करने का निश्चय किया। भारदारों की समस्त सभा तथा भारदार इस नीति के घोर विरोधी थे। उन्होंने जंग बहादुर को मार डालने की योजना बनाई किन्तु ब्रिटिश रेजीडेंट की 'कूट नीति' के फलस्वरूप जंग बहादुर की विजय हुई और अगस्त सन् १८५७ ई० में तीन हजार गोरखा सैनिकों को विवश होकर भारतीय विद्रोही देशभक्तों के विरुद्ध अंग्रेजी सत्ता की रक्षा करने के लिए भारत जाना पड़ा। जंग बहादुर को भारत पहुँचने पर स्वयम् भी भारतीय विप्लवकारियों से मिल जाने की आशंका थी। नेपाली सैनिकों को लेकर जंग बहादुर ने हिन्दुओं के पवित्र धाम अयोध्या होकर सर कोलिन कैम्पबल के साथ लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। दिसम्बर, सन् १८५७ ई० में जंग बहादुर ने नेपाल से नौ हजार और गोरखा सैनिकों को बुलवाया और जनरल फ्रैंक्स तथा गोरखाओं के साथ बनारस के उत्तर तथा अवध के पूर्व के विप्लवकारियों को दबाने के लिए धावा बोला।

२५ फरवरी सन् १८५८ ई० को जंग बहादुर की सेना ने अंग्रेजी सेना के साथ घाघरा नदी पार करके अम्बरपुर दुर्ग पर आक्रमण किया और पचासों विप्लवकारियों को तोपों से मारकर दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया। मार्च के द्वितीय सप्ताह में जंग बहादुर और फ्रैंक्स की सेनाओं ने पूर्व की ओर से तथा सर कालिन कैम्पबल की

सेना ने पश्चिम में कानपुर की ओर से लखनऊ पर हमला किया। अवध के विप्लव कारियों ने सन् १८५८ ई० के जून से नवम्बर तथा सन् १८५९ ई० के नवम्बर से १८६०



महाराज जंग बहादुर

के अप्रैल तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे। अन्त में विवश होकर भारतीय विप्लवकारियों को भारत से भागकर नेपाल में शरण लेनी पड़ी। विप्लवकारियों के नेता नाना साहब

एवं नाना साहब आदि ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद नेपाल-नरेश को भारत का भी अधिनायक शासन का वचन दिया। तब भी जंग बहादुर को निर्भीक होकर इन्हें शरण देने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने कूटनीति से काम लिया और कतिपय बागियों को अंग्रेजों को सौंपकर अधिकांश को नेपाल तराई तथा पहाड़ों में छिपा दिया। नेपाली जनता ने विद्रोहियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और वे काफी अरसे तक नेपाल में रहे। महाराज जंग बहादुर ने नाना साहब पेशवा आदि को कुछ गांव और पेन्शन आदि भी दिये।

नेपाली सेना ने गदर को दबाने में तत्परता से अंग्रेजों की सहायता की जिससे प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने जंग बहादुर को 'सर' की उपाधि दी। अप्रैल सन् १८७२ में चीन के बादशाह ने भी उन्हें उपाधि दी।

जंग बहादुर ने अपनी तीन पुत्रियों का विवाह महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह के पुत्र युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह से करके उन्हें अपने वश में कर लिया।

महाराज जंग बहादुर महत्त्वाकांक्षी तथा शक्तिशाली थे। उन्होंने समग्र देश के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो काल एवं परिस्थिति के अनुसार बड़ा ही अनुकूल माना जाता रहा। उन्होंने नेपाल में तीस वर्ष तक शासन किया और अपने तथा अपनी संतानों के लिए प्रचुर सम्पत्ति तथा हीरे-जवाहरात आदि जमा किये।

राजेन्द्र वीर विक्रम शाह तथा राज्य लक्ष्मी देवी के आपसी मतभेद से जंग बहादुर ने काफी फायदा उठाया। उन्होंने अपने धैर्य और साहस का परिचय देकर देश की मनोवृत्ति को अभिभूत कर लिया। अंग्रेजी सरकार को भी इस क्रान्ति-काल में जंग बहादुर को परखने का अच्छा मौका मिला।

साठ वर्ष की अपनी अन्तिम अवस्था में वह नेपाल की तराई में शिकार खेलने आये और पथरघट्टा नामक स्थान के आसपास २५ फरवरी, सन् १८७७ ई० को उनकी मृत्यु हो गई। महाराज जंग बहादुर के शव को बागमती तट पर लाया गया जहां उनकी धर्मपत्नी महारानी हिरण्यगर्भा देवी अपने पति के साथ सती हो गईं। उनके साथ ही अन्य चिताओं पर दो अविवाहिता रखेलियां भी सती हुईं।

रणोद्दीपसिंह

महाराज जंग बहादुर की मृत्यु के पश्चात् उनके पांचवें भाई जनरल रणोद्दीपसिंह बावन वर्ष की आयु में प्रधान मंत्री तथा धीर शमशेर सेनापति हुए। धीर शमशेर ने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त करके काफी नाम कमाया। कार्तिक सन् १८८४ ई० में उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय सेनानी धीर शमशेर ने अपने सत्रह पुत्रों को 'बिसनी तलवार—हमारा दरबार' का उपदेश दिया और इसका पालन उनके सभी पुत्र जीवनपर्यन्त करते रहे।

प्रधान मंत्री रणोद्दीपसिंह त्यागी तथा सत्ताहीन थे। वह योग्य शासक भी नहीं थे। शासन में कमजोरी आने के कारण उनके भाई और उच्चाधिकारी आदि असंतुष्ट थे और वे उनको हटाकर योग्य शासक चाहते थे। परिस्थिति से लाभ उठाकर जंग बहादुर के पुत्रों ने धीर शमशेर के सभी पुत्रों को समाप्त कर डालने का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के अगुवा जगत जंग तथा युद्ध प्रताप जंग थे। धीर शमशेर की संतानों को इसका पता लग गया और वे रणोद्दीपसिंह के पास गये किन्तु उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। परिणामस्वरूप धीर शमशेर के पुत्रों ने रणोद्दीपसिंह तथा जंग बहादुर के पुत्रों की हत्या का षड्यंत्र किया। महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाह की माता भी पांच महारानी की छोटी बहन कांछी मैया खड्ग शमशेर की मौसी थी और वह रणोद्दीपसिंह की हत्या की साजिश में शामिल होकर खड्ग शमशेर को प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहती थी।

२२ नवम्बर, सन् १८८५ ई० को खड्ग शमशेर डम्बर शमशेर तथा भीम शमशेर ने एक साथ ही वृद्ध रणोद्दीपसिंह को गोली का निशाना बनाया। इन्हीं तीन गोलियों के निशानों ने इन शमशेरों का प्रभुत्व कायम किया। इसके कुछ ही घंटों के बाद जंग बहादुर के पुत्र जगत जंग तथा उनके बड़े पुत्र युद्ध प्रताप जंग की भी हत्या कर दी गई।

इस समय नेपाल में शक्ति का ही बोलबाला था और प्रधान मंत्री के पद के उत्तराधिकारी का क्रम विच्छिन्न हो गया था जिससे राज्य-लक्ष्मी किसी को भी हाथ लग सकती थी। भाग्य ने वीर शमशेर का साथ दिया और जनरल खड्ग शमशेर ने अपने सौतेले भाई वीर शमशेर को प्रधान मंत्री बनने में मदद की।

रणोद्दीपसिंह के लगभग आठ साल के शासन-काल में शासन सम्बन्धी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ और उनके लिए बराबर षड्यंत्रों की ही भूमिका तैयार होती रही और शासन के विरोधी प्राणदण्ड और कठिन दण्ड के भागी होते रहे।

वीर शमशेर

वीर शमशेर सेनापति जनरल धीर शमशेर के सबसे बड़े पुत्र थे। जंग बहादुर ने उन्हें अठारह वर्ष की ही अवस्था में नेपाल सरकार का प्रतिनिधि बनाकर कलकत्ते भेजा था। रणोद्दीपसिंह की मृत्यु के पश्चात् वीर शमशेर छत्तीस वर्ष की अवस्था में नेपाल के प्रधान मंत्री हुए। उन्होंने सर्वप्रथम रणोद्दीपसिंह द्वारा बने हुए रोलबाल क्रम को खारिज किया और उच्च विभागों के कर्मचारियों को इधर से उधर किया। उन्होंने जगत जंग के साथियों को नेपाल से निर्वासित किया और उनकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली। इसके कुछ ही दिनों बाद वीर शमशेर और खड्ग शमशेर में भी मतभेद हो गया और खड्ग शमशेर को स्वदेश छोड़ देना पड़ा। वीर शमशेर ने त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह की बड़ी महारानी को भी निर्वासित किया और उनके मासिक सहायता राशि बन्द कर दी। महारानी की दयनीय

धार्मिक वृत्ति देखकर उदयपुर के महाराणा फतहसिंह ने उनके लिए चार हजार रुपए वार्षिक भत्ते की व्यवस्था कर दी।

फरवरी सन् १८८८ ई० में वीर शमशेर वाइसराय लार्ड डफरिन से मिलने कलकत्ते गये। नेपाल वापस आकर उन्होंने अपनी दो पुत्रियों का विवाह पृथ्वी वीर विक्रम शाह से किया। सन् १८८० ई० में चीन-सम्राट ने उन्हें थुङ्ग-लिङ्ग-पा-म्यूमो-काङ्ग-वाङ्ग सियाङ्ग की उपाधि दी। सन् १८ ७ तथा १८९० ई० में उन्हें ब्रिटिश सरकार से भी दो उपाधियाँ मिलीं।

सन् १८९७ ई० में वीर शमशेर ने भारतीय सेना के अंग्रेज सेनापति को काठमाण्डू आमंत्रित किया। यह नेपाल के इतिहास में सर्वप्रथम अवसर था जब नेपाली सेना का निरीक्षण एक विदेशी सेनापति ने किया।

सन् १८०० ई० में वीर शमशेर लार्ड कर्जन से मिलने पुनः कलकत्ते गये। उनके शासन-काल में तिब्बत के लिए नमक का निर्यात कुछ दिनों के लिए बन्द होने के कारण नेपाल और तिब्बत में संघर्ष की संभावना उत्पन्न हो गई किन्तु कुछ ही दिनों के बाद यह झगड़ा शान्त कर लिया गया।

महाराज वीर शमशेर ने सोलह वर्ष तक शासन किया। उन्होंने अपने अवैधानिक पुत्र गज शमशेर, रुद्र शमशेर, तेज शमशेर तथा प्रताप शमशेर आदि को राज्यवाले वर्ग में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने पाँच विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान भेजा। वीर अस्पताल, वीर पुस्तकालय, घंटाघर, धुर्सीखानी का पुल तथा लाल दरबार उनके समय में बने। लोगों का अनुमान है कि उन्होंने चार-पाँच करोड़ रुपये नकद तथा हीरे-जवाहरात अपने लिए इकट्ठे किये।

देव शमशेर

महाराज वीर शमशेर के पश्चात् धीर शमशेर के पुत्र देव शमशेर नेपाल के प्रधान मंत्री हुए। वह सरल और शान्त प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण शासक के गुणों से सर्वथा वंचित थे। राणा वंश के इतिहास में यह वह समय था जब महाराज जंग बहादुर तथा उनके भाइयों की सन्तानें प्रधान मंत्री पद को हस्तगत करने के लिए एक दूसरे की जड़ खोदने में ही व्यस्त रहीं। इस झगड़े की जड़ महाराज जंग बहादुर ने ही रोपी थी जिन्होंने प्रधान मंत्री पद का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र न रखकर भ्रातृ-परम्परा के क्रम से बाँध दिया था।

देव शमशेर की अयोग्यता से चन्द्र शमशेर ने लाभ उठाया। २७ जून १ ०१ ई० का दिन एक षड्यंत्र के लिए निश्चित हुआ और फतह शमशेर, दुर्गा शमशेर तथा [illegible] शमशेर की सहायता से चन्द्र शमशेर ने देव शमशेर को बन्दी बनवा दिया। इस काम में चन्द्र शमशेर के छोटे भाई भीम शमशेर ने भी सहायता की। अन्त में महाराजाधिराज पृथ्वी वीर

विक्रम शाह को चन्द्र शमशेर को प्रधान मंत्री मान लेना पड़ा। चन्द्र शमशेर ने देव शमशेर को बन्दी करके धनकुटा भेजा और वहाँ से कुछ दिन बाद मसूरी चले गये।

चन्द्र शमशेर

महाराज जंग बहादुर के छोटे भाई जनरल धीर शमशेर के पुत्र जनरल चन्द्र शमशेर अड़तीस वर्ष की अवस्था में २६ जून सन् १९ १ ई के दिन नेपाल के प्रधान मंत्री हुए। उनके छोटे भाई जनरल भीम शमशेर प्रधान मंत्री तथा ज्येष्ठ पुत्र मोहन शमशेर सेक्रेटरी जनरल हुए। महाराज वीर शमशेर के पश्चात् जनरल खड्ग शमशेर को प्रधान मंत्री पद का उत्तराधिकार प्राप्त था किन्तु वीर शमशेर और चन्द्र शमशेर ने उन्हें प्रधान मंत्री नहीं होने दिया। प्रधान मंत्री होते ही चन्द्र शमशेर ने देव शमशेर, फत्तह शमशेर तथा महेन्द्र शमशेर आदि को बहुत तंग किया। उन्होंने देव शमशेर के ऊपर बनारस-न्यायालय म नालिश करने का मुकदमा भी दायर किया किन्तु न्यायालय ने देव शमशेर आदि को निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने महेन्द्र शमशेर को भी जेल में डाल दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।



चन्द्र शमशेर
(चीनी पोशाक में)

चन्द्र शमशेर पृथ्वी वीर विक्रम शाह के कृपापात्र थे और वह अपने दिल की बात किसी प्रकार भी प्रकट नहीं करते थे। वह महाराजाधिराज को विलासी बनाकर जन-सम्पर्क से सर्वथा वंचित किये हुए थे और उन्हें किसी विदेशी से भी मिलने का अवसर नहीं दिया जाता था। शाही परिवार इस कूटनीति का रहस्य समझते हुए भी कुछ भी करने में असमर्थ था।

सन् १ १ ई में नेपाली प्रतिनिधि की हैसियत से चन्द्र शमशेर दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुए। वह २५ जनवरी सन् १९०४ ई को लार्ड कर्जन से मिलने कलकत्ता गये। इसी वर्ष चीन से एक शिष्टमण्डल आया जिसने महाराज जंग बहादुर की भांति चन्द्र शमशेर को भी थुङ्ग लिङ्ग-पिम्-मा-कपुओ-कङ्ग-वाङ्ग-सियाङ्ग की उपाधि प्रदान की जिसका अर्थ अधिपति सब सेनाओं में वीर सब विषयों में पारंगत सुयोग्य सेनाध्यक्ष तथा महाराजा होता है।

नेपाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव को देखकर ल्हासा की सरकार का सदा

हुई और इसका निराकरण चन्द्र शमशेर ने जून सन् १९०४ ई० में तिब्बत के दलाई लामा को एक व्यक्तिगत चिट्ठी लिखकर किया। उन्होंने तिब्बत सरकार तथा अंग्रेजी सरकार के बीच की गलतफहमी को दूर करने का सफल प्रयास किया और दोनों सरकारें नेपाल सरकार की नीति का समर्थन करने लगीं। चन्द्र शमशेर ने नवम्बर, सन् १९०५ ई० में भारत के सेनापति लॉर्ड किचनर को काठमाण्डू आमंत्रित किया। सन् १९०७ ई० में कलकत्ते जाकर उन्होंने वाइसराय लॉर्ड मिण्टो से भेंट की। सन् १९०८ ई० में वह इंगलैंड गये। लंदन में सम्राट् एडवर्ड सप्तम ने चन्द्र शमशेर का स्वागत किया और उन्हें जी सी बी तथा आर डी सी बी की उपाधियाँ दीं। चन्द्र शमशेर ने यूरोप में कई प्रकार की सरकारों को देखा और उनके विषय में काफी जानकारी भी हासिल की। उन्हें इंगलैण्ड की सरकार सबसे अच्छी लगी और वह नेपाल को भी उसी के आधार पर चलाने की चेष्टा करने लगे। चन्द्र शमशेर ने फ्रांस स्विट्जरलैण्ड आदि का भी ६ मास तक भ्रमण किया। स्वदेश लौटने पर उन्होंने महाराजाधिराज को सोने की चिड़िया से तुलना करके उनको सब प्रकार से सन्तुष्ट और प्रसन्न रखने की चेष्टा की। सन् १९११ ई० में उन्होंने ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पंचम के साथ ठोरी के जंगल में शिकार खेला और शिकार के ग्यारह दिनों में सम्राट् को अपना मित्र बना लिया और उनके दिल में यह विश्वास जमा दिया कि राणा परिवार अंग्रेजी हुकूमत का सदैव साथ देगा।

पृथ्वी वीर विक्रम शाह की मृत्यु सन् १९११ ई० में युवावस्था में हुई। कहा जाता है कि चन्द्र शमशेर ने उनको इतना विलासी बना दिया था कि उसी के कारण उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े। इसके पश्चात् शिशु त्रिभुवन वीर विक्रम शाह महाराजाधिराज बनाये गये। नन्हें नरेश को पाकर चन्द्र शमशेर और भी शक्तिशाली हो गये और वह बहुत ही इत्मीनान के साथ शासन करने लगे।

सन् १९१२ ई० में न्यायालयों की स्थापना और न्याय-पद्धति में परिवर्तन हुआ। इससे केन्द्रीय प्रशासकीय तंत्र को बल मिला और भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण होने लगा।

६ अगस्त सन् १९१४ ई० को यूरोपीय प्रथम महायुद्ध छिड़ने का समाचार काठमाण्डू पहुँचा। चन्द्र शमशेर ने वाइसराय से तुरन्त ही सैनिक सहायता देने की इच्छा प्रकट की और ब्रिटिश सरकार ने उसे सधन्यवाद स्वीकार कर लिया। पहले ६ हजार नेपाली सैनिकों की माँग भारत के लिए पूरी की गई। इसके बाद पंद्रह हजार नेपाली सैनिक जनरल बबर शमशेर के अधिनायकत्व में भारत रवाना हुए। नेपालियों ने फ्रांस जर्मनी टर्की मेसोपोटामिया तथा अफगानिस्तान आदि देशों में अपने जौहर दिखलाए। महायुद्ध में विजयी होकर नेपाली सैनिकों ने विक्टोरिया क्रास तथा अन्य सामरिक पदक इत्यादि भी प्राप्त किए। तभी से नेपाली जाति योद्धा के लिए प्रख्यात हुई।

इस महायुद्ध से पहले भारत में बीस बटालियन गोरखा फौज रहती थी किन्तु महासमर के बाद यह संख्या बढ़ाकर चालीस तक कर दी गई। महाराज चन्द्र शमशेर ने

सन् १९१४ ई० से १९१८ ई० के बीच अंग्रेजी सरकार को तीन बार में दस लाख रुपये भी युद्धकोष आदि में भेंट किये। उन्होंने अंग्रेजों को एक हजार चौरी गायें भी दीं। ब्रिटिश सरकार ने इससे प्रसन्न होकर नेपाल सरकार को सैनिक-सुधार के लिए दस लाख रुपये प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया।

जनवरी सन् १९१७ ई० में चन्द्र शमशेर ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड से और सन् १९२१ ई० में ड्यूक ऑफ कनॉट से भारत में भेंट की। दिसम्बर सन् १९२१ ई० में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को शिकार खेलने के लिए नेपाल तराई में आमंत्रित किया और अपने शानदार स्वागत से प्रिंस ऑफ वेल्स को भी प्रसन्न किया। इस प्रकार चन्द्र शमशेर ने अंग्रेज शासकों से घनिष्ठता कायम कर ली और नेपाल तथा भारत में कई संधियां भी हुईं।

प्रभावशाली व्यक्तियों के पीछे चन्द्र शमशेर अपने गुप्तचर लगाये रखते थे। राणा परिवार के पीछे भी उनके आदमी षड्यन्त्रों आदि की टोह लगाया करते थे। उन्हें न केवल राजनीतिक गतिविधियों अपितु घरेलू बातों का भी पूरा पता लगता रहता था। इसके बावजूद भी एकतन्त्री शासन के विरोधी अपना काम करते रहे। नेपाल-तराई में भारतीय नेताओं का नाम खूब प्रचलित था और तराईवासी उनके भाषणों को सुनने के लिए भारत में प्रायः जाया करते थे। चन्द्र शमशेर के गुप्तचर सिर्फ राजधानी तक ही सीमित थे और वह तराई के कार्यकर्ताओं को पकड़ने की चिन्ता नहीं करते थे। चन्द्र शमशेर ने अंग्रेजी सरकार से किसी भी नेपाली सैनिक को सूबेदारी के पद से ऊंचा कोई पद भी न देने की प्रार्थना की।

२८ जून सन् १९२० ई० को उन्होंने सती-प्रथा को पूर्णरूप से समाप्त कर दिया। नेपाल में दास और सती-प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी। महाराज जंग बहादुर तथा वीर शमशेर ने सती-प्रथा को बन्द करने के लिए प्रयास किया किन्तु तब भी वह चालू रही। दास प्रथा को समाप्त करने का तो साहस किसी प्रधान मंत्री को नहीं हुआ था। चन्द्र शमशेर ने १९२६ ई० के अन्त तक दास प्रथा का अन्त कर दिया। इस महान् कार्य के लिए प्रधान मंत्री ने पशुपतिनाथ के कोष से तैंतालीस लाख रुपये व्यय किये। इस प्रकार साठ हजार दास दासी मुक्त हो गये और तभी से ये मुक्त नर-नारी 'शिवभक्त' कहलाते हैं। फरवरी सन् १९२७ ई० में कलकत्ता की मार्टिन कम्पनी ने रक्सौल से अमलेखगंज तक पच्चीस मील रेलवे लाइन बनाने के लिए कार्य प्रारम्भ किया।

महाराज चन्द्र शमशेर का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह महाराज जंग बहादुर की भांति ही सफल शासक सिद्ध हुए। जंग बहादुर ने यदि नेपाल में राणाशाही की नींव डाली तो चन्द्र शमशेर ने उसे सुदृढ़ किया। जंग ने नेपाल सरकार को यदि ब्रिटिश हुकूमत की ओर उन्मुख किया तो चन्द्र ने उसे इस योग्य बना दिया कि अंग्रेजी सत्ता उसकी सहायता और सुरक्षा करती रही। अट्ठाईस वर्ष के शासन-काल में उन्होंने अपनी सन्तानों के लिए भी दरबार बनवाये और करोड़ों रुपये की कीमती चीजें भी विदेशों से

सेनाएँ।

महाराज चन्द्र शमशेर ने पूर्वी नेपाल तराई में हनुमनिया दरबार बनवाया और वहां वह साल में तीन चार महीने रहकर तराई का शासन देखते थे। उन्होंने सप्तरी जिले में दस मील लम्बी नहर खुदवाई। भीमफेदी और काठमाण्डू के बीच रास्ते कायम, टेलीफोन तथा पहाड़ और तराई में कहीं कहीं पुल आदि भी बनवाये। उन्होंने अपनी सन्तानों को अपार धन-सम्पत्ति तथा हीरे-जवाहरात आदि भी दिए।



(बायें से दायें)
भीम शमशेर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर

महाराज चन्द्र शमशेर भारत की गतिविधि से बहुत सतर्क रहते थे और वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि महाराजाधिराज के अक्षम होने से सब काम बिगड़ जायेगा और शासन में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जायेगा।

२४ नवम्बर, सन् १९२ ई० को महाराज चन्द्र शमशेर की मृत्यु हो गई और रोल क्रम के अनुसार उनके छोटे भाई जनरल भीम शमशेर नेपाल के प्रधान मंत्री हुए।

भीम शमशेर

जनरल भीम शमशेर पन्द्रह वर्ष वीर शमशेर तथा उन्नीस वर्ष महाराज चन्द्र शमशेर की संरक्षता में रहकर अनुभवशील हो गये थे। उन्होंने वीर शमशेर से दृढ़ता तथा चन्द्र शमशेर से चातुरी भी सीख ली थी।

शासन की बागडोर संभालते ही उन्होंने प्रचण्ड गोरखा दल के सभी षड्यन्त्रकारियों को कालकोठरी में बंद करके नाना प्रकार की कठिनतम यातनाएं दीं। तंग तथा गंदी कोठरी में रहने के कारण लखमान सिंह तथा मैना बहादुर क्षय-रोग के शिकार हुए और बन्दीगृह में ही उनकी मृत्यु हो गई। मैना बहादुर की पचहत्तर-वर्षीय वृद्धा माता मृत्यु-शैया पर पड़े हुए अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए कई दिन तक बिना खाना-पानी के बन्दीगृह के फाटक पर पड़ी रही किन्तु प्रधान मंत्री ने उसे अपने पुत्र को देखने की आज्ञा नहीं दी और उसका वैसे ही स्वर्गवास हो गया। भीम शमशेर ने पद्म शमशेर द्वारा संचालित सरकारी अड्डों को पूरे देश में मजबूत किया और तराई के जो-जो जिले इनके विरुद्ध थे उनको डरा-धमकाकर तथा दण्ड देकर अपने काबू में किया।

उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ नेपाल और तिब्बत के बीच के मनमुटाव को भी समाप्त किया।

भीम शमशेर ने अपनी अवैवाहिक संतान हिरण्य शमशेर, राम शमशेर, प्रकाश शमशेर आदि को रोलवाला बनाया। इससे शासक परिवार में वैमनस्य उत्पन्न हो गया। इस झगड़े से पारिवारिक शक्ति क्षीण होने लगी और शासन-विरोधी तत्वों को बल मिलने लगा। प्रधान मंत्री भीम शमशेर अपनी रखेली महारानी गीता के गर्भ से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह युवराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह से कर देना चाहते थे किन्तु इसके पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी।

शासनकाल में प्रधान मंत्री भीम शमशेर ने राजधानी में पानी-कल, टोखा में क्षय अस्पताल, मार्ग में पानी-कल काम किये। उन्होंने सिपाहियों के वेतन में भी वृद्धि की और जिनके काम अच्छे थे उन्हें पदक भी प्रदान किये। शनिवार को छुट्टी मनाने की प्रथा इसी समय से प्रारम्भ हुई।

महाराज भीम शमशेर कुव्यसनी थे। उनके दरबार में ऐसे ही लोगों का जमघट लगा रहता था। उन्होंने अपने चौंतीस महीने के शासन काल में राजधानी में चार-पांच महल बनवाए और अपनी सन्तानों को करोड़ों रुपये भी दिये। रखेलियों के लिए भी उन्होंने आर्थिक व्यवस्था की।

युद्ध शमशेर

जनरल धीर शमशेर के पुत्र जनरल युद्ध शमशेर उनसठ वर्ष की अवस्था में नेपाल के प्रधान मंत्री हुए। इन्हीं के समय ही महाभूकम्प आया जिससे उत्तरी भारत, बिहार और नेपाल तबाह हो गये। काठमाण्डू, पाटन, भक्तपुर तथा पूर्वी नेपाल में विशेष क्षति हुई। इसी समय भारत में महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार में तूफान मचा दिया और अंग्रेजी सरकार की जड़ हिल गई। इस आन्दोलन की प्रतिक्रिया पूर्वी नेपाल तराई में भी हुई और लोगों ने सरकार को भूमि-कर देना ही बन्द

कर दिया। युद्ध शमशेर ने तराई की माँगें पूरी करने का आश्वासन देकर उसे फिर टाल दिया। काठमाण्डू में काफी प्राणी भी मर गये थे इसलिए प्रधान मंत्री ने भूकम्प-पीड़ितों की सहायतार्थ तीस लाख रुपये दान दिये। उन्होंने कुछ लोगों को भूकम्प-पीड़ित सेवक की उपाधि और तमगे भी दिये।

सन् १ ३५ ई. में युद्ध शमशेर ने धीर शमशेर तथा चन्द्र शमशेर की अवैधानिक संतानों को रोल-क्रम से हटा दिया। परिणामस्वरूप असन्तुष्ट हिरण्य शमशेर, रुद्र शमशेर तथा तेज शमशेर आदि ने षड्यंत्र करके बदला लेना चाहा किन्तु युद्ध शमशेर ने सबको राजधानी से बाहर निकाल दिया। रुद्र शमशेर पाल्पा तथा हिरण्य शमशेर वीरगंज के बड़ा हाकिम बना दिये गये। उन्होंने प्रकाश शमशेर के पुत्र महावीर शमशेर को भी काठमाण्डू छोड़ देने के लिए बाध्य किया और वह कलकत्ता जाकर व्यवसाय इत्यादि करने लगे।

महाराज युद्ध शमशेर क्रूर तथा निर्भीक स्वभाव के थे। उन्होंने नेपाल प्रजा परिषद् के चार सदस्यों को मृत्यु-दण्ड तथा अन्य को जीवनपर्यन्त कारावास का दण्ड दिया। उन्होंने सामूहिक कीर्तन करने की मनाही कर दी थी। भागवत तथा वेद के श्लोकों का अनुवाद करने तथा पाठ और प्रवचन करने के अपराध में पण्डित मुरलीधर को जीवनपर्यन्त कारावास का दण्ड दिया गया था।

द्वितीय महायुद्ध में युद्ध शमशेर ने पच्चीस हजार नेपाली सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता की। पाँच हजार नेपाली सैनिक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित होकर भारत और नेपाल को अंग्रेजों के पंजे से स्वतन्त्र कराने के लिए प्रयास करते रहे। अगस्त सन् १९४२ ई. के भारतीय जन-आन्दोलन की उग्रता को देखकर युद्ध शमशेर को किंचितमात्र आशंका हुई। उन्होंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को गांधी और जवाहर को गोली से मार देने की सलाह दी। उन्होंने नेपाल-तराई में भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण तथा प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना आदि को भी गोली से मार देने के हुक्म दिये। युद्ध शमशेर ने भारत में गिरफ्तार सभी नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों को जान से मार डालने के लिए भारत सरकार से नेपाल भेज देने की प्रार्थना की किन्तु भारतीय न्यायालयों ने ऐसा निर्णय देने से इनकार किया और इस प्रकार दर्जनों नेपाली युवकों की जानें बच गईं। युद्ध शमशेर ने अपनी सारी शक्ति देशभक्तों तथा प्रजातंत्र चाहने वालों को दबाने में लगा दी। इसकी प्रतिक्रिया देश और विदेश में अच्छी हुई और लोगों की सहानुभूति राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति स्पष्ट हो गई। उन्होंने सहस्र शेरों को मारने की प्रतिज्ञा पूरी करके जीवनपर्यन्त शिकार खेलना छोड़कर हथियार रख दिये। मेची और महाकाली नदियों के बीच में कोई भी जंगल ऐसा नहीं बचा जिसमें महाराज युद्ध शमशेर ने शिकार नहीं खेले। वह घोड़े की सवारी के बड़े शौकीन और सिनेमा के कट्टर विरोधी थे।

प्रधान मंत्री ने कुछ लोगों को सन्तुष्ट रखने के लिए 'उद्योग परिषद्' 'कृषि परिषद्'

तथा 'ब्यूरो ऑफ माइन्स' खड़ी की। तेरह वर्ष एक माह के शासन काल में युद्ध शमशेर ने जयनगर से जनकपुर तक लाइट रेलवे लाइन, विराटनगर तथा बीरगंज में पानी-कल चालू की। उन्होंने नाना महल और मठ-मन्दिर तथा विद्यालय आदि बनवाये। अपनी संतानों के लिए उन्होंने आठ-दस करोड़ रुपये भी बचाये।

१९४५ ई० में राजत्याग के पश्चात् महाराज युद्ध शमशेर ने संन्यास ले लिया और वह राजर्षि कहलाने लगे। उन्होंने पण्डित मदनमोहन मालवीय द्वारा संस्थापित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को एक लाख रुपया दान दिया। रोड़ी नामक तीर्थ-स्थान छोड़ने के बाद वह देहरादून चले गये और नवम्बर, सन् १९५१ ई० में वहीं उनकी मृत्यु हुई।

पद्म शमशेर

दिसम्बर, सन् १९४५ ई० में महाराज भीम शमशेर के पुत्र जनरल पद्म शमशेर प्रधान मंत्री हुए। इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का सिंहासन लड़खड़ा रहा था और भारतीय नेता अपने देश का शासन संभालने के लिए तैयार बैठे थे। इसी बीच नेपाली नेता भी भारतीय नेताओं के सहारे नेपाल में आन्दोलन करने की रूपरेखा तैयार करते रहे। उनके इस सम्पर्क को देखकर नेपाल का शासक वर्ग सतर्क हो गया और वह प्राणपण से अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए व्यग्र हो उठा।


पद्म शमशेर

पदच्युत तथा निर्वासित राणाओं को भारत स्थित नेपाली नेताओं के सम्पर्क में आने में देर नहीं लगी। उनके पास पैसे थे और पद्म शमशेर से भी उनके सम्बन्ध अच्छे थे। प्रधान मंत्री पद्म शमशेर ने परिस्थिति को संभालने के लिए १० दिसम्बर, सन् १९४६ ई० को नागरिक अधिकार सम्बन्धी पर्चे बँटवाए। इससे काठमाण्डू की जनता उनकी ओर आकृष्ट हुई और उनसे शासन में परिवर्तन लाने की आशा करने लगी। दूसरी ओर नेपाल-तराई तथा भारत में जन-जागृति बढ़ती ही रही। फलस्वरूप नेपाल सरकार ने भारत के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू से सम्पर्क कर बढ़वाने तथा नेपाल के लिए एक शासन विधान तैयार करवाने में मदद माँगी। भारत से प्रसिद्ध कानूनी नेता श्री श्रीप्रकाश तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापक डा० राम उग्र सिंह नेपाल भेजे गये। उन्होंने

परिस्थिति का अध्ययन करके तीन-चार प्रकार के विधान नेपाल सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये। पद्म शमशेर विधान को लागू करने के लिए तैयार थे किन्तु सेनापति जनरल मोहन शमशेर ने उनके निश्चय तथा संकल्प में बाधा डाली। विधान में एक केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की स्थापना तथा उसकी सहायता के लिए एक कारबारी सभा तथा एक राष्ट्र-सभा की व्यवस्था थी। महाराज पद्म शमशेर भी प्रकृति तथा निर्बल स्वभाव के थे। वह शासन में परिवर्तन लाने की इच्छा रखते हुए भी सर्वथा अयोग्य सिद्ध हुए। मोहन शमशेर की धमकी से डरकर वह राज्य छोड़कर भारत भाग गये और वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया। इसके उपलक्ष में मोहन शमशेर ने उन्हें दो-तीन लाख रुपये दिये। शांति के समय महाराज पद्म शमशेर ने महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह तथा नेपाली शांति के कार्यक्रम का स्वागत किया और वह बिहार के प्रसिद्ध नगर रांची में निवास करने लगे।

मोहन शमशेर

महाराज चन्द्र शमशेर के ज्येष्ठ पुत्र जनरल मोहन शमशेर सन् १९४८ ई० में नेपाल के प्रधान मंत्री हुए। वह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और कट्टर सनातन धर्मी किन्तु साथ ही वह आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों के कट्टर विरोधी रहे। इसलिए इन्होंने प्रधान मंत्री बनते हुए महाराज पद्म शमशेर के समय किये गये सुधारों का अन्त कर दिया और शासन के विरोधी क्रान्तिकारियों का जोरों से विरोध किया जिसका फल यह हुआ कि क्रान्ति की ज्वाला उनके शासन काल में भयंकर रूप धारण कर गई और थोड़े ही काल के बाद इन्हें पदच्युत होना पड़ा और राणाशाही का नेपाल से सदा के लिए अन्त हो गया।



पण्डित जवाहरलाल नेहरू
तथा मोहन शमशेर

जनवरी सन् १९५० ई०, में प्रधान मंत्री की हैसियत से महाराज मोहन शमशेर दिल्ली गये और वहाँ राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। वहाँ से काठमाण्डू लौटने के कुछ मास बाद सितम्बर में उन्होंने बहुत से

राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाया और उन पर यह अभियोग लगाकर कि वे सब उनकी हत्या का षड्यन्त्र कर रहे थे प्राण-दण्ड देना चाहा किन्तु महाराजाधिराज ने इसकी स्वीकृति नहीं दी।

परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर ने उनको मार डालने की धमकी दी। इससे बचने के लिए महाराजाधिराज ने ६ नवम्बर सन् १९५ ई० को सपरिवार भारतीय दूतावास में शरण ले ली और वहां से वह भारत सरकार द्वारा दिल्ली बुला लिये गये। इसी के फलस्वरूप सारे नेपाल में राणाशाही के विरुद्ध क्रांति उठ खड़ी हुई। इस समय काठमाण्डू में भारतीय राजदूत सर चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह थे जो सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया के बाद दूसरे राजदूत थे। नरेश के शरण लेने आदि की बात भारतीय राजदूत ने तुरन्त ही भारत सरकार को बताई।

महाराज मोहन शमशेर ने महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को अपनी गद्दी छोड़ जाने पर पदच्युत घोषित किया और उनके तीन वर्षीय पौत्र ज्ञानेन्द्र को नया महाराजाधिराज घोषित कर दिया। भारत सरकार ने नेपाली क्रांति का स्वागत किया और नेपाल-नरेश का समर्थन करके शिशु ज्ञानेन्द्र को नया नरेश मानना अस्वीकार कर दिया।

इसी बीच में ३ दिसम्बर, सन् १९५ ई० को दिल्लीस्थित ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर राबर्ट्स तथा ब्रिटिश परराष्ट्र विभाग के विमपक्ष सर एस्टर डनिंग काठमाण्डू पहुंचे। वह राणा-शासन के समर्थन में हस्तक्षेप करना चाहते थे किन्तु राजधानी की जनता ने एक विराट प्रदर्शन करके उनका वहां रहना तक असम्भव कर दिया। उसने भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए अपने नरेश को काठमाण्डू वापस बुलाए जाने की बारबार मांग की। अन्त में विवश होकर महाराज मोहन शमशेर को समझौता करना पड़ा। ११ दिसम्बर, सन् १९५ ई० को नेपाल की भारदारी सभा ने महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नेपाल का नरेश पुनः स्वीकार कर लिया और १५ फरवरी सन् १९५१ ई० को वह दिल्ली से वायुयान द्वारा काठमाण्डू लौट आये। इस अवसर पर राजधानी की जनता ने उनका अद्वितीय स्वागत किया।

१८ फरवरी सन् १ ५१ ई० को अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई और जिसके प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर ही बनाये गये किन्तु राणा और कांग्रेस की यह मिली जुली सरकार बहुत समय तक कार्य नहीं कर सकी और महाराज मोहन शमशेर के स्थान पर मातृका प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में एक नयी सरकार बनी। यह सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी और शासन की सारी बागडोर अपने हाथों में ले लेनी पड़ी जब उन्होंने कार्य-संचालन के लिए ६ व्यक्तियों की एक परामर्शदातृ समिति बना ली। बाद में भी मातृका प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बना जो अब तक शासनारूढ़ है।

नेपाल के प्रधान मंत्री और उनका शासन-काल

जनरल भीमसेन थापा	१० अप्रैल १८०६—१८३० ई०
जनरल माथबर सिंह	२८ नवम्बर, १८४३—१८ मई १८४५ ई०
महाराज जंग बहादुर	१७ सितम्बर १८४६—२५ फरवरी १८७७
जनरल रणोद्दीप सिंह	७ फरवरी १८७७—२२ नवम्बर १८८५
जनरल वीर शमशेर	२२ नवम्बर १८८५—५ मार्च १९०१
जनरल देव शमशेर	५ मार्च १९०१—२६ जून १९०१
जनरल चन्द्र शमशेर	२६ जून १९०१—२४ नवम्बर, १९२९
जनरल भीम शमशेर	२४ नवम्बर १९२९—१९३२
जनरल युद्ध शमशेर	१९३२—दिसम्बर, १९४५ ई०
जनरल पद्म शमशेर	दिसम्बर, १९४५—१९४८ ई०
जनरल मोहन शमशेर	१९४८—११ नवम्बर, १९५१ तक
जनरल मातृका प्रसाद कोइराला	१६ नवम्बर, १९५१ ई०

७

प्रकृति की देन

नेपाल के इतिहास के अनुरूप ही इस देश का प्राकृतिक गठन भी बड़ा ही विचित्र-सा है। एक ओर तो यहां संसार के सबसे ऊँचे पहाड़ों की चोटियां हैं और दूसरी ओर साधारण से साधारण तराई क्षेत्र हैं जो पूर्णतया समतल हैं। इसकी यह विशेषता यहां की जलवायु पर भी पूरी तरह से अपना प्रभाव डालती है—जहां नेपाल के एक अंश में कठिनतम शीत का प्रकोप होता है वहां दूसरे अंशों में ग्रीष्म भी बुरी तरह की पड़ती है। नेपाल का एक अंश तो पहाड़ी होने के फलस्वरूप पूर्णतया ऊसर है इसका दूसरा भाग बड़ा ही उपजाऊ है। इन सब बातों का प्रभाव नेपाल के निवासियों पर भी पड़े बिना नहीं रह सका है और पहाड़ तथा तराई में बसने वाली जातियां एक-दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि दोनों को एक साथ ही नेपाली कहने से भ्रम होने लगता है।

नेपाल की जनसंख्या सन् १९११ ई० में ५५,७३,००१ तथा सन् १९२० ई० में ५५,७४,०५६ बताई जाती है किन्तु इस जनगणना को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आजकल नेपाल की आबादी लगभग एक करोड़ है। इसका क्षेत्रफल ५४,००० वर्गमील है और यह लम्बाई में पूर्व से पश्चिम ५२५ मील है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण ९० से १४० मील तक है। संसार के नक्शे में इसका स्थान २६°२० तथा ३०°१० अक्षांशों के बीच और ८०°१५ तथा ८८°१ देशान्तर के मध्य में है।

नेपाल की वर्तमान सीमायें उत्तर में तिब्बत, पूर्व में सिक्किम, दक्षिण में बंगाल, बिहार तथा उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम में कुमायूं प्रदेश से मिलती हैं। चीन और भारत के बीच स्थित होने के कारण नेपाल की राजनैतिक महत्ता बहुत बढ़ी है।

नेपाल के दक्षिण में तराई भाग को छोड़कर अन्य सभी नेपाल पहाड़ी है और बीहड़ जंगल समस्त देश में फैले हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि यहां वर्षा बहुत होती है—जून से अक्तूबर तक नेपाल में औसतन ६० इंच पानी बरसता है। नवम्बर से अप्रैल तक कड़ी सर्दी पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में ९० डिग्री से अधिक गर्मी नहीं पड़ती। कुहरे यहां अक्सर छाये रहते हैं और बादल की गड़गड़ाहट तो एक बड़ी साधारण बात है।

प्राकृतिक और प्रशासनीय दृष्टि से नेपाल को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है—एक पर्वतीय तथा दूसरा तराई प्रदेश।

पर्वतीय प्रदेश पर्वतों की ऊंचाई दस हजार फीट से उन्तीस हजार फीट तक है।

यह भाग प्रायः बर्फ से ढका रहता है। इसी प्रदेश में संसार की सब से ऊंची चोटी माउण्ट एवरेस्ट अथवा सिभीपग २९,००२ फीट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कंचनजंगा २८,१४६ फीट मकालू-चम्लों अथवा कुम्भकर्ण २७,७९० फीट धौलागिरि २६,८०० फीट गुसाईंनाथ २६,३०५ फीट अन्नपूर्णा २६,४९२ फीट तथा गौरीशंकर २३,४४० फीट ऊंची पर्वत चोटियां हैं।

इस प्रदेश में केवल वही पशु बसते हैं जो बर्फ में रहने के अभ्यस्त हैं। पर्वत-श्रेणियों को पार करने के लिए प्रकृति ने यहां बारह-तेरह गिरि द्वार अथवा दर्रे बना दिये हैं। इन में से नेपाल से तिब्बत जाने वाले सात गिरि द्वार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं—

(१) तकला दर्रा—घोलागिरि और नन्दादेवी के बीच में है। (२) मुस्तांग दर्रा—काली गण्डकी के तीर में स्थित है और जो धौलागिरि पर्वत के चालीस मील पूर्व में है। यह गिरि द्वार काफी चालू रहता है। इसी से होकर यात्री मुक्तिनाथ तथा तिब्बत जाते हैं। (३) करोंग दर्रा—गुसाईंनाथ पर्वत के पश्चिम की ओर है। (४) कुटी दर्रा—यह नेपाल के पूर्व में है। कुटी दर्रे से होकर ल्हासा के यात्री नेपाल की राजधानी काठमाण्डू आते-जाते हैं। यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। (५) हतिया दर्रा—इस मार्ग से होकर अरुण नदी बहती है। (६) वालन दर्रा—कंचनजंगा के पश्चिम और नेपाल के पूर्वी छोर पर है। (७) चम्भा दर्रा—यही नेपाल से तिब्बत जाने का साधारण मार्ग है।

पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई चार हजार से लेकर दस हजार फीट तक है। इसका क्षेत्र लगभग दस हजार वर्गमील है। इस प्रदेश में शिवपुरी पर्वत (९,००० फीट) फूल चौक पर्वत (८ ०० फीट) नागार्जुन पर्वत (७ ०० फीट) महादेव पोखरी पर्वत (६,७०० फीट) तथा चन्द्रागिरि पर्वत (६,६०० फीट) की ऊंची चोटियां हैं।

नेपाली सभ्यता संस्कृति वेषभूषा तथा रहन-सहन का यही उद्गम-स्थान है।

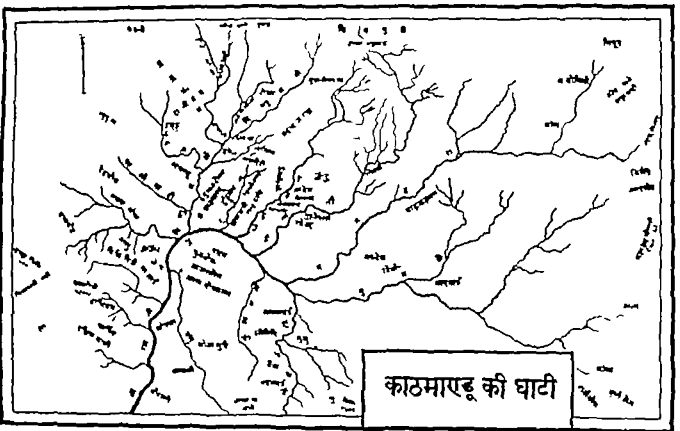
इस प्रदेश में प्रकृति ने अपनी सर्वतोमुखी सुषमा एवं गरिमा प्रकट कर दी है। यहां के वृक्षों से आच्छादित पर्वत-मालिका और टेढ़ी-मेढ़ी तन्वंगी नदियां प्रत्येक आगन्तुक का मुग्ध कर लेती हैं।

तराई

पर्वतीय प्रदेश के सिलसिले का तलहटी प्रदेश तराई (मधेस) कहलाता है। यह प्रदेश समुद्र के धरातल से दो हजार से लेकर साढ़े तीन हजार फीट तक ऊंचा है और इसका क्षेत्रफल लगभग सोलह हजार वर्गमील है।

तीन नदियां

नेपाल में मुख्य तीन नदियां हैं। कोसी नदी पूर्व में गण्डकी मध्य में और कर्णाली पश्चिम में बहती है। ये तीनों नदियां हिमालय पार करके भोट से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं।


काठमाण्डू की घाटी

गुसाईंथान तथा कंचनजंगा के बीच से निकलकर कोसी नदी की सात धारायें उत्तर से दक्षिण बहती हैं। इन धाराओं में अरुण सबसे बड़ी है। इसके अतिरिक्त तामा कोसी, लिखू, दूध कोसी, सुन कोसी, इन्द्रावती तथा तमोर प्रसिद्ध हैं।

धौलागिरि तथा गुसाईंथान के बीच का जल गण्डकी नदी की सात धाराओं से बहता है। जब सातों धारायें एक में मिल जाती हैं तब यह गण्डकी नदी कहलाने लगती है। यह सभी श्वेत गण्डकी, काली गण्डकी, बूढ़ी गण्डकी, मादी, मर्स्यांगदी तथा त्रिशूली के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन धाराओं के अन्य नाम भी हैं।

कर्णाली की मुख्य नदियाँ कर्णाली, भेरी, सेती तथा महाकाली (शारदा) हैं।

इनके अतिरिक्त तराई में बूढ़ी गंगा और राप्ती बहती हैं। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में मोरी नदी, काठमाण्डू के पूर्व में रुद्रमती, मणिमती, इच्छुमती तथा इन्दुमती, उसके पश्चिम में भद्रमती, विष्णुमती और काठमाण्डू के दक्षिण में प्रभावती, वागमती तथा कर्मनाशा बहती हैं।

सप्त कोसी, गण्डक तथा कर्णाली नदियों की सहायक नदियाँ समूचे नेपाल में जाल की तरह फैली हुई हैं। जब तक ये नदियाँ पहाड़ी प्रान्तों में बहती हैं तब तक तो बहुत ही भयंकर गति से बहती हैं। किन्तु जब यह तराई में आ जाती हैं तब उनकी गति काफी धीमी हो जाती है और इनमें आसानी से नावें चलाई जा सकती हैं। इन्हीं नदियों के द्वारा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तराई की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में ये नदियाँ छिछली तथा पतली हैं और इनकी धारायें भी तीव्र होती हैं। इन नदियों में से प्रतिवर्ष लाखों रुपया की मछलियाँ पकड़कर बेची जाती हैं। इन नदियों से बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न करके कल-कारखाने चलाये जा सकते हैं। और तराई में इन नदियों को बाँधकर इनसे अनेक नहरें निकाली जा सकती हैं जिनके द्वारा सिंचाई का काम बहुत बढ़ाया जा सकता है और अन्न उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

पर्वतीय प्रदेश का हृदय

काठमाण्डू को 'पर्वतीय प्रदेश का हृदय' कहा जा सकता है। यह चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में भंजयाङ्, पश्चिम में मयूप और पांच माने भंजयाङ् तथा दक्षिण में ताम कोट स्थित हैं। इनके बीच में स्थित घाटी की जनसंख्या लगभग छः लाख है।

इस घाटी को तीन भागों में विभक्त किया गया है—

१ काठमाण्डू (कान्तिपुर) वागमती नदी के पश्चिम-उत्तर में स्थित है।

२ पाटन (ललितपुर) काठमाण्डू के दक्षिण में है।

३ भातगांव (भक्तपुर) काठमाण्डू के पूर्व में है।

मध्य नेपाल की घाटी के पूर्व में कोसी प्रदेश है जो सात क्षेत्रों में बांटा गया है। कामेरनाचोर, सिन्धु पाल्चोक, पूर्वा त्रियुग, माझ किरात, पल्लो किरात तथा ईलाम।

खास नेपाल की घाटी के पश्चिम में गण्डकी प्रदेश है जो बीस भागों में विभाजित है—मुवाकोट भामी डांडा सल्याने चादिम मोर्सा तन्हूँ कास्की सम्भुंग सिरिस मिरिंग बोर, पस्सो मुवाकोट भिरकोट, सती गहूँ पर्व्यु पर्वत पाल्पा गुल्मी बस्कोट घुरकोट, मुसीकोट इस्मा अर्घा खांची तथा प्यूठाना।

उपर्युक्त पहाड़ी प्रदेश पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में विभक्त कर दिये गए हैं। पूर्वी पहाड़ी तथा पश्चिमी पहाड़ी के ये जिले चार चार नम्बरों के नाम से पुकारे जाते हैं।

गण्डकी प्रदेश के पश्चिम में कर्नाली प्रदेश है जो छः उपखण्डों में बांट दिया गया है—सल्यान दैलेख दुल्लू, जुम्ला अछाम तथा डोटी।

भीतरी तराई (मधेश) को भी जिलों में बांटा गया है—मकवानपुर, सिन्धुली उदयपुर, चितौन नवलपुर, दाय देउखुरी सुरखेत तथा सुर्खेत।

खास तराई (मधेश) का बारह जिलों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्व में परसा बारा रौतहट सर्लाही महोत्तरी सप्तरी तथा मोरंग नामक सात जिलों में से मध्य में बुटवल जिला पाल्ही माझखण्ड खजहनी तथा स्यूराज चार तहसीलों में विभक्त है और पश्चिम में चार जिले बांके बर्दिया कैलाली तथा कंचनपुर हैं। इस प्रकार भीतरी तथा खास मधेश में सब इक्कीस जिले हैं और जिनकी जनसंख्या समूचे देश की जनसंख्या की आधी से अधिक है।

जलवायु

शीतप्रधान देश होने के कारण नेपाल के पर्वतीय लोग बड़े बलिष्ठ और परिश्रमी होते हैं। कतिपयों में आर्य तथा मंगोल रक्त का सम्मिश्रण है। पर्वतों पर बसने वाले पहाड़ियों का कद बहुत ही नाटा होता है परन्तु उनकी बाहें तथा छाती की हड्डियां अत्यधिक मजबूत होती हैं। उनके शरीर का गठन ऐसा निराला होता है कि चालीस और पचास वर्ष का व्यक्ति भी नवयुवक-सा प्रतीत होता है। उनकी स्त्रियां भी बहुत स्वस्थ परिश्रमी और सुन्दर होती हैं।

खनिज पदार्थ

नेपाल में कितने प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इसकी अभी तक निश्चित खोज ही नहीं हो सकी है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वैज्ञानिक साधनों की पहुंच अति कठिन अवश्य है किन्तु असम्भव नहीं। पहाड़ों में नाना प्रकार के बहुमूल्य पत्थर, सीसा सुरमा गन्धक इत्यादि आसानी से निकाला जा सकता है। इनके अतिरिक्त सोना चांदी लोहा कोयला तांबा जस्ता अभ्रक कोबाल्ट तथा शीशा सोडा इत्यादि अनेक पदार्थ भी यहां बहुत हैं। पत्थरों को कूट-कूट कर सीमेण्ट तथा चूना भी तैयार किया जा सकता है। कुछ विदेशी अन्वेषकों का कहना है कि हिमालय पर्वत में बहुमूल्य रत्नों में उपयोगी रत्न भी यहां पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं। तराई में भी मिट्टी के तेल आदि की बड़ी-बड़ी खानों

का पता लगता है। इस प्रकार के खानों का पता लगाने में भारत सरकार का भी सहयोग नेपाल को प्राप्त है।

जड़ी-बूटियां

पर्वतीय प्रदेश के आंचल में स्थित वन प्रान्तों में अनेक प्रकार की कीमती लकड़ियां मिलती हैं। कहीं-कहीं तो धूप और चन्दन इत्यादि सुगंधित वृक्षों की पंक्तियां ही पंक्तियां हैं। इनके अतिरिक्त लाखों प्रकार की जड़ी-बूटियां इत्यादि भी आयुर्वेद के ग्रन्थों को देख देख कर प्राप्त की जा सकती हैं। वन प्रान्तों में शेर, चीते, हाथी, गैंडे, हिरन तथा मुलायम खाल वाले कई प्रकार के पशु तथा सुन्दर पक्षी आदि भी मिलते हैं।

अन्न-फलादि

शरद ऋतु में वन्य फल तथा नारंगी मुख्य रूप से मिलती हैं। पहाड़ी प्रदेश में कोदो उरद मक्का मूंगी आलू लहसुन प्याज तथा कपास प्रचुर मात्रा में बोया जाता है। मधेश में विशेष रूप से धान की खेती होती है। तराई का चावल मशहूर है। इसके अतिरिक्त गेहूं सरसों तम्बाकू पाट रुई आलू सब्जी और अदरक इत्यादि भी अधिक मात्रा में पैदा किये जाते हैं। पूर्वी नेपाल के धनकुटा तथा ईलाम प्रान्त में चाय भी होती है। नेपाल में ऐसी घासें कई सौ मील तक मिलती हैं जिन से कागज बनाया जा सकता है। दियासलाई बनाने के लिए भी प्रचुर सामान उपलब्ध है।

८

पुण्य तीर्थ भूमि

नेपाल को तिब्बत के लोग 'नेपा' कहते हैं जिसका अर्थ तिब्बती भाषा में 'तीर्थ वासी होना है'। जिसका अर्थ यही है कि वे लोग नेपाल को अपनी पुण्य तीर्थ-भूमि मानते हैं। इसी प्रकार आर्य-संस्कृति के उपासक भी नेपाल को अपना तीर्थ-स्थान मानते हैं। बौद्धानुयायी स्वयम्भू चैत्य महाबौद्ध मन्दिर आदि की पूजा करते हैं।

वस्तुतः यदि नेपाल को धार्मिक दृष्टि से देखा जाय तो यह पवित्र तथा पूजनीय है। तभी तो आर्यों की पूर्वज 'शरण्यं सर्व भूतानाम्' की दार्शनिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर हिमालय के वनों में अपनी चतुर्थावस्था बिताया करते थे। कैलाश पर्वत तो त्रिकालदर्शी भगवान् शंकर का धाम ही ठहरा जहाँ से वह डमरू बजा-बजा कर अखिल सृष्टि का कौतुक देखा करते हैं। वनों तथा पर्वतों का प्रशान्त वातावरण मानस में वैराग्य की भावना भरता रहता है। और यही कारण है कि पहाड़ों में रहने वाले धर्मभीरू तथा आस्तिक होते हैं। यद्यपि नेपाल में बौद्धानुयायी भी बहुत हैं किन्तु वे भी किसी परोक्ष सत्ता की ही उपासना करते हैं।



स्वयंभू-चैत्य

नेपाल में पर्वतस्थित तीर्थ-स्थानों में मुक्तिनाथ का बहुत बड़ा महत्व है किन्तु वहाँ बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। इस प्रकार के तीर्थ-स्थानों का सम्राट् मुक्तिनाथ को माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि जो मुक्तिनाथ के दर्शन कर लेता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय की उपत्यकाओं में सहस्रों तीर्थ-स्थान हैं जहाँ किसी न किसी शुभ मुहूर्त में मेले लगा करते हैं।

स्कन्दपुराण में श्रीगर धाम 'श्रीमद्गी क्षेत्र' का माहात्म्य बहुत ही विस्तार

उल्लेख किया गया है जिसमें पूजन तथा परिक्रमा करने की विधियां भी बताई गई हैं। नेपाल में बहुत से एसे व्यक्ति हैं जो इन चौसठों लिंग तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा नागचूड़ पर्वत स्थित कुपालेश्वर से प्रारम्भ होकर काठमाण्डू स्थित सिद्धेश्वर पशुपतिनाथ तक समाप्त होती है।

कुपालेश्वर के समीप ही भीमेश्वर, काष्ठेश्वर तथा कश्यपेश्वर स्थित हैं। कश्यपेश्वर के पास ही चन्द्रकान्ति हिमवती नदी के मध्य में स्फटिकेश्वर पर आश्विन शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। इसके पश्चिम में गन्ध पर्वत पर गन्धेश्वर नामक तीर्थ-स्थान है। यहां माघ कृष्ण पंचमी को एक मेला लगता है। पंचेश्वर तथा विकटेश्वर भी यहीं हैं और सीतावती तथा रुद्रावती नदी के संगम पर इन्द्रेश्वर है। इसके पश्चिम में मालेश्वर स्थित है यहां माघ कृष्ण नवमी को मेला लगता है। पुण्येश्वर सिद्ध तीर्थ में तिम्मेश्वर सप्तमी तीर्थ में तथा कल्मेश्वर सरस्वती तीर्थ में स्थित हैं। रामेश्वर लिंग प्रभावती और सरस्वती नदी के संगम पर है। इसके दक्षिण में दो नदियों के संगम पर कालेश्वर का लिंग है। पश्चिम ब्रह्मतीर्थ में कुटेश्वर है। व्याघ्रेश्वर धर्म गंगा नदी के तट पर है यहां के लोगों का विश्वास है कि धर्म गंगा नदी विष्णु भगवान् के पसीने से निकली है। धर्म गंगा नदी का स्नान बड़ा ही पुनीत माना जाता है। यहां एक रुद्र कुण्ड भी है। गोकर्णेश्वर गोमती तथा बागमती के संगम पर एवं कम्पेश्वर मणिमंचा और विष्णु तीर्थ में है। इसके पश्चिम में दो मील की दूरी पर उन्मत्तेश्वर स्वर्णतीर्थ में स्थित है। यहां माघ शुक्ल षष्ठी को पर्व मनाया जाता है। पश्चिम में नन्दिकेश्वर, गोकुरेश्वर तथा फणिकेश्वर पुण्य माने जाते हैं। कीटेश्वर नागतीर्थ में स्थित है। अग्निश्वर इसके उत्तर में है और यहां माघ शुक्ल द्वादशी को मेला लगता है। इच्छावती और मणिकी के संगम पर भैरवेश्वर की स्थापना की गई है। यहां पांच नदियों का संगम है और उसी संगम पर पञ्चमय लिंग है। यहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को मेला लगता है।

बज्रेश्वर ब्रह्मतीर्थ में है। कहा जाता है कि यहीं बाणासुर का संहार कर भगवान् ने पयपान किया था। इसी स्मृति में यहां फाल्गुन पूर्णिमा को मेला लगता है। बदरीश्वर लिंग का स्पर्श करते ही प्रत्येक धातु स्वर्ण हो जाता है—ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है। यहां चैत्र शुक्ल चतुर्दशी का मेला लगता है। गणेश्वर मृगस्थापन नृसिंह तीर्थ में है। बागीश्वर लिंग के बारे में यहां के लोगों की बड़ी विचित्र मान्यता है। यहां स्वयं शंकर रूप तथा शिव लिंग का रूप है। यहां माघ कृष्ण पंचमी को एक मेला लगता है। यहीं आकाश गंगा भी बहती है। गन्धि चंडेश्वर पुर्णगिरि क्षेत्र में है। यहां फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। नारायण की स्थापना एक सीम में हुई है। यहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को पर्व लगता है। इसके पश्चिम में रुद्र महासागरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महासागरेश्वर की पूजा वैशाख पूर्णिमा को विशेष रूप से की जाती है। इसके पश्चिम में रत्न बटेश्वर है। यहां एक पुनीत सीम है जिसमें माघ कृष्ण चतुर्दशी तथा आषाढ़ पूर्णिमा को स्नान किया जाता है। बागेश्वर

रत्नचूड़ेश्वर से एक मील की दूरी पर है और इसके पश्चिम में किलेश्वर है। यहां माघ पूर्णिमा तथा श्रावण शुक्ल पंचमी को पर्व लगता है। वाल्मिकेश्वर और हनुमान जी मौरमड़ तीर्थ में है। मणलेश्वर में चैत्र शुक्ल तृतीय को उत्सव मनाया जाता है। इससे कुछ ही दूर निकुञ्ज कन्दरा में विमलेश्वर हैं जहां विमलोदक गंगा बहती है। अनन्तेश्वर ऋष्याश्रम पर्वत में है। माद्र कृष्ण अष्टमी तथा चैत्र कृष्ण नवमी को यहां मेला लगता है। इनके पास ही वृद्ध गंगा में विम्पेश्वर है। यहां वैशाख पूर्णिमा को पूजा होती है। सोमेश्वर सोम तीर्थ में है और यहां कार्तिक शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी और आश्विन पूर्णमासी को मेला लगता है। गोभन्देश्वर शृंगी तीर्थ में है। यहां शृंगि ऋषि ने तपस्या की थी। यहां चैत्र शुक्ल द्वादशी तथा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को पर्व लगता है। शृंगीश्वर सिद्धरस कुण्ड के सन्निकट है। यहां चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। कुपितेश्वर पर चैत्र कृष्ण द्वादशी को मेला लगता है। सर्वेश्वर गौरी कुण्ड और शिव गंगा में है। इसको कुम्भेश्वर तथा मृत्युञ्जय भी कहते हैं। यहां कार्तिक की पूर्णमासी को मेला लगता है। गोपालेश्वर अथवा गोपाल कृष्ण पर कार्तिक पूर्णिमा चैत्र षष्ठी तथा माघ कृष्ण अष्टमी को मेले लगते हैं। मीन तीर्थ तथा चन्द्रभट्टारेश्वर भस्मगया तथा धारा तीर्थ में है। यहां इन्द्रहृद धेनुतीर्थ और विष्णुपद तीर्थादि हैं।

गन्धेश्वर, पिण्डाग्रेश्वर तथा धर्मेश्वर एक दूसरे के पास ही हैं। धर्मेश्वर पर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को मेला लगता है। इन्हीं के समीप जलशायी नारायण हैं। गोकर्णेश्वर चन्द्रभागा नदी तथा वाग्मती नदी के संगम पर है। इस संगम को यहां के लोग ब्रह्मतीर्थ नाम से पुकारते हैं। टीकेश्वर संख मूल तीर्थ में है। इस तीर्थ को उत्तर प्रयाग तीर्थ और उत्तर काशी तीर्थ भी कहते हैं। मातेश्वर मयूर तीर्थ में है। यहां चैत्र शुक्ल षष्ठी तथा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को मेले लगते हैं। नागेश्वर, पर्वतेश्वर तथा जलेश्वर एक दूसरे के समीप ही हैं। लोगों की धारणा है कि जलेश्वर सदा जलमग्न ही रहते हैं। यहां चैत्र पूर्णिमा की रात्रि तथा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को विशेष पूजा होती है। किरातेश्वर वाग्मती के दक्षिण में है। भस्मेश्वर भस्म गया कुण्ड में है। इसके पश्चिम में ज्ञान कुण्ड है। भुवनेश्वर ज्ञान कुण्ड के ही पास है। गन्धमादेश्वर शिव का दर्शन इस कुण्ड में स्नान करने के पश्चात् किया जाता है। मायेश्वर आसुरी गुफा में है।

पशुपतिनाथ

नेपाल और तिब्बत के हिन्दू तथा बौद्ध दोनों ही इन तीर्थों तथा देवताओं का दर्शन करते हैं। इन सबों के दर्शन तथा परिक्रमा कर चुकने के पश्चात् तीर्थयात्री सिद्धेश्वर पशुपतिनाथ जी के दर्शन तथा पूजन करने का अधिकारी माना जाता है। पहाड़ों की चढ़ाई तथा मार्ग की अव्यवस्था का विचार करके अधिकांश तीर्थयात्री पशुपतिनाथ के दर्शन करके लौट जाते हैं। पशुपतिनाथ का पूजन शिव चतुर्दशी के दिन फाल्गुन के

कृष्ण पक्ष में विशेष धूमधाम के साथ किया जाता है। इस तिथि को भारत से लाखों गृहस्थी तथा साधु-सन्यासी यहां आते हैं। इतना बड़ा पर्व और मेला नेपाल में कभी नहीं लगता। शान्तिपुर का तुलजा मन्दिर तथा ललितपुर का महाबौद्ध मन्दिर भी पवित्र माना जाता है और वहां जनता किसी की बराबर भीड़ लगी रहती है।



पशुपतिनाथ का मन्दिर

यात्रायें

काठमाण्डू पाटन तथा भादगांव में तो प्रतिदिन ही किसी न किसी उत्सव-यात्रा की धूम रहती है। इनमें मत्स्येन्द्रनाथ यात्रा घोड़ा यात्रा इन्द्र यात्रा गाई यात्रा तथा रथ यात्रा विशेष प्रसिद्ध हैं। चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन शाही परिवार तथा प्रधान मन्त्री इत्यादि टुंडी खेल के मैदान में घुड़दौड़ देखने आते हैं। इस दौड़ में विजेताओं को पुरस्कार भी दिये जाते हैं। यात्राएं तथा समारोह नेपाल की परम्परागत वीरता तथा भावनाओं को व्यक्त करने के प्रयासों की ही गाथायें हैं। दुर्गा पूजा काठमाण्डू में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और जिसमें असंख्य पशुओं की बलि भी दी जाती है।

धार्मिक स्थान

तराई में लुम्बिनी, जनकपुर, बाराह क्षेत्र तथा त्रिवेणी इत्यादि तीर्थ-स्थानों का विशेष महत्व है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म-स्थान है। यहां प्रतिवर्ष लाखों बौद्ध मतावलम्बी चीन जापान लंका तथा बर्मा इत्यादि देशों से आते रहते हैं। लुम्बिनी में

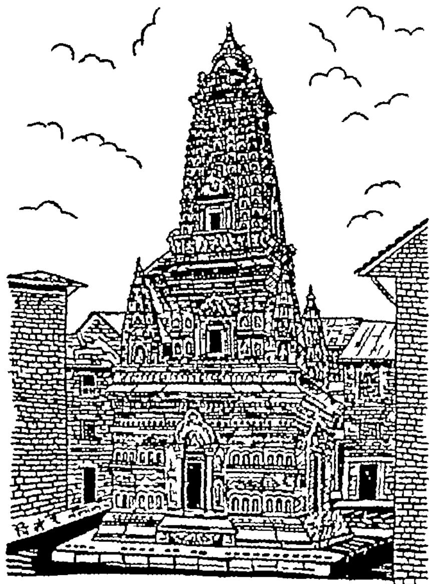
चैत्र रामनवमी तथा पूर्णिमा का मेला लगता है। यह तराई व मैदानों में महत्वपूर्ण माना जाता है। बाराह क्षेत्र में बाराहावतार हुआ था ऐसा माना जाता है।



तुलजा मन्दिर कान्तिपुर

त्रिवेणी' तीन नदियों का संगम है। यहां गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। माघ अमावस्या को यहां बहुत बड़ा मेला लगता है जो महीनों तक चलता रहता है। व्यापारिक दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी है।

जनकपुर महारानी सीता की जन्म-भूमि है। यहां प्रतिवर्ष लाखों हिन्दू अपनी श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। यहां मेले भी लगते हैं। पश्चिमी नेपाल के पहाड़ी प्रदेश में



महाबौद्ध मन्दिर ललितपुर

रीडी बैतडी तथा जौलजिबी पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। लोगों का कथन है कि प्राचीन काल म रीडी में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। यहां यज्ञ करने का विशेष माहात्म्य बताया गया है। बैतड़ी डोटी प्रान्त का एक नगर है। यहां श्रावणी के दिन बनमाली का मेला लगता है। यहा देवी-देवताओं के अनेक मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में सहस्रों देवदासियां रहती हैं जिनके कारण यहा का वातावरण काफी दूषित हो गया है। जौलजिबी महाकाली नदी के किनारे स्थित है। यहा अगहन की संक्रान्ति को विराट मेला लगता है। पश्चिमी पहाड़ के मेलो म जौलजिबी का स्थान सर्वोच्च है। व्यवसायिक दृष्टि से पश्चिमी नेपाल में यही एक ऐसा मेला है जहा भारत नेपाल तथा तिब्बत क हजारो व्यापारी एक साथ मिलते हैं।

९

कला और संस्कृति

नेपाल में ललित कलाओं की अपेक्षा उपयोगी कलाओं की अपनी विशेष महत्ता है। इस दिशा में यहाँ वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला की समान उन्नति हुई है।

वास्तुकला तथा चित्रकला को प्रश्रय प्राचीन काल से ही मिलता रहा है, किन्तु मूर्तिकला की उन्नति का श्रेय बौद्ध धर्म को ही प्राप्त है और यही कारण है कि नेपाल के प्रत्येक मन्दिर में बौद्ध धर्म की भी मूर्तियाँ मिलती हैं।

इन मूर्तियों की कला-शैलियाँ मंगोल आर्य, मंगोल नेपाली, तिब्बती मंगोल, तिब्बती नेपाली, आर्य तिब्बती, मंगोल तिब्बती, आर्य नेपाली तथा शुद्ध नेपाली सभी ढंग की पाई जाती हैं। इनके तुलनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन से ही नेपाली संस्कृति का पूरा ज्ञान हो सकता है। ये मूर्तियाँ नेपालियों के धार्मिक जीवन को व्यक्त करती हैं।

मुसलमानों ने नेपाल पर जब आक्रमण किया तब सबसे पहले उन्होंने मूर्तियों तथा मन्दिरों को ही तोड़ना प्रारम्भ किया और जब नेपालियों ने उन्हें पराजित करके नेपाल से भगाया तब उन्होंने सबसे पहले इन मूर्तियों तथा मन्दिरों का ही जीर्णोद्धार कराया। ऐसा करने में उनकी शैलियों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन तो अवश्य हो ही गया। फलस्वरूप उन पर मुसलमानी शैली का भी प्रभाव यत्र-तत्र स्पष्टतया दीखता है।

नेपाल ने वास्तुकला तथा मूर्तिकला में विदेशी शैलियों का कोरा अनुकरण मात्र ही नहीं किया अपितु उन्हें आत्मसात कर लिया है। इसके अतिरिक्त नेपाल ने कुछ नवीन शैलियों का आविष्कार करके तिब्बत, चीन तथा भारत को दिया है। पगोडा की शैली वस्तुतः नेपाली शैली है। नेपाल की वास्तुकला में चीनी, तिब्बती तथा भारतीय कलाओं का प्रचुर मात्रा में सम्मिश्रण हो गया है। नेपालियों के घर भी दूर से देखने पर चैत्याकार मन्दिर की भाँति ही प्रतीत होते हैं। उनकी भवन-निर्माण कला विचित्र ढंग की है। कुछ मन्दिरों के प्रांगण चीनी ढंग के हैं। पाटन तथा भक्तपुर में शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने भी मिलते हैं। इनमें महाबौद्ध मन्दिर तथा कुमजा मन्दिर विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

नेवार तथा गुरुंग इत्यादि जातियाँ ऊन की बहुत अच्छी-अच्छी चीजें बनाते हैं। नेवार लोग सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल तथा काँसे का काम बहुत सुन्दर करते हैं। ये लोग कपास से वस्त्र भी तैयार करते रहते हैं। नेपाल में हाथ से बाँस का कागज भी बनाया जाता है। यह कागज बहुत ही मजबूत किन्तु खुरदरा होता है। नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में एक सरकारी राष्ट्रीय कलागारशाला भी है जिसमें सब प्रकार की कलाओं का नमूना मिलते हैं। इसके पास ही एक शस्त्रशाला भी है जो नेपाल की वीरता का प्रतीक है।

तरहवीं शताब्दी में मल्ल वंश वालों ने काठमाण्डू की घाटी में जाति रीति आदि मध्यवस्थित रीति-रिवाजों का पुनसंस्कार किया। इस समय बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था और शैव सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव बड़े जोरों के साथ हो रहा था। इसके बाद नवार जाति के लोगों ने नेपाली संस्कृति का अभ्युत्थान किया। इन लोगों ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विशेष अनुकरण किया। नेवार हिन्दू जाति बौद्ध धर्म के प्रभाव में विशेष रूप से आ गई थी और यही कारण है कि नेवारों में अबतक शाक्य भिक्षु वज्राचार्य आदि श्रेणियां मिलती हैं। इस समय हिन्दुओं के पशुपतिनाथ एवं बौद्धों के स्वयम्भू तथा बौद्धनाथ को शैव और बौद्ध दोनों सम्प्रदायों के लोग पूजन लग गये थे। इसी लिए नेपाल में बौद्ध और शैव सम्प्रदाय में कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता और न दोनों में कोई विरोध ही पाया जाता है।

वज्रयान में शैव और बौद्ध पद्धतियों का गठबन्धन हो गया था वह अब भी सर्वत्र प्रकट है। काठमाण्ड में अब भी मुहल्लों का नाम बहाल ही है। यह 'बहाल' शब्द विहार का अपभ्रंश है।

नेवारों में अधिकांश आदिवासी मंगोल जाति के हैं। इसमें थोड़े ही भारतीय आर्य हुए। नेपाल में प्रथमतः आर्य अथवा भारतीय ही बौद्ध हुए और बाद में उन्होंने नेवारों को एक सूत्र में बांधकर बौद्ध मतावलम्बी बनाया। तत्पश्चात् वर्णाश्रम धर्म के कट्टर अनुयायी हिन्दू राजाओं ने चार वर्ण और छत्तीस जातियां बनाकर नेवार जाति को विभक्त किया। कुछ विद्वान् नेवारों का कथन है कि नेवारी बौद्ध नेपाल के ही आदिम निवासी हैं, वह वर्णाश्रमी आर्य मंगोल वंशज नहीं। नेपाल के जो बौद्ध पुरोहित या वज्राचार्य हैं वह सब ब्राह्मण से बौद्ध हुए हैं और बहुत से बौद्ध मल्ल तथा लिच्छवी वंशज भी हैं जो कालान्तर वैश्यों में गिने जाने लगे।

तिब्बत के लोग लामा' को 'ल्हम' भी कहते हैं। यह 'ल्हम' संस्कृत के 'ब्रह्म' शब्द का अपभ्रंश है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन लामा नाम वाले भी मूलतः आर्य ही हैं।

तराई में बसन वाले थारू अपने को सनातन हिन्दू धर्म का ही मानते हैं। थारू शब्द पाली के शब्द 'स्थविर' का अपभ्रंश है। शैवों के विशेष प्रभाव के कारण इस जाति में जादू-टोने और मन्त्र तन्त्र इत्यादि का विशेष प्रचार है।

नेपाल-तराई में कहीं-कहीं इस्लामी संस्कृति की भी झलक मिलती है परन्तु पहना के रहन वाले मुसलमान न तो राम का ही जानते हैं और न रहीम ही को। उन पर तो शैवों के देवी देवता ही सवार हैं। काठमाण्डू के पूर्वी भाग में तो कुछ ऐसे भी मुसलमान मिलते हैं जो बौद्ध मन्दिरों की पूजा करते हैं। सरदार इकबालअली शाह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां मुहम्मद की शिक्षाओं का सर्वथा बहिष्कार किया गया है।

१०

भाषा और साहित्य

हिन्दी और नेपाली भाषा के सम्बन्ध पर साहित्याचार्यों के भिन्न-भिन्न मत रहे हैं। हिन्दी साहित्य के कुछ विद्वान् जैसे नेपाली भाषा का ढाँचा प्राकृत अपभ्रंश से निर्मित मानते हैं उसी प्रकार कुछ लोग खस भाषा को पैशाची तथा दरदी भाषासमूह की उपशाखा मानते हैं। डाक्टर ग्रियर्सन का मत है कि 'खसकुरा' शौरसेनी और मागधी की भांति प्राकृतिक अपभ्रंश का एक रूप है। मूलतः नेपाली भाषा हिन्दी की संतान है जिसमें पाली तथा प्राकृत के अपभ्रंश शब्दों की प्रचुरता है। नेपाल में बौद्ध धर्म के फैलने के साथ ही साथ पाली भाषा भी खूब फैलती गई। यह पाली भाषा अपने सांस्कृतिक रूप को छोड़कर व्यावहारिक रूप में परिणत हो गई।

खसों की बोली 'खसकुरा' का उद्भव-स्थान नेपाल की पाली व पश्चिम माण्डलिकी प्रदेश है। प्राचीन इतिहास तथा वाङ्मय में इसके सम्बन्ध में काफी सामग्री मिलती है। खस जाति आर्यों में भी प्राचीन जाति बताई जाती है। इसका निवासस्थान उत्तर-पश्चिम पहाड़ बतलाया जाता है। नेपाल पर्वतों में बोली जाने वाली बोली को ही आज 'पर्वतिया' कहते हैं। यह भाषा अभी तक संसार की अन्य भाषाओं के समक्ष अनुभव दशा में है। यूरोप में जैसे 'वालापुक' और 'एसपरेन्टो' तथा हिन्दुस्तान में 'हिन्दुस्तानी' खिचड़ी भाषाएं बनीं उसी प्रकार नेपाल में यह 'नेपालीकुरा' भी खिचड़ी भाषा कही जा सकती है। राणा शासकों की उपेक्षा-नीति के कारण नेपाली भाषा विकसित नहीं हो सकी और उसमें संस्कृत पाली अरबी फारसी अंग्रेजी तिब्बती तथा चीनी भाषाओं के शब्द घुल-मिल गए। तिब्बती वाङ्मय में 'ने' अथवा मध्य तथा 'पा' अर्थात् देश अर्थात् 'नेपा' शब्द का अर्थ 'मध्यदेश' होता है। नेपाल 'नेपा' का सांस्कृतिक रूप है। 'ल' केवल एक प्रत्यय है। कुछ लोगों का कथन है कि 'ने' मुनि का बसाया हुआ होने के कारण 'नेपाल' नाम पड़ा। कहाँ तक यह सत्य है, कहना कठिन है। कुछ लोग यह नहीं मानते कि 'ने' नामक कोई मुनि भी हुए हैं। इतिहासविदों ने 'ने' नामक गुप्तवंशज एक राजा का उल्लेख किया है। यह भी सत्य है कि 'निमि' नामक एक राजर्षि हो गए हैं और उसी के आधार पर 'निमिपाल' से 'नियाल' और क्रमशः उच्चारण-सौकर्य के फलस्वरूप 'नेपाल' हो गया। ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। यह भी सत्य है कि तिब्बत में ऊन को 'ने' कहते हैं और 'पा' का अर्थ 'वास होता' है। इसलिए 'ने' में 'पा' जोड़ दिए जाने पर 'नेपा' का अर्थ 'ऊनवासी' होता है।

काठमाण्डू को नेवारी भाषा में 'ये' और तिब्बती में 'यम्बू' (यम्बी) पाटन

को नेवारी में 'यल' और तिब्बती में 'यारंग'। भादगांव (भक्तपुर) को नेवारी में 'ख्वोप' और तिब्बती में 'खोखोंग' कहते हैं। ऐसे ही बहुत से नगर, गांव तथा तीर्थ हैं जो नेवारी और तिब्बती में एक प्रकार से उच्चारित होते हैं। ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से काठमाण्डू की प्रमुख भाषा नेवारी तथा तिब्बती भाषा एक ही परिवार की सगी बहिनें हैं।

बोलियां

काली और गण्डक नदियों के बीच मध्यवर्ती प्रदेश में नेपाली भाषा पर राजपूतों के सम्पर्क से राजस्थानी बोली की छाप पड़ी है। यहां की बोली पर ब्रजभाषा का अधिक और अवधी का कम प्रभाव पड़ा है। पूर्वी तराई में मैथिली तथा मध्य तराई में भोजपुरी बोली जाती है। परन्तु पश्चिमी तराई में एक ऐसी भी बोली बोली जाती है जो गढ़वाल तथा कुमायूं की बोली से अधिक मिलती-जुलती है। भीतरी मधेश की शिवाली तलहटी में 'थरुहटी' बोली है जिसे केवल थारू लोग बोलते हैं। इन सब बोलियों के मूलस्रोत तो प्राचीन हिन्दी में निहित हैं। सुदूर पश्चिम में 'डोटाली' भाषा बोली जाती है जो डोटी के नाम पर बनी है।

पर्वती बोलियां नेपाली बोलियों की समूह भी हैं। इनमें गुरुङ, तामाङ, स्यार्पा, ल्होमा, मान्पा, लिम्बू, किरांती, मुर्मी, सुनवार, मगरी, थके और तिब्बती-बर्मी भाषा की भी बोलियां सम्मिलित हैं। नेवारी तथा तिब्बती बोलियां एकाक्षरा-सी हैं और चीनी परिवार की हैं। तिब्बती भाषाओं की भांति नेवारी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकी है, और एक-एक शब्द के प्रायः कई कई अर्थ होते हैं।

पर्वती बोलियां में गीतों की मधुरता है। इनमें झाउरे, झ्याउरे या झ्याउरिया, सवाई, देउसरे, गुवारी, मालसिरी, रत्नी, फागुन, संगिनी, चैत, असारे, साउन, नाची, फूस्पोल और बारहमासे आदि गीत विशेष रूप से गाये जाते हैं।

नेपालीभाषा को 'गोरखाली' भी कहा जाता है। 'गोरखा' (गर्खा) शब्द से निकला हुआ मालूम होता है जो जिला, परगना या भूमि का पर्यायवाची है। 'गर्खा' का अर्थ बनी बस्ती होता है। जैसे—नेपाली को गोर्खाली कहना असंगत है उसी प्रकार नेपाली भाषा का गोरखाली कहना भी आपत्तिजनक है।

लिपियां

नेपाल में रोमन्, रंजा, भुजिम् और नगरी में उर्दू फेंसी इत्यादि लिपियां प्रयुक्त की जाती हैं परन्तु देवनागरी तो समस्त नेपाल की राष्ट्र-लिपि और धर्मलिपि दोनों ही है। नेपाली भाषा में फारसी के भी काफी शब्द प्रचलित होते हैं। इनमें हजूर, मालिक, तमस्सुक, रैयत (रैती) इत्यादि अत्यधिक साधारण हैं।

साहित्य

साहित्य और कला की दृष्टि से नेवारी भाषा का भी अपना स्थान है। पुराने शासकों

ने नेवारी और हिन्दी भाषा का प्रचलन बिल्कुल बन्द कर दिया था। कोई साहित्यकार नेवारी भाषा में कुछ लिखने-पढ़ने नहीं पाता था। बहुत पहले तो इस भाषा का इसलिए प्रचार नहीं हो पाया कि उस समय पाली प्राकृत और अपभ्रंश आदि का बोलबाला था। नेवारी व्याकरण पहले एक जर्मन विद्वान् ने लिखी। इसके पश्चात् अमर शहीद शुक्रराज शास्त्री ने सन् १९३० ई० में नेवारी भाषा की संक्षिप्त व्याकरण रची।

नेपाली भाषा का साहित्य समृद्धिशाली नहीं हो पाया है। सन् १९२१ ई० में डाक्टर टर्नर ने बहुत परिश्रम से नेपाली भाषा का शब्दकोष तैयार किया। इसमें अभी तक भाषा विज्ञान इन्जीनियरिंग दर्शन शिल्प व्यापार, ज्योतिष भौतिक शास्त्र तथा कला आदि विषयों पर पुस्तकें ही नहीं लिखी गई हैं। इस भाषा में सर्वप्रथम छन्दोबद्ध धार्मिक रचनायें रघुनाथ भट्ट तथा परमानन्द की मिलती हैं। इसके पश्चात् बाइबिल का अनुवाद नेपाली भाषा में हुआ। आदिकवि भानुभक्त नेपाली साहित्य के संत तुलसीदास माने जाते हैं। जिन्होंने भी एक 'रामायण' लिखकर राष्ट्रीयता फैलाई। तराईवासियों की भाषा हिन्दी है। इसी में तराई का सारा काम-काज होता है। धीरे-धीरे हिन्दी पहाड़ों में भी घुस गई है और अब नेपाल सरकार ने इस भाषा को मान्यता दे दी है। तराई-निवासी हिन्दी भाषा ही में पुस्तक आदि लिखते हैं। यही हिन्दी पड़ोसी भारत की राष्ट्रभाषा है जो पूर्ण विकसित विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं के समकक्ष पहुंच चुकी है।

नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त के पश्चात् कुछ साहित्यकारों द्वारा महाभारत और भागवत तथा अध्यात्म रामायण का श्लोकबद्ध अनुवाद नेपाली में लिखा गया। इसी समय कुछ गद्य लेखकों ने उर्दू तथा फारसी के उपन्यासों का अनुवाद किया। इसी समय कुछ लोगों ने उर्दू की कविताओं के आधार पर भक्तिरस की कवितायें लिखीं। अनुवाद के क्षेत्र में अभिज्ञान शाकुन्तलम् विक्रमोर्वशीय बुद्धि चाणक्य तथा हितोपदेश विशेष प्रसिद्ध हैं।

बीसवीं शताब्दी के पहले का नेपाली साहित्य बहुत पिछड़ा हुआ है किन्तु बीसवीं शताब्दी का पदार्पण होते ही नेपाली साहित्य में विकास होने लगा। सन् १९१० ई० में रामपुर पं० हेमराज ने नेपाली भाषा की 'चन्द्रिका' नामक व्याकरण लिखी। इसके पश्चात् पण्डित सोमनाथ ने 'मध्य चन्द्रिका' तथा पण्डित देवीदत्त पराजुली ने 'शब्दरूप' की रचनायें कीं।

सन् १९१५ ई० के बाद पण्डित शम्भुनाथ ने 'ऋतुविचार' 'सत्य-कलि-सम्वाद' तथा 'बुद्धि-विनोद' नामक पुस्तकों की रचना की। साहित्यिक दृष्टि से तो इन पुस्तकों का महत्त्व अवश्य है किन्तु इनमें से किसी में भी सामयिक समस्याओं की झलक मात्र नहीं मिलती है। इसी समय मोतीराम का एक संग्रह 'सूक्ति सिन्धु' तथा पण्डित धरणी शर्मा के 'नैवेद्य' प्रकाशित हुए, किन्तु उनका कोई विशेष प्रचार नहीं हो सका।

सन् १९२४ ई० में प्रधान मंत्री चन्द्र शमशेर ने 'गोरखा भाषा प्रचारिणी' नामक

एक प्रकाशन संस्था खड़ी की जिसका उद्देश्य राणा सरकार का समर्थन करना तथा विद्या सभा के लिए पाठ्य-पुस्तकों को प्रकाशित करने की स्वीकृति देना था। बाद में अंग्रेजी संस्कृत तथा बंगाली भाषा के भी दो-तीन ग्रंथ नेपाली भाषा में अनूदित हुए।

सन् १९१ ई० के पश्चात् साहित्यकारों का ध्यान गद्य की ओर विशेष रूप से गया। इस युग में काव्य, उपन्यास, कहानी तथा नाटक विषयक ग्रन्थों की रचनाएं हुईं। इसी काल में अंग्रेजी-नेपाली शब्दकोष तथा कहावतों, मुहावरों और दन्तकथाओं के संग्रह भी प्रकाशित हुए।

सन् १९१ ई० के अन्त में नेपाली साहित्य पर हिन्दी तथा बंगाली भाषाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। इस समय की जितनी रचनायें हैं जनता के लिए एक न एक संदेश लेकर आती हैं। काव्य के क्षेत्र में पण्डित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आदि कवियों ने विशेष प्रयास किया है। पण्डित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा की रचनाओं में प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों प्रकार के कवियों की शैलियां पाई जाती हैं। इनकी कविताओं में रहस्यवाद, छायावाद तथा कुछ अन्य वादों की भी छाप देखने को मिलती है। जन गीतकारों में धर्मराज थापा का नाम उल्लेखनीय है। थापा के गीतों में संगीत के साथ ही साथ राष्ट्रीयता तथा मौलिकता भी पाई जाती है।

बालकृष्ण 'सम' तथा भीमनिधि तिवारी दृश्य काव्य के कुशल कलाकार हैं। 'सम' की काव्य-पुस्तकों में 'मुटुको व्यथा', 'ध्रुव' और 'प्रह्लाद' सुन्दर हैं। भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों की सुन्दर अभिव्यञ्जना है। गद्य-साहित्य में रुद्रराज पाण्डेय के 'प्रायश्चित' तथा 'रूपमती' का मौलिक उपन्यास हैं। इन दोनों के अतिरिक्त इनका विलायत और भारतवर्ष का इतिहास तथा 'नवरत्न' भी पठनीय हैं।

पत्र-पत्रिकाएं

नेपाल का सर्वप्रथम पत्र 'गोरखा पत्र' था जिसे नेपाल के प्रधान मंत्री देव शमशेर ने जन्म दिया। यह पत्र अब तक सरकारी है और इसका प्रकाशन सप्ताह में तीन बार होता है।

सन् १९१५-१७ ई० में मुख्या देवीप्रसाद सापकोटा के सम्पादकत्व में 'गोरखाली' नामक एक साप्ताहिक पत्र बनारस से प्रकाशित हुआ किन्तु पांच वर्ष के बाद राणा सरकार ने भारत सरकार से कहकर इसे बन्द करवा दिया। इसके बाद सन् १९२७-२८ में ठाकुर चन्दन सिंह के सम्पादकत्व में देहरादून से 'गोरखा संसार' और 'तरुण गोरखा' राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुए। राणा सरकार ने इन पत्रों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया और कोई नेपाली इन्हें नेपाल की सीमा में नहीं ले जा सकता था। सन् १९४४-४५ ई० में ईश्वर सिंह गुरुंग ने दार्जिलिंग से 'भारती' नामक पत्र को जन्म दिया। पत्रों की संख्या जब कम होने लगी तब भारत स्थित नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सन् १९४७ ई० में सूर्यप्रसाद देवकोटा के सम्पादकत्व में 'युगवाणी' नामक एक नया राष्ट्रीय साप्ताहिक

पत्र का प्रकाशन किया। इस पत्र का उद्देश्य राणा सरकार का विरोध तथा नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार करना था।

इसके कुछ दिनों के बाद 'नेपाल पुकार' नामक एक साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होने लगा। 'नेपाल पुकार' हिन्दी और नेपाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसी समय 'नव नेपाल' तथा 'नेपाल टुडे' नामक दो साप्ताहिक पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगे।

१५ जनवरी सन् १९५१ ई० में नई दिल्ली से 'फ्री नेपाल' नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र स्वतन्त्र रूप से भारतीय नेता प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ। नेपाल सम्बन्धी यह पहला ही पत्र था जो विश्व के प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र में भेजा जाता रहा है।

अन्तरिम सरकार की स्थापना हो जाने के बाद काठमाण्डू से नेपाली भाषा में 'आवाज' नामक एक दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हुआ किन्तु कुछ दिनों के बाद वह बन्द हो गया।

इसके बाद कोई भी दैनिक अथवा साप्ताहिक समाचारपत्र नियमित रूप से काठमाण्डू से नहीं प्रकाशित हो सका और इसके लिए जो प्रयास किये भी गये वे असफल ही रहे। अलबत्ता हिन्दी के कुछ साप्ताहिक नेपाल के लिए भारत से प्रकाशित होते रहे किन्तु उनकी भी हालत बहुत खराब ही रही।

११

पहाड़ और तराई

पहाड़ और तराई के सैनिक तथा आर्थिक आधार पर नेपाल जीवित है। एकतंत्री तथा उसके पहले भी सरकारों को दोनों भागों से उतना ही सम्बन्ध था जितने से राज्य का काम चल सकता था। पुरानी सरकारों और जनता के बीच केवल राजस्व वसूल करने तक का सम्पर्क रहा। सबकी दृष्टि राजधानी पर केन्द्रित रहती और यहां के परिवर्तन और मान्यताएं समूचे राज्य पर प्रभाव डालती।

राणाशाही स्थापित होने पर इस दृष्टिकोण में थोड़ा-बहुत परिवर्तन आया किन्तु तब भी राज्य की राजधानी काठमाण्डू ही 'नेपाल' कहलाती रही—शासनतंत्र पर भी यही शहर हावी रहा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजधानी को संतुष्ट रखना अनिवार्य था और शासकों का यही अभिप्राय भी रहा। सारी शक्ति प्रशासकीय तथा राजकीय योजनाएं काठमाण्डू की घाटी में केन्द्रीभूत रहती और पुलिस तथा सेना का जाल राज्य के अन्य भागों में फैलाया जाता।

राजधानी के अतिरिक्त शासकों को देश के किसी भी प्रान्त से भय नहीं रहता। पहाड़ों पर बसने वाले आम पर्वतियों के लिए पुलिस और सेना की सरकारी नौकरी वरदान सिद्ध होती और तराई-वासी सोना उगलने वाली धरती की गोदी में प्रमुदित रहते।

शासकों का तराई से केवल भूमि-कर वसूल करने तक का सम्बन्ध रहता और तराई के निवासी भारत के सहारे ही अपनी सारी आवश्यकताएं, समस्याएं पूरी करते और नेपाल की सीमा में बसे होने के नाते काठमाण्डू की सरकार को भूमि का कर देकर अपना पिण्ड छुड़ाते।

तराई बहुत अरसे से संग्राम-भूमि रही है। मुगल तथा ब्रिटिश साम्राज्यों से नेपाल की लड़ाई इसी प्रदेश पर होती रही। प्रागैतिहासिक काल में किरातों और पाण्डवों की भी लड़ाई यहीं होती बतलाई जाती है। सारांश यह कि तराई शताब्दियों तक साधारण-सी बनी रही। एकतंत्री राणाशाही के विरुद्ध भी जितनी हलचलें आरम्भ हुईं किसी रूप में वह सभी मधेश की ही भूमि पर हुईं।

परिस्थिति के अनुसार जमीन की मांग उसके जंगल और उपजाऊपन के नाते बढ़ती रही और ज्यों-ज्यों आबादी में वृद्धि होती गई त्यों-त्यों वीरान जगह आबाद होती गई। फलस्वरूप तराई अथवा मधेश के लिए एक अलग विभाग ही नहीं बल्कि कानून में भी कुछ भिन्नता बरती गई। पर्वतीय प्रदेश के लिए इस बात की जरूरत नहीं महसूस की गई।

एक ही सरकार के लिए तराई और पहाड़ के भागों का भिन्न महत्त्व मिलने और

ज़मीन आदि के हक की प्राथमिकता पर्वतीय को मिलती। इतना ही नहीं अपितु नेपाल-तराई में भारतीय सिक्के का ही प्रचलन रहने दिया गया। यह सब प्रारम्भिक काल में सही था। इस सद्भाव को रखना उस समय अनिवार्य प्रतीत हुआ जब तराई की भूमि पर आबादी तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगी और इस प्रदेश में जो दिक्कतें रहीं वह दूर हो चलीं।

समस्त की भूमि पर आधिपत्य शासन की मुख्यतः विरासत प्रथा से हुई जब शासक अपने लोगों को खुश रखने के लिए जंगल और ज़मीन के टुकड़े—बख्शीश रूप में देने लगे। धीरे-धीरे यह रोग व्यापक होता गया और समस्त तराई की आधी कृषि योग्य भूमि उसी वर्ग विशेष के हाथों में चली गई जो शासनतंत्र पर भी हावी था। शासकों ने भूमि को प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी दुरंगी नीति से काम लिया। इससे देश को सदमा हुआ और सत्ताधारियों की चाल पहाड़ और तराई दोनों जगह के वासी समझने लगे।

प्रकृति के कोप का भाजन बनकर पर्वतीय सर्वथा विवश थे। उनका भारत से उतना प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था जितना तराई के रहनेवालों का। उन्हें काठमाण्डू की कृपा पर जीना, मरना और उसी की ताबेदारी में व्यस्त रहना पड़ता। शासक उनको तराई में आबाद कराने की बात न सोचकर स्वदेश के बाहर भगाने में अपनी बला टालना समझते। विदेश में सैनिक और दरबान आदि के पद उनके लिए निःसन्देह साबित होते और वे खेती की ओर मुखातिब न होकर नौकरी की ही ओर आगे बढ़ते। तराई वालों की मनोवृत्ति ठीक इसके विपरीत बनती रही और वे नौकरी की अधिक परवाह न करके धरती की ही उपासना करते और शासक वर्ग भी इसको अधिक पसन्द करते।

राणा शासकों की नीयत यद्यपि मधेसियों के प्रति शुरू से अंत तक खराब रही तथापि तराईवासियों की हस्ती बनती ही गई और उनकी आर्थिक हालत खेती के सहारे अच्छी होती रही। पर्वतवासियों की हालत इसके प्रतिकूल रही। यही राणा हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित हुई।

पहाड़ी जनता को तराई में बसने की तथा तराई की जनता को सरकारी नौकरी की भूख बढ़ती ही गई और समय आते ही तराई तथा पहाड़ की जनता कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरुद्ध आन्दोलन कर बैठी।

नेपाल की एकतंत्री सरकार ने जनता की एकता तथा शक्ति को विभक्त और निर्बल बनाने के लिए पहाड़ और तराई में भेदनीति रखी थी। वर्तमान सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि पहाड़ और तराई की एकता और विकास पर ही नेपाल राज्य का अस्तित्व टिका हुआ है। इसी अभिप्राय से यह सरकार की अनुदार नीति का परिवर्तन करके जनवादी सिद्धांतों पर चलने का प्रयास कर रही है।

शासन-व्यवस्था

क्रान्ति के पश्चात् शासन सत्ता जब प्रजातान्त्रिक शक्तियों के हाथ में आई तब

उसके सामने सबसे अहम सवाल प्रशासकीय यंत्र को ही ठीक करने का उठ खड़ा हुआ। वस्तुतः यह एक बहुत बड़ी समस्या साबित हुई और जिसे कोई भी अस्थिर सरकार भला कैसे हल कर सकती थी। दूसरी ओर देश का प्रतिक्रियावादी तत्व भी सोया हुआ नहीं था और वह अपनी जड़ पर कुठाराघात होते हुए देखकर सरकार के इस कदम को पीछे खींचता रहा। इस दौरान में पहाड़ और तराई की जनता को मुश्किलें ही नसीब हुईं और सभी जगह अराष्ट्रीय तत्व सिर उठाकर विकराल रूप धारण करने लगा। शिक्षा के अभाव तथा पुलिस की कमजोरी से तराई प्रदेश राणा शासन के समय से ही अशान्ति का घर रहा। ऐसी स्थिति में चोरी और डकैतियों का ही बोलबाला रहा और यही कारण है जो गर्मी के महीनों में तराई का कोई जमींदार अथवा किसान सुख की नींद सो नहीं पाता। जमींदार आदि अपने बाल-बच्चों को प्रायः भारत के किसी गांव अथवा नगर में भेज देते हैं। गर्मी की ऋतु में डाकुओं का विशेष भय रहता है और वे कभी-कभी नोटिस देकर डाके डालते हैं। नेपाल की तराई में तो एक-एक रात में दो-दो चार चार डाके पड़ना साधारण-सी बात है और निरीह व्यक्तियों की निर्मम हत्याएं हुआ करती हैं। डाके का बहाना लेकर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है। इस प्रकार की घटनाओं में सरकार अपनी विवशता दिखलाकर अपना पिंड छुड़ा लेती है। किसानों के घर फूस के होते हैं। इसलिए तनिक-सी बात पर गांव के गांव फूंक दिए जाते हैं। नेपाल सरकार की पुलिस इतनी निकम्मी, अकुशल और घूसखोर रही है कि वह प्रायः चोरों और डाकुओं से मिलकर जनता की लूट में हिस्से लेती रही।

नेपाल और भारत के बीच में कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। दोनों देशों के बीच एक चौड़ी सड़क बना दी गई है जिसे 'दस गजा' कहा जाता है। इसी सड़क में ईंट के खंभे खड़े कर दिये गये हैं। ये खंभे मील-मील की दूरी पर खड़े हुए दूर ही से सफेद रंग के दृष्टिगोचर होते हैं जो दोनों देशों की सीमा निर्धारित करते हैं। नेपाल के लोग भारत को 'मद्‌ठासार' भी कहते हैं। मद्‌ठासार का अर्थ होता है गम के पार वाला देश। नेपाल के लोग भारत को अब भी प्रायः 'मुगलान' अथवा 'मधेसी' ही कहा करते हैं। 'दस गजा' पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। इस सीमा पर दिन दहाड़े डकैती होती है परन्तु तब भी एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते। मान लिया कि सीमा पर नेपाल का एक गांव है और उस गांव में आग लगी या डाका पड़ा तो उसी के सामने भारत के गांव वाले दस गजा पर खड़े होकर सिवाय तमाशा देखने के और कुछ भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि सीमा पर स्थित गांवों में प्रायः डाके पड़ा करते हैं। इतना ही नहीं, लोग हत्याएं करके भी इधर उधर हो जाते हैं। मान लिया भारत के एक व्यक्ति ने नेपाल के किसी नागरिक को मार डाला और दस गजा पार कर तुरन्त ही भारत की सीमा में आ घुसा तो इस परिस्थिति में न तो नेपाल की पुलिस ही पकड़ सकती है और न ही नेपाल की जनता ही। इस प्रकार के मामलों में तो यही कह दिया जाता है कि अपराधी तो मद्‌ठासार हो गया।

नेपाल में एक प्रकार के 'पिसनखोर' होते हैं। ये मकान को पार अनुमोदित करके जिसकी चोरी कर लेते हैं उससे पनाही वसूल करते हैं। 'पनाही' दण्ड-स्वरूप उस जुर्माने को कहते हैं जो चोर को इच्छित बाध्य होकर देना पड़ता है जिससे चोर चोरी का माल वापस कर दे। 'पनाही' पाने पर ही चोर चोरी का माल वापस करता है। बड़े-बड़े डाकू इसमें मध्यस्थता का काम करते हैं।

नेपाल सरकार की असमर्थता भारतीय डाकुओं को भी नेपाल की तराई में पनाह पाने का प्रमुख कारण रही है। भारत सरकार और नेपाल सरकार में यद्यपि एक संधि द्वारा डाकुओं आदि को पकड़ने के लिए एक दूसरे के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है तथापि यह रवैया नेपाल में अभी जारी ही है।

अस्पताल तथा डाकघर

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में टुंडी खेल के मैदान के पास एक मिलिटरी अस्पताल है। इसमें केवल असाध्य रोगों से पीड़ित सैनिक ही भरती किए जाते हैं। इसके प्रबन्ध के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड है जिसे कुछ वार्षिक सहायता मिलती है। इसी के समीप 'सिविल वीर अस्पताल' है जिसमें केवल सौ ही रोगियों के रहने के लिए स्थान है। इन्हीं दोनों अस्पतालों के पास एक जनाना अस्पताल भी है। जिसका नाम 'वीर पौषक अस्पताल' है। इसके अतिरिक्त काठमाण्डू में एक टोखा सेनीटोरियम है जिसमें क्षय के रोगियों की दवा होती है।

पहाड़ी प्रदेश तथा तराई में अच्छे अस्पताल नहीं हैं। प्रत्येक जिले की छावनी पर एक छोटी-सी सरकारी डिस्पेन्सरी अथवा औषधालय एक मामूली डाक्टर के निरीक्षण में रहता है। इन डिस्पेन्सरियों से आम जनता को दवाइयाँ नहीं मिल पाती। फौजदारी तथा हत्या आदि के मामलों में जिले के डाक्टर को हजारों रुपए घूस देकर अपराधी अपनी सुरक्षा का मार्ग निकाल लेता है।

तराई में नाना प्रकार की भयंकर बीमारियाँ फैलती रहती हैं। क्वार तथा कार्तिक के महीनों में तो मलेरिया तथा जूड़ी बुखार का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है। ज्येष्ठ-बैसाख में चेचक, हैजा तथा ताऊन से पीड़ित होकर जनता त्राहि त्राहि करने लगती है परन्तु अब भी सरकार की ओर से जनता के स्वास्थ्य के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता रहा। इस प्रकार प्रति वर्ष लाखों प्राणी रोगों के शिकार हो जाया करते हैं। अस्पतालों के अभाव के कारण जनता विवशतः झाड़ों और टोनों से अपना काम चलाने का प्रयत्न करती रही है। ये लोग जनता को हर बीमारी में भूत प्रेत का प्रकोप बतलाते हैं। आकुल जनता इस आशा के जाल में पड़कर अपना सर्वस्व गँवा बैठती रही है। गाँवों में हैजा तथा ताऊन पड़ने पर लोग बड़े बकरे की बलि आदि सुलभ करते हैं और प्रतिदिन प्रातः तथा सायं मैदान में जाकर तार स्वर से हृदयविदारक डमरू बाजों से देवी-देवताओं की पुकार

भयानक लगते हैं। पहाड़ों पर जनसाधारण को जड़ी बूटी के अतिरिक्त अन्य कोई दवा मिल ही नहीं पाती। वे उतने पढ़े-लिखे होते ही नहीं जो आयुर्वेद के ग्रन्थों आदि को देखकर जड़ी-बूटियों को पहचानकर उनका सदुपयोग कर सकें। भयानक बीमारी हो जाने पर उन लोगों को ऊंची ऊंची चोटियों से कूद कूद कर आत्म-हत्या कर लेनी पड़ती है। नेपाल में किसी भी प्रसिद्ध डाक्टर को पहले जमने ही नहीं दिया जाता था। देश की अधिकांश भूमि डाक्टरों तथा आधुनिक औषधियों से अछूती रही है।

यातायात तथा संचार

नेपाल में काठमाण्डू, वीरगंज तथा विराटनगर आदि को छोड़कर कहीं भी तार एवं डाक की समुचित व्यवस्था नहीं है। पहाड़ तथा तराई के सभी जिलों में डाक-व्यवस्था नियमित रूप से चालू नहीं है, प्रत्येक जिले तथा तहसील में एक डाकघर रहता है जिससे आम जनता का सम्पर्क प्रायः नहीं रहता।

जेल का प्रबन्ध

नेपाल में एक सेन्ट्रल जेल है, जिसमें दो हजार कैदियों के रहने का स्थान है। इस जेल के लिए एक अस्पताल है जिसमें कैदियों की दवा होती है। राजधानी में नक्खू नामक एक और जेल है जो बहुत खराब माना जाता है। तराई के कैदियों को पहाड़ी जेलों में अधिक दिन रहने के कारण उन्हें पहाड़ का पानी लग जाता है। नेपाल में पानी लगता भी है और पानी चलता भी है। इस पहेली को पूरी तरह वही समझ सकते हैं जो नेपाल की आन्तरिक हालत से भली भांति परिचित हैं। नेपाल में अपराधियों को 'काठ मारने' तथा 'हुरेस मनाने' की प्रथा है। इसके अनुसार कैदियों के दोनों पैरों को एक बड़ी लकड़ी के सुराख अथवा जंजीर में डालकर ताला लगा दिया जाता है। महिलाओं के लिए भी किसी विशेष सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है। नेपाल के बन्दियों से कोई काम नहीं लिया जाता।

अन्तरिम सरकार ने फांसी की सजा रद्द करके 'जेल विधि' में कुछ सुधार किए हैं। इन सुधारों के फलस्वरूप जेल की संख्या बासठ से घटाकर बारह कर दी गई है और जेलों में 'क' श्रेणी के बन्दियों को लिखने-पढ़ने तथा मिलने जुलने की सुविधा मिल गई है। 'ख' श्रेणी के बन्दियों को खाद्य-सामग्री के अतिरिक्त कुछ पैसा भी देने की व्यवस्था है। नेपाल के जेल सेंट्रल जाने से किसी प्रकार भी अच्छे नहीं हैं। बन्दी को प्रायः अपने घर से खाद्य-सामग्री तथा वस्त्र मंगाकर किसी प्रकार अपनी अवधि काटनी पड़ती है। जेलों की यह व्यवस्था विदेशी जमाने की याद दिला रही है और जो किसी भी प्रजातान्त्रिक देश के लिए शर्मनाक की बात है।

१२

शिक्षा

नेपाल में शिक्षा का नितान्त अभाव है। यहां की जनता एक प्रतिशत से भी कम साक्षर है। सन् १९१२ ई० में इंग्लैण्ड के सम्राट् जार्ज पंचम जब भारत आये थे तब उनके साथ नेपाल के तत्कालीन प्रधान मंत्री चन्द्र शमशेर से बातचीत हुई थी। कहा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पंचम ने जब उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि नेपाल में शिक्षा बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो चन्द्र शमशेर ने कहा था कि नेपाल में शिक्षा का वास्तव में अभाव है और जिसका फल यह है कि हमारे नेपाल में तिलक और गोखले जैसे क्रान्तिकारी पैदा नहीं होने पाये।

महाराज चन्द्र शमशेर के इस कथन से राणा शासकों की नीति स्पष्ट हो जाती है कि उनका प्रयत्न सदा यही रहा है कि नेपाल में शिक्षा का प्रचलन कभी भी न होने पाये अन्यथा जनता में शिक्षा का प्रचार हो जाने से क्रान्तिकारी भावनायें स्वतः ही उत्पन्न हो जायेंगी और राणाशाही की ईंट भी हिलनी प्रारम्भ हो जायेगी।

राणा शासकों ने अपने तथा महाराजाधिराज के परिवार को भी आधुनिक उच्च शिक्षा से वंचित रखा। तथापि नरेश की अभिलाषा अपनी सन्तानों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलाने की बराबर रही है। महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रमशाह ने अपनी संतानों को उच्च शिक्षा देने के अभिप्राय से प्रधान मंत्री चन्द्र शमशेर से एक अंग्रेज महिला की मांग की और जिसने शाही परिवार को अंग्रेजी आदि की तालीम दी।

पाश्चात्य ढंग के आधार पर नेपाल के प्रधान मंत्री वीर शमशेर ने सर्वप्रथम सन् १८९४ ई० में दरबार हाई स्कूल का सूत्रपात किया। इसके पहले नेपाल के विद्यार्थी भारत जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। नेपाल के प्रधान मंत्रियों में चन्द्र शमशेर वह प्रथम व्यक्ति था जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की सनद प्राप्त की थी।

राणा शासन में शिक्षा-विभाग प्रायः प्रधान मंत्री के मातहत रहता था और निरीक्षण करने के लिए एक डाइरेक्टर जनरल और उसके नीचे डिप्टी डाइरेक्टर और जिसके मातहत चार इन्सपेक्टर होते थे।

राणा सरकार प्रतिवर्ष कुछ विद्यार्थियों को वजीफ़ा देकर भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजती थी किन्तु वह उनसे प्रायः गुप्तचर का काम लेती थी। विद्यार्थियों को राणा शासकों के पास रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी जिसमें राणा सरकार के विरुद्ध भारत में समस्त कार्यवाइयों का विवरण देना पड़ता था।

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में एक त्रिचन्द्र कालेज है जिसमें बी० ए० तक-तक का

बी॰ काम॰ तथा बी॰ एस-सी॰ तक की पढ़ाई होती है। यह पटना विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। समस्त देश में चालीस हाई स्कूल लड़कों के लिए तथा एक कालेज काठमाण्डू में लड़कियों के लिए है। जिला केन्द्रों तथा छोटे-छोटे कस्बों को मिलाकर सब छह सौ मिडिल स्कूल तीन सौ अस्सी प्राइमरी स्कूल दो सौ चौहत्तर संस्कृत पाठशाला, एक सैन्ट्रल नर्सरी स्कूल, एक सैन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल बेसिक शिक्षा के लिए खुले हुए हैं। इनमें अधिकांश गैर-सरकारी और अर्द्ध-सरकारी हैं। काठमाण्डू में अध्यापिकायें सेवाग्राम से शिक्षा प्राप्त करके खादी तथा घरेलू उद्योग-धन्धों तथा ग्रामोन्नति के कार्यों की शिक्षा देती हैं। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि पच्चीस-छब्बीस लाख की जनसंख्या वाले गोरखपुर जिले में जितने कालेज, मिडिल स्कूल तथा बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं और जितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं और जितना पैसा शिक्षा पर व्यय किया जाता है उतना एक करोड़ की जनसंख्या वाले एक स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल में नहीं होता। त्रिचन्द्र कालेज को खोलकर महाराज चन्द्र शमशेर ने उस राणाशाही को कब्रिस्तान की सजा दी थी।

संस्कृत साहित्य में अभिरुचि

धार्मिक देश होने के नाते पहाड़ी लोग संस्कृत के प्रेमी होते हैं। उनमें पुस्तक कण्ठस्थ करने का सर्वसाधारण प्रचलन है। उनका स्वर भी मधुर होता है। वे वेदों का पाठ भी शुद्ध करते हैं और उनके पाठ में माध्यन्दिनीय और राणायनीय पाठों का सम्मिश्रण होता है। सामवेद के प्रति विशेष अभिरुचि होने के कारण वह पद्य को भी गा गा कर पढ़ते हैं। ब्राह्मण लोग अपने लड़कों को संस्कृत पढ़ने के लिए 'काशी जी' (बनारस) भेज देते हैं। काशी जाकर वे बेचारे भिक्षा मांगकर अपना विद्यार्थी-जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें से प्रायः सबकी बुद्धि तीव्र होती है और अल्पकाल में धार्मिक ग्रन्थों को कण्ठस्थ करके अपने देश लौट जाते हैं।

महाराज चन्द्र शमशेर ने 'गोरखा प्रचारिणी' नामक संस्था खड़ी की थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक ग्रन्थ, उपन्यास एवं अन्य कथा-साहित्य तथा पाठ्य-पुस्तकों इत्यादि का अनुवाद नेपाली भाषा में प्रकाशित करने की स्वीकृति देनी मात्र था। देव शमशेर ने अपने प्रधान मन्त्री काल में 'गोरखा पत्र' नामक अर्द्ध-साप्ताहिक सरकारी पत्र निकलवाया और यह पत्र आज तक प्रकाशित हो रहा है।

राणा सरकार जनता और कवियों की सबसे अधिक खतरनाक शत्रु रही है। कलम की ताकत से वह इतना डरती थी कि प्रधान मन्त्री चन्द्र शमशेर ने श्री कृष्ण लाल उपाध्याय को केवल इसलिए नौ वर्ष की सजा दी थी कि उन्होंने 'मक्के की खेती' नामक पुस्तक रची थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में सिर्फ इतना लिख दिया था कि मक्के में लट भर जाता [illegible] को नहीं मिलती।

सरकार के डर से लोग अपने देश में धार्मिक तथा साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करते थे। राजनीति की पुस्तकें नहीं छपते थे और न किसी पत्र अथवा पत्रिका

त्रिधा

११

अस्पृश्यता का अभिशाप

नेपाल की राणा सरकार अपने को पूर्णतः 'हिन्दू सरकार' कहती रही है और इसने अस्पृश्यता को अपने शासन में एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बना रखा था और वह उसका संरक्षण करती रही। राणा शासकों ने निःसन्देह गांधीजी की खादी प्रचार योजना की कुछ प्रशंसा तो अवश्य की किन्तु अछूतोद्धार के कारण वे बापू को हिन्दू धर्म का महान् शत्रु के रूप में प्रचार करते थे।

सामन्ती शासक परिवार अछूतों को पशु-कोटि के प्राणी मानता रहा है। अछूत का छुआ पानी पी लेने पर स्वाभाविक 'पानी का मुद्दा' कहलाने वाला मुकदमा चला करता था। 'पानी का मुद्दा' उस मुकदमे को कहते हैं जो हिन्दू धर्म के नाम से नेपाल के उच्चवर्ग के नागरिकों को कट्टर मान्यतायें दी जाती थीं। जो अछूतों के हाथ का छुआ पानी पी लेते थे उन्हें अछूतोद्धारक न कहकर अधार्मिक तथा हिन्दू धर्म का उन्मूलन करने वाला कहकर दोषी सिद्ध किया जाता था। 'पानी को मुद्दा' का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि जो अस्पृश्य जातियों के पात्र का अथवा उनके बर्तन का पानी ग्रहण कर लेने पर मुकदमा चलाया जाय। स्पृश्य जातियों का 'पनिया सिम्मान' माना जाता रहा है और जिनके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता था।

पानी का मुकदमा

'पनिया सिम्मान' जातियों का पानी चलता था। पहाड़ में कामी, सार्की, पोड़, च्यामी और तराई हरिजन नटुआ, साकन, पासी, मरविम, धोबी, तेली, डराई, चमार, मुसहर और मुसलमान आदि परिगणित जातियों का पानी नहीं चलता था। किसी अछूत का छुआ पानी पी लेने पर उस विधान की 'पानी का मुद्दा' की धारानुसार जुर्माना और कारावास भुगतना पड़ता था। जान बूझ कर किसी स्पृश्य जाति वाले व्यक्ति का अपने हाथ का पानी पिला देने पर भी कठोर दण्ड भुगतना अनिवार्य था। स्पृश्य जाति वाले को किसी अस्पृश्य जाति वाले की चिलम पीते हुए पकड़ लिया जाता तो उसको भी समान दण्ड दिया जाता था। 'पानी को मुद्दा' के डर से कोई हिन्दू किसी मुसलमान नाई से न तो बाल ही कटवा सकता था और न ही उसका छुआ पानी ही पी सकता था। हलवाई की दुकान तथा किसी मंदिर में अस्पृश्य जा नहीं पाता। यों तो नेपाल में कतिपय ऐसे मठ-मंदिर हैं जिनके अधिष्ठाता एवं पुजारी अछूत ही हैं।

नेपाल में 'पानी का मुद्दा' बहुत ही विचित्र और बदनाम माना जाता था। इस मुद्दे में जो एक बार फंस जाता था वह बहुत ही अनादर की दृष्टि से देखा जाता था।

इस धारा का दूसरा पक्ष अस्पृश्यों का बहुत बड़ा उपकारक था। यदि कोई अस्पृश्य स्पृश्य-जाति की किसी कन्या अथवा स्त्री से अनुचित सम्बन्ध स्थापित कर ले और दोनों प्राणी उसे न्यायालय में स्वीकार कर लें तो उस पर इस प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाता था। परन्तु यदि कोई स्पृश्य जाति का व्यक्ति किसी अस्पृश्य जाति की कन्या अथवा स्त्री से अनुचित सम्बन्ध स्थापित कर ले और न्यायालय को उसकी सूचना मिल जाये तो उस पर 'पानी को मुद्दा' चला दिया जाता था। मान लिया कोई ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय जमींदार किसी अछूत अथवा मुसलमान की कन्या अथवा स्त्री से अनुचित सम्बन्ध स्थापित करके उसे ठुकरा दे और वह अछूत और मुसलमान कन्या अथवा स्त्री प्रमाण देकर न्यायालय में यह सिद्ध कर दे तो उस जमींदार पर केवल 'पानी का मुद्दा' ही नहीं चलता था अपितु उसे उस जमींदार की सम्पत्ति में से उचित हिस्सा भी मिल जाता था और उस जमींदार द्वारा जो सन्तान उत्पन्न हुई थी वह उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होती थी। यदि जमींदार ने किसी भय से उसके गर्भ के बच्चे को गिरवा दिया और उस स्त्री ने उसे न्यायालय में सिद्ध कर दिया तो उस पर 'पानी को मुद्दा' न चलकर 'खून को मुद्दा' चल जाता था और जमींदार महाशय को बीस वर्ष तक की जेल की सजा मिल सकती थी।

नेपाल में स्पृश्य और अस्पृश्य जाति की पहचान करना कठिन है। इसके लिए राणा सरकार ने कोई खास विधान और परिभाषा निश्चित नहीं की थी जिसके अनुसार झट छूत और अछूत का निर्णय कर लिया जाय।

आधुनिक शिक्षा के व्यापक प्रसार होने तथा प्रजातंत्र आने के साथ ही साथ इसका बंधन काफी ढीला होता जा रहा है और सुशिक्षित समाज उसे कलंक और अभिशाप समझकर इसे समाप्त कर रहा है।

नहीं देता। इतनी ही मजदूरी पर उसे चौबीस घंटे काम करना पड़ता है। हलवाहे की स्त्री को भी इसी दस रुपये माह में काम करना पड़ता है। पति के साथ ही पत्नी पर भी जमींदार का अधिकार हो जाता है। हलवाहे को अपने घर सोने तक की आज्ञा नहीं होती। उसे जमींदार की रानी और उसके घर की चौकसी करनी पड़ती है। जङ्गल की सर्दी जाड़ा में लगती है। तराई में जाड़ा कितना पड़ता है यह तो वही बतला सकते हैं जो तराई प्रान्तों में रह चुके हैं। वनों में नाना प्रकार के कीड़े-मकोड़े भी अधिक होते हैं परन्तु तब भी हलवाहे को खेतों में जाड़े की रातों में जगकर फसल की रखवाली करनी पड़ती है। जमींदार न तो उसे कोई कम्बल इत्यादि देता है और न कोई सुविधा ही। बेचारे मजदूर खेतों में पुआल जला जलाकर रात काटते हैं। अधिक पुआल जलाते सुनकर जमींदार पुआल भी नहीं जलाने देता। उसे भगवान् के सहारे ही अपनी जिन्दगी काटनी पड़ती है।

हलवाहों के अतिरिक्त जो भी मजदूर खेत में काम करते हैं उन्हें पैसे न देकर ढाई-तीन सेर धान दिया जाता है। हिसाब लगाने से पता चलता है कि यह मजदूरी महँगी के समय में भी दस-बारह आने से अधिक नहीं पड़ती। तराई में अच्छे से अच्छे किसानों को भी जमींदारों की मजदूरी करनी पड़ती है और जो किसान मजदूरी करने में हिचकता है जमींदार उसके गाय-भैंसों को अपने गाँव के चरागाहों में घास नहीं चरने देता और उसे ऋण आदि भी नहीं देता।

जमींदारों ने अपने बड़े-बड़े आसामियों से अपना काम करवाने के लिए कई पद भी बना रखे हैं। वे उनको प्रसन्न करने के लिए बड़घर (बड़ घरवाला) महतो (चौधरी) नम्बरदार (नम्बरी खेत जोतनेवाला) तथा दरबारी (दरबार करनेवाला) इत्यादि नाम से प्रसिद्ध कर रखे हैं। तराई का कोई भी ऐसा गाँव नहीं मिलेगा जिसमें दरबारी बड़घर तथा महतो न मिलते हों। इनके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के मजदूरों को प्रसन्न करने के लिए जमींदार हलवाहे (हलवाला) बरदवारे (बैलवाला) गयवारे (गाय चरानेवाला) भैंसवार (भैंस चरानेवाला) घोड़ाहे (घोड़ा चरानेवाला) डाबाहे (बाग की माली-पानी देनेवाला) मावराहे (मावर उगानेवाला) इत्यादि नामों से विभूषित करता है। जमींदार इन मजदूरों को नाममात्र की मजदूरी देकर अपना समस्त कार्य करवाता रहता है।

खेतिहर मजदूरों का संगठन करके उनकी आर्थिक हालत सुधारने तथा बेकार युवकों को रचनात्मक कार्यों में लगाने की योजनाएँ राणाशाही हुकूमत की समाप्ति के बाद भी अभी तक नहीं बन पाई हैं।

नेपाल के तीन ही नगरों में कुछ कल-कारखाने हैं। इनमें विराटनगर का स्थान सर्वप्रथम है। विराटनगर पूर्वी नेपाल की तराई में बसा हुआ है। विराटनगर और बीरगंज में सब अठारह-बीस मिल हैं। देश के मजदूरों की धारणा थी कि नेपाल की

अन्तरिम सरकार उनकी समस्याएं हल करने की दिशा में अग्रसर होकर उन्हें सभ्य देशों के श्रमिकों के समकक्ष लाने में समर्थ हो सकेगी किन्तु सरकार की उपेक्षा तथा अवांछक की दमन-नीति ने उनकी इस आशा को भंग कर दिया है।

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू पहाड़ों के बीच में बसी हुई है जिससे वहां कल-कारखाने बहुत ही कठिनाई से खोले जा सकते हैं। यहां तो केवल नेपाली सैनिक सरकारी कर्मचारी तथा कुछ अन्य श्रमिक ही हैं।

राणा सरकार नेपाल के सभी अफसरों तथा सरकारी कर्मचारियों को वेतन प्रति मास नहीं देती थी। वर्ष के अन्त में वेतन देते समय नौकरों से कुछ 'सलामी' ली जाती थी। दो सौ रुपये पाने वाले सिपाही को कम-से-कम बीस रुपए सलामी देनी पड़ती थी। राणा सरकार प्रायः न तो किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि ही करती थी और न उसे किसी उच्च पद पर ही नियुक्त करती थी। नौकरी से छुट्टी मिल जाने पर उसे पेंशन भी नहीं मिलती थी। उसे महंगाई का भत्ता भी नहीं दिया जाता था।

वह नेपाल के बड़े-बड़े अफसरों को भी पर्याप्त वेतन नहीं देती थी और उन्हें बाध्य होकर घूस लेनी पड़ती थी। उनमें जो न्याय तथा ईमान की रक्षा करते हुए अपने वेतन ही में निर्वाह करते थे। उन्हें न तो कोई उच्च पद ही दिया जाता था और न उनके वेतन में कोई वृद्धि ही की जाती थी। सरकार की इस नीति से सब अफसर बहुत ही दुःखी तथा असंतुष्ट रहा करते थे। कभी-कभी तो सरकारी कर्मचारी ही विद्रोह कर बैठते थे। सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए सरकारी मकान भी नहीं होते थे इसलिए अफसरों को प्रायः दफ्तर की कुर्सी बनाकर ही अपने बाल-बच्चों के साथ खानाबदोशों की भांति अरक्षित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रजा के कार्य के लिए हाकिमों को बार-बार दौरे भी करना पड़ता था किन्तु राणा सरकार उन्हें न तो कोई सवारी ही देती थी और न ही मार्ग-व्यय इत्यादि।

पटवारी के बिना नेपाल सरकार का काम नहीं चल सकता। मालगुजारी तथा गांवों का लेखा-जोखा वही रखता है। वह विशेषतः मालगुजारी ही वसूल करने के लिए नियुक्त होता है। प्रत्येक सरकारी आज्ञा को व्यक्ति-व्यक्ति तक वही पहुंचाता है। उसे भी वर्ष में एक बार ही वेतन मिलता है। पटवारी का वेतन मालगुजारी के अनुपात से नियत होता है। एक ही काम करने वाले एक ही योग्यता के दो पटवारियों का वेतन भिन्न-भिन्न होता है। वेतन को नेपाल में 'रवानगी' भेंट को 'सलामी' तथा घूस को 'पान-खर्च' कहा जाता है।

नेपाल में कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतन के तीस रुपये से भी कम और प्रायः सभी नौकरियां उत्तराधिकार स्वरूप ही मिलती थीं। अन्तरिम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन कम से कम तीस रुपए निश्चित करके इस प्रथा को भी तोड़ देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

एकतंत्री शासन-काल में प्रधान मंत्री आदि मनमाना वेतन लेते थे किन्तु अन्तरिम सरकार की स्थापना के पश्चात् नवीन व्यवस्था के अनुसार उन्हें अब क्रमशः ढाई हजार तथा डेढ़ हजार रुपये मासिक वेतन मिलने लगे हैं। इसी व्यवस्था के अनुसार जिले के बड़े हाकिम तथा सूबों के वेतन भी चार हजार तथा बारह सौ रुपये वार्षिक से ड्योढ़े दूने कर दिये गये हैं। नवीन शासन-व्यवस्था के अनुसार नेपाल में नये-नये विभाग खोले जा रहे हैं। और उन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में आधुनिकता लाई जा रही है। अन्तरिम सरकार वर्ष में एक ही बार वेतन देने की प्रथा तोड़कर सबको प्रति मास वेतन देने लगी है।

मित्र राष्ट्रों की सहायता तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों के सहयोग से देश का औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास करना कोई कठिन काम नहीं है। राज्य एक विस्तृत विकास की योजनानुसार देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का उपयोग करके देश को समृद्धशाली तथा सुखी बना सकता है। इस दिशा में हमारे सामने अपने पड़ोसी भारत और चीन की मिसालें ही काफी हैं जिनके आधार पर नेपाल आगे चलकर बेकारी आदि की समस्याएं भी बहुत जल्दी हल कर सकता है।

१८

किसानों की स्थिति

नेपाल के प्रथम राणा प्रधान मंत्री महाराज जंगबहादुर ने इंग्लैण्ड से वापस आकर 'फूट डालकर शासन करने' की नीति अपनायी। उन्होंने तराई की भूमि खंड खंड करके किसानों को न देकर बड़े-बड़े चौधरियों तथा अपने चाटुकारों को दी। यही चौधरी और जमींदार राणा सरकार के पालतू हाकिम बनकर किसानों का शोषण करते रहे।

महाराज चन्द्र शमशेर ने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए तराई में नापी (पैमाइश) करवाई। इस नापी में नाना प्रकार की धाँधलियाँ की गईं। इसमें जिस व्यक्ति ने जितनी अधिक घूस दी उसे उतनी ही अधिक भूमि मिली। इस प्रकार लाखों खेतिहर किसान बिना जमीन वाले और सैकड़ों बिना खेतवाले महाजन घूस देकर बड़ी बड़ी जोतवाले बन गए।

महाराज चन्द्र शमशेर के पश्चात् भी तराई में नापी करने की प्रथा ही चल पड़ी। नापी (पैमाइश) करने के लिए राणा सरकार तराई में कभी-कभी सरकारी कर्मचारियों के दल के दल भेजती थी। नापी वाले कर्मचारी तराई के आस-पास किसानों की भूमि नापा करके घूस देने वालों का दे देते थे। जैसे नाप की नापी करते समय कोई किसान वहाँ उपस्थित नहीं रहा तो उसकी भूमि नापी वाले घूस लेकर किसी दूसरे आदमी के नाम लिख देते थे और किसी गाँव की मालगुजारी भी घटा-बढ़ा देते थे। यही कारण है कि आज भी नापी का नाम सुनते ही तराई का किसान भयभीत हो जाता है।

नेपाल के पहाड़ी लोग पत्थरों से लड़कर अपने भरण-पोषण के लिए कुछ न कुछ पैदा करते ही रहते हैं। वहाँ पानी का अत्यन्त अभाव रहता है लेकिन तब भी वहाँ के किसान एक-एक मील की दूरी से घड़ों में पानी भर-भर कर खेतों में डालते ही रहते हैं। पहाड़ों में अधिक से अधिक पाँच प्रतिशत व्यक्तियों को भरपेट भोजन मिल पाता है। यही कारण है कि लाखों नेपाली भारत में आकर अपना पेट पालते हैं। पहाड़ों में जमींदारी या नहीं के बराबर है फिर भी वहाँ के 'जिमुवाल' (जमीनवाल) लगान के ठेकेदारों की तरह किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के घर में लूट मारकर अपना घर भरते रहते हैं। इन जिमुवालों का प्रभाव स्थानीय कर्मचारियों पर विशेष रूप से रहता चला आया है और इसलिए कोई भी व्यक्ति इन ज्यादतियों के भी विरुद्ध नहीं जा पाता था।

भीतरी मधेश में कृषि योग्य भूमि थोड़ी-सी अवश्य है किन्तु वह आम मधेश की भाँति उपजाऊ नहीं होती। भीतरी मधेश में भी मक्का बाजरा तथा अन्य विशेष अन्न

न होता है। यहाँ केले इत्यादि की भी खेती होती है।

पश्चिमी भीतरी मधेस में जिमुवाल प्राय बड़ी-बड़ी सीरें ही करवाते हैं। सीर की भूमि जिमुवाल की ही रहती है किन्तु वह आसामियों द्वारा बिना मजदूरी दिए केवल इसलिए जुताई-बुआई जाती है कि व उनकी जमीन में बसे हुए होते हैं। दूसरी प्रकार की खेती को 'मैल' कहते हैं। 'मैल' जिमुवाल की भूमि होती है। अधिया-बटाई (फसल की आधी) अथवा तीसरी प्रकार की खेती को 'बगारी' कहते हैं। बगारी जिमुवाल की भूमि कहलाती है जो असामियों द्वारा बिना मजदूरी इत्यादि के जोती-बोई जाती है किन्तु उसका फल जिमुवाल ही चखता है। इसके अतिरिक्त जिमुवाल बगारी में बिना मूल्य के घी दूध मलाई फल-फूल लकड़ी तथा अनाज इत्यादि किसानों से जबरदस्ती वसूल किया करता है। सशस्त्र क्रांति के समय विद्रोहियों ने उपयुक्त तीनों प्रथाओं को नष्ट करके भूमि किसानों को बाँट दी थी किन्तु बाद की सरकार ने जिमुवालों को संतुष्ट रखने के लिए पुरानी व्यवस्था पुनः स्थापित की जो आजकल भीतरी मधेश में असंतोष का प्रमुख कारण बनी हुई है।

खास तराई में कृषि-योग्य भूमि बहुत अधिक है। उसमें जमींदार बड़ी-बड़ी सीरें करवाते हैं। सरकार ने इसी बगारी बन्द करने की घोषणा कर दी है और उसे अवैधानिक कर दिया है तथापि जमींदार आदि किसानों को मार-मार कर बगारी आदि करते ही रहते हैं। बेगारी देने से जो आसामी आनाकानी करता है उसे जमींदार अपने गाँव से निकाल देने की धमकी देता है। जमींदार की सीर में प्रत्येक आसामी को सहयोग देना पड़ता है। गाँव की खेती का श्रीगणेश जमींदार की ही सीर से होता है। जमींदार की सीर के पहले कोई आसामी अपने खेतों में न तो सिंचाई ही कर सकता है और न बुआई ही। गाँववालों को मिलकर पहले जमींदार की सीर को जोतना-बोना पड़ता है और उसके बाद ही वह अपनी खेती कर पाते हैं। गाँव के पोखरा तालाबों तथा बाग-बगीचों इत्यादि पर जमींदार का सर्वाधिकार होता है। नदियों तथा तालाबों की मछलियाँ भी कोई किसान पकड़ने नहीं पाता।

तराई के जमींदारों ने जैसे अपने आराम के लिए बाग बगीचे लगा रखे हैं उसी प्रकार ताल-पोखरों में भी उन्होंने मछलियाँ रख छोड़ी हैं और प्रतिदिन अपने खाने के लिए उन्हें पकड़ लेते हैं। इन तालाबों अथवा पोखरों में किसानों के मवेशी पानी नहीं पीने पाते। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि किसानों को सताने के लिए जमींदार पोखरा और तालाब को बेच देता है और मछलियों को पकड़ने के लिए उसका सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। पानी बाहर हो जाने पर तालाब बहुत जल्दी सूख जाते हैं। बैशाख और ज्येष्ठ के महीनों में तराई के जानवरों के पानी न मिल सकने का मुख्य कारण जमींदारों की यही स्वार्थपरता और कूटनीति होती है। तराई घास का मैदान कहलाता है और यहाँ अच्छे अच्छे चरागाह भी पाये जाते हैं जमींदारों की क्रूर नीति

का शिकार आसामियों के चौपाये भी होते हैं। बाग तथा बगीचों की रखवाली जमींदार के कारिन्दे तथा मीरधार करते हैं। उनके फल भी गांव के लोग नहीं खाने पाते। जमींदार या तो उस बाग को अपने खाने के लिए रख छोड़ता है अथवा किसी व्यापारी को बेच देता है। आसामी का यदि कोई बच्चा एक आम अथवा अन्य कोई फल तोड़ लेता है तो उससे जमींदार बीसों रुपए दण्ड वसूल कर लेता है।

तराई में अधिकांश ऐसे गांव हैं जिनमें हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य होती है। इसमें से अधिकांश जमींदार की सीर होती है। शेष भूमि आसामियों को अधिया (बटाई) कुन्हा अथवा मालगुजारी पर मिली होती है। सीर की देखभाल करने के लिए जमींदारों ने गांवों में सीर को मकान बना रखे हैं। सीर के मकान में एक कारिन्दा और तीन-चार मीरधार रहकर कुछ हलवाहों की सहायता से जमींदार की पूरी सीर करवाते हैं। ये कारिन्दे तथा मीरधार प्रायः ऐसे लोग होते हैं जो निर्भय होकर निर्ममतापूर्वक किसानों पर खूब अत्याचार करते हैं। इनको जमींदार दो-चार बीघे खेत और आठ-दस रुपए मासिक वेतन से अधिक नहीं देता। जमींदार के कारिन्दे आसामियों से सैकड़ों रुपए नजराना तथा घूस लेकर मालगुजारी पर उनको खेत देते हैं। ये कारिन्दे गांवों में 'बिना टीके के राजा' कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जमींदार कुछ गुण्डे तथा लठैतों को अपने प्रत्येक गांव में कुछ खेत देकर बसाए रहता है जो अपनी लाठी के बल से आसामियों तथा मजदूरों को दाब बनाए रहते हैं। जमींदार की सीर का मकान प्रायः व्यभिचार का अड्डा होता है जहां आसामियों तथा मजदूरों की बहू-बेटियों के सतीत्व के साथ जमींदार के नौकर खुली छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे ही सीर के मकानों को गिरा देने का सारा शांति के समय दिया गया था और जिस अवसर जिले के किसानों ने बड़े उत्साह के साथ पूरा किया।

जमींदार की सीर से जो भूमि शेष बच जाती है उससे जमींदार को फसल की आधी तथा कुन्हा' के अनुसार एक निश्चित रकम मिल जाती है।

नवम्बर सन् १९५० की क्रांति के समय पश्चिमी नेपाल की विद्रोही सरकार ने इन दोनों प्रथाओं को तोड़कर इस प्रकार की समस्त भूमि किसानों को बांट दी थी। इसके अतिरिक्त जमींदारों की बड़ी-बड़ी सीर भी तोड़कर बिना खेत वाले मजदूरों को बांट दी गई थी किन्तु समझौते वाली सरकार ने किसानों से भूमि छीनकर पुनः जमींदारों को लौटा दी। अधिया (बटैया) प्रथा के विरोध में सदा मुल्क के अन्तर्गत राजपुर तथा बेल्था में मई सन् १९५१ ई० को किसानों ने जब एक विराट प्रदर्शन किया तब प्रतिक्रियावादी तत्वों ने निरीह किसानों के ऊपर गोली चलवा दी और एक स्त्री समेत तीन किसानों को गोली का शिकार बनाया और अनेक प्रदर्शनकारियों को घायल कर दिया। इसके अतिरिक्त मोरङ्ग बारा महात्तरी तथा अन्य जिलों में भी किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई और कई किसान कार्यकर्ता मारे गए।

राणा सरकार किसानों तथा जमींदारों को लूटने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे आविष्कार करती रहती थी। इनमें 'दौड़ाहा' विशेष उल्लेखनीय है। इसके अनुसार दौड़ाहा (दौरा करनेवाला हाकिम) किसानों के भूमि सम्बन्धी झगड़ों के निपटाने के लिए अपनी पल्टन लेकर तराई में दौरा करने के लिए राणा सरकार की ओर से दूसरे-तीसरे वर्ष भेजा जाता था। यह तराई में आकर जमींदारों से रुपये घूस लेकर किसानों के खेत छीनकर जमींदार की सीर में मिला देता था। यही कारण था कि दौड़ाहा हाकिम बनने के लिए चाटुकार लोग नेपाल के प्रधान मंत्री को वर्षों सलामी चढ़ाया करते थे। ये लोग प्रधान मंत्री को अपने वश में करने के लिए नाना प्रकार के अमूल्य रत्नों को उपहार में भेंट करते रहते थे। 'दौड़ाहा हाकिम' अपने साथ मुन्शियों की एक टोली भी लेकर चलता था। वह अपना दौरा समाप्त करने के पश्चात् घूस के पैसों से एक इलाका खरीद लेता था और अपने नौकरों तथा कारिन्दों को वहीं नियुक्त करके पुनः अपने स्थान पर चला जाता था। तराई में इस प्रकार दौड़ाहा हाकिमों के सैकड़ों छोटे-मोटे इलाके हो गए हैं। ऐसे इलाकों के किसानों की फरियाद स्थानीय जिला अधिकारी कभी नहीं सुनते थे। इन अधिकारियों को सदा यही भय लगा रहता था कि दौड़ाहा हाकिम जब स्वयं ही हम लोगों के ऊपर एक बड़े मान्य हाकिम हैं तो हम लोग छोटे हाकिम होकर उनके इलाकों के प्रबन्ध में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं।

तराई में यातायात की असुविधा होने के कारण जमींदारों को घोड़े तथा हाथियों का विशेष शौक है। इन्हीं पर बैठकर वे अपने गाँवों तथा इलाकों का निरीक्षण करते हैं। तराई के कुछ जमींदार अपने हाथियों से विशेष कार्य भी लेते हैं। वे रात्रि में अपने हाथियों पर डाकुओं को सजाकर गाँवों में डाका डलवाया करते हैं। डाकू हाथी की पीठ पर रखे हुए हौदा में बन्दूकों को लाद जोड़ कर छिपाये रहते हैं और उसे देखकर किसी व्यक्ति को साधारणतया शंका भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त जब कोई आसामी अथवा मजदूर जमींदार की आज्ञा का उल्लंघन करता है तब जमींदार अपने हाथियों से उसके घर तथा फसल को नष्ट भ्रष्ट करके उसे अपने गाँव से उजाड़ देता है।

पश्चिमी तराई की भूमि-व्यवस्था पूर्वी तराई की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है। पश्चिमी तराई में किसानों के अधिकार में जो भूमि होती है उसे 'निरजा' अथवा 'सम्बरी' कहते हैं। 'निरजा' की मालगुजारी जमींदार अथवा सरकार को दी जा सकती है। निरजा के अतिरिक्त एक 'क' फार्म की भूमि होती है। 'क' फार्म की भूमि वस्तुतः जमींदारों की ओर से किसानों को मिली हुई होती है। जमींदारों ने इस भूमि को भी रिश्वत लेकर दूसरे व्यक्तियों के नाम लिखवा दिया है। यही कारण है जो मध्य तराई के किसान आपस में एक दूसरे का गला काटने के लिए सदा तैयार रहते हैं। किसानों को आपस में लड़ाकर जमींदार दोनों पक्षों का खूब शोषण करते हैं। तीसरी प्रकार की व्यवस्था 'उगड़ा भूमि' कहलाती है। 'उगड़ा भूमि' उस भूमि को कहते हैं जो जमींदार तथा

आसामी की ओर से बकिया हुआ अथवा मालगुजारी पर साल दो साल के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती है। 'उखड़ा भूमि' का लगान वास्तविक लगान से कई गुना अधिक वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह उससे 'बढ़पोत' भी लेता रहता है जो लगान से ऊपर अधिक धन होता है।

सामन्ती अत्याचारों से तंग आकर, पूर्वी तराई के किसान बिरता और जमीदारों के विरुद्ध वर्षों से आवाज बुलन्द करके आन्दोलन छेड़ते आ रहे हैं।

विगत जनक्रांति में तराई के अधिकांश जमीदारों ने अपनी सीर की सुरक्षा के लिए नाना प्रकार के उपायों का प्रयोग किया। उन लोगों ने राणा सरकार तथा जनता



कुछ किसान कार्यकर्ता

दोनों का साथ दिया। राणा सरकार की दृष्टि में समर्थक बनने के लिए एक ओर तो वे पंच मालियों का कार्य करते रहे और दूसरी ओर जन-सेना में भरती होने के लिए अपना एक भाई अथवा कारिन्दे को जन-सेना में भेज देते रहे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जमीदार थे जो अपने को राणा सरकार का समर्थक तथा भक्त कहकर सरकारी सैनिकों के साथ हो विद्रोहियों की जन-सेना पर आक्रमण करते रहे। पश्चिमी नेपाल में बुढ़कम्पी जिले के कुछ राणा सरकार के भक्त जमीदारों ने सरकारी सैनिकों से अस्त्रशस्त्र प्राप्त करके जिगिना नामक स्थान पर एक जमीदार की कोठी में अपना फौजी अड्डा बनाया और जन-सेना पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। बीसों हजार विद्रोही किसानों तथा

मजदूरों की जन-सेना ने उनका हथियार रख देने के लिए ललकारा किन्तु जमींदारों ने उसका उत्तर गोलियों से दिया। फलतः विद्रोही किसानों तथा मजदूरों की जनसेना ने उन पर आक्रमण करके उनको समाप्त कर दिया और उनके अस्त्र-शस्त्रों को भी छीन लिया।

पूर्वी नेपाल तराई में भूमि-व्यवस्था दूसरी तरह की है। यहां ऐसे भी सामन्त हैं जो सिर्फ आठ-दस बीघे के जमींदार हैं, किन्तु वे हजारों बीघों के जोतदार होते हैं। पूर्वी तराई में मीर को जिरायत तथा मोर के मकान को कामत कहते हैं। यहां खेत को अधा बटाई (अधिया बटाई) तथा हुण्डा आदि पर कमाने का साधारण रिवाज है। मालिक और किसान दोनों खुशी से इस प्रथा का पालन करते हैं।

राणा शासन काल में पूर्वी तराई में शासकों के अधिक संपर्क रहे। पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी तराई की भूमि पर अधिक भार है और वह उपजाऊ तथा कीमती भी अधिक है। लिम्बुवान खास किरात में किपट प्रथा है। किपट लिम्बुवान जाति की पुश्तैनी चीज है और जिसका सम्बन्ध लिम्बू अपने धर्म से जोड़ते रहे हैं। किपट दो प्रकार के हैं जो निराधार हैं। किसी लिम्बू की जमीन जब गैर लिम्बू जाति की हो जाती है तब वह किपट न कहलाकर 'रैकर' कहलाने लगती है। लिम्बुवान की सबसे विकट समस्या यही है और जो आम जनता की गरीबी का एक कारण बनी हुई है।

निर्धनता

नेपाल का किसान अपना वही पुरातन हल लेकर खून-पसीना एक करके खेती करता है परन्तु तब भी उसको इतना अनाज नहीं मिल पाता जिससे कि वह अपनी साधारण दैनिक आवश्यकताओं को पूरी कर सके। उसे प्रतिवर्ष कर्ज पर कर्ज लेना पड़ता है और फसल कटते ही अपने महाजनों को खाता चुकता करना पड़ता है। नेपाल में सूद भी ज्यादा दूना देना पड़ता है। जमींदार प्रतिवर्ष अपने आसामियों को अनाज 'बिसार' देता है और ६ माह पूरे होते ही उधार की सवाई मार-पीट कर वसूल कर ली जाती है। नेपाल का किसान कर्ज ही लेकर जीवन-पर्यन्त बैलों के साथ खेती में काम करता है। जाड़ा गर्मी और बरसात की कुछ भी परवाह न करके वह हर दम खेती की बाजी लगाता रहता है परन्तु तब भी उसे कर्ज ही लेकर अपने जीवन का भी प्रबन्ध करना पड़ता है।

किसान स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी होता है। उसे अपने समाज में रस्म रिवाजों को आंख मूंदकर मानना पड़ता है और उसे पग-पग पर सामाजिक नियमों का पालन पूर्णतया करना पड़ता है। समाज से बहिष्कृत होने के लिए ही वह डरता है। वह अपने बाल-बच्चों के विवाह आदि में अधिक खर्च करता है। विवाह तथा त्योहारों के अवसरों पर निर्धन से निर्धन किसान भी अपना नेम पालता था। तरह बराबर समाज में अपना सर ऊंचा रखने का प्रयत्न करता है। मितव्ययता उसके समाज में कंजूसी समझी

जाती है और मितव्ययता से काम लेने पर उसकी नाक कट जाती है। वह कर्ज लेकर इस हँसाई से बचने का प्रयत्न करता है।

नेपाल में किसानों को ब्राह्मण तथा साधु महन्त बुरी तरह लूटते हैं। मरनी करनी में तो उसकी और भी दुर्दशा की जाती है। ब्राह्मण अथवा बिरादरी भोज दिये बिना उसका समाज में उद्धार ही नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त तीर्थ-व्रत न करने से वह पापी कहा जाता है और अन्त में उसे नरक ही मिलना बताया जाता है। ग्राम-ग्राम का मुखिया होते हुए भी उसे कर्ज पर कर्ज लेकर अपने समाज-बन्धु-बान्धव तथा मालदारों को समय-समय पर खिलाना-पिलाना पड़ता है।

भोला किसान कर्ज ही में उत्पन्न होता है और कर्ज में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जमींदार तक का काम ऋण से चला करता है। ऋण देने और लेने का रिवाज नेपाल के प्रत्येक घर में व्याप्त है। कर्ज क्या तो नेपाल में विषम जंजाल-सा हो गया है। जनता उसी को बड़ा मानती है जो कर्ज लेना और देना दोनों जानता है। सूद की कमाई से ही धनिक महाजनों का काम चलता है।

प्रायः यह देखा जाता है कि जमींदारों अथवा महाजनों के घरों की स्त्रियों ने 'सापट' अथवा ऋण देना अपना पेशा बना लिया है। वे जिन्हें 'सापट' देती हैं उनसे ड्योढ़ा अथवा दूना वसूल भी करने लगी हैं। अधिकांश जनता अभी इतनी धर्म भीरु है कि एक बार ऋण ले लेने पर जब तक वह पाई-पाई नहीं चुका देती तब तक वह यही समझती है कि अगले जन्म में उसे नरक में भी ऋण चुकाना ही पड़ेगा। स्त्रियों से ऋण लेते समय यद्यपि उन्हें कोई कागज इत्यादि नहीं लिखना पड़ता परन्तु तब भी वहाँ जनता इतनी निश्छल और विश्वसनीय होती है कि वह स्वयं बिककर भी कर्ज से अपना पिंड छुड़ाने के लिए अहर्निश व्यग्र रहता है।

महाजनों के कर्ज लेन और देन का ढंग बड़ा कठिन तथा क्रूरता-पूर्ण है। वे किसानों को जब कर्ज देते हैं तब अंगूठे का निशान ले लेते हैं। गरज का बावला भोला-भाला किसान महाजन के कोरे कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा देता है और महाजन उस कोरे कागज पर जो चाहता है लिख लेता है। नेपाल में ग्राम के कोरे कागज पर हजारों रुपये तक के तमस्सुक (प्रोनोट) लिखवाये जाते हैं। भारत की तरह नेपाल में उस पर कोई टिकट नहीं लगाना पड़ता है। यदि किसी महाजन ने किसान को सौ रुपये ऋण दिये तो वह उससे दो सौ रुपये का तमस्सुक लिखवा लेता है और उस पर भी किसान को कम से कम पच्चीस रुपये प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ता है। इतना ही नहीं उसे दस रुपये प्रतिशत तमस्सुक की लिखाई तथा पाँच रुपये गाँठ खुलवाई भी महाजन को देनी पड़ती है।

नेपाल में जब किसी त्यौहार अथवा उत्सव का अवसर आता था तब राणा सरकार की ओर से जुआ खेलने की विशेष आज्ञा दी जाती थी। इसी तरह जब राणाशाही में किसी

मजदूरों की आम-सभा में उनको हथियार रख देने के लिए ललकारा किन्तु जमींदारों ने उनका उत्तर गोलियों से दिया। फलतः विद्रोही किसानों तथा मजदूरों की जनसेना ने उन पर आक्रमण करके उनका समाप्त कर दिया और उनके अस्त्र-शस्त्रों को भी छीन लिया।

पूर्वी नेपाल तराई में भूमि-व्यवस्था दूसरी तरह की है। यहां ऐसे भी जमींदार हैं जो सिर्फ आठ-दस बीघे के जमींदार हैं किन्तु वे हजारों बीघों के जोतदार होते हैं। पूर्वी तराई में सीर को जिरायत तथा सीर के मकान को कामत कहते हैं। यहां खेत को आधा बटाई (अधिया बटाई) तथा हुण्डा आदि पर कमाने का साधारण रिवाज है। मालिक और किसान दोनों खुशी से इस शर्त का पालन करते हैं।

राणा शासन काल में पूर्वी तराई में शासकों के अधिक संपर्क रहे। पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी तराई की भूमि पर अधिक भार है और वह उपजाऊ तथा कीमती भी अधिक है। लिम्बुआन नाम के इलाके में किपट प्रथा है। किपट लिम्बुआन जाति की पुश्तैनी चीज है और जिसका सम्बन्ध लिम्बू अपने धर्म से जोड़ने लगे हैं। किपट दो प्रकार के हैं या निराधार है। किसी लिम्बू की जमीन जब गैर लिम्बू जाति की हो जाती है तब वह किपट न कहलाकर 'रैकर' कहलाने लगती है। लिम्बुआन की सबसे विकट समस्या यही है और जो आम जनता की गरीबी का एक कारण बनी हुई है।

निर्धनता

नेपाल का किसान अपना वही पुरातन हल लेकर खून-पसीना एक करके खेती करता है परन्तु तब भी उसको इतना अनाज नहीं मिल पाता जिससे कि वह अपनी साधारण दैनिक आवश्यकताओं को पूरी कर सके। उसे प्रतिवर्ष कर्ज पर कर्ज लेना पड़ता है और फसल कटते ही अपने महाजनों को सारा चुका देना पड़ता है। नेपाल में सूद भी ड्योढ़ा लगा रहता है। जमींदार प्रतिवर्ष अपने आसामियों का अनाज 'किमार' लेता है और ६ माह पूरे होते ही उधार की सवाई मार-पीट कर वसूल कर ले जाता है। नेपाल का किसान कर्ज ही लेकर जीवन-पर्यन्त बैलों के साथ खेतों में काम करता है। जाड़े, गर्मी और बरसात की कुछ भी परवाह न करके वह हर दम आशा की बाजी लगाता रहता है परन्तु तब भी उसे कर्ज ही लेकर अपने कफन का भी प्रबन्ध करना पड़ता है।

किसान स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी होता है। उसे अपने समाज के रस्म रिवाजों को आँख मूंदकर मानना पड़ता है और उसे पग-पग पर सामाजिक नियमों का पालन पूर्णतया करना पड़ता है। समाज से बहिष्कृत होकर वह जिन्दा ही मर सकता है। वह अपने बाल-बच्चों के विवाह आदि में अधिक खर्च करता है। विवाह तथा त्योहारों के अवसरों पर निर्धन से निर्धन किसान भी आस पास वालों की तरह बराबर समाज में अपना नाक ऊँचा रखने का प्रयत्न करता है। मितव्ययता उसके समाज में कंजूसी समझी

१५

जन-जागरण

राणावंश के प्रवर्तक महाराज जंग बहादुर के प्रभुत्व को देखकर शाही परिवार डर उठा और उसे अपने भविष्य का भी आभास मिलने लगा। फलतः महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह के ज्येष्ठ पुत्र युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए राणा-विरोधी युवकों का आह्वान किया। कालान्तर महाराज जंग बहादुर ने अपनी दो पुत्रियों के विवाह त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह से सम्पन्न करके उनको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तथापि सरकार विरोधी युवक दल संगठित होता रहा और आगे चलकर जिसका नेतृत्व राजकुमार नरेन्द्र वीर विक्रम ने किया। नरेन्द्र वीर विक्रम के साथ काठमाण्डू के कतिपय प्रभावशाली युवक थे जो प्रधान मंत्री रणोद्दीप सिंह तथा सेनापति धीर शमशेर की हत्या करके शासन-सत्ता को राजवंश में छीन लेने पर तुले हुए थे। ६ फरवरी सन् १८८२ ई० को षड्यंत्र का पता शासकों को मिल गया और सभी प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्ता बन्दी बना लिए गए। इस अपराध में इकतीस व्यक्तियों तथा दस कुलीन ब्राह्मणों का अभिमुण्डन करके कारावास का दण्ड मिला। संग्राम सूर, संसार विजय थापा, विक्रम सिंह थापा, अमर विक्रम थापा, इन्द्र सिंह ठकुरी तथा चन्द्र सिंह पाण्डेय आदि नवयुवकों के सिर धड़ से अलग किए गए। सेनापति जनरल धीर शमशेर की हिम्मत राजकुमार नरेन्द्र वीर विक्रम को मार डालने की नहीं हुई इसलिए उन्होंने उन्हें अंग्रेजों को सौंपकर चुनारगढ़ के किले में बन्द करवा दिया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही नेपाल के राजनीतिक इतिहास की धारा पलटी और महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाह ने प्रधान मंत्री देव शमशेर को समझाकर नेपाल में संसदीय व्यवस्था स्थापित करने का विचार किया। इसी समय पण्डित माधवराज जोशी ने आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का प्रचार काठमाण्डू में करना प्रारम्भ किया किन्तु राणा शासकों ने पण्डित माधवराज जोशी की वाक्-स्वतन्त्रता को सहन नहीं किया और उन्हें जीवन पर्यन्त कारावास का दण्ड देकर उनके सभी साथियों को भी कारावास से लेकर देश-निष्कासन तक का दण्ड दिया।

भारत में सन् १९०१ ई० ही से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन बिहारी पाल ने स्वदेशी आन्दोलन उग्ररूप में छेड़ा था। इस आन्दोलन की हवा नेपाल को भी लगने लग गई थी किन्तु राणा शासकों की तानाशाही से भयभीत होकर काठमाण्डू के लोगों को खुलकर विद्रोह करने का साहस नहीं होता था। भारत के स्वदेशी आन्दोलन की प्रतिक्रिया नेपाल में दूसरे रूप में हुई और काठमाण्डूवासी हिमा

प्रधान मंत्री के घर उत्सव होता था तब कुछ कैदी भी छोड़ दिये जाते थे और समस्त नेपाल में जुआ खेलने की सरकारी आज्ञा दी जाती थी। दीवाली में तो जुआ महीनों चलता रहता था। इतना ही नहीं नेपाल के प्रधान मंत्री स्वयं बड़े-बड़े जुआरियों को जुआ खेलने के लिए अपने दरबार में अनिवार्य आमंत्रित किया करते थे और जो व्यक्ति प्रधान मंत्री के साथ जुआ खेलते थे वह बड़े प्रतिष्ठित माने जाते थे।

सामन्ती शासन को समाप्त करके भूमि की समस्या को हल किए बिना किसानों की हालत सुधर नहीं सकती। यह काम उच्च कोटि के देशभक्तों का एक कमीशन ही कर सकता है और जिसको वास्तविक रूप देने में जनता अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे कार्यान्वित करने में सरकार को पूरा सहयोग देगी और देश के सामन्त तथा जमींदार भी सरकार की योजना का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे।

१९

जन-जागरण

राणावंश के प्रवर्तक महाराज जंग बहादुर के प्रभुत्व को देखकर शाही परिवार भर्रा उठा और उसे अपने भविष्य का भी आभास मिलने लगा। फलतः महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह के ज्येष्ठ पुत्र युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह ने अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए राणा-विरोधी युवकों का आह्वान किया। कालान्तर महाराज जंग बहादुर ने अपनी दो पुत्रियों के विवाह त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह से सम्पन्न करके उनको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तथापि सरकार विरोधी युवक दल संगठित होता रहा और आगे चलकर जिसका नेतृत्व राजकुमार नरेन्द्र वीर विक्रम ने लिया। नरेन्द्र वीर विक्रम के साथ काठमाण्डू के बावन प्रभावशाली युवक थे जो प्रधान मंत्री रणोद्दीप सिंह तथा सेनापति धीर शमशेर की हत्या करके शासन-सत्ता को राणावंश से छीन लेने पर तुले हुए थे। ६ फरवरी सन् १८८२ ई० को षड्यन्त्र का पता शासकों को मिल गया और सभी प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ता बन्दी बना लिये गये। इस अपराध में इक्कीस व्यक्तियों तथा दस कुलीन ब्राह्मणों को जातिच्युत करके कारावास का दण्ड मिला। संग्राम सूर, संसार विक्रम थापा, विक्रम सिंह थापा, अमर विक्रम थापा, इन्द्र सिंह टण्डन तथा चन्द्र सिंह पाण्डेय आदि नवयुवकों के सिर धड़ से अलग किये गये। सेनापति धीर शमशेर की हिम्मत राजकुमार नरेन्द्र वीर विक्रम को मार डालने की नहीं हुई इसलिए उन्होंने उन्हें अंग्रेजों को सौंपकर चुनारगढ़ के किले में बन्द करवा दिया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही नेपाल के राजनीतिक इतिहास की धारा पलटी और महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाह ने प्रधान मंत्री देव शमशेर को समझाकर नेपाल में संसदीय व्यवस्था स्थापित करने का विचार किया। इसी समय पण्डित माधवराज जोशी ने आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का प्रचार काठमाण्डू में करना प्रारम्भ किया किन्तु राणा शासकों ने पण्डित माधवराज जोशी की वाक्-स्वतन्त्रता को सहन नहीं किया और उन्हें जीवन पर्यन्त कारावास का दण्ड देकर उनके सभी साथियों को भी कारावास से लेकर देश-निष्कासन तक का दण्ड दिया।

भारत में सन् १९०१ ई० ही से लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन बिहारी पाल ने स्वदेशी आन्दोलन जोरों से छेड़ा था। इस आन्दोलन की हवा नेपाल को भी अवश्य लग गई थी किन्तु राणा शासकों की तानाशाही से भयभीत होकर काठमाण्डू के लोगों को खुलकर विद्रोह करने का साहस नहीं होता था। भारत के स्वदेशी आन्दोलन की प्रतिक्रिया नेपाल में दूसरे रूप से हुई और काठमाण्डूवासी हिंसा

को अपना अस्त्र बनाकर राणा शासकों को समाप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाह राज्य में संसदीय व्यवस्था कायम करके राणा शासकों के हाथ से सत्ता छीनकर जनता के हाथों में देने के पक्ष में थे। इस कार्य के लिए स्वयं पृथ्वी वीर विक्रम शाह ने कर्नल कुमार जंग राणा, कप्तान शमशेर सिंह, कप्तान मदनसिंह, कप्तान गया बहादुर बस्नेत तथा मुखिया दुर्गानाथ अधिकारी इत्यादि को उभाड़ करके एक क्रान्तिकारी दल बनाया। इस दल का उद्देश्य हिंसात्मक नीति अपनाकर सिंह दरबार को राणा सहित उड़ाना तथा नेपाल को विमुक्त करना था। मुखिया दुर्गानाथ बहुत ही कायर तथा लोभी प्रकृति का व्यक्ति था इसलिए उसने चन्द्र शमशेर से सब रहस्य खोल दिया। इस षड्यन्त्र का समाचार पाते ही प्रधान मंत्री चन्द्र शमशेर ने महाराजाधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाह के समर्थकों को पकड़वा बुलवाया। उनमें से तीन व्यक्तियों को देश-निष्कासन तथा कप्तान जंग वीर राणा को दगाबाज़ी घोषित करके कारागार भेज दिया गया और कर्नल कुमारजंग को बनकुट्टा की जेल में जीवन-पर्यन्त कारावास दे दिया गया।

सन् १९२१ ई० में महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग-आन्दोलन छेड़ा और अंग्रेजों को यह भय हुआ कि यह प्रचण्ड आंधी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़कर ही रहेगी। पर अंग्रेजों ने नेपाल को पहले ही से अपना कर रखा था। उन्होंने बर्मा को भी भारत से पृथक करके भारत की शक्ति छिन्न-भिन्न कर देने का निश्चय किया। महात्मा गांधी के आन्दोलन की आंधी ने राणाशाही को भी झकझोरा। सन् १९२७ ई० में ठाकुर चन्दन सिंह ने देहरादून में 'गोरखा लीग' की स्थापना की। इस लीग का मुख्य उद्देश्य भारतस्थित नेपालियों को संगठित करना था। ठाकुर चन्दन सिंह का विशेष ध्यान केवल उन्हीं नेपालियों पर था जो स्वदेश छोड़कर भारत में बस गये थे। इसलिए इस लीग की हवा नेपाल तक अधिक नहीं पहुंच सकी। २४ नवम्बर सन् १९२ ई० के दिन जनरल भीम शमशेर नेपाल के प्रधान मंत्री हुए। उन्होंने भारत में महात्मा गांधी का व्यापक प्रचार तथा उसका प्रभाव नेपाल के नवयुवकों पर भी पड़ते हुए देखकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर नवयुवकों को दबाने की चेष्टा की। फलस्वरूप शाह वंश के उमेश विक्रम शाह, खड्गमान सिंह, कप्तान कप्तान खड्गमान सिंह, मैना बहादुर तथा रंगनाथ शर्मा इत्यादि काठमाण्डू के नवयुवकों ने सन् १९३० ई० में 'प्रचण्ड गोरखा' नामक क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना की। प्रचण्ड गोरखा के क्रान्तिकारी सिपाहियों ने डायनामाइट द्वारा विस्फोट करके जनरल भीम शमशेर आदि प्रमुख-प्रमुख राणा शासकों को उड़ा देना चाहा। महाविस्फोट का यह क्रान्तिकारी अंकुर देखते ही भीम शमशेर बौखला उठे और उन्होंने उमेश विक्रम शाह, खड्गमान सिंह, मैना बहादुर, रंगनाथ शर्मा तथा कप्तान [illegible] सिंह को जीवन-पर्यन्त कारावास की सज़ा सुना दी। कुछ लोगों की धारणा है कि स्वयं राजा ने इस दल की सूचना प्रधान मंत्री भीम शमशेर को दे दी थी।

अमानुषिक यातना

महाराज भीम शमशेर ने पाचों सपूतों को लोहे के एक संकीर्ण पिंजड़े में जिसकी लम्बाई तथा चौड़ाई दस फीट और ८ फीट थी और जिसे काठमाण्डू में 'गोलघर' कहा जाता है—बन्द कर दिया। 'गोलघर' में बन्द होने पर भी राजनीतिक बन्दियों की हथकड़ी बेड़ी के अतिरिक्त पांच सेर लोहे की हथकड़ी तथा कमर में बीस सेर लोहे की जंजीर भी डाल दी गई। इतना ही नहीं बल्कि राज-बन्दियों को प्रतिदिन गोलघर से बाहर निकालकर दो सौ कोड़ों से मारकर अपमानित किया जाता था और उनके मामूना में शामिलें भी चुनौती आनी रही। इसी गोलघर में बन्दियों को साथ में रहकर मलमूत्र भी त्यागना पड़ता था और रात्रि को उसी में एक साथ सोना भी पड़ता था। उनका मल-मूत्र साफ करने के लिए बाहर से कोई चीज भी नहीं मिलती थी और चौके की राख से उन्हें अपने मल-मूत्र को प्रतिदिन साफ करना पड़ता था। भोजन भी उसी गोलघर में स्वयं बनाना पड़ता था और अनाज भी इतना नहीं दिया जाता था कि वे अपना पेट भर सकें।

जेल की कठिन यातना को शाही परिवार में पला हुआ उमेश विक्रम शाह सहन नहीं कर सका और वह बिना एक बूंद औषधि पान किये हुए अपना मृत शरीर छोड़कर पिंजड़े के बाहर हो गया। जेल की यातनाओं से ऊबकर असमय बन्दियों ने आमरण अनशन प्रारम्भ किया किन्तु भीम शमशेर ने जेल में सुधार करने का आश्वासन देकर अनशन भंग करवा दिया। थोड़े दिन पश्चात् भीम शमशेर की मृत्यु हुई और जनरल युद्ध शमशेर नेपाल के प्रधान मन्त्री हुए। उसी दिन से जेल में पुनः अनशन प्रारम्भ हो गया। युद्ध शमशेर ने अनशन के पांचवें दिन अपने पुत्र जनरल हरि शमशेर को अनशन भंग करवाने के लिए जेल में भेजा। जनरल हरि शमशेर जेल में पिस्तौल लेकर पहुंचे और उन्होंने अनशन कारियों को धमकाकर उनका व्रत भंग करवाने का प्रयत्न किया। हरि शमशेर की इस धृष्टता को देखकर मैना बहादुर आग-बबूला हो गया। उसने छलांग मारकर हरि शमशेर की कमीज फाड़ डाली और उन्हें थप्पड़ मारकर ललकारा। शेर की दहाड़ को सुनते ही हरि शमशेर के छक्के छूट गये और वह उल्टे पैर अपने रनिवास में जा छिपे।

इस घटना के पश्चात् सब बन्दी अलग-अलग कर दिये गये और मैना बहादुर को लोहे की हथकड़ी बेड़ी के अतिरिक्त पांच सेर लोहे की गलपटी डाल दी गई। अन्त में तपेदिक के शिकार होकर मैना बहादुर तथा कप्तान नगनमान सिंह की इह लीलाएं समाप्त हुईं। प्रचण्ड गोरखा की चिनगारी राजधानी तक ही सीमित रही और वह काठमाण्डू की घाटी से बाहर नहीं फैल सकी। इसी बीच भारत में महात्मा गांधी का 'सत्याग्रह' भी जोर पकड़ चुका था और जिसके प्रति नेपाल-भर का ध्यान स्वभावतः आकृष्ट हो रहा था। ५ मार्च सन् १९३१ ई० को गांधी-इर्विन पैक्ट हुआ। इसके पश्चात् सितम्बर सन्

किया कि नरेश का षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं था। श्री पाँच महाराजाधिराज का इस प्रकार से अपमान होते हुए देखकर नेपाल की सारी जनता में सनसनी मच गई और ऐसा दीखने लगा कि समस्त नेपाल में विप्लव उठ खड़ा होगा यदि श्री पाँच सरकार को षड्यंत्र में किसी प्रकार फंसाया गया। कहा जाता है कि इस अवसर का लाभ उठाकर युद्ध शमशेर महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को पदच्युत करके उनके ज्येष्ठ पुत्र महेन्द्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का महाराजाधिराज और श्री पाँच त्रिभुवन को उनके द्वितीय तथा तृतीय पुत्रों के साथ भारत के नगर में भेज देना चाहते थे किन्तु वह ऐसा कर नहीं सके। २६ जनवरी सन् १९४१ ई० को शुक्रराज शास्त्री को बागमती नदी के किनारे अर्ध रात्रि को एक वृक्ष से लटकाकर मार डालने की आज्ञा हुई। शास्त्री जी ने बागमती में स्नान तथा गीता पाठ कर लेने की अनुमति मांगी। शुक्रराज शास्त्री के कहने पर उनको नदी-स्नान तथा श्री गीता जी का पाठ कर लेने की अनुमति तो मिली किन्तु फांसी देने के बारह घंटे पहले ही युद्ध शमशेर ने काठमाण्डू में प्रतिबन्ध लगवा दिये और स्थान-स्थान पर सशस्त्र सैनिकों को बैठा दिया गया।

जाड़े की नीरव रात्रि में शुक्रराज शास्त्री को फांसी की सूखी डोर के पास ले जाया गया। डोर को देखते ही शुक्रराज शास्त्री ने उस डोर को चूम लिया और रक्षकों की



शहीद धर्मभक्त



शहीद गंगालाल

ओर देखकर उनको सम्बोधित करते हुए कहा कि यह फांसी मुझ को मारने के लिए बनाई गई है किन्तु मैं तो अमर हूँ। इसके पश्चात् शास्त्री जी ने रक्षकों से कहा कि यदि हो सके तो मेरे भाई के नाम यह संदेश पहुंचा देना कि मेरी फांसी के लिए कौन जिम्मेदार है क्योंकि उसने झूठ बोलकर उनके विरुद्ध मुखबिरी कर दी थी। इतना कहकर शास्त्री जी

ने फाँसी का फंदा अपने गले में स्वयं डाल लिया और 'ओ३म्' 'ओ३म्' कहकर अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। इसके कुछ ही दिनों के पश्चात् बागमती नदी के किनारे नीरव रात्रि में धर्मभक्त को भी एक वृक्ष में लटका दिया गया। धर्मभक्त की हत्या बड़ी ही बुरी तरह नृशंसतापूर्वक की गई। उनको गलत तरीके से लटकाया गया। धर्मभक्त को फाँसी के फंदे में छटपटाते हुए देखकर नर शमशेर अट्टहास मारकर हँसता भी जाता था। रक्षकों के बार-बार प्रार्थना करने पर धर्मभक्त जी को नीचे उतारकर उनके हाथ-पैर बाँध दिए गए। नर शमशेर ने धर्मभक्त को मार-मार कर लहू-लुहान कर दिया और अंत में टाँगकर मार डाला। थोड़े समय के बाद गंगालाल तथा दशरथचन्द्र को गोली से उड़ा



शहीद दशरथचन्द्र



शहीद शुक्रराज शास्त्री

दिया गया। गंगालाल की अवस्था दशरथचन्द्र से कम थी इसलिए दशरथचन्द्र ने यह प्रार्थना की कि पहले गंगालाल पर गोली चलाई जाय क्योंकि सम्भवतः गंगालाल खून की धारा बहते देखकर भयभीत हो सकता था। दशरथचन्द्र की इस प्रार्थना को सुनकर नर शमशेर ने दशरथचन्द्र को बाद में गोली मारने की आज्ञा दी। गोली उनके सीने में न मारकर जाँघ में इसलिए मारी गई कि दशरथचन्द्र को अधिक पीड़ा हो और गंगालाल विचलित हो जाय। जाँघ में गोली लगने से दशरथचन्द्र पाँच मिनट तक छटपटाते रहे। नर शमशेर ने कहा कि यदि तुम अब भी राणा सरकार के समर्थक बन जाओ तो हम तुमको अभी अस्पताल में भर्ती करा देंगे। अस्पताल का नाम सुनते ही दशरथचन्द्र खिलखिला पड़े और उन्होंने नर शमशेर से कहा कि मुझ पर दया करो और गोली मेरे सीने में तुरन्त मार

अत्यधिक पीड़ा प्राप्त करने के बाद गोली के एक दूसरे सिपाही ने गीत को पार कर उनके प्राण लिये। दशरथचन्द्र की खून की धारा तथा छटपटाहट देखकर गोली चलाने वाले सिपाही ने आगे में गोली मारने से इन्कार किया। उसने कहा कि यह दृश्य मैं अब देख सकता। मुझे सीने में गोली मारने की आज्ञा दी जाय। पर सफसर की आज्ञा ही दो गोलियाँ गंगालाल के सीने में आ लगी और गंगालाल वहीं ढेर हो गए।

शहीदों की लाशें बाजार की सड़कों पर तमाम दिन पड़ी रहीं जिससे जनता भय हाकर फिर कभी सरकार का विरोध करने का साहस न करे। राणा शासकों ने यही था कि शहीदों की लाशों की दुर्गति देखकर जनता सर्वदा के लिए भयभीत हो जायगी: राणा सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकालेगी परन्तु शासकों को पता यह मालूम कि आजतक किसी भी इतिहास ने शहीदों के खून का व्यर्थ बहते हुए सिद्ध नहीं किया।

नेपाल में शासकों के अत्याचार ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते थे त्यों-त्यों भारत में शिक्षा ग्रहण करने वाले नेपाली विद्यार्थी राणाशाही का समाप्त करने के लिए भारतीय नेताओं की सहानुभूति प्राप्त करके सरकार-विरोधी मोर्चे बनाने में संलग्न थे। इस उद्देश्य से बनारस में 'नेपाली संघ' तथा कलकत्ता में 'गोरखा कांग्रेस' नामक दो संस्थाएँ भारत में कार्य कर रही थी।

अगस्त सन् १९४२ ई. में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध 'भारत छोड़ो' आन्दोलन छेड़ा तब उस में भारतस्थित नेपाली विद्यार्थी भी सम्मिलित हो गये। इस आन्दोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरी शक्ति लगा दी। इस आन्दोलन में समाजवादी नेता बाबू जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जेल से भागने के बाद नेपाल तराई में आश्रय लिया किन्तु वह बहुत समय तक तराई में छिपे नहीं रह सके और राणा सैनिकों ने उन्हें पकड़कर सप्तरी जिले के हनुमान नगर नामक जेल में बन्दी बना दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात् जयप्रकाश नारायण वहाँ से भागकर भारत में चले गये।

नेपाली नेताओं को यह पहले से विदित था कि जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं होगा तब तक नेपाल भी राणाशाही से विमुक्त नहीं हो सकता। यही सोचकर नेपाली नेता भारत के प्रत्येक आन्दोलन में सक्रिय भाग लेते रहे। इस समय भी भारतीय नेताओं के साथ नेपाली रमेश नेपाली उदय राज मान हरि प्रसाद प्रधान विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तथा ... प्रसाद उपाध्याय इत्यादि भारत में गिरफ्तार कर लिये गये और इनके साथ को भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में बन्दी बना लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना कलकत्ता तथा दार्जिलिंग इत्यादि स्थानों पर भी अन्य नेपाली राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये। राणा सरकार ने ब्रिटिश सरकार से सभी राजबन्दी नेपालियों को नेपाल भेजने के लिए प्रार्थना की। भारत सरकार ने भी सभी नेपाली नेताओं को नेपाल भेज दिया जाता किन्तु भारतीय न्यायालयों ने नेपालियों के साथ ऐसी कार्यवाही नहीं करने दी जिसके फलस्वरूप सभी बन्दी भारतीय जेलों में ही रहे और कालान्तर में रिहा किये गये। नेपाल में

राणा सरकार ने इसके साथ-ही-साथ लगभग डेढ़-दो सौ व्यक्तियों पर सरकार विरोधी मुकदमा चलाया और कतिपय व्यक्तियों को छः-छः वर्ष की जेल की सजायें भी दी। इसमें से कृष्णवीर स्वामी की मृत्यु काठमाण्डू की जेल में हुई। बाद में 'भारत छोड़ो' जन आन्दोलन की सफलता देखकर प्रधान मंत्री युद्ध शमशेर ने नेपालियों का विश्वास जीतने पर नेपाली राजनीतिक बन्दियों को छोड़ना प्रारम्भ किया। उन्होंने नेपाली प्रजा परिषद् के सभी नेताओं को छोड़ने का विचार किया किन्तु गणेशमान सिंह, पुष्प बहादुर, टंक प्रसाद आचार्य, चूड़ा प्रसाद, राम हरि शर्मा तथा गोविन्द प्रसाद उपाध्याय आदि ने जेल से किन्हीं भी शर्तों पर छूटना स्वीकार नहीं किया।

जनवरी सन् १९४६ ई० में भारतीय नेताओं की प्रेरणा से दिल्ली रमण रेग्मी तथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने बनारस में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। २५ जनवरी सन् १९४७ ई० को इसका उद्घाटन-समारोह कलकत्ता में सम्पन्न हुआ। और जिसकी सफलता के लिए भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी तथा पण्डित विजय लक्ष्मी और जयप्रकाश नारायण इत्यादि नेताओं ने अपने शुभ संदेश भेजे। सम्मेलन ने टंक प्रसाद आचार्य को नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापति मनोनीत किया जो कि काठमाण्डू के जेल में बन्दी थे।

सत्याग्रह

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहिंसात्मक नीति धारण करके नेपाल में सत्याग्रह करने की तैयारी की। यह सत्याग्रह विराटनगर के जूट मिल मजदूरों की माँगों को लेकर ४ मार्च सन् १९४७ ई० को आरम्भ हुआ। विराटनगर के मिल-मजदूरों के नेता मन मोहन अधिकारी ने सभी मजदूरों को हड़ताल कर देने के लिए आदेश दिया। फलतः विराटनगर के मिल-मजदूरों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की। इसी हड़ताल के फलस्वरूप राणा सरकार ने मनमोहन अधिकारी के साथ उनके सभी साथियों को जिसमें विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भी थे बन्दी बनाकर काठमाण्डू भेज दिया गया। इसके पश्चात् विराटनगर, काठमाण्डू, इलाम, धनकुटा, [illegible], पर्सा तथा जनकपुर इत्यादि नगरों में भी अहिंसात्मक सत्याग्रह छिड़ा। इसी समय डाक्टर कुँवर इन्द्र सिंह, कृष्ण दास भक्त, उदय राज साह, [illegible] प्रसाद, [illegible] देवी, रामचरन शर्मा, जनरवि 'दिवेश' आदि ने अपना एक जत्था बनाकर पश्चिमी नेपाल के पहाड़ी [illegible] भगवानपुर तथा कृष्णनगर तथा कुँवर इन्द्र सिंह आदि ने नेपाल गंज में भी आन्दोलन छेड़ा। १३ अप्रैल सन् १९४७ ई० को विराटनगर में सत्याग्रह छिड़ा किन्तु नेपाल सरकार ने सभी सत्याग्रहियों को बन्दी बना लिया। २० अप्रैल को बीरगंज तथा २७ अप्रैल को जनकपुर में सत्याग्रह छेड़ा गया। बीरगंज के सत्याग्रह में बीरगंज हाई स्कूल के लगभग ६० छात्रों ने विशेष भाग लिया किन्तु राणा शासकों ने प्रमुख सत्याग्रहियों को बन्दी बनाकर

विद्यार्थियों को मार-पीट कर छोड़ दिया। हुकूमी सरकार ने अहिंसात्मक सत्याग्रह को दबाने के लिए विराटनगर इत्यादि स्थानों पर गोलियाँ भी चलाईं जिससे विराटनगर में तीन स्त्रियाँ गोलियों की शिकार बनीं और अनेकों सत्याग्रही घायल हुए। १० अप्रैल सन् १९४७ ई० को नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में सत्याग्रह छिड़ा। इसकी लपटें पाटन तथा भादगाँव तक पहुँचीं। स्वाधीनता की भूखी जनता ने सरकार के विरुद्ध विराट प्रदर्शन किया। इस सत्याग्रह को दबाने के लिए जनरल नर शमशेर ने भरसक परिश्रम किया। उन्होंने राजधानी के नागरिकों का भी चुनौती दी। इस सत्याग्रह में राजधानी की महिलाओं ने विशेष भाग लिया। सत्याग्रह आन्दोलन में राजधानी के सैकड़ों सत्याग्रही खूब मार-पीट कर बन्दी बनाये गये। इसकी सूचना जब महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने जोर देकर नेपाल सरकार को जनता की माँगें पूरी करने तथा सत्याग्रहियों को विशुद्ध अहिंसा से काम लेने की अपील की। महात्मा गांधी की सम्मति राणा सरकार ने ठुकरा दी किन्तु सत्याग्रहियों ने अहिंसात्मक नीति धारण कर पुनः सत्याग्रह छेड़ने की तैयारी की। ११ जुलाई सन् १९४७ ई० को बनारस में मुन्शी देवी प्रसाद सापकोटा के सभापतित्व में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ। इस समारोह में डाक्टर राममनोहर लोहिया आदि भी उपस्थित थे। सम्मेलन ने डिल्ली रमण रेग्मी को नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। इस अधिवेशन में आगत प्रतिनिधियों ने नेपाल में अहिंसात्मक आन्दोलन करने का प्रस्ताव पास किया।

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह को जोर पकड़ते देखकर प्रधान मंत्री महाराज पद्म शमशेर ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू से सत्याग्रह स्थगित करा देने की अपील की। उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री को यह विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही सभी राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करके नेपाल के शासन में सुधार की ओर अग्रसर होंगे। बाद में पद्म शमशेर ने भारत सरकार से एक वैधानिक सलाहकार की माँग की। फलतः श्रीप्रकाश जी के नेतृत्व में सन् १९४७ ई० में एक शिष्टमण्डल काठमाण्डू आया। श्रीप्रकाश जी ने तीन चार प्रकार के विधान तैयार करके नेपाल सरकार को दिये। किन्तु राणा शासकों ने उन विधानों का केवल कागज पर ही पालन किया। श्रीप्रकाश जी की सम्मति को स्वीकार कर राणा शासकों ने सत्याग्रहियों को नहीं छोड़ा। सत्याग्रहियों की हालत संगीन देखकर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने भारत के समाजवादी नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया से तार तथा चिट्ठी लिखकर प्रधान मंत्री के पास एक सिफारिश की चिट्ठी भेजने के लिए लिखा। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की चिट्ठी पाकर डाक्टर राममनोहर लोहिया ने प्रधान मंत्री पद्म शमशेर के नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को छोड़ देने के लिए इस प्रकार की एक चिट्ठी भेजी—

श्री पद्म शमशेर जंग बहादुर राणा
प्रधान मंत्री नेपाल ।
प्रिय श्री महाराज

मेरा तार आपको मिला होगा । श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय महात्मा गांधी का पत्र और यह पत्र आप तक ले जा रहे हैं ।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की अवस्था तो मरणासन्न आ गई है ऐसा यहां सुना गया है, फिर भी कोशिश उन्हें बचाने की बम्बई में की जा सकती है । मेरा विश्वास है कि इस युवक की मृत्यु से हम सभी की बहुत क्षति होगी और इन्हें बचाने की जरा भी आशा है तो अविलम्ब रिहाई दें ।

श्री विश्वेश्वर का लिखा हुआ पत्र मैं आपके द्वारा ही भेज रहा हूं । यदि वे छोड़े जायें तो उन्हें यह पत्र दिया जाय जिससे छूटते ही वे बम्बई चले जायें ।

चाहे देर हो गई है विश्वेश्वर की रिहाई नेपाल और भारत दोनों के लिए कल्याणकारी होगी और आपकी तरफ से एक मानवीय काम तो होगा ही । मेरे नमस्कार और शुभेच्छायें आपको स्वीकृत हों ।

सप्रेम
राम मनोहर लोहिया

दिसम्बर सन् १९४० ई० में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ । इसी समय काठमाण्डू में 'नेपाल प्रजा पंचायत' नाम की एक राजनीतिक संस्था स्थापित हुई । नेपाल प्रजा पंचायत ने काठमाण्डू में जुलूस निकालकर राणा सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ा । राणा सरकार ने प्रजा पंचायत के नेता त्रिपुरवर सिंह, सूर्य बहादुर, विजय बहादुर मल्ल, पूर्ण बहादुर, [illegible] तथा तुलसी लाल आदि के साथ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को भी गिरफ्तार किया । प्रजा पंचायत के युवकों को बन्दी सुनकर कोइराला बन्धु ने एक अधिवेशन द्वारा नेपाल की तराई में सत्याग्रह करने की घोषणा की । प्रथम जून सन् १९४८ ई० से सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने अनशन व्रत धारण करके अन्य राजनीतिक बन्दियों को भी अनशन करने के लिए निवेदन किया । सत्याग्रहियों की मांगें पूरी भी न हो पाई थी कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर का आश्वासन पाकर बिना साथी अनशनकारियों की राय लिए अनशन तोड़कर भारत चले गए ।

इस कार्यवाही से दुखी होकर काठमाण्डू के राजनीतिक बन्दियों ने अपने खास व्यक्तियों द्वारा जयप्रकाश नारायण व विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के पास पत्र भेजे । जयप्रकाश नारायण के पास जो पत्र लिखा गया वह हिन्दी भाषा ही में था किन्तु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के पास जो पत्र लिखा गया वह नेपाली भाषा में था । वे दोनों पत्र क्रमशः इस प्रकार हैं —

विद्यार्थियों को मार पीट कर छोड़ दिया। हुकूमी सरकार ने अहिंसात्मक सत्याग्रह को दबाने के लिए विराटनगर इत्यादि स्थानों पर गोलियाँ भी चलाईं जिससे विराटनगर में तीन स्त्रियाँ गोलियों की शिकार बनीं और जनता का सत्याग्रह आरम्भ हुआ। १० अप्रैल सन् १९४७ ई० को नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में सत्याग्रह छिड़ा। इसकी लपटें पाटन तथा भातगाँव तक पहुँचीं। स्वाधीनता की भूखी जनता ने सरकार के विरुद्ध विराट प्रदर्शन किया। इस सत्याग्रह को दबाने के लिए जनरल शेर शमशेर ने भरसक परिश्रम किया। उन्होंने राजधानी के नागरिकों को भी चुनौती दी। इस सत्याग्रह में राजधानी की महिलाओं ने विशेष भाग लिया। सत्याग्रह-आन्दोलन में राजधानी के सैकड़ों सत्याग्रही खूब मार-पीट कर बन्दी बनाये गये। इसकी सूचना जब महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने जोर देकर नेपाल सरकार को जनता की माँगें पूरी करने तथा सत्याग्रहियों को विशुद्ध अहिंसा से काम लेने की अपील की। महात्मा गांधी की सम्मति राणा सरकार ने ठुकरा दी किन्तु सत्याग्रहियों ने अहिंसात्मक नीति धारण कर पुनः सत्याग्रह छेड़ने की तैयारी की। १६ जनवरी सन् १९४७ ई० को बनारस में श्री देवी प्रसाद सापकोटा के सभापतित्व में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ। इस समारोह में डाक्टर राममनोहर लोहिया आदि भी उपस्थित थे। सम्मेलन ने डिल्ली रमण रेग्मी को नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। इस अधिवेशन में आगत प्रतिनिधियों ने नेपाल में अहिंसात्मक आन्दोलन करने का प्रस्ताव पास किया।

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह की ओर बढ़ते देखकर प्रधान मंत्री महाराज पद्म शमशेर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सत्याग्रह स्थगित कराने की अपील की। उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री को यह विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र ही सभी राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करके नेपाल के शासन में सुधार की ओर अग्रसर होंगे। आरम्भ पद्म शमशेर ने भारत सरकार से एक वैधानिक सलाहकार की माँग की। फलतः श्रीप्रकाश जी के नेतृत्व में सन् १९४७ ई० में एक शिष्टमण्डल काठमाण्डू आया। श्रीप्रकाश जी ने तीन चार प्रकार के विधान तैयार करके नेपाल सरकार को दिए। किन्तु राणा शासकों ने उन विधानों को केवल कागज पर ही रहने दिया। श्रीप्रकाश जी की सम्मति को ठुकराकर राणा शासकों ने सत्याग्रहियों को नहीं छोड़ा। सत्याग्रहियों की हालत अर्धमृत देखकर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने भारत के समाजवादी नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया के पास एक चिट्ठी लिखकर प्रधान मंत्री के नाम एक सिफारिश की चिट्ठी भेजने के लिए लिखी। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की चिट्ठी पाकर डाक्टर राममनोहर लोहिया ने प्रधान मंत्री पद्म शमशेर के नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को छोड़ देने के लिए इस प्रकार की एक चिट्ठी लिखी—

श्री पद्म शमशेर जंग बहादुर राणा
प्रधान मंत्री नेपाल ।

प्रिय श्री महाराज

मेरा तार आपको मिला होगा। श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय महात्मा गांधी का पत्र और यह पत्र आप तक ले जा रहे हैं।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की अवस्था तो मरणासन्न आ गई है ऐसा यहाँ सुना गया है फिर भी कोशिश उन्हें बचाने की बम्बई में की जा सकती है। मेरा विश्वास है कि इस युवक की मृत्यु से हम सबों की बहुत क्षति होगी और इन्हें बचाने की जरा भी आशा है तो अविलम्ब रिहाई दें।

श्री विश्वेश्वर का लिखा हुआ पत्र मैं आपके द्वारा ही भेज रहा हूँ। यदि वे छोड़े जायें तो उन्हें यह पत्र दिया जाय जिससे तुरन्त ही वे बम्बई चले जायें।

चाहे देर हो गई है विश्वेश्वर की रिहाई नेपाल और भारत वालों के लिए कल्याणकारी होगी और आपकी तरफ से एक मानवीय काम तो होगा ही। मेरे नमस्कार और शुभकामनायें आपको स्वीकृत हों।

भवदीय
राम मनोहर लोहिया

दिसम्बर, सन् १९४७ ई० में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ। इसी समय काठमाण्डू में 'नेपाल प्रजा पंचायत' नाम की एक राजनीतिक संस्था स्थापित हुई। नेपाल प्रजा पंचायत ने काठमाण्डू में जुलूस निकालकर राणा सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ा। राणा सरकार ने प्रजा पंचायत के नेता त्रिपुरवर सिंह, सूर्य बहादुर, विजय बहादुर मल्ल, पूर्ण बहादुर, कमरत्न तथा तुलसी लाल आदि के साथ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को भी गिरफ्तार किया। प्रजा पंचायत के युवकों का बन्दी सुनकर कोइराला दल ने एक अधिवेशन द्वारा नेपाल की लड़ाई में सत्याग्रह करने की घोषणा की। प्रथम जून सन् १९४८ ई० से सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने अनशन व्रत धारण करके अन्य राजनीतिक बन्दियों का भी अनशन करने के लिए निवेदन किया। सत्याग्रहियों की माँगें पूरी भी न हो पाईं थीं कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर का आश्वासन पाकर बिना सभी अनशनकारियों की राय लिए अनशन तोड़कर भारत चले गए।

इस कार्यवाही से दुःखी होकर काठमाण्डू के राजनीतिक बन्दियों ने अपने नाम बन्दियों द्वारा जयप्रकाश नारायण विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के पास पत्र भेजा। जयप्रकाश नारायण के पास जो पत्र लिखा गया वह हिन्दी भाषा ही में था किन्तु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के पास जो पत्र लिखा गया वह नेपाली भाषा में था। पत्र [illegible] इस प्रकार है —

सर्वश्री जयप्रकाश नारायण जी
पटना ।
जय नेपाल ! जय हिन्द !
सम्माननीय साथियो !

कुछ लिखने के पहले अपना परिचय देना उचित है। हम सन् १९४६ ई० में यहां काठमाण्डू में नेपाल प्रजा परिषद् नामक जो समाजवादी संस्था की स्थापना हुई थी उसके सदस्य हैं। दो साल बीत गये नेपाली जेल के कठोरतम नियमों को सहते हुए किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे बारे में बहुत-सी बातें नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आप लोगों को मालूम हो चुकी होंगी।

हमें बहुत दिनों से आपको पत्र लिखने की इच्छा थी किन्तु पत्र आप तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति न मिलने के कारण हम ऐसा नहीं कर सके। अभी यहां की परिस्थिति की खास जरूरत से प्रेरित हो हम किसी तरह इन पत्रों को भिन्न तिगड़म से आपके पास पहुंचा रहे हैं।

आप लोगों ने और आपके दल ने जिस तरह हमारी जन-जागृति में मदद पहुंचायी है वह बहुत सराहनीय है। इसके लिए हमारा देश और हम सदा आपके अनुगृहीत बने रहेंगे। हमें विश्वास है जैसे आपने शुरू से मदद प्रदान की है वैसे ही आखिर तक हमारी समस्याओं को सुलझाने में आप सदा सहृदयतापूर्ण तत्परता दिखाते रहेंगे।

आज हमारे देश की राजनीति में जैसी शिथिलता आ गई है वह हमारे लिए बहुत चिन्तनीय है। इस शिथिलता का कारण क्या है यह कैसे हटाई जा सकती है—प्रस्तुत पत्र में इसी बारे में हम आपको लिख रहे हैं।

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने आप लोगों की सहायता पाकर पहले जैसी सफलता प्राप्त की थी उसके नेताओं की अस्थिरता और महत्त्वाकांक्षा के कारण हम लोग अन्त में उस सफलता का फायदा नहीं उठा सके। उनके अन्दर जो फूट हुई वह तो आप जानते ही हैं। फूट होने के बाद भी यदि देश में से कोई भी दल प्रजा की सच्ची भलाई का ध्यान में रखते हुए कार्य-क्षेत्र में आगे बढ़ा होता तो आज तक कुछ हो गया होता किन्तु हमारे नेताओं को यह मंजूर नहीं। वे समझते हैं कि बिना कोई आत्मिक उपाय भाग्य में ईश्वर इच्छा प्रधान से ही सब काम बन जायगा।

जनसाधारण को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए त्याग और संयम बहुत कामदार औजार हैं। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में पली हुई जनता के साथ ये विशेष असर रखते ही हैं। नैतिकतावादी दृष्टिकोण से भी त्याग के बिना निश्चय दृढ़ नहीं होता। निश्चय दृढ़ हुए बिना नीति का ठीक-ठीक व्यवहार और रक्षा हो नहीं सकती और नीति के ठीक-ठीक व्यवहार और रक्षा के बिना सफलता प्राप्त करने की बात मात्र स्वप्न मात्र है। स्वतन्त्रता के कार्यों में नेताओं को प्रथम जनता का विश्वासपात्र बनना पड़ता है।

इसके लिए उन्हें चाहिए कि अपनी नीति की रक्षा को एक परम आवश्यक कार्य समझें। हमारी समझ में यहाँ के जन-आन्दोलन में जो शिथिलता आ गई है वह नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का खासकर श्री विश्वेश्वर प्रसाद जी की भूलों का दुष्परिणाम है। दो वर्ष बाद नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब पहले-पहल आन्दोलन छेड़ा था तब यहाँ की जनता उनके ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास करने लग गई थी। उसने जिस प्रकार उनका अनुगमन किया वह आप लोगों को भी मालूम है। किन्तु बाद में वे नेपाली जनता की आँखों से गिर गये। इसका कारण था जब वे बीमारी की वजह से नजरबन्दी से छोड़ दिये गये (शायद आप लोगों के कहने पर ही राणाओं ने छोड़ा) तब उन्हें उचित था कि बीमारी से आराम हो जाने के बाद अपनी आत्मा की नीति रक्षा के लिए यहाँ लौट आते और सरकार से कहते कि या तो सरकार उन्हें भी उनके सहयोगियों के साथ (जो उनके साथ-साथ पकड़े गये थे) जेल में रखे या उनकी माँगों को पूरी करे। इस तरह अपनी नीति की रक्षा करना तो दूर रहा इसके विपरीत भारत में ही रहकर सभापति-पद के लिए वे डिल्ली रमण जी से लड़ने लगे। परिणामस्वरूप नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। सरकार को भी यह मौका अच्छा हाथ लगा। उसने अपने एजेंटों को कांग्रेस के अन्दर घुसा कर जहाँ तक हो सका फूट को बढ़ा दिया। श्री डिल्ली रमण एक साधारण आदमी ही क्यों न थे फिर भी परिस्थिति को पहचानते हुए भी कोइराला जी को वाजिब था कि श्री डिल्ली रमण को कुछ समय के लिए सभापति के पद में रहने देते और आप यहाँ आकर उपरोक्त काम करके न रहते। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि वे ऐसा करते तो जनता के कैसे विश्वासपात्र बन गए होते और श्री डिल्ली रमण जी उनके विरुद्ध कहाँ तक चल सकते। इसी एक त्रुटि से ही किया-कराया सब मिट्टी में मिल गया और साथ यह बहुत सम्भव कि श्री विश्वेश्वर प्रसाद से राणाओं ने पैसा लेकर आन्दोलन को शिथिल कर दिया। कांग्रेस में भी फूट डाल दी। हो सकता है राणाओं ने ही इस बात की अफवाह फैलायी हो किन्तु साधारण जनता के लिए यह देखते हुए कि आन्दोलन के मुख्य नेता तो छूटकर भारत चले गए हैं तथा उनके साथी और कार्यकर्त्ता (अभी तक) जेल की हवा खा रहे हैं इस बात पर विश्वास करने के सिवाय और चारा ही क्या था। अच्छे-अच्छे आदमी भी इस बात पर विश्वास करने लगे। हाल में जब वे यहाँ आये थे तब हमने इस त्रुटि के बारे में उन्हें लिखा था। उत्तर में उन्होंने लिखा कि वे इस तरह अपनी जान आग में झोंकना नहीं चाहते।

इस बार उनसे आगमन का कारण पूछने पर उन्होंने लिख भेजा था कि सरकार के विरुद्ध सफल कार्य की रचना के लिए ही वे यहाँ आये थे। परन्तु दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस में श्री कोइराला जी और श्री रमण जी के बीच जो फूट हुई थी उसको मिटाने के लिए यहाँ राजबन्दी कार्यकर्त्ताओं से बहुत सलाह की थी किन्तु इसका कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं

निकल सका था। उससे निराश होकर उन कार्यकर्ताओं ने सोचा कि अपने पैरों पर खड़ा होना ही अच्छा है। इसी विचार के अनुसार उन्होंने 'नेपाल प्रजा पंचायत' नामक संस्था स्थापन के लिए जनता से अपील की थी। परिणामस्वरूप यहां जो सत्याग्रह आन्दोलन होने वाला था उसको सरसक अपने पक्ष में मिलाने न हो सका तो उसमें बाधा डालने के लिए ही श्री कोइराला जी यहां आये थे। उनकी इच्छा पूरी न हो सकी क्योंकि यहां के कार्यकर्ता उनसे अलग किए गये थे और साथ ही आन्दोलन के लिए कटिबद्ध थे।

इसी बीच उनके साथ हमारी लिखा-पढ़ी हो रही थी। हम ने उन्हें लिखा था "आप के ऊपर जनता का विश्वास हटता जा रहा है। आप इस बार यों ही लौटकर भारत चले जाइयेगा। आपके पकड़ जाने से ही तमाम काम नहीं रुक जायगा। अपना हिस्सा आप लिजिए शेष प्रकृति आप ही देख लेगी। जन-आन्दोलन एक ही आदमी के बूते या भरोसे नहीं हुआ करता। पहले आप ने जो त्रुटि की है उसके प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाइए। सरकार ने नये वर्ष के शुरू से नया विधान चालू करने की घोषणा की थी किन्तु अभी तक उसे कार्यान्वित नहीं किया है। आप सीमा को लांघिये या कि मुकर्रर तारीख में यहां आकर अपनी कार्रवाई शुरू करले। अब भी मौका है सरकार की झूठी घोषणा के विरोध में यहीं यहीं से आवाज उठाइए। पकड़ गये तो भी कोई हर्ज नहीं आपका हिस्सा तो लिया जायगा" इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे क्यों अपनी जान आग में झोंकना चाहने लगा। लौट जाने को ही थे। परन्तु इसी वक्त सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और एक गुप्तस्थान जेल में बन्द कर दिया।

इसी समय सेन्ट्रल जेल नम्बर दो में जहां पंचायत आन्दोलन के कार्यकर्ता रक्खे गये हैं राजबन्दियों द्वारा जेल के कप्तान के अत्याचारों के विरुद्ध सारा सत्याग्रह के कारण उन पर सरकार की तरफ से जैसी मार पड़ी उसका कोई बयान नहीं। १४२ आदमी घायल हुए। उनमें से ग्यारह और श्री विश्वेश्वर बाबू के चार पुराने सहयोगी सहित जमा संघरह को सरकार ने सेन्ट्रल जेल नम्बर एक के 'कालघर' नामक नरक में अभी तक बन्द कर रक्खा है। हम टंक प्रसाद और रामहरि उस नरक में चार वर्ष रहे और श्री गणपमान सिंह ग्यारह वर्ष। अभी हम लोगों के लिए वहां जगह खाली करवानी पड़ी इसलिए हम लोग नम्बर दो में लाए गये हैं।

इस घटना के कुछ दिनों के बाद श्री कोइराला जी ने भी अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू करने के दो रोज पहले उन्होंने यहां किसी मित्र से सहानुभूति और सहयोग के लिए यहां हम सभी को एक पत्र भेजा था। हम लोगों ने भी इसके लिए प्रबन्ध किया। यहां आए कार्यकर्ताओं ने उनके सहयोग में अनशन शुरू कर दिया। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब की एक तारीख से सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ देने की घोषणा कर दी। अनशन के उन्तीसवें दिन भारत की राजदूत की भेंट श्री भारत सरकार से हुई। हमें पीछे से मालूम हुआ कि श्री भारत सरकार ने यदि आन्दोलन बन्द करने के लिए उनसे कहा

था और उन्होंने भी अपने को रिहाई मिलती देखकर आन्दोलन बन्द करने के लिए अपने मित्रों को पत्र लिखे थे। जो हो वे छोड़ दिये गये। आन्दोलन बन्द करवाने की वजह बतलाते हुए नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने पत्रों में प्रकाशित करवाया— "सरकार और नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बातें होने जा रही हैं। इसके लिए शान्त वातावरण की आवश्यकता है। इसी वजह से कुछ दिनों के लिए आन्दोलन बन्द करवाया जाता है।" रिहाई मिलते ही श्री कोइराला जी पटना की तरफ रवाना हुए।

वहां पहुंचकर वे क्या वक्तव्य प्रकाशित करवाते हैं कि "नेपाल सरकार राजनीतिज्ञों के प्रति संतोषजनक भाव रखती है। अपनी रिहाई के बाद मैं अपने अनशन को चालू किये रहने का कोई आधार नहीं पाता।" इत्यादि इत्यादि। सब वक्तव्य १९ २ ४० के दिन का भार राजबन्दियों पर पड़ी और सरकार अब भी उनके प्रति जो दुर्व्यवहार कर रही है उसके बारे में सब जानते हुए वहां जाकर जब वे ऐसा वक्तव्य देने लगते हैं तब उन के बारे में क्या समझा जा सकता है। क्या उनका अनशन जारी रखने के लिए कोई आधार नहीं था। जब कि सरकार ने उनमें से एक भी मांग (जिन मांगों को लेकर वे अनशन कर बैठे थे) पूरी न की थी और सारे आदमी सभी सहानुभूति और सहयोग से अनशन कर ही रहे थे कि इन लोगों का अपना अनशन तोड़ने की खबर तक दिये बिना वे वहां से चल दिये।

बाद में दिल्ली पहुंचकर वे फिर क्या कहते हैं कि "मुझे विश्वास है कि नेपाल सरकार एक मास के अन्दर ही कुछ करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आन्दोलन को बन्द कर देने का हमारा निर्णय उचित सिद्ध किया जायगा। नेपाल सरकार कुछ सुधार करने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक है। मैं आशावादी हूं और मुझे निश्चय है कि सरकार ऐसी चेष्टा करेगी।" इत्यादि। जिस प्रतिक्रियावादी श्री मोहन शमशेर और उनके साथियों ने अपनी समालोचनाओं के कारण अपने सुधारवादी चचेरे भाई श्री पद्म शमशेर को पद त्याग के लिए बाध्य किया वे प्रजाहित सम्बन्धी सुधारों के लिए कहां तक कुछ करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। यह साधारण से साधारण व्यक्तियों को भी स्पष्टतर मालूम हो सकने वाली बात है। थोड़ी देर के लिए हम यह मानें कि वह इस तरह राणाओं को फुसला कर अपना काम निकालना चाहते हैं तो इस पर भी हमारा दिल विश्वास करना नहीं चाहता क्योंकि श्री कोइराला जी को यह बखूबी मालूम है कि पक्का कूटनीतिज्ञ श्री मोहन शमशेर उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ फंसने वाले आदमी नहीं हैं। श्री कोइराला जी और नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाय आन्दोलन बन्द करवाते वक्त तो कहते हैं कि सरकार और उसके बीच बातें हो रही हैं किन्तु बाद में सरकार ने जब इस बात का खण्डन किया तब वे लोग कुछ जवाब ही नहीं दे सके। आखिर बातें की बात भी झूठी निकली।

महाशय! कांग्रेस जैसी उत्तरदायित्व रखने वाली एक राष्ट्रीय संस्था को क्या इस तरह झूठी बातों में आना और बिना कुछ सबूत जनता में विरोधी बातें कहनी चाहियें? एस

कार्यों से तो जनता का अपने ऊपर जो विश्वास बन गया है उस पर कुठाराघात ही होता है। हमारे नेताओं को यह मालूम नहीं कि यह जन-आन्दोलन है। इसके संचालन के लिए जनता का विश्वासपात्र बनना परम आवश्यक है। नीति की रक्षा के बारे में इस बार भी उन्होंने बड़ी भारी भूल की है। क्या उन्हें अपनी एक भी मांग पूरी हुए बिना रिहाई लेकर भारत लौट जाना उचित था? हां वे एक मुसलमान जेल में रखे गये थे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। इसके लिए सरकार से कहते और जेल के अन्दर कहीं अच्छी जगह अपने को रखवाते। अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग में पड़े हुए सब कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ दिये गये होते तो भी एक बात थी। हमारी समझ में जन-आन्दोलन बन्द करवाने के बदले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई हो जाने के बाद ही उन्हें भारत लौट जाना उचित था।

जन आन्दोलन के नेताओं के जेल में पड़े रहने से सब काम नहीं रुक जाता बल्कि अदृश्य रूप से अच्छा प्रभाव और भी कारगर तौर पर बाहर फैलता रहता है। इस बार भी जब वे पकड़े गये तब ही जनता ने उन पर पुनः विश्वास करना शुरू किया और शायद उसका एक अंश वापिस एक खूब आन्दोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया था। नेताओं की तरफ से सच्चा त्याग दिखाए बिना जनता के पास मापदण्ड ही क्या है जिससे वह असल नेता को नकली का भाव लेकर उसके पीछे हो ले। इससे हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि जहां-तहां जान खतरे में डालें। यह बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि कोरे त्याग से ही सभी काम नहीं बन जाते तथापि जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां वह होना ही चाहिए। नहीं तो लाख तदबीर करने पर भी काम नहीं बन सकता। हम ऊपर कह चुके हैं कि शांति के ठोस-ठीक प्रभाव के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात यह है कि आम जनता के साथ रहना सीखे बिना नहीं बन सकता। उसके साथ ही नम्रता और सच्ची हमदर्दी से पेश आना चाहिए। फिर नेताओं की बातों में स्थिरता भी खूब होनी चाहिए। कभी एक बात कभी दूसरी बात कहना आन्दोलन में विरोध। इन बातों से नेताओं को बहुत परहेज करना चाहिए और सही-सुथरी बात कह देनी चाहिए जिसको साधारण जनता समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। उसके साथ इतना सच्चा तालमेल है ही नहीं जिससे अग्रिम दल जत्था जत्था बराबर बाकी लोगों के बीच सम्पर्क स्थापित कर उनका समर्थन पाए।

था विदेश प्रचार कार्यालय की जो बात यह है उसपर भी किसी रूप की रोशनी का सा कोई अच्छा असर नहीं है। मुल्क में जाना है कि [illegible] जगह [illegible] प्रश्न कार्यालय से प्रकाश किया करे [illegible] 'सम्मिलित सरकार' की मांग परमार्थ का उद्देश्य से। यदि इस तरह केवल कांग्रेस द्वारा [illegible] बाहर से ही सो वर्ष से स्थापित लोकतन्त्रवादी सरकार का दिल से विश्वास बाहर करने में समर्थ होना तो [illegible] के लिए बड़ी-बड़ी सैद्धान्तिक बात मजबूत करने की आवश्यकता ही क्यों [illegible] और [illegible] किसी रूप से तो बात [illegible] सिद्धान्त का आवश्यकता

हुई है कि शायद वे इण्डियन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और उनके द्वारा जो काम होता है लोग उसे आप लोगों का ही कराया समझते हैं। इतनी भूलें करने के बाद भी उनकी जो कुछ इज्जत बच रही है वह आप लोगों के साथ सम्बन्ध होने की बदौलत ही है। किन्तु वे इस तरह कब तक जनता के विश्वासपात्र बने रह सकेंगे ?

अभी आप लोगों के प्रति हमारी जनता की काफी श्रद्धा भक्ति है। अस्तव्यस्त गिरी हुई स्थिति के कारण जिस तरह हमारी जनता की मनोवृत्ति क्रान्ति की तरफ झुक रही है और उसी वक्त जिस तरह आप समाजवादी नेताओं ने उनकी राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवाज उठाई है उससे मालूम होता है कि आई० एस० पी० का प्रभाव हमारे देश में बहुत काल पर्यन्त फैलता रहेगा। किन्तु भी विश्वेश्वर प्रसाद द्वारा जैसी भूलें हो रही हैं वह इसके लिए बहुत खतरनाक है। यहां की जनता उनकी हाल की कार्रवाई के कारण उनसे बहुत चिढ़ी हुई है। हमें इस बात से बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे प्रजा पक्ष की राजनैतिक कार्रवाई में शुरू से ही उनके नेताओं में फूटसूपन आ गया है। उन्हें नेता बनने का शौक तो है लेकिन संकट के समय नेताओं को अपनी जान सब से आगे करनी पड़ती है—यह बात उन्हें मालूम नहीं।

अब आप से हमारा कहना यह है कि जैसे आप ने हमारे मामले में मदद करने की मेहरबानी की है वैसे ही नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के कार्यों पर निगरानी रख उन्हें ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश भी करें। हम यह नहीं कह सकते कि श्री कोइराला जी ने बदनीयत से ही ऐसा किया हो। संभवतः उनके दृष्टिकोण में कुछ भेद या ज्ञान से ही ऐसी गलती हुई है। यदि ऐसा है तो वे फिर ठीक रास्ते पर आ सकते हैं। उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं उल्टा हमारी भलाई ही की थी और अब भी आशा है वे ऐसा करते रहेंगे। किन्तु राष्ट्रीय हित के आगे वैयक्तिक स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए इसीलिए कृतज्ञता को छोड़कर हमें उनके विरुद्ध उपरोक्त बातें कहनी पड़ी हैं। हम आपको अपना सम्मानास्पद साथी और सुहृद समझते हैं। श्री कोइराला जी भी आपको वैसा ही समझते होंगे इस हालत में यदि हम उनके दोषों को सुधार के लिए आपके सामने पेश करें तो हमने उनकी बुराई की है ऐसा ख्याल उन्हें नहीं रखना चाहिए।

संगठन के बारे में यदि नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण ठीक रास्ते पर चल रहे तो अभी तक बहुत बड़ा संगठन हो गया होता। प्रजा नवयुग में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठी है। उसकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और वर्तमान शासक और उनकी शासन-पद्धति के प्रति वह भयानक विरोध-भाव रखती है।

अब यहां जो संगठन होगा वह हमारी राय में समाजवादी सिद्धान्त की नींव पर ही होना चाहिए। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि यहां अभी जागरूक सर्वहारा मजदूर वर्ग की सृष्टि नहीं हुई है। इसलिए यहां समाजवादी संगठन की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर में हम बरमा आदि देशों का उदाहरण पेश करते हुए यह कहना चाहते हैं कि संसार भर में

कार्यों से तो जनता का सबसे ऊपर जो विश्वास बन गया है उस पर कुठाराघात ही होता है। हमारे नेताओं को यह मालूम नहीं कि यह जन-आन्दोलन है। इसके सञ्चालन के लिए जनता का विश्वासपात्र बनना परम आवश्यक है। नीति की रक्षा के बारे में इस बार भी उन्होंने बड़ी भारी भूल की है। क्या उन्हें अपनी एक भी माँग पूरी हुए बिना रिहाई लेकर भारत लौट आना उचित था? हाँ वे एक मुसम्मात जेल में रक्खे गये थे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। इसके लिए सरकार से कहते और जेल के अन्दर कहीं अच्छी जगह अपने को रखवाते। नेताओं के राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्त में पकड़े हुए सब कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ दिये गये होते तो भी एक बात थी। हमारी समझ में जन-आन्दोलन बन्द करवाने के बदले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई हो जाने के बाद ही उन्हें भारत लौट आना उचित था।

जन-आन्दोलन के नेताओं के जेल में पड़े हो सब काम नहीं रुक जाते बल्कि अदृश्य रूप से अपना प्रभाव और भी कारगर तौर पर बाहर फैलता रहता है। इस बार भी जब वे पकड़े गये तब ही जनता ने उन पर पुनः विश्वास करना शुरू किया और शायद उसका एक बड़ा भाग फिर एक नूतन आन्दोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया था। नेताओं की तरफ से सच्चा त्याग दिखाये बिना जनता के पास माप-दण्ड के लिए है ही क्या जिससे वह अपने नेता को सच्चे का साथ लेकर उसके पीछे हो ले। इससे हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि जहाँ-तहाँ जान झोंकते फिरें। यह बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि कोरे त्याग से ही सभी काम नहीं बन जाते तथापि जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ वह होना ही चाहिए। नहीं तो लाख तदबीर करने पर भी काम नहीं बन सकता। हम ऊपर कह चुके हैं कि नीति के ठीक-ठीक प्रयोग के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात यह है कि आम जनता के साथ ज्यादा सेखी शान्ति नहीं चल सकती। उसके साथ तो सरलता और सच्ची हमदर्दी से पेश आना चाहिए। फिर नेताओं की बातों में स्थिरता भी खूब होना चाहिए। कभी एक बात कभी दूसरी बात वह भी आपस में विरोधी। इन कार्यों में नेताओं को बहुत परहेज करना चाहिए और सीधी-सादी बात कह देना चाहिए जिसको साधारण जनता समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। उसके पास इतनी सपनी तालीम है ही कहाँ जिसके जरिये वह अस्पष्ट-अर्थी उलझन वाली बातों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर उनको समझ सके।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की तो बात यह हुई उधर श्री दिल्ली रमण श्री रेग्मी का भी कोई अच्छी खबर नहीं है। सुनने में आता है कि वे एक जगह बैठकर प्रेस कान्फ्रेंस में वक्तव्य दिया करते हैं, बस उन्होंने बहुत दिन बाद ही अन्तरिम सरकार की माँग फरमाई या ललकार से। यदि इस तरह केवल कागजी हाँक देकर कोई बाहर से ही सौ वर्ष से स्थापित स्वेच्छाचारी सरकार को किले से निकाल बाहर करने में समर्थ होता तो शान्ति के लिए बड़ी-बड़ी तैयारियाँ कर मुठभेड़ करने की आवश्यकता ही क्यों हुआ करती? और श्री दिल्ली रमण से तो सब लोगों को इसलिए शिकायत की आवश्यकता

हुई है कि शायद वे इण्डियन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और उनके द्वारा जो काम होता है लोग उसे आप लोगों का ही कराया समझते हैं। इतनी भूलें करने के बाद भी उनकी जो कुछ इज्जत बच रही है वह आप लोगों के साथ सम्बन्ध होने की बदौलत ही है। किन्तु वे इस तरह कब तक जनता के विश्वासपात्र बने रह सकेंगे?

अभी आप लोगों के प्रति हमारी जनता की काफी श्रद्धा-भक्ति है। अत्यन्त गिरी हुई स्थिति के कारण जिस तरह हमारी जनता की मनोवृत्ति क्रान्ति की तरफ झुक रही है और उसी वक्त जिस तरह आप समाजवादी नेताओं ने उनकी राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवाज उठाई है इससे मालूम होता है कि आई० एस० पी० का प्रभाव हमारे देश में बहुत जल्द पर्याप्त फैलता रहेगा। किन्तु श्री विश्वेश्वर प्रसाद द्वारा जैसी भूलें हो रही हैं वह इसके लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ की जनता उनकी हाल की कार्रवाई के कारण उनसे बहुत चिढ़ी हुई है। हमें इस बात से बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे प्रजा पक्ष की राजनैतिक कार्रवाई में शुरू से ही उनके नेताओं में फूहड़पन काम रहा है। उन्हें ऐसा करने का शौक तो है मगर संकट के समय नेताओं को अपनी जान सब से आगे करनी पड़ती है—यह बात उन्हें मालूम नहीं।

अब आप से हमारा कहना यह है कि जैसे आप ने हमारे मामलों में मदद करने की मेहरबानी की है वैसे ही नेपाल राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के कामों पर निगरानी रख उन्हें ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश भी करें। हम यह नहीं कह सकते कि श्री कोइराला जी ने बदनियत से ही ऐसा किया हो। संभवतः उनके दृष्टिकोण में कुछ भूल या भ्रम से ही ऐसी बातें हुई हैं। यदि ऐसा है तो वे फिर ठीक रास्ते पर आ सकते हैं। उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। उन्होंने हमारी भलाई ही की थी और अब भी आशा है वे ऐसा करते रहेंगे। किन्तु राष्ट्रीय हित के आगे वैयक्तिक स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए इसीलिए कृतज्ञता को छोड़कर हमें उनके विरुद्ध उपरोक्त बातें कहनी पड़ी हैं। हम आपको अपना सम्माननीय साथी और सुहृद समझते हैं। श्री कोइराला जी भी आपको वैसा ही समझते होंगे। इस हालत में यदि हम उनके दोषों को सुधार के लिए आपके सामने पेश करें तो हमने उनकी बुराई की है ऐसा ख्याल उन्हें नहीं रखना चाहिए।

संगठन के बारे में यदि नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण ठीक रास्ते पर चले होते तो अभी तक बहुत बड़ा संगठन हो गया होता। प्रजा नवयुग में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठी है। उसकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और वर्तमान शासक और उनकी शासन-पद्धति के प्रति वह मार-मार विरोध-भाव रखती है।

अब यहाँ जो संगठन होगा वह हमारी राय में समाजवादी सिद्धान्त की नींव पर ही होना चाहिए। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि यहाँ अभी जागरूक सर्वहारा मजदूर वर्ग की सृष्टि नहीं हुई है। इसलिए यहाँ समाजवादी संगठन की कोई गुंजाइश नहीं। उत्तर में हम बुखारा आदि देशों का उदाहरण पेश करते हुए यह कहना चाहते हैं कि संसार अभी

तक जहाँ जहाँ समाजवादी सिद्धान्त लागू हो सका है वहाँ-वहाँ जागरूक सर्वहारा मजदूर वर्ग के भरोसे नहीं बल्कि इसी सिद्धान्त की चेतनता प्राप्त ऊपरी कुछ व्यक्तियों के जबरदस्त दल संगठन और शक्ति के भरोसे ही लागू हो सका है। चीन देश में भी दल-शक्ति के भरोसे ही पहले-पहल लागू हो सका है। यदि कोई यह कहे कि दल-शक्ति के भरोसे ही सब काम करना बुरा है तो ठीक है किन्तु कुछ दिनों के लिए जब तक कि विरोधियों के साथ लड़ाई जारी रहती है और अपने सिद्धान्तों का महत्त्व और चेतनता आम जनता के नस-नस में नहीं घुल जाती तब तक यह हथियार के रूप में किसी सीमित काल तक प्रयोग किया जा सकता है। अभी हमारी जनता के सामने दो रास्ते हैं एक समाजवादी और दूसरा पूँजीवादी। ऐतिहासिक सिलसिले के दृष्टिकोण से एक के बाद ही दूसरा शुरू होता है किन्तु अपने देश की स्थिति से लाभ उठाकर यदि हम शार्टकट तरीके से आगे के रास्ते को पकड़ सकें तो क्या हर्ज है? यह काम दल-शक्ति के भरोसे राजसत्ता को अपने हाथ में लेकर खुशी से सम्पादन कर सकते हैं। केवल दल-शक्ति ही नहीं इस काम में आम जनता की सहानुभूति और सहयोग भी हमारे साथ रहेगा। नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को अभी इसी बात को दृष्टि में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कोइराला जी को जब हमने इस बारे में लिखा था तब उन्होंने उत्तर में एक जगह तो यह लिखा कि हमारे यहाँ समाजवादी कार्यों के लिए कोई गुंजाइश नहीं दूसरी जगह वह लिखते हैं कि नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस भी बाद में जाकर समाजवादी सिद्धान्त का पोषक बन सकती है। तीसरी जगह दलबन्दी की खूब निन्दा की है। हो सकता है वे भी समाजवादी सिद्धान्त के पोषक हों और बाद में जाकर नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस को समाजवाद की तरफ अग्रसर भी करावें। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी हमारी भोली-भाली जनता में नेताओं द्वारा जिस तरह की चेतनता भरी जायगी बहुत अंशों में हमारा भविष्य उसी के अनुरूप बनेगा। अभी कुछ गड़बड़ी हुई तो बाद में जाकर समस्या किसी तरह सुगम नहीं सकेगी आप सोशलिस्ट बने ही रहेंगे देश पूँजीवाद के गर्त में फँसता ही जायगा जैसा कि नेहरू जी और उनके हिन्द की हालत हो रही है। इसलिए हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी से ही हमारे यहाँ समाजवादी चेतनता पर संगठन होना चाहिए।

अब इस दल के कार्यक्रम के बारे में हमारी राय में भी नागरिक हक के लिए ही आन्दोलन होना चाहिए। साथ ही राजबन्दियों की रिहाई के लिए भी। आन्दोलन के लिए हमारे देश में कोई संस्था अकेली इतनी शक्तिशाली नहीं बन गई है कि वह अपने ही भरोसे कारगर तौर पर आन्दोलन कर सके। इसलिए देश में जितनी संस्थाएँ हैं उन्हें मिलकर ही आन्दोलन करना चाहिए। हम लोगों ने इस बारे में सभी को पत्र लिखे हैं। एक पत्र सहानुभूति और सहायता के लिए श्री नेहरू जी को भी लिख भेजा है। आप ही के भरोसे पत्र भेजा जा रहा है। यदि आप यह समझें कि उनके द्वारा श्री नेहरू जी के पास कुछ काम बन सकेगा तभी आप इसे उनके यहाँ भेज दें।

हम को भारतीय समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत कुछ लिखना था किन्तु स्थानाभाव की वजह से ऐसा नहीं कर सके। और थोड़ा ही लिखकर सन्तोष कर रहे हैं।

हम नम्रतापूर्वक आप से सब से पहले यह पूछना चाहते हैं कि भारतीय समाजवादी पार्टी की अच्छी प्रगति होती नहीं दिखाई दे रही है इसका क्या कारण है? आपका दल क्रान्तिकारी समाजवादी दल है। हमारी समझ में समाजवादी सिद्धान्त वालों के लिए वैधानिक ढंग से आगे बढ़ जाने पर एक दिन बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाय तो उस वक्त भी क्या हमें यह आशंका नहीं बनी रहेगी कि भारत में भी जर्मनी और इटली की तरह पूंजीपतियों के प्रत्याक्रमणकारी फासिस्ट दल खड़ा होगा और वह हमें हर तरह से बरबाद कर डालेगा? जब हम लड़ाई के लिए हर हालत में तैयार रहना पड़ेगा तो अभी से ही क्यों न क्रान्तिकारी उपायों को अपनाया जाय? परन्तु क्रान्तिकारी कार्यों में भारतीय समाजवादी पार्टी इतनी कार्यशील नहीं दिखाई दे रही है फिर हम जैसे के अन्दर रहने वालों को तो मालूम भी कैसे हो सकता है। जो हो हम आप से यह कहना चाहते हैं कि अभी भारतीय समाजवादी पार्टी में जितनी कार्यशीलता दिखाई दे रही है वह वर्तमान स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं।

हमें मालूम है कि कम्युनिस्टों के प्रति आप लोगों का विरोध-भाव है। हो सकता है विभिन्न देशों के कम्युनिस्ट दल सोवियट रूस की ही प्रेरणा के वशीभूत हों और यह भी हो सकता है कि वे रूस की विस्तारनीति ही सारे संसार में फैलाना चाहते हों। यदि बात ऐसी है तो हम भी उनके प्रति सशंक हैं। परन्तु इसकी वजह हमारे सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है वह बहुत विचारणीय है। वह समस्या यह है कि देश के अन्दर उसकी बढ़ती को कैसे रोका जाय। कम्युनिज्म एक बहुत शक्तिशाली मुवमेन्ट है। आर्थिक समानता के विरोधी पूंजीपतियों की कट्टरता और उनके पृष्ठपोषक पुरानी धार्मिक संप्रदायों की कुचालों की प्रतिक्रिया में पर्याप्त रूप से कार्यशीलता और प्रभाव यदि वामपन्थियों के कोई दल प्रदर्शन कर सकता है तो वह कम्युनिस्ट दल है। इसमें अपने विरोधियों के प्रति वैसी ही कट्टरता और निर्ममता है जैसा कि पूंजीपतियों और उनके पक्षपातियों में होता है। पुरानी स्थिति से पीड़ित जनता को यह न केवल नयी आर्थिक प्रणाली ही प्रदान करती है वरन् नये समाज के रूप में तृप्ति भी। यह नयी सामाजिक और धार्मिक प्रणालियों का दावा ही नहीं इसने अमल एक बढ़ाव की है। इसके कार्यकर्ताओं में अदम्य उत्साह और कार्यशीलता है। यह समझना निरी भूल है कि केवल रूस के पैसे और सहायता से ही संसार में कम्युनिज्म फैल रहा है।

आर्थिक समानता की तरफ संसार की सारी गरीब जनता की प्रवृत्ति हो रही है उसका अन्तर्राष्ट्रीय रूप देकर आज कार्यान्वित कम्युनिज्म ही है। भारत में अभी कम्युनिज्म उतना जोर नहीं पकड़ सका। पूर्वीय देशों में यह जिस तरह फैल रहा है उसे आप देख ही रहे हैं। यदि आप भारत में इसकी बढ़ती को रोकना चाहते हैं तो आपको भी

उसी तरह की कार्यशीलता और मजहबी तौर पर कट्टरता दिखानी होगी पूजीवाद के विरुद्ध अपने अनुयायियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करना होगा और उनके हाथों से देश के शासन की बागडोर छीनकर बहुत जल्दी कम्यूनिस्टों की बराबरी का या उससे भी अच्छी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अपने देश में लागू कर देनी होगी तभी आप कम्यूनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सकेंगे।

हम आपको कठिनाइयों का कुछ-कुछ दिग्दर्शन हो रहा है। इन कठिनाइयों से पार होने के लिए सुदृढ़ मोर्चे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए हम आप से यह कहते हैं कि यदि आप हमारे आन्दोलन को प्रोत्साहित कर कामयाब बना सकें तो आपके लिए वह सुदृढ़ मोर्चा हमारा देश बनेगा और इसी के जरिये भारत में भी अपने सिद्धान्त के प्रचार के लिए आप बहुत जोरों से काम कर सकेंगे।

हमें अभी एक बात का भय हो रहा है भारत में अभी नेहरू जी और उनके सदृश ही गरीबों के लिए हृदय में स्थान रखने वाले व्यक्तियों के हाथों में सरकार है इस वक्त हम यहा कुछ कर सकें तो हमारे कामों में बाधा देने वाला कोई नहीं होगा। किन्तु यदि वह मौका यों ही गुजर गया और भारत के शासन की बागडोर कहीं पूँजीपतियों के गुलामों के हाथों म चली गयी तो उस वक्त हम लोग समाजवाद के तअल्लुक यहा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी जल्दी ही यहा परिवर्तन न हो। इसके लिए आप लोग हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर मदद करें।

हम लोग बाहरी संसार से बिल्कुल ही बन्द हालत म बहुत दिनों से जेल में हैं। इस वजह से हमारे उपर्युक्त विचारों में दोष भी हो सकते हैं। आप से हमारा निवेदन है कि उन दोषों का आप हमें दिखावें और कौन रास्ता अपनाना ठीक है इस बारे में भी अपनी राय हमें पत्र द्वारा प्रदान करें। पत्र में बहुतेरी त्रुटियां हो गई हैं—क्या करें कागज और समय की कमी से लाचार हैं। अन्त में सब त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए हम आप से विदा होते हैं। अस्तु!

भवदीय

टंक प्रसाद आचार्य आदि आदि

काठमाण्डू जेल कालकोठरी।

कालकोठरी (काठमाण्डू जेल)
२५ मार्च, २००६

श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला
नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस
प्रिय साथी

आपके कार्यों से हम को इतनी क्षुब्धता हुई है कि उसका बयान ही नहीं कर सकते। यहाँ सरकार के द्वारा राजबन्दियों के प्रति किये अत्याचारों के ज्ञात होते हुए भी आप ने जाकर 'सरकार राजनीतिकों के प्रति सन्तोषजनक भाव रखती है" वक्तव्य देने का कैसे साहस किया? पुनः "सरकार कुछ सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है" इत्यादि कैसे कह सके? आपकी यह कैसी नीति है? कुछ समझ में ही नहीं आता। कारावास की कठिन यातनाओं से मुक्त होकर बाहर जगत में पहुँचने के बाद आप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ही तो ऐसा नहीं किया? सरकार द्वारा किये गए अत्याचारों का वर्णन करना तो अलग रहा उल्टा आप सरकार का ही गुणगान करने लग गये।

आपके ऊपर लगाए गए सर्प से ही अनेक शंकाओं की दृष्टि से देखने लगा गया था। परन्तु हम लोगो ने अपने हृदय में उनको तनिक भी स्थान ही नहीं दिया। अन्त में आपके कार्यों को देखकर हमारे मन में अत्यन्त चोट पहुँची। आपके उपर्युक्त काम के बारे में हम ने बाबू जयप्रकाश नारायण का भी लिख भेजा है। इसके लिए आप जो कुछ समझते हों, मुझे तो आप बहुत बड़े नीतिवादी मालूम पड़ते हैं जिसमें सत्यासत्य का तनिक भी ध्यान न रख कर जिस प्रकार भी हो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। किन्तु इस प्रकार आप नहीं के न रहेंगे। नीतिवादी दृष्टिकोण से भी अपनी नीति की रक्षा तथा पालन करना अत्यन्त आवश्यक होता है। अनशन प्रारम्भ करके आप ने सहयोग तथा सहानुभूति के लिए यहाँ लिख भेजा। आठ आदमी यहाँ भी अनशन करने लगे। राणाओं द्वारा अपने को मुक्त होकर आपने "पटना पहुँचने ही अब अनशन चालू किये रहने का कोई आधार ही नहीं रहा" ऐसा वक्तव्य दे मारा। अपने अनशनकारी साथियों का कुछ भी ध्यान न रखना यह कौन सी समझदारी है? क्या इन अनशनकारियों को आपने अपने हाथ का खिलौना समझ लिया? सरकार ने तो आपकी मांगों में से एक भी पूरी नहीं की थी। राजनीति झूठ-मूठ का व्यवहारमात्र नहीं है। इसका ध्यान आप अच्छी तरह कर लीजिए। वहाँ जाकर आप नैतिक विजय का ढोंग बजाने लगे। यहाँ सरकार आपके अनुयायियों से कायरनामा कायम लिखवा रही है। यह किस प्रकार की नैतिक विजय है?

आपके द्वारा की गई अनेक त्रुटियों का बयान कैसे किया जाय? त्रुटि तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा होती है फिर हम क्यों कहते हैं केवल आप ही से त्रुटि हुई है, हमारा कहना यह नहीं है। अभिमानयुक्त तथा बुद्धि की अपरिपक्वतावश त्रुटि होने में अधिक अन्तर है यह किसान के लिए भी बोध्य है। बुद्धि की अपरिपक्वतावश त्रुटि करने वाले व्यक्ति को

अपनी गलती को स्वीकार करना ही पड़ेगा अन्यथा यह भी उतना ही घातक सिद्ध होगा जितना अभिप्राययुक्त त्रुटि-कार्य। हमारे नता लोग तो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं ऐसा सुनने में आता है। "हम जनता की आंखों में चढ़े हुए स्वयमापि नेताओं को अपनी गलती स्वीकार करना उचित नहीं" ऐसा कहते हैं। उपर्युक्त वचनों से आपको क्षोभ आना स्वाभाविक ही है परन्तु राष्ट्रीय कार्य मे हाथ डालने से अपने कारनामों की जवाबदेही वैसी ही होगी। आपस म हम कठोर शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहते। जिसकी इच्छा थी कि मेट होगी हम आपस म बाते करेंगे किन्तु अनेक कारणवश हमारा हृदय पृथक हो रहा है इसमे हम को अफसोस है।

अन्त में हम आप से यह कहेंगे कि अब भी ठीक रास्ता पकड़कर संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एक बार फिर प्रयत्न कीजिए और नागरिक हक प्राप्त करने के निमित्त आन्दोलन कर। हम ने इस सम्बन्ध मे श्री रेग्मी जी श्री महेन्द्र विक्रम जी श्री गोपाल जी इत्यादि को भी लिखा है। सब को एक में मिलाने का प्रयास करके अपने हाथ मे लीजिए और आन्दोलन चालू कीजिए। महाराज साहब लोगों की उदारता की आशा लगाये रहने मात्र से हमारा काम नहीं चलेगा। विपरीत स्वार्थ वाले एक दूसरे की उदारता म कब तक आशा लगाये रखेंगे—यह बात तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों के विचार में आनी ही चाहिए।

आपका
टंक प्रसाद आदि आदि

भारत में डिल्ली रमण रेग्मी और विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को आपस म लड़ते हुए देखकर जनरल हिरण्य शमशेर तथा जनरल महावीर शमशेर को विशेष चिंता हुई। जनरल हिरण्य शमशेर तथा जनरल महावीर शमशेर के सम्पर्क भारतीय नेताओं और मंत्रियों से भी थे इसलिए उन्होंने उनकी प्रेरणा से डिल्ली रमण रेग्मी तथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला म मेल कराने का प्रयास किया। इस कार्य में जनरल हिरण्य शमशेर के पुत्र जनरल सुवर्ण शमशेर न विशेष परिश्रम किया किन्तु तब भी दोनो व्यक्तियों म समझौता नहीं हो सका। फलतः जनरल महावीर शमशेर, सुवर्ण शमशेर महेन्द्र विक्रम शाह ने अगस्त सन् १९४८ ई० में नेपाल प्रजातंत्र कांग्रेस की स्थापना कलकत्ते म की। इसमें कई शिक्षों में मतपाय होकर सफलता भी प्राप्त की। नेपाल प्रजातंत्र कांग्रेस ने डिल्ली रमण रेग्मी तथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला से सहयोग करने की अपील की। नेपाल प्रजातंत्र कांग्रेस गांधीवादी तरीके अपनाकर देश म प्रजातंत्र लाने की हिमायती थी और थोड़े ही काल में उसे नेपाली और भारतीय जनता का समर्थन भी प्राप्त होने लगा था कि श्री इस तथा ग्यारह अप्रैल सन् १९५० ई० को नेपाल प्रजातंत्र कांग्रेस तथा नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के कोइराला दल का संयुक्त अधिवेशन कलकत्ता के ज्ञाइनर मिनमा हॉल में हुआ।

अधिवेशन में दोनों दल मिलकर नेपाली कांग्रेस में परिणत हो गये और जिसके मातृका प्रसाद कोइराला अध्यक्ष तथा महेन्द्र विक्रम शाह महामंत्री निर्वाचित किये गये। संघ के प्रश्न को लेकर प्रतिनिधियों के बीच तीव्र वाद-विवाद हुए और जिसके फलस्वरूप दोनों दल सभा भवन से बाहर निकल जाने को उद्यत हो गये। तराई के प्रतिनिधियों ने मध्यस्थता का काम किया और नेपाल प्रजातंत्र का चार आना वाला सदस्य नेपाली कांग्रेस का सदस्य स्वीकार कर लिया गया। दूसरे दिन दस अप्रैल सन् १९४० ई० को नेपाल में सत्याग्रह करने तथा राणा सरकार से किसी भी परिस्थिति में समझौता न करने के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

इसके पश्चात् २६ तथा २७ सितम्बर सन् १९५० ई० को बैरगनिया कान्फ्रेंस हुई जिसमें नेपाली कांग्रेस की कार्य-समिति भंग करके कांग्रेस के अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला को सर्वाधिकार दिये गये। इस प्रकार के प्रस्ताव का विरोध डाक्टर कुंवर इन्द्रसिंह तथा महेन्द्र विक्रम शाह ने जोरदार शब्दों में किये किन्तु वह प्रस्ताव पास कर ही लिया गया।

सशस्त्र क्रान्ति

नेपाली जनता एकतंत्री शासन-पद्धति से तंग थी। वह सुसंगठित न होने पर भी हुक्मी हुकूमत को समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ी होने की चेष्टा करती रही। दूसरी ओर शाही परिवार भी निरंकुश शासकों के फंदों से स्वतंत्र होना चाहता था। विश्व का इतिहास तो यही सिद्ध करता है कि जनता अपने हितकारक शासन न होने पर प्रायः राजाओं के विरोध में आवाज उठाती आई है परन्तु नेपाल-नरेश ने एक क्रान्तिकारी कदम बढ़ाकर जनभावना को और प्रोत्साहित कर दिया। महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव भी अपने पूर्वजों की भांति निरंकुश शासन से तंग आ गये थे और वह उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सहसा क्रान्ति के अग्रदूत बन गये। राणा शासकों ने समझा था कि वे दुनिया की आंखों में धूल झोंककर शाही परिवार को अपनी कठपुतली बनाए रहेंगे और नेपाल की भोली-भाली जनता पर दमन-चक्र चलाते रहेंगे किन्तु नरेश ने जिस दूरदर्शिता एवं दृढ़ता-पूर्वक कदम बढ़ाया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण-अक्षरों से लिखा जाएगा। नेपाल को फौलादी पंजों से मुक्त करने के लिए भारत में राजनैतिक दल उत्पन्न होकर जहां एक ओर बनारस पटना और कलकत्ता में अपने-अपने काम कर रहे थे वहां दूसरी ओर नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में भी जीवन-पर्यन्त कारावास की सजा पाए हुए नेपाल प्रजा परिषद् की प्रेरणा से काठमाण्डू का नवयुवक वर्ग प्रबुद्ध था कि इसी बीच अप्रैल सन् १९५० ई० को कलकत्ता अधिवेशन में नेपाली कांग्रेस को जन्म दिया और यह प्रस्ताव पास किया कि नेपाल में आन्दोलन छेड़ दिया जाय।

आन्दोलन की पृष्ठभूमि काठमाण्डू में भी बहुत पहले से तैयार थी किन्तु उसको व्यापक रूप देने में परिस्थिति बाधक थी।

२४ सितम्बर, सन् १९५ ई० को राणा सरकार ने डिम्मासनसिंह, गणेशमानसिंह, सुन्दरराज चालिसे सुशीला नारायण शमशेर आदि व्यक्तियों को बन्दी बना लिया और उन पर ये झूठे आरोप लगाकर प्राणदण्ड दे देना चाहा कि वे सब प्रधान मंत्री आदि की हत्या का षड्यन्त्र रच रहे थे। इस प्रस्ताव पर महाराजाधिराज ने लाल मोहर करने से साफ इनकार कर दिया। तब इस पर शासकों के होश हवास उड़ गये और उन्होंने अटपहरियों को भी यह आदेश दे दिया कि बिना सरकारी आज्ञा लिये नरेश को महल के बाहर मत जाने दो। प्रधान मंत्री मोहन शमशेर आदि राणा त्रिभुवन तथा उनके तीनों बालिग पुत्रों को मरवा भेजकर युवराजाधिराज के पंचवर्षीय ज्येष्ठ पुत्र वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। प्रधान मंत्री ने सोचा था कि शिशु महाराजाधिराज के नाम पर वह सब प्रकार

को मनमानी निर्विघ्नरूप से करते रहेंगे और वह दुनिया को यह साबित भी कर देंगे कि नरेश तथा उनके तीनों पुत्र शासन-कार्य से वैराग्य लेकर नेपाल की प्राचीनतम राजधानी गोरखा में प्रसन्न हैं। महाराज मोहन शमशेर की इस चाल को शाही परिवार भांप गया और उसने बलपूर्वक ६ नवम्बर सन् १९५० को शिकार खेलने के बहाने सहसा भारतीय दूतावास में शरण ले ली। इस आकस्मिक घटना से चारों ओर खलबली मच गई। मोहन शमशेर ने किसी प्रकार शाही परिवार को मनाकर राजभवन में वापिस बुला लेने की ठानी किन्तु उन्हें इस कार्य में जब सफलता नहीं मिली तो वह तुरन्त ही ब्रिटिश दूतावास की ओर दौड़े। ब्रिटिश हुकूमत उस शासन का पोषण करती रही और भारत को अपना गुलाम बना लेने के पश्चात् भी उसने नेपाल को पराधीन बना लेने की अपेक्षा उसके साथ मैत्री भाव ही बनाए रखना श्रेयस्कर समझा था। उसके समग्र भारतीय जन-आन्दोलन जहां एक ओर बाधक रही वहां दूसरी ओर अंग्रेजी हुकूमत के स्वार्थ उसके नेपाली गुर्गों द्वारा जिस हद तक पूरे होने संभव थे व पराधीन अथवा भारत में विलीन नेपाल द्वारा कदापि नहीं।

प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर ने सारी घटना ब्रिटिश राजदूत जॉर्ज फाल्कनर के समक्ष प्रकट की। कहा जाता है कि कतिपय राणाशासकों की योजना भारतीय दूतावास पर हमला करके नरेश को वापिस लाने की थी। किन्तु फाल्कनर ने इस रास्ते को खतरा बतला करके संसदीय तरीके से नरेश को पदच्युत कर देने की राय दी। फलस्वरूप प्रधानमंत्री मोहन शमशेर ने तथाकथित भारदारी सभा द्वारा जबर्दस्ती एक प्रस्ताव पास कराकर महाराजाधिराज त्रिभुवन को पदच्युत करके उनके ही तीन वर्षीय पौत्र ज्ञानेन्द्र को सिंहासन पर बैठा दिया। इसके बाद ही शिशु महाराजाधिराज के नाम पर मुद्रा भी प्रसार किया गया।

शिशु ज्ञानेन्द्र का राज्यारोहण समारोह हनुमान ढोका में इक्तीस तोपों की सलामी के साथ सम्पन्न हुआ। तोपों की आवाजें कालकोठरी तक पहुंचीं और जेल के सीखचों में बन्द राजबन्दियों को भी इस परिवर्तन का समाचार मिला। दूसरी ओर भारत में नेपाली कांग्रेस अवसर की प्रतीक्षा में थी ही और इसप्रकार श्री ५ सरकार जिन्दाबाद, राणा-शाही मुर्दाबाद आदि के नारों से गुंजित हो गया। क्रान्ति का बिगुल सुनते ही आजाद हिन्द फौज में शिक्षा पाए हुए नेपाली सैनिक भी अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए स्वाधीनता-संग्राम में कूद पड़े। नेपाल की बहादुर जनता एकबारगी उठ खड़ी हुई और गहन गुफाओं तथा पर्वत कन्दराओं में भी भीषण विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। पश्चिमी नेपाल के विद्रोही तत्त्वों ने एक प्रतिज्ञापत्र पर अपने रक्त से अंगूठे का निशान लगाकर राणाशाही को बिना उखाड़े चैन न लेने की शपथ ली और अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वाधीनता-संग्राम में भाग लिया। पूर्वी नेपाल के लाखों लिम्बू किरातों ने भी अपने सर पर कफन बांध कर सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। तराई की जनता तथा लिम्बू किरातों ने क्रान्ति के प्रथम चरण में अपनी रणकुशलता तथा साहस का अपूर्व परिचय दिया। अहिंसा के

विश्ववंद्य महात्मा गौतम बुद्ध ने यद्यपि विश्व को अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया था किन्तु लुम्बिनी बुटवल की तथा कपिलवस्तु क्षेत्र में ८ नवम्बर को खूनी क्रान्ति के लिए जनता ने जो विराट रूप धारण किया वह कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता।

उसमें सामन्तों तथा पुलिस से बन्दूकें लेकर भारतस्थित पेन्शन पाने वाले नेपाली सैनिकों द्वारा पुलिस चौकियों पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया। इसके दूसरे ही दिन दीपावली की रात्रि में जब कि सभी सरकारी सैनिक तथा कर्मचारी जूआ-शराब में मस्त थे कि नेपाली कांग्रेस के छापेमारों ने वीरगंज पर अचानक कब्जा करके सरकारी कोष

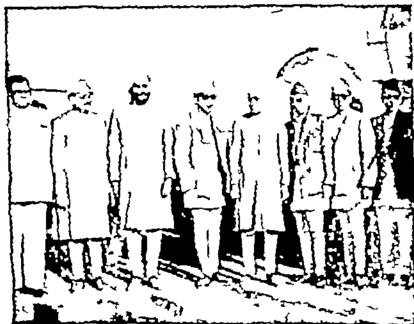


नेपाली कांग्रेस के विद्रोही नेता दिल्ली-हवाई अड्डे पर
(बाएं से दाएं) जनरल सुवर्ण शमशेर, विजयलक्ष्मी कोइराला मातृका प्रसाद कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तथा सूर्य प्रसाद उपाध्याय

और शस्त्रागार पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर लिया। उस समय वीरगंज के सरकारी कोष में लगभग पचास लाख रुपए तथा सोना चांदी के कुछ छत्र आदि भी थे और जिसकी बन्दरबांट विद्रोहियों के कुछ उच्च नेताओं के बीच हुई। इसमें से पैंतीस लाख रुपये तो भारत सरकार ने दिल्ली-हवाई अड्डे पर ही छीनकर अपनी हिरासत में ले लिया। वीरगंज के पतन से राणा सरकार कांप उठी। राजधानी की हालत बहुत नाजुक देखकर १२ नवम्बर को भारत सरकार ने दो वायुयान भेजकर महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को सपरिवार नई दिल्ली बुला लिया और हैदराबाद भवन में ठहराकर अपना अतिथि बना

लिया। बीरगंज में मुक्ति सेना और राणा फौज में घमासान लड़ाई हुई। दोनों पक्ष के अनेकों व्यक्ति मौत के शिकार हुए जिनमें विद्रोही नेता पिरथम मल्ल का नाम स्मरणीय है।

नेपाली कांग्रेस पश्चिमी नेपाल का कोई उचित प्रबन्ध नहीं कर सकी। पर तौलिहवा में सरल से डाक्टर कुँवर इन्द्रसिंह तथा इस पुस्तक के लेखक उनके साथी बहुत पहले से राणाशाही के खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहे थे और नेपाली कांग्रेस की वहां एक मजबूत शाखा थी। पश्चिमी नेपाल के डोटी के निवासी डाक्टर के आई सिंह कई सालों



महाराजाधिराज का दिल्ली-आगमन

से तौलिहवा में चिकित्सा करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और तभी से उनका सम्पर्क भारतीय नेता प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना से हो गया था। जब प्रोफेसर सक्सेना गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तब डाक्टर सिंह तौलिहवा सर्कल कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उस समय कांग्रेस की ओर से शिब्बनलाल सक्सेना ने कुँवर इन्द्र सिंह को तौलिहवा टाउन एरिया के सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा किया था और उनकी शानदार विजय हुई थी। जिस समय नेपाल में सशस्त्र क्रान्ति हुई वह कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता थे।

मौका के आगम वर्षे आने पर डाक्टर के आई सिंह तथा सेना में मुख्य भैरहवा पर कब्जा करके राणाशाही का अन्त करने की योजना बनाई। नेपाली कांग्रेस में महेन्द्र

विक्रम शाह को पश्चिमी नेपाल के आन्दोलन का संचालन करने का भार सौंपा। उन्होंने भैरहवा पर कब्जा करने की योजना का समर्थन किया। इस बीच गोपाल शमशेर ने वहाँ पहुँचकर अपने आपको नेपाली कांग्रेस की ओर से पश्चिमी नेपाल का सेनापति प्रसिद्ध किया। वास्तव में उनका काम आन्दोलन को सहयोग देना नहीं बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। असलियत का पता लगने पर डाक्टर के आई सिंह ने उनका भण्डाफोड़ कर दिया और गोपाल शमशेर को वहाँ से भागना पड़ा।

डाक्टर कुंवर इन्द्रसिंह तथा कर्नल लक्ष्मबहादुर सिंह गुरुंग ने अपने प्राणों को हथेली पर लेकर भैरहवा पर आक्रमण किया। बड़े हाकिम मीरजंग राणा आत्मसमर्पण करना चाहते थे किन्तु गोपाल शमशेर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इससे मीरजंग राणा की हिम्मत बढ़ी और वह विद्रोही सेना से मुकाबिला करने पर उतारू हो गये। प्रथम दिन के संघर्ष में सरकारी सेना के दो सैनिक काम आए और तीन घायल हुए। विद्रोही सेना का एक सिपाही शहीद तथा अनेकों घायल हो गये। इसी दिन मोरंग जिले में जौतपुर नामक स्थान पर किसानों ने अपनी पंचायत खड़ी कर ली।

सिन्धुपाल और माझ किरात में शान्ति की झूठी खबरें बहुत देर न पहुँचती रहीं तथापि जनता कटिबद्ध होकर सरकार के विरुद्ध लड़ती रही। पौष दस गते को तप्लेजुङ आदि पर विद्रोहियों ने कब्जा किया। मोतीपुर में सरकारी सेना और क्रान्तिकारियों में घमासान लड़ाई हुई जिसमें इन्द्र बहादुर नेमबाङ, शमशेर राई, नाथ बहादुर, चक्र बहादुर, दल शेरराई, नर बहादुर राई, भक्त बहादुर राई, पदमवीर राई, रमन सिंह राई तथा विम वीर राई आदि शहीद हुए। धनीपुर के मोर्चे पर उत्तर कुमार श्रेष्ठ, शम्भु बहादुर राणा, भक्त बहादुर कार्की, धर्मराज श्रेष्ठ, रणवीर बहादुर तथा धर्मध्वज गुरुंग आदि शहीद हुए।

वीरगंज में मुक्ति सेना के गैर नेताओं की अदूरदर्शिता से गड़बड़ाने लगे और इसका पूर्वाभास तो १६ नवम्बर को परवानीपुर ही में मिल गया जबकि राणा सरकार की सेना ने मुक्ति सेना को पीछे हटा दिया।

१७ नवम्बर को एजेंसी पर कब्जा करके हरैया पर हमला हुआ। चार कुमार राम कमाण्डरों ने अपनी पल्टन सजाकर म्युजिहवा की मैच फैक्टरी को अपनी फौजी छावनी बनाकर भैरहवा पर तीन तरफ से धावा बोल दिया। उपर्युक्त स्थानों पर राणा सरकार के सैनिक लाए हुए नमक को अदा करते हुए बड़ी ही मुस्तैदी के साथ विद्रोही सेना का मुका-बिला कर रहे थे। जनसेना ने १८ नवम्बर को दक्षिण तथा पूर्व की ओर से भैरहवा पर पुनः आक्रमण किया। इसमें सरकारी सैनिक ही बुरी तरह हताहत हुए। विद्रोही किसानों ने इस दिन महारानी सीता की जन्मभूमि जनकपुर पर भी आक्रमण किया।

विद्रोहियों के कतिपय अवसरवादी नेता अपनी पूरी शक्ति शान्ति में न लगाकर सरकारी कोष अथवा सामग्रियों को लूटने में व्यस्त थे और राणा फौज के साथ सामना होने पर भोले-भाले किसानों को दुश्मनों की गोलियों के सामने झोंककर स्वयं पीछे हट जाते

थे। रौतहट की जनता ने गौर पर हमला किया किन्तु १८ नवम्बर को गौर में रति संन्यासी शिवप्रसाद सिंह तथा मन्नू साहू के साथ बीसों विद्रोही किसान शहीद हुए तथा सैकड़ों घायल हो गए। इसके पश्चात् बाबामौजा साथा और गौरी गंज पर चारों तरफ से हमला हुआ। नेपाली कांग्रेस के नेता वीरगंज के खजाने को पाकर अवांछित अपने मन की मुरादें पूरी करने में मस्त थे कि राणा सरकार के सैनिकों ने वीरगंज पर पुनः अधिकार जमा लिया। इस संघर्ष में तेज बहादुर, प्रेम बहादुर, पद्म जंग तथा द्वारिका प्रसाद आदि बीसों विद्रोही शहीद तथा सैकड़ों घायल हो गये। इनके अतिरिक्त लगभग सौ विद्रोही बन्दी बना लिये गए।

उदयपुर गढ़ी १८ तथा २२ नवम्बर के बीच विद्रोहियों के मातहत हो गया और भैरहवा के सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों की फौजी छावनी पर हमला किया किन्तु उनको ही अपने चार सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। क्रान्तिकारी तत्त्व विजयोल्लास में आगे बढ़ते किन्तु राणा सरकार के समानान्तर विद्रोही सरकार बनाने की हिम्मत बहुत ही कम नेताओं में हुई। सच बात तो यह थी कि वीरगंज के पतन के पश्चात् जनता का नेपाली कांग्रेस में विश्वास नहीं रह गया और वह अवसरवादियों से अपना पिण्ड छुड़ाकर विशुद्ध राष्ट्रवादी तत्त्वों की प्रतीक्षा करने लगी।

पश्चिमी नेपाल की जनता का उत्साह व्यापक हो गया था और कालों की जनता जनवादी सरकार स्थापित करने के लिए कटिबद्ध थी। पूर्वों की भारी सेना के साथ औरतों की भी एक पल्टन कौम्पति मिश्र तथा यमुना देवी के नेतृत्व में खड़ी हो चुकी थी। समय आ गया था कि पश्चिमी नेपाल के विद्रोही नेता एक विद्रोही सरकार की घोषणा करते। क्रान्ति को व्यापक और सफल बनाने के लिए भी एक ऐसी क्रान्तिकारी सरकार की अपेक्षा हुई। २१ नवम्बर, सन् १९५० ई० को विभिन्न जिलों के पाँच सौ प्रतिनिधियों ने बीसों हजार जनता की एक भारी सभा में डाक्टर के आई सिंह का पश्चिमी नेपाल का मिलिटरी गवर्नर सिवल का प्रधान मंत्री तथा कर्नल पद्म बहादुर सिंह मु ग को प्रधान सेनापति चुना। बाद में लोक बहादुर राणा एडजुटेन्ट जनरल होविर आले इन्चार्ज पूर्ति विभाग तथा हर्ष बहादुर मल्लिक इन कमाण्ड नियुक्त हुए।

क्रान्तिकारी सरकार का चुनाव शिब्बन लाल सक्सेना की उपस्थिति में उनके परामर्श से हुआ था।

चुनाव समाप्त होने के बाद जब शिब्बन लाल सक्सेना अपने साथियों के साथ लौटकर आ रहे थे उसी समय राणा फौज की गोलियाँ बरसने लगीं। सक्सेना के साथ उनके साथी मदन पाण्डेय रामानुज पाण्डेय नरसिंह कृपादयाल सिन्हा तथा नेपाली कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता कृष्णदास मल्ल भी थे। गोलियों की बौछारें उनकी मोटर पर होती रहीं और वे ट्रक की दीवाल से टकराकर रहती रहीं। राइफल की एक गोली ड्राइवर के पैर पर से पार करके सक्सेना के टिफिन को तोड़ती हुई बाहर

सहारे ही कुछ दिनों तक डटी रहेगी किन्तु हवाई अड्डे पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और बहुत से युवकों को बन्दी बनाने के बावजूद भी जनमत ने अपना

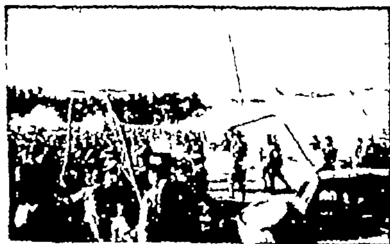


गौचर विमानस्थल पर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ

बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाया तब वह मुँह के बल गिर पड़ी।

एक दिसम्बर को परासी, बमौनी, तीन दिसम्बर को मगली और बर्दिया, चार दिसम्बर को भुम्सा, बोकसिया तथा मतिया पुलिस थानों पर विद्रोही किसानों ने अधिकार कर लिया। दिसम्बर को दार्जीलिंग के पास पशुपति नगर में घमासान लड़ाई हुई।

६ दिसम्बर को नरायणपुर और भगवानपुर, ७ दिसम्बर को महाराजपुर तथा परासी को जनता ने अपने अधिकार में कर लिया। झापा, अमारगढ़ी, बिरटा, तोलका, नकालबसा तथा घोलाधारी पर आठ दिसम्बर को एवं दिसम्बर के मध्य तक मालाखेत, धनगढ़ी, डडेलधुरा, बैतड़ी और डोटी भी जनता के अधिकार में हो गया। धनगढ़ी में बड़ा हाकिम महेन्द्र देव मारा गया। दूसरी टुकड़ी सुरखेत तथा देलख की ओर बढ़ गई। इन्हीं दिनों कोसी क्षेत्र में भी मुक्ति सेना तथा राणा फौज में संघर्ष होते रहे। तराई तथा पहाड़ में आन्दोलन की सफलता देखकर काठमाण्डू का विद्यार्थी समाज प्रबुद्ध हो गया और ११ दिसम्बर को त्रिचन्द्र कालेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की और सरकार के विरुद्ध विराट जुलूस निकालकर



प्रदर्शनकारियों पर लाठी-प्रहार

शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों को शान्त करने के लिए सरकारी सैनिकों ने निहत्थे छात्रों पर गोलियाँ चलाई जिससे चौदह छात्र घायल हुए।

६ दिसम्बर को भारतीय संसद ने भारत की वैदेशिक नीति पर बहस की। परराष्ट्र मंत्री की हैसियत से भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि नेपाल का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार के समय में केवल भारत ही तक सीमित था किन्तु अब भारत सरकार नेपाल को एक प्रगतिशील शक्तिशाली देश के रूप में देखना चाहता है। साथ भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि यद्यपि हम नेपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं यद्यपि भारत के साथ उसके सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ हैं। उनकी

मधेश पर नेपाल में जो क्रान्ति मची हुई है उसमें भारत को भी आशंका है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नेपाल में कोई संविधान ही नहीं है और जनता की भी कोई आवाज नहीं है।

२ दिसम्बर को भारत के प्रधान मंत्री ने नेपाल के सम्बन्ध में फिर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इस दिन आपने कहा कि भारत सरकार ने चार बातों के लिए नेपाल सरकार से अपील की थी और हम खुशी है कि महाराजा मोहन शमशेर ने उसका स्वागत किया है। भारत नेपाल में वैधानिक परिवर्तन, यथाशीघ्र आम चुनाव करा कर एक विधान परिषद की स्थापना, एक अन्तरिम सरकार जिसके प्रधान मंत्री राणा परिवार के ही हों तथा जिसमें और विभाग शाह का हो। नरेश आम जन के पक्ष में था और जिसे नेपाल सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है।



राजधानी में क्रान्ति के समय महिलाओं का प्रदर्शन

इस दरमियान में भी सभी मोर्चों पर लड़ाई होती रही और देश में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास होने लगे।

इनकलाब की आंधी पूर्वी पहाड़ों तक पहुँची। उसमें लिम्बुवान तथा माझ-किरात आदि का भी सहयोग था। राई लिम्बु और किरातों की स्त्रियों ने भी क्रान्ति में सक्रिय भाग लिया। पूर्व दो-तीन नम्बर के जिलों आदि में कतिपय महिलाओं के साथ उनके शिशु भी राणा फौज के शिकार हुए। जिनमें गर्भवती श्रीमती लाल बहादुर, काल बहादुर, बीर बहादुर तामांग, जगत बहादुर तामांग, धन बहादुर, रण बहादुर, लाल बहादुर, पूर्ण बहादुर, टीका राम राई, छाम बाद राई आदि सुप्रसिद्ध थे।

लिम्बुवान माझ-किरात के विद्यार्थियों का नेतृत्व राम प्रसाद राई आदि ने किया।

भोजपुर आदि कब्जा कर लेने के बाद विद्रोहियों की एक फौज विराटनगर की ओर बढ़ी। इसी क्रम पर मशाली कायम ने विराटनगर के सरकारी भवन आदि पर हमला बोल दिया।

धरानी आदि से आगे हुए राणा सैनिकों का विद्रोही सरकार ने गाड़ियों तक पर भर लिया। दोनों पक्षों में डटकर लड़ाई हुई। राणा सरकार के दर्जनों सैनिक काम आये और बीसों घायल हुए। इस मार से राणा फौज के दांत खट्टे हो गये और सरकारी भवन के चारों ओर गहरी खाइयाँ खोदकर वे अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। इसी बीच उनका राशन आदि भी चुक गया और वे खाकसार सिपाही को कष्ट मिले। मातृभूमि के सामन्तों ने सरकारी सैनिकों का पर्याप्त खाद्य आदि दिया और यही कारण था जो उनके संकट पर वे जिस किसी भी गाँव पर टूट पड़ते।



त्रिचन्द्र कालेज के सामने विद्यार्थियों का प्रदर्शन

कार्तिक दिसम्बर को ... नगर और बहादुरगंज पर कब्जा हुआ जहाँ विद्रोही सरदार को सत्तर-अस्सी हजार रुपये हाथ लगे। विराटनगर में लगातार कई दिनों तक भीषण संघर्ष होता रहा। सरकारी भवन के चारों ओर घेरा पड़ा रहा। संघर्ष में बड़ा हाकिम का एक साथी का शिकार हो गया। इसके अतिरिक्त राणा फौज को यह विश्वास हो गया था कि भोजपुर और धनकुटा से विद्रोहियों की बड़ी सेना विराटनगर आ रही है। इसी भय से सरकारी सैनिकों ने आत्म-समर्पण कर दिया। विराटनगर में मशाली कायम को काफी रकम और लड़ाई के सामान भी हाथ लगे। विराटनगर में डाक्टर कृष्णलाल झा के साथ दस विद्रोही शामिल हुए और भाग्य प्रसाद को राज्य का गवर्नर बनाये गये। इसके पश्चात् भी काफी दिन में महीना तक हंगामा मचता रहा और शासन सुव्यवस्थित न हो पाने से भी

काफी राष्ट्रीय क्षति हुई। ओखलढुंगा और बेनपुर पच्चीस दिसम्बर को जनता के मातहत हो गया। बहुदेवमच्छी सिलगढी बैतडी तथा कोषलावास में विद्रोहियों को सरकारी कोष तथा शस्त्रागार हाथ लगा। विद्रोही सेना का नतृत्व भीमदत्त पन्त ने किया जो डा के आई. सिंह से अपन सम्पर्क स्थापित करके लगभग सात महीने तक जन-सरकार चलाते रहे।

राजधानी के नागरिको तथा छात्रो न भयंकर जुलूस निकालकर राजबन्दियों की रिहाई की माँग की। सरकारी सैनिकों न उन पर गोलियाँ बरसाई और सैकड़ों प्रदर्शन कारी घायल हो गये।

चौबीस दिसम्बर को राजधानी के सत्तर कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया। इससे कर्मचारियों के वर्ग मे सनसनी फैल गई, किन्तु उसका उपशमन सरकार न अविलम्ब ही कर लिया।

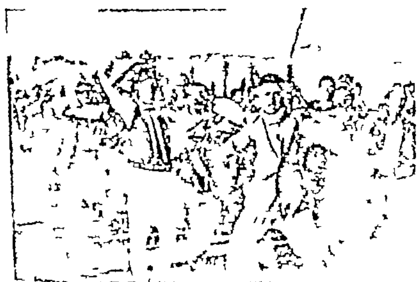
इक्कीस और अट्ठाईस दिसम्बर को विद्रोही किसानो ने महोत्तरी जिला में बीराही मच्छरिया बिरता तथा बैदेही थानों पर अपन झण्डे फहरा दिये। इस दिन कुथाघाट रानीगंज सर्लाही तथा दार्जीलिम के पास देवहुमुम पर धावा हुआ। पहली जनवरी को कुथाघाट पर घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सरकारी फौज का कप्तान घायल हुआ और जिसकी मृत्यु कहरिया सराय अस्पताल में हुई। इसके अतिरिक्त राणा सरकार के लगभग तिहत्तर सैनिक मारे गये और लेह जवान जन-सैनिकों द्वारा गिरफ्तार हुए। पिछली रिपोटों द्वारा मरे हुए सैनिकों की संख्या कुछ कम बतलाई गई।

जनवरी का प्रथम सप्ताह भैरहवा मोर्चे के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रहा। राणा फौज के छक्के विद्रोही सना मे लड़ते-लड़ते छूट गये थे और वह गाय बैलों के मुण्ड आगे करके जनसेना को धर्मसंकट में डालने लगे। इसी प्रकार मुहम्मद गोरी आदि मुगल आक्रमणकारियों न भारतीय सेना को धर्मसंकट में डालकर विजय प्राप्त की थी। इस प्रयास में भी राणा फौज को मुह की खानी पड़ी। दोनों ओर स प्रतिरोध और प्रत्याक्रमण हुए। राणा सरकार के सात सैनिक मौत के घाट उतरे और तीन-चार चौपाए भी गोली के शिकार हुए। इसी प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जितने विद्रोही सैनिक घायल हुए थ उनकी मरहम पट्टी और माकूल इलाज तुरन्त की जाती थी और जिन घायलों की हालत बहुत खराब रहती उनको भारतस्थित अस्पताला म भज दिया जाता रहा। इसके विपरीत राणा सरकार अपने घायलो की तीमारदारी करन के बजाय कभी-कभी जहर अथवा गोली देकर अपनी परे शानी दूर करती रही। राणा सरकार की ओर से जो सैनिक लड़ते थ वे लोग मन मथवा मूर्खतावश। यही कारण था जो प्राणो को संकट में देखकर ऐसे सैनिक विद्रोही सना में सम्मिलित हो जाया करते थ। भैरहवा की लड़ाई में तराई के किसानों के साथ बल बहादुर, तेज बहादुर गुरुंग भीम बहादुर गुरुंग दुर्गा सिंह गुरुंग मन बहादुर गुरुंग मानीलाल गुरुंग रणवीर गुरुंग तथा तोप बहादुर थापा भी शहीद हुए।

तीन जनवरी तक प्यूठान सल्यान दाम-देउखुरी बतडी मनिहारी भगकुटा

महीनाथपुर तथा धनुषा जनता के अधिकार में आ गया। कहा जाता है कि धनुषा में ही मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी ने शिव-धनुष तोड़ा था। यहां विद्रोहियों को बीसों राइफलें मिलीं और राम सिंह तथा नर श्याम तामाङ आदि शहीद हुए।

नेपाल के इतिहास में पाल्पा का स्थान बहुत रोचक रहा है और वह अपनी शानदार परम्परा को अब तक कायम किये हुए है। शासन प्रमत्त राणाओं ने भूतपूर्व कमाण्डर-इन-चीफ रुद्र शमशेर को तानसेन में नजरबन्द करके जनसम्पर्क से वंचित कर दिया था। सशस्त्र क्रान्ति ने पाल्पा [illegible] तथा [illegible] में हलचल मचा दी और पांच जनवरी को पन्द्रह सौ सरकारी सैनिकों ने तानसेन में राज्य क्रान्ति कर दी। सभी राजबन्दी रिहा हुए और सात व्यक्तियों की पंचायती सरकार बनी। इसी सप्ताह पाल्पा ने [illegible] प्रारम्भ किया और बड़ा हाकिम रुद्र शमशेर को आत्मसमर्पण कर देना पड़ा।



काठमाण्डू में युवकों का प्रदर्शन

प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर ने आठ जनवरी को सुधारों की एक घोषणा जारी की। इसका स्वागत नेपाली कांग्रेस तथा भारत सरकार ने भी किया। नेपाली नेताओं ने इस घोषणा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करके असन्तोष ही प्रकट किये और लड़ाई जारी रही। इसकी अभिव्यक्ति वीरगंज में बीसों हजार विद्यार्थियों ने सत्याग्रह के रूप में की। नेपाल की लड़ाई में ऐसा सत्याग्रह कभी नहीं हुआ था और निहत्थी जनता जिस शान के साथ डटी रही वह अविस्मरणीय थी किन्तु राणा फौज ने सत्याग्रहियों पर लाठियों और बंदूकों के कुन्दे बरसाकर बुरी तरह दमन किया। इन्हीं दिनों [illegible] और [illegible] की भी

चलता रहा किन्तु खून-खराबा बिल्कुल ही नहीं हुआ और उसके बरसात भी पूरे हो गये।

महाराज मोहन शमशेर ने अपने पुत्र विजय शमशेर को संधि-वार्ता के लिए दिल्ली भेजा। दूसरी ओर उन्होंने पन्द्रह जनवरी को लंदन में होने वाले कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भी नेपाल का मामला पेश कराने का प्रयास किया। कश्मीर के प्रश्न का संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर भारत सरकार को बहुत बड़ा सबक मिल चुका था इसलिए उसने भी बड़ी होशियारी से काम लिया। इसका इशारा तो भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उसी वक्तव्य में कर दिया जिसमें उन्होंने यह साफ शब्दों में कह दिया कि नेपाल का मामला हमारा है। इस घोषणा ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के कान खड़े कर दिये और प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर ने हथियार रखने तथा राजबन्दियों को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भी कतिपय मोर्चों पर पूर्ववत् लड़ाई जारी रही।

ग्यारह-बारह जनवरी को भैरहवा में फिर सत्याग्रह हुआ। राणा सैनिकों ने दो सौ पुरुषों तथा पचास स्त्रियों को घायल किया। इन दो दिनों में राजधानी की काल-कोठरी से एक सौ छप्पन राजबन्दी मुक्त हुए। सोलह जनवरी को फिर एक सौ छप्पन राजबन्दी मुक्त हुए और रामपुरमण्डी तथा धुमरिया पर राष्ट्रीय सेना का आधिपत्य हुआ।

नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला ने सत्रह जनवरी को मनमानी ढंग से लड़ाई बन्द करने की घोषणा की। यह घोषणा मुक्ति-संग्राम के सच्चे सेनानियों से बिना परामर्श किये ही अवैधानिक ढंग से की गई। इसी समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए बाईस तथा तेईस जनवरी को विद्रोही प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में विशेष बैठक की और जिसमें लड़ाई जारी ही रखने का निर्णय किया गया।

मुक्ति सेना तथा राणा फौज में अनुशासन का अभाव था। फलस्वरूप घोषणा के विपरीत जनकपुर तथा सुनार आदि में संघर्ष हुए। जनकपुर में आठ राणा सैनिक गोली के शिकार और बीसों घायल हुए। भैरहवा के पास मजिमाता में भी मुठभेड़ हुई। राणा फौज का एक सैनिक मारा गया और कुछ बन्दी बनाकर समानान्तर सरकार की जेल में डाल दिये गये। जनवरी के अंतिम सप्ताह में ईलाम दाम बरिया तथा नेपालगंज में गोलियां चलीं। नेपालगंज में घमासान लड़ाई होने की संभावना थी किन्तु बड़ा हाकिम ध्रुव शमशेर ने आत्मसमर्पण करके अपने सैनिकों को बचा लिया। कहा जाता है कि नेपालगंज के सरकारी कोष से साढ़े तीन लाख रुपये थे जो उसी समय लापता हो गये। फरवरी के प्रथम सप्ताह में राजधानी से पर्याप्त सैनिक भैरहवा भेजे गये और विद्रोही सेना को स्यूडिहवा से हट जाना पड़ा। इसके पश्चात् कुंवर इन्द्र सिंह ने पर्वत में अपनी फौजी छावनी बनाई। पश्चिमी नेपाल की क्रान्तिकारी सरकार शक्तिशाली हो गई थी। और उसने मीर बन्दारा का मारा दिया। मारकाट लूट आदि की जांच करने के लिए जांच कमीशन तथा तत्सम्बन्धी झगड़ों को निबटाने के लिए मोबाइल कोर्ट खड़े किये गये। विद्रोही सरकार के इस प्रशंसि-

लीन कायरतापूर्ण ढंग से सामन्तों के कान खड़े कर दिये और वे अपनी धन सम्पत्ति भारत भेजकर अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने लगे। इसमें क्रान्ति-काल में सामन्तों ने जो रवैया अख्तियार किया वह बहुत ही दुविधापूर्ण रहा।

एक ओर तो वे राणा फौज से अपना सम्बन्ध स्थापित करके प्रतिक्रियावादी का कर्तव्य पालन करते और दूसरी ओर अपनी कोठियों पर नेपाली कांग्रेस के झण्डे फहराकर अवसर लेने का भी अभिनय करते थे। सामन्तों की इस कूटनीति का भंडाफोड़ तो उस समय पूर्ण तरह से हो गया जब कि सामन्तों के नेता सुवर्णश्वर प्रसाद शुक्ल तथा सरस्वती लाल ने विद्रोही सरकार से नाता जोड़ लिया। सुवर्णश्वर प्रसाद शुक्ल एक बहादुर बदनाम जमींदार थे और जिन्होंने अपनी काठी जिविता में सुदृढ़ किलाबन्दी कर रखी थी। फलस्वरूप ग्यारह फरवरी को जिविता में खूब घमासान लड़ाई हुई जिसमें जन सरकार से लड़ने वाले सुवर्णश्वर प्रसाद शुक्ल और सरस्वती लाल के साथ सामन्तों के पचासों सैनिक काम आये और विद्रोहियों को काफी बन्दूकें आदि प्राप्त हुईं।

पश्चिमी नेपाल की विद्रोही सरकार सत्याग्रही समझौते के खिलाफ थी और वह इतनी जनप्रिय हो चुकी थी कि राणा सरकार से समझौता करने वाला कांग्रेस गुट घबरा गया। उधर भारत सरकार के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने समस्त जिविता नागर की पिपासा पर ध्यान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शान्ति का नेतृत्व अब नेपाली कांग्रेस के हाथ से निकल गया है और पश्चिमी नेपाल की क्रान्तिकारी सरकार समझौता शान्ति का विरोधी है।

१५ फरवरी सन् १९५१ ई० को महाराजाधिराज त्रिभुवन और विक्रम शाह नरसिंहार नेपाल की राजधानी पहुंचे और दूसरी ओर महाराज मोहन शमशेर से समझौता करने वाले कांग्रेस गुट ने डाक्टर के० आई० सिंह को डाकू और लुटेरा घोषित कर दिया। १८ फरवरी सन् १९५१ ई० को नेपाल नरेश ने अन्तरिम सरकार के मंत्रिमण्डल की घोषणा की। अन्तरिम सरकार ने डाक्टर के० आई० सिंह को पकड़ने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी। फलस्वरूप भैरहवा में संयुक्त सैनिक कार्रवाई हुई और डाक्टर के० आई० सिंह अपने सभी सैनिकों के साथ गिरफ्तार करके भैरहवा जेल में बन्दी बना लिए गए। इसके प्रतिक्रियास्वरूप सशस्त्र क्रान्ति बन्द हो गई और सारे नेपाल में शान्ति स्थापित हो गई। नेपाल की क्रान्ति में लगभग पांच सौ व्यक्ति शहीद हुए जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल से राणाशाही की समाप्ति होकर एक प्रजातन्त्र का मार्ग प्रशस्त हुआ।

१८

प्रजातन्त्र की ओर

सदियों से प्रताड़ित नेपाल की एक करोड़ जनता ने सहसा भयंकर अंगड़ाई ली और श्री पाँच सरकार की जयकार मनाकर राणाशाही के समर्थकों के खून की होली खेलने लगी। विद्रोही जनता ने राणा सरकार को बाध्य करके इस दयनीय परिस्थिति में ला दिया कि वह दिल्ली में भारत सरकार को मध्यस्थ मानकर विद्रोहियों से समझौता करने के लिए विवश हो गई और ८ जनवरी को महाराज मोहन शमशेर को एक शासन-सुधार की घोषणा करनी पड़ी। महाराज मोहन शमशेर ने नेपाल की जनता को सम्बोधित करते हुए काठमाण्डू से अपने वक्तव्य में कहा कि एक सौ चार वर्ष पहले महाराजा जंग बहादुर ने महाराजाधिराज तथा नेपाल की जनता द्वारा सौंपे जाने पर शासन का पूरा भार उठाया। उस समय की ऐतिहासिक घटनायें लिपिबद्ध हैं जब कि नेपाल में अव्यवस्था अशान्ति तथा कुशासन से नेपाल में अराजकता फैली हुई थी और महाराजा जंग बहादुर ने दृढ़तापूर्वक नेपाल में शान्ति तथा स्थिरता ला दी थी।

विगत शताब्दी में जो सफलताएं मिली हैं उनका उल्लेख यद्यपि इसमें नहीं किया गया है लेकिन तब भी यह तो निर्विवाद रूप से कहा ही जा सकता है कि महाराजा जंग बहादुर तथा उनके उत्तराधिकारियों ने न केवल नेपाल की अमूल्य स्वाधीनता की स्थापना और जनता की सुरक्षा ही की है अपितु नेपाल में प्रगति तथा स्थिर सरकार भी रखी है जो किसी राष्ट्र की समृद्धि तथा भलाई के लिए अपेक्षित है।

प्रधान मंत्री मोहन शमशेर ने अपनी घोषणा में कहा कि समय की गति के बदलने के साथ यह अभिलाषा रही है कि नेपाल की जनता शासन जैसे महत्तर कार्यों में भी लगे। इसीलिए संवत् २ ४ का नेपाल सरकार का ऐक्ट १४ अप्रैल सन् १९४८ ई०—वैशाख एक संवत् २ ०५—को लागू कर दिया गया। इसी दिन इस धारा का प्रथम अनुच्छेद घोषित कर दिया और देश के भिन्न-भिन्न भागों के दो सौ गाँवों में ग्राम तथा जिला पंचायतें स्थापित कर दी गईं। केन्द्रीय विधानमण्डल का संगठन यद्यपि अभी पूर्ण नहीं हो पाया था किन्तु पार्लियामेन्ट (संसद्) का उद्घाटन तो २२ सितम्बर, सन् १९५ ई० को हो गया था और संसद् की प्रथम बैठक ही में अनेकों प्रस्ताव पास किये गये थे।

अब कठिन प्रारम्भिक काल समाप्त हो रहा है और नेपाल की जनता प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर स्वतन्त्र प्रजातन्त्र की ओर बढ़ रही है। आज तक जो भी सुधार अपनाये गये उनकी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सूक्ष्म व्याख्या करने पर यही निष्कर्ष निकलता

है कि मेरी सरकार और मेरा स्वयं जनता से निकट सम्पर्क स्थापित हो। हम सन्तुष्ट हैं कि देश की स्थिरता और शान्ति भंग किये बिना ही नेपाल में तीव्र प्रगति लाई जा सकती है। इसी दृष्टिकोण से जनता की देशभक्ति तथा वफादारी में विश्वास रखते हुए हम सबों ने यह निश्चय किया कि उसे प्रथम ध्येय तक पहुँचने के लिए कुछ निश्चित सुविधायें लागू करनी चाहियें। सुविधायें इस प्रकार हैं—

१ एक विधान परिषद् की स्थापना प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर यथासम्भव शीघ्र ही की जाय। इस कार्य के लिए समस्त देश की जन-गणना की जा रही है और मतदाताओं की सूचियाँ शीघ्रातिशीघ्र ही बननी आरम्भ हो जायेंगी। यद्यपि यह कार्य नवीन तथा कठिन है इसलिए यह आशा की जाती है कि विधान परिषद् की प्रथम बैठक सन् १९५२ ई० तक हो सकेगी। इसका प्रमुख कार्य नेपाल के लिए एक विधान प्रस्तुत करना होगा।

२ इस विधान परिषद् की स्थापना में देरी न हो इसलिए यह अभिप्राय है कि केन्द्र में एक मंत्रिमण्डल का निर्माण किया जायगा। इसमें चौदह मंत्री रहेंगे और जिनमें सात प्रतिनिधि जनता की विचारधारा के रहेंगे जिनमें उनका पूर्ण विश्वास रहेगा। सरकार की अधिशासी शक्ति मंत्रिमण्डल में रहेगी और वह सम्मिलित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करेंगे। वह अपने काम करने के लिए नियम भी बनायेंगे। मंत्रिमण्डल का नियन्त्रण राजस्व पर रहेगा उसके साथ ही साथ बजट की पद्धति भी प्रचलित होगी। मंत्रिमण्डल प्रशासकीय सेवाओं में सामान्य योग्यता लाने के लिए समस्त विभागों की काया पलट भी कर सकेगा।

३ (क) जब तक विधान परिषद् द्वारा निर्मित नया विधान लागू नहीं हो जाता तब तक संवत् २००४ के धारा का प्रावधान उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि मंत्रिमण्डल द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किया जाय। इसलिए संवत् २००४ धारा के न्याय सम्बन्धी अनुच्छेद के अनुसार एक एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) एक आडिटर जनरल (महालेखा परीक्षक) पब्लिक सर्विस कमीशन (लोक-सेवा-आयोग) तथा देश की भलाई के लिए आवश्यक अन्य बातें शीघ्रातिशीघ्र ही नियुक्त होंगी।

(ख) लगभग दो सौ ग्राम तथा जिला पंचायतें अब तक स्थापित की जा चुकी हैं। अवशेष ग्राम की पंचायतों को सन् १९५२ ई० के पहले ही स्थापित करने का विशेष प्रबन्ध किया जायगा।

४ (क) सरकार की उत्कट अभिलाषा है कि भूमिकर तथा भूमि सम्बन्धी सुधार की व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए एक कमेटी से जिस पर राज्य जल्द ही विचार करेगा दिशा में विशेष ध्यान तथा सहायता करने के पश्चात् ग्राम रिहाई कर दी जायगी। बिर्ता, गुठी तथा अन्य जमीन वाले जागीरदारों पर यह नहीं लागू होगा। यह ग्राम रिहाई उन सब कैदियों का उचित दण्ड उन पाने राजनीतिक बन्दियों के लिए भी है।

(ख) नेपाल में नेपाली नागरिकों द्वारा नियमानुसार राजनीतिक संस्था खड़ी करने का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

(ग) नेपाली नागरिकों की सभी राजनीतिक संस्थायें जो वर्तमान काल में बाहर कार्य-सम्पादन कर रही हैं और ऐसी ही नेपाली प्रजा जो हिंसा से विमुख होकर अहिंसा की समर्थक है और यदि वह भलाई तथा अच्छी सरकार की अभिलाषी है तो उसका मातृभूमि में स्वागत किया जायगा।

५ जिस परिस्थिति में श्री पांच ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपाल के राज्य-सिंहासन पर बैठाये गये वह सर्वविदित है। नेपाल के किसी भी पड़ोसी देश ने जो उससे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं नए श्री पांच सरकार को मान्यता नहीं दी और इसी नाते जनता में भ्रम तथा अशान्ति फैल गई। इसी प्रसंग के फलस्वरूप दुष्ट प्रकृति के लोगों ने श्री पांच सरकार का नाम लेकर अशान्ति लूट-फूट स्त्रियों का अपमान निरपराध व्यक्तियों की हत्या की है। इसी नाते वाद-विवाद के समय भारत सरकार के मैत्रीपूर्ण सुझाव के अनुसार श्री पांच त्रिभुवन नेपाल के महाराजाधिराज बने रहेंगे। श्री पांच सरकार अपनी अनुपस्थिति-काल में नेपाल सरकार से परामर्श लेकर अपना एक संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। ७ जनवरी सन् १९५१ ई० को इस पर विचार करने के लिए संसद् तथा भारदारी की विशेष बैठकें बुलाई गईं। उन्होंने यह स्वीकृति दी कि इस परिस्थिति में नेपाल में शान्ति तथा स्थिरता स्थापित रखने के लिए श्री पांच त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव अपनी अनुपस्थिति में नेपाल सरकार की सम्मति लेकर अपना एक संरक्षक नियुक्त कर दें। अब मुझे यह घोषित करना है कि संसद् तथा भारदारी के विचार तथा निर्णय को नेपाल सरकार गंभीर समझती है और इसको पुष्ट भी करती है। मैं इन विचार लिये हुए अपने और सभी भाइयों के लिए यह महसूस करता हूं कि इस अवसर पर उनको एक विशेष संदेश दूं। देश के इस संकट तथा संघर्ष काल में आप लोगों ने धीरता एवं देश-भक्ति की परम्परागत प्रतिष्ठा कायम रखी है। आप लोगों ने सरकार का साथ निश्छल विश्वास के साथ दिया है और आप लोगों ने अपने कार्यों तथा कर्तव्यों का पालन बड़ी ही वफादारी तथा उद्यम के साथ किया है। मेरे प्यारे भाइयो! मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की भलाई तथा मान हम लोगों के हृदय में जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। देश के प्रशासन के परिवर्तन के पश्चात् भी हम लोग आप लोगों से अनुग्रहीत तथा अविचल उसी प्रकार रहेंगे जिस प्रकार आप लोग अपनी सरकार तथा देश के प्रति रहे हैं।

मैं अपनी सरकार तथा अपनी ओर से सभी सरकारी अफसरों की प्रशंसा तथा हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संकट-काल में अत्यन्त वफादारी और तत्परता से हमारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पालन किया है। यह मेरी आशा है कि शुद्ध देश-भक्ति की भावना से जो व्यापक सुधार चालित किये जा रहे हैं नेपाल की जनता उनका स्वागत करेगी। इसके लिए वह सरकार को हृदय से पूर्ण सहयोग करेंगे जिससे कि प्यारी

मातृभूमि के उज्ज्वल भविष्य के लिए शान्ति, उन्नति तथा सम्मान प्राप्त हो सकें। हमें विश्वास है कि शासन के इस स्थानान्तरण के बाद नेपाल का प्रत्येक नागरिक शान्ति काल की उज्ज्वलता में प्रवेश करेगा।

यह स्मरण रखिए कि समस्त संसार की आँखें इस पर लगी हुई हैं। हमें संसार को यह दिखला देना है कि नेपाल का भावी उत्तरदायित्व नेपालियों के ही द्वारा सम्भाला जा सकता है। वस्तुतः हम लोगों का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि हम अपने प्यारे देश का नाम गौरवान्वित करें। नेपाल के लोगों ने स्वाधीनता तथा न्याय के लिए अनेक समर क्षेत्रों में जो अक्षय कीर्ति प्राप्त की है और जिन्होंने पूर्ण शक्ति के अनुसार अपना रक्त बहाकर साहस तथा पारस्परिक सद्भाव से अपनी मातृभूमि की रक्षा की है वे सब बधाई के पात्र हैं।

मैं इस भूमि तथा जनता के श्री पशुपतिनाथ तथा श्री गुह्येश्वरी देवी के आशीर्वाद चाहता हूँ जिससे कि हम अपने अपने उच्च आदर्शों तथा राष्ट्र के सुख तथा समृद्धि के लिए जो मैंने सुधारों की घोषणा की है उसको प्राप्त कर सकें। इस कठिन समय में प्रत्येक सच्चे नेपाली को अपने सब भिन्न भिन्न अपने देश की शान्ति, पवित्रता तथा स्वाधीनता पर लगा देने में सहमत हों।

प्रधान मंत्री मोहन शमशेर की शासन-सुधार की योजना के सम्बन्ध में नेपाल के विभिन्न नेताओं ने अपने अपने निम्न प्रकार के वक्तव्य दिये—

पश्चिमी नेपाल की विरोधी सरकार के प्रधान मंत्री श्री डिल्लीरमण ने ९ जनवरी सन् १९५१ ई० को इन पंक्तियों के लेखक से नई दिल्ली में महाराज मोहन शमशेर की सुधार सम्बन्धी घोषणा की आलोचना करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि यह घोषणा स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले स्वयंसेवकों तथा सैनिकों को संतुष्ट नहीं करती। यह ठीक है कि सन् १९४७ ई० के पहले नेपाल में एक विधान परिषद् की स्थापना हो चुकी थी किन्तु जब काश्मीर की सरकार आपस में लड़ाई होते हुए भी विधान परिषद् के लिए चुनाव कर सकती है तो क्या कारण है कि नेपाल में भी इसी तरह विधान परिषद् का चुनाव नहीं हो सकता? प्रधान मंत्री मोहन शमशेर ने अपनी घोषणा में सम्मिलित सरकार की जो रूपरेखा बताई है वह आपत्तिजनक है। प्रस्तावित सम्मिलित सरकार के चौदह मंत्रियों में आधे-आधे दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की संख्या तथा महाराज मोहन शमशेर का ही प्रधान मंत्री बना रहना प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती। घोषणा में यह भी तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंत्रियों का चुनाव कौन करेगा और उनके विभागों का बँटवारा भी कौन करेगा। यह योजना असन्तोषकारी है। वर्तमान ऐसी परिस्थिति में यही उचित है कि नेपाल की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले सभी व्यक्तियों का चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के हों एक सम्मेलन बुलाया जाय और उसमें यह घोषणा विचार-विमर्श के लिए रखी जाय और तब उस सम्मेलन द्वारा पास कराकर कोई अन्तिम निर्णय किया जाय। इसके पश्चात् ही लड़ाई बन्द करने का प्रश्न उठ सकता है।

(घ) नेपाल में नेपाली नागरिकों द्वारा नियमानुसार राजनीतिक संस्था खड़ी करने का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

(ङ) नेपाली नागरिकों की सभी राजनीतिक संस्थायें जो वर्तमान काल में बाहर कार्य-सम्पादन कर रही हैं और ऐसी ही नेपाली प्रजा जो हिंसा से विमुख होकर अहिंसा की समर्थक है और यदि वह भलाई तथा अच्छी सरकार की अभिलाषी है तो उनका मातृभूमि में स्वागत किया जायगा।

५ जिस परिस्थिति में श्री पांच ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपाल के राज्य-सिंहासन पर बैठाये गये वे सर्वविदित हैं। नेपाल के किसी भी पड़ोसी देश ने या उससे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं उन्होंने भी पांच सरकार की मान्यता नहीं दी और इसी नाते जनता में भ्रम तथा अशान्ति फैल गई। इसी प्रसंग के फलस्वरूप दुष्ट प्रकृति के लोगों ने श्री पांच सरकार का नाम लेकर अशान्ति लूट-खसूट स्त्रियों का अपमान निरपराध व्यक्तियों की हत्या की है। इसी नाते वाद-विवाद के समय भारत सरकार के मैत्रीपूर्ण सुझाव के अनुसार श्री पांच त्रिभुवन नेपाल के महाराजाधिराज बने रहेंगे। श्री पांच सरकार अपनी अनुपस्थिति-काल में नेपाल सरकार से परामर्श लेकर अपना एक संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। ७ जनवरी सन् १९५१ ई० को इस पर विचार करने के लिए संसद् तथा भारदारी की विशेष बैठक बुलाई गई। उन्होंने यह स्वीकृति दी कि इस परिस्थिति में नेपाल में शान्ति तथा स्थिरता स्थापित रखने के लिए श्री पांच त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव अपनी अनुपस्थिति में नेपाल सरकार की सम्मति लेकर अपना एक संरक्षक नियुक्त कर दें। अब मुझे यह घोषित करना है कि संसद् तथा भारदारी के विचार तथा निर्णय को नेपाल सरकार गम्भीर समझती है और इसको दृढ़ भी करती है। मैं हथियार लिये हुए अपने वीर सभी भाइयों के लिए यह महसूस करता हूं कि इस अवसर पर उनको एक विशेष सन्देश दूं। देश के इस संकट तथा संघर्ष काल में आप लोगों ने वीरता एवं देश-भक्ति की परम्परागत प्रतिष्ठा कायम रखी है। आप लोगों ने सरकार का साथ निश्चय विश्वास के साथ दिया है और आप लोगों ने अपने कार्यों तथा कर्तव्यों का पालन बड़ी ही वफादारी तथा संयम के साथ किया है। मेरे प्यारे भाइयो! मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की भलाई तथा मान हम लोगों के हृदय में जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। देश के शासन के परिवर्तन के पश्चात् भी हम आप आप लोगों से अनुगृहीत तथा अविचल इसी प्रकार रहेंगे जिस प्रकार आप लोग अपनी सरकार तथा देश के प्रति रहे हैं।

मैं अपनी सरकार तथा अपनी ओर से सभी सरकारी अफसरों को प्रसन्नता तथा हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संकट-काल में अत्यन्त वफादारी और तत्परता से हमारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पालन किया है। यह मेरी आशा है कि शुद्ध देश-भक्ति की भावना से या व्यवहार सुधार घोषित किये जा रहे हैं नेपाल की जनता उनका स्वागत करेगी। इसके लिए वह सरकार का हृदय से पूर्ण सहयोग करेंगे जिससे कि प्यारी

मातृभूमि के उच्च अभिप्राय शान्ति उन्नति तथा सम्मान प्राप्त हो सकें। हमें विश्वास है कि शासन के इस स्वतन्त्रीकरण के बड़े कदम का प्रत्येक नेपाली नागरिक बहुत ही उत्साह से प्रशंसा करेगा।

यह स्मरण रखिये कि समस्त संसार की आँखें हम पर लगी हुई हैं। हमें संसार को यह दिखला देना है कि नेपाल का भावी उज्ज्वल भविष्य नेपालियों के ही द्वारा बनाया जा सकेगा। वस्तुतः हम लोगों का यह पवित्र कर्तव्य है कि हम लोग अपने देश का नाम गौरवान्वित करें। नेपाल के लोगों ने स्वाधीनता तथा न्याय के लिए अनेक समर क्षेत्रों में जो अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त की है और जिन्होंने पूर्ण शक्ति के अनुसार अत्यन्त दृढ़ता साहस तथा पारस्परिक सहयोग से अपनी मातृभूमि की रक्षा की है वे सब बधाई के पात्र हैं।

मैं इस भूमि तथा जनता के श्री पशुपतिनाथ तथा श्री गुह्येश्वरी देवी के आशीर्वाद चाहता हूं जिससे कि हम लोग अपने उच्च आदर्शों तथा राष्ट्र के सुख तथा समृद्धि के लिए जो मैंने सुधारों की घोषणा की है उसको प्राप्त कर सकें। इस कठिन समय में प्रत्येक सच्चे नेपाली को अपने देश जिसे अपने देश की शान्ति पवित्रता तथा स्वाधीनता पर गर्व है वे सफल हों।

प्रधान मंत्री मोहन शमशेर की शासन-सुधार की घोषणा के सम्बन्ध में नेपाल के विभिन्न नेताओं ने अपने अपने निम्न प्रकार के वक्तव्य दिये—

पश्चिमी नेपाल की विद्रोही सरकार के प्रधान मंत्री की हैसियत से ९ जनवरी सन् १९५१ ई० को इन पंक्तियों के लेखक ने नई दिल्ली से महाराज मोहन शमशेर की सुधार सम्बन्धी घोषणा की आलोचना करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि यह घोषणा स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले स्वयंसेवकों तथा सैनिकों को संतुष्ट नहीं करती। यह ठीक है कि सन् १९५२ ई० के पहले नेपाल में एक विधान परिषद् की स्थापना हो जाय, किन्तु जब काश्मीर की सरकार अगले सितम्बर तक ही विधान परिषद् के लिए चुनाव कर सकती है तो क्या कारण है कि नेपाल में भी इसी वर्ष विधान परिषद् का चुनाव नहीं हो सकता? प्रधान मंत्री मोहन शमशेर ने अपनी घोषणा में अन्तरिम सरकार की जो रूपरेखा बताई है वह आपत्तिजनक है। प्रस्तावित अन्तरिम सरकार के चौदह मंत्रियों में साथ-साथ राणों तथा के प्रतिनिधियों की संख्या तथा महाराज मोहन शमशेर को ही प्रधान मंत्री बना रहना जनतान्त्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती। घोषणा में यह भी तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंत्रियो का चुनाव कौन करेगा और उनके विभागों का बँटवारा भी कौन करेगा। यह घोषणा असंतोषकारी है। अतएव ऐसी परिस्थिति में यही उचित है कि नेपाल की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले सभी व्यक्तियों का चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल के हों एक सम्मेलन बुलाया जाय और उसमें यह घोषणा विचार-विमर्श के लिए रक्खी जाय और तब उसी सम्मेलन द्वारा पास कराकर कोई अन्तिम निश्चय किया जाय। इसके पश्चात् ही लड़ाई बन्द करने का प्रश्न उठ सकता है।

इसके अतिरिक्त भावी अन्तरिम व्यवस्था के बारे में एक घोषणा भी पाँच सरकार द्वारा होनी चाहिए न कि प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर द्वारा ।

इसी दिन दिल्ली रमण रेग्मी ने भी कलकत्ता से मोहन शमशेर को सुधार सम्बन्धी घोषणा की आलोचना करते हुए वक्तव्य दिया कि नेपाल के प्रधान मंत्री की घोषणा द्वारा भी पाँच सरकार को सम्प्राट् नाम लेना विधान परिषद् बनाने के लिए सन् १९५२ ई० के पहले तक तिथि निश्चित करना तथा समस्त राजनीतिक बन्दियों को मुक्त कर देना ये तीन शर्तें तो पूरी हो जाती हैं परन्तु दो माँगें तो अभी पूरी ही नहीं की गईं। प्रथम तो यह कि जनता को नागरिक अधिकार मिले और द्वितीय जनता के प्रतिनिधियों को महत्त्वशाली विभाग भी मिले ।

१० जनवरी सन् १९५१ ई० को नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला ने पटना से एक वक्तव्य दिया कि प्रधान मंत्री मोहन शमशेर की तथाकथित घोषणा की प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेस शब्दों में केवल एक शब्द 'भ्रामक' द्वारा व्यक्त की जा सकती है। कोइराला ने कहा कि नेपाली कांग्रेस के झण्डे और उसके नेतृत्व के नीचे जो वर्तमान संघर्ष चल रहा है उसका लक्ष्य केवल सामन्तवादी शासन को उखाड़ फेंककर नेपाल में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित करना है। मोहन शमशेर की घोषणा में सब से मुख्य बात प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर विधान परिषद् खड़ी करने की है लेकिन यह स्मरण रखने की बात है कि विधान परिषद् उसी सरकार द्वारा खड़ी की जा सकती है जिसमें जनता का पूर्ण विश्वास हो। और यह स्वतन्त्र वायुमण्डल में ही संभव है। इस तथाकथित घोषणा द्वारा विधान परिषद् का निर्माण इस प्रकार कठिनाई ही से संभव हो सकेगा। कोई अन्तरिम व्यवस्था नेपाल सरकार को तब तक नहीं मान्य होगी जब तक वास्तविक रूप से शासन का भार जनता को न सौंप दिया जाय। यह तथाकथित घोषणा जनता को इस प्रकार शासन का भार देने का आशय ही नहीं प्रकट करती ।

११ जनवरी सन् १९५१ ई० को पश्चिमी नेपाल की विद्रोही सरकार के गवर्नर डाक्टर कुँवर इन्द्र सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं भी पाँच सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुनय करता हूँ कि जब तक नेपाल में पूर्ण प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापित नहीं हो जाती तब तक वह राणाओं द्वारा फैलाये हुए जाल में फँसकर नेपाल न जायें। मैं यह अनुभव करता हूँ कि जब सामन्तवादी राणाओं ने देखा कि अब अपनी तानाशाही की रक्षा करने का दूसरा मार्ग नहीं रह गया तो उन्होंने यही उचित समझा कि एक तथाकथित प्रजातान्त्रिक सरकार नेपाली कायम के तथाकथित प्रतिक्रियावादी राणाओं के बहुमत से स्थापित कर दी जाय। वे अब भी अपनी शक्ति का ही जोर राज्य-शासन पर बनाकर नेपाली जनता का बदला लेना चाहते हैं। मैं राणाओं का सावधान कर देना हूँ कि नेपाल की भोली तथा निर्धन जनता को बेवकूफ बनाने की उनकी यह चाल बेकार सिद्ध होगी में नेपाली जनता तथा नेपाल के बाहर भारतीय के मित्रों से अपील करता हूँ कि व म

इन कार्यों की सहायता करें जिससे हम अपने चरम ध्येय की पूर्ति तक अविराम संघर्ष करते ही रहें।

१४ जनवरी सन् १९५१ ई० को नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री महाराज पद्म शमशेर ने रांची में अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि नेपाल के महाराजाधिराज को ही अन्तरिम सरकार के लिए नए मंत्रियों का चुनने का भार सौंपा जाय। जनता की अन्तरिम सरकार में विश्राम काल के लिए नेपाली कांग्रेस को ही महत्त्वपूर्ण विभाग मिल जायँ। मुझे इस बात पर विशेष प्रसन्नता है कि श्री त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव ही नेपाल के महाराजाधिराज बने रहेंगे। सैद्धान्तिक दृष्टि से मैं इस सुधार को जनतन्त्रवाद की ओर बढ़ा हुआ एक कदम मानता हूँ। यही तो मैं जब से नेपाल का प्रधान मंत्री हुआ तब से समझता रहा था। तब भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि यदि इसमें सच्चाई न रही तो यह घोषणा भी स्वांग में परिणत हो जायगी। सच्चाई न रहने से विधान-निर्माण की बात पराजित हो जायगी। मैं इस बात पर और जोर देना चाहता हूँ कि श्री पाँच सरकार को राज्य-सिंहासन पर वापस लाने के समय सब प्रकार की आवश्यक सावधानी बरती जाय और श्री पाँच सरकार तथा मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध भी स्पष्ट कर दिए जायँ। श्री पाँच महाराजाधिराज को ही पूर्ण अधिकार सम्पन्न राज्य का सर्वोच्च अधिकारी रहना चाहिए।

इसी दिन नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला ने गोरखपुर में एक वक्तव्य देते हुए कहा कि नेपाल में प्रस्तावित वैधानिक परिवर्तन बहुत ही अस्पष्ट है। प्रस्तावित अन्तरिम सरकार और विधान परिषद् की शर्तें जो घोषणा में रक्खी गई हैं वह ऐसी नहीं हैं जो नेपाल में जनतन्त्रवाद ला सकें। कोइराला ने कहा कि इस घोषणा में तीन त्रुटियाँ हैं—

१ यह घोषणा नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा न होकर नेपाल के महाराजाधिराज द्वारा होनी चाहिए।

२ यह प्रश्न कि अन्तरिम सरकार में जनता के सच्चे मंत्रियों का नाम कौन पेश करेगा और कौन विभाग-वितरण करेगा तथा उनके अधिकार क्या रहेंगे यह अनिश्चित ही है।

३ इस घोषणा में राज्य की राजनीतिक संस्थाओं की ओर संकेत किया गया है जब कि नेपाल में केवल एक ही राजनीतिक दल है और वह है नेपाली कांग्रेस।

यदि यह अवरोध हटाया नहीं गया तो स्वाधीनता-संग्राम परिस्थिति के अनुसार हिंसात्मक और अहिंसात्मक ढंग से होता ही रहेगा।

१६ जनवरी सन् १९५१ ई० को नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला ने अपने स्वयंसेवकों को सभी गतिविधियाँ बन्द कर देने को कहा। उन्होंने उन सबों से यह अपील भी की कि नेपाल में शान्ति स्थापित की जाय। मातृका प्रसाद कोइराला ने कहा कि नेपाल के प्रधान मंत्री की घोषणा भारत के प्रधान मंत्री की अपील तथा

नेपाल के महाराजाधिराज के वक्तव्य से उत्पन्न परिस्थिति तथा भारत सरकार से पूर्ण विचार-विमर्श करने के पश्चात् हम ने यह तय किया है कि सब प्रकार की कार्यवाहियाँ फौरन बन्द करके समझौते के लिए अनुकूल परिस्थिति लाई जाय। हम इसलिए सब कार्यकर्ताओं को सब प्रकार की सैनिक कार्यवाइयों को बन्द कर देने की अपील करते हैं और सबों से अपील करते हैं कि नेपाल में शान्ति स्थापित करने में सब सहायता करें। हम भारत सरकार के उन सब कार्यों के लिए अनुगृहीत हैं जिससे नेपाल में सुधार और प्रगति आई। इस विषम काल में हम भारत के प्रधान मंत्री का आदेश स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि नेपाल की समस्या जल्दी ही सन्तोषपूर्वक हल हो जायगी। भारत सरकार के समक्ष नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइराला तथा उनके छोटे भाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एवं नेपाली कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जनरल सुवर्ण समशेर ने राणा सरकार के प्रतिनिधि जेनरल बबर समशेर विजय समशेर तथा राणाओं के समर्थक सरदार नरेन्द्र मणि आचार्य दीक्षित के समक्ष संधि शर्तें भाकीं। संधि शर्तों में कोइराला बन्धुओं ने अन्य किसी पुरुष तथा राजनैतिक दल के नेताओं को सम्मिलित होने का अवसर ही नहीं दिया।

८ फरवरी सन् १९५१ ई० को 'काठमाण्डू-दिल्ली संधि-वार्ता' समाप्त हुई और १५ फरवरी सन् १९५१ ई० को भारत सरकार ने महाराजाधिराज को सपरिवार बहुत ही आदर के साथ अपने विशेष वायुयान द्वारा नेपाल की राजधानी काठमाण्डू विदा कर दिया। राजधानी की लाखों जनता ने गौचर विमान पत्तन पर अपने महाराजाधिराज का अभूतपूर्व स्वागत किया।

१८ फरवरी सन् १९५१ ई० को महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव ने नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से अन्तरिम सरकार के मंत्रिमण्डल की घोषणा तथा जनता से सरकार का पूर्ण सहयोग करने की अपील कर दी। फलस्वरूप नेपाल में सर्वत्र शान्ति स्थापित हो गई।

इसी दिन श्री पाँच महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव ने अपने नारायण हिटी दरबार में सैकड़ों व्यक्तियों को आमंत्रित करके नेपाली भाषा में प्रथम शाही घोषणा की जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

स्वस्तिश्री गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपाल तारा ओ३म् रामपट्ट अतुल ज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखा दक्षिणबाहु महाधिपति श्री मन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराज त्रिभुवन वीर विक्रम जंग बहादुर शाह बहादुर समसेर जंग देवानाम् सदा समर विजयिनाम्।

आज हमारे समस्त देश के भाइयो भारदार, सन्त-महन्त भारी प्रजा साहू महाजन इत्यादि को सम्बोधित—

उपरान्त सवत् १   १ साल में हमारे स्वर्गीय पूज्य प्रपितामह श्री पाँच महाराजा

/

विराज सुरेन्द्र और विक्रम शाह ने अपने सिंहासन-काल में अनेक गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण कारणों से अपना तथा अपने उत्तराधिकारियों द्वारा देश का शासन-भार श्री जंग बहादुर राणा को सौंप दिया।

उपर्युक्त श्री तीन महाराज जंग बहादुर राणा के उत्तराधिकारी हमारे पूर्वजों द्वारा नियुक्त होकर प्रधान मन्त्री की हैसियत से राज्य का शासन चलाते आ रहे हैं और वर्तमान समय में भी श्री तीन महाराज मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा हमारी तरफ से हमारे नाम से इस राज्य का शासन चलाते आ रहे हैं और अब हमारी इच्छा तथा निर्णय है कि हमारी प्रजा का शासन उन्हीं के निर्वाचन द्वारा एक वैधानिक सभा खड़ी करके प्रजातंत्रात्मक विधान के अनुसार हो।

और जब तक यह विधान तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारा कार्य सम्पादन करने एवं सहायता तथा सम्मति देने के निमित्त जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की एक मंत्रिमण्डल संगठन करने की हमारी इच्छा और निर्णय है। इसी लिए हमारी ओर से इस घोषणा-पत्र द्वारा हमारे कार्य-सम्पादन में सहायतार्थ हमारे अति विश्वासपात्र तथा प्रिय श्री तीन महाराज मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा हमारे प्रधान मंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री नियुक्त किये जाते हैं।

श्री मंशा बबर शमशेर जंग बहादुर राणा	रक्षा मंत्री
श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला	गृह मंत्री
श्री सुवर्ण शमशेर	अर्थ मंत्री
श्री चूड़ाराज शमशेर	वन विभाग मंत्री
श्री गणेशमान सिंह	उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री
श्री नृप जंग राणा	शिक्षा मंत्री
श्री भद्रकाली मिश्र	यातायात मंत्री
श्री यज्ञ बहादुर बस्नेत	स्वास्थ्य मंत्री
श्री भरत मणि शर्मा	खाद्य तथा कृषि मंत्री

एक मंत्रिमण्डल संगठित तथा नियुक्त हो रहा है। उपर्युक्त मंत्रीगण अपने-अपने ओहदों पर रहें और संयुक्त रूप में हमारे प्रति जिम्मेदार रहें। हमारे प्रधान मंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्य के शासन सम्बन्धी इत्यादि विषयों में मंत्रिमण्डल का निश्चय आदि हमें अवगत कराते रहें और राज्य के शासन सम्बन्धी विषय इत्यादि के बारे में हमारी सम्मति लेकर उसकी प्रतिक्रिया फिर हम से प्रकट करना उनका कर्तव्य होगा।

और हम इसके द्वारा अपनी समस्त प्रजा को अपने तथा अपने उत्तराधिकारी के प्रति सच्ची वफादारी कायम करने के निमित्त आमंत्रित करते हैं। और हमारे सभी जंगी निजामती अफिसर इत्यादि तथा राज्य के वासिन्दों को आज्ञाकारी होकर हमारे मंत्रियों को अपने अपने कर्तव्य के सम्पादन में मदद तथा सहायता देने का आदेश दिया जाता है।

राजनीतिक अपराध में पड़े हुए सभी लोग २ अप्रैल १९५१ ई० तक अपने-अपने घर आकर शान्तिमय कार्य में लग जाने पर उन लोगों को हम माफी तथा विस्मृति और उस अपराध में जब्त हुई सम्पत्ति को उन्हें वापस देने की हमारी शाही इच्छा है।

हमारी आन्तरिक आशा है कि इस नवीन व्यवस्था में सरकार तथा जनता मिल-जुल कर नेपाल की उन्नति एवं समृद्धि के निमित्त प्रयत्नशील होंगे। परमेश्वर हमें तथा हमारे अधिकारी वर्ग को हमारी प्रजा के हित के निमित्त हमारी उपर्युक्त इच्छा इत्यादि को पालन करने की शक्ति दे।

नारायण हिटी दरबार,
काठमाण्डू
१८ फरवरी १९५१ ई०

राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकार

नई दिल्ली में समझौता-वार्ता के साथ ही साथ यह भी तय हो गया था कि समझौते के सब से घोर विरोधी डाक्टर के० आई० सिंह को पकड़ने के लिए भारत सरकार अन्तरिम सरकार की सैनिक सहायता भी करे। फलतः शाही घोषणा के पहले ही भारतीय सेना भैरहवा के लिए कूच कर चुकी थी। दूसरे ही दिन १९ फरवरी सन् १९५१ ई० को भैरहवा के पास कर्बला नामक विद्रोही सेना की फौजी छावनी पर नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के सैनिकों की संयुक्त सैनिक कार्यवाही हो गई और डाक्टर के० आई० सिंह अपने तीन सौ अस्सी सैनिकों के साथ भैरहवा की जेल में बन्द कर दिए गए। इस संयुक्त सैनिक कार्यवाही का प्रभाव नेपाल की जनता पर बुरा पड़ा और नेपाली जनता को बहुत रोष हुआ कि महाराजाधिराज ने जब अपनी शाही घोषणा में सब राजनीतिक अपराधियों को माफी तथा विस्मृति दे दी थी तो फिर क्यों डाक्टर के० आई० सिंह संयुक्त सरकार द्वारा बन्दी बना लिये गये। इससे नेपाली जनता को यह विश्वास हो गया कि यह सारा षड्यन्त्र नेपाल की नयी सरकार केवल इस अभिप्राय से कर रही है जिससे कि डाक्टर के० आई० सिंह तथा उनके साथी शासन को कमजोर न पा सकें और उसने भारत सरकार को धोखे में डालने के विचार से ही उन्हें डाकू तथा खूनी होने की गलत सूचना दी और इसी आधार पर नयी सरकार ने भारत से सैनिक सहायता प्राप्त की।

इसी समय नेपालगंज तथा बर्दिया क्षेत्र में भी विद्रोही सेना ने संयुक्त सरकार को चुनौती दी। नेपाल सरकार की प्रार्थना पर ११ अप्रैल सन् १९५१ ई० को उत्तर प्रदेश सरकार की सशस्त्र पुलिस की पांच कम्पनियों ने विद्रोही सेना का पीछा किया और ११ [illegible] सन् १९५१ ई० को भारतीय सेना ने नवलपुर पहुँचकर विद्रोही सेना का एक सप्ताह में दमन करके अठ्ठावन विद्रोहियों को बन्दी बना लिया। संयुक्त सरकार ने

भारतीय सेना के सहयोग से प्रायः सभी विरोधी तत्वों को कुचल तो दिया परन्तु भीतर ही भीतर आग सुलगती ही रही और पूर्वी नेपाल के लिम्बू तथा किरातों ने तो सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया और जिस में काफी धन जन की भी क्षति हुई। १२ अप्रैल सन् १९५१ ई० को गोरखा दल ने काठमाण्डू में एक हजार के लगभग खुकरीधारी गोरखों का भयंकर जुलूस निकालकर गृहमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की कोठी पर



भद्रकाली मिश्र



विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला

हमला किया। गोरखा दल का इरादा गृहमंत्री आदि को मारकर सत्ता हथियाने का था। संयुक्त सरकार ने इसी अपराध में गोरखा दल के नेताओं को गिरफ्तार किया। २ मई सन् १९५१ ई० को रक्षा मंत्री जनरल बबर शमशेर भी इसी दल में शामिल होने के नाते काठमाण्डू भाग पर दोषी ठहराए गये। ८ मई को रक्षा मंत्री जनरल बबर शमशेर पदच्युत कर दिये गये और रक्षा विभाग महाराजा मोहन शमशेर को सौंप करके उस विभाग के बहुत से अधिकार कम करके प्रधान सेनापति को दे दिये गये। रक्षा विभाग का सचम देश की रक्षानीति पर ही कमल दल का अधिकार किया गया। इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन विभाग गृह विभाग से साथ-साथ सिंचाई विभाग तथा विकास विभाग में से पृथक कर खाद्य तथा कृषि-विभाग में सम्मिलित कर दिया गया।

नेपाली कांग्रेस में गुटबन्दी बड़े जोरों से हो रही थी इसलिए १० जून सन् १९५१ को भरत मणि शर्मा के स्थान पर सूर्य प्रसाद उपाध्याय खाद्य तथा कृषि मंत्री नियुक्त किये गये। इसी समय दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत कमाण्डिंग जनरल सिंह शमशेर के स्थान पर मेजर जनरल विजय शमशेर की नियुक्ति हुई और सिंह शमशेर संयुक्त सरकार के वन विभाग के मंत्री बनाये गये।

आपसी पटबन्दी तथा देश को विकास के मार्ग पर न ले जा सकने के नाते राणा-
कांग्रेस सरकार लड़खड़ाने लगी कि इसी बीच महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह
न भारत के प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को काठमाण्डू आमंत्रित किया। १६
जून सन् १९५१ ई० को भारत के प्रधान मंत्री नेपाल की राजधानी में पहुँचे। वहां
नेपाली जनता तथा नेपाल सरकार ने उनका शानदार स्वागत किया।

महाराजाधिराज के सभापतित्व में टुंडीखेल के मैदान में एक विराट सभा हुई जिसमें
भारत के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि भारत नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप
नहीं करना चाहता और न ही वह नेपाल को किसी खास शक्ति का अखाड़ा ही बनने देना
चाहता है। १८ जून को काठमाण्डू से आकाशवाणी द्वारा अपना भाषण प्रसारित करते
हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों देशों की एकता पर जोर देते हुए घोषित
किया—"हम न तो युद्ध आरम्भ करना चाहते हैं और न ही हम इरादे
को लेकर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं।
हम स्वतन्त्र देशों की स्वतन्त्रता में किसी
का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त कर सकते। हिमालय
पर्वत हमारा और नेपाल का संतरी है। इसके
धवल शिखर मित्रों का स्वागत और शत्रुओं
को चेतावनी देते हैं। भारत और नेपाल का
निकट सम्बन्ध है। हमें अपनी स्वतन्त्रता की
रक्षा करनी चाहिए।" इसके आगे आपने
भावावेश में कहा कि "नेपाल जो पर्वतीय कटि
प्रदेश है हिमालय की पुत्री है और भारत की
छोटी भगिनी है। यहां मैं आया हूँ। मैं भारतीय
जनता की सद्भावना लेकर आपके यहां आने
की बड़ी पुरानी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
नेपाली जनता ने जो प्रेम प्रदर्शित किया है
उसका मैं आभारी हूँ। उनके व्यवहार से मुझे



जनरल सुवर्ण शमशेर

ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं उन्हीं में से एक हूँ—बाहर नहीं हूँ। मैं इस प्रेमपूर्ण व्यवहार के लिए
महाराजाधिराज प्रधान मंत्री तथा समस्त जनता का आभारी हूँ। मैं स्वयं पर्वतीय प्रदेश
का हूँ और पर्वतमाला को देखकर मेरा हृदय गद्‌गद् हो जाता है।

नेपाल के साहसी सैनिकों ने विश्व की अनेक युद्ध-भूमियों में ख्याति प्राप्त की है।
अतएव उन्हें नेपाल की स्वतन्त्रता की भाव रक्षा करनी है। नेपाल में एक नवीन दिशा में
कदम उठाया है और समस्त भारत की उसके साथ सहानुभूति है। मुझे आशा है
कि समस्त प्रयासों से और सहयोगपूर्ण कार्य से सभी नेपाल की स्वतन्त्रता का शक्ति

माली अवलम्ब प्रदान करता। पिछले महीनों नेपाल में जो घटना घटित हुई है वह अद्वितीय और अपने तरह की एक निराली है। और देशों की भांति नेपाल भी समस्याओं से भरा है। खास बात यह है जो पुराने धर्म मजहब के साथ बदल गये और एक-दूसरे से सहयोग कर रहे हैं।

डाक्टर क० आई० सिंह

जून सन् १९५१ ई० के अन्तिम सप्ताह की रात्रि में कुछ बन्दी डाकुओं ने भैरहवा जेल की दीवाल में बहुत बड़ी सेंध लगाकर सभी राजनीतिक बन्दियों को बाहर निकल जाने के लिए अनुरोध किया। किन्तु एक भी राजनीतिक बन्दी जेल से भगने के लिए उद्यत नहीं हुआ यद्यपि पांच अपराधी जेल से बाहर निकल गये।

संयुक्त सरकार ने डाक्टर के० आई० सिंह के पैर में बेड़ी डालकर एक छोटी-सी कोठरी में बन्द करके चारों ओर पहरा बैठा दिया और उनके सभी साथियों को जेल में बन्द कर दिया परन्तु तब भी जनता डाक्टर के० आई० सिंह को ही अपना रक्षक मानकर पूजती थी। जनता को जो भी कष्ट होता था वह डाक्टर के० आई० सिंह की खिड़की पर आकर फरियाद करती थी। डाक्टर के० आई० सिंह अपने बन्द कमरे के अन्दर से ही वादी तथा प्रतिवादी की फरियाद सुनकर उचित समझौता करा दिया करते थे।

वस्तुतः डाक्टर के० आई० सिंह ही पूरे जिले के समस्त मुद्दों का समझौता पंचायत तथा सच्चे गवाहों के आधार पर करा दिया करते थे और वादी तथा प्रतिवादी दोनों प्रसन्नतापूर्वक उसी समझौते को मान लेते थे। इस प्रकार के समझौते करा देने से डाक्टर के० आई० सिंह की प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही गई और निर्धन तथा प्रताड़ित जनता डाक्टर के० आई० सिंह की जयकार मनाकर उनकी रिहाई की माँग करती रही।

इधर डाक्टर के० आई० सिंह ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में बीसों हजार किसानों को भैरहवा बुलाकर सबको शान्तिपूर्वक मिल-जुलकर रहने तथा महाराजाधिराज के प्रति कृतज्ञ बने रहने की शपथ दिलाई। उसी रात्रि में डाक्टर के० आई० सिंह ने बुटवल जिले के समस्त राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की भैरहवा के बड़े हाकिम रामेश्वर प्रसाद शर्मा के समक्ष सरकारी भवन में एक गोष्ठी की। डाक्टर के० आई० सिंह ने एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाकर प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्त्ता से ताम्रपत्र में रक्खे हुए गंगाजल को उठवाकर मातृभूमि तथा महाराजाधिराज के प्रति निष्ठावान बने रहने की शपथ खिलवाई और सबको सच्चाई के साथ किसानों की सेवा करने के लिए उत्प्रेरित किया। इस प्रतिज्ञा का प्रभाव कार्यकर्त्ताओं पर सुन्दर पड़ा और प्रत्येक कार्यकर्त्ता ने डाक्टर के० आई० सिंह की राय लेकर अपने-अपने क्षेत्र में संगठन-काम प्रारम्भ कर दिया। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के इस संगठन को देखकर सरकारी कर्मचारी भयभीत-से हो गये और डाक्टर के० आई० सिंह के आदेशों का पूर्णतया पालन करने लगे। चपरासी से लेकर बड़े हाकिम तक सभी डाक्टर के० आई० सिंह के प्रभाव को भली भांति जानते थे। सरकारी कर्मचारियों को यह विश्वास हो गया था कि

सभी बन्दी मुक्त कर दिये जायेंगे और नरेश डाक्टर के० आई० सिंह को किसी ऊँचे पद पर नियुक्त करेंगे। यही सोचकर सभी सरकारी कर्मचारी पहले ही से उनकी जी-हजूरी में व्यस्त रहने लगे और जब बड़े हाकिम साहब ने अपनी कन्या के विवाह-संस्कार को सम्पन्न कराने के लिए अवकाश ले लिया तो १ जुलाई सन १९५१ ई० को रात्रि में जेल का फाटक खोल दिया गया और सभी राजबन्दियों ने बाहर निकलकर भैरहवा के सरकारी भवनों पर अपना झण्डा लहरा दिया। दूसरे दिन ११ जुलाई को सिपरहिया के बाग में पचासों हजार किसानों तथा सरकारी कर्मचारियों ने डाक्टर के आई सिंह को अपना गवर्नर घोषित कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी स्वामी-भक्ति का प्रमाण एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके दिया। इसके पश्चात् डाक्टर के आई० सिंह ने जनता को शान्त रहने तथा अहिंसा से काम लेने की अपील की। डाक्टर के आई सिंह ने सरकारी कोष पर सशस्त्र सैनिकों का पहरा बैठा दिया। सरकारी सैनिकों ने जब यह सुना कि डाक्टर के आई० सिंह ने अहिंसात्मक ढंग से आत्मसमर्पण करने की अपील की है तो उन सबों ने बड़े हाकिम की कोठी में शरण ले ली। १२ जुलाई सन् १९५१ ई० को दस बजे दिन में बड़े हाकिम के भवन में बन्द सरकारी सैनिकों ने यह कहला भेजा कि यदि हजारों निःशस्त्र किसान बड़े हाकिम के भवन के सामने आकर हम लोगों को यह सबूत दे दें कि वे लोग सचमुच डाक्टर के आई० सिंह को अपना गवर्नर मानते हैं तो हम लोग भी डा० के० आई सिंह को अपना गवर्नर मान लेंगे। फलतः उसी दिन साढ़े चार बजे किसानों तथा मजदूरों का एक वृहत् जलूस सरकारी सैनिकों को मनाने के लिए बड़े हाकिम के भवन की ओर बढ़ा और ज्यों ही जुलूस सरकारी भवन के द्वार के समीप पहुँचा त्यों ही सरकारी सैनिकों ने गोली चला दी जिसके फलस्वरूप तीन स्त्रियों के अतिरिक्त पच्चीसों किसान गोली के शिकार बने और अनेकों बुरी तरह घायल हो गये।

इसके पश्चात् भी डाक्टर के आई० सिंह ने अहिंसा से काम लेने की अपील की। ११ जुलाई सन् १९५१ ई० को जब डाक्टर के आई सिंह को यह पता चला कि भारतीय सेना उन्हें पकड़ने के लिए भारत-नेपाल की सीमा तक आ पहुँची है तो वह सरकारी कोष की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को छोड़कर वहाँ से हट गये। १४ जुलाई को भारतीय सेना ने आकर सरकारी कोष को अपने कब्जे में कर लिया। भारतीय सैनिकों ने पहरेदारों को बन्दी बना करके जेल में डाल दिया। इसके पश्चात् डाक्टर के आई सिंह की सेना ने परासी पर बिना रक्तपात के पुनः आधिपत्य जमा लिया और जब भारतीय सेना ने परासी पर भी हमला कर दिया तो डाक्टर के० आई० सिंह ने जंगलों तथा पर्वत-कन्दराओं में शरण ले ली। भारतीय सेना ने वहाँ भी उनका पीछा किया परन्तु वह असफल रही। नेपाल सरकार ने २५ जुलाई सन् १ ५१ ई० को डाक्टर सिंह आदि को डाकू तथा फरार घोषित करके उन्हें पकड़ने के लिए पाँच हजार रुपये का पुरस्कार रख दिया। इस पर भी जब नेपाल सरकार को सफलता नहीं मिली तो उसने तत्सम्बन्धी समाचारों

पर कमाल डाल दिया ।

इस अगस्त को नये विधान के अनुसार नपाल प्रधान न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किये गये । इस दिन डाक्टर के० आई० सिंह तथा कर्नल खड्ग बहादुर सिंह गुरुंग अपने दल के तीस सैनिकों के साथ पाल्पा से साठ मील पश्चिम भोरपाटन में—विश्वासघात पूर्वक बन्दी बनाये गये ।

राणा-कांग्रेस सरकार का लड़खड़ाती देखकर महाराजाधिराज न २ अक्तूबर, सन् १९५१ ई० को पैंतालीस सदस्यों को एक सलाहकार समिति खड़ी की । इसके बावजूद भी सरकार सँभल नही सकी और राजधानी के विद्यार्थी उस उजाड़ फंक्स के लिए उत्पात मचाते ही रहे । गृह मंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने विरोधी नेताओं तथा कतिपय विद्यार्थियों को सुरक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द करके कड़ाई से काम लिया । प्रतिक्रिया-स्वरूप विद्यार्थियों ने उग्र रूप धारण किया किन्तु गृह मंत्री ने उनको नाकामयाब बनाने के लिए गोलियां चलवाई और जिसमें एक विद्यार्थी चिनिया काजी शहीद हो गए । इसी गोलीकाण्ड को लेकर प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमशेर तथा गृह मंत्री में मतभेद हो गया और दोनों न त्यागपत्र दे दिए । इसी घटना से राणा-कांग्रेस सरकार भंग हो गई । १५ नवम्बर, सन् १९५१ ई०, को महाराजाधिराज ने अपनी प्रशस्ति के साथ निम्न प्रकार की एक दूसरी घोषणा की—

आगे हमारी प्यारी प्रजा सबको यथोचित,

उपरान्त मंत्रिमण्डल के पुनर्निर्माण के लिए दोनों पक्ष के मंत्रियों की थोड़ी बहुत सलाह लेने और प्रधान मंत्री महाराज शमशेर जंग बहादुर राणा और अन्य मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र पेश किये जाने पर वर्तमान मंत्रिमण्डल का कायम रहना असम्भव हो गया है । इस मंत्रिमण्डल ने अपनी कार्य अवधि में निःसन्देह बहुत ही अच्छा काम किया है तो भी इच्छानुसार उन्नति नहीं हुई ऐसा हमारा विश्वास है । हमने जैसा चाहा था वैसी सुखी और संतुष्ट हमारी प्रजा नहीं हो पाई है । हाल में उपस्थित परिस्थिति के बहुत कारणों में संमिश्रित उत्तरदायित्व ही शायद एक प्रमुख कारण दिखलाई पड़ता है ।

देश को पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक ढंग पर ले जाने वाली वैधानिक सभा द्वारा निर्मित विधान-अनुसार हमारे देश का शासन चलाना हमारा घोषित उद्देश्य है । नियमपूर्वक निर्वाचन द्वारा हमारी प्रजा की राय निश्चित हो जाने पर बहुमत पक्ष के नेता पर सरकार निर्माण करने का अभिभार हो जाता है । इस वर्तमान परिवर्तन में लोकप्रिय और जनता की इच्छानुसार चलने वाली सरकार खड़ी करने की हमारी इच्छा है । हमारी चेष्टा मिश्रित उत्तरदायित्व तथा आपसी मतभेद हटाने वाली और यथाशक्ति हमारे देश की बहुत आवश्यक कार्यों का हित करने वाली प्रतिनिधि स्वरूप सरकार बनाने की है । हमारे देश की भलाई और हित करने वाली सरकार का उत्तरदायित्व पूर्णरूप से वहन कर सकने वाले प्रधान मंत्री को नियुक्त करने की हमारी इच्छा है । स्वभावतः ऐसा प्रधान मंत्री हमारी प्रजा की शुभेच्छा के सकने वाला होना चाहिए । हम अनुभव करते हैं कि निर्वाचन न होने

तक और जनता की राय इस प्रकार निश्चित नहीं की जाय तब तक सबसे बड़ी संस्था के नेता का चुन लेना ही आदर्श तरीका है। इसे बहुतों ने पसन्द भी किया है। यथासंभव हमारे प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार अन्य मंत्री हमारे द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। प्रधान मंत्री को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मंत्रिमण्डल समाज के बहुत से विभाग एवं देश के विभिन्न भागों को सन्तुष्ट करने वाला ठीक प्रतिनिधि स्वरूप होना चाहिए और संस्थाओं के अतिरिक्त महत्व रखने वाले विभिन्न सांस्कृतिक तथा आर्थिक वर्गों का भी ध्यान रखना होगा।

इन कारणों से विभिन्न तरफों से सलाह ली कि नेपाली कांग्रेस के सभापति श्री मातृका प्रसाद कोइराला को प्रधान मंत्री पद का अधिकार हमारे द्वारा देकर निम्न सदस्यों का मंत्रिमण्डल में हमारे द्वारा नियुक्त किया गया है।

श्री मातृका प्रसाद कोइराला—प्रधानमंत्री साधारण राज्य-व्यवस्था तथा परराष्ट्र मंत्री।

श्री सुवर्ण शमशेर जंग बहादुर राणा—अर्थ मंत्री।

श्री सूर्य प्रसाद उपाध्याय—गृह तथा खाद्य मंत्री।

श्री महाकाली मिश्र—यातायात मंत्री।

श्री गणेश मानसिंह—कृषि पशु-संरक्षण तथा भूमि व्यवस्था मंत्री।

श्री केसर शमशेर जंग बहादुर राणा—रक्षा मंत्री।

श्री महेन्द्र विक्रम शाह—उद्योग वाणिज्य रसद मंत्री।



मातृका प्रसाद कोइराला

श्री महावीर शमशेर जंग बहादुर राणा—योजना विकास खान बहन तथा विद्युत मंत्री।

श्री खड्गमान सिंह—संसदीय प्रबन्ध मंत्री।

श्री शारदा शमशेर जंग बहादुर राणा—शिक्षा मंत्री।

श्री नारदमुनि थुलुंग—स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—कानून मंत्री तथा न्याय मंत्री।

श्री नर बहादुर गुरुङ—उपमंत्री।

श्री धर्म रत्न यमी—उपमंत्री।

हम इच्छा करते हैं कि हमारे नये प्रधान मंत्री उदार राजनीतिज्ञतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और मंत्रिमण्डल में जनता की निष्पक्षता सद्भावना तथा श्रद्धा

बनाये रखने के लिए मंत्रिमण्डल का कार्य सम्पादन करा सकेंगे। जनता की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था स्थापित करने के अभिप्राय से यथाशीघ्र जनता के नागरिक अधिकार स्पष्ट और निश्चय करना हमारे मंत्रिमण्डल का कर्तव्य होगा।

(क) शासन विभाग का प्रभाव बिल्कुल ही न पड़ने का ध्यान रख स्वतन्त्र न्याय विभाग खड़ा करना।

(ख) पब्लिक सर्विस कमीशन का अच्छी तरह कार्य सम्पादन करना।

(ग) यथासम्भव संवत् २००९ साल के अन्दर ही वैधानिक सभा खड़ी करने के लिए निर्वाचन का शीघ्र प्रबन्ध करना।

(घ) पुलिस तथा सेना का पुनः संगठन तथा उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री महाराज मोहन शमसेर जंग बहादुर राणा ने अपने को नयी परिस्थिति में ढालने के लिए सचमुच ही असाधारण तरीके से काम किया है। हमारी ओर से उन्हें इस कार्य के लिए बधाई दी जाती है कि उन्होंने अपने प्राप्त अधिकारों तथा शक्ति को त्याग करके नयी परिस्थिति के अनुसार कार्य सम्पादन किया। हमारी ओर से यह भी आशा की जाती है कि प्रधान मंत्री न रहने पर भी वह नेपाल की उन्नति के काम में ध्यान देते रहेंगे।



जनरल महावीर शमशेर

हम अपनी प्रजा को आमंत्रित करते हैं कि वह मंत्रिमण्डल के समक्ष आए हुए कार्यों में पूर्ण सहायता तथा सहयोग दें। सरकारी कर्मचारियों को विशेषतया होशियारी बरतनी है। उन्हें अपने को सरकारी कर्मचारी समझ कर ईमानदारी तथा आदर्श अनुशासन का पालन करना चाहिए। उन्हें हमारी प्रजा की सुविधा तथा भलाई के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करना चाहिए और अपने कार्य तथा स्वभाव से सच्चा देशसेवक बनने का परिचय देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक परिवर्तन की परवाह न करके व्यक्तिगत तौर से वफादारी तथा श्रद्धापूर्वक प्रजातान्त्रिक देशों की प्रथानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

हम विश्वास करते हैं कि यह नया परिवर्तन स्वच्छ प्रजातन्त्र प्रगति एवं समृद्धि की ओर बढ़ने का एक और कदम है।

श्री परमेश्वर हमें और हमारे मातहत अधिकारी वर्ग को प्रजा की भलाई करने के लिए हमारी इच्छा पूरी करने में शक्ति प्रदान करें।

नारायण हिट्टी दरबार, काठमाण्डू।

इति संवत् २००८ साल मार्ग १ गते रोज ६ शुभम्।

कांग्रेस सरकार

इस सरकार में नेपाली कांग्रेस के आठ तथा अन्य स्वतन्त्र सदस्य थे। यह सरकार नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में बनी थी और वह जनता के लिए कुछ प्रगतिशील काम भी करना चाहती थी। मंत्रिमण्डल के इस रुख को देखकर उसी के भीतर रहने वाले बैलीशाहों तथा उनके मतलो न एक सूक्ष्म चाल चलकर सरकार तथा संस्था के बीच दरारें डाल दीं। इतने ही से उस जमात विशेष को सतोष नहीं हुआ। कालान्तर उसने फिर पैंतरे बदले और जन-शक्ति को दूसरी ओर मोड़कर एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि न जनता की इच्छा पूर्ण हुई और न नरेश की और न नेपाल के प्रसन्न चाहने वाले मित्रराष्ट्र की ही। परिणाम स्वरूप देश तबाही की ओर ढकेला जाने लगा और उन्हीं का आश्रय पाकर अनावश्यक इच्छा रखने वाले विश्व-शान्ति के बाधक सेवा तथा सहायता के बहाने अपना जाल फैलाने लगे। इस दिशा में उन्होंने एक ओर राजनीति में हाथ घुसाकर सरकार को भारत की कठपुतली तथा निकम्मी साबित करने की चेष्टा की और दूसरी ओर वे छद्मवेशियों के आर्थिक जाल को आधार बनाकर भारत-विरोधी भावना फैलाने में जी-तोड़ कोशिश भी करते रहे। इस प्रकार टट्टी की आड़ से शिकार खेलकर देश नरेश तथा भारत को धोखे में डालकर जनता के प्रतिनिधियों को बदनाम किया जाने लगा। यह हथकंडा न केवल मंत्रियों के साथ अपितु संस्थाओं के साथ नेताओं पर भी इस्तेमाल होने को आया। इस प्रयास में प्रतिगामी शक्तियों को कुछ सफलता का आभास मिला और वे सब एक होकर उन सगठनों को आपस में लड़ाने लगे। इसका प्रारम्भ उस समय हुआ जब मातृकाप्रसाद मिश्र को मंत्रिमण्डल से बाहर निकाल दिया गया और मातृका प्रसाद कोइराला को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाने का प्रयत्न होने लगा।


डाक्टर के० आई० सिंह

संयुक्त मोर्चा

नेपाली कांग्रेस की सरकार ने डाक्टर के० आई० सिंह तथा उनके साथियों को कठोर दण्ड देने की भूमिका तैयार की। दूसरी ओर सचाई को प्रकाश में लाने के लिए नेपाल प्रजा परिषद् तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी न संस्थाओं को एक मंच पर लाकर जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा खड़ा किया। इस मोर्चा में अखिल नेपाल किसान संघ नेपाल राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टूडेन्ट्स

महिला संघ, युवक संघ, प्रगतिशील अध्ययन मण्डल तथा समाज सुधार संघ भी सम्मिलित हुए।

जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा ने विदेशी प्रभाव को रोकने तथा एक सर्वदलीय सरकार की स्थापना की माँग की। उसने डाक्टर के० आई० सिंह को डाकू और खूनी न मानकर उन्हें नेपाल का राष्ट्रीय नेता माना। इसकी प्रतिक्रिया सारे देश तथा तमाम नेपाली जनता पर हुई और चारों ओर कांग्रेसी सरकार का सक्रिय विरोध होने लगा।

राजधानी की मुक्ति सेना तथा राष्ट्रीय नेता को पूरा पता था कि प्रतिक्रियावादी तत्त्व नेपाल तथा मित्रराष्ट्र भारत को खराब स्थिति में रखकर नवजात प्रजातन्त्र का गला घोंट देना चाहते हैं। उन्हें देश के अस्तित्व के नष्ट होने तथा नेपाल को युद्ध का अखाड़ा बनने की भी आशंका हुई।

जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यों में नियुक्त करके सरकार का सक्रिय विरोध किया।

अक्तूबर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि सम्मेलन द्वारा इसका घोषणा पत्र तैयार किया गया और टंक प्रसाद आचार्य इसके अध्यक्ष निर्वाचित किये गये। जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा का घोषणा-पत्र नेपाली भाषा में प्रकाशित किया गया जिसका शाब्दिक हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

जनता के जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा में सम्मिलित होने के लिए हम लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टी, जन और वर्गीय संगठन की अन्तिम ध्येय-प्राप्ति के लिए यद्यपि अपने-अपने विभिन्न कार्यक्रम और नीति हैं तो भी आज की ऐतिहासिक स्थिति ने हम सबों को देश में वास्तविक जनतन्त्र की स्थापना के लिए एक ही मोर्चा में खड़ा किया है। एक ओर अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद और भारतीय पूँजीवाद का शोषण पहले से उग्ररूप धारण कर रहा है और दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी नेता लोग वधीम सामन्तवाद के साथ मिलकर सब वर्गों के ऊपर शोषण का चक्र घुमा रहे हैं। देश की सुख शान्ति, प्रगति और मुक्ति रोकने वाले यही भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ हैं। जब तक इन लोगों के पंजों से देश मुक्त नहीं किया जायगा तब तक जनता की किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। तदर्थ, हम लोगों को इन लोगों से लड़ना है। आज की परिस्थिति में कोई भी संस्था अकेले लड़कर साम्राज्यवाद और सामन्तवाद समाप्त नहीं कर सकती। अतः हम सब जनवादी तत्त्वों को एक ही मोर्चे में संयुक्त होकर साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष करके वास्तविक जनवाद के लिए लड़ना होगा। तब तक सच्चा जनतन्त्र नहीं हो सकेगा यह सिद्ध हो चुका है। अतएव इस संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित होनेवाली सभी संस्थाओं, जन और वर्गीय संगठनों की प्रगतिशील राजनीतिक और आर्थिक

योजना होना अत्यन्त आवश्यक है। संयुक्त मोर्चा कोई एक राजनीतिक पार्टी अथवा जन या वर्गीय संगठन के नेतृत्व में नहीं चला है। इसका संचालन सम्मिलित सभी शक्तियों के नेतृत्व में होगा। इस संयुक्त मोर्चे के निर्माण से नेपाल की जनता की बहुत दिनों की इच्छा पूरी की है। देश के सब जनवादी तत्वों को मिलकर सामन्तवादी साम्राज्यवादी और उनके दलाल प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध लड़ना होगा। यह भावना हमारे देश के क्रान्तिकारियों के मन में बहुत दिनों से उठ रही थी। इसलिए अपना-अपना कार्यक्रम और नीति यद्यपि नहीं मिलते हैं तो भी किसी भी पार्टी अथवा दल के नेतृत्व में नेपाल के प्रत्येक जनवादी काम में नेपाल की जनता पार्टी और दल शुरू से ही सहयोग देते चले आये थे। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में हुई गत सशस्त्र क्रान्ति में भी नेपाल के सभी दल जन और वर्गीय संगठनों ने सहयोग दिया था। उसी सहयोग के फलस्वरूप उस संघर्ष ने व्यापक रूप धारण कर लिया और सब तरफ जनता की जीत और राणाशाही की हार होती गई। उस संघर्ष का नेतृत्व सिर्फ नेपाली कांग्रेस के हाथ में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील शक्तियों के हाथ में जाने लगा। इसके फलस्वरूप अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद भारतीय पूंजीवाद मोहनगुट और नेपाली कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी नेता वर्ग से मिलकर श्री त्रिभुवन ने घबड़ाकर दिल्ली-समझौता किया। इस दिल्ली-समझौते का मुख्य अर्थ 'साम्राज्यवादी और सामन्तवादी शोषण को समाप्त करेंगे'—कहकर आगे बढ़नेवाले नेपाल के प्रगतिशील तत्वों को बढ़ने से रोकना नेहरू सरकार के आदेशानुसार चलने वाली एक पिट्ठू सरकार नेपाल में खड़ी करना और भारत चीन और नेपाल की जनता की बढ़ती हुई जनवादी एकता में खलल डालना था। इस बात की पुष्टि आजकल की प्रत्येक सरकारी कार्रवाई में हम लोग पा रहे हैं। प्रत्येक बात में नेहरू सरकार का हस्तक्षेप रहता है। यहाँ तक कि प्रधान मंत्री से लेकर सभी मंत्रियों की छँटनी भी नेहरू सरकार ही करती है।

देश के शत्रुओं को हटाने के लिए हमारे देश के क्रान्तिकारियों ने जो सिखाया है उसी के अनुसार नेपाल प्रजा परिषद् कम्यूनिस्ट पार्टी अन्य प्रगतिशील जन और वर्गीय संगठनों के प्रयास से आज संगठित रूप धारण किया है। यह देखकर प्रतिक्रियावादियों की नींद हराम होने लगी है। इस मोर्चे को तोड़ने के लिए उन लोगों ने सैद्धान्तिक और पुलिस द्वारा हमला किया। संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित संस्थाओं और अन्य जन-संगठनों के बीच में फूट डालने के लिए उन्होंने यहाँ तक कहकर प्रचार किया कि यह संस्था कम्यूनिस्ट का रचा हुआ जाल है। लेकिन देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को यह पता चला था कि संयुक्त मोर्चा न तो कम्यूनिस्ट पार्टी का रचा हुआ जाल है और न ही कम्यूनिस्टों के हक में पैदा हुआ है। इस संस्था का निर्माण तो समस्त क्रान्तिकारी शक्ति और उनकी इच्छाओं का फल है और प्रतिक्रियावादियों को खतम करने का एकमात्र साधन है। अनेकों तरीकों से जाल रचकर भी हमारी क्रान्तिकारी एकता में फूट डालने में असमर्थ

होकर प्रतिक्रियावादियों ने हमारे उद्घाटन को असफल कराने के लिए हमारे सभापति कॉमरेड टंक प्रसाद पर झूठा अभियोग लगाकर गिरफ्तार किया और हमारे मंत्री कॉमरेड गौरीभक्त को पकड़ने के लिए वारन्ट जारी किया और अनेकों साथियों को जल में भी ठूंस दिया। देशवासियों ने इसका जवाब सभा प्रदर्शन और हड़ताल से दिया। अपनी परम्परा की रक्षा करते हुए किसान मजदूर, महिला आदि सबों ने संघर्ष में डटकर भाग लिया—विद्यार्थी जिनकी परम्परा उज्ज्वल है—उन लोगों का संघर्ष में डटकर उसका नेतृत्व करना स्वाभाविक है। राजबन्दियों की मुक्ति के लिए और राणा-कोइराला मंत्रिमंडल के विरुद्ध आन्दोलन छिड़ गया। खासकर राजधानी में इसने उग्र रूप धारण किया। आखिरकार सरकार राजबन्दियों की मुक्ति के लिए ही बाध्य नहीं हुई बल्कि स्वयं भी टूटी। यह प्रतिक्रियावादियों की हार और प्रगतिशील शक्तियों की विजय का मूर्त रूप है। मोहन और विश्वेश्वर को मंत्रिमण्डल में रखकर 'अब जनता को भुलावे में रखना असंभव है' यह बात भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियावादियों ने देखी। फिर जनता की आँखों में धूल डालने के लिए मंत्रिमण्डल में हेर-फेर करना नितान्त आवश्यक हो गया। ये सब हस्तक्षेप हमारे देश के लिए और उसमें रहने वाली समस्त जातियों के लिए एक भारी अपमान जनक है।

अंग्रेज-अमेरिकी साम्राज्यवाद और भारतीय पूँजीवाद हमारे देश में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत जरूरी है। खासकर अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवादी नेपाल को अपने तृतीय विश्वयुद्ध की योजना में जनवादी चीन के विरुद्ध फौजी अड्डा बनाना चाहते हैं और नेपाल के युवकों को अपनी फौज में भर्ती कर एशियाई जातियों के मुक्ति-आन्दोलन के विरुद्ध वही अपनी करतूतें पुन कायम रखना चाहते हैं। विराटनगर आदि स्थानों में मिल खोलकर देश के व्यापार में पचहत्तर प्रतिशत से अधिक धेमर हस्तगत करके भारतीय पूँजीपति लोग नेपाल की प्राकृतिक सम्पत्ति खान जंगल इत्यादि में भी अपना एकाधिकार कायम करना चाहते हैं। इन लोगों के हस्तक्षेप करने का कारण यह भी है कि भारत चीन और नेपाल की जनता की जनवादी एकता में कुठाराघात करना।

जब तक हम अपने देश को अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद भारतीय पूँजीवाद और देशीय सामंतवाद के चंगुल से मुक्त नहीं करेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकेगी। हमारे जनवादी कार्य में वे लोग वैसी ही बाधाएं दे रहे हैं जैसी पहले से ही देते रहे हैं। अतएव आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार में सबका हित करने वाली सरकार खड़ी करने के लिए अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद, भारतीय पूँजीवाद और देशीय सामन्तवाद के विरुद्ध संगठित होकर लड़ना नेपाल के विभिन्न वर्गों का प्रथम कर्तव्य है। सामन्तवादी (राणाशाही) और साम्राज्यवादी शोषण से ही हमारे देश में संघर्ष संगठन और एकता का अभाव है। इस अभाव की पूर्ति करना हमारा प्रधान लक्ष्य है।

हम सामन्तवादी भूमि-व्यवस्था का पूर्वत विरोध करते हैं लेकिन उसके उन्मूलन के लिए हम क्रमशः कदम बढ़ाते हैं। फिलहाल हम केवल राणा और अन्य सामन्तों को भूमिहीन कर उन लोगों को मध्यवर्गीय जीवन स्तर में रखकर किसानों में बांटते हैं। छोटे-छोटे जमींदार जिम्मावाल और बिर्ता वालों की भूमि हम नहीं छूते हैं, क्योंकि ये लोग भी विदेशी साम्राज्यवाद और बड़े-बड़े राणा जमींदार, बिर्ता वालों से सताए ही जाते हैं। अतः ये लोग भी हमारे संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए हम अपील भी करते हैं। संयुक्त मोर्चे का ध्येय नेपाल में मजदूर किसान मध्य वर्ग और जातीय पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सच्चे जनवादी तत्वों के नेतृत्व में पूरी जनवादी सरकार कायम करना है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए नेपाल के विभिन्न वर्गों की मजबूती—एकता एक महान् हथियार है। इस हथियार को मजबूत न करने से अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद और भारतीय पूंजीवाद को देश से निकालने और देशीय सामन्तवाद को समूल फेंकने के लिए हम असमर्थता का अनुभव करेंगे।

विदेशी साम्राज्यवाद के पक्ष में चलने वाली कोई भी सरकार न तो देश को मुक्त कर सकती है और न ही देश में जनतन्त्र ही कायम कर सकती है। मातृका-सरकार की यही हालत है। आज की हमारे देश की ऐतिहासिक स्थिति ने हम लोगों को एक ही मोर्चे में खड़ा होकर देश को मुक्त करने और देश में जनतन्त्र कायम करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर रख दी है। इस ऐतिहासिक जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए संयुक्त मोर्चा निम्नलिखित उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करेगा—

१ अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवाद भारतीय पूंजीवाद और देशी सामन्तवाद के चंगुल से देश को मुक्त कर मजदूर किसान मध्यवर्ग बुद्धिजीवी और जातीय पूंजीपतियों की प्रतिनिधित्व करने वाली जनवादी सरकार सच्चे जनवादियों के नेतृत्व में खड़ी होगी।

२ सामन्ती भूमि-व्यवस्था को खतम करने की बात आगे रखकर क्रमशः आवश्यक भूमि-सुधार करेगा। मजदूर को जीवन-निर्वाह के योग्य वेतन दिलाएगा और किसानों के लिए उन्हीं के सहयोग से सरकारी संस्थाएं खुलवाएगा। स्थानीय सरकारी कृषि बैंक खड़ा करके उसके द्वारा कम ब्याज पर ऋण और कृषि के औजार दिलाएगा।

३ किसानों के ऊपर लदा हुआ सामन्ती शोषकों का अनुचित कर्ज खतम कर जनता की एक तमस्सुक जांच कमीशन खड़ी करके नाजायज तमस्सुक को रद्द करेगा।

४ देश को सच्चे तौर से औद्योगीकरण करने के लिए इच्छुक जातीय पूंजीपतियों के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देकर बढ़ाएगा। भारत से आकर नेपाल में व्यापार करने वाले छोटे-छोटे व्यापारी लोग नेपाल में कमाई हुई पूंजी को भारत में न ले जाकर नेपाल के ही उद्योग में लगाते हैं तो उन लोगों के प्रति हमारा व्यवहार जातीय पूंजीपतियों की तरह होगा।

५ छोटे-छोटे व्यापारियों को उनके व्यापार में हर प्रकार से व्यापारिक सुविधा

और मदद दी जायगी।

६ मजदूरों को जीवन-निर्वाह के योग्य वेतन आठ घंटे का दिन चौवालीस घंटे का हफ्ता संगठन और हड़ताल करने का हक और उद्योग-धंधा चलाने वाले बोर्ड में बराबर भाग दिलाता। स्वतन्त्र काम करने वाले दस्तकारों के लिए तो ६ घंटे का दिन होगा।

७ महिलाओं को बराबर (समान) कार्य में समान वेतन दिलाएगा। जातीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के समान हक देश और इसको योग्य बनाने के लिए हर संभव उपायों से उन लोगों की सहायता की जायगी। मजदूर-स्त्री के लिए प्रसव के पहले एक महीने और बाद को दो महीने सवेतनिक छुट्टी दिलाएगा।

८ धर्म की आड़ में होने वाले शोषण को समाप्त करेगा लेकिन पूजा-पाठ करने के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्ण रूप से दिलाएगा।

९. देश में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दिलाएगा।

१० उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आदि खुलवाएगा।

११ जनता के मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा।

१२ देश की सभी जाति अथवा वर्ग के मनुष्यों में भेद भाव न रखकर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिया जायगा।

१३ स्वतन्त्र न्यायालय चुनाव करके खड़ा किया जायगा परन्तु यदि निर्वाचित व्यक्तियों ने भी अपनी जिम्मेवारी की पाबन्दी को ख्याल में न रखा तो उन लोगों को बर्खास्त करने का अधिकार भी वोटरों के आधीन होगा।

१४ देश में महामारी को रोकने के लिए पहले से बन्दोबस्त करने के लिए और जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए केन्द्र-केन्द्र में अस्पताल और सूतिका-गृहों को खुलवाने का आयोजन करेगा।

१५ भारत और चीन से विशेष राजनीतिक सम्बन्ध रखेगा और अन्य प्रजातान्त्रिक देशों से भी पारस्परिक लाभ के आधार पर सम्बन्ध कायम करेगा।

इस समय संयुक्त मोर्चा निम्नलिखित तात्कालिक माँगों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है —

१ नपाल में अंग्रेज-अमरीकी पूजी को घुसने नहीं दिया जाय लेकिन जनवादी चीन अन्य जनवादी राष्ट्र और भारत से भी अपने राष्ट्र के लाभ के आधार में राष्ट्र का औद्योगीकरण करने के लिए पूजी ली जाय।

२ इस अन्तरिम काल के लिए समस्त प्रगतिशील राजनीतिक दल जन और वर्गीय संगठनों के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति का गठन किया जाय। यह समिति अपने में से एक मंत्रिमण्डल चुनेगी जिसके तत्वावधान में विधान-सभा को बुलाया जाय। मंत्रिमण्डल सलाहकार समिति के प्रति उत्तरदायी होगा।

३ राजा और सामन्तों की भूमि और कृषि-साधन उन लोगों को मध्यवर्गीय जीवन-

स्तर के अनुसार जीवनयापन करने के लिए जमीन देकर बिना मुआवजा जब्त किये कार्य और गरीब किसान खेतिहर मजदूरों में बांटा जाय। परती जमीन को किसानों में बांट कर आबाद कराने के लिए सरकार से सहायता दी जाय।

४ मजदूरों के संगठन और हड़ताल करने के मामले में सरकार की तरफ से कुठाराघात न हो। उन लोगों की इस समय की मांग को पूरा किया जाय। उन लोगों की छँटनी भी बन्द की जाय।

५ सुरक्षा कानून प्रेस कानून तथा अन्य दमनकारी कानूनों को रद्द करके जनता को पूर्ण रूप से नागरिक अधिकार प्रदान किये जायें।

६ स्वतन्त्र न्यायालय की स्थापना सलाहकार समिति द्वारा की जाय और न्यायाधीश को वापस बुलाने का हक भी उसी समिति को दिया जाय।

७ मंत्री और अन्य अधिक वेतन पाने वालों जागीरदारों के वेतनों में कमी करके सभी न्यूनवेतनिक कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह करने के उपयुक्त तलब कर दिया जाय।

८ पुरानी फौज को रक्षा दल की भांति सुविधा और तलब दिया जाय। रक्षा दल को किसी भी दल अथवा संस्था की सेना के रूप में न रखकर सरकारी फौज में मिलाया जाय। पुरानी फौज और रक्षा दल के आतंककारी रूप को हटाने के लिए उन लोगों को देशसेवक रूप में विकसित किया जाय।

९ सेना और पुलिस का खर्च घटाकर शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ाया जाय।

१ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्कूल कालेज अस्पताल और सूतिका-गृह इत्यादि का प्रबन्ध किया जाय।

११ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त आयोग नियुक्त कर विदेशी मुद्रा प्रचलन और स्फीति रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जाय।

१२ देश भर में शीघ्र ही मार्ग अथवा यातायात का प्रबन्ध किया जाय। डाक के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करके—डाक के अभाव के स्थानों में उसकी पूर्ति की जाय।

१३ देश में पशुपालन गृह-उद्योग का प्रचार और वृद्धि की जाय। जंगल रक्षा का सुप्रबन्ध भी किया जाय।

१४ भारत के ममता की गई ब्रिटिश-नेपाल फौजी संधि को रद्द करके नेपाल से गोरखा फौज बुलाई जाय। इस फौज की रोटी-रोजी का प्रबन्ध भी किया जाय।

१५ जनवादी चीन से दौत्य और मैत्री सम्बन्ध शीघ्रातिशीघ्र कायम किये जायें।

संयुक्त मोर्चा और अन्तर्जातीय क्षेत्र

यह स्पष्ट है कि आज संसार दो भागों में विभक्त हो गया है। एक तरफ अमरीकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में विभिन्न साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी सरकार और उनके पिट्ठुओं की जनवाद-विरोधी कैम्प है तथा दूसरी ओर समाजवादी और जनवादी देशों

के नतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी और शान्तिवादी कैम्प है। पहले कैम्प का मुख्य ध्येय अपने स्वार्थ के निमित्त दूसरों के देश का हड़पना जातीय मुक्ति-आन्दोलन को दबाना और विश्व-शान्ति और जनवाद में बाधा डालकर तृतीय विश्व-युद्ध की तैयारी करना है और दूसरे कैम्प का मुख्य ध्येय विश्व में शान्ति और सुरक्षा कायम करना है। हमारा संयुक्त मोर्चा विश्व-शान्ति चाहता है। साम्राज्यवादियों के युद्ध को उपनिवेशों में चल रहे हैं वह उनका विरोध करता है। संयुक्त मोर्चा विश्व के प्रगतिशील तत्त्वों के प्रति और साथ ही मुक्ति-आन्दोलन के प्रति सदा सहानुभूति रखता है।

संयुक्त मोर्चा और विश्व-शान्ति आन्दोलन

नेपाल विश्व-युद्ध की चोट से बच नहीं सका है। प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्ध में हमारे लाखों भाइयों के प्राण इन साम्राज्यवादियों की स्वार्थ-रक्षा के लिए बलिदान हो गये यह हम सबों को विदित है। इसका फल यह हुआ कि हमारी कितनी बहिनें विधवा हुई उन लाखों की जिन्दगी बरबाद हुई कितने ही बालक-बालिकाएं अनाथ हो गये और कितने ही मां-बाप पुत्र-शोक से विह्वल हो गये। फिर लड़ाई के बाद जो आर्थिक संकट पूंजीवादी संसार में फैला उसकी चपेट में आने से नेपाल भी बच नहीं सका। आज नेपाल में भयानक आर्थिक संकट और दुर्भिक्ष है। पूंजीवादी संसार भर में यही हालत है। साम्राज्यवादियों को जनता की इच्छा से कोई मतलब नहीं सिर्फ अपनी थैली भरनी है। अपनी स्वार्थ-रक्षा के लिए साम्राज्यवादी तृतीय विश्व-युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे समाजवादी रूस और जनवादी चीन को अपना मुख्य शत्रु समझते हैं। इसलिए आज वे उन मुल्कों के चारो तरफ फौजी अड्डा बना रहे हैं। सैनिक समान की चेष्टा जारी है। इन्हीं फौजी अड्डों के अन्दर एक नेपाल भी है। यदि नेपाल साम्राज्यवादियों का फौजी अड्डा बन गया तो बम गोले झोंपड़ियों और महलों गली और सड़क मस्जिदों और मन्दिरों को भस्म नहीं करेंगे। सब नेपाल की जनता ध्वस्त होगी। नेपाल और नेपाल की जनता की इस तरह की बरबादी हम कदापि देख नहीं सकते। इसके लिए हम लोग आज ही से संघर्ष करेंगे और नेपाल को युद्ध का अखाड़ा किसी हालत में भी नहीं बनने देंगे।

विश्व की शान्तिप्रिय जनता के संयुक्त-विरोध के कारण अमरीकी साम्राज्यवाद कोरिया में अणुबम गिराने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी आवाज उसके गले ही में अटक गई। यह शान्तिवादियों की महान् विजय है। विश्व-शान्ति कायम रखने के लिए रूस चीन फ्रांस विलायत और अमरीका के बीच में शान्ति-संधि होनी चाहिए। यह विश्व-शान्ति के लिए जोरों से आन्दोलन चला रही है। इस आन्दोलन का संयुक्त मोर्चा हृदय से समर्थन करता है और इसको और मजबूत बनाने के लिए नेपाल की जनता प्रतिज्ञा करती है।

संयुक्त मोर्चा की ऐतिहासिक आवश्यकता और देशवासियों के कर्तव्य

नेपाल का जातीय मुक्ति-आन्दोलन आज नया कदम बढ़ा रहा है। जनता का प्रबल

विरोध होते हुए भी अंग्रेज अमरीकी साम्राज्यवाद भारतीय पूंजीवाद और देसी प्रतिक्रियावादी दिल्ली-समझौता करने में सफल हो गये। इसके विरुद्ध किया गया संघर्ष पहली अवस्था हो में कुचल दिया गया। लेकिन यह राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति जो दिन-प्रति दिन खराब होती जा रही है और मजदूर, किसान महिला विद्यार्थी इत्यादि का दिन पर दिन बढ़ता हुआ संघर्ष एक मजबूत संयुक्त नेतृत्व की माँग कर रहा था। संयुक्त मोर्चा इसी ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए खड़ा हुआ है।

यदि संसार की तरफ देखा जाय तो संसार के अधिकांश भागों में सामन्तवादी और प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर आगे बढ़ती हुई जनता नजर आएगी। चीन में जनता के संयुक्त मोर्चे ने अमरीकी साम्राज्यवाद और च्याङ-काई शक को समाप्त कर दिया। कोरिया की बहादुर जनता संयुक्त मोर्चा बनाकर अमरीकी साम्राज्यवाद और सिंगमन री के विरुद्ध जोड़-तोड़ से लड़ रही है। वियतनाम में जनता संयुक्त मोर्चा बनाकर देश के सभी प्रतिशत भागों में जनता की सरकार कायम करने में सफल हुई। ऐसे ही फिलीपाइन मलाया स्याम बर्मा आदि देशों की जनता भी संयुक्त मोर्चे के बल पर काम कर रही है। हमारे पड़ौसी भारत में भी प्रगतिशील शक्तियाँ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए जी-जान से कोशिश कर रही है और उन लोगों का प्रयास सफल हो रहा है। नेपाल की विभिन्न शक्तियों के अथक परिश्रम से हमारा भी संयुक्त मोर्चा कायम हुआ है। यह बड़ी खुशी की बात है।

संयुक्त मोर्चे की ऐतिहासिक आवश्यकता के बारे में हम लोग देशवासियों को बहुत कह चुके हैं।

यह स्पष्ट हो चुका है कि जब तक नेपाल में साम्राज्यवाद और सामन्तवाद रहेगा तब तक नेपाल के मजदूर, किसान मध्यवर्ग जातीय पूंजीपति महिला विद्यार्थी लेखक पत्रकार इत्यादि किसी की भी उन्नति नहीं हो सकेगी। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि नेपाल के हम सब वर्ग मिलकर संयुक्त मोर्चे को मजबूत बनाने से ही अपनी उन्नति हो सकेगी। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि सारे देशवासी इसमें उत्साहपूर्वक पूरा सहयोग देंगे।

विश्व की समस्त जनता और उनके प्रगतिशील आन्दोलन को हमारा संयुक्त मोर्चा दिल से समर्थन करता है। भारत और चीन हमारे पड़ौसी होने से इन दोनों राष्ट्रों से हमारा आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। इसलिए इन तीनों देशों की जनता में सब प्रकार की एकता कायम होनी चाहिए। हम भारत और चीन की जनता को विशेष रूप से आग्रह करते हैं। इसके साथ ही हम विश्व की जनता से यह अपील भी करते हैं कि हमारे जनवादी आन्दोलन को जैसे पहले से समर्थन करते हुए आए है उसी प्रकार अब भी करते जायेंगे।

नया वातावरण

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा कोइराला सरकार की तानाशाही को समाप्त

करने तथा देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के निमित्त खड़ा हुआ था। उसने नेपाली कांग्रेस की सरकार की जड़ें भी थोड़े ही समय में हिला दीं और मंत्रिमण्डल भंग होने की हालत में पहुँच गया। यद्यपि यह मोर्चा बहुत समय तक कायम नहीं रहा तथापि उसने एक ऐसे वातावरण की सृष्टि कर दी जो कालान्तर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

सिंह दरबार काण्ड

राजधानी की जनता नेपाली कांग्रेस की राष्ट्रघाती नीति से बहुत तंग आ गयी थी इसलिए उसने उसका सक्रिय विरोध किया। नेपाली कांग्रेस की सरकार डाक्टर के. आई. सिंह आदि को दण्ड देकर सारा अपराध भारत सरकार के ऊपर मढ़ देना चाहती थी। इस बात को राजधानी की जनता तथा राष्ट्रीय सेना भली भांति जानती थी। इसके बावजूद भी कांग्रेसी सरकार धांधली पर आमादा थी यद्यपि मुक्ति सेना डाक्टर के आई सिंह को अच्छी नजर से देखती थी।

नेपाल की राजधानी काठमाण्डू की जनता ने पड़ोसी जनवादी नये चीन के साथ भी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की मांग की। उसने अन्तरिम काल में एक सर्वदलीय सरकार की भी मांग की। वह डाक्टर के आई सिंह को डाकू तथा खूनी न मान कर नेपाल का राष्ट्रीय नेता मानती थी।



डॉ० कुँवर इंद्रसिंह तथा कर्नल खड्गबहादुर सिंह गुरुंग

२२ जनवरी सन् १९५२ ई० को साढ़े ग्यारह बजे रात्रि में डाक्टर के. आई. सिंह तथा कर्नल खड्ग बहादुर सिंह गुरुंग तथा उनके अन्य साथी जेल से बाहर निकल पड़े। सिंह दरबार से निकलते ही डाक्टर सिंह ने बिना रक्तपात

रक्षा दल के सैनिकों की सहायता से सचिवालय सरकारी कोष रेडियो हाउस स्त्रागार, तोपखाना बारूदखाना तथा गोचर हवाई अड्डे को अपने अधिकार में कर लिया। रक्षा दल के सैनिको ने रात्रि ही में अन्तरिम सरकार के सभी मंत्रियों को समाप्त र नारायण हिट्टी दरबार को भी तोप से उड़ा देने की योजना बना ली थी किन्तु डाक्टर सिंह ने सभी सैनिकों को अहिंसा ही से काम लेने तथा राष्ट्रीय सेना का बिना रोक-टोक के विचार से लेने की आज्ञा दे दी। सारी राजधानी पर डाक्टर सिंह का बारह घंटा आधिपत्य रहा और वह नेपाल के सर्वेसर्वा रहे। सभी मंत्री शाही भवन में शरण लिये रहे। दूसरे दिन तड़के ही उन्होंने टंक प्रसाद आचार्य तथा मंत्री सूर्यप्रसाद सिंह को बुला भेजा। डा के आई सिंह ने सारी शक्ति प्राप्त करके भी दूरदर्शिता से काम लिया। उन्होंने शान्तिपूर्वक समझौते द्वारा अपनी सारी माँगें पूरी कराने की कोशिश की। डाक्टर के. आई सिंह ने इसी अभिप्राय से 'शान्ति संदेश' देकर महाराजाधिराज तथा सभी भयभीत मंत्रियों को जो नारायण हिट्टी दरबार में शरण लिये हुए थे अभयदान दे दिया। डाक्टर क. आई सिंह ने टंक प्रसाद आचार्य कुँवर इन्द्र सिंह तथा गणेशमान सिंह के द्वारा अपनी माँग महाराजाधिराज के पास भेजी। वह सभी प्रगतिशील राष्ट्रों से मैत्री स्थापित करके नेपाल के पड़ोसी भारत और चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध कायम करने देश में एक सर्वदलीय सरकार खड़ी करने एक राजनीतिक सम्मेलन बुला कर उसके निर्णय को मान्यता देने शान्ति से सब काम करने पंचवर्षीय योजना को



डॉ के. आई. सिंह

अविलम्ब कार्यान्वित करने तथा सर्वोत्तम के मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। शासन के सभी अंग डा सिंह के अधीन थे किन्तु उन्होंने रक्तपात बचाने के विचार से राजधानी म उपद्रव नहीं होने दिया। थोड़े ही घण्टों में डा सिंह को ऐसा आभास मिला कि यदि उन्होंने तुरन्त ही अपने आधिपत्य का परित्याग नहीं किया तो काठमाण्डू में रक्तपात हुए बिना न रहेगा। इसस वह स्वयं स्वदेश छोड़कर तिब्बत की ओर प्रयाण कर गये। नपाल सरकार ने तिब्बत सरकार से डाक्टर के आई सिंह को पकड़कर नपाल भज देने की अपील की किन्तु ल्हासा की सरकार ने डाक्टर सिंह तथा उनके सभी साथियों को नव चीन की राजधानी पेकिंग भेज दिया जहाँ वह चीन की जनवादी सरकार के अतिथि बना

लिये गये।

परामर्शदातृ समिति

इस बीच में नेपाल में मातृका प्रसाद कोइराला की अध्यक्षता में जो नयी सरकार स्थापित हुई थी उसमें पारस्परिक मतभेदों के फलस्वरूप दिन-प्रति-दिन झगड़े बढ़ते ही गये और अन्त में महाराजाधिराज को बाध्य होकर उसका तथा सलाहकार सभा का अन्त कर देना पड़ा और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेनी पड़ी। इस अवसर पर जो शाही घोषणा हुई वह इस प्रकार है—

हमारी प्यारी प्रजा

मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्य तथा हमारे प्रधान मंत्री श्री मातृका प्रसाद कोइराला द्वारा अपने पदों का त्यागपत्र देने के कारण मंत्रिमण्डल भंग हो गया है। वर्तमान परिस्थिति में सहयोगपूर्वक प्रजा-हित के लिए अच्छी तरह काम चलाने लायक तत्काल किसी नये मंत्रिमण्डल का गठन सम्भव नहीं है। किन्तु देश की इस गम्भीर और नाजुक परिस्थिति में शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार की दिलाई और खोखलापन न आने देने के लिए तत्काल ही इसकी व्यवस्था भी अत्यावश्यक हो उठी है। अतः देश की विभिन्न वर्गीय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने इस प्रिय देश का शासन सञ्चालन-कार्य कुछ परामर्शदाताओं की सहायता से चलाने का निश्चय करते हुए हम ने पांच सलाहकारों की नियुक्ति की है जिनकी नामावली इस प्रकार है—

१ श्री जनरल केसर शमशेर।
२ श्री मेजर जनरल महावीर शमशेर।
३ श्री खड्गमान सिंह।
४ श्री लेफ्टिनेन्ट जनरल सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत।
५ श्री काजी माणिक लाल।

उपरोक्त परामर्शदातागण हमारी इच्छानुसार अपने पदों पर कायम रहते हुए हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे। सहयोगपूर्वक एक प्रकार से स्थायी हो सकने वाले कार्यक्षम प्रभावशाली तथा जन विश्वास और सम्भावना प्राप्त करके जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने लायक किसी मंत्रिमण्डल का सहयोग और सहायता प्राप्त न होने तक हमारा यह उपरोक्त प्रबन्ध कायम रहेगा।

हमारे विश्वासपात्र प्रधान मंत्री श्री मातृका प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में भूतपूर्व मंत्रिमण्डल ने जनता की सेवा करने का भरसक प्रयत्न किया है। अतः प्रत्येक मंत्री द्वारा किये गए उनके सुकार्यों की मैं प्रशंसा करता हूं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री और अन्य सभी मंत्रियों को उनकी भक्ति-पूर्ण सेवा के लिए, हमारा धन्यवाद है। आज मंत्रि-पद पर न रहते हुए भी उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से भलाई और देश की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सरकार को प्रत्येक सम्भव सहायता प्राप्त होती रहेगी ऐसी मेरी

जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रजा वर्ग से सरकार को उत्तरदायित्वपूर्ण तथा महत्त्व पूर्ण कार्यों में सम्पूर्ण सहयोग मिलता रहे और देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थिर रहे तभी हम उन्नति और प्रगति मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। इस शान्ति और सुव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सभी का सम्पूर्ण सहयोग अत्यावश्यक है। हमारी यह भी इच्छा है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने कामों को ईमानदारी तत्परता और निष्ठापूर्वक करने में संलग्न रहें। प्रजातान्त्रिक पद्धति में सरकारी कर्मचारियों को राजनैतिक संस्था और दलबन्दियों से सर्वथा पृथक ही रहना पड़ता है तथा व्यक्तिगत काम और लालच से अपने को मुक्त रखकर निष्पक्षता और राजभक्ति की परम्परा की स्थापना करनी पड़ती है। सचिवालय का उत्तरदायित्व अब और अधिक हो गया है। उसके सभी कर्मचारियों में अब उच्चतम प्रवीणता तथा दक्षता की आवश्यकता है। उन कर्मचारियों में अब इन गुणों का अभाव नहीं रहना चाहिए। हमारी इच्छा है कि देश और जनकल्याण के लिए 'नमक-हलाली' का ख्याल रखते हुए, हमारी राजभक्त सेना तथा पुलिस भी निष्पक्षता और ईमान दारी के साथ अपना-अपना कार्य करती रहे। हमारी राजभक्त सेना का अविच्छिन्न राज भक्ति तथा ईमानदारी का इतिहास प्रसिद्ध है। देश और राजा के प्रति जन्मजात वफादार हमारी सेना के जवानों ने और अफसरों ने गम्भीर और विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए अनेकों साहसिक विजय प्राप्त की है और इसमें हमें आज भी शक नहीं है कि हमारे फौजी जवान तथा सेना के अफसर वर्ग अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास में किसी प्रकार का धब्बा और कलंक न लगने देकर उसकी स्वर्णिम उज्ज्वलता को कायम ही रखेंगे। हमारे सैनिकों की बहादुरी संसारप्रसिद्ध है और हमें पूरा विश्वास है कि देश में शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए, जनता की भलाई और उन्नति के लिए उनका सहयोग और भक्तिपूर्ण सेवा सम्पूर्ण मात्रा में प्राप्त होती रहेगी।

सलाहकार सभा का काम समाप्त हो चुका है किन्तु इधर उसकी बैठक स्थगित है। देश के विभिन्न भाग और वर्गों से आने के कारण सलाहकार सभा के सदस्यों से देश के शासन राज्यालय में प्रचुर सहायता प्राप्त हो सकती है। इस संकट काल में मंत्रिमण्डल न रहने के कारण यद्यपि सलाहकार सभा से अपने उसी रूप में हमें सहायता नहीं मिल सकेगी फिर भी सभा के सदस्यों से हमारी आशा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार और शासन को सहायता देते रहेंगे।

हमारी इन शुभ इच्छाओं को कार्यान्वित करने के लिए नेपाल अन्तरिम शासन विधान (संवत् २ ८) में यथानुकूल संशोधन शीघ्र हो ही जायगा। हम आशा करते हैं कि सहयोग सद्भावना कायम रखते हुए, एक प्रकार से स्थायी हो सकने वाले सक्रिय और प्रभावशाली मंत्रिमण्डल के संगठन की संभावना न हो सकने तक हमारी प्रिय प्रजा के हित और कल्याण के लिए किया गया यह प्रबन्ध सुचारु रूप से चलता रहेगा।

इस वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार शासन-व्यवस्था से सम्बद्ध सभी का प्रजाहित के

निमित्त समुचित प्रयास करने का, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में पक्षपात को निर्मूल करने का, जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, मौलिक हकों की स्पष्ट परिभाषा तथा व्याख्या करने का और संविधान सभा के लिए सम्भव शीघ्रता-पूर्वक चुनाव करवाने का सर्वप्रथम कर्तव्य होगा ।

श्री पशुपतिनाथ और श्री गुह्येश्वरी माता से हमारी प्रार्थना है कि हमारी प्यारी प्रजा और सभी की भलाई के निमित्त हमारे द्वारा किये गये इस प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिए हमें और हमारे सभी मातहतों को बल प्रदान करें ।

नारायण हिटी दरबार,
काठमाण्डू
शुभ संवत् २००९ साल श्रावण १० गते रोज ५ शुभम् ।

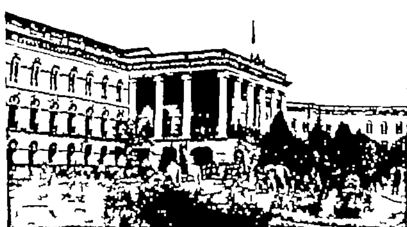
परामर्शदातृ सरकार की नियुक्ति को राजनीतिक संस्थाओं ने एक प्रतिक्रियावादी कदम ठहराया और वे सब एकस्वर होकर प्रजातान्त्रिक आधार पर बनी एक सर्वदलीय मंत्रिमण्डल की माँग करने लगे । यह सरकार राजनीतिक संस्थाओं के लिए एक चुनौती सिद्ध हुई । बाद में परामर्शदातृ सरकार के प्रमुख सलाहकार जनरल केसर शमशेर बनाए गये । यह सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकी और वह भंग हो गई ।

नया मन्त्रिमण्डल

नरेश ने मातृका प्रसाद कोइराला से नया मंत्रिमण्डल बनाने को कहा । उन्होंने १५ १ १९५३ को अपने ही दल 'राष्ट्रीय प्रजा पार्टी' की नई सरकार बनायी । जिसमें त्रिपुरवर सिंह, सूर्यनाथ दास यादव, भारतमुनि पुर्जुंग, महावीर शमशेर मंत्री हुए ।

राष्ट्रीय प्रजा पार्टी की सरकार में कुल पाँच व्यक्ति थे जिनमें चार संस्था के तथा एक स्वतन्त्र सदस्य थे । केन्द्रीय सरकार की कमजोरी से जिलों में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की मात्रा बढ़ चली । राजधानी में भी नेपाली मुद्रा का विनिमय भाव काफी नीचे गिर गया । इसके अतिरिक्त सरकार की कमजोरी का पता पाकर तराई में किसान आन्दोलन भी जोर पकड़ने लगा । इस प्रकार के आन्दोलन सामन्ती शोषकों के विरुद्ध छिड़े । इसमें सरकार अपनी स्थिति सँभालने ही में व्यस्त रही । पश्चिमी नेपाल के डोटी प्रान्त में बाजार चढ़ने की महँगी और मुनाफाखोरी से तमाम जनता उठ खड़ी हुई और केन्द्रीय सरकार को विवश होकर भारत सरकार से सैनिक सहायता लेनी पड़ी । इस क्रम में डोटी के वीर भीम दत्त पन्त के साथ उनके सभी साथी शहीद हुए । इसके थोड़े ही दिनों बाद महाराजाधिराज अस्वस्थ हो गए और अपनी चिकित्सा के लिए देश के बाहर जाना उनके लिए अनिवार्य हो गया । दूसरी ओर शासन में भी काफी गड़बड़ी थी । इसी अभिप्राय से २० सितम्बर, सन् १९५३ ई०, को महाराजाधिराज ने अपनी अनुपस्थिति में कार्य-संचालन के लिए एक राजकीय परिषद् भी खड़ी की । इस परिषद् के सदस्य युवराजाधिराज तथा

प्रथम और द्वितीय महारानियाँ नियुक्त किये गये। नरेश ने राजकीय परिषद् के लिए एक विधान की स्वीकृति भी दी जिसके अनुसार मन्त्रिमण्डल द्वारा पास किये विषयों पर आवश्यकतानुसार लाल मोहर लगाने तथा उन पर स्वीकृतियाँ देने के अधिकार दिये गये। राजकीय परिषद् को मन्त्रिमण्डल भंग करने अथवा उसमें परिवर्तन करने के अधिकार नहीं दिये गये। इसके अतिरिक्त उसे पद-नियुक्ति पद-वृद्धि निष्कासन स्थानान्तरण की कार्यवाहियाँ तथा पारिनियमित पद इत्यादि विषयों पर आवश्यकतानुसार सरकारी सहमति देने के अधिकार दिये गये और मन्त्रिमण्डल के निर्णय के विरुद्ध राजकीय परिषद् को कोई कार्यवाही करने से वंचित रखा गया।



नारायण हिटी शाही भवन

राजकीय परिषद् स्थापित करके नरेश अपनी चिकित्सा कराने के लिए यूरोप गये जहाँ वह कई मास रहे। इस बीच राष्ट्रीय प्रजा पार्टी की सरकार की स्थिति डाँवाडोल रही और प्रधान मंत्री अपनी सरकार की स्थिति सँभालने ही में व्यस्त रहे। वह राजनीतिक संस्थाओं से सहयोग करने की बात भी चलाते रहे। स्वदेश लौटने पर महाराजाधिराज ने वस्तुस्थिति को समझ उन्होंने एक दूसरी घोषणा इस प्रकार की कर दी—

हमारी प्यारी प्रजा का यथोचित

हम सबों ने जो प्रजातन्त्र का मार्ग अनुसरण करने का गम्भीर और दृढ़ संकल्प किया था आज ठीक तीन वर्ष पूरे हो गये। अच्छा या छोटा जो कहें इस तीन वर्ष की अवधि के भीतर, उक्त महान् संकल्प को पूरा करने की दिशा की ओर हम लोगों ने कौन-कौन

सफलता प्राप्त की अथवा कौन-कौन बात नहीं कर पाए इन सब बातों का लेखा जोखा करने का समय हुआ जैसा लगता है। उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयत्न में हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई तो भी अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी ही है। हमारे प्रधान मंत्री तथा अन्य अधिकारी वर्ग के यथाशक्ति प्रयत्न होने पर भी संविधान सभा के लिए आम चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। एक समय की बनी हुई सलाहकार सभा को भी उस वक्त की परिस्थिति के कारण विघटन करना पड़ा। उक्त सभा को फिर खड़ा करने का हमारा निश्चय भी विविध कठिनाइयों के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सका है। तथापि आज इस ऐतिहासिक दिवस में उक्त पुनीत संकल्प को दोहराते हुए अपने मार्ग में अटल होकर आगे बढ़ जाना चाहिए, यह महान् उद्देश्य किसी एक व्यक्ति अथवा एक समूह मात्र के प्रयत्न द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। इसके निमित्त तो प्रत्येक तथा सभी नागरिकों को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। प्रजातन्त्र में नागरिकों का बड़ा भारी उत्तरदायित्व होता है। प्रजातन्त्र की बातें करते समय हमें केवल अपने अधिकार का मात्र ख्याल रखकर अपने कर्तव्य का विस्मरण नहीं करना चाहिए। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है और सभी अपने कर्तव्य का पालन करें तभी अधिकार का उपभोग सम्भव होता है—यह बात सभी को याद रखनी चाहिए। जनसाधारण को इस बात का बोध कराने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के ऊपर भी है। ऐसा किये बिना हम लोग अपने उद्देश्य में कदापि सफल नहीं हो सकते हैं।

आज देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा अनिश्चितता का जो वातावरण पैदा हुआ है वह देश तथा जनता किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। यह अनिश्चितता बहुत समय तक रही तो देश के लिए घातक सिद्ध होगी। इसी बात को दृष्टि में रखकर देश में स्थिरता लाने इस अभिप्राय से हमारी यह बहुत पहले से ही इच्छा थी कि देश में यथाशीघ्र एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हो। पर दुर्भाग्यवश अनेक कारणों से जिनमें हमारे देश की भौगोलिक अवस्था और यातायात साधनों के अभाव मुख्य हैं यह कार्य आशा किये हुए समय के भीतर पूरा नहीं हो सका। पर चुनाव-सम्बन्धी सभी कार्य पूरे किये जा रहे हैं। मतदाताओं की नामावली बनाने का काम भी प्रायः समाप्त हो चुका है। चुनाव सम्बन्धी कार्य में किसी किस्म की शिथिलता न हो ऐसा आदेश हम दे चुके हैं और हमें आशा है कि देश की परिस्थिति में कोई विपरीत परिवर्तन न हुआ तो चुनाव जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस महत्त्वपूर्ण कार्य में सभी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा ऐसी आशा हमने की है।

किसी भी देश में प्रगति के लिए एकता और पारस्परिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक होता है यह बात सर्वविदित ही है। पर देश की इस नाजुक और गम्भीर परिस्थिति में भी हमारे देश में एकता और सहयोग के वातावरण को आता न देखकर हमें बहुत ही दुःख है। हमें कहने जरूरत नहीं है कि देश की वर्तमान स्थिति में छोटी-छोटी बात पर भेद-भाव तथा मन-मुटाव करने से देश का बड़ा भारी अकल्याण होगा। इतिहास बताता है कि देश की

स्थिति भावुक होने में केवल संसार के महान् राष्ट्रों के व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत अथवा दलगत स्वार्थ को त्याग आपस के सभी भेदभावों को मिटाकर सम्पूर्ण राष्ट्र के बृहत्तर हित को दृष्टि में रखकर कार्य किये हैं। ऐसा करने वाले राष्ट्र उन्नति के शिखर पर भी पहुँच गये हैं। हमें भी इतिहास का यह सबक हमेशा याद रखना चाहिए।

देश की वर्तमान परिस्थिति को ही लेकर आज जनसाधारण में एक निराशा और उदासीनता फैली हुई है ऐसा हमें महसूस होता है पर इस भावना को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब तो सबों को देश में पुन समान भावी इस उदासीनता को त्यागकर नवीन स्फूर्ति और चेतना के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। देश कोई व्यक्ति अथवा दल की निजी सम्पत्ति नहीं है। यह तो सभी का साझा है और इसको उन्नति की ओर ले जाने की जिम्मेदारी भी सभी के ऊपर है। हमारा यह प्यारा तथा रमणीय देश छोटा होते हुए भी प्राकृतिक धनधान्य सम्पन्न है। ऐसे देश को पाकर भी हम लोग इसकी विकसित नहीं कर पायें तो हमें भविष्य का सन्तति अपराधी साबित करेंगे उस बात को ध्यान में रखकर अदम्य उत्साह और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ देश की प्रगति में हम अपना शक्ति भर योगदान देना चाहिए।

देश में एकता बढ़े इस अभिप्राय से सरकार को यथाशक्ति प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए हमारा किया हुआ अनवरत प्रयत्न प्रायः लोगों को मालूम ही है। उन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप आज राष्ट्रीय आधार में एक विस्तारित मंत्रिमण्डल की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है। हमारे प्रधान मंत्री की सिफारिश पर विचार कर हमने आषाढ़ दो गते २०१० साल के घोषणा के अनुसार मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन किया है। अब मंत्रिमण्डल निम्नलिखित होगा—

१ श्री मातृका प्रसाद कोइराला—प्रधान मंत्री
२ श्री महावीर शमशेर—मंत्री
३ श्री नारद मुनी थुलुङ—मंत्री
४ श्री टंक प्रसाद आचार्य—मंत्री
५ श्री केशर शमशेर—मंत्री
६ श्री दिल्ली रमण रेग्मी—मंत्री
७ श्री भद्रकाली मिश्र—मंत्री

और बाकी तीन नाम पीछे घोषित होंगे।

हमने बहुत बड़ी आशा रखी है कि यह मंत्रिमण्डल सभी में पारस्परिक सहिष्णुता तथा सद्भावना फैलाकर हमारे इस प्यारे देश को विकास तथा निर्माण के मार्ग में अग्रसर कराने में जायगा। पर सरकार कितनी ही अच्छी हो तो भी जनता का सक्रिय सहयोग पाये बिना सफल और प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। अन्त में देश की इस नाजुक तथा गम्भीर परिस्थिति को याद दिलाते हुए हम सारे सभी लोगों से सरकार को अपना यथासाध्य

महत्त्वपूर्ण देन के लिए हृदय से हार्दिक अपील करते हैं।

सरकार के प्रति किए जाने वाली आलोचना के विषय में भी हम कुछ कहना चाहते हैं। सरकार की आलोचना करने का अधिकार सभी का है। सरकार ने कोई भूल नहीं की है अथवा वह नहीं कर सकती है यह भी हम नहीं कह सकते। भूल सब से होती है पर सरकार के प्रत्येक कार्य को केवल छिद्रान्वेष की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए। सरकार द्वारा की हुई भूलों को अवश्य दर्शाना चाहिए, पर साथ ही उसको सुधारने का उपाय भी दिखाना चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार इस किस्म की रचनात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत करेगी और उसके ऊपर उचित विचार भी करेगी क्योंकि मनुष्य भूल से ही शिक्षा लेता है पर केवल व्यक्तिगत दोष मात्र दिखाने वाली आलोचना से कोई काम नहीं बन सकता है। वह केवल पारस्परिक वैमनस्य का एक कारण मात्र ही बन जाता है।

प्रधान न्यायालय के अख्तियार इत्यादि के बारे में फिलहाल कुछ गलत धारणा के जाने के कारण इस विषय में भी कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। अभी सरकार के कार्य कारिणी अंग तथा न्यायालय के अधिकारों के बारे में कुछ शंका उत्पन्न होने से इस शंका के निवारण के लिए गत माघ सात गते को घोषणा करनी पड़ी और उसी कारण से अन्तरिम शासन-विधान तथा प्रधान न्यायालय ऐन में कुछ संशोधन भी करना पड़ा। कानून शब्द और वाक्य की व्याख्या सम्बन्धी एक नया ऐन भी जारी किया है। प्रजातन्त्र को जाम अक्षुण्ण तथा राष्ट्रीय संस्थाओं को बलवती बनाने का हमारा और हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है यह बात सबको समझनी चाहिए। शासन-यन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा प्रधान न्यायालय की प्रतिष्ठा कायम रखकर न्यायाधीशों का दुनिया की निगाह में उच्च रखने के लिए आवश्यकतानुसार परिवर्तन मात्र किया गया है। हमें आशा है कि ये परिवर्तन देश के न्याय-बन्दोबस्त को सुदृढ़ बनाने में तथा दुनिया की पीर और मर्म हटाने में सहायक सिद्ध होंगे।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में हमने अपने इसम भाग की घोषणा में ही जिक्र किया है। हमारा और हमारी सरकार का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण करने का अभिप्राय न तो पहले था और न अब है। हमारी सरकार इस विषय में पहले से ही एक नये कानूनों का तर्जुमा कर रही है वह तर्जुमा पूरा होते ही वह ऐन अविलम्ब जारी होगा।

२००७ साल माघ मासान्त तक के दण्ड और कैद की सजा पाने वाले व्यक्तियों को हमने इस अवसर पर कुछ छूट देने का निश्चय किया है। इस बारे में और विवरण हमारे दूसरे आदेश में निकलेगा।

अन्त में हम लोग सभी के प्रति आज के इस राष्ट्रीय दिवस में अपनी हार्दिक शुभकामना प्रकट करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके अनुग्रह से हमारा कदम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता जाय और प्रत्येक कदम में हमें सफलता प्राप्त हो। जय नेपाल!

राष्ट्रीय सरकार

इसके थोड़े ही दिन बाद मंत्रियों के विभाग के बँटवारे हुए जिसके अनुसार प्रधान मंत्री मातृका प्रसाद कोइराला को राज्य-व्यवस्था और अर्थ, टंक प्रसाद आचार्य को गृह, दिल्ली रमण रेग्मी को विदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन, भद्रकाली मिश्र को कानून, यातायात तथा मजदूर प्रबन्ध मिले, तथा नारद मुनि थुलुंग को वन तथा मालपोत विभाग मिले। कैसर शमशेर को रक्षा, महावीर शमशेर को योजना-विकास तथा भूमि-सुधार विभाग सौंपा गया। राष्ट्रीय सरकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नरेश ने अन्य संस्थाओं से भी वार्ता चलायी, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली और उल्टे उन्हें प्रधान न्यायालय के कानून में मनचिन्हा संशोधन करने एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण करने का जिम्मेदार सिद्ध किया गया।

इस सरकार में राष्ट्रीय प्रजा पार्टी, नेपाल प्रजा परिषद् तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त तीन सदस्य स्वतन्त्र भी थे। उनमें की एकता बनाये रखने के अभिप्राय से वैशाख १९ गते २०११ साल को एक बत्तीस सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है—

राष्ट्रीय सरकार का न्यूनतम कार्यक्रम

देश के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और नेपाल के सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने की इच्छा से प्रेरित होकर इसकी स्वतन्त्रता तथा अखण्डता को सुरक्षित रखते



टंक प्रसाद आचार्य



दिल्ली रमण रेग्मी

हुए इनको इनके इतिहास संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के आवश्यकतानुरूप विकास एवं प्रगति के पथ पर संलग्न होने के लिए राष्ट्रीय सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को यथाशीघ्र कार्यरूप में परिणत करने का निश्चय किया है—

(क) प्रशासकीय व्यवस्था का पुनःसंगठन

इसका उद्देश्य इस व्यवस्था में सब प्रकार के अस्वास्थ्यकर प्रभाव तथा बुराइयों को हटाना भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार को दूर करके इसके साथ मितव्ययी आधुनिकतम और मितव्ययपूर्ण बनाना है।

१ निष्पक्ष विचारधारा वाले विश्वव्यापी प्रतिष्ठावान व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक स्थिरमिष कमिटी सभी नियुक्तियों तथा कर्मचारियों के कार्य का सिंहावलोकन करेगी और अयोग्यता उचित शिक्षा की कमी बकरत से ज्यादा भर्ती वालों और इस सम्बन्ध में जो अनियमिततायें आदि हैं उनके बारे में सरकारी मामलों की छानबीन करके दरबार में पेश करेगी। सरकार उस पर यथासम्भव शीघ्र कार्य करेगी।

२ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग—इसमें प्रतिष्ठित सम्पन्न तथा सच्चे व ईमान वाले स्तर के योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। यह विभाग संगठित खुफिया व्यवस्था का सहयोग प्राप्त करके भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी रखकर छानबीन करेगा। इस विभाग के उपलब्धानुसार प्रशासकीय अदालत अथवा न्यायाधिकार वाली अदालत कानून के आधार पर मामलों को देखकर उचित तथा कड़ा दण्ड देगा। कानून के अन्दर कहीं कोई कमी तथा छिद्र हो तो उसकी फौरन पूर्ति की जायगी।

३ सरकारी कामों में सुविधा प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न कर्मचारी तथा बीच के अधिकारी वर्गों के अधिकार तथा कार्यक्षेत्र की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी।

४ सरकारी प्रचारार्थ स्थापित संघों का प्रशासन पूर्ण निष्पक्ष और तटस्थता के आधार पर किया जायगा और इसके सम्बन्ध में एक नीति सरकार बहुत शीघ्र निर्धारित करेगी।

५ नागरिकों के जीवन और धन के उचित संरक्षण के लिए राज्य में न्याय और व्यवस्था कायम रखने के लिए हथियारबन्द सिपाहियों तथा खुफिया पुलिसों को जो परिस्थिति अनुकूल क्षमता कर सकने में समर्थ हो इस हेतु से ठोस आधार पर आधुनिक ढंग का बनाया जायगा। इसी सम्बन्ध में एक प्रशासनीय रिपोर्ट पेश होगी और स्वीकृत नीति पर सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करेगी।

६ देश का प्रशासनीय विभाजन अवैज्ञानिक तरीके से गठन हुआ है और कतिपय इलाके बहुत ही छोटे से होने से प्रशासन को सरल सम्बद्ध मितव्ययी तथा योग्य बनाने के लिए सरकार जिलों का पुनर्गठन करेगी।

७ सरकार नियुक्ति के सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात् जनसेवा

आयोग को सुचारु रूप से कार्य करने योग्य बनायेगी ।

८ जिलों को प्रशासन योग्य तथा प्रभावकारी बनाया जायगा ।

(ख) अन्य विषय

१ राष्ट्रीय मुद्रा में सर्वांगीण स्थिरता लाने का प्रयत्न होगा ।

२ देश के औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय पूंजी को प्रोत्साहन और संरक्षण मिलेगा ।

३ स्वदेशी व्यापारिक स्वार्थों का समुचित संरक्षण होगा ।

४ बेकारी की समस्या के समाधान के लिए जीविकाओं के नए-नए स्रोत प्रदान किये जायेंगे । ग्रामीण तथा शहरी बेकारी को कम करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं के अन्दर न माल वाले तथा कम खर्च वाले उद्योग-धंधों को कच्चा माल और श्रम सुगमता से उपलब्ध होने वाले जगहों पर स्थापित किये जायेंगे ।

५ देश में न्याय व्यवस्था वैज्ञानिक, कम खर्चीली तथा शीघ्र होने वाली की जायगी । अदालतों को 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' आवेदनपत्र सुनने का अधिकार रहेगा तथा इसी सम्बन्ध में बन्दी को अदालत में हाजिर करने का आदेश भी जारी करने का अधिकार रहेगा ।

६ वैज्ञानिक और उचित तरीके से हिसाब रखने तथा जांच करने की व्यवस्था कायम होगी ।

७ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों में गलत मतलब लगाये जाने वाली बातों को हटाने के लिए इनकी स्पष्ट व्याख्या की जायगी । इसमें देश के सभी नागरिकों को जाति, विश्वास तथा धर्म का भेदभाव न करते हुए भाषण, संगठन, प्रकाशन, व्यवसाय तथा देश के अन्दर आवागमन की स्वतन्त्रता भी निहित रहेगी ।

८ प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत किया जायगा । विश्वविद्यालय, शिक्षक-विद्यालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधानशालाएं शीघ्र स्थापित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

९. एक स्वतन्त्र व्यवस्था के द्वारा यथाशीघ्र स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव किया जायगा ।

१० जिले की आमदनी का एक निश्चित प्रतिशत उसी इलाके के विकास में खर्च किया जायगा और अनुन्नत इलाकों को उचित सहायता देने की व्यवस्था होगी ।

११ परती जमीन आबाद करके निस्सहाय भूमिहीन किसानों में वितरण की व्यवस्था होगी ।

१२ सरकार से सहायताप्राप्त सहकारी संस्थाओं द्वारा सस्ते ब्याज में ग्रामीण जनता को ऋण देने की सुविधा प्रदान की जायगी तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े-बड़े क्षेत्रों में खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायगा ।

१३ किसानों को शीघ्र सहायता देने के उद्देश्य से कानून बनाकर लागू किया जायगा। इसके अन्तर्गत बेदखली से बचने का अधिकार, खेत मालिक तथा खेतिहर के बीच उपज के विभाजन में कमी करके किसानों को फायदा पहुँचाने का प्रबन्ध तथा सभी प्रकार के सामन्ती शोषण और बंठ बेगारी का अन्त होगा।

१४ जमीन की नापी और दर्जा करके उचित रूप में अच्छी और खराब जमीन अलग की जायगी।

१५. ग्रामोद्योग का विकास किया जायगा।

१६ कानून द्वारा मजदूरों की भलाई और उनके हित का संरक्षण होगा।

१७. सभी सामन्ती सुविधाओं तथा बड़-बड़े बिर्तो का अन्तिम रूप से उन्मूलन होगा।

१८ सरकारी पद तथा शिक्षा के सम्बन्ध में पिछड़े हुए प्रदेशों को प्रोत्साहन दिया जायगा।

१९. शीघ्र ही स्थापित होने वाली सलाहकार-सभा में राष्ट्रीय जीवन तथा प्रादेशिक जन विचारधारा के महत्वपूर्ण अंगों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा।

२० नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का प्रयत्न होगा।

२१ वैदेशिक सम्बन्ध में नेपाल भौगोलिक और एतिहासिक मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ जहां तक हो सके अधिक मित्रता कायम रखेगा। साथ ही मित्र राष्ट्र तथा पड़ोसियों से भी मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेगा।

२२ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नेपाल शक्तिशाली गुटों से सम्पर्क न रखकर प्रगतिशील स्वतन्त्र नीति अख्तियार करके विषयों पर उनके महत्व के ऊपर निर्णय दिया जायगा।

(ग) सहायता और सामाजिक भलाई की तात्कालिक योजना

१ राष्ट्रीय साधनों की खोज करने तथा सर्वांगीण विकासार्थ एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक 'राष्ट्रीय योजना आयोग' गठन किया जायगा।

२ एक मुद्रा आयोग मुद्रा समस्या की छानबीन करेगा। विशेषतः यह नेपाली सिक्कों का ह्रास तथा देश में दो प्रकार के मुद्रा-प्रचलन स्थिति तथा उससे हमारे आयात-निर्यात में पड़ हुए कुप्रभावों का अध्ययन करेगी। मुद्रों का सट्टा तथा नाजायज व्यापार दण्डनीय घोषित किया जायगा।

३ सरकार खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग के अन्य पदार्थों की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए फौरन कार्यवाही करेगी। साथ ही ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए सस्ते दामों में मिलने वाली दूकानें तथा इसी प्रकार के अन्य साधन खोले जायेंगे।

सरकार नेपाली मुद्रा के विनिमय मूल्य के ह्रास को रोकने के लिए कारवाई करने के साथ ही एक स्थिर दर में नियंत्रित रखने के लिए उपाय और व्यवस्था करेगी।

४ सरकार सामूहिक विकास-योजनाओं को विभिन्न इलाकों में लागू करेगी और उत्पादन-वृद्धि करने के लिए सिंचाई-योजनाएं तथा वैज्ञानिक खेती के तरीके कार्यरूप में परिणत करेगी।

५ बिजली और पेय-जल की अधिक सुविधा का प्रयत्न किया जायगा।

६ स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे नीचे पंचायत और ऊपरी स्तर में प्रादेशिक बोर्ड स्थापित किये जायेंगे। इनको अपने उचित क्षेत्र के अन्दर विकास करने का पूरा मौका दिया जायगा।

७ सभी क्षेत्रों की जनता में अधिकाधिक औषधियों की सुविधा पहुंचाने की बात ध्यान में रखते हुए जगह-जगह पर औषधालय खोलने की योजना चालू की जायगी।

८ सरकार ने पुनः संगठन आधार पर सामूहिक शिक्षा की योजना चलाने का विचार किया है। इसमें प्रौढ़-साक्षरता आन्दोलन, बाल-शिक्षा आदि समावेश होंगे और उक्त योजना में देश में प्राप्त होने वाले नैतिक प्रतिभा वालों को शामिल किया जायगा।

९ जंगलों की मनमानी कटाई को रोकना सरकार का सर्वप्रथम काम है। कोरा निकासी के जरिए लकड़ी उठा ले जाने का काम बन्द करना और वैज्ञानिक ढंग से जंगल की देखभाल करने की व्यवस्था शीघ्र ही आरम्भ की जायगी।

१० देश को उन्नत व्यापारिक तुलना की स्थिति में पहुंचाने के उद्देश्य से निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ऐसी व्यवस्था का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करेगी।

देश में कई बार राजनीतिक परिवर्तन होने तथा प्रजातान्त्रिक आधार पर मंत्रिमण्डल की नींव न होने से लोगों की यह मांग बहुत समय से रही। दूसरी ओर देश में विधायी आर्थिक तथा वैज्ञानिक कानून के अभाव में भी चारों ओर त्रुटियां दीख पड़ती थीं। इस अभिप्राय से सर्वप्रथम राष्ट्रीय जीवन तथा विभिन्न अंगों के प्रतिनिधियों को लेकर सलाहकार सभा की घोषणा हुई। इसके साथ ही सभा का एक विधान भी तैयार हुआ। सलाहकार सभा का प्रथम अधिवेशन ७ जून सन् १९५४ ई० को आरम्भ हुआ और जिसका उद्घाटन-भाषण नरेश की अस्वस्थता के कारण युवराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह द्वारा हुआ जो देश की सारी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो इस प्रकार है—

सलाहकार सभा के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण

आज इस नवगठित सलाहकार सभा के अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत सम्बोधित करने का मौका पाकर मुझे हर्ष है। मुझे आशा है कि देश के विभिन्न भागों से उपस्थित आप लोग विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श कर देश को आगे बढ़ाने में देश को सुखी और समृद्ध बनाने में मुझे सलाह तथा सहायता देंगे। इस महान् राजनीतिक परिवर्तन के बाद देश को प्रजातान्त्रिक पद्धति पर ले जाना जो मेरी दृढ़ इच्छा तथा अभिलाषा है वह आप लोगों को विदित ही है। पर इन सात वर्षों में देश के लिए जिस राजनीतिक सद्भावना और

सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी वह नहीं हो सकी। यह दोष सभी नेपालियों का है। देश किसी खास व्यक्ति दल या वर्ग का नहीं है देश सबका है और इसकी अवनति उन्नति का फल हम सबों को भुगतना है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। किसी व्यक्ति तथा दल का ध्यान न रखकर देश की सामूहिक उन्नति तथा विकास को ध्यान में रखना समस्त देशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। परिवर्तन के बाद इन तीन वर्षों में सरकार के गठन में कई प्रयोग हुए पर कोई स्थायी न होने से देश में जो उन्नति होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी या नहीं की गई या करने का मौका नहीं मिला। सर्वप्रथम दो दलों की संयुक्त सरकार स्थापित हुई। आपस की खींचातानी तथा एक दूसरे पर दोषारोपण करने से उसका अन्त हुआ। इसके बाद एकदलीय सरकार बनी और आशा की गई कि सरकार कुछ काम करेगी। प्रथम सलाहकार सभा का अधिवेशन भी उसी समय आह्वान किया गया। पर इसके पूर्व कि सरकार कुछ काम करे सरकार बनाने वाले दल में ही आपसी मतभेद हो जाने से उसका भी अन्त हुआ और उसके साथ ही साथ सलाहकार सभा का भी। अन्त में मुझे बाध्य होकर अपने ही हाथ में शासन लेना पड़ा और कुछ परामर्शदाताओं के परामर्श से कुछ महीने शासन चला। मुझे आशा थी कि इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों में सौहार्द तथा सद्भावना उत्पन्न होगी और देश के राजनीतिक वातावरण में कुछ परिवर्तन आयेगा पर विभिन्न प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। इसी बीच मेरा स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरने लगा और उपचार के लिए मुझे विदेश जाना पड़ा। मेरी इच्छा आशानुसार विभिन्न दलों को मिलाकर सम्मिलित सरकार गठन करने की थी पर यह संभव नहीं हो सका और स्थिति अनुसार अपने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को फिर से सरकार गठन करने की अनुमति देनी पड़ी। उस समय भी मेरी आशा तथा अभिलाषा यही थी कि विभिन्न राजनीतिक दल आपस में सौहार्द और सद्भावना बढ़ाकर सरकार में सम्मिलित होकर प्रजातन्त्र को दृढ़ बनाने का उत्तरदायित्व लें। मेरे प्रधान मंत्री के अनवरत प्रयास करने पर भी कुछ महीनों तक यह संभव नहीं हो सका। अन्त में चार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से समझौता हो गया और आज की यह सरकार इसी अथक प्रयास के फलस्वरूप खड़ी है। दूसरे राजनीतिक दलों को भी प्रधान मंत्री ने अवकाश दिया था पर उन लोगों ने यह उत्तरदायित्व लेने से इन्कार किया।

आम निर्वाचन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संगठित सरकार जब तक स्थापित नहीं होती तब तक इस अन्तरिम अवधि में किसी-न-किसी प्रकार की सामयिक सरकार आवश्यक ही है। विभिन्न दलों में हम बड़ा कहने का मापदण्ड बिना जनता की इच्छानुसार मत लिये मैं भला किस को मानूं। अतः सभी दलों के मिलकर काम करने से उनका स्वयं समाधान होते देखकर मैंने राष्ट्रीय सरकार के लिए बराबर जोर दिया है। आज इस सलाहकार सभा के संगठन से मुझे आशा मात्र ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सरकार चलाने की जिम्मेवारी विस्तृत रूप से जनता के प्रतिनिधियों को दे दी गई है। सबों के

परिश्रम सद्भावना तथा सहयोग-बल को प्राप्त कर हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त को विशाल समवाय प्रणाली को सर्वहिताय के लिए सक्रियात्मक स्तर पर ले जाने की दृढ़ इच्छा है। देश और दुनिया के कल्याण के निमित्त इस लक्ष्य और ध्येय को सफल बनाने के लिए सबों के निःस्वार्थ सेवा-सहयोग की परमावश्यकता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की संविधान सभा जब तक कहीं नहीं हो जाती तब तक इस अन्तरिम समय में जनता को अधिकाधिक सरकार के मामले में शरीक तथा लोगों को संविधान की प्रणाली का ज्ञान कराने के अभिप्राय से इस सभा का निर्माण हुआ है। देश के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नयी नहीं होने पर भी नयी-नयी जाग हुए प्रजातन्त्र को सुदृढ़ तथा प्रबल बनाने के लिए इस सभा के सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी।

पुरानी सलाहकार सभा से इसको वृहत्तर बनाकर सभी अंग वर्ग तथा दलों के प्रतिनिधियों के समावेश कराने के मेरे विचारानुसार और आह्वान पर कुछ दल तथा व्यक्तियों ने इसमें भाग लेना भी स्वीकार नहीं किया। सरकार की स्वस्थ आलोचना करने का अवसर देने पर भी इस अवसर को काम में नहीं लाने पर मुझे उत्तरदायित्व न लेने जैसा लगता है। सदस्यगण निःस्वार्थ देश-सेवा की भावना को अपनाकर केवल देश और जनता की वृहत्तर उन्नति भलाई का ही ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य अच्छी तरह निभायेंगे —ऐसी मुझे आशा है। देश में शुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रणाली को पनपने देने में आप लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे यह भी मेरी आशा है। सत्य तथा स्वार्थरहित आलोचना द्वारा देशोन्नति तथा भलाई के काम में मेरी सरकार का सहयोग तथा सहायता करना इस सभा का मुख्य कर्तव्य होगा।

वर्तमान जगत में कोई भी राष्ट्र अकेला पृथक जीवन नहीं व्यतीत कर सकता—यह बात निर्विवाद है। पारस्परिक सहयोग से निकटतर सम्बन्ध स्थापित करते राष्ट्रों को मानव मात्र की भलाई करने के अभिप्राय से प्रगति की ओर अग्रसर होकर उन्नति करनी चाहिए यही युग की माँग है। अतएव हम लोगों को भी उसी मार्ग का अवलम्बन कर सबों से मैत्री तथा सद्भावना रखकर पृथ्वी से अलग रहकर हमारा सार्वभौम सत्ता को अकुण्ठित रखकर प्रगतिशील होकर उन्नति करनी है। इसी नीति के अनुसार प्रगतिशील देशों से मैत्री-सम्बन्ध बढ़ाकर उन्हीं लोगों की सहायता स्वीकार कर भरपूर सर्वतोमुखी उन्नति के लिए कोशिश करने में ही हमारा कल्याण है। विज्ञान में उन्नतिशील स्विट्जरलैण्ड इंग्लैण्ड अमरीका प्रभृति देशों से विशेषज्ञ तथा पूर्ती ही दूसरी सहायता प्राप्त हो चुकी है। हमारे अनेक छात्र उक्त देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये हैं। प्राचीन मित्र पड़ोसी भारत से भी सभी हर आवश्यकीय सहायता ली गई है। भारत से प्राप्त सहायता हमारी भौगोलिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक कारणों से दूसरों से प्रचुरतर है। इस राष्ट्र से हमारा निकटतर सम्बन्ध होना हम दोनों देशों की पारस्परिक समान स्थिति ध्येय नीति इत्यादि के कारण ही है। तथा पड़ोसी पड़ोसी के युग-युग की नयी धारा में शरीक होकर एक दूसरे

का अधिक मददगार होना स्वाभाविक तथा हित की ही बात होना निर्विवाद है। हमारे
बहुत से नागरिक विश्व का भ्रमण करके ग्राम-परिधि-परिवर्तन कर रहे हैं। विदेश के
नागरिक भी नेपाल के प्रति पारस्परिक सौहार्द तथा सहानुभूति काम में सचेष्ट हैं। ईराक
टर्की सर्वेन्गाइना जापान कनाडा से उच्च व्यक्ति नेपाल आते हो रहे हैं। हमारे भी छात्र
यूक्रेनिया आस्ट्रेलिया जापान प्रभृति सुदूर देशों में शिक्षा प्राप्त हो कर रहे हैं। पिछड़े
हुए देश का प्रगतिमान देश से सहायता लेना प्रगतिशाम देश का बिना दान या बिना बन्धन
सहायता देना युग का कर्तव्य माना गया है। इससे पिछड़े हुए देश को मदद करना न तो
स्म की ही बात है और न सहायता लेने पर कोई अवहेलना हो कर सकता है। इस प्रकार
पारस्परिक सहयोगिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को हस्तक्षेप-सा नामकरण करना असंगत
इत्युक्त वातावरणपूर्ण विकृत भावना का परिचय देना मात्र है यह आप लोगों को विदित ही
है। किसी देश-विशेष मात्र से सहायता लेकर अन्यों से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता हो
तो शायद इस प्रकार का आक्षेप समुचित होता। परन्तु नेपाल विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं
जैसे विश्व स्वास्थ्य संघ एफ़ ए ओ, यू एन ई सी ओ कोलम्बो प्लान यू एस ओ ए
(फाइव प्वाइंट फ़ोर) इत्यादि से भी सहायता प्राप्त कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य
होने के लिए सक्रिय है। नेपाल विलायत अमरीका फ्रांस हिन्दुस्तान के साथ दौत्य
सम्बन्ध स्थापित कर चुका है एवम् उत्तर के पड़ोसी से भी हमारा सम्बन्ध अच्छी तरह है
और आवश्यकतानुसार इस सम्बन्ध को मजबूत कर दूसरे देशों से भी सम्बन्ध स्थापित करेंगे।
नेपाल की सार्वभौम सत्ता का सतत संरक्षण करके सबों के साथ मैत्री-भाव रखकर किसी
के प्रभाव में तथा गुटबन्दी में न पड़कर नेपाल को अग्रगामी बनाना हमारी वैदेशिक नीति
है। इस सद्भावनायुक्त नीति को जान-बूझकर भी बदनाम करना सत्य से पारगमन
होना स्वतः सिद्ध होगा ऐसी आशा करते हैं।

हमारी आर्थिक स्थिति शोचनीय है फिर भी इसके सुधार के लिए हम यथाशक्ति
प्रयत्नशील हैं। सर्वसम्पन्न देशों को भी चांदी का सिक्का चालू रखना कठिन होता है फिर
हमारे देश ऐसे गरीब के लिए क्या बात? अब कम्यूप्रामिकेल का सिक्का चालू हो गया है।
इससे चांदी की बचत होकर काफी लाभ होने का अनुमान किया गया है। सन् १९५० के
भारत सरकार के साथ की गई वाणिज्य-संधि को लागू कराने तथा अन्तःशुल्क वापस कराने
के लिए यथोचित कार्रवाई हो रही है।

अन्तःशुल्क वापस होने और किसी नये टैक्स के न लगाने से करीब साठ लाख
रुपए की सरकार को अधिक आय होने का अनुमान किया गया है। चुंगी की आय जो इधर
उधर हो जाती है उसे रोकने के लिए आधुनिक तरीके से चुंगी सुधार सम्बन्धी कार्य हो रहा
है। टैरिफ बोर्ड खड़ी होने से एक ही माल में दो-तीन जगह चुंगी लगने की परिस्थिति हटाकर
जनसाधारण की सुविधा के लिए योजना बन रही है।

हमारी मुद्रा-स्फीति से जनसमुदाय की खलबली मची हुई है। पुराने शासन में सरकार

कम खर्च करने, बचत को प्रचलन में न आने और सम्पन्न हो जाने के कारण मुद्रा का भाव वैसा ही था। प्रजातन्त्र के बाद कम की सब आय वैसा हो न खर्च होने से मुद्रा प्राचुर्य तथा जनता में बढ़ अधिक बढ़ जाने से स्फीति होने का अनुमान होना अनुचित बात नहीं है। प्रचलन में लाये हुए नेपाली मुद्रा का यदि नेपाल भर में प्रचलित किया जाय और हमारे सुदूरपूर्व तथा पश्चिम पहाड़ में जहाँ अभी-अभी नेपाली मुद्रा का प्रचलन हुआ है और इसके पश्चात् समग्र देश भर में यदि यही प्रबन्ध किया जाय तो तीस चालीस करोड़ नेपाली मुद्रा सुगमता से हो बाजार में प्रचलित हो जायगी। इस दृष्टिकोण से समुचित प्रबन्ध हो रहा है और वर्तमान अवमूल्यन स्थायी नहीं होगा ऐसी आशा और विश्वास है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी उन्नति के लिए भी हमारी सरकार ने अपने साधन तथा विदेशी सहायता के जरिए काफी प्रगति की है। इकतीस डिस्पेन्सरी हाल ही में बढ़ाई जानेवाली हैं। नेपाल के अस्पताल के लिए भारत सरकार की ओर से सामान सहित पाँच सौ बिस्तरे मुफ्त प्राप्त हुए हैं। मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया इत्यादि के नियंत्रण के लिए विश्व-स्वास्थ्य संघ से भी सहायता मिली है। नर्सों की ट्रेनिंग भी यथाशीघ्र शुरू होने वाली है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए अलग डाइरेक्टर नियुक्त होकर काम प्रारम्भ हो गया है।

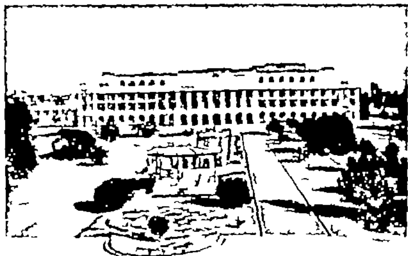
स्वास्थ्य सम्बन्धी सार्वजनिक काम करने वाली सरकारी संस्थाओं को यथासंभव आर्थिक तथा दूसरी प्रकार की सहायता देकर गैरसरकारी संस्थाएँ भी खुलवाने का प्रोत्साहन दिया गया है।

नेपाल में शिक्षा का नितान्त अभाव होने से उसकी पूर्ति के लिए सरकार के साधन सीमित हैं फिर भी यथाशक्ति कार्रवाई हो रही है। नेपाल के लिए उपयुक्त शिक्षा-योजना के लिए शिक्षा-आयोग निर्माण किया जा चुका है। जहाँ पाठशालाएँ नहीं हैं वहाँ दो सौ पचीस पाठशालाएँ खुलने की व्यवस्था होकर कुछ तो सहायता भी पा चुकी हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी यथाशक्ति मदद दी गई है। हाई स्कूल, कालेज, संस्कृत महाविद्यालय इत्यादि भी अभी अभी खोले गए हैं। विदेश में विद्याध्ययन करने वालों को छात्रवृत्ति दी गई है। कोलम्बो प्लान एवं टी० सी० ए० की प्राप्ति द्वारा छात्रवृत्ति पाकर सैकड़ों नेपाली छात्र छात्राएँ विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गए हैं। शिक्षा अतिशय महत्त्व का विषय होने से सरकार ने उसके लिए भरसक प्रयत्न किया है तथापि अभी तक सफलता प्राप्त करने के समुचित मार्ग का अन्वेषण हो रहा है।

देश के प्राकृतिक साधन तथा सामग्री के लिए हमारी सरकार यथाशक्ति कोशिश कर रही है। विभिन्न प्रकार के भौतिक, कृषि तथा खनिज पदार्थ इत्यादि के निरीक्षण तथा जाँच-पड़ताल होने से हमारे इंजीनियरों द्वारा होना प्राय असम्भव-सा था पर प्रगतिशील देशों से सहायता की प्राप्ति आसानी से हमें इस काम में विदेशी विशेषज्ञों से बहुमूल्य सहायता मिली। भौगोलिक सम्बन्ध रखता में आई थी जाने जिससे नेपाल की ओर की माँग पूरी हुई भी जाता है। डाक्टर हागन नामक स्विस विशेषज्ञ ने 'जियालाजी ऑफ नेपाल' नामक

रिपोर्ट तैयार की है। इससे निकट भविष्य में दूसरी भिन्न-भिन्न खानों का काम हो सकेगा जाँच-पड़ताल हो रही है। काठमाण्डू उपत्यका में मिट्टी के कोयले का उपयोग कुछ हिस्सा में हुआ था फिर भी वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं हो पाया था। अब पक्की ईंट बनाने के काम में इससे की काफी बचत होने लगी है और अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर लकड़ी की बचत कर जंगल सुरक्षित रखने का प्रबन्ध होगा। राप्तीदून में चौदह लाख मुरी अर्थात् लगभग एक लाख टन अन्न उत्पादन करने की योजना यथाशीघ्र कार्यान्वित होने वाली है। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य एफ. ए. ओ. से प्राप्त हुए विशेषज्ञ सुन्दर संतोषजनक रूप से कर रहे हैं। कृषि तथा ग्रामोद्योग विकास के लिए त्रिभुवन ग्राम विकास योजना चालू हो गई है। कोसी के खतरे से बचने के लिए भारत सरकार को कोसी बाँध बनाने की इजाजत दी गई है। इस बाँध से हमारे देश को यथेष्ट लाभ होने का विश्वास किया जाता है। तीन महीने के अन्दर शायद सौ किलोवाट बिजली उत्पादन के हेतु एक थर्मल प्लान्ट काठमाण्डू में नियोजित होने वाला है। तिनाऊ सिरसिया दुधौरा योजना तराई में महादेव खोला सिंचाई योजना उपत्यका में ट्यूबवेल योजना आदि कृषि सम्बन्धी योजनाएं भी चालू हो गई हैं। उपर्युक्त विकास के काम को हमारे साधन तथा कोलम्बो प्लान टी. सी. ए. एफ. ओ. आदि से प्राप्त सहायता सम्मिलित कर यथासम्भव शीघ्र सर्वतोमुखी विकास करने के लिए समुचित प्रयत्न हो रहा है। त्रिभुवन राजपथ तथा त्रिशूली योजना के लिए कुल करीब चार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान किया गया है और जो कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत भारत द्वारा प्राप्त होने वाला है। त्रिभुवन राजपथ करीब-करीब बन चुका है और आगामी मौसम से चालू होने का अनुमान किया गया है। यातायात तथा संचार की सुविधाओं से भी देश की उन्नति में काफी मात्रा में बाधा आती है अतएव इस ओर भी सरकार ने यथासम्भव ध्यान दिया है। सड़क-निर्माण में बहुत धन की आवश्यकता पड़ने तथा हमारे साधन की कमी से सड़क-निर्माण वैदेशिक सहायता से कराने की नीति अपनायी गई है। साइकल सड़कें बनाने के लिए भी नेपाली नागरिकों को काफी सहुलियतें दी गई हैं। वायुयान के लिए पाँच-सात जगहों पर हवाई अड्डे भी तैयार हो गये हैं और पहाड़ तराई के सभी प्रमुख स्थानों में आगे से अड्डा जल्द बनाने की योजना है। पाल्पा से बुटवल भैरहवा तक टेलीफोन की लाइन का विस्तार हो चुका है। [illegible] से दाण तक टेलीफोन-लाइन-विस्तार करने के लिए कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं। [illegible] के पन्द्रह-सोलह स्टेशन चालू हो चुके हैं। देश के प्रमुख स्थान से जिससे टेलीफोन या [illegible] हो सकेंगे। यथाशीघ्र सम्बन्ध स्थापित करने की योजना कार्यान्वित हो रही है। भारतीय सीमा निकट के प्रमुख नेपाली पोस्ट आफिसों को एक्सचेंज डाकघरों में परिणत करने के लिए भारत सरकार के साथ लिखा-पढ़ी हो रही है।

काठमाण्डू उपत्यका में राजधानी में टेलीफोन व्यवस्था अविच्छिन्न रूप से चलाने के लिए और कभी भी कुछ गड़बड़ी न होने देने और साथ ही सर्वसाधारण जनता भी इसका



सिंह दरबार

उपयोग कर सकें इस हेतु से पृथ्वी के नीचे तार ले जाने की व्यवस्था के लिए लगातार काम हो रहा है । और वो जल्द ही सम्पन्न होने वाला है ।

उद्योग वाणिज्य में देश कितना पिछड़ा हुआ है यह बात दुबारा कहने की आवश्यकता नहीं है । हमारा देश पिछड़ा हुआ होने से कच्चा माल निर्यात और तैयार माल आयात होता है । विराटनगर की दो जूट मिलों में से एक जूट मिल विराटनगर जूट मिल घाटा भार बढ़ जाने से बन्द में रहकर कुछ महीनों तक बन्द रहा । इस तरह सभी भाँति चालू हुआ मिल बन्द होने से देश के उद्योग में बड़ा आघात लगता है । इसलिए हमारी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक मिल की मदद कर फिर से चालू किया है । दूसरी मिल रघुपति जूट मिल में भी मैनेजिंग एजेन्सी की गड़बड़ गत पाँच वर्ष से झगड़ा होकर मिल चल नहीं पा रहा था । देश के प्रमुख उद्योग होने के कारण और उसमें हमारे नागरिकों के बहुत पैसे फँसे होने से उन्हें बरबाद होने के डर से झगड़ा समाप्त करवाकर मिल को चालू कर साझीदारों तथा देश के हित के लिए मिल की मैनेजिंग एजेन्सी राइट भी खरीदकर उसे चला दिया गया है । आशा है इन दो प्रमुख मिलों के चलने के बाद दूसरी मिलों को भी उन्नति करने में सुविधा होगी । नये उद्योग चालू करने की कोशिश करने से चालू किये हुए उद्योगों का संरक्षण करना ही बेहतर समझकर सरकार ने यह कदम उठाया है ।

वाणिज्य के विषय में भी नेपाल का वाणिज्य अधिकतर भारत से ही होता आया है इसलिए भारत-नेपाल वाणिज्य संधि जो कुछ वर्ष पहले हुई थी पर परिणत अभी तक नहीं हो पायी थी इसी महीने के अन्दर कार्यरूप में परिणत करने की व्यवस्था भी गई है ।

'हरा वन नेपाल का धन' यह बात आप लोगों को मालूम ही है। हम लोग इस धन का पूर्णरूपेण वैज्ञानिक सदुपयोग नहीं कर पाये हैं। स्थिति को सँभालने के लिए भारत से वन विशेषज्ञ मँगाकर इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद ही यथाशीघ्र वैज्ञानिक ढंग से इस धन के संरक्षण तथा संवर्धन करने की सरकार की नीति को कार्यरूप में परिणत करने के लिए सरकार ने निर्माणात्मक सुझाव के लिए सबसे अनुरोध किया है। गत वर्ष जैसा इस वर्ष भी वन महोत्सव मनाने की आवश्यक कार्रवाई हो रही है।

गत ज्येष्ठ १५ को हम सब जनगणना दिवस भी मना चुके हैं। पूर्व तरफ जनगणना का काम २००९ साल में ही समाप्त हो चुका है। पश्चिम ओर यह काम जोर-शोर से हो रहा है। यह बात आप लोगों को मालूम ही है।

निर्वाचन उचित समय में करने की कोशिश हो रही है। अभी तक जो नहीं हो पाया यह दुःख की बात है। निर्वाचन नेपाल के लिए अनूठा बात होने तथा प्रजा में शिक्षा की कमी होने, उचित मात्रा में सहयोग प्राप्त न होने और काम भी महान् होने से काफी समय लग रहा है। चुनाव अफसरों को तालीम देने का काम भी हो रहा है। चुनाव के लिए जिलों को जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों में विभक्त करने का काम भी हो रहा है। अब तक १ ८९,१०८ मतदाताओं की नामावली तैयार हो चुकी है। अब जल्दी ही निर्वाचन होने की आशा है।

मालपोत मुठे भूमि इत्यादि की जटिल समस्या समाधान के लिए सम्बन्धित विभाग क्रियाशील है। क्याडस्ट्रल सर्वे कराने का निर्णय होकर तत्सम्बन्धित योजना आंशिक रूप में कार्यान्वित भी हो चुकी है। इस सर्वे से भूमि-सुधार तथा मालपोत सुधार के लिए भी काफी मदद मिलने की आशा की गई है। समस्या अतिशय जटिल और महान् होने से—आकांक्षित फल साथ ही मिलने की कठिनाई स्वाभाविक ही है। इस पर भी इस महान् कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त होने पर सफलता प्रस्तावित समय के पहले ही मिल सकती है। भूमि-सुधार कमीशन तीन अधिवेशन कर चुका है और फिर अधिवेशन आगामी आषाढ़ में करने की योजना है।

जमींदार तथा किसान की कठिनाइयाँ सुलझाकर उचित व्यवस्था करने के लिए एक भूमि-सुधार-योजना जल्दी ही लागू करने के लिए चलती-फिरती अदालतें भेजने की कार्रवाई सरकार कर रही है।

मोबाइल कोर्टों के नियम तैयार हो जाने के बाद तुरन्त ही उन्हें जिले-जिले में भेजकर जमींदारों तथा किसानों की कठिनाइयाँ दूर करने की आशा की गई है।

देश की आन्तरिक तथा बाहरी सुरक्षा के लिए राष्ट्रसेना और पुलिस की उपयोगिता सर्वविदित ही है। नव रक्षादल तथा सेना के क्रमीकरण पुनर्गठन कर नया तालीम देने की बात आप लोगों को विदित ही है। पुलिस भी राष्ट्र के आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था का अंग

होने से इसका भी उचित पुनर्गठन वांछनीय होने से काम जोरों के साथ चालू है। राष्ट्र के लिए पुलिस संगठन में विभिन्न तरीके इकाइयाँ होने से सबको एकीकरण के साथ वर्गीकरण करने का काम अच्छी तरह हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे पुलिस आफिसरों में से एक माउन्ट आबू के ट्रेनिंग कालेज से आई० पी० की तालीम तथा आठ मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके आ गये हैं।

जिले-जिले में शान्ति भंग करने वाले तत्वों को यथोचित रूप से पकड़ने और बन्दी करने के लिए बड़े हाकिमों को सुरक्षा कानून प्रयोग करने के अधिकार दे दिये गए हैं। यह अधिकार परिस्थितिवश आवश्यक होने से दिए गये हैं। फिर भी प्रधान न्यायालय ने इसका विरोध कर वैसे तत्वों को मुक्त कर मंत्रिमण्डल का कार्यकारिणी अधिकार नहीं है ऐसा निर्णय फुल बेंच द्वारा देने से देश में ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन मिलने से सरकार की कार्यकारिणी शक्ति की अवहेलना हो जाने और देशव्यापी विप्लव हो जाने की भी आशंका से प्रधान न्यायालय के कानून में संशोधन करना आवश्यक हो जाने से प्रधान न्यायालय के कानून में संशोधन कर दिया गया है।


सरकार महेन्द्र वीर विक्रम शाह

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण करने की निराधार आशंकाओं का खण्डन करते हुए हमने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं हुआ है यह सुरक्षित है—कहकर फाल्गुन ७ २०१० में घोषणा की थी। इसका समर्थन हम यहाँ भी करते हैं। शासन के प्रत्येक अंग विधान तथा कानून के बन्धन हो जायें यही मेरा अभिप्राय है।

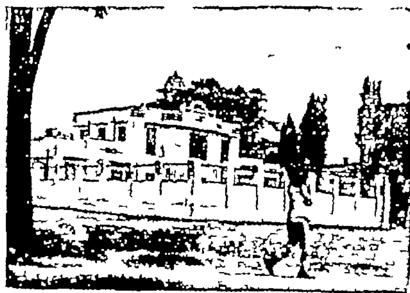
स्थानीय स्वायत्त शासन में भी काफी प्रगति हुई है। काठमाण्डू, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर में नगर पालिकाएं स्थापित हो चुकी हैं और शीघ्र ही नेपालगंज भरतपुर आदि में स्थापित करने की योजना है। लगभग छः सौ नगर पंचायतें भी शुरू गई हैं। विराटनगर, वीरगंज

जैसे प्रमुख स्थान में बारह मंच रचने की योजना तैयार हो चुकी है। म्युनिसिपैलिटी मैनुअल आफिस खड़ा करके म्युनिसिपल मैनुअल आदि बनाने का काम भी हो रहा है।

राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही आवश्यक विधान परिवर्तन के लिए भी 'लॉ कमीशन' अर्थात् विधि आयोग की नींव पड़ चुकी है। इस कमीशन से नेपाल के कानूनों को आधुनिक और प्रजातान्त्रिक ढाँचे में ढालकर नेपाल के लिए उपयुक्त कानूनों के विकास का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

नेपाल सरकार का प्रचार विभाग तथा गोरखा पत्र रेडियो नेपाल को और सुचारु रूप से चलाने के लिए सुझाव पेश करने के हेतु एक पब्लिसिटी कमीशन का गठन हुआ है। आशा है इस कमीशन की रिपोर्ट काफी मदद देगी।

नेपाल की खाद्य स्थिति सुधारने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के सुझाव देने के निमित्त खाद्यान्न संकट निवारण समिति का गठन हुआ है। उपत्यका को अन्न-संकट से बचाने के लिए ऐसी परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए अन्न स्टोर भी रखा गया है।



प्रभात व्यायामालय

हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए जो कदम उठाया गया है उसका दिग्दर्शन करते हुए अब मैं उस कदम का भी संकेत करता हूँ। वह कदम न्यूनतम कार्यक्रम के नाम से २०१० साल चैत्र २१ गते के गोरखा पत्र में प्रकाशित हो चुका है।

देश-सेवा के भाव से प्रेरित होकर सभा में सम्मिलित आप सब से इन निर्देशक सर्वमान्य सिद्धान्तों की रक्षा के साथ ही कार्यान्वित करने में यथाशक्ति सहयोग दें। आशा की जाती है कि प्रजातान्त्रिक भावना, कार्यकुशलता आदि विषय के लिए भी समग्र देश का ही आप लोग उदाहरणस्वरूप तथा प्रेरक भी होंगे।

श्री पशुपतिनाथ इस सलाहकार सभा को सफल बनावें यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। जय नेपाल!

राज्य परिषद्

अक्तूबर सन् १९५४ ई० में पाँचों मुसाहिबों का एक राज्य परिषद् स्थापित करके महाराजाधिराज अपनी चिकित्सा कराने के लिए विदेश गये। राज्य परिषद् के लिए एक विधान तैयार हुआ। उस सरकार में परिवर्तन करने आदि के भी अधिकार दिये गये।

पिछले दिनों में एक साथ अनेक अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। सम्राट स्विट्जरलैंड में बीमार थे कि अचानक रोग ने भीषण रूप धारण कर लिया और १३ मार्च १९५५ को ज्यूरिक में उनका देहावसान हो गया। सम्राट लोकप्रिय थे किन्तु अस्वस्थता के कारण स्वयं राज्य का काम नहीं कर रहे थे। जब श्री मातृका प्रसाद कोइराला ने मन्त्रिमंडल के आपसी वैमनस्य के कारण त्याग-पत्र दिया तो युवराज महेन्द्र (वर्तमान सम्राट) अपने स्वर्गीय पिता से परामर्श करने स्विट्जरलैंड गये थे और वहाँ से लौट कर उन्होंने मन्त्रिमंडल का त्याग-पत्र स्वीकार करके स्वयं ही समस्त अधिकार ग्रहण कर लिये थे।

वर्तमान सम्राट महेन्द्र कुशल और विवेकशील व्यक्ति हैं। आशा की जा रही है कि वह शीघ्र ही आम चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे और आवश्यकता हुई तो मन्त्रिमंडल के लिए भी ऐसे दल को आमंत्रित करेंगे जो उस उत्तरदायित्व को वहन कर सके और जिसे बहुमत ही नहीं, लोकमत का विश्वास प्राप्त हो। ज्ञात हुआ है कि इस सम्बन्ध में बातचीत चल भी रही है।

देश की आर्थिक योजना सुधारने तथा निर्माण की योजनाएँ नये नरेश के समक्ष समुपस्थित हैं। उनको कार्यान्वित और सफल करने के लिए मित्रराष्ट्रों का सहयोग भी नरेश को प्राप्त है। इस अवसर पर एक स्थिर एवं प्रगतिशील सरकार हो तभी सहायताओं और अपने साधनों का सदुपयोग करके फायदा उठा सकता है। अन्तरिम काल में राजनीतिक संघर्ष बना रहना किसी हालत में भी देश के हित में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में जनता के प्रतिनिधियों की सरकार तथा विधान परिषद् के स्थापित करने के प्रश्न कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं जिनके पूरा हुए बिना नरेश का शासन-व्यवस्था किसी हालत में भी ठीक नहीं हो सकता और न ही देश की जनता ही उसमें सहयोग कर सकती है।

२०

संस्थाएं

एकतंत्री पारिवारिक शासन की समाप्ति के बाद नेपाल में नाना प्रकार की राजनीतिक सामाजिक तथा वर्गीय संस्थाएं उत्पन्न होकर देश में जागृति लाने की चेष्टा कर रही हैं। नेपाल जैसे एक छोटे से राज्य में जिसमें अभी सच्चे प्रजातन्त्र की नींव ही नहीं पड़ सकी है इतनी अधिक पार्टियों का होना कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। इनमें यद्यपि समय-समय पर समझौते संयुक्त मोर्चे तथा विलीनीकरण की बातें आपस में चलती रहती हैं तथापि इनसे देश का वातावरण स्वच्छ होने की अपेक्षा धुंधला ही होता जाता है और जनता भी संस्थाओं से ऊबकर उनमें विशेष अभिरुचि नहीं रखती। इस समय नेपाल में जो प्रमुख प्रमुख संस्थाएं हैं और अपने विधान के अनुसार काम कर रही हैं वह इस प्रकार हैं—

नेपाल प्रजा परिषद्

नेपाल प्रजा परिषद् नेपाल की सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था है। इसकी स्थापना ज्येष्ठ २० गते संवत् १९९३ साल को हुई। आरम्भ ही से इस संस्था ने अपने पर्चों और लेखों द्वारा राणाशाही के विरुद्ध जनता में राजनीतिक जागृति लाने की कोशिश की किन्तु थोड़े दिनों के बाद ही यह संस्था राणाशाही के दमन-चक्र का शिकार हुई। इसके बहुत से कार्यकर्ता पकड़े गये जेल भेजे गये और फांसी देकर मार डाले गये। तब भी काम नहीं रुका और किसी न किसी रूप में चलता ही रहा। परिषद् के जीवनपर्यन्त बन्दी नेताओं की प्रेरणा से नेपाली युवकों तथा विद्यार्थी स्वतन्त्र भारत में राणाशाही के विरुद्ध प्रचार करते रहे। सशस्त्र क्रान्ति में भी प्रजा परिषद् के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भाग लिया। नयी सरकार द्वारा जनता की भलाई होते न देखकर परिषद् के नेताओं ने जेल से मुक्त होने के पश्चात् उसका पुनर्संगठन किया। नेपाल प्रजा परिषद् का अन्तिम लक्ष्य सब प्रकार के शोषकों को समाप्त कर देश के सर्वतोमुखी विकास के साथ-साथ वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। यह नेपाल में विदेशी साम्राज्यवाद के उन्मूलन स्वदेशी सामन्तवाद के नाश तथा पूर्ण जनवाद की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका रूप राष्ट्रीय और आर्थिक और रूप जनवादी है। इसके संगठन का आधार जनतान्त्रिक केन्द्रीयता है जो किसानों और मजदूरों को अपना स्तंभ मानती है।

नेपाल प्रजा परिषद् साम्राज्यवाद और उसके परिणाम युद्ध से विरोध तथा देशों की सभी जनता और जन आन्दोलनों के प्रति मैत्री-भाव रखती है।

यह परस्पर लाभ के आधार पर सभी प्रगतिशील एवं जनतन्त्रवादी देशों के साथ व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में है। पड़ोसी भारत और चीन

के साथ यह विचार मित्रता का सम्बन्ध चाहती है। नेपाल प्रजा परिषद् किसी भी देश का दबाव अथवा अनुचित हस्तक्षेप अपने देश पर नहीं होने देना चाहती।

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन् १९४६ ई० में बनारस में हुई। इसने नेपाल में कई बार सत्याग्रह छेड़कर सफलता भी प्राप्त की किन्तु कुछ ही दिनों के भीतर यह दो-तीन टुकड़ों में विभक्त हो गई। यह सार्वभौम स्वतन्त्र प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्र की स्थापना तथा शक्तियों की हर प्रकार की सहायता लेकर साम्राज्यवादी सामन्तवादी तथा अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ पूर्णतया मुकाबला करना चाहती है। यह भारत के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक और भौगोलिक सम्बन्ध निकटतम होने के कारण भविष्य में भी इसी आधार को लेकर निकटतम सम्पर्क रखने दुनिया की तमाम प्रगतिशील शक्तियों के साथ मेल रखने तथा रूस और चीन को साम्राज्यवादी शक्ति मानने के पक्ष में है।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी युवकों की सब से सुगठित तथा सक्रिय राजनीतिक संस्था है। समस्त क्रान्ति के पहले से ही इसके कार्यकर्ता प्रत्येक जन-आन्दोलन में सक्रिय भाग लेते रहे और अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से कभी भी पीछे नहीं रहे। कुछ दिनों तक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल प्रजा परिषद् आदि जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा बनाकर एक साथ काम करते रहे किन्तु मोर्चा भंग हो जाने के बाद फिर सब अलग अलग हो गये। डाक्टर के० आई० सिंह के सिंह दरबार काण्ड के समय ही से नेपाल सरकार ने इस पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तब से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जनवादी संगठनों में सम्मिलित होकर कार्य कर रहे हैं। यह देश के सामने उपस्थित राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए फौरी तरीकों पर विचार करने के लिए देश की तमाम जनतन्त्रवादी राजनीतिक पार्टियों जन व वर्ग संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा अल्पकालीन एक प्रतिनिधि सभा तथा उसके द्वारा एक न्यूनतम कार्यक्रम निश्चित करके जनता को फौरी सुविधा प्रदान कर सकने तथा जनता के प्रति उत्तरदायी एक अन्तरिम मंत्रिमण्डल का चुनाव कराने के पक्ष में है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देश की जनतन्त्रवादी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकार से सभी देशों से उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के भेदभाव के बगैर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कराने तथा अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसी भी देश से नेपाल की स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता तथा शान्तिपूर्ण नीति से मेल न खाने वाले राजनीतिक या अन्य शर्तों को स्वीकार किये बगैर मैत्रीपूर्ण सहायता लेने जिससे परस्पर लाभ तथा देश के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने की शर्तों पर आधारित होने आवश्यक होने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। यह अपने पड़ोसी भारत और चीन की जनता के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करके अपने सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धों का विकसित करना चाहती है।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस की स्थापना अप्रैल सन् १९४८ ई० में कलकत्ता में हुई और उसके आह्वान पर सारे देश में एकतंत्री राणा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति छिड़ी। नेपाली जनता का सहयोग प्राप्त करके यह संस्था किसी दिन बहुत शक्तिशाली हो गई थी किन्तु सत्ता मिलने के साथ ही साथ इसमें दरारें पड़ने लगीं। कोइराला बन्धुओं के बीच पारस्परिक मतभेद काफी भीषण रूप धारण कर गये। इन को दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण की मध्यस्थता में एक संधि हुई जिसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है—

संधिपत्र

देश की वस्तुस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, हम यह अनुभव कर रहे हैं कि कांग्रेस के ओहदों में मनमुटाव वांछनीय नहीं। देश को सबल बनाने के विचार और शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है कि कांग्रेस में एकता हो। देश को शीघ्र उन्नति के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी केवल हमारी संस्था ही ले सकती है। गुजरे दिनों में हमारे परिवार व देश को उन्नति के लिए बहुत कुछ किया है। और हम यह महसूस करते हैं कि हमारी आपसी फूट से हमारे पूर्व उद्देश्य को नुकसान पहुँचेगा। उभय पक्ष की ओर से बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जिससे हमारे काम को क्षति पहुँचता जाय। ऐक्य स्थापना के उद्देश्य से हमने यह निश्चय किया है कि हम समझौता कर लें और निम्नलिखित शर्तें उभयत स्वीकृत हुई हैं—

१ काठमाण्डू में कार्यकर्ताओं की आपसी बैठक में प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष के विरोध में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसे अस्वीकृत समझा जाय और इस कार्रवाई के लिए खेद प्रकट किया जाय।

२ सद्भावना का वातावरण सृजन किया जाय भविष्य में हम दोनों में से किसी के विरोध में जो भी सदस्य प्रचलनशील होगा वह हम दोनों के द्वारा धुत्कार दिया जायगा तथा आवश्यक हुआ पर उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की जायगी।

३ कांग्रेस पार्टी तथा सरकार व उसके प्रतिनिधियों में एकसूत्रता का स्थापन।

४ अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन का निश्चयीकरण।

५ *काम सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री के पद अलग* अलग रहेंगे।

६ गलतफहमी तथा असामंजस्य से बचने के लिए पार्टी सरकार की नीति के कार्यान्वित करने में नित्यप्रति दखलन्दाजी नहीं करेगी तथा शासन प्रबन्ध में सरकार पार्टी के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र रहेगी।

७ कांग्रेस के आदर्श और कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए सरकार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निर्धारित नीति के अनुसार चलना स्वीकार करेगी। कांग्रेस एक बार

के लिए कार्यक्रम निर्धारित करेगी जिसे सरकार कार्यान्वित करेगी ।

८. कार्यसमिति में उचित प्रादेशिक प्रतिनिधित्व रहेगा तथा सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त परामर्श से होगी ।

इसके बावजूद भी मातृका सरकार और नेपाली कांग्रेस में नहीं निभी और कांग्रेस की कार्यसमिति ने सरकार में सम्मिलित मंत्रियों को संस्था से निष्कासित कर दिया । परिणाम स्वरूप सरकार भंग हो गई और नेपाली कांग्रेस को भी पदच्युत होना पड़ा । इसके पश्चात् इस संस्था का एक भाग मातृका प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस से पृथक हो गया ।

नेपाली कांग्रेस अपने को क्रान्तिकारी संस्था मानकर संसदीय प्रजातन्त्रवाद तथा महाराजाधिराज को वैधानिक शासक मानती है । वह अपने पड़ोसी चीन और भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत को अपना अगुवा मानती है । वह संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता की वृद्धि साम्राज्यवादी औपनिवेशिक नीति का अन्त तथा नेपाल में शोषणरहित प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था की कल्पना करती है ।

नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्

नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् का जन्म राणा शासन की समाप्ति के बाद हुआ । यह अपने को राष्ट्रवादी संस्था सिद्ध करके सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता बढ़ाने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों का अपने अपने ढंग से जीवन बिताने अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार चलते हुए समानता का पद प्राप्त करने और परस्पर आक्रमण की चिन्ता से बचने को परमावश्यक मानती है । इसी विचारधारा पर वह अपनी वैदेशिक नीति भी निर्भर रखती है । वह संसार में शान्ति के लिए अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए नाना राष्ट्रों के किसी गुट से कोई वास्ता नहीं रखने तथा नेपाल की वैदेशिक नीति में कहीं से भी हस्तक्षेप न होने देने के पक्ष में है ।

नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् भारत से अपना सम्बन्ध सभी सधि पर निर्धारित करती है । वह मित्रता के साथ भी जातीय और सांस्कृतिक समानता मानकर अपनी मित्रता जारी रखने की घोषणा करती है । गोरखा परिषद् अपने को विरोधी पार्टी सिद्ध करके देश को अराजक शान्ति तथा सत्तारूढ़ दल की तानाशाही से बचाना आवश्यक समझती है । यह नेपाल के लिए मिली-जुली आर्थिक व्यवस्था तथा सहकारी समिति की सम्पत्ति के सिद्धान्त को अपने घोषणापत्र में विशेषता देती है ।

नेपाल तराई कांग्रेस

नेपाल तराई कांग्रेस का जन्म उस समय हुआ जब नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ थी और वह कई टुकड़ों में विभक्त हो रही थी । तराई कांग्रेस प्रत्येक क्षेत्र को आत्मनिर्णय का अधिकार और स्वशासित प्रान्तों को एक सूत्र में आबद्ध करके 'नेपाल यूनियन' की स्थापना करना चाहती है । यह भाषा भौगोलिक और आर्थिक तथा सामाजिक संगठनों के आधार पर

पहाड़ और तराई को दो या दो से अधिक प्रान्त कायम करने और उन्हें आन्तरिक शासन का पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में है।

नेपाल तराई कांग्रेस मिश्रित तथा नियोजित अर्थ-व्यवस्था को देश के लिए उपयुक्त तथा हिन्दी भाषा को नेपाल की राष्ट्रभाषा मानती है। वह अन्तर्राष्ट्रीय दलबन्दी से नेपाल को पृथक रखने का समर्थन करती हुई संसार के सभी स्वतन्त्र देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने को आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं मानती। वह अपने घोषणा-पत्र में केवल हित कर और नितान्त आवश्यक देशों के साथ कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने को आवश्यक मानती है।

अखिल नेपाल जन कांग्रेस

अखिल नेपाल जन कांग्रेस नेपाली कांग्रेस से निकली हुई एक राजनीतिक संस्था है। यह सर्वोदयवाद में विश्वास करके देश को सच्चे प्रजातन्त्र की ओर अग्रसर कराने के पक्ष में है। जन कांग्रेस अपने घोषणापत्र में दो सिद्धान्तत विरोधी एंग्लो-अमरीकी एवं सोवियत रूस गुट के प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए नेपाल की अपनी लोकशाही के दौरान में अपने सीमित साधनों को काम में लाकर उसे कम कराने के लिए प्रयत्नशील होने का विचार प्रकट करती है। यह दुनिया के तमाम देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके देश में सर्वतोमुखी विकास चाहती है। अखिल नेपाल जन कांग्रेस नेपाल की भूमि समस्या को चीन की भूमि समस्या से मिलती जुलती मानकर उसे सुलझाने के लिए चीन की घटनाओं से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करेगी।

राष्ट्रीय प्रजा पार्टी

राष्ट्रीय प्रजा पार्टी नेपाली कांग्रेस से निकली हुई नेपाल की सब से नयी राजनीतिक संस्था है। परामर्शदात्री समिति के पश्चात् इसी राष्ट्रीय प्रजा पार्टी का मंत्रिमण्डल बना जिसमें कई स्वतन्त्र सदस्य भी थे। देश की परिस्थिति न संभाल सकने के कारण प्रजा पार्टी को विवश होकर अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लेना पड़ा। यह यद्यपि नेपाली कांग्रेस से ही आविर्भूत हुई है तब भी दोनों की नीति और कार्यक्रम में काफी भिन्नता है। नेपाली कांग्रेस जहां अपने को क्रान्तिकारी और समाजवादी संस्था मानती है वहां राष्ट्रीय प्रजा पार्टी अपने को सुधारवादी तथा प्रजातन्त्रवादी। नेपाली कांग्रेस की अपेक्षा यह राष्ट्रीयता पर भी अधिक जोर देती है।

राष्ट्रीय प्रजा पार्टी आर्थिक प्रणाली को प्रश्रय देकर कृषि की औद्योगिकता को प्राथमिकता देती है। वह राष्ट्रीय पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देकर देश का औद्योगीकरण करना चाहती है।

राष्ट्रीय प्रजा पार्टी तटस्थता की नीति धारण करके मित्रराष्ट्रों से अच्छा सम्बन्ध स्थापित रखना चाहती है। वह भारत से घनिष्ठ सम्पर्क रखने के भी पक्ष में है।

मैत्री संघ

नेपाल-भारत मैत्री संघ नेपाल-चीन मैत्री संघ तथा नेपाल-भूटान सद्भावना समिति भी नेपाल में स्थापित हैं। ये एशियाई जनता की अविच्छिन्न एकता को सुदृढ़ करके विश्व-बन्धुत्व तथा सांस्कृतिक अभ्युत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं।

वर्गीय संगठन

अखिल नेपाल किसान संघ नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस समाज सुधार संघ विद्यार्थी संघ महिला संघ तथा युवक संघ आदि वर्गीय संगठन हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी संगठन हैं जो केवल जिलों तथा नगरों ही तक सीमित हैं और नेपाल के पर्वतीय तथा तराई प्रदेश में काम करते हैं।

(क) वाक् और प्रकाशन स्वतन्त्रता
(ख) शान्तिपूर्वक और बिना हथियार लिये सम्मेलन सभा करना
(ग) संस्था या संघ खड़ा करना
(घ) नेपाल राज्यभर में बिना रोक-टोक विचरण करना
(ङ) नेपाल राज्य भर में जिस किसी भाग म भी निवास करना और घर जमीन लेना
(च) सम्पत्ति अर्जन करना उपभोग करना खरीद-बिक्री करना और
(छ) कोई पेशा रोजगार, उद्योग या व्यापार करना।

१७ राज्य द्वारा निश्चय दिलाने की व्यवस्था—

(क) कोई व्यक्ति भी उस समय मे प्रचलित कोई एन विरुद्ध कुछ काम करने के सिवाय और किसी अपराध का दोषी नही माना जायगा और अपराध करने के समय जारी किये हुए एन म निश्चित किये गये दण्ड से अधिक दण्ड नही दिया जायगा।

(ख) किसी व्यक्ति के ऊपर एक ही अपराध में एक बार से अधिक मुकदमा नही चलाया जायगा और दण्ड सजा नही दिया जायगा।

(ग) किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह होने के लिए बाध्य नही किया जायगा।

१८ सार्वजनिक हित के लिए अथवा सार्वजनिक शान्ति कायम रखने के लिए या राज्य-सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाये गये एन अथवा नियम से स्थापित की गई रीति के विपरीत किसी व्यक्ति की भी जान या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही छीनी जायगी।

१९ (क) मनुष्यो की खरीद-बिक्री और बेगारी प्रथा तथा इसी प्रकार के जबर्दस्ती काम कराने का मनाही किया गया है। किसी के द्वारा इसके विपरीत किया हुआ साबित होने पर कानूनन सजा होगी।

(ख) इस धारामा म उल्लिखित बातों से लोक प्रयोजन के निमित्त काम अनिवार्य करने म राज्य का बाधा अड़चन नही होगा। ऐसा करने म धर्म जाति जात (वर्ण) या वर्ग इत्यादि किसी बात के जरिये भेदभाव नही किया जायगा।

२० १४ वष से कम उम्र के किसी भी बालक का कारखाना या खान के काम मे अथवा अन्य किसी जोखिम के काम में नही लगाया जा सकता है।

भाग ३
परिच्छेद २—कार्यकारिणी अधिकार

२१ (क) राज्य का कार्यकारिणी अधिकार श्री पाच महाराजाधिराज और मौसूफ के मंत्रिमण्डल को सौंपा गया है। मौसूफ उक्त अधिकार बमोजिम काम करने के समय

मंत्रियों की सलाह लेकर इस ऐन के अनुसार, स्वयं या मौसूफ के मातहत के कर्मचारियों द्वारा करेंगे।

व्याख्या—श्री ५ महाराजाधिराज से किया जायगा कहने का मतलब श्री ५ से मंत्री अथवा मंत्रियों की सलाह से किया जाने वाला समझना चाहिए।

(ख) ऊपर दफे में उल्लेख की गयी बातों को बाधा न पहुंचने के तौर पर नेपाल की जंगी फौज का सर्वोच्च कमाण्डर-इन-चीफ का पद श्री ५ महाराजाधिराज में व्यवस्थित रहा है। उक्त पद सम्बन्धी काम और कार्यों का संचालन ऐन बमोजिम नियमित होगा।

२२ (अ) निम्नलिखित मुकदमों में किसी अपराध के दोषी ठहराये गये किसी व्यक्ति की दण्ड सजा माफी करना, विलम्ब करना, घटाना या बदलना या मुल्तवी रखने का अधिकार श्री ५ महाराजाधिराज का होगा—

(क) सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) से दण्ड सजा किया गया

(ख) नेपाल के कार्यकारिणी अधिकार लागू होने के विषय सम्बन्धी ऐन के विरोध में किये गये अपराध की दण्ड सजा दी गयी।

(ग) जान सजा का दण्ड किया गया।

(घ) दफा (१) के उपदफा (क) में उल्लेख किये गए बातों से नेपाल की सशस्त्र सेना का जिस किसी आफिसर को ऐन से दिया गया सेना न्यायालय से किया गया दंडादेश मुल्तवी रखने, माफी देने या बदलने के अधिकार में बाधा नहीं दी जायगी।

२३ (क) श्री ५ महाराजाधिराज के शासन सम्बन्धी किये जाने वाले कार्य सम्पादन में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिमण्डल रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य होंगे।

(ख) मंत्रियों द्वारा श्री ५ महाराजाधिराज को कोई सलाह दी गई है या नहीं और यदि दी गई है तो क्या सलाह दी गई यह बात किसी अदालत में भी नहीं पूछी जायगी।

२४ मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से श्री ५ महाराजाधिराज के प्रति उत्तरदायी होगा।

२५ (क) नेपाल सरकार की कार्यकारिणी सम्बन्धी सभी काम श्री ५ महाराजाधिराज के नाम में किये जायेंगे।

(ख) श्री ५ महाराजाधिराज के नाम में तैयार होकर कार्यान्वित किया गया आर्डर आदेश (वर्दी) और अन्य अधिकार पत्र (सवाल सनद) श्री ५ महाराजाधिराज में दिये गये नियम बमोजिम प्रमाणित किए जायेंगे और इस तरह प्रमाणित किया गया आर्डर, वर्दी या अधिकार पत्र उचित है या नहीं ऐसी बातों में श्री ५ महाराजाधिराज से कार्यान्वित किया गया अथवा तैयार कराया गया आदेश या अधिकार पत्र यह नहीं है कहकर सवाल-जवाब नहीं किया जायेगा।

(ग) नेपाल सरकार के काम कार्यवाही अधिक सुगमता से चलाने के लिए यह

काम मंत्रियों में विभाजित करने के लिए श्री ५ महाराजाधिराज से नियम और आदेश बनाया जायगा।

२६. प्रधान मंत्रियों का कर्तव्य—

(क) नेपाल के शासन सम्बन्धी विषयों में मंत्रिमण्डल द्वारा किया गया सभी निर्णय श्री ५ महाराजाधिराज के समक्ष पेश करना।

(ख) नेपाल के शासन-सम्बन्धी विषयों में श्री ५ महाराजाधिराज से मांगी गयी हाल खबर मौसूफ के समक्ष पेश करना।

(ग) एक मंत्री से निर्णय किया गया परन्तु मंत्रिमण्डल से विचार नहीं किया गया कोई विषय श्री ५ महाराजाधिराज मंत्रिमण्डल में विचार कराना चाहें तो मंत्रिमण्डल में पेश करना।

आर्थिक विषय की कार्य प्रणाली

२७. श्री ५ महाराजाधिराज से हरेक आर्थिक वर्ष के लिए नेपाल सरकार का अनुमान किया गया आमदनी खर्च का एक विवरण तैयार किया जायगा। इस विवरण को वार्षिक आर्थिक विवरण या बजट कहा जायगा।

२८. यह विवरण श्री ५ महाराजाधिराज और मौसूफ के मंत्रिमण्डल से मंजूर होने पर ही सुनिश्चित किया जायगा।

२९. (क) जिस किसी समय में भी श्री ५ महाराजाधिराज से मंत्रिमण्डल के सलाह अनुसार तत्काल ही कुछ करने की परिस्थिति आयी है ऐसा समझने से आवश्यक आर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है।

(ख) इस नियम अनुसार जारी किया गया आर्डिनेन्स मुल्क में जारी किये गये अन्य ऐन की तरह होगा परन्तु ऐसी प्रत्येक आर्डिनेन्स—

(अ) जब उपरान्त से बनने वाला विधानानुसार रीतिपूर्वक बनायी गयी व्यवस्थापिका सभा की बैठक बैठने के तीन महीना पूरे हो जाने पर खारिज होगा।

(ब) श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा उक्त आर्डिनेन्स मंत्रिमण्डल की सलाह से कभी भी खारिज किया जा सकता है।

परिच्छेद तीन—न्याय-प्रबन्ध

३०. (क) प्रधान न्यायालय मुल्क का सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसमें एक प्रधान न्यायाधीश और श्री ५ महाराजाधिराज के द्वारा मंत्रिमण्डल के सलाह अनुसार निश्चित किये गये अन्य न्यायाधीश भी रहेंगे।

(ख) प्रधान न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और प्रत्येक न्यायाधीश श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा मंत्रिमण्डल की सलाह कर नियुक्त किये जायेंगे और पेंशन वर्ष के उम्र न होने तक वे अपने पद में रहेंगे।

प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के समय प्रधान न्यायाधीश से सलाह ली जायगी।

न्यायाधीश श्री ५ महाराजाधिराज के समक्ष अपने हस्ताक्षर पत्र लिखकर पदत्याग कर सकते हैं।

(ग) नेपाल के नागरिक न होने पर और (क) कम से कम १० वर्ष तक नेपाल में कोई इन्साफ करने के पद पर बहाल न होकर या (ख) कम से कम १० वर्ष तक प्रधान न्यायालय में वकील न होकर कोई भी व्यक्ति प्रधान न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश के पद के लिए योग्य नहीं माना जायगा। परन्तु प्रधान न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशों के पद में नियुक्त करने के लायक नेपाल के नागरिक न मिलने की अवस्था में गैर नागरिक भी नियुक्त हो सकेगा।

(घ) प्रधान न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश श्री ५ महाराजाधिराज ने मंत्रिमण्डल की सलाह अनुसार निर्धारित तनखाह पायेंगे। उन्हें भर्ती होने के बाद उनका नियुक्ति पत्र इस तरह नहीं बदला जायगा जिससे उन्हें बाधा पड़े।

(ङ) प्रधान न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश या और कोई न्यायाधीश खराब आचरण का या अयोग्य ठहरने पर मंत्रिमण्डल के कम से कम तीन खंड के दो खंड बहुमत से उनको खारिज किया जाय ऐसी राय श्री ५ महाराजाधिराज के समक्ष दिया गया तो मौसूफ की आज्ञामात्र से वे अपने पद से खारिज होंगे अन्यथा नहीं।

११ मामला मुकदमा सम्बन्धी कागज-पत्र मिसिल रखने का आफिस प्रधान न्यायालय होगा न्यायालय की अवहेलना सम्बन्धी सजा देने का अधिकार और उक्त आफिस का सभी अख्तियार इस प्रधान न्यायालय को होगा।

१२ प्रधान न्यायालय का अधिकार और कार्यप्रणाली एवं अमीनिम जब तक न बदली जायेगी तब तक पूर्ववत् रहेगी।

परिच्छेद ४—नेपाल का नियन्त्रक (कण्ट्रोलर) महालेखा परीक्षक (आडिटर-जनरल)

१३ (क) नेपाल में एक नियन्त्रक महालेखा परीक्षक रहेगा जिसको श्री ५ महाराजाधिराज मंत्रिमण्डल की सलाह अनुसार नियुक्त करेंगे।

(ख) नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की तनखाह और नौकरी की अन्य शर्तें प्रधान न्यायालय के न्यायाधीश के मुताबिक होंगी।

१४ नेपाल सरकार का स्याहा श्रेस्ता हर हिसाब श्री ५ महाराजाधिराज की स्वीकृति सहित नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निश्चित किये गये रूप में रखा जायगा।

१५. नेपाल सरकार का स्याहा श्रेस्ता हर हिसाब सम्बन्धित नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट श्री ५ महाराजाधिराज के समक्ष पेश होनी चाहिए।

भाग ४

३६ (क) मुल्क का एम अभिलेख (रेकार्ड) और न्याय संबंधी कार्यवाही को सारे नेपाल में पूर्ण विश्वास और सम्मान दिया जायगा।

(ख) नेपाल की अदालतों द्वारा किया हुआ अन्तिम फैसला या आदेश एवं डिक्री सारे नेपाल में जहां कहीं भी कार्यान्वित होगा।

भाग ५

३७ *नेपाल के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन (लोक सेवा आयोग) रहेगा।* उसमें एक सभापति और श्री ५ महाराजाधिराज से निश्चित किये हुए अन्य सदस्य भी रहेंगे।

३८ मन्त्रिमण्डल की सलाह अनुसार श्री ५ महाराजाधिराज पब्लिक सर्विस कमीशन के सभापति और अन्य सदस्यगण की नियुक्ति करेंगे।

३९. पब्लिक सर्विस कमीशन के सभापति और सदस्यों के वेतन और नौकरी की शर्तें प्रधान न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुरूप होंगी।

४० (क) नेपाल सरकार की सभी जागीरों नौकरियों में नियुक्ति के लिए जांच करने का कर्तव्य पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा।

(ख) निम्नलिखित विषयों में पब्लिक सर्विस कमीशन से सलाह लेनी पड़ेगी—

(अ) निजामती पद और नौकरी में नियुक्त करने के तरीके-सम्बन्धी विषयों में

(आ) निजामती नौकरी और पद में नियुक्ति करने और बदली बढ़ाने के सिद्धान्त में और उक्त नियुक्ति और बदली-बढ़ाव से सम्बन्धित उम्मेदवारों की योग्यता के विषय में

(इ) नेपाल सरकार के निजामती जागीरदार के अनुशासन सम्बन्धी सभी विषय और इससे सम्बन्धित स्मृति-पत्र विज्ञप्ति उजुरी या निवेदन-पत्र सहित सभी विषय में

और सरसल्लाह के निमित्त पेश किया गया तथा श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा सलाह मांगे जाने पर जिस किसी विषय में सलाह देने का काम पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। परन्तु श्री ५ महाराजाधिराज से इस विषय में साधारण तौर से या विशेषतः अमुक विषयों में या अमुक परिस्थिति में पब्लिक सर्विस कमीशन से सलाह लेनी आवश्यक नहीं है कहकर नियम द्वारा निश्चित किये जाने पर वैसा ही होगा।

भाग ६

निर्वाचन (चुनाव)

४१ नेपाल के लिए एक विधान बनाने वाली विधान परिषद् का निर्वाचन करने के लिए अनुकूल सभी उचित परिस्थिति का सृजन करना अन्तरिम सरकार का ध्येय रहेगा।

भाग ७

७ संवत् २००४ (सन् १९४८) को नेपाल सरकार वैधानिक कानून जारित किया गया है।

नोट—इस विधान में समय-समय पर संशोधन आदि भी हुए हैं जिससे इसका रूप परिवर्तित होता गया है।

२३

सलाहकार सभा का विधान

स्वस्ति श्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावलि विराजमानमानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्ज्वल नेपालतारा ओ३मृरामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अति प्रबल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति सर्वोच्च कमाण्डर इन-चीफ श्री मन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराज त्रिभुवन वीर विक्रम जंग बहादुर शमशेर जंग देवानाम् सदा समर विजयीनाम्।

नेपाल के निमित्त एक सलाहकार सभा का गठन करने के लिए नेपाल अन्तरिम शासन-विधान २००७ को संशोधित करने के निमित्त

एक ऐन

प्रस्तावना—देश के शासन प्रबन्ध म जनता के प्रतिनिधियों को अधिक सम्मिलित कराने के लिए श्री ५ महाराजाधिराज तथा मौसूफ के मंत्रिमण्डल को अपने कार्य-सम्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक सलाहकार सभा का गठन आवश्यक तथा वांछनीय होने के नाते देशाय के अधिनियम आदि बनाये गये हैं—

१ (क) इस ऐन का नाम नेपाल अन्तरिम शासन-विधान (द्वितीय संशोधन) २००९ होगा।

(ख) यह ऐन तुरन्त लागू होगा।

परिभाषा

२ प्रसंग से दूसरा अर्थ न लगने के समय तक इस ऐन में—

प्रधान ऐन—नेपाल अन्तरिम शासन-विधान २००७ को कहा जायगा।

सभा—सलाहकार सभा को कहा जायगा। अन्य शब्दों के जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं की गई है वही अर्थ तथा महत्त्व होंगे जो प्रधान ऐन में थ। प्रधान ऐन के भाग ३ के परिच्छेद १ कार्यकारिणी अधिकार के बाद निम्नलिखित दूसरा परिच्छेद जोड़ा जायगा।

परिच्छेद १ (क) सलाहकार सभा

साधारण

२८ क (१) नेपाल में एक सलाहकार सभा का गठन होगा जिसके सदस्यगण श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा नेपाल के प्रामाणिक नागरिकों के बीच से मनोनीत होंगे तथा जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्री राज्य मंत्री तथा उपमंत्री पदेन सदस्य होंगे।

(२) संविधान सभा के गठन के पश्चात् सलाहकार सभा का अस्तित्व समाप्त हो जायगा।

२८-क सभा के गैर सरकारी सदस्यों में यथासम्भव देश के विभिन्न भाग वर्ग तथा विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को चुना जायगा।

२८-ख (१) नेपाल के नागरिक

( ) २५ वर्ष की आयु तथा

(३) २८ ग में दिये हुए अयोग्यतारहित न होने से कोई भी व्यक्ति सलाहकार सभा के सदस्य मनोनीत होने के योग्य नहीं होंगे।

२८-ग (१) निम्नलिखित व्यक्ति सलाहकार सभा के सदस्य के अयोग्य होंगे—

(क) नेपाल सरकार के मातहत किसी लाभ के पद को धारण करने वाले व्यक्ति

(ख) अदालत द्वारा नैतिक विकृति तथा भ्रष्टाचार के अभियोग में दोषी सिद्ध हुए तथा

(ग) दिमाग खराब वाले व्यक्ति।

किन्तु इसमें नेपाल के मंत्रि मंडल के सदस्य राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री को लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं माना जायगा।

(२) शपथ नहीं ग्रहण करने के समय तक कोई व्यक्ति सभा का सदस्य नहीं माना जायगा।

२८ द (१) सलाहकार सभा के सदस्य भी निम्नलिखित किसी अवस्था में अपना स्थान रिक्त करना माने जायेंगे—

(क) अपने हस्ताक्षर से सभा के अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र पेश करने अथवा

(ख) दफा २८ ग में लिखे अयोग्यतानुसार अथवा

(ग) सभा की अनुमति बिना सभा की बैठक में २५ दिन की अवधि तक लगातार अनुपस्थित रहने से।

किन्तु इस २५ दिन की अवधि की गणना में सभा-स्थगन-काल यदि लगातार ४ दिन से अधिक रहे तो वह सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(२) कोई सदस्य दफा २८ ग में वर्णित अयोग्यता का भागी है अथवा नहीं इस प्रश्न का निर्णय श्री ५ महाराजाधिराज के समक्ष पेश होगा और मौसूफ का निर्णय अन्तिम होगा।

२८ च सभा के सदस्य वेतन या और भत्ता श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा निर्णय बमोजिम होगा।

छ यदि कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करने के पहले अथवा अपनी सदस्यता के निमित्त योग्य नहीं है अथवा अयोग्य है यह जान होते हुए भी सभा की बैठक में सदस्य की हैसियत से बैठता है अथवा मत देता है तो उस व्यक्ति को सभा में भाग लेने अथवा मत देने से प्रत्येक दिन के वास्ते सौ रुपए की दर से जुर्माना राज्य देय ऋण के रूप में वसूल करेगा।

सल्लाहकार सभा का विधान

२८-ख सभा में कोई स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति करने का अधिकार श्री ५ महाराजाधिराज का है।

सभा के पदाधिकारी

२८-ग श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा माने हुए सदस्य अथवा व्यक्ति के सभापतित्व में सल्लाहकार सभा अपने अधिवेशन की प्रथम बैठक में दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी पीछे भी जैसे-जैसे अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा अन्य सदस्यों को स्थिति अनुसार अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा तथा पदेन सदस्य इन पदों के चुनाव के निमित्त उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकेंगे।

२८-घ सल्लाहकार सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद धारणकर्ता—

(१) यदि सल्लाहकार सभा के सदस्य रहना न चाहे तो अपना रिक्त करेंगे।

(२) अपने हस्ताक्षर में लिखित श्री ५ महाराजाधिराज का सम्बोधित पत्र देने से पद त्याग हो सकेगा।

(३) सभा में उपस्थित सदस्यों के तीन खंड में से दो खंड के बहुमत से पास हुए प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकेंगे।

२८-ङ (१) सभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद भी रिक्त होने पर श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा नियुक्त सदस्य इस प्रयोजन के निमित्त उस पद के कर्तव्य का पालन करेंगे।

(२) सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यविधि के नियमानुसार सभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

२८-च. सभा के अध्यक्ष के निमित्त अथवा अध्यक्ष रूप में कार्य करने वाले उपाध्यक्ष अथवा अन्य किसी व्यक्ति को प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा किन्तु मत बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

२८-छ अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन काल में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन काल में उपाध्यक्ष सभा में पदासीन नहीं होने पाएंगे।

२८-ज अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पाने का वेतन और भत्ता श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा नियत किये हुए बमोजिम होगा।

सभा का आह्वान तथा अधिवेशन

२८-झ (१) सल्लाहकार सभा प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार आवाहन करेगी तथा एक अधिवेशन की अन्तिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में ६ महीने का काल व्यतीत नहीं होने पाएगा।

(२) उपर्युक्त दफा (१) के अधीन श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा समय-समय पर—

(क) उपयुक्त स्थान तथा समय का आवाहन हो सकेगा।

(ख) सभा का अधिवेशन भंग हो सकेगा।

२८ ग श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा प्रत्येक अधिवेशन के प्रारम्भ में सभा का सम्बोधन होगा जिसमें सभा के आवाहन का कारण ज्ञात कराया जायगा।

२८ घ (१) श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा सभा का सम्बोधन हो सकेगा। इस प्रयोजन के निमित्त सदस्यों की उपस्थिति होनी होगी।

(२) श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा सभा के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत विषय अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में सन्देश पठाया जा सकेगा तथा सभा उस संदेश में लिखित विषय के ऊपर सुविधानुसार यथाशीघ्र विचार करेगी।

सभा का कार्य-सचालन

२८ ङ सभा के प्रत्येक सदस्य अपना आसन ग्रहण करने के पहले श्री ५ महाराजाधिराज अथवा मौसूफ द्वारा उस काम के निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा।

२८-च (१) इस पत्र में अन्यथा लिखे हुए के अतिरिक्त सभा की बैठक में प्रश्नों के निर्णय अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का काम करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य के बहुमत द्वारा होगा।

(२) सभा के किसी स्थान के रिक्त होने अथवा किसी अनधिकृत व्यक्ति के सभा में मत देने अथवा अन्य किसी प्रकार से भाग लेने का पता लगने पर सभा की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।

(३) सभा की बैठक के निमित्त सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति २५ होगी।

(४) सभा के बैठक काल में अनिवार्य उपस्थिति संख्या कम सिद्ध होने पर अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का काम करने वाले व्यक्ति आवश्यक उपस्थिति संख्या न पहुँचने तक सभा की कार्यवाही रोक सकेंगे अथवा सभा को स्थगित कर सकेंगे।

सदस्यों का विशेषाधिकार

२८ छ (१) इस पत्र तथा सभा की कार्यविधि के नियमों के अन्तर्गत सभा में वाक्-स्वतन्त्रता होगी।

(२) सभा में अथवा सभा की किसी समिति में कही हुई बात अथवा दिये हुए मत के सम्बन्ध में सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध न्यायालय में भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। किसी व्यक्ति के विरुद्ध सभा की अधिकृत अथवा सभाधीन किसी रिपोर्ट पत्र-पत्र तथा कार्यवाही का प्रकाशन करने के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

सल्लाहकार सभा की शक्ति

२८-य सल्लाहकार सभा निम्नलिखित बातों के अतिरिक्त सरकार के व्यवस्थापक तथा कार्यकारिणी कृत्यों से सम्बन्धित किसी विषय के ऊपर विचार विमर्श कर सकेगी—

(१) जिससे नेपाल सरकार के किसी विदेशी राष्ट्र के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध में असर पड़ सके।

(२) श्री ५ महाराजाधिराज तथा मौसूफ के परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी बात।

(३) ऐसी बातें जिसके प्रकट होने से सार्वजनिक अहित होने की सम्भावना हो जैसे सेना की नियुक्ति तथा गतिविधि।

(४) किसी मंत्री अथवा सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव।

२८-क्ष सल्लाहकार सभा में बिना विचार-विमर्श हुए तथा मत लिये कोई भी कानून श्री ५ महाराजाधिराज की स्वीकृति के निमित्त मौसूफ के समक्ष पेश नहीं हो सकेगा।

२८ त्र सल्लाहकार सभा के कोई सदस्य भी दफा २८-य में लिखी बातों के अतिरिक्त सरकार व्यवस्थापक तथा कार्यकारिणी कृत्यों से सम्बन्धित बाकि किसी विषय के बारे में भी प्रश्न पूछ सकेंगे।

२८ ज्ञ सभा के कोई सदस्य भी अध्यक्ष की अनुज्ञा तथा सभा की कार्यविधि के नियमानुसार सभा के विचारार्थ किसी बिल में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे।

२८-अ श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा अपने विवेक से सभा में पास हुए बिल प्रस्ताव के ऊपर भी अस्वीकार की अनुमति दी जा सकेगी अथवा उचित समझकर उसमें हेर-फेर तथा संशोधन सहित सभा में पुनः विचारार्थ वापस किया जा सकेगा।

२८-य सभा यदि किसी सरकारी बिल अथवा प्रस्ताव का स्वीकार करती है अथवा श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा प्रस्तावित हेर-फेर तथा संशोधन को स्वीकार नहीं करती है तथा यदि सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित सिद्ध होने पर उस बिल प्रस्ताव में हेर-फेर, तथा संशोधन को श्री ५ महाराजाधिराज सभा से पास करवाकर प्रमाणित कर सकेंगे।

२८-ट. श्री ५ महाराजाधिराज द्वारा इस ऐन की दफाओं के अधीन सभा की कार्य विधि तथा काम-संचालन के सम्बन्ध में नियमादि बनाये जा सकेंगे।

४ प्रधान ऐन का दफा २८ रद्द किया जाता है तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित २८ रखा जायगा।

२८. वार्षिक आर्थिक विवरण या बजट सल्लाहकार सभा के समक्ष रखा जायगा तथा सभा को आर्थिक विवरण या बजट के ऊपर विचार-विमर्श अथवा मत देने का अधिकार रहेगा।

परन्तु, श्री ५ महाराजाधिराज के व्यक्तिगत कोष अथवा ऐसे सम्बन्धित विषयों पर सभा बहस नहीं कर सकती।

तथा दफा २८ म तथा म म के नियमादि इस दफा के अधीन बातों के ऊपर भी लागू हो सकेगा।

५ दफा २८ का उपदफा (२) को रद्द करके उसके स्थान पर निम्नलिखित उपदफा २ रखा जायगा।

सलाहकार सभा का अधिवेशन शुरू होने के तीन माह के व्यतीत होने पर खारिज होगा।

अनुसूची

१ मन्त्री राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्री के निमित्त पद शपथ का विवरण—

मैं ......ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्री ५ महाराजाधिराज मौसूफ के उत्तराधिकारियों तथा कानून द्वारा स्थापित अन्तरिम विधान के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा रखूंगा तथा नेपाल के मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का पालन श्रद्धापूर्वक तथा शुद्ध अन्तःकरण से करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष न रखते हुए सब प्रकार के व्यक्तियों के प्रति विधान तथा कानून के अनुसार न्याय करूंगा।

२ मन्त्री राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्री के निमित्त गोपनीयता के शपथ का विवरण—

मैं ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी भी ऐसी बात जो कि मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के रूप में मेरे पास विचारार्थ आएगी अथवा मुझे ज्ञात होगी उस में अपने कर्तव्यपालन के अतिरिक्त अन्य किसी अवस्था में किसी को भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा।

३ सलाहकार सभा के सदस्य के निमित्त शपथ का विवरण—

सलाहकार सभा का सदस्य मनोनीत हुआ मैं ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्री ५ महाराजाधिराज तथा मौसूफ के उत्तराधिकारियों के प्रति कानून द्वारा स्थापित अन्तरिम विधान के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा रखूंगा और अपने ग्रहण किए हुए पद के कर्तव्यों का पालन श्रद्धापूर्वक करूंगा।

परिशिष्ट

१

नेपाल के साथ वाणिज्य संधि—१ मार्च १७९२ ई०

महाराज रणबहादुर शाह बहादुर शमशेरजंग की लाल मोहर द्वारा यह संधि प्राधिकारित की गई। यह उस संधि के अनुरूप है जिसका पारपत्र मिस्टर जोनाथन डन्कन बनारस के रेजीडेंट ने राइट आनरेबुल चार्ल्स अर्ल कार्नवालिस के० जी० परिषद् सहित गवर्नर जनरल की ओर से किया तथा उक्त अधिकारी द्वारा उक्त महाराजा से वाणिज्य संधि निष्पत्ति करने की क्षमता प्राप्त की और आनरेबल इंगलिश कंपनी तथा नेपाल राज्यों की प्रजाओं द्वारा मुल्कों की प्रवेशता निश्चित एवं संनिवेशित की। उक्त महोदय के तत्वावधान में नेपाल की प्रजा द्वारा मुल्कों की प्रवेशता का एवं तदनुरूप में पूर्वोक्त महाराजा की कंपनी की राज्य प्रजा द्वारा नेपाल को मुल्कों की प्रवेशता निश्चित हुई। उक्त संधि मुझे (उक्त महाराजा) मौलवी अब्दुल कादिर खां पूर्वोक्त महोदय के वकील अथवा अभिकर्त्ता ने सौंपी। इसकी प्रतिवस्तु नेपाल राज्य द्वारा लिखी गई और उक्त खां महोदय को अर्पित की गई जैसी नीचे सूक्ष्म रूप में वर्णित है—

अभिधारा १—साधारण कल्याण के अभिनिवेश का विमर्शन करते एवं व्यापारियों व व्यवसायियों के सुख व सतोष के लिए, कंपनी और नेपाल दोनों राज्यों के प्रशासकों की ख्याति को समालोच कर, यह सम्मत एवं स्थिर किया जाता है कि दोनों देशों के आयात पर २½ की सदी के अनुपात में शुल्क लिया जायगा। यह शुल्क व्यापारियों के पास माल के बीजकों की राशि पर लगाया जायगा। उक्त व्यापारियों को मिथ्या बीजकों के प्रदर्शन से निवारण करने के लिए उक्त बीजकों के पृष्ठों पर दोनों पक्षों के नियामक कर गृह की मुद्रा अंकित कर दी जायगी उसकी प्रतिलिपि रख ली जायगी तथा मूल लिपि व्यापारियों को प्रत्यर्पण कर दी जायगी। व्यापारियों के पास मूल बीजक न होने की अवस्था में नियामक कर गृह के अधिकारी बाजार दर के अनुसार निर्धारित मूल्य पर २॥ की सदी शुल्क लगा देंगे।

अभिधारा २—दोनों देशों की सीमा के आमने-सामने के निर्दिष्ट स्थान शुल्क लगाने के लिए निर्धारित कर दिये गये हैं। इन स्थानों पर व्यापारियों का शुल्क जमा होगा और एक बार शुल्क दे देने पर तथा उसका रसीद प्राप्त कर लेने पर किसी अन्य प्रकार का या अधिक शुल्क दोनों देशों अथवा अधिराज्यों में देने की आवश्यकता न होगी।

अभिधारा ३—दोनों ओर के अधिकारियों में जो कोई निश्चित दरों के अधिशासन में अतिक्रमण करेगा अथवा शुल्क में बलपूर्वक आधान करेगा उसे संपुष्ट शासन द्वारा

उदाहरण स्वरूप दंड दिया जायगा जिससे अन्य ऐसे अपराधों के करने से निवारित हों।

अभिधारा ४—व्यापारियों के माल के चोरी अथवा लूट जाने की दशा में फौजदार अथवा उस स्थान का अधिकारी अपने उच्च अधिकारी शासन को प्रज्ञापित करके उक्त स्थान के जमींदार अथवा सत्ताधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए बाधित करेगा जो हर दशा में निश्चयात्मक रूप से व्यापारियों को दे दिया जायगा।

अभिधारा ५—दोनों देशों के व्यापारियों पर किसी प्रकार की हिंसा अथवा दमन होने की दशा में उस स्थान के अधिकारी जहाँ यह घटना घटित होगी तुरन्त पीड़ित व्यक्तियों की परिवेदना पर विचार एवं अनुसंधान करेगा तथा निरपेक्षतापूर्वक विचार करके अपराधियों को दंड देगा।

अभिधारा ६—नियुक्त शुल्क दे देने के पश्चात् दोनों देशों के व्यापारी अपना माल एक या दूसरे राज्य के अधिराज्यों में बेचने के लिए ले जा सकेंगे। यदि उनका माल एक राज्य में बिक गया तो ठीक है अन्यथा यदि व्यापारी अपना माल एक राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में परिवहन करने के इच्छुक होंगे जो इस संधि के अंतर्गत है तो परवर्ती राज्य के अधिकारी व प्रजा उस माल पर अधिक या अन्य कर केवल उतने के अतिरिक्त जो प्रथम प्रवेश पर दिया जा चुका है न ले सकेंगे। इस पर धून शुल्क का बलात् ग्रहण न होगा एवं किसी प्रतिरोध के उनका माल सुरक्षित रूप में बाहर जाने दिया जायगा।

अभिधारा ७—यह संधि दोनों राज्यों के वर्तमान एवं भविष्य शासनकर्ताओं पर पूर्ण रूप से बाध्य एवं वैध होगी। दोनों ओर से वाणिज्यिक संधि के रूप में विवेचित किये जाने के कारण दोनों राज्यों में पारस्परिक ऐक्य की भित्ति होगी तथा सदा के लिए जनता के लाभ और मैत्री की उन्नति के लिए होगी।

५वीं रज्जब १२०६ हिजरी और फसली पद्धति का ११९९ वर्ष तदनुसार १ मार्च १७९२ ईसवी अथवा २२ फाल्गुण १८४८ संवत् के दिनांक को दो संधियां एक ही अभिप्राय से दोनों संविदा पक्षों के निमित्त लिखी गईं। इन्होंने परस्पर अभियोजित किया है कि १ बैशाख १८४९ संवत् से दोनों राज्यों के अधिकारी अपने शासकों की आज्ञानुसार इसे तुरंत कार्यरूप में परिणत करेंगे तथा उपरोक्त अभिसंविदा का प्रतिपालन करेंगे तथा किसी एवं अन्य नवीन निर्देश की प्रतीक्षा न करेंगे।

२

नेपाल राजा के साथ संधि, १८०१

उच्च अभिज्ञान वर्गों महिमाशाली राजाओं एवं शासनकर्ताओं के ज्ञान दीप्त बोध का यह मध्याह्न सूर्य के समान सुस्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने राजाओं को विश्व की रक्षा एवं शासनभार प्रदत्त किया है जिनका प्रमुख न्याय है और आपस में मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने से सार्वभौम सुख और समृद्धि प्रतिभूत होती है और जिनसे

ही अधिक मैत्री एवं एकता के सम्बन्ध होंगे। दोनों ही अधिक सम्बन्ध स्थापना प्राप्त हुये। इन परिस्थितियों को विचार में रखते हुए हिज एक्सेलेन्सी परम अनिश्चल [illegible] जनरल मार्क्विस वलेजली [illegible] तथा महाराजा [illegible] और राजा [illegible] के मध्य मैत्री की पद्धति की स्थापना की है तथा निम्न अभिधाराओं को स्वीकृत किया है—

अभिधारा १—दोनों राज्यों व प्रजा और अधिकारियों के निमित्त यह आवश्यक व अपरिहार्य है कि दोनों देशों की मैत्री को पुष्ट करने व अविरल प्रयास करें और न्यायपूर्वक तथा निष्कपट भाव से राज्य और दोनों प्रजाओं की समृद्धि और पारस्परिक कल्याण हो।

अभिधारा २—विद्रोहियों के जो हमारी पारस्परिक मैत्री के विरोधक हैं मनगढ़न्त बातों और उत्पातजनक अभ्यावेदनों पर बिना अनुसंधान और प्रमाण के कोई ध्यान नहीं दिया जायगा।

अभिधारा ३—दोनों राज्यों के प्रधान और अधिकारी अपने राज्य के मित्रों और शत्रुओं को दूसरे राज्य के मित्रों और शत्रुओं सदृश आन्तरिक भाव से समझेंगे। इस सम्बन्ध की समता स्थायित्व रूप में वंशानुवंश रहेगी।

अभिधारा ४—यदि दोनों में से किसी राज्य की कोई पड़ोसी शक्ति किसी प्रकार की उत्तेजना के बिना, कोई तर्क-वितर्क विवाद या अभिसन्धि अन्यायपूर्वक दोनों में से किसी एक के प्रदेश को हथियाने के लिए प्रारम्भ करेगा और उस देश को लेने के लिए तदनुरूप अभिप्राय का पोषण करेगा हमारे स्वस्थ राज्य के वकील सारा विवरण राज्य के स्वामी को विदित करायेंगे जो दोनों राज्यों में अवस्थित मैत्री बाध्यता के कारण उक्त विवरण सुनने के बाद उचित उत्तर एवं प्रशस्ति देंगे।

अभिधारा ५—यदि कभी दोनों देशों के बीच सीमा या प्रदेश का विवाद उत्पन्न हो जाय तो उसका समाधान अपने निज के वकीलों अथवा अपने अधिकारियों द्वारा न्याय और अधिकार के सिद्धान्तों के अनुसार होगा और उक्त सीमा पर सीमा-चिह्न लगा दिया जायगा जो अविरत रहेगा जिसे वर्तमान और भविष्य के अधिकारी अपना पथ प्रदर्शक समझें और अधिकार लंघन न करें।

अभिधारा ६—जो स्थान कि नवाब-वजीर और नेपाल के अधिराज्यों के सीमान्त पर हैं तथा जिनके कारण कोई विवाद उठ खड़ा हो तो वे विवाद नेपाल राज्य और परमश्रेष्ठ नवाब वजीर के एक एक वकील के सम्मुख तथा कम्पनी की ओर के वकील की मध्यस्थता द्वारा तय किये जायेंगे।

अभिधारा ७—मुकवानीपुर के कारण इतनी संख्या में हाथी नेपाल के राजा कंपनी को भेजते हैं और इसलिए गवर्नर जनरल ने नेपाल के राजा के परितोषवर्धन के लिए, उक्त मैत्री सम्बन्ध तथा इस नई संधि का विचार करते हुए, ऊपर उल्लिखित राजस्व का अवत्याग व परित्याग कर दिया है और निर्देश करते हैं कि कंपनी के वर्तमान व

भविष्य अधिकारी वंशानुवंश तब तक जबतक इस संधि का नियमन अंगीकृत रहेगा (जबतक इस संधि के नियम लागू होंगे) राजा से कभी भी बलपूर्वक हाथी न लेंगे।

अनुच्छेद ८—यदि इन देशों का कोई प्रतिष्ठित या अधिवासी पलायन कर दूसरे देश में आश्रय ले और ऐसे व्यक्ति के लिए गवर्नर-जनरल के सम्मुख उपस्थित नेपाल राज्य के संस्थापित वकील द्वारा प्रार्थना की जाय या कम्पनी राज्य की ओर से उसके नेपाल स्थित प्रतिनिधि द्वारा तो ऐसी दशा में यह पारस्परिक समझौता किया जाता है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने राज्य के नियमों को अमान्य करके पलायन कर जाय तो दोनों राज्यों के प्रधानों के लिए यह अपरिहार्य है कि उसे अपने यहां स्थित वकील को तुरन्त सौंप दें और वह पूरी सुरक्षित दशा में अपने देश की सीमान्त पर भेज दिया जाय।

अनुच्छेद ९—महाराजा नेपाल ने अंगीकार किया है कि स्वामीजी को उनके खर्चे के लिए विशेषाधिकार की अथवा धार्मिक कृत्यों के निमित्त प्रदान की भूमि को छोड़कर, एक परगना उससे संलग्न भूमि सहित प्रदान कर दिया जाय। यदि स्वामी जी बनारस में निवास करें या कम्पनी राज्य के किसी प्रांत में रहें तो नियमित किस्तों में उन्हें वसूली की रकम दी जाया करेगी। वह धन वे अपने आवश्यक खर्चों में व्यवहार कर सकते हैं तथा नियमों के अनुसार अपने धार्मिक कृत्यों का प्रतिपालन कर सकते हैं। ये नियमन पोलक पत्र पर खुदे हैं जो उन्होंने राज को त्यागते समय अंगीकार किये थे तथा जिसका स्वत्वाधिकार मुझे प्राप्त है। पर यदि वे निश्चय करें कि वे अपनी जागीर में निवास की व्यवस्था करेंगे और वसूली स्वयं अपने अधिकारियों द्वारा करेंगे तो वे किसी प्रतिकूल मनुष्य को नौकर नहीं रखेंगे और सौ मनुष्यों तथा परिचारिकाओं के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का सैनिक की हैसियत से न रख सकेंगे। अपने रक्षकों के रूप में वे नेपाल सरकार के दो सौ सैनिक रख सकेंगे इनका वेतन राजा नेपाल देंगे। उन्हें सावधानी बर्तनी चाहिए कि किसी प्रकार के शब्द या वाणी द्वारा प्रतिकूल कार्रवाई न करें न उन्हें नेपाल देश के विद्रोही तथा झगड़ों को आश्रय देना होगा और न नेपाल की प्रजा पर मारकाट या अत्याचार करना होगा। यदि दोनों राज्यों का उनके आरोप के प्रमाण मिल जायेंगे तो कंपनी की सहायता और सुरक्षा उन पर से हटा ली जायगी और उस दशा में राजा नेपाल की इच्छा पर यह निर्भर होगा कि उनकी जागीर जब्त कर ली जाय।

महाराजा ने यह भी अपनी ओर से स्वीकार कर लिया है कि यदि स्वामी जी कंपनी के प्रांत में निवास करें, और नेपाल के अधिकारियों को भूमि की व्यवस्था सौंप दें तथा शर्तों के अनुसार किस्तें न दी जाय या वे मारे जायें उसी जागीर में बसें और नेपाल के अधिवासी उन्हें या उनके परगने के निवासियों को सताये तो उस दशा में कंपनी के गवर्नर जनरल उक्त व्यक्ति का मौन वध के लिए शिकायत करेंगे। गवर्नर जनरल राजा के कार्मों का पूरा करने का अधिकार लेते हैं और महाराजा तुरन्त ही ऊपर लिखी शर्तों के अनुसार उन मनुष्य को गवर्नर जनरल को सौंप देंगे। परगने की वसूली में यदि नाम

की प्राप्ति होगी या अधिकारियों की असावधानी से उसमें हानि होगी तो उसमें राजा-नेपाल का कोई सरोकार न होगा।

अभिधारा १०—इस संधि में लिखित अन्य कतिपय अभिप्रायों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, और अन्य मौखिक संधियों को सफल करने के लिए गवर्नर-जनरल और राजा नेपाल अपनी इच्छा और संतोष से एक विश्वस्त व्यक्ति को एक दूसरे के पास वकील नियुक्त करते हैं। वे सदैव अपने शासकों के सम्मुख उपस्थित रहेंगे। वे उपरोक्त वर्णित कार्यों का प्रतिपालन करेंगे तथा दोनों राज्यों के बीच मैत्री-भावों को दृढ़ करने में संलग्न रहेंगे।

अभिधारा ११—दोनों राज्यों के मुखियाओं तथा अधिकारियों के लिए यह आवश्य है कि वे दूसरे राज्य के वकीलों का उनके पदानुसार जैसा अन्तर्राष्ट्र में प्रचलित है समादर एवं सम्मान करें। तथा वे निरन्तर इसका प्रयास करें कि वे पूर्ण रूप से सुरक्षित सुख व शांति से अपना कर्तव्य पालन कर सकें तथा विदेश में अपने अपने राज्यों की प्रतिष्ठा स्थापन कर सकें।

अभिधारा १२—दोनों राज्यों के वकीलों का यह कर्तव्य होगा कि वे दूसरे देश की प्रजा व निवासियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखें ऐसा वे वहाँ के अधिकारियों द्वारा कर सकते हैं। बिना उन अधिकारियों की आज्ञा के वे किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी उनसे नहीं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई पत्र उन्हें मिले वे उसका उत्तर बिना उस राज्य के अधिपति के जनाये न दें तथा उस पत्र का पूरा ब्यौरा उन्हें सूचित कर दें जिससे हमारे बीच में सौहार्द एवं मैत्री की सम्भावना रहे।

अभिधारा १३—मुखियाओं और अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि इस संधि के वास्तविक तत्त्व को समझें जो उनके धर्म और विश्वास पर समावृत है। इसका प्रतिपालन वंशानुक्रम होगा तथा इसके प्रतिकूल कोई कार्य न होगा। जो कोई इसे भंग करेगा उसे इस संसार में तथा भविष्य में परमात्मा दण्ड देगा।

गवर्नर जनरल ने परिषद् सहित इसका अनुमोदन १० अक्तूबर, १८०१ ई० को तथा नेपाल दरबार के अनुसार २८ अक्तूबर, १८०२ ई० को किया।

दानापुर में राजा नेपाल द्वारा निष्पत्ति संधि की पृथक अभिधारायें

२६ अक्तूबर, १८०१

महाराजा इत्यादि इत्यादि से हिज एक्सिलेंसी परम उदार गवर्नर-जनरल के साथ पूर्वेहुएँ गुमानंद स्वामीजी महाराजा के महान् पिता के जीवन यापन के विषय में निम्नलिखित संधि संपादन हुई—

वार्षिक आमदनी जो पट्टा लिखत के अनुसार बयासी हजार रुपया है इस में से बहत्तर हजार नगद और दस हजार में हाथी दास व परिचारिकायें दी जायेंगी। यह स्वामी

जो के पारिवारिक व्यय के लिए विलम्ब सहा के वप में है और अगहन १८५८ से यह दी जायगी। इसको बने के लिए बीजापुर का परगना उसकी सारी भूमि सहित (कवल लगान माफ भूमि धार्मिक या अन्य दान संस्थाओं को अर्पित भूमि जागीर या जिसका विवरण अन्यत्र दिया है) स्वामी जी को प्रदान किया जाता है। इसकी शर्तें ये है। स्वामी जी के बनारस में वास करने पर, या माननीय कंपनी के प्रदेश में रहने पर, और उक्त जागीर की वसूली नेपाल राज्य के अधिकारियों द्वारा किये जाने पर, बहत्तर हजार रुपये नकद तथा दस हजार रुपये हाथियों के मूल्य में उन्हें प्रति वर्ष ठीक समय और नियत किस्त पर मिलते रहेंगे। इसकी प्राप्ति से स्वामी जी अपनी धोषणानुसार परमात्मा की आराधना में कालयापन करें। यह राज्य को महाराज के लिए छोड़ते समय पीतल पत्र पर खुदवाया गया था। यदि वे अपनी जागीर में रहें और वसूली अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त करें, तो यह आवश्यक है कि वे अपनी सेवा में विद्रोही व शांतिभंग करने वाले व्यक्ति न रखें। वे सौ मनुष्य और परिचारिकाओं से अधिक नहीं रख सकते हैं तथा अपनी अंगरक्षा के लिए किसी प्रकार का सैनिक नहीं रख सकते हैं। अपनी अंगरक्षा के लिए तथा परगने की वसूली के लिए वे राजा नेपाल से दो सौ सैनिक ले सकते हैं। इनका वेतन महाराजा नेपाल देंगे। उन्हें लिखित या कथित कोई ऐसा कार्य नहीं करना होगा जिससे उत्तेजना फैले न अपने पास विद्रोही या नेपाल से भागे हुए व्यक्तियों का प्रश्रय बना होगा और न उस राज्य में षड्यन्त्र करनी होगी। यदि दोनों दलों को इसका निश्चय हो जायगा कि उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है तो माननीय कम्पनी का सरपोषण हटा लिया जायगा और महाराजा नेपाल की इच्छा पर उनकी जागीर की जब्ती रहेगी। महाराजा ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि स्वामीजी माननीय कंपनी के प्रदेश में अपना स्थिर करें, और नेपाल राज्य के अधिकारियों को अपनी जागीरदारी की वसूली सौंपें और अगर निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें किस्त न मिलें अथवा वे अपनी जागीर में रहें और नेपाल की प्रजा उन्हें या रैयत को सतावे ऐसी दशाओं में गवर्नर-जनरल तथा माननीय कंपनी को राजा नेपाल से क्षतिपूर्ति कराने का पूर्ण अधिकार होगा। गवर्नर जनरल राजा नेपाल से इस शर्त का प्रतिपालन कराने को बाध्य हैं। और गवर्नर जनरल की प्रार्थना पर महाराजा तुरन्त ऊपर निर्देशित संधि की आज्ञाओं का प्रतिपालन करेंगे। स्वामीजी के अधिकारियों के परिचालन से यदि वसूली में वृद्धि होगी या किसी विपरीत कारण से उसमें ह्रास होगा तो इसमें महाराजा का कोई सरोकार न होगा। महाराजा ने स्वीकार किया है कि बीजापुर के परगने को स्वामीजी के अधिकारियों को दे देने के पश्चात् वार्षिक आय पच्चासी हजार के बराबर हजार रुपया होंगे यदि इसमें कमी हुई तो वह उसे पूरा कर देंगे और वसूली की दशा में उनके अधिकारी स्वामीजी होंगे।

गवर्नर जनरल ने परिषद् सहित १० अक्तूबर, १८०१ ई० को तथा नेपाल दरबार के अनुसार २८ अक्तूबर, १८ २ ई०, को अनुमोदित किया।

३

आनरेबुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराजा विक्रमशाह के मध्य मैत्री संधि।
इस आनरेबुल कम्पनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रेडशा ने जिन्हें हिज एक्सिलेंसी राइट
आनरेबुल फ्रांसिस मॉइरा के अर्ल आफ रिंक्स दि मोस्ट नोबुल आर्डर ऑफ गार्टर, जो
हिज मजेस्टी के परम आदरणीय राज-सभा सचिव हैं और जिनकी नियुक्ति आनरेबुल
कंपनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने ईस्ट इंडीज के निर्देशन और शासन के लिए की
और श्री गुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय ने गीर्वाण युद्ध विक्रम शाह
बहादुर, शमशेरजंग की ओर से उक्त अधिकार प्राप्त करने पर राजा नेपाल की ओर से प्रति
पादित किया— २ दिसम्बर, १८१५ ई ।
आनरेबुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा नेपाल के राजा में युद्ध छिड़ गया है और
दोनों ओर के इस शांति और मैत्री की पुनः स्थापना के इच्छुक हैं जो सम्प्रति मतैक्य के पूर्व
दोनों राज्यों के मध्य संस्थापित थे तथा निम्न संधि की शर्तें स्वीकृत की जाती हैं—
अभिधारा १—आनरेबुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी और राजा नेपाल के मध्य चिर
स्थायी शांति व मैत्री रहेगी।
अभिधारा २—युद्ध के पूर्व दोनों राज्यों के बीच जिन प्रदेशों के लिए वादानुवाद
था नेपाल के राजा उनका परित्याग करते हैं। और उन प्रदेशों पर आनरेबुल ईस्ट इण्डिया
कम्पनी के एकाधिपत्य का अधिकार स्वीकार करते हैं।
अभिधारा ३—नेपाल के राजा आनरेबुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रति निम्न
सूचित भूमि खंड चिरस्थायी रूप से परित्याग करते हैं अर्थात्—
प्रथम—काली और राप्ती सरिताओं के मध्य की समस्त नीची भूमि
द्वितीय—राप्ती और गण्डक के मध्य की समस्त नीची भूमि (बुटवल खास को
छोड़कर)
तृतीय—गण्डक और कुसाह के मध्य की समस्त नीची भूमि जहाँ ब्रिटिश शासन का
अधिकार प्रारंभ हो चुका है अथवा प्रारंभ होने जा रहा है।
चतुर्थ—मेची और तिस्ता सरिताओं के मध्य की समस्त नीची भूमि और
पंचम—मेची सरिता के पूर्वी पर्वतमालाओं का समस्त भूमिखंड जिसके अन्तर्गत
नगरी का दुर्ग व भूमिखंड है और नगरकोट का गिरिपथ जो मोरंग से पर्वतों में
गया है तथा यह भूमिखंड जो उक्त गिरिपथ और नगरी के मध्य है। उपरोक्त भूमिखंड
को गोरखा सेना इस तिथि से चालीस दिनों के अन्दर खाली कर देगी।
अभिधारा ४—नेपाल राज्य के प्रमुखों और भारदारों की क्षतिपूर्ति के लिए,
जिनके स्वार्थों का पिछली अभिधाराओं में वर्णित भूमि के हस्तांतर से हानि पहुँची है,
ब्रिटिश शासन ने उन प्रमुखों को सम्मिलित रूप में दो लाख रुपया पेंशन देना स्वीकार किया
है जो नेपाल के राजा द्वारा मनोनीत किये जायेंगे और जिसका अंश राजा स्थापित करेंगे।

प्रवरण हो जाने के पश्चात् पेंशन के लिए गवर्नर-जनरल की मुद्रा और हस्ताक्षर सहित सनदें प्रदान की जायेंगी।

अभिधारा ५—राजा नेपाल अपनी ओर से अपने वारिसों और उत्तराधिकारियों की ओर से उन प्रदेशों से सम्बन्धित जो काली सरिता के पश्चिम में हैं समस्त अधिकारों का परित्याग करते हैं और उन प्रदेशों से अथवा वहां के निवासियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखना अंगीकार करते हैं—

अभिधारा ६—नेपाल के राजा सिक्कम के राजा को उनके प्रदेशों के अधिकार के बारे में किसी प्रकार का सतामा या शान्तिभंग न करना अंगीकार करते हैं परन्तु यह स्वीकार करते हैं कि यदि नेपाल के राज्य और सिक्कम के राजा के या उनकी प्रजा के मध्य कोई विवाद होगा तो वह विवादास्पद विषय ब्रिटिश शासन की मध्यस्थता के लिए प्रेषित किया जायगा और उनका निर्णय नेपाल के राजा को मान्य होगा।

अभिधारा ७—नेपाल के राजा अंगीकार करते हैं कि अपनी सेवा में कोई ब्रिटिश प्रजा या किसी यूरोपीय और अमरिका की प्रजा को बिना ब्रिटिश शासन की सम्मति के नहीं रखेंगे।

अभिधारा ८—दोनों राज्यों में मित्रता और शान्ति के सम्बन्धों को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए यह स्वीकार किया जाता है कि एक राज्य के विश्वासपात्र मंत्री दूसरे राज्य में रहेंगे।

अभिधारा ९—यह सन्धि जिसमें ९ अभिधारायें हैं नेपाल के राजा द्वारा इस तिथि से पंद्रह दिन में अनुमोदित की जायगी और उसका अनुमोदन लफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशा को दे दिया जायगा जो गवर्नर-जनरल का अनुमोदन राजा को बीस दिनों के अन्दर या उससे शीघ्र दे देंगे।

२ दिसम्बर, १८१५ को सिगौली में सम्पादित हुई

परिस ब्रैडशा—लेफ्टि. क पी ए

नेपाल के राजा का भार मे उनके अभिकर्ता चन्द्रशेखर उपाध्याय से यह संधि ढाई बजे मध्याह्नोत्तर ४ मार्च १८१६ को मिली और संधि की प्रतिलिपि ब्रिटिश शासन की ओर से उन्हें प्रदान की।

डी डी आक्टरलोनी

एजेंट गवर्नर-जनरल

४

मपाल के राजा की स्वीकृति और अनुमोदन के लिए स्मरण-पत्र

८ दिसम्बर १८१६ को अर्पित

१ नेपाल के राजा के साथ मैत्री और विश्वास के कारण ब्रिटिश शासन सिगौली की

संधि की कुछ अभिव्यक्तियों में सामर्थ्यानुसार कमी करना चाहते हैं जिनका पालन राजा के लिए कठिन है।

२ एक विषय पर जो राजा के मन में अधिक है और उन्हें संतुष्ट करता है ब्रिटिश शासन तराई के हस्तगत प्रदेश को उन्हें दे देना चाहता है। तराई का वह प्रदेश जो कूसा और गंडक के बीच में है केवल तिरहुत और सारन के विवादास्पद प्रदेशों को छोड़कर, तथा उन ऐसे प्रदेश के भागों को छोड़कर जो सीमा निर्धारित करने के लिए छोड़े जायेंगे तथा उस भूमि को छोड़कर जो ब्रिटिश शासन के अधिकार में आया है। यदि राजा इस प्रदेश को दूसरे प्रदेश के बदले लेना चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि तिरहुत जिले के उस विस्तृत भूभाग को जो काफी समय तक विवाद का विषय रहा है १८१२ ई० का समझौता तदनुसार १८१६ वि० मान्य होगा तथा अन्य विषय छोड़ दिये जायेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के समझौते और संधियाँ इस मामले में मान्य होंगी।

३ ब्रिटिश शासन गंडक और राप्ती के बीच की तराई अर्थात् गंडक से गोरखपुर जिले की पश्चिमी सीमा तक साथ बुटवल व शिवराज जो विवाद के पूर्व नेपाल के पास था उन्हें दे देना चाहता है। इसमें तराई के विवादास्पद प्रदेश तथा सीमा निर्धारण के लिए भूमि शामिल नहीं है।

४ बिना नापजोख किए दोनों पक्षों की सीमा तय हो सकना असम्भव है इससे यह ठीक होगा कि दोनों ओर से कमिश्नर नियुक्त किये जायें जो पिछले नियमों के अनुसार सीमा निर्देश करें और सीमान्त की सीधी रेखा निर्धारित कर जिससे दोनों देशों के प्रदेशों का उचित विभाजन हो जाय नेपाल का उत्तर में ब्रिटिश राज्य का दक्षिण में।

५ यदि ऐसा हो कि भूमि के स्वामी दोनों सामान्तों पर अवस्थित हों तो वे नेपाल के राजा के तथा ब्रिटिश शासन की प्रजा समझे जायेंगे जिससे दोनों राज्यों में वितण्डावाद व विवाद न बढ़े। कमिश्नर आपस में तय करके उन्हें एक राज्य की प्रजा बनाने का प्रयास करें।

६ तराई का भूभाग कभी भी मिल जाने पर नेपाल के राजा को वार्षिक दो लाख रुपया देना बन्द हो जायगा जिसे ब्रिटिश शासन ने कुछ भारदारों के लिए देना स्वीकार किया था।

७ इसके अतिरिक्त नेपाल के राजा ने स्वीकार किया है कि तराई के निवासी को दंड न दें, जब उस पर उनका प्रभुत्व हो जाय क्योंकि इन्होंने युद्ध के समय ब्रिटिश राज्य की सहायता की थी। और काश्तकारों को छोड़कर यदि कोई कम्पनी की सीमा में आना चाहे तो उसे रोका न जाय।

८ इन शर्तों को मानने के बाद सीमा-निर्धारण का कार्य किया जायगा और

सीमा चिह्न लगा दिए जायेंगे। तत्पश्चात् दोनों देश सनद तैयार कर और मुहर लगाकर एक दूसरे को देंगे और स्वीकार करेंगे।

एडवर्ड गार्डनर
रेजीडेंट

नेपाल के राजा के एक पत्र का सारांश—११ दिसम्बर, १८१६ ई० अभिवादन के पश्चात्—

मैंने ८ दिसम्बर १८१६ अर्थात् पौष ४ १८७३ संवत् का मसौदा पढ़ा जिसमें आपने गंडक और राप्ती के बीच की तराई देना तय किया है। यह हमारे संतोष और मैत्री को देखते उचित है। मैं नियमों को स्वीकार करने पर तराई की दक्षिणी सीमा वही हो जायगी जैसी हम शासन की थी। मुझे आपकी संधि की धारायें स्वीकृत हैं। आपने यह भी सूचित किया कि विवादास्पद भूमि को छोड़कर तथा कमिश्नरों द्वारा सीमा-निर्धारित भूमि को छोड़कर बाकी प्रदेश दे दिया जायगा। इन तथा अन्य विषयों पर आप को चाहें करें। सिगौली की संधि का हवाला देकर आपने यह कहा है कि मेरी मैत्री व स्नेह के कारण आप उसकी कुछ शर्तें हटा देना चाहते हैं। मैं पूर्ण रूप से समझता हूँ कि हृदय से आप मेरी चिन्ता दूर ही करना चाहते हैं तथा आप ऐसा काम करेंगे जिसमें इस देश की भलाई होगी तथा दोनों राज्यों में मैत्री सुदृढ़ होगी।

मैं उस आज्ञा की प्राप्ति सूचित करता हूँ जो हमारे राज्य की लालमोहर द्वारा अंकित है जो गंडक तथा राप्ती के बीच की तराई के अधिकारियों को संबोधित है जिसमें उनके वहां से हटने का तथा तराई के दल का आदेश है। यह आपको थानेकोर पर मिली थी और आपने मेरे सन्तोष के लिए लौटा दी है।

५

ठगों के आत्म-समर्पण के विषय में दरबार से प्राप्त कागज

२० जनवरी १८२७

जब कोई अनुमोदनकारी उस विष द्वारा या गला घोटकर किसी हत्या की सूचना देवे और हत्या करने वाला नेपाल का निवासी हो सूचना में हत्या करने वाले की पूरी हुलिया उसके परिवार की संख्या आर्थ-संबंधी गांव का नाम इत्यादि का पूर्ण विवरण हो और वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा जाँच-पड़ताल करने पर यह विदित हो कि अभियुक्त उस स्थान का स्थायी अधिवासी नहीं है उसके परिवार का पता-ठिकाना नहीं है उसके भरण-पोषण का ठीक ठिकाना नहीं है परन्तु वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता है अथवा यह पता चले कि वह आस-पास तीन-चार महीनों तक रहता है भरण-पोषण का ठौर-ठिकाना न होने पर भी वह अनुपस्थित रहा है और जब अनुमोदनकारी के बताये मारे या पीड़ी कमाई करने इस में मन लगा जाये तब नेपाल राज्य ऐसे व्यक्ति को ब्रिटिश

राज्य में न्याय व दंड के लिए सौंप देगा। इससे विपरीत दशा में यह आशा की जाती है कि ब्रिटिश राज्य के मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को तराई के नेपाल पदाधिकारियों को न्याय व दंड के लिए समर्पण कर देंगे और नेपाल द्वारा यदि अनुमोदनकारी की सूचना जाँच पड़ताल पर ठीक न निकलेगी तो समर्पण रोक लिया जायगा।

६

महाराजा नेपाल का रेजीडेंट को पत्र—लाल मुद्रांकित समझौते का अनुवाद—

६ नवम्बर १८३९

आपकी (रेजीडेंट) प्रार्थना के अनुसार तथा दोनों राज्यों में मैत्री चिरस्थायी करने के लिए और प्रतिपादन का काम मुबारक रूप से चलता रहने के लिए, निम्न पद स्थिर किये जाते हैं—

2779

१ समस्त वार्ता वह या लिखित गुप्त षड्यन्त्र बिल्कुल बन्द कर दिए जायें।

२ नेपाल राज्य कम्पनी पर निर्भर गंगा-पार मित्रराज्यों से कोई सम्बन्ध न रखेगा जिन्हें संधि द्वारा संपर्क रखने की मनाही है, ऐसा रेजीडेंट के आदेशपत्र व स्वीकृति से किया जायगा।

३ गंगा के इस पार के जमींदारों व बाबुओं से जिनका नेपाल के राजघराने से व्याहिक सम्बन्ध है नेपाल राज्य से व्यक्तिगत व पत्रों द्वारा संपर्क रहेगा।

४ दोनों सरकारों के पथ प्रदर्शन के लिए यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायायिक विषयों में असैनिक मामले जहां के होंगे वहीं निर्णय किये जायगे। नेपाल राज्य ने स्वीकार किया है कि ब्रिटिश प्रजा नेपाल की कचहरी में असैनिक मामलों में जबरदस्ती वकालत करने के लिए बाध्य न किये जायेंगे।

५ नेपाल राज्य ने स्वीकार किया है कि जहां तक न्याय मामलों का सम्बन्ध है ब्रिटिश प्रजा नेपाल प्रजा के समकक्ष रहेगी तथा नेपाल की रीति के अनुसार उनका भी न्याय होगा।

६ नेपाल राज्य ने स्वीकार किया है कि एक प्रामाणिक बिवरणी रेजीडेंट को दी जायगी जिसमें नेपाल में लगाए मुल्कों का ब्यौरा होगा। इसके बाद ब्रिटिश प्रजा पर कोई अन्य निर्यात-कर जो इस बिवरणी में नहीं है न लगाया जायगा।

७

एक इकरारनामा का अनुवाद इस पर गुरुओं मुखियों इत्यादि ने ने हस्ताक्षर किये। १ तिथि शनिवार पूस सुदी ९, १८९७ तदनुसार जनवरी १८४१

हम निम्न हस्ताक्षरित मुखिया इत्यादि पूर्ण रूप से निम्नलिखित भावनाओं का प्रभावर स्वीकार करते हैं—

नेपाल और ब्रिटिश राज्यों में उत्तरोत्तर सुदृढ़ मैत्री की अभिवृद्धि हो। और इस लिए कम्पनी से मैत्री सम्बन्ध बढ़ाने के प्रत्येक कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। रेजीडेंट के साथ सदा और सर्वदा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी कारण ऐसी घटना घटित हो जिससे हमारे पारस्परिक मैत्री सम्बन्ध विशृंखलित हों या काठमाण्डू में अशांति और गड़बड़ी हो तो उसका दायित्व हम पर है।

१४ मुखियों द्वारा हस्ताक्षरित

८

आनरेबुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी व हिज़ हाइनेस महाराजाधिराज सुरेन्द्र विक्रमशाह बहादुर नेपाल के राजा में संधि—१० फरवरी १८५५

आनरेबुल ईस्ट इण्डिया कम्पनी व हिज हाइनेस महाराजाधिराज सुरेन्द्र विक्रमशाह बहादुर शमशेरजंग राजा नेपाल के मध्य संधि हुई जिसे एक ओर मेजर जनरल रैमसे रेजीडेंट जिन्हें मोस्ट नोबुल जेम्स एण्ड मार्क्विस ऑफ डलहौजी ने अधिकार दिया तथा दूसरी ओर जनरल जंग बहादुर कुंवर राणा जी—नेपाल के प्रधान मंत्री ने जिन्हें महाराजाधिराज सुरेन्द्र विक्रम शाह बहादुर जंग नेपाल के राजा ने अधिकार दिया निष्पत्ति की।

अभिधारा १—दोनों राज्य निम्नलिखित आदान-प्रदान का पालन करेंगे

अभिधारा २—शासन किसी ऐसे व्यक्ति को जो मांगने वाले राज्य की प्रजा नहीं है नहीं सौंपेगा।

अभिधारा ३—कोई राज्य किसी ऋणी या अनैतिक अपराधी या ऐसे व्यक्ति को जो अभिधारा ४ के अन्तर्गत दोषों की सूची में नहीं आता है नहीं सौंपेगी।

अभिधारा ४—ऊपर लिखी अभिधाराओं के अतिरिक्त यदि कोई राज्य एक व्यक्ति को मांगेगा जो दूसरे राज्य की सीमा में होगा और इन अपराधों को करेगा तो सौंप दिया जायगा। अपराध ये हैं—हत्या हत्या का प्रयास बलात्कार, अंगहीन करना ठगी डकैती राजमार्ग पर चोरी विष देना चोरी और आग लगाना।

अभिधारा ५—जिस राज्य में अभियुक्त का न्याय हो सकता है उसके भागने पर तथा पर्याप्त प्रमाण मिल जाने पर कि उसने अपराध किया है वह पकड़कर दूसरे राज्य में सौंपा जायगा।

अभिधारा ६—कोई व्यक्ति जो नेपाल की प्रजा न हो तथा रेजीडेंट की सीमा में रहता हो उस सीमा से बाहर नेपाल की सीमा में ऐसा अपराध करे जो नेपाल राज्य द्वारा दंडनीय है तो वह पकड़कर ब्रिटिश रेजीडेंट को न्याय के लिए सौंप दिया जायगा। परन्तु ऐसी दशा में नेपाल की प्रजा को नेपाल राजदण्ड के लिए नहीं सौंपेगा। यदि कोई हिन्दुस्तानी व्यापारी जो नेपाल सीमा में रहता है और रेजीडेंसी सीमा से बाहर अपराध करता

है, जो नेपाल राज्य में दंडनीय है और रेजीडेंसी सीमा में शरण लेता है उसे नेपाल राज्य में न्याय व दंड के लिए सौंप दिया जायगा।

अभिधारा ७—ऊपर वर्णित धाराओं में जो राज्य अपराधी का मांगता वही मामले उस कार्य में वहन करेगा।—

अभिधारा ८—यह संधि उस समय तक चलेगी जब तक कोई किसी ओर का उच्च पदाधिकारी उसके समाप्त होने की सूचना न दे।

अभिधारा ९—किसी संधि के प्रतिकूल होने के अतिरिक्त सभी वर्तमान संधियाँ मान्य समझी जायेंगी।

९

नेपाल से संधि १ नवम्बर १८६०

सन् १८५७ में बंगाल की देशी सेना के विद्रोह के कारण जो उत्पात हुए उसमें महाराजा नेपाल ने सिगौली की संधि की मैत्री और शांति स्थापित करने के लिए हुई थी उसका पूर्ण रूप से प्रतिपालन किया और ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता के लिए सीमान्त देशों पर शांति स्थापना रखने के लिए सेना की सहायता दी। बाद में लखनऊ का पुनः हस्तांतरित करने व विद्रोहियों के दमन के लिए ब्रिटिश सेना को सैनिक सहायता देकर सहयोग प्रदान किया। इन प्रयत्नों के समाप्त हो जाने के बाद वायसराय व गवर्नर जनरल ने उनको इस सहायता के पुरस्कार में उन्हें काली सरिता व गोरखपुर जिले के बीच की समस्त नीची भूमि लौटा देने का निश्चय किया है जो १८१५ में नेपाल के आधीन थी और उक्त संधि के अनुसार ब्रिटिश राज्य को प्राप्त हुई थी। ये प्रदेश कमिश्नर की देख-रेख में है तथा सीमा पर स्थापत्य चिह्न बना दिये गये हैं जो दोनों देशों की सीमा निर्धारित करते हैं। नेपाल राज्य को स्थायी रूप से इन प्रदेशों पर अधिकार रखने के लिए, और उक्त प्रदेश के पुनः देने की गंभीरता का विचार करके निम्नलिखित संधि दोनों देशों के बीच निष्पन्न की जाती है—

धारा १—महाराजा नेपाल और ब्रिटिश शासन के बीच अब तक की सब संधियाँ या संयोजित धारायें केवल वे या इस संधि द्वारा बदली जायें स्वीकृत की जाती हैं।

धारा २—ब्रिटिश शासन महाराजा नेपाल को काली और राप्ती सरिताओं के बीच की समस्त नीची भूमि प्रदान करता है तथा राप्ती सरिता और गोरखपुर जिले के बीच की समस्त नीची भूमि भी देते हैं। ये १८१५ तक महाराजा नेपाल के आधीन थी और ब्रिटिश शासन में सिगौली की संधि के अनुसार आई जो ७ दिसम्बर के उसी वर्ष में हुई।

धारा ३—काली सरिता या धारा से बघौराताल के उत्तरीय पर्वत शृंखला के नीचे तक जो सीमान्त रेखा ब्रिटिश कमिश्नरों ने स्थापत्य रूप में निर्धारित की है अब से ब्रिटिश प्रांत अवध और महाराजा नेपाल के प्रदेशों के मध्य की सीमा होगी।

हिज एक्सिलेंसी राइट आनरबुल चार्ल्स जॉन अर्ल केनिंग वायसराय और गवर्नर जनरल की ओर से नियुक्त लफ्टिनेंट कर्नल जार्ज रेमसे और महाराजाधिराज सुरेन्द्र विक्रम शाह बहादुर शमशेर जंग की ओर से नियुक्त महाराजा जंग बहादुर राणा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर के बाद तीस दिनों के भीतर इसका अनुमोदन काठमाण्डू में होगा।

१ ११ १८६० तदनुसार ३ कार्तिक बदी १९१७ वि
जी. रेमसे ले. क. नेपाल के रजीडेंट—

यह संधि हिज एक्सिलेंसी गवर्नर-जनरल द्वारा कलकत्ते में १५ नवम्बर, १८६० को अनुमोदित हुई।

ए. आर. यंग
डिप्टी सेक्रेटरी भारत सरकार

१०

२१ जुलाई, १८६६ का स्मृति-पत्र—नेपाल राज्य के साथ १०-२-५५ की संधि का परिपूरक। आपस में भोपवतय अपराधियों को सौंपने का विषय उक्त संधि की चौथी अधिधारा में पशु चुराने वन पदाधिकारियों द्वारा अपहरण और बुरदर धारों के अपराधों का संकलन— २१ जुलाई १८६६।

हिज एक्सिलेंसी व राइट ऑनरबल सर जॉन लेयर्ड मेयर लॉरेंस हूर मजेस्टी के ब्रिटिश भारत के वायसराय व गवर्नर-जनरल द्वारा प्राधिकारित कर्नल जॉर्ज रमसे नेपाल राज्य में रेजीडेंट और महाराजाधिराज नेपाल द्वारा प्राधिकारित महाराजा जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधान मंत्री व सेनापति के मध्य यह निर्णीत और निष्पत्ति हुआ।

१० फरवरी १८५५, तदनुसार ८ फागुन १९११ सं० का काठमाण्डू में जो संधि हुई थी उसकी सब धारायें मान्य करते हुए, तथा सीमान्त झगड़ों का रोकने के लिए, और, शीघ्रातिशीघ्र पशु अपहरण जनपदाधिकारियों द्वारा अपहरण और बुरदर धारों को रोकने की इच्छा से जिनमें धारी किया कम मरणिक हो या शारीरिक हिंसा की गई हो य अपराध भी अपराधों की सूची में सम्मिलित किये जायेंगे जिनमें कोई भी शासन सौंप देन की माँग कर सकता है। ये अपराध उक्त संधि की चौथी अधिधारा में संकलित किये जा रहे हैं।

२१ जुलाई १८६६ तदनुसार २६ आषाढ़ १९२३ सं० को काठमाण्डू में निष्पत्ति हुई।

जी. रेमसे कर्नल
नेपाल के रजीडेंट
जॉन लारेंस
गवर्नर-जनरल

हिज एक्सिलेंसी गवर्नर-जनरल ने शिमला में इस संधि को १ अगस्त १८६६ को अनुमोदित किया ।

डब्लू म्यूर
मन्त्री भारत सरकार

११

नेपाल के साथ संधि—७ जनवरी १८७५

हम दोनों असिस्टेंट कर्नल जार्ज एच. मैक एन्ड्रू, न्यायाधीश सीतापुर के कमिश्नर और ब्रिटिश शासन की ओर से नेपाल सीमा निर्धारण करने को नियुक्त कमिश्नर और कर्नल सिद्धमान सिंह साहब बहादुर राज भंडारी नेपाल राज्य की ओर से नियुक्त सूबा पर्वत मानस की सीमा नियुक्त करने वाले एकमत होकर निश्चय करते हैं कि दोनों राज्यों की सीमा सूबा पवनमाला पर से खारा नदिया से लेकर बगौरा ताल के ऊपर की पवन सुखना व गैलबाबु तक जहाँ वे मैदान में मिलती हैं निम्न नियमों पर तय होती है—

एक—ब्रिटिश राज्य की प्रजा को पहाड़ों में रास्ता मय मालमता उन वहाँ उसी रूप की शर्तों पर मिलती जैसी तम्भीपुर में थी ।

दो—सेन भाषकारी द्वारा निर्णीत पवन व नौच की सीमा नेपाल राज्य को मान्य होगी ।

जार्ज एच. मैक एन्ड्रू, क० क०
७ जनवरी १८७५ कमिश्नर ब्रिटिश सरकार
नेपाली अक्षरों में हस्ताक्षरित

१२

१० फरवरी १८५५ ई० तदनुसार ८ फागुन १९११ संवत की संधि और २१ जुलाई, १८६६ ई० तदनुसार २६ आषाढ़ १९२३ के स्मरण-पत्र का परिपूरक अपराधियों को सौंपने के लिए तय हुआ—२४ जून १८८१ ।

हिज एक्सिलेंसी मार्क्विस आफ रिपन वायसराय व गवर्नर-जनरल ब्रिटिश भारत द्वारा प्राधिकारित चार्ल्स एडवर्ड गिरडले नेपाल के रेजीडेंट और महाराजाधिराज नेपाल द्वारा प्राधिकारित महाराजा सर रणोदीपसिंह राणाबहादुर नेपाल के प्रधान मंत्री व सेनापति यह स्वीकार करते हैं कि दंड-भुगतान की अवधि में यदि कोई व्यक्ति दंड पाने के बाद भाग जाता है तो वह अपराध उक्त संधि की चौथी अधिकारा के अन्तर्गत सम्मिलित हुआ ।

काठमाण्डू में २४ जून १८८१ तदनुसार १३ आषाढ़ १९३८ को निष्पादित हुआ ।

चार्ल्स एडवर्ड गिरडलस्टन में
नेपाल रेजीडेंट
रिपन भारत के वायसराय तथा गवर्नर-जनरल

१३

ग्रेट ब्रिटेन और नेपाल के मध्य मैत्री संधि। यह काठमाण्डू में निष्पादित हुई और २१ दिसम्बर १९२३ को हथियार भेजने के विषय में नोट लिखा गया।

संधि

ब्रिटिश राज्य और नेपाल राज्य के मध्य मैत्री और शांति स्थापित हो चुकी है। सिगौली की संधि के बाद (२ दिसम्बर, १८१५) नेपाल राज्य उत्तरोत्तर मित्रता प्रदर्शित कर रहा है और ब्रिटिश राज्य भी अपना स्नेह प्रदर्शित करता रहा है। अब दोनों राज्य और अधिक सुसम्बन्ध स्थापित करने को इच्छुक हैं जो लगातार एक शताब्दी से चले आ रहे हैं। अतएव यह संधि दोनों ओर से निष्पादित की जाती है—

धारा १—ब्रिटिश राज्य और नेपाल राज्य में चिरस्थायी मैत्री व शांति रहेगी। दोनों राज्य परस्पर एक दूसरे की अंतर्बाह्य स्वाधीनता का मान्य करेंगे।

धारा २—अब तक की सब संधियाँ नियम-पत्र स्वीकृतियाँ सिगौली की संधि (१८१५) सहित पूर्वतः निष्पादित की जाती हैं। वर्तमान संधि द्वारा थोड़ा-सा परिवर्तन किया जाता है।

धारा ३—चूंकि दोनों देशों की सीमा एक स्थान पर मिलती है और मैत्री व शांति की आवश्यकता दोनों ओर अति आवश्यक है एक दूसरे को सूचित करने के लिए यह निर्णय किया जाता है कि यदि किसी कारण परस्पर वाद-विवाद हो जाय जो मैत्री में बाधक हो तो हर प्रकार से आपस की नासमझी दूर करने की चेष्टा की जायगी।

धारा ४—दोनों ओर से यह चेष्टा की जायगी कि एक दूसरे की सीमा परस्पर हानि के लिए व्यवहृत न हो।

धारा ५—दोनों देशों में जो सदा से मैत्री व शांति रही है उसे विचार में रखते तथा पड़ोसी होने के नाते सुसम्बन्ध बनाये रखने के लिए ब्रिटिश राज्य यह तय करता है कि नेपाल राज्य ब्रिटिश भारत से नेपाल में हर प्रकार के हथियार, गोला-बारूद सैनिक सामग्री तथा अन्य सामान जो नेपाल को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा ले जा सकता है। और यह प्रबन्ध उस समय तक चालू रहेगा जबतक ब्रिटिश राज्य को पूर्णतः इसका विश्वास रहेगा कि नेपाल राज्य के विचार मैत्रीपूर्ण हैं और भारत को इनकी वस्तुओं के निर्यात से कोई भय नहीं है। नेपाल राज्य यह पालन करने को बाध्य है कि कोई सैनिक सामग्री नेपाल की सीमा से बाहर नेपाल राज्य या अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं भेजा जायगा।

धारा ६—नेपाल राज्य द्वारा बाहर भेजे माल पर ब्रिटिश बंदरगाहों पर कोई निषकासन कर नहीं पड़ता। इसके लिए अधिकारियों द्वारा एक निरीक्षण-पत्र निषकासनगृहों पर जो दोनों राज्यों द्वारा समय-समय पर [illegible] होगा, दिखाना होगा। निरीक्षण

पत्र में यह सूचित होगा कि माल नेपाल राज्य का है तथा नेपाल राज्य की जनसेवा के लिए है और नेपाल को नेपाल राज्य की आज्ञा से प्रेषित किया जा रहा है। यह माल तुरन्त काठमाण्डू भेज दिया जायगा।

धारा ७—यह संधि ब्रिटिश राज्य की ओर से ले० क० डब्लू ओ. कानर नेपाल में ब्रिटिश राजदूत द्वारा तथा नेपाल राज्य की ओर से जनरल महाराजा सर चन्द्रशमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधान मंत्री व सेनापति द्वारा मनोनीत होगी और उसका विनिमय काठमाण्डू में शीघ्र ही होगा।

काठमाण्डू में हस्ताक्षर किए गये व मोहर लगी। ति २१ दिसम्बर, १९२३ ई० तदनुसार ६ पौष १९८० ई।

डब्लू एफ. टी ओ' कानर
ब्रिटिश राजदूत
नेपाल के लिए

(स्थानीय भाषा में अनुवाद)
चन्द्र शमशेर
प्रधान मंत्री नेपाल सेनाध्यक्ष

नोट—नेपाल के मंत्री की ओर से नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत को।

नेपाल दिसम्बर २१ १९२३

प्रियवर कर्नल ओ' कानर,

नेपाल की सुरक्षा एवं भलाई के लिए नेपाल राज्य जो हथियार व युद्ध-सामग्री खरीदता है और उस मार्ग प्रदेशों में ब्रिटिश भारत द्वारा मंगाता है जो धारा ५ की दोनों राज्यों के बीच की संधि के अनुसार है नेपाल राज्य यह निश्चय करता है कि हथियार ब्रिटिश बन्दरगाहों में निर्यात करने के पूर्व उसका पूर्ण विवरण नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत को सूचित कर दिया जायेगा जिससे ब्रिटिश भारत बंदरगाह के अधिकारियों को इस विषय में उचित आदेश दे सके और उनका निर्यात इस संधि की छठी धारा के अनुसार हो सके।

भवदीय

चन्द्र

ले० क० डब्लू एफ. टी ओ' कानर सी आई ई., सी वी ओ. नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत की सेवा में।

१४

भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच शांति और मैत्री की संधि

भारत सरकार और नेपाल सरकार इस तथ्य का अभिज्ञान करते हैं कि सौभाग्यवश से दोनों देशों में शताब्दियों से प्राचीन बन्धन विद्यमान हैं। इन सम्बन्धों को और अधिक सबल एवं विकसित करने की इच्छा से तथा दोनों देशों में चिरस्थायी शान्ति स्थापित करने के निमित्त

परस्पर शांति व मैत्री की संधि के प्रवृत्त करने में कृतसंकल्प होते हैं और इसके निमित्त निम्न व्यक्तियों को पूर्णाधिकारी नियुक्त करते हैं अर्थात्

भारत सरकार

परमश्रेष्ठ चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह नेपाल में भारतीय राजदूत

नेपाल सरकार

मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा महाराजा प्रधान मंत्री तथा सर्वोच्च महा सेनापति नेपाल

जिन्होंने एक दूसरे के अभिज्ञानपत्र परीक्षण किये और उन्हें यथार्थ और निर्दिष्ट मुताबिक पाकर निम्न धाराओं में सम्मत हुए—

धारा १—भारत सरकार व नेपाल सरकार में चिरस्थायी शान्ति व मैत्री रहेगी। दोनों सरकार एक दूसरे के सम्पूर्ण प्रभुत्व प्रादेशिक अखण्डता और स्वतन्त्रता को स्वीकार और सम्मान करने के लिए परस्पर सम्मत हैं।

धारा २—दोनों सरकारें किसी पड़ोसी राज्य में विग्रहजनक संघर्ष या भ्रांति जिसमें दोनों सरकारों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध में विच्छेद होने की संभावना है परस्पर सूचित करना अंगीकार करते हैं।

धारा ३—धारा १ में निर्दिष्ट सम्बन्धों को दृढ़ एवं समर्थन करने के लिए दोनों सरकारें परस्पर प्रतिनिधियों द्वारा कूटनीतिक सम्बन्ध अवस्थित करना अंगीकार करते हैं और इसके मुताबिक रूप से कार्यान्वित होने के लिए आवश्यक कर्मचारी रख सकते हैं।

अंगीकृत प्रतिनिधि और उनके कर्मचारीगण वे सब कूटनीतिक विशेषाधिकार और विमुक्ति उपभोग करेंगे जो सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं तथा वे किसी दशा में उनसे कम न होंगे जो अन्य राज्यों में उसी पद पर व्यक्तियों को प्राप्त है जहां शासन में परस्पर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हैं।

धारा ४—दोनों सरकार महावाणिज्यदूतों वाणिज्यदूतों उप-वाणिज्यदूतों, तथा अन्य वाणिज्यदूताभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए सम्मत हैं। जो परस्पर स्वीकृत प्रदेश के नगरों पत्तनों तथा अन्य स्थानों में आवास करेंगे। महावाणिज्यदूतों वाणिज्यदूतों उप-वाणिज्यदूतों और वाणिज्यदूताभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए वाणिज्यपत्रों या अन्य वैध प्राधिकरणों की व्यवस्था होगी। ये प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर निर्णय देने वाले द्वारा प्रत्याहरित हो सकते हैं प्रत्याहार करने के कारण यदि संभावित होगा निर्दिष्ट कर दिये जायेंगे।

ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों को पारस्परिक अधिकारों विशेषाधिकारों सुविधाओं और विमुक्तियों का प्राधिकार होगा जो उन्हीं पदों के व्यक्तियों को अन्य राज्य में प्राप्त होंगे।

धारा ५—नेपाल सरकार भारत के प्रदेश द्वारा अस्त्र-शस्त्र युद्धोपकरण या युद्ध-सामग्री या भाग जिसकी नेपाल की रक्षा के लिए आवश्यकता हो प्रवेशन

करने को स्वाधीन होगा। इस व्यवस्था को कार्य रूप में देने की प्रणाली दोनों सरकारें आपस में सलाह द्वारा सम्पन्न करेंगी।

धारा ६—भारत और नेपाल में प्रतिवेशी मैत्री के चिह्नस्वरूप दोनों शासन दूसरे राष्ट्रीयों को अपने प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करेंगे और उस प्रदेश के विकास के लिए सुविधाएं और छूट देंगे।

धारा ७—भारत सरकार व नेपाल सरकार प्रति व्यवहार की भित्ति पर एक देश के राष्ट्रीयों को दूसरे प्रदेशों में बसने की सम्पत्ति के स्वत्वाधिकार की, वाणिज्य-व्यापार में योगदान को तथा इसी प्रकार के अन्य विशेषाधिकारों के लिए सम्मत होते हैं।

धारा ८—जहां तक इसमें उल्लिखित विषयों का सम्बन्ध है—यह संधि इसके पूर्व की समस्त संधियों, सविदाओं और अंगीकार पत्रों को रद्द करती है—जो भारत की ओर से ब्रिटिश सरकार और नेपाल सरकार में हुई थी।

धारा ९—दोनों सरकारों के हस्ताक्षर करने की तिथि से यह संधि लागू होगी।

धारा १०—इस संधि की क्षमता उस समय तक रहेगी जब तक कोई पक्ष एक वर्ष की सूचना देकर उसे समाप्त नहीं कर देगा।

काठमाण्डू में ३१ जुलाई, १९५० को प्रतिलिपि में प्रस्तुत हुई।

चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा
भारत की ओर से नेपाल सरकार की ओर से

१५

भारत और नेपाल की सरकारों के बीच व्यापार और वाणिज्य की संधि (१९५०)

भारत और नेपाल की सरकारों ने अपने-अपने राज्य-क्षेत्रों के अन्तर्गत एक दूसरे के व्यापार और वाणिज्य के सुविधात्मक विकास के लिए तथा उनकी अभिवृद्धि के विचार से एक व्यापार और वाणिज्य-संधि पर हस्ताक्षर करने का निश्चय किया है और इस उद्देश्य से क्रम से निम्नलिखित अधिकारियों को संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की है—

भारत सरकार की ओर से—

चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह नेपालस्थित भारतीय राजदूत।

नेपाल सरकार की ओर से—

महाराज मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा प्रधान मंत्री और नेपाल के प्रधान सेनापति।

इन महानुभावों ने एक दूसरे के प्रमाण-पत्रों की परीक्षा करके और उनको नियमानुकूल पाकर निम्नलिखित बातों से सहमति प्रकट की है।

धारा १—भारत सरकार नेपाल सरकार को पूर्ण अधिकार देती है कि वह व्यापार के लिए माल और तैयार सामान भारतीय राज्यक्षेत्र या बन्दरगाहों से होकर बरोकटोक नेपाल ले जाय जैसा कि नीचे की २, ३ और ४ धाराओं में निहित है।

धारा २—दोनों सरकारों के बीच स्थिर नियम के अधीन भारत सरकार को अपने किसी बन्दरगाह पर उतरे माल को जो नेपाल को निर्यात के लिए होगा उसे नेपाल राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच ठहराए गए स्थानों को भेजना स्वीकार होगा। इस प्रकार के भेजे हुए माल में नेपाल सरकार को अपने किसी माल के खुलने का डर नहीं होगा और न उसे किसी भारतीय बन्दरगाह पर कोई शुल्क ही देना पड़ेगा।

धारा ३—दोनों सरकारों के बीच स्थिर नियम के अधीन नेपाल में उत्पन्न मालों को यदि भारतीय राज्यक्षेत्र से होकर नेपाल के अन्तर्गत किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान को जाना है तो उसके लिए भी नेपाल को किसी प्रकार का आयात-कर या शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

धारा ४—दोनों सरकारों के बीच स्थिर नियम के अधीन नेपाल सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अपने देश में बने या उत्पन्न माल को नेपाल के निश्चित स्थानों से ले जाकर भारत के राज्य-क्षेत्र या बन्दरगाहों पर से विदेशों को निर्यात करे।

धारा ५—नेपाल सरकार को यह मंजूर है कि वह नेपाल के लिए बाहर से भारत होकर आने वाले माल पर या नेपाल से भारत के बाहर भेजे जाने वाले माल पर भारत में तत्काल प्रचलित दर के मुताबिक ही चुंगी स्थिर करेगी। नेपाल सरकार को यह भी मंजूर है कि नेपाल में उत्पादित या बनाए गए मालों पर जो भारत को भेजे जावें उतनी चुंगी लगा जिससे उनके भारत में विक्रय से भारत के बने मालों जिन पर केन्द्रीय अंतःशुल्क भी लगते हैं के विक्रय को धक्का न पहुंचे।

धारा ६—भारत और नेपाल की सरकारों को यह स्वीकार है कि वे एक दूसरे की अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक मालों को अपने-अपने देश से जहां तक संभव हो प्रदान करेंगी।

धारा ७—दोनों देशों को यह स्वीकार है कि वे एक दूसरे की व्यापारिक संस्थाओं आदि में सम्पर्क बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और आवश्यक सामग्रियों के आयात-निर्यात के लिए सभी सुविधाएं देंगे। इसके अतिरिक्त दोनों सरकारों को यह भी मंजूर है कि वे एक दूसरे के देश की व्यापारिक संस्थाओं को माल ले जाने और ले आने के लिए यातायात के सब से किफायत और सुविधाजनक साधनों का सौजन्य प्रदान करेंगे।

धारा ८—एक दूसरे देश के व्यावहारिक (Civil) वायुयानों को साधारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार एक दूसरे देश के ऊपर उड़ने की अनुमति होगी।

धारा ९—जहाँ तक यहाँ जिक्र की हुई बातों का सम्बन्ध है यह संधि-पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की ओर से नेपाल के साथ की गई अब तक की संधियों समझौतों और अन्य प्रकार के संधि-पत्रों को समाप्त करता है।

धारा १०—यह संधि संधि-पत्र पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर होने की तिथि से तीन महीने बाद लागू हो जाएगी। प्रथमतः यह संधि दस वर्ष तक लागू रहेगी और उसके बाद यदि दोनों में से कोई पक्ष इसका अन्त चाहेगा तो उसे इसके लिए एक वर्ष पूर्व लिखित सूचना भेजनी पड़ेगी। ऐसा न होने पर संधि की अवधि और दस वर्ष के लिए बढ़ जायगी।

इस संधि पर सन् १९५० की ३१ जुलाई को दोनों देशों के मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर हुए।

१६

ज्ञापन पत्र (Memorandum)

(भारत और नेपाल सरकारों के बीच व्यापार और वाणिज्य-संधि की धाराएं दो और तीन)

भाग अ

इस संधि की धारा २ में वर्णित व्यवस्था इस प्रकार व्यवहृत होगी—

१ जब कोई माल भारत में उतरता है जो नेपाल को निर्यात के लिए है तो उस माल के मँगाने वाले को चुंगीघर में माल उतारने पर—

(क) यह घोषित करना होगा कि जो माल उसने मँगाए हैं वे नेपाल भेजने के लिए हैं और नेपाल ले जाते समय बीच में वह उन्हें और किसी देश को नहीं जाने देगा।

(ख) एक खास फार्म में मालों के विवरण की चार प्रतियाँ देनी पड़ेंगी और इस विवरण को इस काम के लिए नियुक्त एक नेपाली अधिकारी से सही कराना पड़ेगा। इस फार्म में यह भी बताना पड़ेगा कि किसी प्रामाणिक स्थल मार्ग से सामान लाया जायगा और भारत के किसी सीमान्त चुंगीघर से निकालकर माल नेपाल लाया जायगा।

(ग) उस माल पर—जितना भारतीय पण्य शुल्क (Tariff) लग सकता होगा उसके बराबर की पूँजी जमा करनी होगी या किसी विश्वासपात्र बैंक से जमानत दिलवानी होगी जो कि उसे बाध्य करेगा कि वह माल के किसी भाग के नेपाल के चुंगीघर से नियुक्त शुल्क पोस्ट पर भी निकास न होने पर माल के उस अंश पर शुल्क देगा।

२ ऊपर कही बातों के पूरा होने पर माल पर बहिःशुल्क कार्यालय (Customs House) की सील लगेगी और उसके बाद उसे मँगाने वाले को विवरण-पत्र की मूल प्रति के साथ लौटा दिया जायगा। विवरण-पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रतियाँ उसी समय जैसा कि ऊपर (१) (ख) में संकेत है चुंगीघर के स्थल बहिःशुल्क अधिकारी (Land Customs Officer) को भेज दी जायेंगी।

३ बहिःशुल्क अधिकारी जिसके सामने माल लाया जायगा सीलों की परीक्षा करेगा और यदि वह टूटे-फूटे न होंगे तो इस बात के लिए प्रमाणपत्र देगा कि माल भारत की सीमा को पार करके नेपाल की सीमा में सीलों के सहित पहुँच गये। विवरण-पत्र की मूल प्रति माल के मालिक को नेपाल के चुंगीघरों में प्रस्तुत करने के लिए दे दी जायगी। विवरण-पत्र की दूसरी प्रति पृष्ठांकित करके जिस चुंगीघर से वह आई थी उसी को वापस कर दी जायगी और तीसरी प्रति पृष्ठांकित करके नेपालस्थित भारतीय दूतावास को भेज दी जायगी।

४ ऊपर जिस पूँजी को जमा कराने की बात कही गई है उसे वापस लेने के लिए या पैराग्राफ (१) (ग) के अन्तर्गत जो बॉण्ड प्रस्तुत करने की बात कही गई है उसे रद्द कराने के लिए व्यापार करने वाले व्यक्ति या उसके किसी अभिकर्ता (Agent) को चाहिए कि उस आशय का एक आवेदन-पत्र दे जो मूल विवरण-पत्र से पुष्ट हो और पैराग्राफ (३) के कथनानुसार स्वयं बहिःशुल्क अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि माल भारतीय सीमा को पार कर गया है और नेपाल बहिःशुल्क कार्यालय द्वारा प्रमाणित हो कि वह साबुत भारतीय सील के साथ नेपाल पहुँच गया है और जिन सामानों का विवरण विवरण-पत्र में है उनके निकास के लिए उन्होंने बहिःशुल्क लेकर अनुमति प्रदान कर दी है।

नेपाल चुंगीघर द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र पर नेपाल सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त एक विभागाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर होगा। विवरण-पत्र की मूल प्रति भारतीय चुंगीघर में ६ महीने के अन्दर-अन्दर पहुँचनी चाहिए। यह अवधि भारतीय बहिःशुल्क प्रशासन द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है। यदि उन्हें यह संतोष हो जाय कि विलम्ब [illegible] कारणों से हुआ है जिनके ऊपर माल मँगाने वाले का कोई अधिकार नहीं था।

५ जमा की हुई पूँजी को लौटाने या बॉण्ड को रद्द करने के पहले चुंगीघर के सम्बन्धित अधिकारी का यह काम है कि वह विवरण-पत्र की मूल प्रति की तुलना सम्बन्धित बहिःशुल्क अधिकारी से प्राप्त विवरण-पत्र की दूसरी प्रति से करा ले।

भाग 'ब'

शासन की सुविधा की दृष्टि से फिलहाल भारत सरकार इस संधि की धारा ३ में जिस व्यवस्था के लागू होने की चर्चा की गई है उसको लागू करने की आवश्यकता नहीं समझती। किन्तु जब कभी भी भारत सरकार इसकी आवश्यकता समझकर लागू करना चाहे जिस व्यवस्था का भाग 'अ' में वर्णन है वह संधि की धारा ३ में भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी।

भाग 'स'

जहाँ तक संधि की २ और ३ धाराओं का सम्बन्ध है दोनों सरकारें नेपाल राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित रेल केन्द्रों के निकटवर्ती प्रदेशों को मान्यता देती हैं —

१ रक्सौल २ जोगबनी ३ नेपालगंज ४ भीठामोड़ा और ५. जयनगर।

इस ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि ३१ जुलाई, १९५० है और हस्ताक्षरकर्ता क्रमश: भारत और नेपाल की सरकारों की ओर से चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और महाराज मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा हैं।

१७

ज्ञापन पत्र (Memorandum)

(भारत और नेपाल सरकारों के बीच व्यापार और वाणिज्य संधि की धारा चार)

भाग 'अ'

संधि की धारा ४ में कथित व्यवस्था इस प्रकार होगी—

१ नेपाल में बने सामान या तैयार माल जो भारत में लाये जायें किन्तु जिनका अन्तत: निर्यात भारत के बाहर किसी देश को हो तो उस स्थिति में उक्त माल को भारतीय राज्य-क्षेत्र से गुजरने की पूर्ण सुविधा होगी। इस सुविधा के अन्तर्गत भारतीय बहि:शुल्क (Customs duty) उपकर (Cess) या उत्पादन-शुल्क (Excise duty) से विमुक्ति भी निहित है। इसके अतिरिक्त उक्त माल के सम्बन्ध में भारतीय आयात-निर्यात नियंत्रण नियम के पालन की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा हो कि माल बाहर भेजने वाला व्यक्ति या उसका कोई प्रमाणित अभिकर्ता (Agent)

(क) भारतीय स्थल बहि:शुल्क प्रवेश थाना (Indian Land Customs Station of Entry) को नियत फार्म में एक घोषणा के रूप में दे दे कि जो माल वह नेपाल से भारत में लाया है वह भारत के बाहर किसी अन्य देश को निर्यात के निमित्त है;

(ख) मालों का विवरण एक नियत फार्म में देकर और उस विवरण-पत्र पर, जितनी बार प्रतियाँ होनी आवश्यक हैं, एक इसी काम के लिए नियुक्त नेपाली अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर कराकर यह लिखित स्पष्टीकरण दे दे कि वह माल को किन-किन प्रमाणित स्थल-मार्गों से ले जा रहा है और भारत से बाहर किस भारतीय बन्दरगाह से भेज रहा है और

(ग) भारतीय कस्टम पण्य शुल्क (Indian Customs Tariff) के नियम के अनुसार जितना शुल्क उसके माल पर लगने की संभावना हो उसके बराबर की पूँजी जमा कर दे या किसी विश्वस्त बैंक में एक बॉण्ड प्रस्तुत करे जिसके अन्दर जमानत की व्यवस्था हो जो समय पड़ने पर उसे माल के किसी एक अंश पर शुल्क देय को वापस करे जिस अवस्था (ख) में कथित बन्दरगाह का चुंगीघर किसी कारण से निकालने की आज्ञा न दे।

२ उपर्युक्त नियमों का पालन करने के उपरान्त मालों पर भारतीय स्थल बहि:शुल्क कार्यालय (Indian Land Customs Station) की सील लगाकर

जैसा कि ऊपर १ (क) में निर्दिष्ट है, उन्हें व्यापार करने वाले या उसके अभिकर्ता को विवरण-पत्र जो नियमानुसार भरा हुआ और रजिस्ट्री किया हुआ होगा की मूल प्रति के साथ दे दिया जायगा। विवरण पत्र की द्वितीय तथा तृतीय प्रतियां उसी समय और ऊपर के पैराग्राफ १ (ख) में निर्दिष्ट नियम के अनुसार उस भारतीय बन्दरगाह के चुंगीघर को भेज दी जायगी जहां से माल को भारत से बाहर जाना है।

३ माल के उस भारतीय बन्दरगाह से किसी और देश को भेजे जाने वाले पहले बन्दरगाह के चुंगीघर का अधिकारी देखेगा कि उन पर जो सीलें लगाई गई थी वे साबुत हैं या नहीं और उनके सही होने पर यह प्रमाण-पत्र देगा कि माल बन्दरगाह में जहाज पर लदान के लिए जब आये थे तो उनकी सीलें साबुत थी। मालों के ठीक-ठीक भेजे जाने के बाद विवरण-पत्र की मूल प्रति उसके मालिक को एक प्रमाण-पत्र के साथ कि सामानों का पुनर्निर्यात हो गया वापस कर दी जायगी जिससे कि वह उसे स्थल शुल्क कार्यालय के अधिकारियों को दिखा सके। विवरण-पत्र की दूसरी प्रति पृष्ठांकित होकर स्थल सीमा शुल्क कार्यालय को वापस हो जायगी और तीसरी प्रति पृष्ठांकित होने के बाद चुंगीघर में रेकार्ड के लिए रख ली जायगी।

४ जमा की हुई पूंजी को वापस लेने के लिए या पैराग्राफ १ (घ) के अन्तर्गत दाखिल किए गए बॉण्ड को रद्द कराने के लिए माल बाहर भेजने वाले या उसके अभिकर्ता (Agent) को चाहिए कि वह उक्त आशय का आवेदनपत्र दे जिसके साथ वह विवरण पत्र की मूल प्रति को भी जिस बन्दरगाह से उसका सामान बाहर गया वहां के चुंगीघर से प्रमाणित कराकर कि माल का पुनर्निर्यात भारत से बाहर हो गया साथ में नत्थी कर दे। विवरण-पत्र के मूल को स्थल सीमा शुल्क कार्यालय के सामने माल भेजने के ६ महीने के भीतर या बन्दरगाह के चुंगी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित ऐसी बढ़ी हुई अवधि जिसका बढ़ाना परिस्थितिवश आवश्यक हो जाय के अन्दर प्रस्तुत करना चाहिए।

५ जमा की हुई पूंजी की वापसी की अथवा बॉण्ड को रद्द करने की स्वीकृति देने के पूर्व स्थल सीमा शुल्क कार्यालय का सम्बन्धित अधिकारी माल भेजने वाले व्यापारी द्वारा प्रेषित विवरण-पत्र के मूल प्रति की सम्बन्धित चुंगीघर से प्राप्त विवरण-पत्र की प्रति से तुलना करके अपने को सन्तुष्ट करता है।

भाग 'ख'

जहां तक सन्धि की धारा ४ का सम्बन्ध है—दोनों सरकारें नेपाल राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित रेल-हेडों के निकटवर्ती प्रदेशों को मान्यता देती हैं—
(१) रक्सौल (२) जोगबनी (३) नेपालगंज (४) नौतनवा और (५) जयनगर।

इस व्यापार पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि ११ जुलाई १ ५ है और हस्ताक्षरकर्ता क्रमशः भारत और नेपाल की सरकारों की ओर से चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और महाराज मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा हैं।

१८

संयुक्त राज्य सरकार और नेपाल सरकार के मध्य संधि

हस्ताक्षरित ३० अक्तूबर, सन् १९५० ई० काठमाण्डू

महा ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त राज्य सरकार और नेपाल सरकार
ने प्रस्थापित किया है कि शांति मैत्री और सद्भाव सौभाग्य क्रम से दोनों देशों में २
दिसम्बर सन् १८१५ ई० से वर्तमान है ।

इसका विस्मरण किया है कि तत्कालीन राज्य भारत और पाकिस्तान के प्रतिष्ठापन
से काठमाण्डू में २१ दिसम्बर, सन् १९२३ ई० को संयुक्त राज्य और नेपाल सरकारों के
मध्य हस्ताक्षरित संधि के कतिपय प्रावधान तथा प्रागवर्ती संधियाँ प्रयोजनीय नहीं रह गई
हैं—अभिलाषा की कि अब तक विद्यमान सम्बन्धों को और अधिक सबल और परिपुष्ट
किया जाय और इसलिए संकल्प किया कि एक नवीन संधिकरण हो ।

निम्नलिखित स्थापन किये—

धारा १—संयुक्त राज्य की सरकार और नेपाल सरकार के मध्य शाश्वत शांति
और मैत्री रहेगी ।

धारा २—दोनों प्रसंविदा पक्ष एक दूसरे की बाह्य एवं आन्तरिक स्वाधीनता का
आदर एवं मान्यता देना परस्पर स्वीकार करते हैं ।

धारा ३—संयुक्त राज्य की सरकार और नेपाल सरकार के मध्य शांति और मैत्री
के घनिष्ट सम्बन्धों को निरापद और सम्पुष्ट करने के विचार से दोनों देश एक दूसरे के
यहाँ क्षमता-प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और सुचारु रूप से काम
संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारी रखेंगे ।

धारा ४—दोनों प्रसंविदा पक्ष अपनी तत्कालीन और स्नेहमयी मैत्री के अनुरूप
…ा अन्तर्राष्ट्रीय विधि-विधानों के अनुसार परस्पर लाभदायक वाणिज्यिक सम्बन्धों का
…पित और विकसित करेंगे ।

धारा ५—(क) प्रत्येक प्रसंविदा पक्ष के राष्ट्रिकों को दूसरे प्रदेश में जिस पर यह
धारा लागू है प्रवेश यात्रा निवास और छोड़ने का अधिकार होगा जब तक वे उक्त राज्य
में सब विदेशियों के ऊपर लागू प्रवेश यात्रा निवास और छोड़ने के नियमों का पालन एवं
समाधान करेंगे । प्रत्येक प्रसंविदा पक्ष के राष्ट्रिकों का दूसरे राज्य में जिस पर यह धारा
लागू है अन्तर्राष्ट्रीय विधि-विधानों के अनुसार व्यवहार और समादर होगा । उन्हें उस राज्य
में व्यक्तिगत सम्पत्ति और अधिकारों और उन सब विषयों पर जिनका सम्बन्ध वाणिज्य
से उद्यम में तथा किसी प्रकार का व्यापार करने में है व्यवसाय और वृत्ति के संचालन में
सम्पत्ति का उपार्जन स्वामित्व और विन्यास करों के संग्रह तथा कर संग्रह की प्रयोजनीयता
में किसी विदेशी को राष्ट्रीय से कम सुविधाजनक व्यवहार नहीं मिलेगा ।

(ख) इस संविदा के प्रयोजन के लिए, जहाँ तक संयुक्त राज्य सरकार का किसी विदेशी का राष्ट्रीय के साथ व्यवहार का प्रश्न है विदेश से अभिप्राय उस किसी देश से है जो निम्न तालिका में अंकित नहीं है—

महा ब्रिटेन और उत्तरी आयर्लैण्ड का संयुक्त राज्य

कनाडा

आस्ट्रेलिया का समष्टि-राज्य

न्यूजीलैण्ड

दक्षिणी अफ्रीका का संघ

भारत

पाकिस्तान

लंका

वर्तमान संधि के हस्तान्तरित होने के दिन से संयुक्त राज्य सरकार, आस्ट्रेलिया का समष्टिराज्य न्यूजीलैण्ड और दक्षिणी अफ्रीका का संघ और आयर्लैण्ड का प्रजाराज्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के राज्यों के लिए उत्तरदायी है।

(ग) इस धारा के प्रावधान अभी आगे नेपाल सरकार को उन कामों के विषय में लागू न होंगे जो सशस्त्र सेना से सीमान्त क्रय-विक्रय द्वारा प्राप्त हों।

धारा ६—(क) धारा ५ के प्रावधान का प्रयोग इन पर होगा—

१ संयुक्त राज्य सरकार के सम्बन्ध में महाब्रिटेन और उत्तरी आयर्लैण्ड और किसी राज्य में जिसमें धारा ५ के प्रावधान का प्रसार इस धारा के खण्ड (ख) के अनुसार किया गया है।

२ नेपाल सरकार के सम्बन्ध में नेपाल को।

(ख) वर्तमान संधि के हस्ताक्षरित या पुष्टीकरण के समय से या उसके पश्चात्, संयुक्त राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नेपाल की सरकार को घोषित करेगी कि धारा ५ उन राज्यों में लागू होगी जिनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए संयुक्त राज्य उत्तरदायी है और धारा ५ अधिसूचना के प्राप्त होने के समय से उसके उल्लिखित राज्यों में प्रसारित होगी।

(ग) इस धारा के खण्ड (ख) के अन्तर्गत घोषणा करने के बाद संयुक्त राज्य सरकार धारा ५ को उन राज्यों पर भी प्रसारित कर सकती है जिनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए वह उत्तरदायी है और वह नेपाल सरकार को अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि धारा ५ अधिसूचना में उल्लिखित किसी राज्य के लिए प्रसारित न होगी और अभिधारा ५ अधिसूचना के प्राप्त होने के समय से उस राज्य में लागू नहीं होगी।

धारा ७—वर्तमान संधि में 'राष्ट्रीय' शब्द का अर्थ संयुक्त राज्य के सम्बन्ध में यह है—

१ संयुक्त राज्य और मण्डलों के नागरिक जो अपनी नागरिकता की व्युत्पत्ति इस धारा में लागू सम्बन्ध से प्राप्त करते हैं।

२ सब ब्रिटिश रक्षित व्यक्ति जो धारा ५ में लागू राज्यों के सम्बन्ध से मर्यादित हैं।

३ यदि दक्षिणी रोडेशिया पर यह धारा प्रभावित की जाय तो दक्षिणी रोडेशिया के नागरिक।

और (ख) नेपाल सरकार के सम्बन्ध में नेपाल के समस्त राष्ट्रीय।

धारा ८—२१ दिसम्बर, १९१५ के पूर्व की समस्त सन्धियाँ अभिपुष्टियाँ और संविदा जो संयुक्त राज्य सरकार और नेपाल सरकार के मध्य निष्पादित हुईं और उस तिथि को हस्ताक्षरित काठमाण्डू में संधि उस तिथि से समाप्त हो जायेंगी जिस तिथि से यह संधि लागू होगी जहाँ तक संयुक्त राज्य और नेपाल से इसका सम्बन्ध है।

धारा ९—वर्तमान संधि का पुष्टीकरण होगा और संधि उस तिथि से लागू होगी जब से पुष्टीकरण विलेखों का आदान-प्रदान होगा। काठमाण्डू में पुष्टीकरण विलेख शीघ्र आदानित प्रदानित होगा।

धारा १०—वर्तमान संधि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी। प्रसंविदा पक्ष में किसी के दूसरे को एक वर्ष की लिखित अभिसूचना देने पर समाप्त हो सकेगी।

अपनी सरकारों द्वारा प्राधिकारित निम्न हस्ताक्षरितों ने वर्तमान संधि अंग्रेजी और नेपाली में हस्ताक्षरित की है। दोनों मूल वचन प्राधिकारित हैं शंका उठने पर अंग्रेजी के मूल वचन अधिभावी होंगे।

३० अक्तूबर, सन् १९५० ई० तदनुसार १४ कार्तिक २००७ वि० को काठमाण्डू में प्रतिलिपियों में हुई।

(हस्ताक्षर) जार्ज फाल्कनर (से० क०)
नेपाल के ब्रिटिश सम्राटों के राजदूत

(हस्ताक्षर) मोहन शमशेर
नेपाल के प्रधान मंत्री और सर्वोच्च महा सेनापति

१९

नेपाल-अमरीकी सम्बन्ध

संयुक्त राज्य अमरीका तथा नेपाल की सरकारों ने वाशिंगटन और काठमाण्डू स्थित अपने कूटनीतिक कार्यवाहकों को राजदूत पदों पर वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है तथा वे आपस में राजदूतों का आदान-प्रदान करेंगे।

संयुक्त राज्य सरकार ने १९४७ में नेपाल सरकार का प्रत्यभिज्ञान किया था। और २५ अप्रैल १९४७ में काठमाण्डू में वाणिज्य और मैत्री का संविदा सम्पादित हुआ था। सन् १९४८ में वाशिंगटन और काठमाण्डू में प्रथम नेपाली और अमरीकी मंत्रियों ने अपने

अभिमान पत्र समर्पित किये थे। वर्तमान काल में किसी राजदूत का कार्यक्रम पूरा
सरकार का राजधानी में नहीं है। अमरीकी मंत्री जो भारत में भी राजदूत हैं अभी दिल्ली
में रहते हैं तथा नेपाली मंत्री जो लन्दन में वास करते हैं संयुक्त आंग्ल देश में राजदूत हैं
आशा है कि इस काम से संयुक्त राज्य (अमरीका) और नेपाल में घनिष्ठ सम्बन्ध
की अभिवृद्धि होगा।
सितम्बर सन् १९५१ ई०

२०

नेपाल सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार में औद्योगिक सहकार्य के लिए चतुर्सूत्री सामान्य संविदा।

संयुक्त राज्य अमेरिका और नेपाल की सरकारों ने यह स्वीकृत किया है।

धारा १ सहायता और सहकार्य—१ नेपाल के आर्थिक संसाधन तथा उत्पादक शक्ति की समुचित एवं सामञ्जस्य उन्नति के अवदान के लिए संयुक्त राज्य अमरीका और नेपाल की सरकारों ने आपस में औद्योगिक ज्ञान और नैपुण्य का आदान प्रदान स्वीकार किया है। विशेष औद्योगिक सहकार्य कार्यक्रम और योजना अन्य लिखित संविदाओं के प्रावधान के अनुसार सम्पादित होंगी जो नेपाल के उपयुक्त नामोद्दिष्ट प्रतिनिधियों और संयुक्त राज्य अमरीका के प्राद्योगिक सहकार्य प्रशासन द्वारा या अन्य व्यक्तियों, अभिकरणों या संस्था द्वारा स्वीकृत होंगी।

नेपाल सरकार अपने नामोद्दिष्ट प्रतिनिधियों द्वारा और संयुक्त राज्य अमरीका के औद्योगिक सहायक प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा और संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रतिनिधियों द्वारा सब प्रकार के औद्योगिक सहायक कार्यक्रम के सम्पूर्ण संगमन का प्रबन्ध नेपाल में करेगी।

३ नेपाल सरकार औद्योगिक ज्ञान एवं नैपुण्य का आदान प्रदान उन देशों से करेगी जो इस संविदा के अन्तर्गत औद्योगिक सहायक कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

४ संयुक्त अमरीका के सहयोग से नेपाल सरकार नेपाल में औद्योगिक विस्तार के परिणामों का प्रभावी उपयोग करेगी।

५ एक दूसरे की प्रार्थना पर दोनों सरकारें इस संविदा के अन्तर्गत योजनाओं की प्रगति पर परस्पर विचार-विनिमय करेंगी अथवा उसे किसी प्रबन्ध के विषय में जो इस संविदा के कारण व्यवहार में लाया जायगा।

धारा २ सूचना और प्रकाशन—१ नेपाल सरकार संयुक्त राज्य अमरीका को परस्पर स्वीकृति-पत्र और नियत समय पर निम्न बातें सूचित करेगी—

(क) योजनाओं सम्बन्धी सूचना कार्यक्रम साधन और प्रवर्तन जो इस संविदा

उपकरण तथा सेवाकार्य
के अन्तर्गत होंगे इसके अन्तर्गत धन राशि का उपयोग सामान अन्तर्राष्ट्रीय संघों से
भी माने जायेंगे । अन्य देशों अथवा
(ख) औद्योगिक सहायता की सूचना जो संयुक्त राज्य अमरीका की
दी जा रही है या जिसके लिए प्रार्थना की गई है ।
२ कम से कम वर्ष में एक बार नेपाल और कार्यक्रम के सम्पन्न होने के विषय में
सरकारें इस संविदा के अन्तर्गत औद्योगिक सहायक इन विवृतियों में धनराशि सामान
परस्पर विचार-विनिमय द्वारा उसे प्रकाशित करेगी । भी होगा ।
करण तथा सेवाकार्य के उपयोग का विवरण सरकार परस्पर समझौता करके इस
३ संयुक्त राज्य अमरीका तथा नेपाल के ध्येय एवं उन्नति को पूरी तौर से
संविदा के अन्तर्गत औद्योगिक सहायक कार्यक्रम
प्रकाशित करेंगी । ऊपर धारा १ कण्डिका १ में
धारा ३ कार्यक्रम और योजना सम्मेलन—१ नीति सम्बन्धी प्राविधान प्रशासक
उल्लिखित कार्यक्रम और योजना सम्मेलन के अन्तर्गत प्रत्येक दल का कार्यक्रम और योजना के
कार्य प्रणाली धन-राशि का वितरण व विवरण कण्डिका १ में उल्लिखित कार्यों व
परिव्यय में सहयोग-दान तथा उपर्युक्त अभिधारा २ संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा नेपाल को
सविक्षेप एवं सूक्ष्म सूचना होगी । संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार पर
२ इस कार्यक्रम एवं योजना के अन्तर्गत निस्सारण आवश्यकतायें न लागू
प्रदत्त धनराशि सामान तथा उपकरणों पर, या
किसी प्रकार का कर, सेवा-प्रसार और विनियोग
होंगी और वह विनिमय मार्गदर्शन से मुक्त होगा । सरकार औद्योगिक सहायता कार्यक्रम
३ परस्पर समझौते के अनुसार नेपाल कार्यक्रम और योजना के
और योजना में उचित परिव्यय वहन करेगी । सहायता
धारा ४ सेविवर्ग—१ सहकार, औद्योगिक जिन्हें नेपाल में काम करने के
सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका के समस्त कर्मचारीगण नेपाल का आय-कर निम्न बातों
लिए भेजा जायगा तथा उनके अनुसरणी परिवारों पर एवं परिलाभ और कोई और
में लागू न होगा । संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दिया वेतन आय-कर अथवा सामाजिक
गैर नेपाली आय जिस पर संयुक्त राज्य अमरीका को
रक्षण-कर दिया जाता है । व्यक्ति निरावृत्य और प्रवेशन कर
२ ऐसे कर्मचारी और उनके परिवार के सम्पत्ति तथा एक स्वतःवाही (मोटरकार)
से व्यक्तिगत गृह-सम्बन्धी और व्यावसायिक विदेश विभाग को यथार्थ सूचना देनी होगी कि
मुक्त होंगे । इसमें उन्हें नेपाल सरकार के व्यवहार के लिए है । ऐसी किसी वस्तु
यह सम्पत्ति उनके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गई है या तीन वर्षों के भीतर विक्रीत
पर शुल्क देना बाध्य होगा जो बिना कर के लाई

हुई है परन्तु यदि ऐसी वस्तुएं इसी अवधि में पुनः निर्यातित की जाती हैं तो व्यवस्था होगी

धारा ९ प्रभाव में आना, संशोधन, अवधि (लागू होना)—१ यह संविदा हस्ताक्षर होने के दिन से लागू माना जायगा। यह सरकारों के लिखित सूचित करने के पश्चात् कि उनका विचार इस संविदा को समाप्त कर देने का है, उस दिन से तीन मास तक लागू रहेगा।

२ इस संविदा के जीवन काल में यदि कोई सरकार यह समझती है कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है तो वह दूसरी सरकार को इसकी सूचना देगी और दोनों सरकार विचार-विनिमय करके संशोधन स्वीकार करेंगी।

३ सहायक योजना और दूसरी स्वीकृतियां और प्रबन्ध जिनकी निष्पत्ति हो जाय इस संविदा के समाप्त होने के पश्चात् भी दोनों सरकारों के प्रबन्धानुसार लागू रहेंगे।

४ यह संविदा पूरक है तथा दोनों सरकारों के बीच वर्तमान समझौते को यदि उसमें इसके प्रतिकूल कोई नियम न हुआ तो स्थानच्युत नहीं करेगा।

अपनी सरकारों की ओर से पूर्णरूपेण अधिकृत होकर निम्न हस्ताक्षरित व्यक्तियों ने वर्तमान संविदा पर हस्ताक्षर किये।

२३ जनवरी सन् १९५२ ई० को नयी दिल्ली में प्रतिलिपियों में लिखा गया।

	नेपाल सरकार की ओर से—
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की ओर से—	(हस्ताक्षर) सिंह
(हस्ताक्षर) लॉय डब्ल्यू हेण्डरसन	कमाण्डिंग जनरल
नेपाल में संयुक्त राज्य अमरीका के मंत्री	सिंह शमशेर जंग बहादुर राणा
	नेपाल के राजदूत

२१

औद्योगिक सहकारिता में नेपाल और स्विट्जरलैण्ड के सम्बन्ध में संविदा

औद्योगिक सहायता के लिए स्विस समन्वय समिति से

तथा

नेपाल राज्य की सरकार से

नेपाल के औद्योगिक विकास में स्विस विशेषज्ञों की सहकारिता सम्बन्धी

सन् १९५ में नेपाल राज्य की सरकार और स्विस समन्वय समिति द्वारा नियुक्त स्विस-नेपाल अध्ययन समूह ने औद्योगिक सहायता के लिए भाग विभाजन किया गया और वन-भूमि निर्माण, बौद्धिकाय समापन के अवसर पर कृषि इत्यादि क्षेत्रों में वास्तविक साधनों के लिए इच्छित सामग्री प्राप्त कर ली है, अतएव देश के औद्योगिक विकास के

लिए अन्य स्विस विशेषज्ञों के अग्रदर्शी होने की संभावना है ।
अतएव औद्योगिक विकास पर स्विस समन्वय समिति और नेपाल राज्य की सरकार
न इस सहकारिता के निमित्त निम्न सामान्य व्यवस्थाकरणों का स्वीकरण किया है—
नेपाल के अपवहन में स्विस विशेषज्ञों का निर्धारण
धारा १—औद्योगिक सहायता के लिए स्विस समन्वय समिति सिद्धान्तत विशेषज्ञों
को नेपाल के अपवहन में निर्धारित करने को उद्यत है ।
धारा २—औद्योगिक सहायता के लिए नेपाल सरकार स्विस समन्वय समिति
(इसके पश्चात् यह "स्विस समिति उल्लिखित होगी) को स्विस विशेषज्ञों के विषय में
की समीक्षा सूचित करेगी ।
धारा ३—नेपाल सरकार की प्रार्थना स्विस समिति के प्रधान द्वारा स्विस सेविकर्गों
व्यक्तियों के सहकाय द्वारा सम्पादित होगी ।
धारा ४—नियुक्ति के नियम और प्रत्येक विशेषज्ञ का कार्यभार, नेपाल सरकार
और विशेषज्ञों के मध्य विशेष प्रसंविदा में संनिबंधित होंगे । विशेषज्ञ इसके सामान्य
निर्देश यथापूर्व स्वीकार कर लेंगे तथा अवश्य रूप से स्विस समिति की नियुक्ति के नियम
स्वीकार होंगे ।
धारा ५—वर्तमान संविदा के अन्तर्गत नेपाल में कार्य करने वाला प्रत्येक स्विस
विशेषज्ञ स्विस समिति के प्रशासन में रहेगा तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होगा ।
धारा ६—वर्तमान संविदा के अन्तर्गत नेपाल में अवस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ अपनी
औद्योगिक सक्रियता के लिए स्विस समिति से सीधा सम्पर्क रखेगा ।
धारा ७—वर्तमान संविदा के अन्तर्गत नेपाल में अवस्थित विशेषज्ञों में से एक
विशेषज्ञ निर्वाचित होगा जो भारत में स्विस दूतावास द्वारा नेपाल सरकार और स्विस
समिति के संस्पर्श से उन औद्योगिक प्रश्नों को जो नेपाल में तत्कालीन अवस्थित विशेषज्ञों के
अधिकारक्षेत्र से बाहर होंगे स्थायी निश्चय प्रदान करेगा ।
धारा ८—नेपाल और स्विट्जरलैण्ड के मध्य औद्योगिक सहकारिता के साधारण
प्रकृति के सभी प्रश्न भारत में स्विस दूतावास द्वारा स्विस समिति को विचारार्थ भेजे
जायेंगे और धारा ७ में उल्लिखित विशेषज्ञों को सूचित कर दिया जायगा ।
धारा ९—नेपाल सरकार विशेषज्ञों का स्विट्जरलैण्ड से नेपाल तक की यात्रा और
उनके वहाँ रहने का परिव्यय समर्थन करती है । इसके अतिरिक्त वह उन्हें वेतन की
सहायता देगी जो अंशतः स्विट्जरलैण्ड को सक्रमण होगा ।
धारा १०—प्रत्येक वर्ष के अन्त में या अन्य अवधि के लिए नेपाल सरकार सूचना
देगी । उदाहरण के लिए, वर्षा ऋतु काल, या दूसरे वर्ष के लिए स्विस विशेषज्ञों के व्यय
एवं वेतन के लिए सम्पूर्ण धन-राशि । संभवतः प्रत्येक वर्ष के लिए या अगले वर्ष के लिए
प्राप्य धन राशि के अनुसार कार्यक्रम निश्चित कर लिया जायगा ।

धारा ११—प्रत्येक विशेषज्ञ जो नेपाल के आयबद्ध में है उसके बारे में स्थित समिति विचार करेगी कि स्विटजरलैण्ड में कहाँ तक वे समादर संग्रहण के अधिकारी हैं।

लागू होने की तिथि अवधि संशोधन

धारा १२—यह संविदा हस्ताक्षर होने के दिन से लागू होगा। इसकी अवधि अनिश्चित है।

धारा १३—इसे कोई दल किसी समय अस्वीकार कर सकता है परन्तु वर्तमान संविदा के अन्तर्गत नेपाल में काम करने वाले विशेषज्ञों के अनुबंध के समाप्त होने तक वह लागू रहेगा।

धारा १४—कोई पक्ष किसी समय संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। संशोधन के सम्बन्ध में वर्तमान संविदा के अन्तर्गत नेपाल में कार्य करने वाले विशेषज्ञों पर वह लागू नहीं होगा परन्तु जो बाद में नियुक्त होंगे उन पर लागू होगा।

नेपाल राज्य की सरकार के नाम पर — औद्योगिक सहायता के लिए

१ फरवरी सन् १९५२ ई० — स्विस सहकारी समिति के नाम पर

अध्यक्ष

२२

ब्रिटिश सेना में गुरखा सैनिकों की भरती के लिए ब्रिटिश सरकार और नेपाल सरकार के बीच अन्तरिम संविदा

नेपाल सरकार ने तथा ब्रिटिश सरकार ने सम्मत किया है—

(क) कि नेपाल भूमि पर गुरखों की भरती के लिए सैनिक अड्डे स्थापित होंगे।

(ख) ये अड्डे नेपाल सीमान्तर्गत होंगे।

(ग) नेपाल के सैनिक अड्डों में ब्रिटिश सेना के लिए गोरखों की भरती अवश्य पाँच वर्षों तक लागू रहेगी। इस प्रबन्ध को आगे स्थापित देने का कोई विचार, इसी अवधि अथवा उपरान्त पर, उसके समाप्त होने के पूर्व परिचालित कर लिया जायगा। इस संविदा के स्थापित काल में यदि नेपाल सरकार या ब्रिटिश सरकार के विचार में इसके संविदा पत्र में कोई परिवर्तन उचित समझा जायगा तो दोनों सरकार उसे उचित परामर्श द्वारा निर्णीत करेंगी।

११ जुलाई सन् १९५१ ई०

२३

प्रत्यर्पण की संधि

भारत सरकार और नेपाल सरकार में

भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों देशों के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण को नियमानुसार स्थिर करने की इच्छुक हैं और प्रत्यर्पण की नवीन संधि का स्थिर करने के लिए निम्न व्यक्तियों को पूर्ण अधिकारी नियुक्त करती हैं—

परिशिष्ट

परमश्रेष्ठ भालचन्द्र कृष्ण गोखले नेपाल में भारत के राजदूत और माननीय श्री मातृका प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधान मंत्री जो एक दूसरे के अभिज्ञान-पत्र परीक्षण कर उन्हें यथार्थ व शृंखलाबद्ध पाकर निम्न धाराओं में सम्मत हुए।

धारा १—दोनों सरकारें परस्पर स्वीकार करती हैं कि वे अपराधी या दण्डित व्यक्ति जो एक सरकार के प्रदेश में अपराध कर दूसरी सरकार के प्रदेश में पाए जायँ अपनी सरकार को सौंप दिए जायँ इसकी परिस्थितियाँ तथा नियम इस संधि में निर्देशित हैं।

धारा २—कोई सरकार उस व्यक्ति को माँग करने वाली सरकार को नहीं सौंपेगी यदि वह उसका राष्ट्रीय नहीं है। इस धारा में छूट उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में होगी जिन्होंने अभिधारा ३ के खण्ड (१) में निर्देशित अपराध किए हैं।

धारा ३—इस संधि के अनुसार निम्न अपराधों के लिए प्रत्यर्पण लागू होगा—

(१) हत्या या प्रयास या हत्या करने का षड्यंत्र

(२) वध-वर्जित सदोष मानव-हत्या

(३) घोर उपघात

(४) बलात्कार

(५) डकैती

(६) राजपथ पर लुण्ठन

(७) हिंसा के साथ लुण्ठन

(८) चोरी या सेंध लगाना

(९) गृहदाह

(१०) सशस्त्र सेना से पलायन

(११) निष्काम्य और प्रवेश्य वस्तुओं की रोक के नियमों के विरुद्ध अपराध

(१२) धन अधिकारियों द्वारा धन हरण

(१३) गुरुतर चोरी अर्थात् चोरी की वह दशा जिसमें हिंसा का व्यवहार हो या जहाँ चोरी किए माल का मूल्य पाँच सौ रुपए से अधिक हो और पशु-हरण

(१४) अपहरण या बालापहरण

(१५) कूटकर्म और उसका व्यवहार जो कूट है मुद्रा कूटकरण या उसमें आपरिवर्तन कूटकरण या आपरिवर्तित मुद्रा का प्रचार या प्रचलित करना

(१६) लोक सेवक द्वारा उत्कोच लेना और

(१७) खण्ड (१) से (१६) में निर्देशित अपराधों के लिए दण्ड पाने पर सौंपने की दशा में रक्षण से भागना।

धारा ४—किसी भी दशा में कोई सरकार उस अपराधी व्यक्ति को सौंपने के लिए बाध्य न होगी जब तक उसके लिए उस सरकार द्वारा प्रार्थना न की जायगी जिसके प्रदेश में अभिकथित अपराध किया गया है तथा ऐसे अपराधिक प्रमाणों के आधार हाय या उस देश के नियमों के अनुसार जहां अपराधी पाया जाय उसका दोष स्पष्ट होता और वहां अपराध करने पर वह दोषी माना जाता हो।

धारा ५—कोई सरकार उस व्यक्ति को समर्पण करने को बाध्य न होगी यदि उसका अपराध राजनीतिक रूप का होगा या यदि वह इसे प्रतिपादित कर देगा कि उसके समर्पण की माँग राजनीतिक अपराध में दण्ड देने के लिए की गई है।

धारा ६—यदि कोई व्यक्ति दूसरी सरकार में प्रत्यर्पण के अपराध में दण्ड भोग चुका है और छूट गया है या दण्डित है या विचाराधीन है तो किसी सरकार में प्रत्यर्पण का अपराध नहीं माना जायगा।

धारा ७—यदि कोई व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की एक सरकार माँग करती है और वह दूसरी सरकार के प्रदेश में किसी अन्य अपराध के लिए विचाराधीन है तो विचार समाप्ति तक उसका उत्पण स्थगित कर दिया जायगा।

धारा ८—समर्पित व्यक्ति किसी दशा में भी उस सरकार के प्रदेश में किसी अन्य अपराध के लिए रोका या विचार के लिए उपस्थित नहीं किया जायगा जहां समर्पित किया गया है। वह केवल प्रत्यर्पण के अपराध के लिए ही होगा या जब तक वह उस देश में प्रत्यर्पण न कर जहां से वह सौंपा गया था।

धारा ९—प्रत्यर्पणकारी व्यक्ति के गिरफ्तार होने के दिन से दो मास तक यदि उचित प्रमाण उसके प्रत्यर्पण के नहीं मिलते हैं या सरकार द्वारा अनुमति दिए समय के भीतर तक वे नहीं मिलते हैं या उस न्यायालय में जहां प्रमाण उपस्थित करते हैं उसे छोड़ देगा।

धारा १०—इस संधि के अनुसार गिरफ्तारी के रास्ते के अथवा समर्पण के तमाम व्यय वही सरकार करेगी जो सौंपने की प्रार्थना करेगी।

धारा ११—यह संधि इस विषय पर समस्त पूर्व संधियों, संविदाओं और अंगीकार पत्रों को रद्द करती है।

धारा १२—यह संधि बिना अनुमोदन के स्वीकार करने के दिन के एक महीने बाद लागू समझी जायगी और एक वर्ष की सूचना देकर कोई दल इसे समाप्त कर सकेगा।

काठमाण्डू में २ अक्टूबर, १९५३ को प्रतिलिपि में प्रस्तुत हुई।

बी० के० गोखले
भारत सरकार की ओर से

मातृका प्रसाद कोइराला
नेपाल सरकार की ओर से

२४

कोसी योजना

२५ अप्रैल १९५४ ई० को नेपाल राज्य की सरकार (आगे इसका निर्देश 'सरकार' होगा) से और भारत सरकार (आगे इसका निर्देश 'संघ' होगा) में यह संविदा हुआ।

विषय

संघ पूर नियंत्रण के लिए, अवष्टंभ शीर्षकर्म और अन्य उपाबद्ध काम कोसी सरिता में हनुमाननगर से तीन मील प्रतिस्रोत पर पूर तटों नहरों और रक्षक कामों को नेपाल राज्य की भूमि पर, पूर नियन्त्रण सिंचन जल-विद्युत-शक्ति-जनन और नेपाल की सरिता के दाहिने तट की भूमि को अपरदन से बचाने के निमित्त इच्छुक है। (आगे इसे 'योजना' निर्देशित किया जायगा।)

और सरकार ने उक्त अवष्टंभ शीर्षकर्म और अन्य सम्बन्धित कामों को संघ के और नाग परिव्यय पर, उससे होने वाले कामों का विचार में रखकर स्वीकार किया है।

पक्षकारों ने निम्न अंगीकार किये हैं—

योजना विस्तार

१ (क) अवष्टंभ का स्थितिनिदर्शन हनुमाननगर से तीन मील प्रति स्रोत होगा।

(ख) अवष्टंभ का सामान्य रेखाकुल बाहोत्थान तट के क्षेत्रफल पूर तट बन्ध और संचार की रेखायें इस संविदा से अनुबद्ध मानचित्र में 'अनुबन्धन A' में दिखाई गई हैं।

(ग) इस संविदा के ३ और ८ वाक्यों के लिए यह जलाशय के क्षेत्रों के अन्तर्गत भूमि और सीमाएं जो उपर्युक्त उपवाक्य (ख) के मानचित्र में निर्देशित हैं जलमग्न समझी जायगी।

प्रारम्भिक अनुसन्धान और भूमापन

२ (क) सरकार संघ के नहर और अन्य अधिकारियों को या अन्य व्यक्तियों को जो इन अधिकारियों के आदेश से काम करेंगे पूरी सुविधाएं, आवश्यक व्यक्तियों पशुओं सामान वाहन यंत्रों और आवश्यक औजारों के साथ किसी भूमि में प्रवेश करने देगी जिसकी आवश्यकता इस योजना के लिए अनुसंधान और भूमापन की होगी।

बिहार सरकार सिंचाई विभाग के मुख्य अभियांत्रिक लोक-कर्म-विभाग (कोसी पायजना) योजना के सम्बन्ध में उसके निर्माण के पूर्व पश्चात् और होने की अवस्था में भी आ जा सकेंगे।

इन अनुसन्धानों और भूमापनों के अन्तर्गत भैमानिक और भूमापन आम्मक तरम्-मितीय तलमीय और भौमिकीय मापन साथ में अभिकवियरों का निर्माण तल और

उपक्रम के समन्वेषणों के लिए, सुधार के लिए अनुसन्धान तथा यथार्थ बहिरेखी अवष्टंभ का निर्माण और उसकी सुरक्षा तथा योजना के अन्तर्गत सारे विषय होंगे।

(ख) सरकार आवश्यक सुविधाएं, कोसी या उसकी सहायक सरिताओं के जल को एकत्रित रखने या संचय के अनुसन्धान भूमि रक्षा उपादान जैसे वनरोपण, वनरोपण, इत्यादि या भविष्य में कोसी की समस्याओं के समाधान के लिए होगी प्रदान करेगी।

अधिवासी कार्य का अधिकार, भूमि तथा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार

३ (क) संघ का संयोजन प्राप्त करने के बाद तथा संघ की सरकार को सूचना देने के बाद सरकार संघ को योजना या उसके कुछ अंशों के निर्माण का अधिकार देगी। यह मुख्य अभियान्त्रिक तथा अन्य संघ अधिकारियों कर्मचारियों मनुष्यों पशुओं, वाहनों मशीनों, और आवश्यकीय उपकरणों के साथ जिनकी आवश्यकता योजना को कार्यान्वित करने में होगी उन स्थानों तथा भूमि पर प्रयोजनीय समय तक जाने की और कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगा।

(ख) खण्ड ३ (क) में उल्लिखित भूमि सरकार द्वारा प्राप्त कर ली जायगी और संघ द्वारा उसका क्षतिपूर्ति खण्ड ८ में उल्लिखित नियम के अनुसार होगा।

(ग) *सरकार संघ के अधिकारियों को अधिकार देगी कि वे अवष्टंभ की सीमा या उससे सटी भूमि पर जाकर किसी दुर्घटना के होने की संभावना को रोकने के लिए* उचित कार्रवाई कर सकें। हर दशा में संघ भूमि के अधिकारियों या अधिवासियों को क्षतिपूर्ति देगी। यह कार्य सरकार के द्वारा खण्ड ८ में उल्लिखित नियमानुसार होगा।

(घ) सरकार संघ को योजना के कार्यान्वित करने के लिए कम परन बाजार या नेपाल के अन्य स्थानों में उत्खनन की सुविधाएं देगी।

जल और शक्ति का उपयोग

४ (क) संघ को कोसी सरिता के जल नियमन या अवष्टंभ के स्थान पर तथा शक्ति उत्पादन के लिए योजना को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा। इस कार्य में नेपाल की सिंचन के लिए जल-व्यवहार करने के अधिकार में कोई कमी नहीं होगी।

(ग) सरकार ५० प्रतिशत जल-विद्युत-शक्ति के उपयोग की अधिकारी होगी। इसके लिए वह उतना शुल्क देगी जितना सरकार और संघ में तय हो जायगा।

सर्वप्रभुत्व-सम्पन्नता और अधिकार-क्षेत्र

५ खण्ड ३ में उल्लिखित नियमों के अनुसार सरकार द्वारा प्राप्त भूमि पर संघ का अधिकार होगा उसका संघ को हस्तान्तर होगा तथा खण्ड ४ (क) में जलाधिकार प्राप्त था भी।

इस हस्तान्तर से सरकार के सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न अधिकारों में कमी नहीं होगी।

अधिकार शुल्क

६ (क) शक्ति के जनन में और भारतीय संघ द्वारा उपयोग करने में सरकार उस पर अधिकार शुल्क लगी। इसकी दर परस्पर निर्धारित होगी। नेपाल को बेची शक्ति पर कोई अधिकार शुल्क नहीं मिलेगा।

(ख) पत्थर, कंकड़ और सिंगार पर जो नेपाल में राज्य से निकाला जायगा और योजना के निर्माण में तथा भविष्य संधारण म उपयोगी होगा सरकार संघ को अधिकार शुल्क देगी जिनकी दरें आपस में अंगीकृत कर ली जायेंगी।

(ग) सरकार द्वारा उपार्जित और संघ को हस्तांतरित भूमि म उसे मिट्टी बालू और भूमि को किसी प्रतिरोध के हटाने की स्वाधीनता होगी।

(घ) समतोलन देने के पश्चात् नेपाल के वनों से योजना के लिए लकड़ी के व्यवहार की अनुमति होगी। उन लकड़ियों पर समतोलन नहीं दिया जायगा जो नेपाल में दाहिने तट पर वपसारण के लिए काम में लाई जायेंगी तथा दोनों सरकारों में इस पर स्वीकृति हो जायगी। सरकार द्वारा उपार्जित और संघ को हस्तांतरित वनों की लकड़ियों पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जायगी।

७ योजना के निर्माण में या उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के निर्माण में या उनके संधारण में किसी वस्तु या सामान पर सरकार निराकाम्य गृह कर या अन्य कोई कर नहीं लगी।

भूमि और सम्पत्ति के लिए समतोलन

८ (क) संघ की सरकार की रोकड़ में समतोलन के अभिनिर्धारण के लिए

(अ) खण्ड १ (ख) और खण्ड ९ (क) में उल्लिखित योजना विस्तार के लिए भूमि पर

(आ) निम्नम भूमि पर निम्न भागों में विभाजित होंगे—

१ कृषि भूमि

२ वन भूमि

३ ग्राम्य भूमि और घर तथा अन्य उन पर स्थावर सम्पत्ति और

४ क्षेप्य भूमि।

वह समस्त भूमि जो नेपाल राज्य में पंजी-लेखन में वास्तविक कृषि भूमि पंजीसित होगी कृषि भूमि मानी जायगी।

(ख) संघ उन पर समतामन देगी।

(ग) उस संघ पर जो सरकार से हटा ली गई है तथा उस पर उपार्जित करते समय जिसका प्रतिकार किया जाता था।

(ख) जिस किसी से भूमि, मकान या स्थावर सम्पत्ति योजना के लिए ली गई है और संघ को हस्तान्तरित की गई है ।

क्षतिपूर्ति का अभिनिर्धारण और उसका शोधन सरकार और संघ में परस्पर अंगीकृत होगा ।

(ग) योजना के निमित्त समस्त भूमि का माप सरकार और संघ के अधिकारियों द्वारा साथ-साथ होगा ।

संचार

(क) सरकार अंगीकार करती है कि संघ पथ, ट्राम पथ, रेल पथ, रज्जुमार्ग इत्यादि का निर्माण योजना के लिए कर सकती है उसके लिए खण्ड ८ में उल्लिखित भूमि क्षतिपूर्ति के शोधन के बाद प्राप्य होगी ।

(ख) सरकार के प्रादेशिक अधिकारों के अन्तर्गत पक्के पथों, ट्राम पथों, रेल पथों पर संघ का स्वामित्व व अधिकार रहेगा । संघ के सिंचाई विभाग के ये विभागिक पथ होंगे और वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक कामों द्वारा उनका उपयोग उन्हें यातायात का कोई अधिकार नहीं देगा ।

(ग) सरकार उन्हीं विधियों पर जैसी दूसरों को देता है, सब पथों, जल-मार्गों तथा नेपाल में अन्य संचार-साधनों को अवष्टंभ के निर्माण तथा अन्य कामों के व्यवहार के लिए प्रदान करेगा ।

(घ) हनुमान नगर अवष्टंभ का सेतु जनसाधारण के लिए खुला रहेगा परन्तु उसके जीर्णोद्धार के लिए उसे बन्द करने का संघ को अधिकार होगा ।

(ङ) योजना के निर्माण व संधारण के लिए सरकार नेपाल में तार, टेलीफोन और रेडियो संचार बनाना स्वीकार करती है ।

(च) योजना-क्षेत्र के अन्तर्गत संघ अपने अधीन कर्मचारियों को आन्तरिक टेलीफोन व तार व्यवहार में लाने की अनुमति देती है उनका व्यवहार किसी भी दशा में योजना-निर्माण में रुकावट नहीं डाल सकेगा ।

नदी वाहन का उपयोग

१० नेपाल में कोसी सरिता में नौचरण के समस्त अधिकार सरकार के हैं । किसी नदी वाहन का उपयोग जैसे मशीन वाहन या काष्ठ वाहन अवष्टंभ से दो मील तक नहीं चलाए जा सकते हैं जब तक ऐसा करने के लिए अवष्टंभ के मुख्य अधिकारी द्वारा आज्ञा न प्राप्त कर ली जाए । अनधिकार वाहन का उपयोग करने वाला दण्ड का भागी होगा ।

मात्स्यिकी अधिकार

११ नेपाल में कोसी सरिता के समस्त मात्स्यिकी अधिकार, अवष्टंभ से दो

मील की सीमा छोड़कर, नेपाल सरकार के होंगे। अवप्न्म तथा शीर्ष कम से दो-दो मील की सीमा में मछली नहीं पकड़ी जायगी।

मैपाली श्रमिक का उपयोग

१२ संघ नेपाली श्रमिक सेवा वर्ग और ठेकेदारों को जहां तक वे प्राप्य हो सकेंगे और योजना के निर्माण में उपयोगी होंगे अधिमान देगा परन्तु आवश्यक सब वर्गों के श्रमिक बाहर से भी मँगा सकेगा।

नेपाल में योजना-क्षेत्र का प्रशासन

१३ नेपाल में योजना क्षेत्र के अन्तर्गत संघ ऐसे कार्यों को जैसे विद्यालयों की स्थापना उनका प्रशासन चिकित्सालय जल की सुविधा विद्युत लाली ट्राम लाइनें तथा अन्य नागरिक सुविधाएं प्रदान करेगा।

१४ नेपाल राज्य के अन्तर्गत योजना-क्षेत्र म सरकार न्याय और अधिकार का संधारण करेगी। सरकार और संघ समय-समय पर उचित व्यवस्था इसके लिए करेंगे।

१५. संघ की इच्छा से सरकार योजना क्षेत्र म विशेष न्यायालय या न्यायालयों की स्थापना स्वीकार करती है। ये योजना-क्षेत्र शीघ्र मुकदमे तय करेंगे। सरकार की इच्छा से संघ इनका व्यय वहन करेगा।

कोसी नियन्त्रण कमशाला का भविष्य

१६ यदि और अनुसन्धान यह निर्देश करें कि कोसी और उसकी सहायक सरिता मे भूमि-संरक्षण की रोपन के एकत्र रखने की आवश्यकता है तो सरकार उन्हीं नियमों पर जो यहां उल्लिखित है उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।

मध्यस्थ निर्णयन

१७ यदि कोई प्रश्न भेद या किसी प्रकार की आपत्ति उठ खड़ी होगी जिस का सम्बन्ध इस संविदा या उसके किसी खण्ड के तात्पर्य से होगा या किसी पक्ष के अधिकार कर्तव्य या देयता से तो ऐसे विषय मध्यस्थ निर्णय के लिए दो व्यक्तियों को एक सरकार द्वारा तथा दूसरा संघ द्वारा नियुक्त सौंप दिये जायेंगे। इनके निर्णय सर्वमान्य होंगे। दो मध्यस्थों के बीच अस्वीकृत होने की दशा में विचाराधीन विषय तृतीय मध्यस्थ व्यक्ति को दोनों मध्यस्थों द्वारा नियुक्त होगा सौंप दिया जायगा।

१८. सरकार और संघ के अधिकारी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर करने की तिथि से यह संविदा लागू होगा।

इस संविदा पर अपनी सरकारों द्वारा अधिकारित निम्न व्यक्तियों न काठमाण्डू में हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षर) महावीर समशेर जंग बहादुर राणा नेपाल सरकार की ओर स

(हस्ताक्षर) गुलजारीलाल नन्दा भारत सरकार की ओर से

२५

कोसी योजना के लिए सहकार-समिति

१ कोसी योजना के शीघ्र कार्यान्वित होने के लिए तुरन्त निर्णय करने तथा साधारण उपयोगी समस्याओं के विचार-विमर्श के लिए एक विचारालय की आवश्यकता प्रतीत होती है और इसके लिए भारतीय संघ व नेपाल सरकार राष्ट्र सहकार समिति की स्थापना के लिए सम्मत होते हैं। समिति में हर देश के तीन प्रतिनिधि होंगे जो अपनी सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। यह भी तय किया जाता है कि समिति का प्रधान नेपाल सरकार का एक मंत्री होगा और सचिव कोसी योजना का प्रशासक होगा। समिति साधारण योजना के समानोपयोगी विषयों पर विचार करेगी जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन, विस्थापितों का पुनर्वास, विधि व व्यवस्था का संस्थापन, भू-रक्षा के नियमन तथा अन्य विषय जो समिति का विचार करने के लिए नेपाल सरकार व भारतीय संघ द्वारा समय समय पर प्रेषित किये जाएँ।

२ समिति आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर काठमाण्डू में या पेटनी के स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ समिति ठीक समझेगी मिलेगी।

३ समिति के सभा करने पर उसका आय-व्यय भारतीय संघ अपने यहाँ प्रचलित नियमों के अनुसार देगा।

४ समिति के कर्मचारीगणों के अन्य व्यय भार वहन करेगा।

२६

भारत तथा नेपाल सरकारों में लघुसिंचन योजना और लघु जल-प्रदाय योजना पर संविदा।

एक दूसरे के साथ सहकारिता की भावना से तथा नेपाल की आर्थिक उन्नति को बढ़ाने के विचार से तथा भारत सरकार की नेपाल सरकार को सहायता की इच्छा से—आर्थिक सहायता द्वारा (चाहे वह अनुदान या ऋण हो) तथा सामान और दक्ष से विशेष सहायता से स्वीकृत योजनाओं का जो नेपाल के आर्थिक विकास में सहायक होंगी—यह स्वीकार करते हैं—

धारा १—भारत सरकार पचास लाख रुपया (भारतीय मुद्रा में) देगी जो चार वर्षों में सन् १९५४-५५ से दिया जायगा। यह नेपाल में लघु सिंचन योजना और लघु जल-प्रदाय योजना के लिए है।

धारा २—सहायता का उपयोग इन में होगा—

(क) योजना के लिए भूमि लेने में श्रम तथा सामान के प्राप्त करने में

(ख) भारत सामान सम्पूर्ण यानों तथा योजना या योजनाओं के सामान के मोल लेने में

(ग) इन योजनाओं के लिए नेपाल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के वेतन-भत्ते मार्ग-व्यय में

(घ) भारत से मँगाये गये ऐसे व्यक्ति के व्यय में इन योजनाओं के निर्माण की सहायता या सलाह के लिए और समान प्रभियन्त्र योजनाओं में।

धारा ३—सरकार द्वारा (ख) तथा माल सामान कल-पुर्जे का व्यय वहन करेगी और प्रचास लाख रुपये से यह पुस्तक समायोजन द्वारा काट लिया जायगा। योजना अथवा योजनाओं पर जो प्रचास में होंगे समय-समय पर वन-प्रवित दी जायगी तथा नेपाल सरकार के प्रमाण पर अथवा वास्तविक प्रगति देखकर और व्यय दिया जायगा।

धारा ४—यह संधि नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के वास्तविक प्रतिनिधियों के निष्पादन से लागू होगा।

निम्न हस्ताक्षरित भारत तथा नेपाल सरकार के उचित प्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपनी सरकार की ओर से काठमाण्डू में १४ जुलाई १९५४ को अंग्रेजी भाषा में प्रसंविदा की दो प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किये।

बी. के. मोसके	बी. के. मिश्र
ए. एस. मेहता की उपस्थिति में	आर. पी. मानन्धर की उपस्थिति में

२७

कोलम्बो योजना

मार्च सन् १९५२ ई० में नेपाल कोलम्बो योजना का सदस्य बना। इस योजना का मूल उद्देश्य दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अर्द्ध-विकसित देशों को सहायता देना है। इसके सदस्य राष्ट्रों को विकास-कार्य में प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है।

एक सौ चार वर्षों तक नेपाल एक ऐसी स्वदेशी कौलाशी पंजों में जकड़ा हुआ था कि वह विकास की ओर कुछ भी अग्रसर नहीं हो सका था। इससे निकलने के बाद नेपाल को इस योजना से लाभ उठाने का अवसर मिला और इस दिशा में भारत सरकार का उसे विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। नेपाल को भारत से अब तक लगभग सात करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त मित्रराष्ट्रों से भी देश को और पर्याप्त सहायता मिलने की सम्भावना है। नेपाल को राष्ट्रों से प्राप्त सहायताएं बिना किसी शर्त के मिली हुई हैं और जिसे नेपाल सरकार स्वेच्छानुसार कार्यान्वित कर रही है। राज्य की सारी आमदनी चार करोड़ रुपये से कम ही है इसलिए बिना ऐसी सहायता बिना नेपाल की आर्थिक स्थिरता ही नहीं अन्य अधिकाधिक विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त आर्थिक वातावरण भी उत्पन्न करना होगा।

विकास-कार्यों के लिए पारस्परिक आधार आवश्यक है तथा किसी विशिष्ट विकास योजना की सफलता या असफलता उसकी बहुमुखी योजना की रूपरेखा पर निर्भर करती है। अनेकों अभावों के कारण नेपाल के लिए, बृहत् राष्ट्रीय योजना बनाने के रास्ते में यद्यपि प्रचुर कठिनाइयाँ हैं किन्तु उन अभावों से परिचित रहते हुए भी नेपाल सरकार ने उनमें से अनेकों को पूरा करने का प्रयत्न इस प्रकार किया है—

(क) अन्तर्देशीय तथा विदेशी प्रशासकों के सहयोग से शासन-पद्धति में सुधार,

(ख) जनगणना, व्यापार, उत्पादन आदि तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक आंकड़ों का संकलन

(ग) प्राकृतिक साधनों की हवाई तथा मैदानी सर्वे

(घ) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विदेशी राष्ट्रों द्वारा प्राविधिज्ञों की प्राप्ति और उम्मीदवारों को शिक्षा देने के लिए विदेश भेजने के सम्बन्ध में प्रदत्त सहायता की उपलब्धि और

(ङ) आय पर कर लगाने के नये उपायों को लागू करने तथा आमदनी के अन्य साधनों की खोज।

बृहत् योजनाओं को सुव्यवस्थित करने का काम होते हुए भी निम्नलिखित कार्य शुरू कर दिये गये हैं—

(१) यातायात और संचार में सुधार—

(क) नेपाल की राजधानी और भारत की सीमा को संबद्ध करने वाली पगडंडी और उसे पक्का करने वाली सड़क नेपाल तथा भारत के संयुक्त प्रयास से शीघ्रतापूर्वक बनाई जा रही है।

(ख) पहाड़ तथा तराई के मुख्य जिलों से नेपाल की राजधानी काठमाण्डू हवाई मार्ग से मिला दी गई है। अन्य जिलों से हवाई यातायात स्थापित करने के लिए सम्भाव्यता की जाँच की जा रही है।

(ग) अत्यन्त दुर्गम जिलों के साथ ही देश भर में आकाशवाणी (वायरलेस) स्टेशनों की स्थापना और आवश्यकतानुसार इनके विकास की व्यवस्था हो रही है।

(२) भूमि-सुधार को लागू करने के विषय में—

एक भूमि-सुधार कमीशन का गठन हो चुका है जिसके द्वारा कृषक समुदाय को जो नेपाल की कुल जनसंख्या का ९५ प्रतिशत है भूमिकारी अधिकार दिलाने और आर्थिक विषमता दूर करने की दिशा में शीघ्रतापूर्वक काम हो रहा है।

(३) विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण (पड़ताल)—

(क) समस्त देश का हवाई फोटो लेने का कार्य हो रहा है। इस पड़ताल के सम्पन्न हो जाने पर एक सुव्यवस्थित नक्शा तैयार किया जा सकेगा।

(ख) यू एन टी ए ए द्वारा निर्धारित एक स्विस जियोलोजिस्ट (भूगर्भवेत्ता) नेपाल के जियोलाजिकल स्थिति की पड़ताल (सर्वे) कर रहे हैं। एक पेट्रोल विशेषज्ञ नियुक्त करने के सम्बन्ध में यू एन टी ए ए से बातचीत चल रही है। इन दोनों विशेषज्ञों के प्रयास से नेपाल के भूगर्भस्थित खनिज साधनों की जिनके सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं, स्थिति और परिमाण का पता चल जायगा।

(४) ग्राम्य-विकास—

टी सी ए द्वारा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताओं से नेपाल सरकार द्वारा ग्राम्य-विकास योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत ३,८०० ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इन कार्यकर्त्ताओं के जिम्मे एक गांव अथवा एक ग्राम समूह होगा। इस तरह खेती की नयी पद्धतियां और विभिन्न प्रणालियों का अवलम्बन करने से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने की बात भी इन्हीं कार्यकर्त्ताओं द्वारा जनता को बताई जायगी।

(५) प्राविधिज्ञों की संख्या-वृद्धि—

प्राविधिज्ञों (टेक्नीशियन्स) की अत्यधिक कमी तथा उनकी प्राप्ति की आवश्यकता का अनुभव करके सरकार ने संभवतः अधिक संख्या में छात्रों को भारत तथा अन्य देशों में विविध विषयों का प्रशिक्षण देने के लिए भेजने की नीति अपनायी है।

भारत तथा कोलम्बो योजना के अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थापित सहायता तथा सुभेच्छा कोष तथा यू एन टी ए ए और एफ. ए. ओ तथा भारत और अमरीका द्वारा दी जाने वाली प्राविधिक सहायता क्रम से हमारी उपर्युक्त चेष्टाएं और भी अग्रसर होतीं किन्तु देश की लगातार राजनैतिक अस्थिरता के कारण स्वभावतः आकांक्षित प्रगति में गत्यवरोध हुआ है।

आर्थिक बहुमुखी योजनाओं की अपेक्षा आंशिक विकास-योजनाओं की उत्तमता का पूर्ण विश्वास होने के कारण सरकार ने उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य विकास कार्यों को भी कार्यान्वित किया है जिनका विवरण इस प्रकार है—

कार्यान्वित की गई विकास-योजनाएं

१ यातायात और संचार—

(क) सड़कें—

सितम्बर, १९५२ में ७० मील लम्बी 'काठमाण्डू से भैंस' तक मोटर चलने लायक सड़क का काम प्रारम्भ हुआ था और अब जीप मोटर गाड़ी चलने योग्य सड़क तैयार हो गई है। इस सड़क के पूर्ण रीति से तैयार हो जाने पर मध्य नेपाल और भारत के मध्य अबाध व्यापार चालू हो जाने की आशा की जाती है। सड़क के निर्माण में लगभग डेढ़-दो

विकास-कार्यों के लिए पारस्परिक आधार आवश्यक है तथा किसी विशिष्ट विकास योजना की सफलता या असफलता उसकी बहुमुखी योजना की रूपरेखा पर निर्भर करती है। अनेकों अभावों के कारण नेपाल के लिए, वृहत् राष्ट्रीय योजना बनाने के रास्ते में यद्यपि प्रचुर कठिनाइयाँ हैं किन्तु उन अभावों से परिचित रहते हुए भी नेपाल सरकार ने उनमें से अनेकों को पूरा करने का प्रयत्न इस प्रकार किया है—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय तथा विदेशी प्रशासकों के सहयोग से शासन-पद्धति में सुधार

(ख) जनगणना व्यापार, उत्पादन आदि तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक आंकड़ों का संकलन

(ग) प्राकृतिक साधनों की हवाई तथा मैदानी सर्वे

(घ) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विदेशी राष्ट्रों द्वारा प्राविधिविज्ञी की प्राप्ति और उम्मीदवारों को शिक्षा देने के लिए विदेश भेजने के सम्बन्ध में प्रबन्ध सहायता की उपलब्धि और

(ङ) आय पर कर लगान के नये उपायों को लागू करने तथा आमदनी के अन्य साधनों की खोज।

वृहत् योजनाओं को सुव्यवस्थित करने का काम होते हुए भी निम्नलिखित कार्य शुरू कर दिये गये हैं—

(१) यातायात और संचार में सुधार—

(क) नेपाल की राजधानी और भारत की सीमा को सम्बद्ध करने वाली पक्की और बारह महीने चालू रहने वाली सड़क नेपाल तथा भारत के संयुक्त प्रयास से शीघ्रतापूर्वक बनाई जा रही है।

(ख) पहाड़ तथा तराई के मुख्य पाँच जिलों से नेपाल की राजधानी काठमाण्डू हवाई मार्ग से मिला दी गई है। अन्य जिलों से हवाई यातायात स्थापित करने के लिए तत्सम्बन्धी खोज की जा रही है।

(ग) अत्यन्त दुर्गम जिलों के साथ ही देश भर में आकाशवाणी (वायरलेस) स्टेशनों की स्थापना और आवश्यकतानुसार इसके विकास की व्यवस्था हो रही है।

(२) भूमि-सुधार को लागू करने के विषय में—

एक भूमि-सुधार कमीशन का गठन हो चुका है जिसके द्वारा कृषक समुदाय को जो नेपाल की कुल जनसंख्या का ९५ प्रतिशत है भूमिधारी अधिकार दिलाने और आर्थिक विषमता दूर करने की दिशा में शीघ्रतापूर्वक काम हो रहा है।

(३) विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण (पड़ताल)—

(क) समस्त देश का हवाई फोटो लेने का कार्य हो रहा है। इस पड़ताल के सम्पन्न हो जाने पर एक सुसंगठित नक्शा उपलब्ध किया जा सकेगा।

(ख) यू एन टी ए ए द्वारा नियोजित एक स्विस जियोलोजिस्ट (भूगर्भवेत्ता) नेपाल के जियोलाजिकल स्थिति की पड़ताल (सर्वे) कर रहे हैं। एक पेट्रोल विशेषज्ञ नियुक्त करने के सम्बन्ध में यू एन टी ए ए से बातचीत चल रही है। इन दोनों विशेषज्ञों के प्रयास से नेपाल के भूगर्भस्थित खनिज सामग्री की जिसके सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं स्थिति और परिमाण का पता चल जायगा।

(४) ग्राम्य-विकास—

टी सी ए द्वारा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताओं से नेपाल सरकार द्वारा ग्राम्य-विकास योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत १८० ग्रामीण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इन कार्यकर्ताओं के जिम्मे एक गांव अथवा एक ग्राम समूह होगा। इस तरह खेती की नयी पद्धतियां और विशेष प्रणालियों का अवलम्बन करने से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने की बात भी इन्हीं कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को बताई जायगी।

(५) प्राविधिज्ञों की संख्या-वृद्धि—

प्राविधिज्ञों (टेक्नीशियन्स) की अत्यधिक कमी तथा उनकी प्राप्ति की आवश्यकता का अनुभव करके सरकार ने समवत अधिक संख्या में छात्रों को भारत तथा अन्य देशों में विविध विषयों का प्रशिक्षण देने के लिए भेजने की नीति अपनायी है।

भारत तथा कोलम्बो योजना के अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थापित सहायता तथा यूनेस्को कोष तथा यू एन टी ए ए और एफ. ए ओ तथा ब्रिटेन और अमरीका द्वारा दी जाने वाली प्राविधिक सहायता क्रम से हमारी उपर्युक्त चेष्टाएं और भी सफल होतीं किन्तु देश की लगातार राजनैतिक अस्थिरता के कारण स्वभावतः आकांक्षित प्रगति में अवरोध हुआ है।

आर्थिक बहुमुखी योजनाओं की अपेक्षा आंशिक विकास-योजनाओं की उपयोगिता का पूर्ण विश्वास होने के कारण सरकार ने उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य विकास कार्यों को भी कार्यान्वित किया है जिनका विवरण इस प्रकार है—

कार्यान्वित की गई विकास-योजनायें

१ यातायात और सचार—

(क) सड़कें—

सितम्बर, १९५२ में ७० मील लम्बी 'काठमाण्डू से भैंसे' तक मोटर चलने लायक सड़क का काम आरम्भ हुआ था और अब जीप मोटर गाड़ी चलने योग्य सड़क तैयार हो गई है। इस सड़क के पूर्ण रीति से तैयार हो जाने पर मध्य नेपाल और भारत के मध्य सचार व्यापार चालू हो जाने की आशा की जाती है। सड़क के निर्माण में लगभग डेढ़-दो

२ नल-कूपो की सिचाई—

नेपाल सरकार ने अमरीकी सरकार के सहयोग से पश्चिम तराई म सिचाई के लिए १० नलकूपा को गाड़ने का प्रस्ताव किया है। इनसे १० वर्गमील जमीन की सिचाई होगी और इसम १५ ० ० डालर तथा ३ ०० रुपयों का व्यय होगा।

३ डीजल लिफ्ट पम्प (डीजल तेल द्वारा सचालित सिचाई-यत्र)—

इस योजना का लक्ष्य नेपाल के भिन्न-भिन्न भागों में सिचाई के काम के लिए १२० हलके सफरी डीजल पम्पों की व्यवस्था करनी है। इन पम्पों से एक घंटे में २५००० से ४५ ०० गैलन तक पानी निकाला जा सकता है और प्रत्येक पर ३ ०० रुपयो का व्यय होगा। इन पम्पो को देश की जनता से बेचकर विकास-योजना के लिए सहायता कोष का प्रबन्ध किया जायगा।

४ राप्ती घाटी विकास योजना—

यह एक अत्यधिक साधन संपन्न नदी-घाटी है। मलेरिया नियंत्रण हो जाने पर इस योजना से लगभग ५ ० एकड़ परती अनुत्पादित भूमि में खेती की जा सकेगी। राप्ती घाटी म मलेरिया निवारण तथा उसकी स्थिति सम्बन्धी पड़ताल (सर्वेक्षण) का प्रबन्ध किया जा चुका है। अनुमानत १९५५ ई० में पूरी होने वाली इस योजना पर १ ० रुपये खर्च होंगे।

एक पचवर्षीय समय के भीतर कोसम्बो योजना के अंतर्गत भारत नेपाल सरकार को छोटी सिचाई योजनाओं के लिए ५ लाख रुपये देने की स्वीकृति दे चुका है। इस रकम द्वारा निम्नलिखित सिचाई योजनाओं का काम चालू करने का निश्चय किया जा चुका है—

योजना विवरण	अनुमानित सम्पूर्ण व्यय	हो सकने वाली सिचाई की भूमि बीघा-संख्या
(क) विजयपुर (पश्चिम नं० १)		
(ख) बतार (पश्चिम नं १)	१५४२७५	
महादेव खोला (काठमाण्डू घाटी)	२९११५८६	११ ०
तुमलिंग टार (धैनपुर इलाका जिला धनकुटा)	७ ० ०	१५ ०
		१ ०
चिसपानी हजारी बेंदी और चितला फेदी (पूर्व नं ४)	८० ००	१ ०
…मपीपुर जल-संचय कुण्ड (…गौलिहवा) का पुनर्निर्माण	५० ०	१६ ०
…नाली योजना (सप्तरी)	२७४५०	
	१२७,२७१	९० ०
		४ ०

(ख) यू एन टी ए ए द्वारा निर्धारित एक स्विस जियोलोजिस्ट (भूगर्भवेत्ता) नेपाल के जियोलाजिकल स्थिति की पड़ताल (सर्वे) कर रहे हैं। एक पेट्रोल विशेषज्ञ नियुक्त करने के सम्बन्ध में यू एन टी ए ए मे बातचीत चल रही है। इन दोनो विशेषज्ञों के प्रयास मे नेपाल के भूगर्भस्थित खनिज साधनों की जिनके सम्बन्ध म विभिन्न प्रकार की विचारधाराए चल रही ह स्थिति और परिमाण का पता चल जायगा।

(४) ग्राम्य-विकास—

टी सी ए द्वारा प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताओं से नेपाल सरकार द्वारा ग्राम्य-विकास योजना चल रही है। इस योजना के अंतर्गत १८ ग्रामीण कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इन कार्यकर्ताओ के जिम्मे एक गाव अथवा एक ग्राम समूह होगा। इस तरह खेती की नयी पद्धतिया और सिचाइ प्रणालियों का अवलम्बन करने स उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने की बात भी इन्ही कार्यकर्ताओ द्वारा जनता को बताई जायगी।

(५) प्राविधिविज्ञों की संख्या-वृद्धि—

प्राविधिविज्ञों (टेक्नीशियन्स) की अत्यधिक कमी तथा उनकी प्राप्ति की आव श्यकता का अनुभव करके सरकार ने संभवत अधिक सख्या में छात्रो को भारत तथा अन्य देशों में विविध विषयो का प्रशिक्षण देने के लिए भेजने की नीति अपनायी है।

भारत तथा कोलम्बो योजना के अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्थापित सहायता तथा प्वाइन्ट फोर, यू एन टी ए ए और एफ. ए ओ तथा भारत और अमरीका द्वारा दी जाने वाली प्राविधिक सहायता क्रम से हमारी उपर्युक्त चेष्टाएं और भी अग्रसर होती किन्तु देश की लगातार राजनैतिक अस्थिरता के कारण स्वभावत आकांक्षित प्रगति में गत्यवरोध हुआ है।

आंशिक बहुमुखी योजनाओं की अपेक्षा आंशिक विकास-योजनाओं की उत्तमता का पूर्ण विश्वास होने के कारण सरकार ने उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य विकास कार्यों को भी कार्यान्वित किया है जिनका विवरण इस प्रकार है—

कार्यान्वित की गई विकास-योजनायें

१ यातायात और सचार—

(क) सड़कें—

सितम्बर १९५२ में ७ मील लम्बी 'काठमाण्डू से भैसे तक मोटर चलने लायक सड़क का काम प्रारम्भ हुआ था और अब जीप मोटर गाड़ी चलने योग्य सड़क तैयार हो गई है। इस सड़क के पूर्ण रीति से तैयार हो जाने पर मध्य नेपाल और भारत के मध्य अबाध व्यापार चालू हो जाने की आशा की जाती है। सड़क के निर्माण में लगभग डढ़-डा

करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान है और जो भारत नेपाल को अनुदान के रूप में दे रहा है। इसका नाम 'त्रिभुवन राजपथ' रखा गया है।

मार्ग विकास सम्बन्धी योजनायें

(क) भारत सरकार से मँगाये गये इन्जीनियरों की सहायता से लगभग ४० मील लम्बी मोटर गाड़ियाँ चलाने योग्य सड़कों के खाके की पड़ताल समाप्त हो गयी है। हर मौसम में काम देने वाली नयी सड़कों का विदेश विभाग द्वारा सड़क सम्बन्धी सर्वे का नक्शा तैयार कर लिया गया है।

(ख) नेपाल में हवाई यातायात के विकास को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। १९५२-५३ में नेपाल के पाँच प्रमुख जिले हवाई सर्विस के द्वारा सम्बद्ध कर दिये गये हैं। नेपाल में विदेशी और अन्तर्देशीय हवाई यातायात के लिए 'एयर नेपाल लिमिटेड' नाम की एक नई सरकारी कम्पनी की स्थापना की गई है। हवाई सर्विस के विकास के लिए भारत सरकार से डकोटा विमानों की माँग की गई है।

(ग) एक नया 'मीडियम फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिशन' स्टेशन काठमाण्डू में खोला जा चुका है। इस योजना पर नेपाल सरकार के २ ० रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) केयुल की ७ मील लम्बी २०० लाइन सेन्ट्रल बैट्री दोहरी एक्सचेंज टेलीफोन सर्विस का प्रबन्ध भी किया गया है। तत्सम्बन्धी कार्य के लिए ५ लाख रुपये का टेलीफोन का सामान भारत से मँगाया है। काठमाण्डू से गौचर हवाई अड्डा तक मोटर चलाने लायक पाँच मील लम्बी सड़क-निर्माण के काम में २० रुपयों के व्यय का अनुमान है।

२ कृषि—

(क) अनुसन्धान—

टी सी ए विशेषज्ञों की देखरेख में नेपाल के विभिन्न ऊँचाइयों पर होने वाले गेहूँ मक्का धान आदि के प्रकारों का शोध हो रहा है। प्रयोगों के परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) दुग्धशालाओं और मवेशियों की उन्नति—

दुग्धशालाओं और पशु उद्योगों के लिए नेपाल एक उपयुक्त क्षेत्र होने के कारण एक स्विस दुग्धशाला विशेषज्ञ की देखरेख में ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र में 'स्विस' पद्धति पर एक छोटी दुग्धशाला की स्थापना की गई है। साथ ही काठमाण्डू में भी एक केन्द्रीय पशुशाला विकास फार्म खोला गया है। स्थानीय मवेशियों की नस्लों में सुधार करने के लिए करांची से सिन्धी गायें और साँड मँगाये गये हैं। इन मवेशियों की नस्ल-सुधार योजना पर १ १० ० रुपयों के सरकारी खर्च का अनुमान किया जा रहा है।

(ग) मत्स्य-पालन—

नेपाल देश नदियों और झीलों से भरा पड़ा है। मत्स्य-उद्योग के लिए यह देश बहुत उत्पादन-क्षमता से परिपूर्ण है। हाल ही में कृषि-विभाग के अंतर्गत सरकार ने एक मत्स्य-

विभाग का भी संगठन किया है। प्रयाग और परीक्षण के लिए सरकार ने काठमाण्डू में सभी प्राप्य तालाबों को बिहार से मँगाई गई बड़ी जाति वाली रोहू मछलियों से भरवा दिया है। अब तक विदेश से मछलियों के चार लाख छोटे बच्चे मँगाये जा चुके हैं। मत्स्य पालन प्रयोग के परिणाम प्रचुर उत्साहवर्द्धक हैं।

(घ) सिंचाई—

२५ ०-२५०० एकड़ भूमि को सींचने लायक दो छोटी नहरों का निर्माण हो रहा है। अमेरिकन सरकार से दस बड़े नल-कूप (ट्यूब-वेल्स) मध्य तराई के वास्ते नहर और चार स्थानों पर नदी से सिंचाई करने का सर्वे करने के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। इस योजना के अनुसार ८७३१० रुपया और १४० ००० डालर के खर्च पर १६ ००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। काम चालू करने के लिए आवश्यकीय प्रबन्ध किये जा चुके हैं।

३ विद्युत-शक्ति

राजधानी में बिजली देने के लिए, सरकार द्वारा १५ ० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाले एक डीजल-संचालित विद्युत-यन्त्र स्थापित किया जा रहा है। यह एक तात्कालिक क्षणिक-परिणाम है। समूची विद्युत-विकास योजना पर लगभग २ ०० ० रुपयों के खर्च का अनुमान है।

४ जन-स्वास्थ्य—

नेपाल सरकार द्वारा टी सी ए योजना के सहयोग से कीटाणुजनित महामारियों का नियन्त्रण-कार्य नेपाल के पाँच स्थानों में शुरू कर दिया गया है। मलेरिया नियन्त्रक सामान डी डी टी रोमुथीन टे सेट और पिचकारी आदि के लिए १४ ००० डालर टी सी ए अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ है। समझौते के अनुसार नेपाली छात्र भारत की मलेरिया-प्रशिक्षण संस्थाओं में मलेरिया-निरोधक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नेपाल में ५ वर्षों के भीतर मलेरिया का मूलोच्छेद करने के लिए बनाई गई इस योजना पर ५,१९,७० डालर तथा १६ ४२०० रुपये व्यय होंगे।

५ जल-शोधक यन्त्र—

राजधानी में पीने वाला पानी स्वच्छ करने के लिए नेपाल सरकार ने दो जल-शोधक योजनाओं को १९५० ई० से चालू किया था। अब तक इन योजनाओं पर ४७९, ० रुपये खर्च किये जा चुके हैं। उक्त योजनायें लगभग समाप्त-प्राय हैं।

६ ग्राम-विकास योजना—

भारत की सामुदायिक योजना जैसी ही नेपाल में भारत तथा अमरीकी सरकारों के सहयोग से एक पंचवर्षीय योजना चालू की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काठमाण्डू में और तराई क्षेत्रों के लिए परकोली में दो प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गये हैं। इनमें एक साथ

पचास ग्राम्य नेताओं को ६ महीने के समय में कृषि-पद्धतियों और प्रविधियों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पांच साल में १८ ग्राम-विकास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षणपूर्वक तैयार करना है।

इस योजनानुसार नेपाल १ केन्द्रों में विभाजित किया जायगा। प्रत्येक केन्द्र में विशेषज्ञ प्रशासक व्यवस्थापक १ सुपरवाइजर और १ ग्राम-विकास-कार्यकर्ता होंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता के जिम्मे पांच सौ परिवारों का एक समूह सौंप रहेगा।

पांच साल की इस योजना में नेपाल सरकार के १ १८ १२ ०० रुपयों के व्यय का अनुमान है जिसका एक भाग टी सी ए वहन करेगा। सन् १९५२-५३ में १० कार्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिनमें से ८ की नियुक्तियां पांच विकास-केन्द्रों में हो चुकी हैं, जो कुल ३७ ग्रामों में सेवा कर रहे हैं।

नेपाल राज्य में धान पैदा किये जाने वाले खेतों का भूमि परिमाण लगभग ३५८९ हजार एकड़ है। देश की भूमि में चावल की पैदावार प्रमुखता रखती है। ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चावल की १ प्रतिशत गेहूं की २० प्रतिशत मकई की २ प्रतिशत और आलू की १ प्रतिशत उपज बढ़ने का अनुमान है। इस योजना के सफलता-पूर्वक पूर्ण होने पर नेपाल के कृषि-उत्पादन में कई गुनी वृद्धि हो जायेगी तथा यह जनता के जीवन-स्तर को उठाने में सहायक होगी।

७ भूगर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण—

भारत सरकार और यू एस टी ए ए के सहयोग से नेपाल में सर्वप्रथम भूगर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण नियमित रूप से हो रहा है। मध्य नेपाल में भूगर्भ-सर्वेक्षण का काम समाप्त हो चुका है। इस सर्वेक्षण की प्रगति ऐसी ही रही तो १९५५ के पहले ही पूरे नेपाल राज्य भर में यह काम सम्पन्न हो जायगा। इस कार्य से देश के खानीय स्रोतों की ठीक अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। खानों के स्थानीय और विदेशी इन्जीनियरों सहित भूतत्ववेत्ताओं की एक टोली सर्वेक्षण रिपोर्टों की संभावना की पुष्टि करती है। अब तक मध्य नेपाल में लोहे और ताम्बे के खान होने की रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी विस्तृत और ब्योरेवार पड़ताल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस योजना पर सरकार के १५३९१ रुपये खर्च होंगे।

८ हवाई सर्वेक्षण—

कोलम्बो योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता से नेपाल की २ • वर्गमील की हवाई पैमाइश पूरी हो गई है। हवाई फोटोग्राफ और सुस्पष्ट सुविचारित हवाई नक्शे अब प्राप्त हो जायेंगे। नेपाल में सड़क नहर बांध और नये शहरों की स्थापना में ये अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे।

परिशिष्ट

१ प्रचार और प्रसारण—

पांच किलोवाट का एक उच्च शक्तिशाली प्रसारण यंत्र (हाई फ्रिक्वेन्सी ब्राडकास्ट ट्रान्समीटर) और १ २५० वाट का मध्यम शक्ति प्रसारण यंत्र (मीडीयम फ्रिक्वेन्सी ट्रान्स मीटर) की योजना पर सरकार के २४० ० रुपयों के अतिरिक्त तत्सम्बन्धी अन्य खर्चों को मिलाकर लगभग पांच लाख रुपयो के व्यय का अनुमान है।

२. जिलों के विकास-कार्य के लिए जिला अफसरों के निवेदन पर नेपाल सरकार ने निम्नलिखित धन की स्वीकृति दी है। यह सम्पत्ति १९५२ ५३ के स्वीकृत बजट के अतिरिक्त राष्ट्र-निर्माण के लिए दी गई है।

विषय	रुपयों की संख्या
१ जन-स्वास्थ्य	९१ ०
२ सड़क और पुल	१११५००
३ नल कूवां तालाब और मल-कूप (ट्यूब-वेल्स)	१५७९००
४ शिक्षा	८१६००
५ मरम्मत और निर्माण	१०२,८००
६ नहर	४१०००
७ टलीफोन	५०००
८ नवीन पुलिस चौकियां	११२४४
९ नदी बांध	१ ०
१० डाकखाना	१४०००
११ साधारण हवाई यातायात तथा अग्नि-काण्ड से ग्रस्त आपत्कार्य	२००००
	५८६२४४

प्रस्तावित विकास योजनायें

निम्नलिखित योजनायें टी सी ए के अंतर्गत अमरीकी सरकार के पूर्व नियोजित सहयोगिक आधार पर पूरी की जाने वाली है। इस सम्बन्ध में एक तात्कालिक समझौता भी हो गया है।

१ नदी सिंचाई योजना—

नेपाल सरकार ने सन् १९५४ में टी सी ए की सहायता से मध्य नेपाल में एक नदी-सिंचाई योजना के विकास का प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त योजना पर अमरीकी और नेपाल सरकारों का क्रमश ५१ ० डालर तथा ११५३५९४ रुपयों का व्यय होगा। नहर को पूरा करने में दो साल लगेंगे। इसके द्वारा १७०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इससे प्रचुर उत्पादन-वृद्धि होगी।

२ नल-कूपो की सिंचाई—

नेपाल सरकार ने अमरीकी सरकार के सहयोग से पश्चिम तराई में सिंचाई के लिए १ नलकूपो को गाड़न का प्रस्ताव किया है। इससे १ बर्गमील जमीन की सिंचाई होगी और इनम १५ ०० डालर तथा १ ०० ०० रुपयों का व्यय होगा।

३ डीजल लिफ्ट पम्प (डीजल तेल द्वारा संचालित सिंचाई-यन्त्र)—

इस योजना का व्यय नेपाल के भिन्न-भिन्न भागों में सिंचाई के काम के लिए १२० इनके सफरी डीजल पम्पो की व्यवस्था करनी है। इन पम्पों से एक घंटे में २५,००० से ८५,०० गैलन तक पानी निकाला जा सकता है और प्रत्येक पर ३ रुपयों का व्यय होगा। इन पम्पों को देश की क्षमता से लेकर विकास-योजना के लिए सहायता कोष का प्रबन्ध किया जायगा।

४ राप्ती घाटी विकास योजना—

यह एक अत्यधिक साधन संपन्न नदी-घाटी है। मलेरिया नियंत्रण हो जाने पर इस योजना से लगभग ५०० एकड़ परती अनुत्पादित भूमि में खेती की जा सकेगी। राप्ती घाटी म मलेरिया निवारण तथा उसकी स्थिति सम्बन्धी पड़ताल (सर्वेक्षण) का प्रबन्ध किया जा चुका है। अनुमानत १९५५ ई० में पूरी होने वाली इस योजना पर १ ० ० रुपये खर्च होंगे।

एक पंचवर्षीय समय के भीतर कोलम्बो योजना के अंतर्गत भारत नेपाल सरकार को छोटी सिंचाई योजनाओ के लिए ५० लाख रुपये देने की स्वीकृति दे चुका है। इस रकम द्वारा निम्नलिखित सिंचाई योजनाओं का काम चालू करने का निश्चय किया जा चुका है—

योजना विवरण	अनुमानित सम्पूर्ण व्यय	हो सकने वाली सिंचाई की भूमि बीघा-संख्या
(क) विजयपुर (पश्चिम नं १)	१५४१७५	११०
(ख) बतर (पश्चिम नं १)	२११५८६	१५०
महादेव खोला (काठमाण्डू घाटी)	७०००	३
तुर्गाबिम टार (चैनपुर इलाका जिला धनकुटा)	८००	३ ०
विगमा हजारी बेंसी और विगमा फेदी (पूर्व नं ४)	५० ०	११
जगदीसपुर जल-संचय कुण्ड (तौलिहवा) का पुनर्निर्माण	२७३५	९
कन्नाकी योजना (नवाटी)	१२७२७१	४ ०

महेन्द्रनहर (मार्ग)	२० ०००	१० ०००
सिंचाई बाँध (मार्ग)	११ ०००	३ ०००
कमलीया बाँध (मार्ग)	५,००	४ ०००
पानी निचोड़ रखने वाले कुएँ का मामला २५ पम्पिंग कुएँ (तराई)	८९,९४५	५, ००
	११ ३३ २९५	६३ ९००

७ जल विद्युत-शक्ति—

काठमाण्डू के लिए विद्युत-शक्ति की प्राप्ति अत्यावश्यक हो उठी है। साढ़े पाँच लाख की जनसंख्या वाले काठमाण्डू शहर के लिए वर्तमान में प्राप्त ९ ० किलोवाट मात्र की बिजली शहर की माँग के अनुसार, बहुत कम है। अतः शहर में नजदीक ही ५,००० से १० किलोवाट तक की विद्युत-शक्ति उत्पादन करने वाले जल-विद्युत यंत्र का तुरन्त स्थापन अत्यावश्यक हो उठा है।

विद्युत-शक्ति उत्पन्न करने के लिए काठमाण्डू से क्रमशः ५ और १५ मील की दूरी पर अवस्थित नारायण गढ़ और त्रिशूली बाजार उपयुक्त स्थान माने गए हैं। लंदन के एक सलाहकार इञ्जीनियरिंग फर्म—"प्रीस कार्डयू एण्ड रायडर" द्वारा नारायणगढ़ की पूरी जाँच-पड़ताल की जा चुकी है। दूसरे स्थान का भी प्राथमिक सर्वेक्षण हो गया है।

सभ्य समाज की आर्थिक उन्नति में अत्यन्त सहायक उपर्युक्त दोनों योजनाओं में सहायता करने के लिए कोलम्बो योजनान्तर्गत देशों से अनुरोध किया गया है। साथ ही बुटवल के लिए एक बहुमुखी योजना और सर्लाही तथा जनकपुर की दो प्रवाही सिंचाई योजनाओं की रिपोर्ट भी कोलम्बो योजनान्तर्गत देश के समक्ष सहयोग-प्राप्ति के लिए अविलम्ब पेश की जा चुकी है। नेपाल की उन्नति में रुचि रखने वाले (कोलम्बो योजना के) सदस्य राष्ट्र तत्सम्बन्धी अन्य सहयोग के लिए आमंत्रित हैं।

चालू योजनाओं पर होने वाले खर्चों की संक्षिप्त रूप-रेखा

नं	विषय	रुपया	डालर
१	ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन	११००००	
		७० ०००	
	टेलीफोन	५० ०००	
२	कृषि	११८००	
३	सिंचाई	८७६१००	१४० ०००
४	विद्युत-शक्ति	२० ०० ०००	
५	जन-स्वास्थ्य		१४० ०००
६	जल धावक यंत्र	६३५००	
७	ग्राम्य-विकास	१ ०००	७५,०००
		११३०५,०००	३५५,०००

प्रस्तावित विकास-योजनाएं

१	सिंचाई कार्य	१४५३५९४	१५१ ०
	सिंचाई	१००००००	
२	डीजल संचालित मशीनों से पानी खींचने का पम्प		३१ ०
३	प्रशिक्षणार्थी		८५
४	राप्ती घाटी	१०००००	
५	मत्स्य-पालन	४३९००	
६	भौगोलिकीय (भाग समीक्षा)	१४४०००	
७.	जन-स्वास्थ्य	२,५९,०००	११२०० ०
		३००४१९४	४७३०००

विदेशी आर्थिक सहायता

भारत सरकार से (सिंचाई पर)—

भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत तराई और पहाड़ी प्रदेशों में छोटी प्रवाही सिंचाई योजनाओं के लिए पांच वर्षीय किस्तों में ५० लाख रुपया देने की स्वीकृति दी है।

इस योजना से प्राकृतिक उदारता मात्र पर अब तक निर्भर रहने वाली भूमि को न केवल सिंचाई मात्र होगी प्रत्युत बहुत सी परती गैर आबाद जमीन भी उत्पादक खेती लायक बन जायगी फलतः देश के खाद्य-उत्पादन की अत्यधिक परिमाण में वृद्धि हो जायगी।

प्राविधिक प्रशिक्षण—

भारत सरकार ने नेपाली छात्रों और अफसरों को कोलम्बो योजना के अंतर्गत वर्षों तक प्रशासकीय तथा प्राविधिक विषयों का प्रशिक्षण देने की स्वीकृति दी है।

हवाई सर्वे—

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संपूर्ण नेपाल की हवाई पड़ताल चालू है। ८३ से ८८ देशान्तर रेखा के बीच पड़ने वाले क्षेत्र की पड़ताल की समाप्ति पर ही तत्सम्बन्धी व्यय की संख्या प्राप्त की जा सकेगी।

सड़क—

भारत सरकार के सहयोग से नेपाल की रा[illegible] काठमाण्डू को, भारत से जुड़ी हुई एक दूसरी सड़क से [illegible] ७० मील [illegible] का निर्माण हो रहा है। इस पर ९० लाख [illegible] है। [illegible] होने पर मध्य नेपाल और भार[illegible]

भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत तीन आर. ये सी सी आई पार्टी (पड़ताल करने वाली टोलियों) को उत्तर-दक्षिण की एक चार सौ मील अत्यन्त चालू होने वाली (मोटर चलने लायक) सड़क की संभावित पथ-निर्णय की पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया था। अन्य कई सड़कों के पथ-निर्णय की दूसरी पड़ताल भी इस वर्ष की जायगी।

अमरीकी सरकार से—

अमरीकन सरकार से तीन योजना-समझौतों पर, हस्ताक्षर किये जा चुके हैं जिनके अंतर्गत १० नल-कूप १ प्रवाही सिचाई का काम पूरा करने और चार जगहों पर सिंचाई की पड़ताल के लिए १५१ ०० डालर प्राप्त किया जा सकेगा। अमरीकी सरकार द्वारा टी सी ए योजना के अंतर्गत १९५२-५३ के लिए स्वीकृत रकम ४ ९० ००० डालरों का एक अंश उक्त १५३० डालर की रकम है। यह सम्पत्ति ग्राम-विकास कार्यक्रम मलेरिया-निवारण प्राविधिक प्रशिक्षण और प्राविधिकों के ऊपर खर्च की जा चुकी है। यू एस ए सरकार ने तात्कालिक रूप में टी सी ए योजनान्तर्गत एक १ ०००० डालरों की रकम की स्वीकृति देना मंजूर कर लिया है। रकम निम्नलिखित योजनाओं के लिए खर्च की जायगी। नेपाल और अमरीकी सरकार के सम्मिलित प्रयत्न से चलाई जाने वाली निम्नांकित योजनाओं पर खर्च किये जाने के लिए इस रकम की स्वीकृति हुई है।

अमरीका से प्राप्त सहायताओं के आंकड़ों वाला संक्षिप्त लेखा इस प्रकार है—

ग्राम-विकास—

	डालर खर्च	रुपया खर्च
ग्राम-विकास-कार्य	७० ००	१७६,०००
किसानों की कृषि-आवश्यकता-पूर्ति	७ ० ०	१०० ०००
रसायन-शाला के सामान	१५,००	७५, ०
धरती माटी की पड़ताल	१० ०००	२० ०००
	१ ९५,००	२९,० ०

जन स्वास्थ्य—

	डालर खर्च	रुपया खर्च
कीटाणु सम्बन्धी कार्यक्रम	१०० ०००	१, ००००
चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकता-पूर्ति के आयात कार्यक्रम	३० ०००	१०० ०००
	१ ३० ०००	२,०० ०००

सिंचाई—

	डालर खर्च	रुपया खर्च
डीजल संचालित पानी खींचने के यंत्र	७५,० ०	
सिंचाई की पड़ताल करने वाले दल	१७ ०००	३४ ०००

सिरसिया योजना		
शिलाशा योजना	४६०	१२ ०
२० नल-कूप (ट्यूब वेल्स)	१४०	१०२५.००
	,	३१
	१ ७	१७८ ००
विदेशों में प्रशिक्षण	८५ ०	
पूर्णांक	३ ७२	२३४५.०

विषय-सूची (ग)

प्रशिक्षणार्थी वर्ग

१९५१-५२

देश	सहायता	विषय	संख्या
आस्ट्रेलिया	कोलम्बो योजना	खानों की शिक्षा (माइनिंग)	१
		मेड़ों की नस्ल-सुधार (शीप ब्रीडिंग)	१
"		वैमानिक यन्त्र-विज्ञान (एरोनॉटिकल इन्जीनियरिंग)	१
भारत	"	पार्थिव रसायन-शास्त्र (इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री)	१
"		एम बी बी एस (डाक्टरी)	२
		रश्मि-निदान (स्पेक्ट्रस्कपी)	१
"	"	यान्त्रिक-शिल्पकला (मेकेनिकल इंजीनियरिंग)	१
	"	वैद्युतिक-शिल्प (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	४
	"	परिगणन-शास्त्र (स्टैटिस्टिक्स)	१
"	"	डाक-व्यवस्था (पोस्टल वर्क्स)	२५
सीलोन		सहयोमिक निरीक्षक (कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर)	१
		सहयौगिक सहायक (कोऑपरेटिव असिस्टेंट)	१
		१९५२-५३	
बिलायत	"	पार्थिव रसायन-शास्त्र (इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री)	१
"	"	शिशु-रोगों की ट्रॉपिकल औषधि और चिकित्सा	१
आस्ट्रेलिया	"	बीमो प्रोग्राम	१
सीलोन	"	सहयौगिक सहायक	,
भारत	"	पुगी-गुल्क-भाय	७

"

संयुक्त राज्य अमरीका	अनुसूचीय योजना	औषधि (मेडिसिन)	१
		सर्जरी	१
"		वन-विज्ञान	२
		सिंचाई यंत्र-शिल्प	१
		कृषि	४
		जल प्रशासन	७
		शिक्षा	१
		खानों की शिक्षा (माइनिंग)	२
		पथ-निर्माण-शिल्प (रोड इंजीनियरिंग)	१
		शैक्षिक और शिक्षक प्रशिक्षण	१
		औषधीय प्रशासन (मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन)	१
		जल प्रशासन	१
		भूमि-सुरक्षा (स्वायल कन्जर्वेशन)	१
	"	कृषि प्रशासन	१
	"	औद्यानिक-विज्ञान	१
"		संसदीय प्रबन्ध	१
"		रेडियो प्रशासन	२
"	"	गुप्तचर (पब्लिक इन्क्वीजस)	१
बैंकाक	खाद्य कृषि-संस्था	कृषि	१
विलायत	ब्रिटिश काउन्सिल	अंग्रेजी साहित्य	१
"	"	भूगोल	१
"		एम आर सी पी	१
	नेपाल सरकार छात्रवृत्ति	रोग-निदान (पैथोलॉजी)	१
		औषधि-विज्ञान	१
"		उर-विशेषज्ञ (चेस्ट स्पेशलिस्ट)	१
न्यूज़ीलैण्ड	टी ए ए	परिगणन-शास्त्र	१
कनाडा	"	पथ-अभियान्त्रिकता (रोड इंजीनियरिंग)	१
[illegible]		वैद्युतिक-यंत्र-शिल्प (इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग)	१
आस्ट्रेलिया	"	आय-व्ययक योजना	१
भारत	सांस्कृतिक छात्रवृत्ति	कास्ट हिसाब-किताब (कास्ट एकाउन्टेंसी)	१

भारत	सांस्कृतिक छात्रवृत्ति	गुप्तचर (इन्टेलीजेन्स)	१
		एम बी बी एस (चिकित्सा-शास्त्र)	१
		एल एल बी (कानून-शास्त्र)	१
	भारत सरकार छात्रवृत्ति	सामाजिक कार्य	१
		१९५३ ५४	
संयुक्त राज्य अमरीका	संयुक्त राज्य साझदारी सहायता	संसदीय प्रबन्ध	१
		रेडियो प्रशासन	१
		वनस्पति व्याधि निदान (प्लैन्ट पैथोलोजी)	१
		रेल्वे इंजीनियरिंग	१
		खाद्य और पोषक रसायनशास्त्र (फूड एण्ड न्यूट्रीशनल केमिस्ट्री)	१
भारत	कोलम्बो योजना	एम बी बी एस (डाक्टरी)	११
		भूगर्भ शास्त्र (जीओलोजी)	२
		उच्च वन विज्ञान प्रशिक्षण (सुपीरियर फौरेस्ट कोर्स)	२
	"	खान सम्बन्धी शिल्प प्रशिक्षण (माइनिंग इंजीनियरिंग)	१
	"	वनपाल प्रशिक्षण (फारेस्ट रेन्जर कोर्स)	२
	"	नागरिक शैल्पिकता (सिविल इंजीनियरिंग)	४
"	"	यान्त्रिक शैल्पिकता (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	४
"		वैद्युतिक शैल्पिकता (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	४
"	"	बेतार का मंत्र शिल्प (वायरलेस इंजीनियरिंग)	२
	"	प्रादेश्य इंजीनियरिंग (भूमि-शिल्प)	१
"	"	वनस्पति-विज्ञान (बाटनी पोस्ट ग्रैजुएट)	१
	"	कृषि-शास्त्र (एग्रोनोमाजी)	१
	"	टेलीफोन इंजीनियरिंग	१
"	"	जनरल एग्रिकल्चर (सामान्य कृषि)	१
	"	एग्रोनोमी (भारतीय कृषि-कला)	१
"		औद्यानिक शास्त्र (हार्टीकल्चर)	१
"	"	वन-प्रशासन	१

परिशिष्ट १

		बैंकिंग	१
भारत	कोलम्बो योजना	सहयोगिक	
"	"	काष्टक हिसाब-किताब (चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी)	१
"		डिप्लोमा कोर्स	
		सिविल इंजीनियरिंग (नागरिक शिल्पकला)	६
		इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (वैद्युतिक शिल्प)	७
"		मैकेनिकल इंजीनियरिंग (यंत्र शिल्पकला)	४
"		टेलीफोन इंजीनियरिंग (टेलीफोन यांत्रिकता)	९
"		रेडियो इंजीनियरिंग (रेडियो प्राविधिक)	१८
"	"	वायरलेस आपरेटर (बेतार का तार संचालक)	११
"		हवाई यातायात नियंत्रक अफसर	१
		रेडियो आपरेटर (रेडियो-संचालक)	

विषय सूची (ख)

प्राप्त प्राविधिक सहायता

देश	संस्था	विषय	संख्या
	खाद्य-कृषि संस्था	एग्रोनोमी (शास्त्रीय कृषि-कला)	१
		वन विज्ञान	१
		सिंचाई-शिल्प (इरिगेशन इंजीनियरिंग)	१
		दुग्धशाला (डेरी फार्मिंग)	१
		भूमि-विकास (लैण्ड डेवलपमेन्ट)	१
	टी सी ए	वेटीनरी	१
		कृषि-शास्त्र (एन्टोमोलोजी)	१
		कृषि यंत्र शिल्प (एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट इंजीनियरिंग)	
		कृषि-विस्तार (एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन)	
		जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	
		शास्त्रीय कृषि (एग्रोनोमी)	
		खान (माइनिंग)	
		भूगर्भ-सर्वेक्षण	
	भारत सरकार	सैनिक-दल भूगर्भ वेत्ता (मिलिट्री मिशन जीओलोजीकल)	

परिशिष्ट

			१
		बैंकिंग	१
भारत	कोलम्बो योजना	मधुपालिक	१
"		लागत हिसाब-किताब (कास्ट एकाउन्टेन्सी)	
"	"	डिप्लोमा कोर्स	६
		सिविल इंजीनियरिंग (नागरिक शिल्पिकता)	
	"	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (वैद्युतिक शिल्प)	८
		मेकेनिकल इंजीनियरिंग (यंत्र शिल्पिकता)	
	"	टेलीफोन इंजीनियरिंग (दूरभाष यांत्रिकता)	१४
	"	रेडियो टेक्निशियन्स (रेडियो प्राविधिक)	११
"	"	प्रोग्राम मास्टर (प्रसार का सार संचालन)	३
		हवाई यातायात नियंत्रण अफसर	
	"	रेडियो मास्टर (रेडियो-संचालक)	

विषय सूची (ख)

प्राप्त प्राविधिक सहायता

देश	संस्था	विषय	संख्या
	खाद्य-कृषि संस्था	एग्रानामी (शास्त्रीय कृषि-कला)	१
		वन विज्ञान	१
		सिंचाई-शिल्प (इरिगेशन इंजीनियरिंग)	१
		दुग्धशाला (डेरी फार्मिंग)	१
		भूमि-विकास (लैण्ड डेवलपमेन्ट)	१
	टी सी ए	कर्मचारी	१
		कृषि-शास्त्र (एग्रानामी)	
		कृषि यंत्र शिल्प (एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स इंजीनियरिंग)	१
		कृषि-विस्तार (एग्रीकल्चरल एक्स्टेन्शन)	१
		जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हैल्थ)	१
		शास्त्रीय कृषि (एग्रानोमी)	१
		खान (माइनिंग)	
		भूगर्भ-सर्वेक्षण	
	भारत सरकार	सैनिक-दल भूगर्भ कला (मिलिट्री मिशन जीओलोजिस्ट)	१

●